

# उन्नीसवीं शताब्दी का अजमेर ( Ajmer in Nineteenth Century )

MLSU - CENTRAL LIBRARY



72721CL

लेखक

डा० राजेन्द्र जोशी

इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

( Dr. Rajendra Joshi )



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
जयपुर-४

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय  
ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित :

प्रथम संस्करण—१९७२

मूल्य—१६.००

© राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर-४

मुद्रक—  
अणिमा प्रिंटर्स,  
पुलिम मेमोरियल,  
जयपुर-४

## विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

१. प्रस्तावना	
२. प्राक्कथन	
३. ऐतिहासिक सन्दर्भ	१
४. मेरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुदृढीकरण	२३
५. अजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन -	४२
६. भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि	७०
७. हस्तमस्तरदारी-व्यवस्था	८६
८. भौत, जागीर व माफ़ी	११२
९. पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था	१५५
१०. शिक्षा	१८४
११. जनता की आर्थिक स्थिति	२१६
१२. १८५७ का विद्रोह और अजमेर	२४१
१३. राष्ट्रीय एवं आन्तरिकी हलचल	२५१
१४. सन्दाबन्धी	२७५

स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त जी शर्मा  
की पुण्य स्मृति में  
अष्टावलि के रूप में

## प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम-परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामतः भारत सरकार ने इस स्थूलता के निवारण के लिए “वैज्ञानिकी तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग” की स्थापना की थी। इसी योजना के अन्तर्गत पीछे १९६६ में पाँच हिन्दी भाषी प्रदेशों में प्रथम-अकादमियों की स्थापना की गयी।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रन्थ-निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्थों का निर्माण करवा रही है। अकादमी चतुर्यं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तीन सौ से भी अधिक ग्रंथ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तैयार करवायी गयी है। हमें आशा है कि यह अपने विषय में उत्कृष्ट योगदान करेगी।

चंदनमल बौद  
अध्यक्ष

यशदेव शर्मा  
का. बा. निदेशक

## प्राक्कथन

अजमेर नगर राजस्थान की हृदयस्थली रहा है। यह महत्वपूर्ण नगर आधुनिक इतिहास में ही नहीं अपितु भारत के प्राचीन इतिहास में भी आकर्षण एवं घटनाओं का केन्द्र-बिन्दु रहा है। अंग्रेजी राज्यकाल में सुदीर्घकाल तक यह एक राजनीतिक प्रकाश स्तम्भ के रूप में अवस्थित रहा है।

आधुनिक इतिहास में तो अजमेर बहुत समय से समूचे राजस्थान में सभी राजनीतिक हलचलों का एक अप्रतिम केन्द्र रहा है। प्रशासन में आधुनिकता एवं वैज्ञानिकता के तत्त्व ने संभवतः इसी नगर का सर्वप्रथम स्पर्श किया और फिर समूचा राजस्थान उससे किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ। इसलिए अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन के अध्ययन का ऐतिहासिक महत्व हो जाता है क्योंकि सच्चे अर्थों में प्रशासन का शुभारम्भ आधुनिक इतिहास में अजमेर से ही हुआ और कालांतर में समूचे राजवाड़े ने प्रशासन का सूत्र किसी न किसी रूप में यहीं से ग्रहण किया। यह स्वयं स्पष्ट है कि अजमेर के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्पर्शन ने समूचे राजस्थान को सुदीर्घकाल तक स्पर्शित रखा। अभी तक वैज्ञानिक दृष्टि से अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन का अध्ययन नहीं हुआ था। संभवतः इस दिशा में प्रस्तुत ग्रन्थ पहला कदम है। लेखक ने ३ वर्षों के कठिन परिश्रम से सभी मौलिक स्रोतों का अध्ययन किया और पहली बार सम्बन्धित मौलिक सामग्री के आधार पर समूची सूचनाएँ एकत्र कर उसे सुशुद्धित रूप में प्रस्तुत किया।

ब्रिटिश राज्यकाल में अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन का एक सांगोपाग चित्र हम ग्रन्थ में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है और इसके लिए छोटी से छोटी

घोर बड़ी से बड़ी सूचना मौलिक एवं अधिष्ठित मूलों से ही ग्रहण की गई है। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ जिनसे सूचना-संचय में मुझे सहायता मिली है। स्वर्गीय श्री नाथूराम खड्गावत के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिनके सौजन्य से मेरी पहुँच मौलिक सामग्री के लेखागार तक हो सकी।

यह ग्रन्थ विनीत लेखक की ओर से अपनी जन्मभूमि के प्रति एक मौन प्रद्वाराञ्जलि भी है। अजमेर मेरी जन्मभूमि है—स्वर्गादिपि गरीयसी।

राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर।

राजेन्द्र जोशी

## ऐतिहासिक सन्दर्भ

**भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिचय :**

अजमेर-मेरवाड़ा जो इन दिनों वर्तमान अजमेर जिले का भू-भाग है, स्वा-धीनता के पूर्व, अंग्रेज शासित भारत में चीफ कमिश्नरी का एक छोटा सा प्रांत माना था। यह राजस्थान के केन्द्र में स्थित था। चारों ओर से राजपूत रियासतों से घिरा हुआ था। इसके पश्चिम में मारवाड़, उत्तर में किशनगढ़ और मारवाड़, पूर्व में जयपुर और किशनगढ़ तथा दक्षिण में मेवाड़ की रियासतें थीं। इसका कुल क्षेत्रफल २,७७१ वर्गमील तथा जनसंख्या ३८०,३८४ थी। अजमेर मेरवाड़ा की स्थिति पूर्वी गोलार्द्ध में २५° २३' ३०" और २६° ४१' अक्षांश तथा ७३° ४७' ३०" और ७५° २७' ०" देशान्तर के मध्य थी। अंग्रेजों के शासन काल में अजमेर दो जिलों (अजमेर व मेरवाड़ा) में विभक्त था जिनका क्षेत्रफल क्रमशः २०६६ और ६४१ वर्गमील था।<sup>१</sup>

भरावली पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से आरम्भ होती है वास्तव में अजमेर की उत्तरी सीमा से अपना मस्तक उठाती है और उस स्थान पर जहाँ अजमेर स्थित है अपना पूर्ण स्वरूप प्रदर्शन करने लगती है। अजमेर के दक्षिण में कुछ ही मील की दूरी पर यह पर्वत श्रृंखला दुहरी हो जाती है।<sup>२</sup> अजमेर नदियों से वधित है। बवास केरन इसके दक्षिणी पूर्वी सीमाज को छूती है और खारी व ढाई नदियाँ



जिले के दक्षिणी पूर्वी भू-भाग के कुछ अंशों को ही प्रभावित करती है। सागरमती जो अजमेर की परिक्रमा सी करती है, गोविन्दगढ़ में सरस्वती से संगम करती हुई मारवाड़ में लूनी नदी के नाम से प्रख्यात होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है।<sup>३</sup>

भारत के तलहटी क्षेत्र में स्थित होने और मरुस्थलीय भू-भाग का सीमांत होने के कारण यह बगाल की खाड़ी और अरबसागर के मानसूनी के लाभ से वंचित सा रह जाता है। अजमेर में बहुत कम और अनिश्चित वर्षा होती है। इसमें यहाँ पाये दिन प्रकाश एवं अभाव तथा सूखे की स्थिति बनी रहती है। वर्षा की भारी कमी के बावजूद अजमेर क्षेत्र में खरीफ और रबी की दो फसलें होती हैं। कुम्हों और जलाशयों द्वारा सिंचित कृषि से लोगों को गुजारे लायक साधन उपलब्ध हो जाता है। जिले में केवल दो भीरें हैं जिनमें एक पुष्कर में तथा दूसरी सरगाव और करनिय्या के मध्य स्थित हैं। करनिय्या भील ही भकैसी ऐसी है, जिसका पानी मिर्चाई के काम आता है। कर्नेल डिवसन के द्वारा इस जिले में कई तालाबों के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में सदियों में पानी की कमी नहीं रहती।<sup>४</sup>

अजमेर-मेरवाड़ा की वनस्पति और पशु-पक्षी राजपूताना के पूर्वी भाग में पाये जाने वाली वनस्पति और पशु-पक्षियों से मिलते हैं। वृक्षों में भविकाश नीम, बबूल, पीपल, बरगद, सेमल, सालर, ढाक, खेजड़ा और गारग्रा मिलते हैं। यद्यपि बाघ बहुत ही कम थे, तथापि चीते, लकड़वाघा, सूमर, काला हरिण, नीलगाय, बतखें, तीलोर, जलमुर्गा, खरगोश और तीतर साल भर नजर आते थे। अजमेर के प्रथम सुपरिटेण्डेंट ने अपने प्रशासनकाल में यहाँ घने जंगलों का उल्लेख किया है परन्तु बाद में यह सम्पूर्ण क्षेत्र वृक्षविहीन सा हो गया था। ब्यावर शहर, नसीरगवाड की छावनी तथा सालाव निर्माण के लिए चूना तैयार करने में ईंधन की आवश्यकता के कारण, वन, वृक्ष विहीन हो चले थे और वहीं वहाँ इसके दुबके पेड़ नजर आते थे। सन् १८७१ में जंगलात-नियम लागू किये गये और वन विभाग ने कुछ क्षेत्र वन उगाने के लिए भारते अधिकार में लिए जिसके फलस्वरूप इस राज्य के सुरक्षित बनो का क्षेत्र १४२ वर्गमील और १०१ एकड़ हो गया था।<sup>५</sup>

राजपूती रिवाजों में अजमेर के लिये संघर्ष :

फरिश्ता के अनुसार अजमेर का अस्तित्व ६६७ ईस्वी में भी था जब कि हिन्दुओं ने मुकुन्दगिरि के विरुद्ध मयूर के लिए सब स्थापित किया था।<sup>६</sup> किन्तु वास्तव में अजमेर शहर मूल रूप से अजमेर के नाम से प्रख्यात था और ११३३ ईस्वी में अजमेरराज ने इसकी स्थापना की थी।

अजमेरराज के पुत्र और उत्तराधिकारी अर्धोराज के शासन काल में लाहौर और गजनी के समीप अजमेर तक चढ़ गये थे। नगर के बाहर खुले मैदान में हुए युद्ध में पानी से शक्ति बुरी तरह से हाथ और घोड़ों से घनी जान बचाने की

भाग गया था। कई मुस्लिम सैनिक अपने भारी मरकम जिरह बल्लरों के बोक से मर गये और अधिकांश जल शून्य मर भूमि में प्यास से छटपटाते हुए दम तोड़ बैठे। प्रजयमेव ने इस तरह यश मरी विजय थी ग्रहण की और उमकी गणना शक्तिशाली दुर्ग के रूप में की जाने लगी।<sup>१०</sup> अर्धोराज ने मानवा, हरियाणा और अन्य सीमा-वर्ती क्षेत्रों पर चढ़ाई करके अपने राज्य की सीमाएं विस्तृत की थी। जयानक लिखते हैं कि "उसे वर्तमान मन्दिरों का निर्माता तथा भावी मन्दिरों का प्रोत्साहक कहा जायेगा क्योंकि यदि वह मुसलमानों को नहीं हराता तो वे बिना उल्लेख के ही रह जाते।"<sup>११</sup> यद्यपि उपर्युक्त वाक्य प्रशस्ति मान है, तथापि इसमें सत्य का पर्याप्त भंग है।

**विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल—**

अर्धोराज की हत्या कर उनका पुत्र जगदेव अजमेर की गद्दी पर बैठा परन्तु वह अधिक समय तक शासन नहीं कर सका, क्योंकि उसके जयप्य कृत्यों से अर्धनुष्ट उसके छोटे भाई विग्रहराज तथा अन्य सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाला। विग्रहराज ने वालुभ्य साम्राज्य के विरुद्ध कनिष्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था।<sup>१२</sup> विग्रहराज ने मदनक को भी पराजित किया था।<sup>१३</sup> बिजोड्या प्रशस्ति में उल्लिखित विजय अभियानों में विग्रहराज के दिल्ली और हांसी के अभियान महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली और हांसी पर विग्रहराज के अधिकार के पश्चात् चौहानों और तोमरो के बीच लम्बे समय से जारी कलह का अन्त हुआ। मुसलमानों, गढ़वालों और चौहानों से निरन्तर सघर्ष के कारण तोमर साम्राज्य अत्यन्त शिथिल हो गया था, इसीलिए अन्त में उन्हें शाकम्भरी चौहानों का आबिपत्य स्वीकार करना पड़ा। ११६५ ईस्वी में, दिल्ली पर मदनराज तोमर का शासन था।<sup>१४</sup> मुहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का सीषा शासन पृथ्वीराज तृतीय के हाथों में न होकर एक अधीनस्थ राजा के हाथों में था जो कदाचित् मदनपाल के वंशधरों में से रहे होंगे।<sup>१५</sup>

दिल्ली पर विजय प्राप्ति से शाकम्भरी और अजमेर के चौहान शक्तिशाली साम्राज्य के स्वामी बन गये थे और उनके कबों पर मुसलमान आक्राताओं से देश की रक्षा का भार था पड़ा था। चौहानों के उत्कर्षकाल में अजमेर की चतुर्मुखी प्रगति हुई। विग्रहराज चौहान को यह श्रेय है कि उसने कनिष्य हिन्दू राजाओं को गजनवी साम्राज्य से मुक्ति दिलाई थी। वह केवल महान् विजेता ही नहीं था परन्तु एक अनुभवी शासक भी था। वह साहित्य, मर्मज्ञ, कला प्रेमी और शिल्पकला का शायी था। उसे ही अजमेर की समृद्धि का अधिराज्य श्रेय है।<sup>१६</sup>

उसने एक उत्कृष्ट संस्कृत नाटक 'हरवेति' की रचना की थी और अजमेर में 'परस्वती कंअरएण महाविद्यालय' स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता कि यह

जो उन दिनों अपनी बहन के पुत्र भीरुल की वात्स्यावस्था के कारण मेवाड़ के प्रशासन की देखरेख का काम करते थे, भजमेर पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भजमेर सन् १४५५ तक मेवाड़ के अधीन रहा। उसी वर्ष माँह के सुल्तान महमूद खिलजी<sup>२७</sup> ने भजमेर के हाकिम गजवरराय<sup>२८</sup> को पराजित कर भजमेर अपने अधिकार में कर लिया था। पचास वर्ष के अंतराल के बाद राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज<sup>२९</sup> ने भजमेर के गढ़ बीटली (नारायण दुर्ग) पर अधिकार कर एक बार पुनः इस क्षेत्र पर मेवाड़ का आधिपत्य स्थापित किया<sup>३०</sup>।

गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह<sup>३१</sup> ने सन् १५३३ में धमनेरउल मुल्क<sup>३२</sup> को भेजकर भजमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कदाचित् भजमेर पर हमेशा के लिए गुजरात का आधिपत्य हो जाता, परन्तु केवल दो वर्ष बाद ही मेड़ता के राव भीरमदेव<sup>३३</sup> ने गुजरात के हाकिम को भजमेर से खदेड़ दिया<sup>३४</sup>। मारवाड़ के राव मानदेव<sup>३५</sup> ने सन् १५३५ में इसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और सन् १५४३ तक इसे अपने अधिकार में रखा<sup>३६</sup> उसके बाद शेरशाह सूरी के मारवाड़ पर आक्रमण के समय भजमेर उसके अधिकार में चला गया<sup>३७</sup>।

इस्लाम शाह भूर<sup>३८</sup> के पतन के पश्चात् सन् १५५६ में हाजीसान<sup>४०</sup> ने भजमेर पर अधिकार कर लिया था परन्तु अकबर का मुकाबला करने में असमर्थ होने के कारण वह गुजरात भाग गया और अकबर के सेनापति कासिम खान ने भजमेर दुर्ग पर बिना किसी सपर्य के अधिकार स्थापित कर लिया<sup>४१</sup>।

दिल्ली साम्राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका में जुड़ जाने से भजमेर सन् १७३० तक मुगल साम्राज्य का अलग भाग बना रहा। मुगलों के अधीन भजमेर सम्पूर्ण राजपूताना प्रान्त या सूबे का सदर मुकाम था। राजपूताना के मध्यवर्ती होने से मुगलशासकों के लिए भजमेर पर आधिपत्य बनाये रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण था। सैनिक दृष्टि से यहाँ का जिला भी दुर्गम-दुर्बल था। भजमेर एक छोटे उत्तर भारत से गुजरात के मार्ग तथा दूसरी ओर मासवा के मार्ग का नियंत्रण करता था। एक मुद्दूड जिला होने के साथ ही भजमेर व्यापार व्यवसाय का महत्वपूर्ण केन्द्र भी था। इसी मुद्दूड स्थिति का कारण यहाँ की जनबाहुल्य था। रेनीने भूभागों की तरह यहाँ का पानी गारा न होकर स्थानस्थ था। मुगल सम्राटों को इसका महत्व समझने में देर नहीं लगी और भजमेर जाही निवास का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया<sup>४२</sup>।

सम्राट अकबर भजमेर की समृद्धि में अत्यधिक रवि रसता था। उसने बहुरंगीन बनावट, गान (दरगाह) बाजार और मस्जिदों बनवाये। वह बहुधा गान में एक बार भजमेर आता था। जहाँगीर भजमेर में तीन साल तक रहा। उगने यहाँ महल बनवाए और भानासागर की पान पर एक उद्यान दीर्घवर्ष का निर्माण करवाया। शाहजहाँ की भजमेर की मुन्दरगा में चार चाँद लगाने का

श्रेय है। उसने धानामागर पर संगमरमर की वारादरी और दरगाह में जामामस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब भी सन् १६५६ में अजमेर के निकट देवराई<sup>४३</sup> की निर्णायक लड़ाई जीतने के बाद ही वास्तविक रूप से दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर सका था। उसके पुत्र अकबर ने अजमेर के निकट युद्ध में उसे लगभग हराने की स्थिति पैदा कर दी थी। औरंगजेब बड़ी कठिनाई से यह विद्रोह शांत कर पाया था<sup>४४</sup>।

अकबर के साम्राज्य में राजपूताना और गुजरात के विरुद्ध मुगल अभियानों में अजमेर एक दृढ़ मुगल छावनी बना रहा। मुगल सम्राट ने इसे एक सूबे का रूप दिया और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोंही इसके अधीनस्थ कर दिये। फ्राइन्-ए-अकबरी के अनुसार अजमेर का सूबा ३३६ मील लंबा और ३०० मील चौड़ा था और इसकी सीमा पर भागरा, दिल्ली, मुल्तान और गुजरात स्थित थे। इसके अंतर्गत १८७ सरकारें और १६७ परगने थे जिनका कुल राजस्व २८, ६१, ३७, ६६८ दाम या ७१, ५३, ४४ रुपये था। मुगल साम्राज्य के कुल राजस्व १४, १६, ०६५८४ रुपयों में से अजमेर का भूत ७१, ५३, ४४६ रुपये था।<sup>४५</sup> इस सूबे पर मुगल सेना के लिए ८६, ५०० घुड़सवार, ३,४७,००० पैदल सैनिक प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। जिनमें अजमेर सरकार की जिसके अंतर्गत २८ महल थे १६ हजार घुड़सवार और ८४,००० हजार पैदल सैनिक प्रदान करते होते थे। अजमेर दो सौ वर्षों से भी अधिक समय तक मुगल साम्राज्य का अंग बना रहा<sup>४६</sup>।

औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरम्भ हुआ। फर्रूखसिपर<sup>४७</sup> के शासनकाल में जोधपुर नरेश अजीतसिंह जबकि शक्तिशाली बन गए थे। यहाँ तक कि संघर्ष बंधु<sup>४८</sup> अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन पर निर्भर थे और एक तरह से महाराजा अजीतसिंह अपने समय में युद्ध और शांति के निर्णायक माने जाते थे<sup>४९</sup>। सन् १७१६ में संघर्ष बंधुओं के पतन के बाद अजीतसिंह ने अजमेर पर आधिपत्य कर लिया था<sup>५०</sup>। सन् १७२१ में मुहम्मद शाह ने अजमेर को वापस लेने का प्रयत्न किया। उसने काजी मुखपरार के नेतृत्व में अजमेर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी परन्तु अजीतसिंह के बड़े पुत्र अमरसिंह ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने<sup>५१</sup> के दृष्टिकोण से अमरसिंह ने इसके बाद शाहजहापुर व नारनौन पर चढ़ाई कर इन्हें खूब लूटा तथा कई ग्रामों को सड़े सड़े आग लगा दी<sup>५२</sup>।

इस कठिन परिस्थिति में जयपुर के शासक जयसिंह ने मुगल सम्राट की मदद की। उन्होंने अजमेर पर आक्रमण किया, अमरसिंह, जिन पर कि अमरसिंह की अनुपस्थिति में अजमेर की रक्षा का भार था दो महीनों से अधिक इसकी रक्षा नहीं कर सके। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच जो सविवार्ता हुई उसके अनुसार अजमेर मुगल साम्राज्य को सौंप देना पड़ा<sup>५३</sup>।

सन् १७३० में गुजरात ने सरखुलंदगान<sup>२४</sup> के नेतृत्व में दिल्ली की मघीनता प्रतीकार कर दी थी। इस परिस्थिति में मुगल सम्राट ने उसके विरुद्ध भयसिंह से सहायता मांगी और यह वचन दिया कि उसे भजमेर और गुजरात का हाकिम बना दिया जायेगा<sup>२५</sup>। भयसिंह ने १७३१ में गुजरात की जीत कर वापस मुगल साम्राज्य का अधिकार स्थापित किया, परन्तु मुगल सम्राट ने भजमेर, जयपुर के सवाई-जयसिंह<sup>२६</sup> को भरतपुर के जाट शासक बुढामण को दवाने के उपलक्ष में उन्हें प्रदान कर दिया। मुगल सम्राट के इस कदम ने राजपूताने के दो प्रमुख रणवाहों, राठौड़ों और कछवाहों के बीच भजमेर के लिए संघर्ष अवश्यम्भावी कर दिया।

सन् १७४० में भिनाय और बीसागन के राजाओं की मदद से भयसिंह के भाई जयसिंह ने भजमेर के हाकिम को परास्त कर भजमेर पर राठौड़ों का अधिकार पुनः स्थापित किया। फलस्वरूप जयपुर व जोधपुर के बीच भजमेर के दक्षिण-पूर्व में ६ मील दूर गंगवाना नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण युद्ध = जून १७४१ को हुआ। मुठ्ठी भर राठौड़ों ने जयसिंह की विशाल सेना को भारी पराजय दी। जयसिंह की सधि करनी पड़ी। राठौड़ों को जयसिंह से सात परगने प्राप्त हुए जिनमें भजमेर भी एक था<sup>२७</sup>।

सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह भजमेर पर पुनः अधिकार स्थापित करने की बहुत उत्सुक थे। उन्होंने भजमेर पर आक्रमण की तैयारी भी की परन्तु जयपुर के रायमल व जोधपुर के पुरोहित जगन्नाथ की मध्यस्थता के कारण युद्ध टल गया<sup>२८</sup>। तब से लेकर सन् १७५६ तक भजमेर पर राठौड़ों का शासन रहा।

१८ वीं सदी का अंतिम मध्यवर्ती काल, जहां तक राजपूताने का प्रश्न है, मराठों के भारी सत्ता में घुसपैठ का समय था। राजपूतों के आंतरिक कलह से उन्हें इनके मामलों में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ जो अंत में इस क्षेत्र में उनके आधिपत्य के रूप में परिणत हुआ। राजपूतों के इन आन्तरिक संघर्षों में होकर और सिंधिया ने बढ़पा एक दूसरे के विरुद्ध पक्षों की अलग अलग सहायता की। मेड़ता के युद्ध में जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह की सेना और मराठों की मिलीजुली शक्ति के भागे जोधपुर के राजा विजय सिंह की पराजय ने एक तबे समय के लिए भजमेर का भाग्य निर्णय कर दिया। सन् १७५६ से लेकर १७६८ तक भजमेर मराठों व रामसिंह के आधिपत्य में रहा। रामसर, सरवा, भिनाय और मसूदा जयपुर नरेश रामसिंह के और जोधपुर मराठों के पास रहा। छोटी मोटी घटनाएँ इस बीच भजमेर को मराठा आधिपत्य से मुक्त करने के लिए हुई परन्तु सन् १७६१ तक भजमेर पर मराठों का आधिपत्य बना रहा। सन् १७६१ में मारवाड़ के भीमराज ने मराठा सूबेदार बनवरजय से भजमेर छीन कर अपने छोटे भाई सिधबी बनराज को वहाँ का

प्रशासन सौंप दिया था<sup>२२</sup>। परन्तु शीघ्र ही मारवाड़ के राजा विजयसिंह ने सरवा के ठाकुर सूरजमल (भजमेर दुर्ग के किलेदार) को आदेश दिया कि वे भजमेर मराठों को वापस सौंप दे। इस प्रकार भजमेर वापस मराठों को मिल गया। जनरल पैरो को भजमेर में व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सौंपा गया क्योंकि घेरे के दौरान शांति मंग हो चुकी थी<sup>२३</sup>। पूरे ६ वर्षों तक, अर्थात् सन् १८०० तक भजमेर मराठों और उनके सूबेदारों के हाथों असहनीय अत्याचार सहन करता रहा। विद्रोही मेरों का पूरी तरह से दमन किया गया और उनकी पुलिस चौकियों में सेवाएं ली गईं। जिन लोगों ने पिछली सज़ाई में जोधपुर का साथ दिया था उन पर भारी अर्थ बंड थोपा गया, कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें बंड की मात्रा लाख रुपये तक थी। यह राशि कठोरता से वसूल की गई और जो न चुका सके उनकी जागीरें खालसा कर ली गईं। इसके फलस्वरूप मराठों के विरुद्ध असंतोष की गहरी भाव धधकती रही जो कभी कभी ठिकानेदारों द्वारा मराठों के विरुद्ध हिंसक कारवाइयों के रूप में फूट पड़ती थी<sup>२४</sup>।

मराठा फौज में अनुशासन की बड़ी कमी थी। सन् १८०० में लकवा दादा ने मराठा शक्ति के विरुद्ध खुली बगावत की, इसके पूर्व वह मराठा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति था, अतएव यह आवश्यक समझा गया कि यथा शीघ्र उसे पंगु बना दिया जाय जिससे विद्रोह तीव्र रूप ग्रहण न कर सके। भजमेर लकवा दादा की "जाय-दाद" थी। जनरल पैरो को भजमेर पर आधिपत्य सौंपा गया। १४ नवम्बर, १८०० को पैरो को यह जानकारी दी गई कि लकवा मासवा भाग गया है। उसने मेजर बोरगुई को भजमेर दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा। जिनके अनुसार ३ दिसम्बर, १८०० को भजमेर दुर्ग पर घावा बोल दिया गया, यद्यपि मेजर ने उक्त आदेशों का बहादुरी से पालन करने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे पीछे धकेल दिया गया। उसने पूरे पांच माह तक जो जान लगाकर रात दिन एक कर दिया परन्तु भजमेर दुर्ग को हस्तगत नहीं कर सका। अन्त में वह रिश्वत के माध्यम से ८ मई, १८०१ को किले पर अधिकार पाने में सफल हुआ। पैरो भजमेर के सूबेदार बने और लो महोदय के जिम्मे भजमेर के प्रशासन की देख-रेख का काम सौंपा गया<sup>२५</sup>।

सन् १८०३ से १८१८ तक भजमेर का इतिहास मराठों और अंग्रेजों के बीच उत्तर भारत में आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। लार्ड वेलेजली के समय में अंग्रेजों और सिंधियों के बीच युद्ध छिड़ जाने पर मारवाड़ के राजा मानसिंह ने मराठों से भजमेर छोड़ कर तीन साल तक इसे अपने अधीन रखा था<sup>२६</sup>। बाद में जब अंग्रेजों और मराठों के बीच संधि हो गई तो भजमेर पुनः मराठों के हाथ में आ गया तथा १८१८ तक उनके पास रहा। सन् १८०५ में दोलत राव सिंधिया और अंग्रेज सरकार के मध्य संधि के बाद देश में केवल भरा-जकता व लूटपाट का बोलबाला था। इस संधि के बाद सिंधिया की फौजें

घोष वसूली में भ्रानाकानो करने वाले सरदारों को दवाने के नाम पर दिनरात सक्रिय हो चली थी। अतएव भ्रजमेर में इस सन्धि के बाद अस्तिरता एवं भ्रमुरक्षा की भावना कम होने के बजाय उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था<sup>९४</sup>।

२५ जून, १८१८ को ईस्ट इन्डिया कम्पनी और महाराजा धातीराह दोलतराव सिधिया के मध्य एक संधि हुई जिसके अनुसार भ्रजमेर भ्रमेजों को प्राप्त हुआ<sup>९५</sup>।

भ्रमेजों ने जब भ्रजमेर प्रांत का शासन भार सम्भाला तो यह भू-भाग घाट परगनों और ५३४ ग्रामों में विभक्त था तथा इसमें कुल योग्य १६ लाख पक्का बीघा भूमि थी। इस क्षेत्र के सभी जमींदार अधिकतर राज. राठौर थे, केवल कुछ ही पठान, जाट, मेर और चीना थे। मेर और चीता लोग जिते के अन्तिम दौर पर आबाद थे। केवल इन दो जातियों के जमींदारों को छोड़कर बापू सभी शांतिप्रिय और परिश्रमी थे<sup>९६</sup>।

भ्रजमेर में मराठों के एक सदी के कुशासन के फलस्वरूप जनता में भय की भावना व्याप्त हो गई थी और अधिकांश जनता यहां से दूसरे स्थानों पर चली गई थी। भ्रजमेर पर भ्रमेजों के आधिपत्य के साथ ही वे लोग जो दूसरे प्रदेशों में जा बसे थे, अपने घर पुनः लौटने लगे। लोगों में विश्वास का प्रादुर्भाव हुआ और खेतों में फसलें फिर से लहलहाने लगीं। सातिया और बापू सिधिया ने जो हानिप्रद व भद्र-दक्षिणापूर्ण तरीका अपनाया उसके कारण मराठों को कमी भी ३,४५,७४० रुपये से अधिक की राशि का लगान या ३१,००० हजार की बुंगी की मिलाकर केवल ३७६,७४० रुपये से अधिक की राशि प्राप्त नहीं हुई<sup>९७</sup>।

घाट परगनों में से केवल एक परगना खालसा था। इसमें से भी प्राचा भू-भाग इस्तमरार या जागीर भूमि में था<sup>९८</sup>। इस इस्तमरार भूमि पर जिनका अधिकार था वह किसी पट्टे से या कानूनी हक के अन्तर्गत नहीं था। केवल दीर्घ-कालीन बन्ना ही उन्हें इस जमीन का हकदार बनाये हुआ था। इन परिस्थितियों में भ्रमेजों की व्यवस्था के अन्तर्गत उस समय केरुडी का कस्बा और भ्रजमेर परगने के केवल १०५ ग्राम भ्रमेजों के हाथ लगे। इन क्षेत्रों पर भ्रमेजों के आधिपत्य के बाद ही येनी में इतनी वृद्धि हुई कि केवल आधी फसल ही बापू सिधिया के उस समय के मराठा भूमि कर व अन्य करों की सम्मिलित राशि से अधिक थी<sup>९९</sup>। मराठों के समय खालसा और इस्तमरार भूमि से लगान अव्यवस्थित एवं मनमाने ढंग से वसूल किया जाता था<sup>१००</sup>।

मराठों की व्यवस्था सालब की प्रवृत्ति पर आधारित थी। जब कभी उन्हें धन की आवश्यकता होती वे ग्रामों में जाते और एक न एक बहाने से पैसा बटोर लीते। सन् १८०५ तक इस प्रदेश ने कमी दोष सार्थ (सैनिक व्यय के लिए कर) का नाम

भी नहीं सुना था। सन् १८०५ में बालाराम ने भवानक भिनाय पहुंच कर वहाँ के ठाकुरों से अपनी हैसियत के अनुसार भेंट देने को कहा। उन्हें बाध्य किया गया कि वे ६०,००० रुपये की राशि प्रदान करें। परन्तु बालाराम एक गार्ड भी वसूल करने में असफल रहे। भिनाय के राजा ने इस बात पर कि बालाराम उसके जामा में से एक चौथाई भाग कर दे तो फौज खर्च देना स्वीकार किया।<sup>७१</sup>

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मराठों को जब भी धन की आवश्यकता होती राजस्व के नियमों की परवाह किये बिना ही वसूली के लिए चल पड़ते थे। इस तरह बार-बार धन की माग बने रहने से क्षेत्र का सम्पूर्ण राजस्व प्रशासन अव्यवस्थित हो गया था। उस पर फौज खर्च और घोषा गया जिससे भूराजस्व में बड़ी भारी कमी आ गई थी। बालाराम ने जालीया से फौज खर्च के नाम पर ३५,००० रुपये का कर भ्रजमेर शहरपनाह की मरम्मत व खाई की खुदाई के नाम पर वसूल किया। उसने फौज खर्च के अलावा मुसद्दी खर्च भी वसूल किया। मसूदा से ३५,०००, देवलिया से १५,००० व भिलाय से ३५,००० रुपये फौज खर्च के नाम पर वसूल किए गए। इस तरह के वित्तीय दंड बार दिनों दिन बढ़ते जाते थे इस कारण सन् १८१० में जब तातिया भ्रजमेर का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने एक साल की रकम की माग की परन्तु वह केवल ३५,००० रुपये की राशि ही बटोर पाया था। यह माग उसने इस आधार पर की कि उसे भ्रजमेर की सूबेदारी पाने के लिए एक भारी रकम रिश्वत में देनी पड़ी थी। अगर कोई इस्तमरारदार उनकी माग पूरी नहीं करता तो उसके ठिकाने पर आक्रमण किया जाता था। सन् १८१५ में बड़ली के ठाकुर द्वारा भुगतान से इंकार करने के कारण उनके ठिकाने पर आक्रमण किया गया। ठाकुर अपने कतिपय सगे सम्बन्धियों सहित मारा गया और उसका ठिकाना लूट लिया गया।<sup>७२</sup> मराठा प्रशासन वास्तव में सगठित सूट था जिसमें कतिपय अनुचित कर वसूली से दबकर<sup>७३</sup> गरीब किसान दरिद्रता की चरम सीमा तक पहुंच गया था।<sup>७४</sup>

भ्रजमेर जिला भ्रजमेर और केकडी को मिलाकर बनाया गया था। जिन्हें किशनगड पृथक् करता था। जागीर इस्तमरार व भोग में विभाजित होने के कारण वहाँ सालसा भयवा सरकारी राजस्व भूमि बहुत ही कम थी। जागीर दान तथा बरूशीश के अन्तर्गत २५ ग्राम थे तथा उसका वार्षिक भू-राजस्व एक लाख के लगभग था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जागीर स्वाबा साहिब की दरगाह की थी, जिसमें १४ गांव थे व उनसे २६,६३० ६० की भू-राजस्व आय होती थी। अन्य छोटी जागीरें कुछ व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों से सम्बद्ध थीं जो विविष्ट व्यक्ति, देवस्थान तथा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उमरावों को भेंट में दी हुई थीं।<sup>७५</sup>

इस्तमरार जागीरें ६६ थीं जिनमें २४० ग्राम थे और इनका क्षेत्रफल



८००.३ वर्गमील था। इनकी वार्षिक आय २,५६,१५८ रुपये थी तथा ये जागीरें १,१४,१२६ रुपये का सालाना राजस्व दिया करती थी। ये इस्तमरारदार अपनी जागीरों को वंश परम्परा से इस शर्त पर कि वे सरकार को नियमित बधा हुआ राजस्व देते रहेंगे, ग्रहण किए हुए थे। इस राजस्व में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। प्रारम्भ में इन जागीरों के उपलक्ष्य में सैनिक सेवायें प्रदान की जाती थीं जो कालांतर में सेवा के स्थान पर धीरे-धीरे धनराशि में परिवर्तित हो गई थी। मराठों ने भजमेर पर सन् १७८६ में पुनः आधिपत्य करने के बाद ही इन सब पर नगदी में राजस्व कूँतकर इन्हें तालुकेदारों के हक प्रदान किये। अब उनका उत्तरदायित्व केवल निर्धारित धनराशि देने तक सीमित रह गया था।<sup>७१</sup>

इस तरह भयंशों को मराठों से वह भू-भाग विरासत में मिला जो सभी वास्तविक भयंशों में मराठा झूठ खसोट के कारण प्रायः नष्ट हो चला था। इस क्षेत्र के निवासी मराठा कर उगाहकों के हाथों कंगाल हो चुके थे। लोगों ने अपनी कृषि को विकसित करने के प्रयास छोड़ दिये थे क्योंकि उन्हें यह भय था कि विकास के साथ उन पर और अधिक भार आ पड़ेगा। भजमेर वास्तव में मराठा आधिपत्य के अन्तर्गत कष्टों और दखिना का क्षेत्र बन चला था।

## अध्याय १

१. सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्ट्रिक्टिव (१९११) पृ० ७१ मेरवाड़ा के कुछ विशिष्ट भू-भागों का मारवाड़ और मेवाड़ में हस्तांतरण के पश्चात् जनसंख्या और क्षेत्रफल घट कर ५०६६६ और २३६७ वर्ग भील क्षेत्र रह गया। (सी. सी. वाटसन, भजमेर-मेरवाड़ा गजेटियर्स पृ० १)
२. सी. सी. वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, खंड १ ए, भजमेर-मेरवाड़ा (१९०४)
३. चॉर्टन, गजेटियर्स ऑफ इण्डिया (१८५०) पृ० १८ सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्ट्रिक्टिव (१९११) पृ० १८ सी. सी. वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स खंड १-ए, भजमेर-मेरवाड़ा (१९०४) पृ० २।
४. सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्ट्रिक्टिव (१९११) पृ १८।
५. उपरोक्त।

६. जे. ब्रिज, तारीख ए-फिरस्ता, १ (१६११) पृ० ७ और = (ऐसे किसी संघ का उत्थी, इम्न, उल अमर व निजामुद्दीन जैसे पूर्ववर्ती तथा प्रामाणिक इतिहासकारों ने उल्लेख नहीं किया, यतएव फिरस्ता का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।
७. जयानक, पृथ्वीराज विजय, (६), १-२७ (गौरीशंकर हीराचन्द घोषा एवं गुलेरी संस्करण, अजमेर १९४१) चौहान प्रशस्ति, की पक्ति १५ में भी कहा गया है 'अजयमेरु की भूमि सुकों के रक्तपात से इतनी माल हो गई थी कि मानो उसने अपने स्वामी की विजय के उल्लास में गहरा खाल बरत घाटण कर लिया हो।'
८. जयानक, पृथ्वीराज विजय, (६), (पृ. १५१, डा. घोषा संस्करण, १९४१)
९. एपिग्राफिया इंडिका, (२६), पृ० १०५ खंड २०।
१०. बीजोलिया स्मारक खंड ११।
११. ठक्कर फेरू ने दिल्ली के तोमरों के दो सिक्के मदन पलाहे और धनंज पलाहे का उल्लेख किया है।
१२. उपरोक्त
१३. उपरोक्त लेखक की दिल्ली शिवालिक स्मारक ५, १२२०।
१४. जेम्स टॉड, एनस एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, खंड १ (प्रो. यू. पी. १९२०) पृ० ६०६।
१५. आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वायिक (२) पृ० २६३।
१६. उपरोक्त पृ० २६१।
१७. सारदा, स्पीचेज़ एण्ड राइटिंग्स (१९३५) पृ० २५५।
१८. रेवर्टी, लबाकाते-नासिरी (१८८०)। पृ० ४६८, जे० ब्रिज, तारीख-ए-फिरस्ता, १ (१६११) पृ० १७७।
१९. सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्ट्रिक्टिव (१९४१) पृ० ३४, ३५।
२०. उपरोक्त, पृ० ३५।
२१. मुस्लिम इतिहासज्ञों का कहना है कि सन् १२०६ में कुतुबुद्दीन की मृत्यु पर राजपूतों ने गढ़ बीटली पर आक्रमण किया और वहां की मुस्लिम टुकड़ी को तलवार के घाट उतार दिया और संयद हसन खगसवार इस मौके पर शहीद हुए। उक्त घटना किसी भी प्रामाणिक

इतिहास में उपलब्ध नहीं होती (सारदा, भजमेर-हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव १९४१-पृ० १४८) ।

२२. घनहनवाड़ा अन्हिलवाड़ा पट्टन के नाम से जाना जाता है । गुजरात की अंतिम एवं प्रख्यात हिन्दू राजधानी । चावहीं ने ७४६ ई० में इसकी स्थापना की थी । (बेले हिस्ट्री ऑफ गुजरात,—१९३८-४) ।
२३. सारदा, भजमेर, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव (१९४१) पृ० १४९ ।
२४. तारागढ़ का दुर्ग तारागढ़ पर्वत पर स्थित है । यह पर्वत घरातल से ११०० फीट ऊँचा है । ये चट्टानें आनासागर के पूर्व की पहाड़ियों तक फैली हैं । किवदन्ती के अनुसार, तारागढ़ दुर्ग राजा भजय ने बनवाया था । उनके द्वारा निर्मित यह दुर्ग "गढ़ बीटसी" कहा जाता था । सी०सी० वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, भजमेर मेरवाड़ा (१९०४) खंड १ पृ० ५ और ६ ।
२५. सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव (१९४१) पृ० १५६ ।
२६. टॉड-एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, खण्ड (१२) (मॉन्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (१९२०) पृ० १६ ।
२७. राव राममल मारवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे । उनका जन्म २८ अप्रैल, १३६२ में हुआ था ।
२८. महमूद खिलजी खान जहाँ खिलजी का पुत्र था । उसने १५ मई, १४३६ में मालवा की गढ़ी पर अधिकार स्थापित कर लिया था । २६ की सम्बल ८३६ हिजरी । उसने ३४ चांद वर्षों तक राज्य किया, मृत्यु २७ मई १४६६, ६ वीं जी-का दा ८७३ हिजरी, आयु ६८ वर्ष (बीलु, औरि-मन्टल बायोग्राफिकल डिक्शनरी १८८१-पृ० १६४) ।
२९. ब्रिज, तारीख ए करिश्ता खंड (२) (१९११-पृ० २२२) ।
३०. पृथ्वीराज मेवाड़ के राजा राममल का ज्येष्ठ पुत्र था । जब ज्योति-पियो ने यह भविष्यवाणी की कि राममल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र सांगा राजगढ़ी पर बैठेगा तब वह गोडवाड़ चला आया । नादलाई प्रसन्न के अनुसार राजा राममल के जीवन कार्य में पृथ्वीराज का शासन गोडवाड़ में था (गहलोत, राजपूताना का इतिहास—१९३७-पृ० २१५) ।
३१. टॉड-एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान (मॉन्स० यूनिवर्सिटी प्रेस १९२०) खण्ड (२) पृ० ३७६-४ ।
३२. बहादुरशाह गुजरात के मुखपूरशाह दिलीय का दूसरा पुत्र था । अय्ये

पिता की मृत्यु के समय वह अनुपस्थित था तथा बीनपुर में था, परन्तु जब उसका भाई महमूदशाह अपने बड़े भाई सिकन्दरशाह की हत्या कर गुजरात की गद्दी पर बैठा तो वह गुजरात गोट भाया और बीस घण्टा, १५२६ को महमूद से गुजरात का राज्य छीनकर स्वयं गद्दी पर बैठा। उसने २६ फरवरी १५३१ में मालवा विजय किया और वहाँ के शासक सुल्तान महमूद द्वितीय को पकड़ कर बन्दी बना बांगानेर भेज दिया। (बीन, ओरियण्टल बॉम्बेयाफिकल डिक्शनरी १८८१-पृ० ६४)।

१३. बायले-गुजरात, पृ० ३७१।

१४. बीरमदेव राव बाघा के पुत्र थे। यद्यपि उनके दादा ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मारवाड़ के सरदारों ने इनके भाई गांगा की राजगद्दी पर बिठा दिया। बीरमदेव को सौराष्ट्र का परगना जागीर में मिला। उसने समथेर-उल-मुल्क को हटाकर भजमेर पर अधिकार कर लिया। (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास) खण्ड १ १६३८-पृ० ११८)।

१५. मुहम्मद नेणसी ने उल्लेख किया है कि बीरमदेव ने भजमेर काकिला परमारों से छीना जो सत्य नहीं है। (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास-खण्ड १-१६३८-पृ० ११८)।

१६. राव मालदेव राजपूतों के राठीड़ वंश का मारवाड़ का शासक था और जोधा का जिसने ओडपुर बसाया वगैरह था। सन् १५३२ में उसने राजपूताना में अत्यन्त प्रसिद्धि एवं महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। फिरक्ता के अनुसार वह हिन्दुस्तान के प्रमुख राजाओं में से था। (बीन, ओरियण्टल बॉम्बेयाफिकल डिक्शनरी, १८८१-पृ० १६६)।

१७. रेऊ-मारवाड़ का इतिहास-खण्ड १ (१६११) पृ० ११६।

१८. सिंग, तारीख ए फिरक्ता, खण्ड १ (१६११) पृ० २२७२८ लफीखान मुन्तजाबुल्लुबाब, खण्ड-१-पृ० १००-१, रेऊ, मारवाड़ का इतिहास खण्ड-१ (१६३८) पृ० १३१।

१९. इस्लाम शाह मूर जेरशाह मूर का पुत्र था।

२०. हाजीखान पठान नागौर का शासक था। वह जेरशाह का गुलाम था।

२१. इलियट-हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खण्ड ६ (१८६६-६७) पृ० २२।

२२. सी० सी० वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, भजमेर-मारवाड़ खण्ड १ ए (१९०४) पृ० ११।

४३. देराई का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच ११, १२ और १३ मार्च १६६५ को लड़ा गया। इसने औरंगजेब का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। देराई भजमेर से तीन मील दूर स्थित है। (सारदा भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव १९११-पृ० १६२-६३)।
४४. सी० सी० वाटसन, राजपूताना मजेस्टिक्स, खण्ड (२) (१९०४) पृ० १७। अकबर औरंगजेब का सबसे छोटा लड़का था। उसका जन्म १० सितम्बर, १६३७ को हुआ। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और जून १६८१ में मराठा सरदार शंभू जी सेना मिला। बाद में उसने मुगल दरबार छोड़ दिया और फारस चला गया जहाँ १७०६ में उसकी मृत्यु हुई। (बील, ओरियण्टल बायोग्राफिकल डिक्शनरी-१८८१-पृ० ३१)।
४५. एडवर्ड यॉमस, कोनीकल्स ऑफ दी पठान किंग्स ऑफ देहली (१८७१)। पृ० ४३३-३४।
४६. ब्योचमेन, भार्द्वाज-ए-अकबरी।
४७. फर्लैंससियर दिल्ली का बादशाह था। उसका जन्म १८ जुलाई १६८७ को हुआ। वह बहादुरशाह द्वितीय का द्वितीय पुत्र था। और औरंगजेब का पौत्र था। शुक्रवार ६ जनवरी १७१३ को वह राजगद्दी पर आसीन हुआ। १६ मई, १७१६ को उसकी हत्या कर दी गई। (बील, ओरियण्टल बायोग्राफिकल डिक्शनरी-१८८१-पृ० ८८)।
४८. सैय्यद बघ्नु दिल्ली के राज निर्माताओं के नाम से प्रख्यात हैं। ये लोग सैय्यद अब्दुल और सैय्यद हुसैन घली खान थे। इन दोनों ने मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों में विशेषकर फर्लैंससियर और मुहम्मद शाह के शासन काल में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की।
४९. टॉड-एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान (भाबत० यूनि० प्रेस १९२०) खंड II पृ० ८८।
५०. उपरोक्त, पृ० ८८।
५१. इरविन, नेटर मुपल्स, खंड II (१९२२) पृ० १०६-१०, संस्कृत-मुसलरीन, पृ० ४३४, अजीनोदय, सर्ग ३० श्लोक ६ से ११। रेऊ-भारवाड़ का इतिहास (१९३८) खण्ड-१ पृ० ३२२ II
५२. जब अजीनमिह को यह पता चला कि नुसरतखान खान को उसके विरुद्ध भेजा गया है उसने अपने पुत्र अमरमिह को नारनोल पर भेजा और दिल्ली तथा पानवा के शासक लूट के लिए भेजा।

अभयसिंह ने, १२००० सांढनी सवारों के साथ नारनौल पर घावा बोला वहाँ के फौजदार वयाजीद खान मेवाती को हराया, नारनौल को लूट लिया और अलवर, तिजारा और शाहजहापुर को गम्भीर क्षति पहुँचाई। वह मराय भनीवर्दी खान तक जा पहुँचा जो दिल्ली के ६ मील के घेरे में थी। (रेऊ, मारवाड़ का इतिहास-१६३८-खंड १ पृ० ३२२)।

५३. अजीतोदय, सर्ग ३०, श्लोक ५३ से ६५। राजरूपक में जयसिंह की चर्चा नहीं है, पृ० २३६।

टॉड-एनल्स एण्ड ऐन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान (मॉक्स० यूनी० प्रेस) खंड II (१६२०) पृ० १०२८।

५४. सरबुगन्द खान जिसका खिनाब नयाब मुखरिज अल-मुल्क या फर्कल-सियर के समय में पटना का हाकिम था। उसे सन् १७१८ में वापस मुगल दरबार में बुला लिया गया। मुहम्मदशाह के समय में सन् १७२४ में उसे गुजरात का हाकिम बनाया गया था। परन्तु सन् १७३० में उसे इस पद से इसलिए हटा दिया गया कि उसने मराठों को चीय देना मंजूर किया था। (बील, ओरियंटल बॉयोग्राफिकल डिक्शनरी १८८१-पृ० २३६)।

५५. रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, खंड १ (१६३८) पृ० ३३६, सारदा अजमेर, पृ० १६७।

५६. चूरामन महत्वाकांक्षी जाट नेता था, उसने शाहशाह आलमगीर के अन्तिम दखन अभियान के समय उसका मान असबाब लूट लूट कर घन बटोर लिया और उससे भरतपुर का किला बनवाया। चूरामन जाटों का नेता बन गया। नवम्बर, १७२० में शहशाह मुहम्मद शाह और कुतबुलमुल्क सैय्यद अब्दुल खान की सेनाओं के बीच युद्ध में मारा गया। (बील, ओरियंटल बॉयोग्राफिकल डिक्शनरी १८८१-पृ० ७७)।

५७. टॉड-एनल्स एण्ड ऐन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान खण्ड २ (१६२०)। पृ० १०५०-५१। रेऊ मारवाड़ का इतिहास, खण्ड १ (१६३८) पृ० ३५२-५४।

५८. रेऊ मारवाड़ का इतिहास, खण्ड १ (१६३८) पृ० ३५५५-पुरोहित जगू प्रसिद्ध पुरोहित जगन्नाथ थे, इनके प्रभाव से आनन्दसिंह को ईडर की राजगद्दी विक्रम सन् १७८७ फाल्गुन कृष्ण गप्तमी (४ मार्च, १७३१)।

६९. सारदा, अजमेर-हिस्टोरिकल एण्ड डिस्ट्रिक्टिव (१९११) पृ० १७२ ।
६०. उपरोक्त पृ० १७२-७३ । टॉड-एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान (१९२०) खण्ड २ पृ० १३६ ।
६१. सारदा, अजमेर-हिस्टोरिकल एण्ड डिस्ट्रिक्टिव (१९११) पृ० १७३ ।
६२. उपरोक्त पृ० १७४-७५ ।
६३. उपरोक्त, पृ० १७५ ।
६४. सरकार, सिधियाज अफेयर्स (१९५१) पृ० ७ ।
६५. एचीसन, ट्रीटीज एण्ड एग्जामेन्ट्स (१९३३) खण्ड ५ सवि क्रमांक ८ पृष्ठ ४०९, ४१०-११ ।
६६. एफ बिह्लर सुपरिन्टेंडेंट अजमेर का मेजर जन सर डेविड ऑक्टर-लोनी को पत्र, दिनांक २७-९-१८१८ । (रा० रा० मु० मण्डल) ।
६७. उपरोक्त ।
६८. केविडिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ।
६९. एफ बिह्लर का ऑक्टरलोनी को पत्र दिनांक २७-९-१८१८, (रा० रा० मु० मण्डल) ।

## राजस्व वसूली की विगतों निम्नांकित हैं

क्रमिक	मराठा हाकिम का नाम	वर्ष	वसूल राशि	विशेष
१.	सिवाजी याता	१७६१	१,२२,६६३	इससे ६७६६ का नजराना भी सम्मिलित फौज एवं लागू नहीं किया गया।
२.	" "	१७६२	२,०४,६६६	सं० ६६५१ का नजराना शामिल, फौज एवं लागू नहीं किया गया।
३.	पैरो	१८०१	२,००,६६२	न तो नजराना और न फौज का खर्च लागू किया गया।
		१८०२	२,०२,३६५	" "
		१८०३	२,०२,६७०	" "
४.	बालाराव	१८०४-७	२,०२,०६६	न तो नजराना और न फौज खर्च वसूलक लागू किया गया।
५.	सांतिा सिधिया	१८१०-१५	२,२६,४०५	नजराना, फौज खर्च लागू।
६.	बापू सिधिया	१८१६	२,४७,२६६	भू-राजस्व (ग्रसेसमेन्ट)
		१८१७	७३,०४२	फौज खर्च
७.	"	१८१७	२,५४,४३३	भू-राजस्व, फौज खर्च
			७८,२६६	
८.	"	१८१८	२,३४,७०५	भू-राजस्व, फौज खर्च
			१,२२,०६०	



७०.

विल्डर का पत्र, दिनांक १८-२-१८२० । (रा. रा. पु. मण्डल) ।

७१.

माक्कटन महुदय का पत्र, दिनांक ३०-७-१८४० । (रा. रा. पु. मण्डल) ।

७२.

सेप्टीनेन्ट कर्नल सदरलैंड ए. जे. जी. का तत्कालीन भारत सचिव जेम्स वाम्पसन को पत्र, दिनांक ७-२-१८४१ । (रा. रा. पु. मण्डल) ।

७३.

विल्डर द्वारा लिखे गये भाक्टरलोनी को दिनांक २७-६-१८१६ का पत्र जिसमें मराठों द्वारा उगाहे जाने वाले कर लोगों का विवरण निम्न है:—

क्रमिक प्रोसेसमेंट

दर प्रतिशत

कर का हिसाब

१. फौज सर्वे

५ से ७५

ग्रामों की रक्षा के लिए नियुक्त सेना पर व्यय के कारण ।

२. रटेलदाब

२ से १२

यह मुकदमों और शाब मुखियाओं पर उनके द्वारा दूसरों की अपेक्षा ज्यादा हिस्सा खसूल करने पर लागू कर ।

३. भूमिदाब

५ से २०

उस सम्पूर्ण भूमि पर जो ठिकानेदारों के पास प्राचीन काल से खली झारही भी और कर मुक्त थी । यह कर इन भूमियों पर लागू किया गया ।

४. पी शाब

१ से ३

बुकिं ग्रामों को फौज के लिए भी धाजार भाब से कहीं अधिक सस्ता देना पड़ता था अतएव उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए निश्चित राशि पर देना स्वीकार किया तब से बढ़ कर चलता रहा ।

का का हवाला

प्रतिपात

धर्मेसमेष्ट

कर्मक

५. भेंट सरकार १ से ४ द०  
 ६. तहरीर १ से ७ द०  
 ७. फौजदार १ से ४ द०  
 ८. मुरोते फौजदार १ से ४ द०  
 ९. गणेश चौक प्रति गाँव १ रुपया  
 १०. भेंट दणहरा प्रत्येक गाँव से २ से ४ द०  
 ११. उबवाकन प्रति गाँव से ५ से २० द०  
 १२. भेंट होली १ से ५ द० प्रति गाँव  
 १३. बरसा १ से ५ द० प्रति गाँव  
 १४. भेंट जमान्दी २ से ४ द०
- प्रत्येक गाँव से हाकिम को १५ रुपया प्रतिवर्ष नजराना ।  
 राजस्व खाता लिखने वालों की सेवाओं पर व्यय कर ।  
 खजांची का वेतन कर ।  
 खजांची की वेतन सम्बन्धी फीस ।  
 गलेश चतुर्थी पर भेंट ।  
 दणहरे के प्रवसर पर फसल कटाई की पहली किस्त के समय दणहरे की भेंट ।  
 सभी धरागाह भूमि पर सरकार का भागिपत्य है और जो जमीन कृषि योग्य नहीं मानी गई है उस पर पशु चराने का कर ।  
 फसल कटाई की पहली किस्त के समय होली की भेंट ।  
 प्रत्येक गाँव के मूल्य मवेशियों की खातों की निरिक्त संख्या पर सरकार का हक मानकर यह कर वसूल किया जाता था ।  
 उन गाँवों में जहाँ फसल का राजस्व जिनसे मे चुकाया जाता था वहाँ हिसाब लिखने के लिए मुसदियों के वेतन के लिए नजराना ।

क्रमांक	प्रोपोजेन्ट	वार प्रतिशत	कर का हवाला
१५.	पाचोतरा	२ से ५ रु०	यह प्रतिशत जिनमें से राजस्व चुकाने पर धरूत हो जाता था ।
१६.	साव्यबा	२ से ५ रु०	सूबे के हाकिम की पोशाक खर्च ।
१७.	वैमापरा	१ से २ रु०	जमीन नापने पर ।
		७४.	भारत सचिव श्री योमसुतन द्वारा भांगरा से गवर्नर को लिखे पत्र पर श्री सदरसेंट की दिपण्डी, संदर्भ—भजमेर इन्सपेक्टरवार, भांगरा, मई १८४१ । (रा० रा० पु० मण्डल) ।
		७५.	लेफ्टिनेन्ट कर्नल सदरसेंट द्वारा जेम्स थॉमसन सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक ७-२-१८४१ ।
		७६.	केनॉडिस रिपोर्ट दिनांक ११ जुलाई, १८२६ ।

## मेरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुदृढ़ीकरण

### मेरवाड़ा का पूर्व इतिहास

जून, १८१८ में भजमेर पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद अंग्रेजों का ध्यान सबसे पहले मेरो की तरफ आकर्षित हुआ।<sup>१</sup> अंग्रेजों के आगमन के पूर्व कोई भी शक्ति मेरो को परास्त नहीं कर पाई थी। अपनी लूट मार की प्रवृत्तियों तथा पाशविक व्यवहारों के कारण निकटवर्ती पड़ोसी रियासतों में मेर कुख्यात थे। उनका घातक एवं दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि अब भजमेर पर भी उनके घावे होने लगे थे।<sup>२</sup> मेरों की उत्पत्ति पृथ्वीराज चौहान से बताई जाती है। उसके पुत्र गौड़ साखन ने बुंदी की एक योग्या जाति की महिला से विवाह किया था और उनके बसपर मेर कहलाये। इस तरह के मिश्रित विवाहों एवं सम्बन्धों के कारण मेर आज भी बरार, चौता, मेरात आदि कई उपजातियों (खांपों) में विभाजित हैं।<sup>३</sup> कर्नल टॉड के अनुसार पन्द्रहवीं शताब्दी में इनमें से अधिकांश ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया था। भजमेर के तत्कालीन हाकिम ने बुध मेर को मूलमान बनाकर उसका नया नाम दाऊदखान रखा था। सामान्यतः मेरवाड़ा के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को मेर कहा जाता है।<sup>४</sup> १६०१ में मेरों की कुल जनसंख्या ६२,४१२ थी।<sup>५</sup>

मेर भारतीय धर्म नस्ल के थे। इनका कद लम्बा, शरीर हृष्ट-पुष्ट, गोल मुखाकृति तथा उभरे हुए नाकनका होते थे। ये भारवाड़ी बोली बोलते थे जो कि

अजमेर मेरवाड़ा के जन-साधारण की बोली से मेल खाती थी और बहुत कम भिन्नता लिए हुए थी। यद्यपि ये लोग मुख्यतः मासाहारी थे परन्तु मक्का की राबड़ी और घाट इनका प्रमुख आहार था। ये लोग ज्वार के आटे से बने रोटले प्याज के साथ विशेष रुचि से खाते थे। घूँघ्रपान और मद्यपान इनमें खूब प्रचलित था।<sup>१</sup> मेर लोग गावों में भोंपड़ियाँ बना कर रहा करते थे। इन भोंपड़ियों की छतें खपरैलों की होती थी। पुरुष का पहनावा पोतिया बकलानी लंगोटी तथा जूतियाँ थीं। मेर महिलाएँ रंगीन ओढ़नी, कावली और छोटी या चाधरा पहना करती थी।<sup>२</sup>

अंग्रेजों द्वारा मेरवाड़ा क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के पूर्व मेरों की आजीविका कृषि पर निर्भर होकर लूट-खसोट पर निर्भर थी। जैसे यह जाति अपने आदिम काल से ही कृषि जीवी थी।<sup>३</sup> मेर सामान्यतया विश्वामपात्र, सहृदय और उदार होता था। वह अपनी कौम, कबीला, परिवार तथा घर वालों को प्यार करता था।<sup>४</sup> मेर जितना जल्दी आवेश में आता था उतनी जल्दी ही सात्वता की दो बातों से शांत भी हो जाता था।<sup>५</sup> जोधाविष्ट मेर को मरने-मारने में देर भी नहीं लगती थी।

मेरों का पेशा लूट-पाट होने हुए भी उनमें कई चारित्रिक विशेषताएँ भी थीं। ये लोग कभी आहूण, स्त्री, जोगी या फकीर पर हाथ नहीं उठाते थे। अपने दाल-बच्चों व पत्नी को हृदय से प्रेम करते थे। पत्नी के अपमान के प्रश्न को लेकर ये लोग मरने-मारने पर उतार हो जाते थे। साधारण सी उकसाहट ही एक मेर को पागल बनाने के लिए पर्याप्त होती थी। मेर के हाथ में दाल तलवार होने पर वह वेगड़क होकर काल से भी दो-दो हाथ करने को आमदा हो जाता था। यद्यपि इनमें मद्यपान तथा किडनलर्बी जैसे दुर्व्यसन अवश्य थे, तथापि इनका सामान्य चरित्र ऊँचा था। स्वभावतः मेर दालसी और सहायपूर्ण मनोवृत्ति के होते थे।<sup>६</sup>

अजमेर के दक्षिणी भू-भाग का पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा, मेरों की मातृभूमि थी। यह क्षेत्र ६४ मील लम्बा तथा ६ से लेकर १२ मील तक चौड़ा था। आदिम युग में ये लोग वनों में विचरण करते और शिकार द्वारा भरण-पोषण करते थे। इस आदिम अवस्था में न तो इन्हें खेतीबाड़ी का ही ज्ञान था और न वे कपड़ों का उपयोग ही जानते थे। इस पर्वतीय क्षेत्र में घने वन फैले हुए थे व पथरीली भूमि होने के कारण यहाँ कृषि संभव नहीं थी। यह क्षेत्र उन समाज विरोधी तत्वों के लिए सुरक्षित शरणस्थली था जो आसपास के क्षेत्रों में लूट-मार कर यहाँ छिप जाया करते थे। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कानून व दंड से बचने के लिए अपराधी यहाँ प्रायः शरण लिया करते थे।<sup>७</sup>

अतीत में कई बार इन मेरों को कुचलने के लिए सैनिक अभियान भी किये गए थे। अठ्ठारहवीं सदी के तीसरे दशक में जयपुर रियासत के ठाकुर देवीसिंह<sup>१२</sup> ने जयपुर नरेश के कोष से आग्राह्य होकर इस क्षेत्र में मेरों के यहाँ शरण ली

थी।<sup>१३</sup> जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने मेरों से इस व्यक्ति को लौटाने की मांग का परन्तु उन्होंने यह अनुरोध ठुकरा दिया। फनस्वरूप सवाई जयसिंह ने मेरों पर चढ़ाई कर उनके गाँवों और गढ़ों को तबाह कर दिया था। लगभग एक करोड़ रुपये इस सैनिक अभियान पर जयपुर द्वारा व्यय किये गए थे परन्तु मेरों को दबाने में ये सभी प्रयत्न निष्फल रहे। सन् १७५४ में उदयपुर के महाराणा ने भी मेरों पर आक्रमण किया परन्तु उनको भी सफलता नहीं मिली।<sup>१४</sup> इसी प्रकार जोधपुर के बिजयसिंह को भी सन् १७८८ में मेरों ने खदेड़ दिया था। सन् १७९० में कटालिया के ठाकुर ने भायली पर आक्रमण किया परन्तु उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े और मेरों ने उसके डेरे को लूट लिया।<sup>१५</sup> सन् १८०० में अजमेर के मराठा सूबेदार ने भी मेरों को दबाने का प्रयत्न किया था परन्तु सफलता नहीं मिली।<sup>१६</sup> सन् १८०७ में साठ हजार सैनिकों ने मेरों पर आक्रमण किया परन्तु वे भी इन्हें दबाने में सफल नहीं हो सके। सन् १८१० में मेरों ने टोंक के अमीर मोहम्मद शाहखान और राजा बहादुर को अपने पहाड़ी क्षेत्र से भगा दिया था। सन् १८१६ में इन्होंने उदयपुर के राणा को एक बार फिर बुरी तरह से हराया था।<sup>१७</sup> इस क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने-हेतु अंग्रेजों के लिए इन बिद्रोही मेरों का दमन करना आवश्यक हो गया था।

मेरवाड़ा क्षेत्र से होकर कई ऐसे मार्ग गुजरते थे जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे, इसलिए जबतक इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं की जाती, तबतक व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था।<sup>१८</sup>

### अंग्रेजी आधिपत्य

अजमेर के प्रथम अंग्रेज सुपरिटेण्डेंट बिल्डर ने मेरों को समझा बुझाकर शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया था। उसने भाक,<sup>२०</sup> श्यामगढ़<sup>२१</sup> और सूलवा<sup>२२</sup> में रहने वाले मेरों से समझौता कर लिया था। यद्यपि इन प्रयासों के फलस्वरूप क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं में कुछ कमी अवश्य हुई तथापि स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो सका और मेरों ने अपने वादों को निभाने में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई।<sup>२३</sup>

मेरों पर अभियान करने से पूर्व अंग्रेजों ने सर्वप्रथम स्थानीय सूचनाओं एवं जानकारी का संग्रह किया। मार्च १८१६ में इन्होंने नसीराबाद से तीन स्थानीय पैदल रेजिमेंट, एक घुड़सवार दस्ता और हाथियों पर हल्की तोपों में मेजर लोवरी के नेतृत्व में मेरों के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारम्भ किया। सेना को तीन भागों में विभक्त किया गया था। एक ने सूलवा पर आक्रमण किया, शेष दो ने अलग-अलग दिशाओं व निम्न-निम्न मार्गों से भाक पर हमला किया। यद्यपि इस सेना की प्रत्येक टुकड़ी को कड़े प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ा परन्तु सुदृढ़

संघ्य संचालन के कारण अंग्रेजों की अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। ममूदा के ठाकुर देवीसिंह ने भी इस अभियान में अंग्रेजों को सहायता दी। अंग्रेज फौज पहाड़ी व जंगल के क्षेत्रों में प्रवेश कर गई तथा वहाँ तीन पुलिस चौकियाँ स्थापित करने में सफल रही। मेरों की भजवूर होकर भविष्य में छूटमार न करने व राजस्व कर देने के समझौतों पर हस्ताक्षर करने पड़े।<sup>२४</sup>

कैप्टन टॉड जो कि उन दिनों उदयपुर में पोलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ सीमा क्षेत्र में स्थित मेरों को अपने अधीन करने में सफल रहे थे।<sup>२५</sup> इन अभियानों के फलस्वरूप, क्षेत्र में शांति छा गई, परन्तु यह शांति आने वाले तूफान की सूचक थी। नवंबर १८२० में मेरों ने सशस्त्र आक्रमण कर तीनों पुलिस चौकियों को रौंद डाला, भीम<sup>२६</sup> दुर्ग पर अधिकार कर लिया और चारों ओर मारपीट मचा दी थी। अंग्रेज सुपरिन्टेण्डेंट विल्डर ने तत्काल मेक्सवेल के नेतृत्व में कई सैनिक टुकड़ियाँ भेजकर भ्रूक, श्यामगढ़ और सूखा पर पुनः अधिकार स्थापित किया था।<sup>२७</sup>

अंग्रेजों ने उदयपुर और जोधपुर से भी सहयोग मांगा तथा आवश्यक संपारी के बाद बीरवा<sup>२८</sup> और हथून<sup>२९</sup> पर भारी सैनिक शक्ति से आक्रमण किया। यद्यपि अंग्रेजों ने बीरवा पर अधिकार कर लिया था परन्तु मेरों ने अंग्रेजी सेना को गभीर क्षति पहुँचाई और पीछे खदेड़ दिया। अंग्रेजों ने मेवाड़ की सेना की सहायता से एकबार और प्रयास किया परन्तु बड़ी ही कठिनाई से मेरों को पराजित कर बरासवाड़ा और मांडला पर अधिकार स्थापित किया जा सका<sup>३०</sup>। मेरों को हार माननी पड़ी और अंग्रेजों ने मेवाड़ और मारवाड़ की सैनिक टुकड़ियों की सहायता से कौटकीराना,<sup>३१</sup> वगडी<sup>३२</sup> और रामगढ़<sup>३३</sup> आदि दुर्गों पर अधिकार कर लिया तथा दो सौ मेरों की बंदी बनाया गया<sup>३४</sup>। इस तरह मेरवाड़ा अंग्रेजों के अधिकार में आया। इन अभियान के शीघ्र बाद ही कैप्टन टॉड द्वारा उदयपुर के अधिकतर मेर क्षेत्रों में भी प्रयास किये गये। मेवाड़ में ६०० बंदूकधारी सैनिकों की टुकड़ी गठित की गई और स्थाई मू-राजस्व की व्यवस्था स्थापित की गई। जोधपुर रियासत ने सीमावर्ती ठाकुरों की मेर आगों की व्यवस्था का भार सौंपने के बजाय मारवाड़-मेरवाड़ा क्षेत्र में स्थिति की सुधारने का और कोई प्रयत्न नहीं किया।<sup>३५</sup>

अंग्रेजों के हिस्से में जो भूभाग आया उसे उन्होंने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। प्रारम्भिक स्थिति में यद्यपि कुछ क्षेत्रों की व्यवस्था का भार खरवा तथा ममूदा के ठाकुरों को सौंपा गया था। भ्रूक, श्यामगढ़ और सूखा तथा अन्य आगों में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये अंग्रेजों ने इन ठिकानेदारों को कतिपय अधिकार प्रदान किये। उन्हें विल्डर की देखरेख में काम करना पड़ता था।<sup>३६</sup>

इस तरह मेरवाड़ा को अंग्रेजों द्वारा पहली बार जीता जा सका था। इसके पूर्व मेरों ने कभी भी किसी बाहरी शक्ति के सम्मुख समर्पण नहीं किया था, और न वहाँ इसके पूर्व कभी इस तरह के दमनकारी कदम ही उठाये गये थे। परन्तु इस क्षेत्र में स्थाई शान्ति व व्यवस्था कायम करने के पूर्व कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केप्टिन टॉड उदयपुर के अन्तर्गत जो मेरवाड़ा का क्षेत्र था उस पर वे विशेष ध्यान नहीं दे पाये।<sup>30</sup> यही हालत जोधपुर राज्य की थी। उसने भी अपना क्षेत्र स्थानीय ठाकुरों के हाथ में छोड़ इस और कोई ध्यान नहीं दिया।

इसलिए कुछ ही समय बाद यह महसूस होने लगा कि मेरवाड़ा में तिहरी (अंग्रेज-मेवाड़ व मारवाड़) शासन व्यवस्था दोषपूर्ण व नहीं के बराबर है। एक भाग के अभियुक्त दूसरे भाग में धरण लेने लगे। इससे मेरवाड़ा की स्थिति पहले से भी अधिक शोचनीय हो गई थी। इन परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाने लगा कि मेरवाड़ा के तीनो हिस्से (अंग्रेज-मेवाड़-मेरवाड़) एक ही अधिकारी व प्रशासन के अन्तर्गत रहे जायं तथा उक्त अधिकारी में दीवानी व फौजदारी के सभी अधिकार निहित हो। उसे पूर्व प्रशासनिक व सैनिक अधिकार भी प्रदान किए जाए। उक्त अधिकारी रेजिडेंट की देखरेख व नियंत्रण में कार्य करे। यह भी तय किया गया कि ८ कम्पनियों की एक बटालियन जिसमें प्रत्येक कम्पनी में ७० व्यक्ति हों, मेरवाड़ा के लिए गठित की जाय। इनमें अर्धों मेरों में से की जाय।

**मेवाड़ तथा मारवाड़-मेरवाड़ा**

उपयुक्त फैसले को कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से मेवाड़ के साथ हुई वार्ता के फलस्वरूप मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच मई १८१३ में एक समझौता सम्बन्ध हुआ। जिसके अनुसार मेवाड़ ने मेवाड़-मेरवाड़ा के तीन परगने जिसमें ७६ ग्राम थे, अंग्रेज सरकार को दस साल के लिए सौंप दिये। महाराणा ने स्थानीय फौजी टुकड़ियों के व्यय के लिये पन्द्रह हजार की वार्षिक राशि भी प्रदान करना स्वीकार किया। प्रारम्भ में मेवाड़ महाराणा को इन परगनों का प्रशासन अंग्रेजों को हस्ता-तरित करने में काफी हिचकिचाहट रही थी।

उदयपुर के महाराणा को इस व्यवस्था से अत्यधिक लाभ पहुँचा था। इस व्यवस्था की अवधि सन् १८३३ में समाप्त होने पर, वे इस अवधि को आगामी छठ साल तक और जारी रखने के लिए तत्काल राखी हो गए। इस आशय का एक समझौता दोनों पक्षों के बीच ७ मार्च, १८३३ को ब्यावर में सम्पन्न हुआ। उदयपुर नरेश ने इस बार स्थानीय सैनिक टुकड़ियों के लिये निर्धारित पन्द्रह हजार की वार्षिक राशि के अतिरिक्त पाँच हजार की वार्षिक राशि प्रशासनिक व्यय के लिए भी अंग्रेजों को देना स्वीकार किया।<sup>31</sup>

अंग्रेजों को जोधपुर (मारवाड़) के साथ समझौते में प्रारम्भ में कुछ कठिनाई



का सामना करना पड़ा, क्योंकि जोधपुर नरेश अपने अधीनस्थ भाग के प्रशासन को भंग्रेजों को हस्तांतरित करने में भिन्नक अनुमत्त कर रहे थे। परन्तु अन्त में मार्च, १८२४ में जोधपुर के साथ भी भंग्रेजों का ठीक इसी तरह का समझौता हो गया जैसा मेवाड़ के साथ सन् १८२३ में हुआ था। इस समझौते के अनुसार जोधपुर ने अपने मेरवाड़ा क्षेत्र के २१ गाँवों के प्रशासन को भाठ वर्षों के लिए भंग्रेजों के अधीन रखना तथा साथ ही पन्द्रह हजार की वार्षिक राशि, क्षेत्र में व्यवस्था बनाये रखने के लिए गठित मेर टुकड़ियों के व्यय स्वरूप देना स्वीकार कर लिया। समझौते के अनुसार दोनों रियासतों के नरेशों को खर्चा काटने के बाद हस्तांतरित क्षेत्रों के गाँवों का राजस्व मिलते रहने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था की २३ अक्टूबर, १८३५ में पुनः नये समझौते के द्वारा ८ वर्षों के लिए जारी रखा गया, इसमें भी जोधपुर को पहले की भांति भंग्रेजों को प्रति वर्ष पन्द्रह हजार की राशि देने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त जोधपुर ने पहले के २१ गाँवों के अतिरिक्त ७ और नये गाँवों का प्रशासन भी भंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया।<sup>४१</sup>

मेवाड़ के साथ १८३३ में तथा जोधपुर के साथ १८३५ में किया गया उपर्युक्त समझौता सन् १८४३ में समाप्त होने वाला था। इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए नये समझौते की आवश्यकता अनुभव की गई। मेवाड़ नरेश ने यह पहल की कि भंग्रेजों को जबतक वे चाहें तबतक मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र के गाँवों का प्रशासन उनके अधीन रखने की अनुमति प्रदान करदी।<sup>४२</sup> जोधपुर रियासत ने भी ऐसा ही किया। वे सात गाँव १८३५ के समझौते के अंतर्गत भंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक अधिकार में लिए थे पुनः जोधपुर रियासत को सौदा दिए। परन्तु इस संबंध में कोई स्पष्ट हक़ारनामा नहीं हुआ। भंग्रेजों ने सन् १८४७ में दोनों रियासतों द्वारा उनके हिस्से स्थाईतौर पर भंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिए जाने के आशय के प्रयत्न किए परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इस प्रकार इन्हीं असंतोषजनक परिणामों पर मेरवाड़ा में भंग्रेज प्रशासन कई वर्षों तक जारी रहा।<sup>४३</sup>

मेवाड़ के मेरवाड़ा सम्बन्धी गाँवों का प्रश्न सन् १८७२ और १८७६ में पुनः उठाया गया परन्तु सन् १८८३ में अन्तिम रूप से समझौता हो सका। इसमें यह तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र के प्रशासनिक व्यय तथा मेरवाड़ा बटालियन और भील कोर के खर्च की एवज़ में इस क्षेत्र के पूरे राजस्व की हकदार होगी। अवतक की बकाया राशि के लिए मेवाड़ के राजा से माग नहीं की जाएगी। महाराणा को इसके साथ ही स्पष्टतौर से यह आश्वासन दिया गया कि इस समझौते के कारण मेवाड़-मेरवाड़ा पर उनका स्वामित्व किसी तरह भी प्रभावित नहीं होगा। साथ ही भंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में लिए गए उनके क्षेत्रों का राजस्व जब करी ६६,००० रुपये की वार्षिक राशि से जो मेवाड़ के मेरवाड़ा

क्षेत्र के प्रशासन तथा मेरवाड़ा बटालियन और मील कौर पर व्यय के लिए मेवाड़ द्वारा अंग्रेजों को देना निर्धारित हुआ था, उसमें अधिक की प्राप्ति होने पर इस तरह की पूरी रकम मेवाड़ को लौटा दी जाएगी। इस बारे में मेवाड़ में स्थित अंग्रेज रेजीडेंट प्रति वर्ष पिछले वर्ष के राजस्व का हिसाब मेवाड़ सरकार को प्रस्तुत करते रहेंगे।<sup>४४</sup>

मारवाड़-मेरवाड़ा के बारे में भी जो मेरवाड़ा क्षेत्र में जोधपुर रियासत का भाग था, कई वर्षों के बाद अंग्रेज सरकार व जोधपुर महाराजा के बीच सन् १८८५ में संतोषजनक समझौता हो पाया था। जिसके अनुसार यह तय हुआ कि जोधपुर रियासत का इन गांवों पर सार्वभौमिक अधिकार रहेगा और अंग्रेज सरकार उन्हें प्रति वर्ष तीन हजार रुपये देगी। यदि अंग्रेज सरकार को कभी इन जोधपुर के गांवों से लाभ होया तो उसका ४० प्रतिशत जोधपुर रियासत को मिला करेगा। इन शर्तों के आधार पर अंग्रेज सरकार इन गांवों पर अपना संपूर्ण एवं स्थाई प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर सकी थी।<sup>४५</sup>

### ग्याय-व्यवस्था

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मेरों की अपनी अनोखी ग्याय-व्यवस्था थी। यह व्यवस्था कठोर ढंग पर आधारित थी। इन लोगों की यह विशिष्ट मान्यता थी कि निरपराध व्यक्ति का हाथ यदि गर्म तेल में डलवाया जाए या उसकी हथेलियों पर गर्म लोहे का गोला भी रस दिया जाय तो वह नहीं जलता है। साथ ही वे यह भी मानते थे कि मन्दिर में देवता के सम्मुख रखी हुई सपत्ति को यदि कोई व्यक्ति बिना ग्यायोचित अधिकार के उठाने का साहस करता है तो उसे निश्चय ही देवी प्रकोप का पात्र बनना पड़ेगा। अंग्रेजों की ग्याय-व्यवस्था के सम्मुख इन मान्यताओं को समाप्त होना पड़ा। मुकदमों का पंचायती के द्वारा निपटाने की प्रक्रिया पुनः स्थापित की गई। बादी को अपनी शिकायत लिखित में पंचायत को प्रस्तुत करनी होती थी। प्रतिवादी को अपनी सफाई के लिए लिखित प्रथवा मौखिक उत्तर देना आवश्यक था। उसे इस बात की सुविधा दी जाती थी कि वह अपने मामले की सुनवाई के लिए पंचायती व्यवस्था प्रथवा अन्य उपायों में से जिसे चाहे पसन्द कर सकता था। यदि पंचायत प्रक्रिया निर्विवाद होती तो दोनों ही पक्षों से उनके सदस्यों के नाम आमन्त्रित किए जाते थे। दोनों ही पक्षों के सदस्यों की समान सख्या रहती थी। उन्हें यह लिखित आश्वासन देना होता था कि यदि उनमें से कोई भी पंचायत के निर्णय को नहीं माने तो उस व्यक्ति को पंचायत प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का एक तिहाई या एक चौथाई अंश स्वयं वहन करना होगा। तत्पश्चात् दोनों पक्षों के कागजात जांचे जाते थे व उनमें अपेक्षित भूलें ठीक करने के बाद दोनों पक्षों को वे पड़कर सुनाए जाते थे। उन्हें सुझाव देने तथा पूज पुष्पारने

का पूर्ण हक होता था। तलशवान् स्थानीय अधिकारी को आदेश दिया जाता था कि वह पंचायत बुलाए, गवाहों के नाम उपस्थिति का आदेश जारी करे और कार्यवाही को लेखबद्ध करे। यदि पंच लोक रिश्वत के प्रभाव या अन्य कारणों से न्याय-पूर्ण निर्णय न लेकर किसी के हक में अनुचित निर्णय लेते तो उन्हें भी दंडित करने का प्रावधान था। पंचायत के निर्णयों को अन्तिम स्वीकृति एवं आदेशों के लिए अंग्रेज अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता था। अधिकांश मामलों में पंचायतों का निर्णय सर्वसम्मति हुआ करता था। व्यावहारिक दृष्टिकोण से पंचायती न्याय प्रक्रिया विलम्ब के दोषों से रहित थी।<sup>४६</sup>

फौजदारी मुकदमों अंग्रेज अधिकारीगण संश्लिष्ट विचारण के द्वारा तय करते थे। परन्तु कतिपय ऐसे मुकदमों जिनमें मजूर पूरे घयवा संतोरजनक नहीं होते, उन्हें पंचायतों को सौंप दिया जाता था।<sup>४७</sup>

मृत्युदण्ड बहुत कम दिया जाता था। हत्या अथवा खून के गम्भीर मामलों में ही शारीरिक दण्ड दिया जाता था। साधारण मामलों में चार भाह तक के कारावास का प्रावधान था। बाल अपराधों या महिलाओं की बदचलनी के मामले में सजा नहीं दी जाती थी। जेल-व्यवस्था अपने आप में मुख्यस्थित थी। कैदियों को प्रतिदिन एक सेर जौ का आटा दिया जाता था। कैदियों की शार्भना पर उन्हें कम्बल और कपड़े भी दिए जाते थे, परन्तु इनकी कीमत कैदियों के खर्चों में से काट ली जाती थी। यहाँ तक कि शुराक खर्च तथा अन्य खर्च भी कैदियों की रिहाई के बाद उनसे वसूल किए जाते थे। जेलों में काम का समय दोहर से सायंकाल तक रहता था। काम में लापरवाही या अवहेलना करने पर उन्हें दण्ड स्वरूप प्रतिरिक्त काम करना होता था।<sup>४८</sup>

### भूमि-व्यवस्था :

भूमि भूस्वामी की संपत्ति होती थी। इनके मारिक अधिकारों की सीमा ही होती थी। भूस्वामी अपनी इच्छानुसार भूमि की बेच सकता था, बरहान रख सकता था। परन्तु भूस्वामी को यह अधिकार था कि वह उक्त राशि का भुगतान कर जब भी चाहे अपनी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकता था। भूमि को दूसरों से जुनवारकर लाभ उठाने वाली व्यवस्था का जन्म यहाँ अभी तक नहीं हुआ था। कृषि अधिकारों में स्वयं निगुजारे का भाग था। राजस्व सम्बन्धी सभी चीजों की सुनवाई अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष होती थी। फसल का बीज हिसा वटेनों द्वारा सरकार को भूराजस्व के रूप में दिया जाता था जो कि तत्कालीन भूराजस्व की अधिकतम सीमा थी। जब कि क्षेत्र के अन्य रिमानों से एक तिहाई ही वसूल किया जाता था।

यह निश्चित बात है कि भूराजस्व निर्धारण की इस पद्धति में किसानों के घाय बकी व आभाचार के शर शुर से परशु सनाइ थे, उन दिनों ऐसी ही व्यवस्था

सागू थी और हमने किसी तरह के भूल-भूत परिवर्तन का मतलब सारी व्यवस्था को प्रभावस्थित कर देना था। भूराजस्व वसूली में कोई विशेष दिक्कत पैदा नहीं होती थी और फसल के मूल्यांकन की प्रक्रिया से किसान परिचित थे। अंग्रेज अधिकारियों की राय में तो यदि सरकार फसल का आधा हिस्सा भी भू-राजस्व में लेती तो उन्हें देने में कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु इतनी अधिक भू-राजस्व वसूली इसलिए नहीं की जाती थी कि किसान इनने गरीब थे कि वे कदाचित् ही इतना लगान दे पाते।<sup>४४</sup>

### सामाजिक सुधार

सूदमार, गुलामी, कन्या-हत्या, महिलाओं की त्रिकी जैसी सामाजिक कुरीतियों के घनावा भी मेरे में और कनिष्ठ सामाजिक दोष पाए जाते थे। महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी थी इसका अंदाज इसमें लगाया जा सकता है कि उन्हें चौपायों की तरह बेचा जा सकता था। यहाँ तक कि एक बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ को बेचने का हुक्मदार था। इस तरह का अधिकार माँ की ममता व उसके प्रति अपने प्रेम की कमी पर आधारित नहीं था। इसके मूल में केवल यही भावना काम करती थी कि उसकी माँ को प्राप्त करने में उसके पिता ने नाना को प्रचंडी खासी रकम दी थी अतएव बेटे को यह हक प्राप्त था कि वह अपनी माँ को बेचकर यह रकम वापस प्राप्त कर सकता था। दुनियाँ के किसी भी समाज में ऐसी व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। अंग्रेजों को यह ध्येय दिया जा सकता है कि उन्होंने इस कुरीति को समाप्त करने में योग दिया, फलस्वरूप लड़कियों के विधिवत् विवाह होने लगे, कन्याओं का बालवध भी कम हुआ और कालान्तर में धीरे-धीरे अन्य सामाजिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त हो सका।<sup>४५</sup>

सामान्यतः मेरों में चार तरह के दास होते थे। दास-दासियों का क्रय-विक्रय किया जा सकता था। स्वामी और दासी के बीच इस आशय का समझौता होता था कि वह आजन्म अपने स्वामी की बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सूदमार में प्राप्त स्त्री पुरुष जिन्हें दो या तीन साल में छुटकारे की राशि चुका कर छुड़ाया नहीं जाता तो उन्हें दास बना लिया जाता था। स्वामी और दासियों के बीच विवाह या यौन सम्बन्ध को अनैतिक माना जाता था। यहाँ तक कि स्वामी और दासियों के बीच भाई बहन का सम्बन्ध समझा जाता था। दासों के साथ उनके स्वामियों का व्यवहार उदार और कृपापूर्ण होता था। दास अपनी निजी संपत्ति रख सकता था। यद्यपि इस तरह के घन पर स्वामी का अधिकार होता था, परन्तु कदाचित् ही किसी मालिक ने इस अधिकार का उपयोग कभी किया हो। उपर्युक्त चारों तरह के गुलामों के अतिरिक्त एक और विचित्र दास-प्रथा प्रचलित थी। जब कभी कोई सजाया हुआ हिन्दू किसी ज़क़िदारी सरदार की शरण में चला जाता तो उसे जरण

इस भाषार पर मिलती थी कि वह चोटी काट कर मालिक के हाथ में दे दे। मालिक उसे दूत शिक्षा दासों में शामिल कर लेता और उसे संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करता था। दूतशिक्षा के भरने पर उसकी मागी संपत्ति मालिक की होती थी। जबतक दूतशिक्षा जीवित रहता, मालिक उसकी सूट-खसोट में से एक चौपाई का अधिकारी होता था।<sup>११</sup>

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरो मे व्याप्त उपर्युक्त तथा अन्य कई कुरी-तियों को मिटाने में अंग्रेजों को अत्यंत सफलता मिली। धीरे-धीरे इनमें सुधार होने लगे। एक दूसरे के प्रति उनके आपसी व्यवहार में भी सुधार आया। उनके अपने क्षेत्र में भी शांति स्थापित हुई तथा साथ ही पड़ोसी क्षेत्र जोधपुर, उदयपुर भी उनके हस्तक्षेपों से मुक्त रहे। मेरवाड़ा में शांति स्थापना का जो काम अंग्रेजों ने किया, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने जिस रुढ़ता, साहस और अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है, वह सराहनीय है।

### मेरवाड़ा बटालियन

अंग्रेजों ने मेरों की मेरवाड़ा बटालियन एक ऐसी अनुशासित सेना तैयार की थी कि जिस पर अंग्रेज सरकार किसी भी संकट के समय भरोसा कर सकती थी। बहुत ही कम समय में इन टुकड़ियों को सैनिक तत्परता, खुशी और अन्य फौजी नियमों के अनुकूल ढाल दिया गया और सारी बटालियन किसी भी तरह के शत्रु संकट का सामना करने में सक्षम थी। इस तरह के सैनिक अनुशासन ने जनता में यथासमय जिम्मेदारी निभाना, स्वच्छता का पालन करना, आदेश मानना, सहज व्यवहार तथा अंग्रेज हुक्मत के प्रति विश्वास की भावना पैदा की। इस क्षेत्र में जो अबतक सूट-भार और हत्याओं के कारण बुरावत था, शांति स्थापित हुई। व्यवस्थित समाज का रूप लेने के लिए आवश्यक धर्म और मयम की आदतें धीरे-धीरे मेरो में घर करने लगी।<sup>१२</sup>

### कर्नल हाल और डिक्सन की उपलब्धियाँ

कर्नल हाल ने इस क्षेत्र के विकास के लिए इतना अधिक कार्य किया था कि जब पदस्थता के कारण उन्हें छोड़ना पड़ कर्नल डिक्सन को सौंपा तो लोगों को बड़ा दुःख हुआ। गवर्नर जनरल श्री सी. टी. मेटकाफ को कर्नल डिक्सन की विनूक्ति इस क्षेत्र में करत समय यह पूर्ण विश्वास था कि डिक्सन नदर, लहर, कार्यकुशल, सगनशील और जनसामान्य के हितों के रूप में इस क्षेत्र की विषम समस्याओं को निपटाने में सफल होंगे।<sup>१३</sup>

मेरवाड़ा मुकरज. पड़ाई क्षेत्र है, जहाँ पञ्जी क्षेत्री का विकास सदन नहीं

था। सिपाई के लिए वर्षा के अतिरिक्त अन्य साधनों का भारी अभाव था। सन् १८३२ में इस क्षेत्र में भीषण प्रकाश के कारण लोगों को अपनी तथा अपने मवेशियों के प्राण बचाने के लिए यह क्षेत्र छोड़ कर इधर-उधर घूमने जाने को बाध्य होना पड़ा था। सारा क्षेत्र वीरान रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया था। प्रशासन के समक्ष यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि कहीं कर्नल हाल ने जो विकास के काम हाथ में लिए थे, वे निरर्थक नहीं हो जाएं। लोगों में लूटमार की प्रवृत्ति पुनः जन्म न ले ले, और लोग अपने घरों व धेतों के घन्घे को छोड़ न दें। प्रशासन के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें इस प्राकृतिक प्रकोप से मुकाबले के लिए तैयार करें। इसमें इस व्यय के लिए बहुत बड़ी धनराशि अर्पित थी। जनता इतनी गरीब थी कि उससे इसके जुटाने की बात कही नहीं जा सकती थी। पिछड़ी कृषि को विकसित करने की प्रशासन की योजनाओं व कार्यक्रमों में लोग केवल सहयोग मात्र कर सकते थे।<sup>६६</sup>

सबसे प्रमुख काम पुराने तालाबों की मरम्मत और नये जलाशयों का सरकारी खर्च पर निर्माण का था। प्रत्येक गाँव में खेती को सुधारने के लिए पूरा धन और शक्ति लगाने का वातावरण तैयार किया गया। बेरोजगार लोगों की सूचियाँ तैयार की गईं जिसमें उन्हें भी खेती के काम में लगाया जा सके। १८३२ के प्रकाश से लोगों में विश्वास की भावना बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम किया गया। सरकारी खर्च पर बड़े पैमाने पर कुएँ खुदवाने का कार्य हाथ में लिया। इन कुओं की बाद में किसानों को सौंप दिया गया। सरकार के इस कदम ने स्थानीय लोगों में उसके प्रति गहरे विश्वास की भावना उत्पन्न की। जिस क्षेत्र में कुएँ खोदना कठिन काम था, वहाँ सरकार ने बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण कराया जिससे कि आपत्काल में व संचित-सुरक्षित जलमंडार का काम दे सकें। पहाड़ी धाराओं से धेतों की मिट्टी बह जाने और वर्षा के जल का जमीन में न रहने की समस्या भी विकट थी। इस दिशा में धेतों के चारों ओर पत्थरों की दीवारें खड़ी की गईं।<sup>६७</sup>

उपयुक्त प्रयासों के अतिरिक्त अन्य कतिपय भूमि विकास आयोजनाओं की इस तरह व्यवस्थित ढंग से अंपनाया गया कि हजारों बीघा पड़ती भूमि, जहाँ पहले जंगल थे—अल्प समय में ही कृषि योग्य भूमि में बदल गई। जब लोगों को पता लगा कि सरकार इस भूमि को खेती के लिए वितरित करना चाहती है तो उन्होंने प्रायःना-अन्य देना शुरू किया। पटेलों की निधुक्ता की पर्द और उनके सीपा क्षेत्र निर्धारित किए गए। शुभ मुहूर्त देखकर कई नये गाँवों की स्थापना की गई। पटेलों को पट्टा दिया गया, लोगों को बसने के लिए सरकार की ओर से पूरी रियायतें प्रदान की गईं। यहाँ तक कि उनमें कृषि के सामान का भी सरकार की ओर से निःशुल्क वितरण किया गया।<sup>६८</sup>

सरकार और जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करने व उनकी समस्याओं को प्रतिकूल दूर करने के लिए भजमेर के म्युनिसिपैलिटी द्वारा करते थे जहाँ वे जाते जनता उनके घेरे पर इकट्ठी हो जाती थी। उनकी कठिनाइयों को सुनकर वहीं उनके निवारण का प्रयत्न किया जाता था। इसका परिणाम यह निकला कि जनता में भ्रंज सरकार के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हुई<sup>१५</sup>।

### सामाजिक जीवन

प्रशासनिक कर्तव्यों की पूर्ति के साथ-साथ सरकार ने इन लोगों में सामाजिक जीवन की भावना पैदा करने के प्रयत्न भी किए। सामाजिक जीवन में प्रमुख रूप से किसानों तथा दलितों का जिनमें मुख्यतः सुहार, बडई, कुम्हार, नाई, सेबक, बलई आदि का बाहुल्य था। ये जातियाँ कृषि के साथ ही साथ अपने परंपरागत व्यवसाय भी किया करती थी। किसान का एकमात्र व्यवसाय कृषि था। अन्य जातियों को सेवा के उपलक्ष्य में किसानों के यहाँ से नि:शुल्क भ्रमाज मिला करता था। उदाहरणतया बोली को गाँव में सभी उत्सवों पर डोल बजाना होता था और चमार को घासबासियों के जूते बनाने व उनकी नि:शुल्क मरम्मत करना होती थी। चमार का मूत पशु पर अधिकार होता था और उसकी आजीविका एवं निर्वाह का भार सारे ग्रामीण समाज को वहन करना होता था। इसी तरह बोली का भी सभी परिस्थितियों में समाज पर निर्वाह का दायर रहता था। कुछ ऐसे भू-भाग भी थे जिनमें कई कारणों से लोग जोतने को तैयार नहीं थे। भ्रंज चूँकि उन्हें खेतों का रूप देना चाहते थे, इसलिए जब किसान इसके लिए सहमत नहीं हुए तो उन्होंने बलाइयों को—जिन्होंने खेती और अन्य कृषि जन्य कामों में अपने कौशल का परिचय दिया था, यह भूमि दे दी गई और वहाँ उन्हें बसा कर रहने के भी पड़े भी बनवा दिए गए।<sup>१६</sup> इस प्रकार भ्रंज सरकार ने मेरवाड़े में कृषि को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।

### कृषि-विकास

इस तथ्य की भस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मेरवाड़ा में कृषि-विकास का इतिहास भ्रंज प्रशासन के कड़े परिश्रम का परिणाम है। पहाड़ी नाले जो बरसात में बह कर खेतों के बीच से गुजरते थे उन्हें बाँध दिया गया, कुएँ खोदे गए और लोगों से बिना किसी तरह की व्यय राशि लिए ही प्रशासन ने उन्हें उपयोग के लिए सौंप दिया, बाघ और शालाब राज्य के खर्च से तैयार किए गए। प्रशासन की सफलता सभी प्राप्त हुई जब लोग स्वयं उत्साहित होकर प्रशासन की सहायता देने लगे। लोग उत्साहित होने लगे या अनुत्साहित, यह बहुत कुछ प्रशासन पर निर्भर करता है और इस सन्दर्भ में तत्कालीन भ्रंज-प्रशासन काफी हद तक इस इलाके में सफल रहा।

अंग्रेजों के प्रशासन को यह श्रेय भी देना होगा कि उन्होंने मेरवाड़ा के इलाके में लुटेरों के दलों को समाप्त कर व मेरों को अनुशासित कर शांति स्थापित की। मार्ग, व्यापार के लिए निष्कटक हो गए। इस क्षेत्र में अराजकता काफी कम हो गई थी। अकाल के दिनों में भविष्यो के अपहरण की घटनाओं को छोड़ कर इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो गई। फनस्वरूप यही मेर आगे चलकर अंग्रेजों के लिए सैनिक कार्यों में बड़े सहायक सिद्ध हुए।<sup>१०</sup>

सन् १८५७ के सैनिक विद्रोह में मेरवाड़ा बटालियन पूर्ण रूप से अंग्रेजों की भक्त रही और इसके फलस्वरूप उसे विशेष आदर भी प्राप्त हुआ था। सन् १८७० में लार्ड मेयो ने इसे पुरो तरह सैनिक कोर में पुनर्गठित कर और इसका सदर मुकाम ब्यावर से अजमेर स्थानान्तरित कर दिया था। १८९७ में यह बटालियन भारत सरकार के कमांडर-इन-चीफ के अधीन कर दी गई थी। सन् १९०३ में इसे भारतीय सेना का अंग बना कर और इसका नाम ४४ मेरवाड़ा इन्फैंट्री रख दिया गया था।<sup>११</sup>

U. U. CENT. LIB

## अध्याय २

१. "उन दिनों पश्चिमी घाट के समुद्री तट से देश के आन्तरिक भागों में पूर्व की ओर, उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों तक संचारित होने वाला व्यापार-मार्ग मेरवाड़ा क्षेत्र से होकर गुजरता था। यह क्षेत्र इस व्यावसायिक मार्ग के मध्य में स्थित था तथा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं को पृथक् करता था। इस क्षेत्र से केवल व्यापार ही प्रभावित नहीं होता था वरन् दो राज्यों के बीच दृढ़ कपाट के रूप में भी इस भू-भाग का महत्व था। इस क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट ही ऐसी है कि गाड़ियों के पहिए उधर से गुजर नहीं सकते थे।"

असि० पोलीटिकल ऐजेन्ट ब्यावर को थी एफ विल्डर पीलीटिकल ऐजेन्ट तथा सुपरिटेन्डेंट द्वारा प्रेषित पत्र—अजमेर दि० २० जुलाई, १८२२।

२. सन् १८१८ से लेकर १८३४ तक—अंग्रेजों के राजपूताना में आगमन काल से लेकर मेरवाड़ा की ऐतिहासिक रूप-रेखा, सरकार के आदेशों से प्रस्तुत, फाइल क्रमांक १११० पृ० १ सन् १८७३ (पूर्व फाइल क्रमांक १४५३) अजमेर।
३. अंग्रेजों के आगमन के पूर्व मेरों की उत्पत्ति, उनका धर्म, इतिहास सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण। फाइल क्रमांक १११० सन् १८७३, पूर्व क्रमांक



१४५३ पृ० ६. स्केच ऑफ मेरवाड़ा डिविजन (१८१०) पृष्ठ १ से ६

जोध्या रिटमलोत की रूपात, राजस्थान राज्य पुरातत्व मण्डल पांडुलिपि क्रमांक ७०५ पुरातत्व श्रेणी जो पहले भूतपूर्व जोधपुर रियासत के इतिहास विभाग से उपलब्ध (क्रमांक १३)

४. पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के पोलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा सी० एफ० विल्डर सुपरिटेन्डेंट भजमेर को प्रेषित पत्र, दिनांक ५-१२-१८२० ।
५. भारत की जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट—राजपूताना और भजमेर सन् १९०१ पृष्ठ ६२ ।
६. केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिसम्बर १८३४, फाइल क्रमांक ४ (१८२१) मेर गौवो की सामान्य जानकारी सदर्म सामग्री (राज० रा० पु० मण्डल) । स्केच ऑफ मेरवाड़ा, डिविजन, (१८१०) पृ० ६-१८ ।
७. कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिल्ली के रेजीडेन्ट सर डेविड ब्रॉक्टरलोनी को प्रेषित पत्र दि० १८-६-२१ फाइल, क्रमांक ए (१) पूर्व, क्रमांक ८ । १८२१ (राज० रा० पु० म०) मेर गौवो सम्बन्धी सामान्य जानकारी ।
८. कार्यवाहक पोलिटिकल एजेंट द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ब्रॉक्टरलोनी रेजीडेन्ट मालवा राजपूताना को प्रेषित पत्र दिनांक १७ जून १८२२ । (राज० रा० पु० मण्डल) ।
९. सचिव भारत सरकार द्वारा राजपूताना मालवा के पोलिटिकल एजेंट मेजर जनरल ब्रॉक्टरलोनी को पत्र फोर्ट विलियम दिनांक १७ जून, १८२२ (राज० रा० पु० मण्डल) ।
१०. फाइल क्रमांक १११०, धर्मों के मेरवाड़ा में आधिपत्य के पूर्व मेरों की उत्पत्ति, उनके धर्म तथा इतिहास का संक्षिप्त विवरण पृ० ६-१३, (राज० रा० पु० मण्डल) स्केच ऑफ मेरवाड़ा डिविजन (१८५०) पृ० १३-२० ।
११. सी० सी० वाट्सन—राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजेस्टीयर्स, भजमेर मेरवाड़ा, खंड १ ए (१९०४) पृ० १३-१७, फाइल क्रमांक १११०—धर्मों के आधिपत्य के पूर्व मेरों की उत्पत्ति, उनका धर्म तथा इतिहास सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण, पृ० ६-१३ (राज० रा० पु० मण्डल) स्केच ऑफ मेरवाड़ा-डिविजन (१८५०) पृ० १ से ६ ।
१२. ठाकुर देवीसिंह पारसोती के जागीरदार थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी) मगरा मेरवाड़ा का इतिहास पृ० स० ४४ और ४५ (१९१४) बूंदो सिरीज

नं ४८ आलेख संख्या ५३ मेघराम की दीवान को भर्जी दिनांक मासोज शुक्ला सप्तमी, विक्रम संवत् १७८७ (रा० पु० मण्डल) ।

१३. मेरों की उत्पत्ति, इतिहास तथा धर्म का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ७ से ८ (रा० रा० पु० मण्डल) तथा शिवप्रसाद त्रिपाठी का मगरा मेरवाड़े का इतिहास (१९१४) पृष्ठ ४४-४५, वाक्या दस्तावेज जयपुर रियासत, बूंदी क्रमांक ७, आलेख संख्या ८५ कार्तिक शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत् १७८७ ।

१४. मेर, उनकी उत्पत्ति धर्म तथा इतिहास का संक्षिप्त विवरण (रा० रा० पु० मण्डल) पृष्ठ ८ । "मेवाड़ की सेना ने बदनोर के ठाकुर तथा मसूदा के ठाकुर सुल्तानसिंह के साथ हथुन पर आक्रमण किया । मरकर लड़ाई हुई जिसमें ठाकुर सुल्तानसिंह खेत रहा । मेवाड़ की सेना भाग छूटी ।" (शिव प्रसाद त्रिपाठी—मगरा मेरवाड़े का इतिहास (१९१४) पृष्ठ ४६) ।

१५. मेरों का संक्षिप्त विवरण. "उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास" (रा० पु० मण्डल) पृष्ठ ९ "महाराजा विजयसिंह ने अपने भण्डारी के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजकर चगवाम दुर्ग पर आक्रमण करवाया था परन्तु फौज को हताश होकर बिना लड़े ही वापस जोधपुर लौटना पड़ा । कुछ माह बाद रायपुर के ठाकुर अर्जुनसिंह के नेतृत्व में पुन जोधपुर की फौज ने कोट-किसना पर घावा किया परन्तु रावतों ने आक्रमण करके इन्हें लदेड़ दिया । (शिवप्रसाद त्रिपाठी—मगरा मेरवाड़ा का इतिहास (१९१४) पृष्ठ ४६-४७) ।

१६. मेरों का संक्षिप्त विवरण, उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास (रा० पु० मण्डल) पृष्ठ ९ । भायलां टाडगढ़ तहसील में है ।

१७. मेरों का संक्षिप्त विवरण, उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास (रा० पु० मण्डल) पृष्ठ ९ । जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने उन्हें आक्रमण के लिए उकसाया था ।

१८. यह अभियान भगवानपुरा के ठाकुर ने महाराणा भीमसिंह के आदेश पर किया था । बरार के निकट हुई लड़ाई में ठाकुर को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े । (शिव प्रसाद त्रिपाठी—मगरा मेरवाड़ा का इतिहास १९१४—पृष्ठ ४८) ।

१९. श्री एफ विल्डर पोलिटिकल एजेंट तथा सुपरिन्टेन्डेंट का प्रति. पोलिटिकल एजेंट ब्यावर को पत्र, अजमेर दिनांक ३०-७-१८२२ ।

२०. आक ब्यावर से ६ मील दूर पूर्व में स्थित गाँव है । यह चारों ओर से

पहाड़ियों से घिरा हुआ है। (शिव प्रसाद त्रिपाठी—भगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १९१४—पृष्ठ २२)।

२१. श्यामगढ़ ब्यावर से ६ मील दूर नयानगर के पूर्व में तथा मसूदा के पश्चिम में है। यहाँ के निवासी अपने पड़ोसी क्षेत्र में संगठित रूप से लूटपाट किया करते थे। (शिवप्रसाद त्रिपाठी—भगरा मेरवाड़ा का इतिहास १९१४ पृष्ठ २३)।
२२. लून्वा ब्यावर से ६ मील दूर पूर्व में श्यामगढ़ के दक्षिण में दो मील की दूरी पर स्थित है। शिवप्रसाद त्रिपाठी भगरा—मेरवाड़ा का इतिहास १९१४—पृष्ठ २४)।
२३. फाइल सं० १११० मेरों का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ११-१२ (रा० पु० मण्डल) कॅप्टन एच० हॉल सुपरिटेण्डेन्ट ब्यावर का रेजीडेन्ट मेजर जनरल सर डेविड मॉन्टरलोनी को पत्र दिनांक २०-१०-१८२३।
२४. उपरोक्त।
२५. फाइल क्रमांक १११०, मेरों का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ११-१२ (राज-रा० पु० मण्डल) एफ विल्डर पोलिटिकल एजेन्ट तथा सुपरि-अजमेर का मासवा, राजपूताना और नीमच के रेजीडेन्ट मेजर जनरल सर डेविड मॉन्टरलोनी को पत्र दिनांक २०-५-१८२२।
२६. भीम जिसका प्रचलित नाम पडवा है, टाडगढ़ से पूर्व में १० मील की दूरी पर स्थित है। इस स्थान के निवासी पड़ोसी रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्रों में लूटमार करते रहते थे। (शिवप्रसाद त्रिपाठी—भगरा मेरवाड़ा का इतिहास १९१४—पृ० ३६)।
२७. थीफ-कमीशनर कार्यालय फाइल क्रमांक १४६६२ (१२) सामान्य विविध फाइल क्रमांक ३-अजमेर और मेवाड़ के मेरों का विद्रोह जेम्स टॉड द्वारा विल्डर को प्रेषित पत्र दिनांक १-१२-१८२०। जेम्स टॉड द्वारा मेक्सवेल को प्रेषित पत्र दिनांक १६-१२-१८२०। विल्डर द्वारा मॉन्टरलोनी तथा टॉड को प्रेषित पत्र दिसम्बर १८२० तथा विल्डर द्वारा कर्नल मेक्सवेल को प्रेषित पत्र (राज० रा० पु० मण्डल)।
२८. मोरवा ब्यावर के दक्षिण में ७ मील की दूरी पर स्थित गाँव है। महा-राणा भीमसिंह ने यहाँ एक किला बनवाया था। (शिवप्रसाद त्रिपाठी—भगरा, मेरवाड़ा का इतिहास १९१४—पृष्ठ २६)।
२९. हपूरा या अणूरा ब्यावर से ६ मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित एक गाँव

३। (शि० प्र० त्रिपाठी—मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १९१४—पृष्ठ २५) ।

३०. मंडला, भीम का प्रचलित नाम था ।

३१. कोट किराना टाडगढ़ से पूर्व में १२ मील दूर एक गाँव है । (शि०-प्र० त्रिपाठी—मगरा—मेरवाड़ा का इतिहास १९१४ पृष्ठ ३७) ।

३२. बगड़ी टाडगढ़ से २० मील दूर है । यह जवाजा से ६ मील की दूरी पर है । शि० प्र० त्रिपाठी—मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १९१४ पृष्ठ ३०) ।

३३. रामगढ़ सेंडरा स्टेशन से एक मील दूर है । (शि० प्र० त्रिपाठी—मगरा मेरवाड़ा का इतिहास—१९१४ पृष्ठ २६) ।

३४. फाइल क्रमांक १११०—मेरवाड़ा की रूपरेखा १८१८ में अंग्रेजों के आगमन से लेकर १८३६ तक, केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तैयार सारांश, दिसम्बर १८३४ (राज० रा० पु० मण्डल) ।

३५. फाइल क्रमांक ६-१८२१, कमीशनरी कार्यालय, अजमेर १ ए (१) पुरानी । जी । मेवाड़—मेरवाड़ा १८२१-४७ (रा० रा० पु० मण्डल) । श्री एफ विल्डर को श्री मेक्सवेल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक १३-२-१८२१ तथा कर्नल जेम्स टॉड को श्री सी० भाटिन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक १८-१-१८२१, २२-१-१८२१ ।

३६. फाइल क्रमांक १८२१, कमीशनर कार्यालय, अजमेर १ ए (१) पुरानी । ८ मेर गाँव, सामान्य मामले (राज० रा० पु० मण्डल) सचिव भारत सरकार द्वारा मेजर जनरल डेविड मॉन्टेगलोनी को प्रेषित पत्र दिनांक २४-१२-१८२२ तथा २६-१-१८२३ ।

३७. कमीशनरी कार्यालय अजमेर, फाइल क्रमांक ६ (३) पुरानी । क्रमांक १ सद् १८२१ ।

३८. फाइल क्रमांक ए (१) । पुरानी ८, मेर गाँवों सम्बन्धी सामान्य मामले (राज० रा० पु० मण्डल) फाइल क्रमांक १११० सद् १८७३ दिसम्बर सद् १८३४ में केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तैयार विवरण (राज० रा० पु० मण्डल) ।

३९. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स अजमेर (१९०४) क्रमांक १-१ पृष्ठ १४-१५, राजपूताना मजिस्ट्रेट्स (१८७६) पृष्ठ २० स्केच आफ मेरवाड़ा—डिक्सन (१८५०) पृष्ठ १३-२८ कमीशनरी कार्यालय अजमेर (१९०४) फाइल क्रमांक १० सद् १८२१, ए (१) पुरानी ।

क्रमांक १० मेरवाड़ा में मेवाड़ और मारवाड़े ॥ दावों के बारे में कंस्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट, कमिश्नर कार्यालय, अजमेर, फाइल क्रमांक ६ सन् १८२१, ए (१) पुरानी ६। मेवाड़—मेरवाड़ा सम्बन्धित मामले । (राज० रा० पु० मण्डल) ।

४०. फाइल क्रमांक ६, १८२१ पश्चिमी राजपूताना रियासतों के पोलिटिकल एजेंट का पत्र दिनांक २३-१०-१८३५। सी० सी० वाटसन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, खण्ड १ ए (१६०४) पृष्ठ १४-१५ ।

४१. अजमेर कमिश्नर फाइल क्रमांक ७ सन् १८२३ मारवाड़—मेरवाड़ा से सम्बन्धित मामले । (राज० रा० पु० मण्डल) पश्चिम राजपूताना की रियासतों के पोलिटिकल एजेंट के पत्र दिनांक २-११-१८३५ । बीर बितौड़ पृष्ठ ८६१-८६३ ।

४२. फाइल क्रमांक ६, १८२१, ए (१) पुरानी क्रमांक ६, अजमेर-मेरवाड़ा १८२१—४७ संदर्भ मामले (राज० रा० पु० मण्डल) । पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के पोलिटिकल एजेंट का पत्र दिनांक १-७-१८४३ ।

४३. फाइल क्रमांक ७, १८२२ कमिश्नरी कार्यालय अजमेर ए (१) पुरानी क्रमांक ७ खण्ड २ मेरवाड़ा १८३३-५३ । पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के पोलिटिकल एजेंट का पत्र दिनांक ४-३-१८४७ । संबंधित सामग्री (राज० रा० पु० मण्डल) ।

४४. अजमेर फाइल क्रमांक ४८ ए २ चीफ-कमिश्नरी द्वारा सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट (राज० रा० पु० मण्डल) ।

४५. बीकानेर सरकार, फाइल क्रमांक पी० ४ (३) २१-ए-२ मेरवाड़ा संबंधी दावे और प्रतिनिधित्व (राज० रा० पु० मण्डल) ।

४६. फाइल क्रमांक १११० सन् १८७३ । सन् १८३४ में हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) ।

४७. उपरोक्त ।

४८. मेरवाड़ा के वृत्तांत की रूपरेखा फाइल क्रमांक १११० (राज० रा० पु० मण्डल) ।

४९. डिक्शन, स्केच ऑफ मेरवाड़ा (१८५०) पृष्ठ ३५-४२ ।

५०. फाइल क्रमांक १११० । सन् १८३४ में कंस्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) ।

५१. फाइल क्रमांक १११० सन् १८३४ में केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) ।
५२. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स अजमेर—मेरवाड़ा, खंड १ ए (१६०४) पृष्ठ १३-१७ ।
५३. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स अजमेर—मेरवाड़ा खंड १ ए (१६०४) पृष्ठ १३-१७ ।
५४. डिकसन-स्केच ऑफ मेरवाड़ा, (१८५०) पृष्ठ ८२ ।
५५. उपरोक्त पृष्ठ ८२-८४ ।
५६. फाइल क्रमांक १११०, राजपूताना रेजीडेन्सी कार्यालय चीफ-कमिशनर शाला, जेल फाइल क्रमांक १४५३ (राज० रा० पु० मण्डल) ।
५७. चीफ-कमिशनर कार्यालय, फाइल क्रमांक १११०, मेरवाड़ा की रूपरेखा (१८५०) पृष्ठ ८४-८८ ।
५८. उपरोक्त ।
५९. चीफ-कमिशनर कार्यालय फाइल क्रमांक १११०—स्केच ऑफ मेरवाड़ा, डिकसन पृष्ठ ८४ से ८८ । (राज० रा० पु० मण्डल) ।
६०. फाइल क्रमांक ए (१) पुरानी १८ मेरवाड़ा के सामान्य मामले फाइल क्रमांक १११० सन् १८७३ । केप्टिन हॉल द्वारा दिसम्बर १८३४ में प्रस्तुत रिपोर्ट तथा उसके आधार पर तैयार विवरण (राज० रा० पु० मण्डल) स्केच ऑफ मेरवाड़ा—डिकसन (१८५०) पृष्ठ १३-२८ ।
६१. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स भाग १ ए, अजमेर-मेरवाड़ा (१६०४) पृष्ठ १३ ।

## अजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन

अंग्रेजों द्वारा अजमेर-मेरवाड़ा का प्रशासन सीधा अपने हाथ में सम्भाल लेने के बाद भी जिले की तत्कालीन क्षेत्रीय सीमाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। एकमात्र परिवर्तन यह हुआ कि सन् १८६० में सिंधिया से अंग्रेजों की संधि के अनुसार इस क्षेत्र में पाँच गाँव और जोड़ दिए गए। कूलिया का परगना जो कि अजमेर का ही भाग था परन्तु शाहपुरा के राजा के पास था, उसे अंग्रेजों ने सन् १८४७ में अपने अधिकार में ले लिया था और इस तरह शाहपुरा का अजमेर में सम्मिलन निश्चय हो गया। मेरवाड़ा के वे गाँव जो अंग्रेजों ने जीतकर १८२३ में अजमेर में मिला लिए थे उन पर अंग्रेजों का सीधा प्रशासन उसी रूप में बना रहा। मेरवाड़ा के सात गाँव जो अंग्रेजों के प्रशासन को सौंपे गए थे उनमें भी किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।<sup>१</sup>

### प्रारम्भिक काल (१८१८-१८३२)

अजमेर, अंग्रेजों के प्राधिपत्य में आ जाने के बाद, विल्डर की वहाँ प्रथम सुपरिण्टेण्डेंट नियुक्त किया गया। इसके पूर्व विल्डर दिल्ली के रेजीडेंट के सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे।<sup>२</sup>

उन्होंने २६ जुलाई, १८१८ के सिंधिया के अधिकारियों से अजमेर का कार्यभार समाला। अंग्रेजों ने अजमेर नगर को एकदम वीरान पाया। मेरवाड़ा व

पिहारियों के अत्याचारों और दमन के कारण इसकी हालत अत्यन्त दयनीय हो गई थी।<sup>४</sup> उन दिनों अजमेर आठ परगनों में विभाजित था, जिसके अन्तर्गत ५३४ गाँव थे और ३६ लाख बीघा (पक्का) कृषि भूमि थी। भूमि यद्यपि बालुई थी, तथापि भरपूर उपजाऊ थी, जिसमें खरीफ और रबी की दोनों फसलें होती थीं। कोई भी गाँव बिना कुएँ के नहीं था। इन कुओं का पानी भी पन्द्रह बीस हाथ से अधिक गहरा नहीं था। इन कुओं का जल, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में पीने योग्य नहीं था तथापि सिंचाई के लिए पूर्णतया उपयुक्त था। लगभग सभी जमींदार राठौड़ थे, केवल कुछ ही जमींदार पठान, जाट, मेर और चौता थे। मेर और चौता जिले के एक छोर पर रहते थे। ईसा क्षेत्र में एक लम्बे समय तक अशांति बने रहने के कारण यहाँ की जनसंख्या काफी घट गई थी। शान्ति की स्थापना होते ही दूसरी रियासतों में शरण पाने के लिए गए हुए लोग तेजी से अपने घरों को लौटने लगे। लोगों में विश्वास पुनर्जागृत हो जाने के फलस्वरूप कृषि में भी काफी वृद्धि हुई और पुनः समृद्धि के संकेत दृष्टि-गोचर होने लगे।<sup>५</sup>

विल्डर के समय सबसे बड़ी कठिनाई इस क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न मुद्राओं के कारण उत्पन्न हुई। कम्पनी के सिक्के केवल जयपुर तक ही प्रचलित थे, इससे प्रागे दक्षिण में उनका चलन नहीं के बराबर था। देशी ६ टकसालें मुख्यतः ऐसी थीं जिनके सिक्कों का प्रचलन अजमेर में था। इन टकसालों के लिए चादी सूरत और बम्बई से आयात होती, और पाली के माध्यम से इन टकसालों को मिला करती थी। अजमेर की टकसाल अकबर के समय से ही चालू थी और प्रतिवर्ष डेढ़ लाख के लगभग सिक्के वहाँ डाले जाते थे। ये सिक्के शेरशाही कहलाते थे। किशनगढ़ी रुपया जो किशनगढ़ टकसाल में डलता था पिछले पचास वर्षों से प्रचलित था, यद्यपि कभी-कभी अजमेर-शासकों के हस्तक्षेप के कारण इसे बंद कर दिया जाता था। कुचामनी रुपया कुचामन के ठाकुर द्वारा जोधपुर रियासत की आज्ञा के बिना ही डाला जाता था। जोधपुर के तत्कालीन नरेश उन दिनों इतने असमर्थ थे कि वे इस पर रोक नहीं लगा सके। शाहपुरा टकसाल को भी काम करते हुए ७० वर्ष हो चले थे, यद्यपि उदयपुर के महाराजा ने इसे बंद करने की कई बार कोशिशें की थी। चित्तौड़ी रुपया मेवाड़ का प्राग्यता प्राप्त सिक्का था। भाड़शाही सिक्का जयपुर की टकसाल में डलता था। विल्डर ने विभिन्न मुद्राओं की इस समस्या के निवारणार्थ यह नियम लागू किया कि सरकारी राजस्व फरूखाबादी सिक्कों में चुकाया जाय। इस्तमरारी क्षेत्रों के राजस्व की राशि जो शेरशाही सिक्कों में होती थी, ६ प्रतिशत का "बाध" देकर फरूखाबादी सिक्कों में बदली जा सकती थी। इसके फलस्वरूप अत्येक ठिकाने के राजस्व का हिसाब रुपये-घाना-पाई में प्रचलित हो सका।<sup>६</sup>



मेरवाड़ा क्षेत्र के पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो जाने के बाद मेरवाड़ा को विल्डर ने ६ परगनों में विभाजित किया। चार परगने जो अंग्रेज सरकार की सधि के अंतर्गत सीपें गए वे अजमेर के अंग बनने। मेवाड़ के हिस्से में तीन परगने टाडगढ़, दवेर और सारोठ रहे तथा मारवाड़ के हिस्से में दो परगने चाग और कोटकिराना आए। इस विस्तृत भूभाग के प्रशासन के लिए तीन प्रमुख भारतीय अधिकारी नियुक्त किए गए। पुलिस का काम अपने कार्यों के अतिरिक्त राजस्व वसूली भी था। दवेर, टाडगढ़, भापला और कोटकिराना की राजस्व वसूली टाडगढ़ के तहसीलदार को सौंपी गई। इनमें घाठ गांव ये और कुल १३ ठाणिया थीं। उन दिनों तहसीलदार ही अपने जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी भी होता था। सारोठ के तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में सारोठ बरार और बर काकड़ के परगने थे। इसके अन्तर्गत ५१ गांव और ठाणिया थीं। उत्तरी भूभाग व्यावर, भाक और श्यामगढ़ के परगने थे इनमें कुल १०६ गांव और ८५२ ठाणिया थी। इस क्षेत्र के लिए तीसरे तहसीलदार की नियुक्ति की गई थी।<sup>१६</sup> सन् १८२४ में विल्डर का स्थानान्तरण कर दिया गया था। अजमेर मेरवाड़ा में इनके प्रशासन के ६ वर्ष कोई विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुए। प्रांत के किसी भी विभाग में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। कई पुरानी प्रशासनिक अनियमितताएं विशेषकर राजस्व एवं चुगी विभाग में पचावत रहीं।

विल्डर ने ज़िम भूमि का बन्दोबस्त किया उसकी न तो कीमत मांकने की कोशिश की और न लोगों की स्थिति समझने का प्रयत्न ही किया। उसकी असफलता का प्रमुख कारण प्रत्यक्ष कार्यभार और अन्यत्र व्यस्त रहना था। वह अजमेर के सुपरि-टेंडेंट होने के साथ जोधपुर अंजलमेर और किशनगढ़ का पोलिटिकल एजेंट था।<sup>१७</sup> केवल इतना ही नहीं उसे प्रशासनिक कार्यों के लिए पूरे कर्मचारी भी प्राप्त नहीं थे। विभागों में कर्मचारियों का भारी अभाव था। अग्रपूर्ण जिले का राजस्व तथा पुलिस विभाग का कुल वेतन सर्व प्रति माह १३७४ रुपये था जो विल्डर के मासिक वेतन तीन हजार रुपये के भापे से भी कम था। भारत सरकार ने प्रशासन को विकसित करने के लिए उन्हें निर्देश व निर्धारित नियम भी प्रदान नहीं किए। यहाँ तक कि एक दफा उन्होंने कलकत्तामंत्र की प्रति चाही तो उन्हें इकार कर दिया गया।<sup>१८</sup> वर्षों के बाद एक अंग्रेज सहायक अजमेर के लिए नियुक्त किया गया। विल्डर ने अजमेर के लोगों को पुनर्वास में काफी योगदान दिया। उसने व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को अजमेर में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए उसने देश के कोने-कोने से व्यापारियों को अजमेर में बसने के लिए आमन्त्रित किया। इतना ही नहीं उसने कई व्यापारियों और सेठों को सिपायियों पत्र दिए। इन न्यायाधीशों और दंडनायकों से प्रार्थना की गई थी कि वे इनको बकाया राजि की वसूली में सहायता दें।<sup>१९</sup>

श्री हेनरी मिडलटन ने विल्डर की कार्य निवृत्ति के बाद अजमेर का पदभार सम्हाला। मिडलटन के समय में प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। अक्टूबर, १८२७ में मिडलटन के स्थान पर श्री केवेंडिश की नियुक्ति हुई। श्री केवेंडिश ने कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए और प्रशासन की व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनके अधिक प्रयत्न के फलस्वरूप इसमरार, भीम और जागीर बन्दोबस्त किया जा सका। १८३२ में केवेंडिश के स्थान पर मेजर स्वेयर्स की नियुक्ति हुई।

**द्वितीय चरण (१८३२-४६) अजमेर जिला पश्चिमी सूबे में अन्तर्गत—**

सन् १८३२ में अजमेर जिले की उत्तर-पश्चिमी सूबे के अन्तर्गत ले लिया गया। सन् १८३७-३८ से लेकर १८४०-४१ तक के चार वर्ष अजमेर के लिए भारी विपदा के वर्ष रहे। कर्नल मडरलैंड के समय में लोगों की हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी, एक तो वर्षा न होने से अकाल की स्थिति हो गई थी, दूसरे प्रशासन अपने उद्देश्यों में बुरी तरह अमरुत सिद्ध हुआ था। सगान की सख्ती के कारण पाँच सौ परिवारों ने अजमेर जिले से पलायन कर दिया था क्योंकि उनकी सामर्थ्य इतना सगान चुकाने की नहीं थी<sup>१०</sup>। मरम्मत के अभाव में बाँधों के समूह लालाब वर्षों से टूटे पड़े थे। कुएँ बिना मरम्मत के बह गए थे। लोगों का आत्मविश्वास इतना टूट चुका था कि कृषि विकास के नाम पर कोई भी किसी को श्रम देने को तैयार नहीं था। किसान एडमस्टन के प्रस्तावित कम सगान की अपेक्षा फसल का आधा हिस्सा देना अच्छा समझते थे<sup>११</sup>। घरों की हालत बीरान खड्गरो जैसी हो चली थी। कमिश्नर के मतानुसार सम्पूर्ण खालसा क्षेत्र गरीबी की चपेट से जकड़ा हुआ था जबकि ताबुकेदारों की जमींदारियाँ इनके मुकाबले में कहीं अधिक अच्छी अवस्था में थीं।<sup>१२</sup>

अजमेर जिले में जिस तरह के प्रशासनिक प्रयोग किए गए, उनका परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण रहा। राजस्व बमूली घटते-घटते इस सीमा तक पहुँच गई थी कि मराठों को प्राप्त राजस्व जितनी भी नहीं रही। श्री विल्डर ने ग्राम के स्त्रियों का वास्तविकता से अधिक अनुमान लगा लिया था। इस प्रारम्भिक भूल के कारण विल्डर और मिडलटन द्वारा किया गया बन्दोबस्त अच्छे वर्षों में किए जाने वाले बन्दोबस्त से भी कहीं अधिक बड़ चूड़ कर था। एडमस्टन का बन्दोबस्त जो इन तीनों में सबसे कम था, वह भी फसल के आधे हिस्से की बमूली का था। परन्तु फसलों में दोनों ही फसलों शामिल थी, अतएव एक न एक फसल चौकट होने की स्थिति के कारण यह व्यवस्था बुरी तरह से असफल रही। प्रति सिंचित एकड़ भूमि पर ३१ प्रतिशत के अनुसार ३६ रुपये का राजस्वभार था जो १८३३ के रेगुलेशन ६ के अन्तर्गत उत्तर-पश्चिमी सूबे के लिए निर्धारित लगान की दर से कहीं कम था। अजमेर में लागू

किया गया दम्नोवस्त साधारण नहीं था, घोर खोखो को भारी कष्ट में डाले बिना इसकी वसूली संभव नहीं थी।

दाशनिक करावान व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी, क्योंकि व्यक्तिगत निर्धारित देय की वसूली की उचित व्यवस्था नहीं थी। पुरानी व्यवस्था के स्थान पर, जिसके अन्तर्गत पटेल और पटवारी हर किसान से फसल का प्राधा भाग वसूल किया करते थे, समुक्त जिम्मेदारी के सिद्धान्त को लागू किया गया था। परन्तु यह व्यवस्था अत्यन्त सिद्ध हुई क्योंकि प्रत्येक किसान से उसकी भूमि के आधार पर निर्धारित लगान सरकार द्वारा वसूल कर लेने पर उसके पास भरण-पोषण जितना भी नहीं बच जाता था<sup>१३</sup>।

फरवरी, १८४२ में मेजर डिवसन को भजमेर का सुपरिन्टेन्डेंट नियुक्त किया गया। इस पद के प्रतिरिक्त उनके पास मेरवाड़ा के सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा मेरवाड़ा बटालियन के कमांडर का कार्यभार भी था। इनके कार्यभार सम्हालने के साथ ही भजमेर के प्रशासनिक इतिहास में एक नये युग का आरम्भ हुआ। प्रागामी ६ वर्षों के दौरान ४,५२,७०७ रुपयों की राशि तालाबों, बांध और इनकी मरम्मत पर व्यय की गई। कृषि विकास के लिए किसानों को अधिम राशि दी गई तथा डिवसन अपने व्यक्तिगत उत्साह के कारण किसानों की प्रोत्साहित करने में सफल हुए। सरकार को इन कामों से लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से भी ऐसे गाँवों को जो अपनी जगह से नये बाँधों के समीप यत्नवा चाहते थे अनुमति प्रदान की गई।<sup>१४</sup>

**डिवसन की उपलब्धियाँ—**

सन् १८४२ का वर्ष भजमेर के प्रशासनिक काल की विभाजक रेखा माना जा सकता है। इसी वर्ष कर्नल डिवसन मेरवाड़ा के साथ-साथ भजमेर के भी सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हुए। उनकी सेवाओं का सम्पादन करने के दृष्टिकोण से सरकार ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे उत्तरी-पश्चिमी सूबे के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार कर सकते थे तथा दोनों जिलों का सम्पूर्ण अर्थनिक प्रशासन उनके अधीन रख दिया गया था। इन तरह वे सीधे लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे और भजमेर मेरवाड़ा के प्रति ए० जी० जी० उतने ही उत्तरदायी रह गये जितने कि वे राजपूताना की रियासतों के बारे में थे। इस तरह के परिवर्तन से केवल दोनों जिलों का विनय ही नहीं हुआ बल्कि दोनों जिलों के सामान्य प्रशासन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। इस तरह सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद और अधिकारों में भी वृद्धि हुई और उसका सीधा सम्पर्क लेफ्टीनेन्ट गवर्नर से हो गया<sup>१५</sup>।

अपने वर्तमान पदभार के प्रतिरिक्त मेरवाड़ा बटालियन की कमान भी इन, १८५७ तक डिवसन के हाथों में रही। व्यापक निर्वाचन में उनकी वज्र आज भी मेरों के लिए अज्ञातस्वती है और काफी लोग वहाँ जाकर मनीषी मानते हैं। मेरों ने

इस उदार अधिकारी की सेवाओं की स्मृति को आज तक याद रख छोड़ा है। परकोटे से धीरे-धीरे शहर का निर्माण डिक्सन की देन थी और संभवतया भारत में डिक्सन ही अन्तिम अंग्रेज थे जिन्होंने परकोटे वाले किसी शहर का निर्माण कराया हो। डिक्सन के देहावसान के साथ ही भजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासनिक इतिहास का द्वितीय चरण समाप्त होता है। यह समय भजमेर-मेरवाड़ा के लिए भौतिक विकास का चरण था और केवल इसी काल में संभवतया पहली बार निर्धारित लगान वसूल हो सका।<sup>१४</sup>

सन् १८४८ तक भजमेर के सरकारी आय-व्यय का निरीक्षण कलकत्ता से हुआ करता था परन्तु १८४९ के बाद भजमेर के आय-व्यय का निरीक्षण आगरा में होने लगा। गवर्नर जनरल की यह मान्यता थी कि भजमेर जिला, स्पष्टतया नागरिक प्रभार होने से इसे उत्तर-पश्चिमी सूबो के लेफ्टिनेंट-गवर्नर के अधीन रखना लाभप्रद होगा। इन दिनों कर्नल डिक्सन का मोहडा कमिश्नर स्तर तक उन्नत कर भजमेर जिले का प्रशासन सीधा लेफ्टिनेंट के नियन्त्रण में रख दिया गया था। डिक्सन की प्रशालतों से सभी न्यायिक अपीलें भविष्य में आगरा में होने लगीं। इससे पूर्व ये अपीलें राजपूताना के ए० जी० जी० सुना करते थे।<sup>१५</sup>

U. U. CEN

तृतीय चरण (१८४८-६९)

सन् १८४८ तक ए० जी० जी० भजमेर के कमिश्नर हुआ करते थे तथा सुपरिंटेंडेंट उनके अधीन कार्य करते थे। इस समय तक भजमेर जिला स्पष्टतया गैर नियमन्त्रित था। जिले से सरकार को राजस्व की केवल वार्षिक रिपोर्ट ही प्रस्तुत हुआ करती थी। ब्रिटिश कानून न तो यहाँ लागू ही किए गए थे और न यह सदर न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में था। १८५३ में कर्नल डिक्सन की नियुक्ति कमिश्नर के पद पर की गई व ए० जी० जी० को भजमेर के प्रशासन-कार्य से मुक्त कर दिया गया।<sup>१६</sup> १८५३ के पहले, भजमेर मेरवाड़ा के अधिकारी सुपरिंटेंडेंट कहलाते थे और ये दिल्ली के रेजीडेंट के अन्तर्गत थे, बाद में मालवा-राजपूताना के रेजीडेंट के तहत रहे और सन् १८३२ के बाद इन्हें कमिश्नर के अन्तर्गत रखा गया।<sup>१७</sup> भजमेर-मेरवाड़ा को राजस्व सदर बोर्ड के अन्तर्गत लेने में किसी तरह के विशेष आदेश नहीं पारित हुए। परन्तु अन्तिम वर्षों में यह स्वतः धीरे-धीरे उस कार्यालय के नियन्त्रण में चला गया। सन् १८६२ में न्यायिक सेवाओं और पुलिस विभाग को पृथक् कर दिया गया। उत्तर-पश्चिमी सूबे में प्रचलित सभी कानून धीरे-धीरे भजमेर मेरवाड़ा में भी लागू किए गए। इन वर्षों में भजमेर-मेरवाड़ा भी नियमन्त्रित प्रान्त में शुमार किया जाने लगा।<sup>१८</sup> सन् १८५८ में भजमेर व मेरवाड़ा को मिलाकर एक जिला कर दिया गया तथा उसे डिप्टी-कमिश्नर के अधीन रखा गया। ए० जी० जी० को भजमेर का कमिश्नर का पद

भी प्रदान किया गया था और कमिश्नर के कार्य के लिए उसे उत्तर-पश्चिम सूबे (एन. डब्ल्यू. पी.) के अधीन रखा गया।<sup>२१</sup> ए. जी. जी. रात्रस्व कमिश्नर, सेशन कोर्ट के न्यायाधीश व सिविल कोर्ट के जज भी त्रिभुवन से काम करते थे। सामान्य प्रशासनिक मामलों में वे उत्तर-पश्चिमी सूबे की सरकार के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के प्रति उत्तरदायी थे।<sup>२२</sup>

प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टन जे. सी. ब्रुक्स के अनुसार भ्रजमेर और रात्रगढ़ परगने के किसानों की स्थिति रामसर के किसानों से अच्छी थी। रामसर के किसान सामान्यतः बहुत गरीब थे। श्री ब्रुक्स को भी अपने पूर्वाधिकारियों की भांति उन सभी बाधाओं से सवर्ण करना पड़ा। क्षेत्रीय समस्याओं का निवारण पहले की तरह ही जटिल बना रहा। जिलों में मवेशियों का व्यापक अभाव हो चला था। सन् १८४८ के भीषण अकाल ने क्षेत्र को एक तरह से भूकम्प से झटका दिया था। हजारों की संख्या में मवेशी जो निकटवर्ती क्षेत्रों में चरने के लिए ले जाए गए थे, नष्ट हो गए। त्रिभुवन इस भयंकर क्षति की पूर्ति आसानी से नहीं कर सका। खाद की इतनी भारी कमी हुई कि तालाबों के पेटे में जमी मिट्टी ही खाद के रूप में काम में ली जाने लगी। इस दिशा में मेरवाड़ा की स्थिति दूसरे जिलों की अपेक्षा कुछ अच्छी रही। बन्दोबस्त के बाद टाउनशप परगने में अफीम की खेती काफी अधिक मात्रा में बढ़ चली थी। परन्तु नयानगर शहर के आसपास के किसानों की हालत दयनीय ही थी।<sup>२३</sup>

इनके प्रतिरिक्त और भी कई कठिनाइयां पैदा हो चली थीं जिससे लगान वसूली में बाधा होने लगी। पटवारियों के कागजात खाली बन्दोबस्त रैकार्ड की नकलें मात्र थे। प्रायः किमान यह मान कर चलता था कि उसका लगान निर्धारित है और लगान नहीं चुकाने वालों के स्थान पर घाटे की पूर्ति किसानों से करने की व्यवस्था को वे अन्यायपूर्ण समझते थे। मेरवाड़ा में अधिकांश सिपाहियों में लगान की रकम बकाया चली आ रही थी। जहाँ बन्दोबस्त कठोर था वहाँ वे लोग जमीन जोतने की मेहनत से भी चुराया करते थे। कर्नेल डिक्सन जो मेरवाड़ा बटालियन के कमांडर और जिले के सुपरिंटेंडेंट भी थे सिपाहियों का बकाया लगान उनके बैतन से काट लिया करते थे। परन्तु जब वे कमांडर और सुपरिंटेंडेंट के पद पृथक् कर दिए गए, तब यह दुहरी व्यवस्था संभव नहीं रह सकी।<sup>२४</sup>

उन दिनों जिस किसान की फसल नष्ट हो जाती वह अपना निर्धारित लगान इधर-उधर से कर्ज लेकर चुकाता था। बन्दोबस्त के बाद लगान न चुकाने वालों की सेवा राशि की सन्निधि के लिए गाँव मजदूर में राशि के जमाखान की प्रक्रिया समाप्त करा दी गई थी। सम्मिलित जोनों से प्रायः सम्बन्धी हिसाब नहीं रक्ते जाते थे और सरकार से बकाय के दिनों में प्राप्त सहायता की राशि सारे गाँव द्वारा काम में भी जाती थी। फलस्वरूप उन लोगों को बहुत कम राशि मिल पाती थी

जिन्हें वास्तविक सहायता की जरूरत होती थी। पटवारियों को नाममात्र का वेतन मिलता था और वे गांवों में लोगों को सूद पर कर्जा देने का काम किया करते थे। कैप्टन ब्रुकस ने पटवारियों के सेवा-निर्माणों में परिवर्तन किया था। सरकारी खजाने पर भार डाले बिना पटवारियों को भी अच्छा पारिश्रमिक मिल सके इस भावसे उन्होंने उनके क्षेत्र व हसकों का विस्तार किया और प्रत्येक पटवारी के अन्तर्गत आने वाले छोटे-छोटे गांवों की गणना दुगुनी कर दी।<sup>२४</sup>

डिप्टी कमिशनर मेजर लॉयड ने तो सन् १८६० में सम्पूर्ण क्षेत्र का व्यापक दौरा कर अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र की सामान्य स्थिति तथा क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक व अविलम्ब कार्यवाहियों के बारे में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने सन् १८४६ से लेकर १८५१ तक अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र की स्थिति का १८६० की स्थिति के साथ तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। मेजर लॉयड के अनुसार "जिने की स्थिति में दिनों-दिन तेजी से सुधार होता जा रहा था। वे क्षेत्र जहाँ झाड़ियाँ व छिनराए हुए जंगल थे वहाँ अब लह-लहाते खेत तजर्र आने लगे थे। नये-नये भवनों का निर्माण तीव्रगति से हो रहा था।"<sup>२५</sup>

सन् १८६६ में डिप्टी कमिशनर ने लगान वसूली की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी लगान पटेलों के माध्यम से वसूल करने के आदेश जारी किए गए। इसके पहले प्रत्येक किसान से लगान अलग-अलग वसूल किया जाता था। यह वसूली वास्तव में तम्बरदार के माध्यम से होती थी जिसे तहसील का चपरासी मदद करता था। यह प्रक्रिया साधारणतया भ्रष्टाचारी अवस्था लगती है परन्तु किसानों के अनुकूल होने के कारण यह चल निकली थी।<sup>२७</sup>

**अंग्रेज-प्रशासन की लोकप्रियता :**

सन् १८१८ से लेकर १८६६ तक के अजमेर के सम्पूर्ण प्रशासन को असफल ठहराया उचित नहीं होगा। इस काल में कर्नल हॉल और कर्नल डिवसन के प्रयासों से जनता को लूटपाट से काफी हद तक छुटकारा मिला व मेरों को कृषि प्रधान व शान्तिप्रिय बनाने में सरकार की सफलता मिली। मेर-बटालियन ने इस काम में सरकार की बहुत मदद की। मेर-बटालियन केवल पुलिस निगरानी ही नहीं बल्कि सैनिक गार्ड का काम सम्हालने के भी योग्य हो गई थी। दोनों जिलों में जो तालाब व बंधेबांधे गए उनसे भी क्षेत्र की समृद्धि की बल मिला। यद्यपि सरकार द्वारा लगान वसूली प्रतिवर्ष एक सी दर पर नहीं हो पाई। वर्षापण के आदेशों के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई उसके अनुसार जमीन पर किसान का कच्चा स्वीकार किया गया तथा प्रत्येक गांव के लिए बीस वर्षों की अवधि के लिए साधारण लगान की दरें निर्धारित की गई थीं। व्यवस्था की इस नई प्रक्रिया में क्षेत्र के किसानों को

जमींदारों व सरकारी अधिकारियों की मनमानी व शोषण से मुक्ति मिली और वे लोग अपने थम व उथम का लाभ उठाने में समर्थ हो सके। जिले का पुलिस-प्रशासन अन्य प्रान्तों के प्रशासनो के आधार पर गठित किया गया। छोटे बहुत उत्पात कुछ जमींदारों ने भ्रवश्य किए जिनका सदेहास्पद सम्बन्ध झाकुंधों और चोरो से था, अन्यथा भारे क्षेत्र में शांति बनी रही। बेल अनुशासन अच्छा था। एक कालेज की स्थापना की गई और गाँवों में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। इन सभी प्रशासनिक विभागों में विभागीय अध्यक्षों द्वारा वार्षिक निरीक्षण तथा रेवरेण्ड की समुचित व्यवस्था की गई थी।<sup>३८</sup>

भजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन को जिनो में कातून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत होने तथा भजमेर शहर में कई विभिन्न क्षेत्रों से उरुमाहूट और तनाव का संकट पैदा होने पर भी जून, १८५७ से मार्च, १८५८ तक शांति बने रहने से बल मिला। यही तक कि इस संकट की परिस्थिति में भी भजमेर के कमिशनर की कचहरी प्रतिदिन सगा करती थी और व्यापार निर्विघ्न जारी था।<sup>३९</sup>

भजमेर-मेरवाड़ा के निवासियों के इस तरह के शांतिप्रिय और राजभक्त स्वभाव की सराहना भजमेर के कार्यवाहक डिप्टी कमिशनर कंस्टिन ब्रूकस,<sup>४०</sup> भजमेर के सहायक कमिशनर लेफ्टिनेन्ट बाल्टर,<sup>४१</sup> कार्यवाहक सहायक कमिशनर (ब्यावर) एवं लेफ्टिनेन्ट विपवे<sup>४२</sup> ने अपनी रिपोर्टों में की थी। ब्रिगेडियर जनरल पी. लॉरेंस ने पटनाधी की जो रिपोर्टें प्रेषित की थी उसमें यह घाणा उन्होंने व्यक्त की कि इस जिले द्वारा राजभक्ति का जो परिचय दिया गया उसही बाबतसराय तथा भारत सरकार सराहना करेगी<sup>४३</sup>। अपनी रिपोर्ट के साथ जिले में घटित अपराधों की जो सूची उन्होंने भेजी उसमें बहुत कम सगीन अपराधों का उल्लेख था। राजनीतिक उदल-गुदल के वर्ष में इतने कम अपराधों की घटनाएं जिले की प्रशासनिक स्थिरता पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। मेरों ने १८५७ के विद्रोह की घटनाओं के घटने ही यह टुड़ निश्चय कर लिया था कि वे अपने यहाँ आंतरिक उत्पात और अपराधों पर कड़ी निगाह रखेंगे। जिले के केन्द्रस्थल मसीराबाद में भारतीय सैनिकों की एक पूरी ब्रिगेड द्वारा किल्ले और कनिष्य अन्य विद्रोही पसतनों द्वारा कूच करते समय राह में पड़ने वाले गाँवों के विद्रोह के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं का हड़ता से पालन किया। सन् १८५५, १८५६ तथा १८५७ में सगीन जुर्म और अन्य अपराध क्रमशः २०१६, १४७७ तथा १५०७ रहे। १८५६ के मुकाबले में १८५७ में अपराधों में नाममात्र की ही वृद्धि हुई जबकि १८५५ के अपराधों की तुलना में सन् ५७ में अपराधों के आँकड़े बहुत कम थे।<sup>४४</sup>

पंखों के घनीय भजमेर-मेरवाड़ा का प्रशासन जैसा अच्छा होता चाहिए था नैमा नहीं था। प्रशासन के किनी भी विभाग का कार्य इनका अच्छा नहीं था :

कि यह पड़ोसी रियासतों के लिए आदर्श बन सकता।<sup>३४</sup> यदि अजमेर के लोगों ने खुले विद्रोह में भाग नहीं लिया तो इसका श्रेय अजमेर के प्रशासन को नहीं दिया जा सकता। इसका मुख्य कारण जिले के लोगों का राजनीतिक पिछड़ापन था।

अंग्रेजों के प्रशासन-तंत्र की कमजोरियाँ

प्रशासन के बहुत घट्ठा नहीं होने के कई कारण थे।—अजमेर चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा विस्तृत मैदानी भूभाग है। इसके दक्षिण में स्थित मेरवाड़ा सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ तक कि कई गाँवों में तो बैलगाड़ी का पहुँचना भी असंभव था। बालू घाटियों में ही खेती की जाती थी। कर्नल डिकसन ने अधिकतर जलाशय इसी पहाड़ी क्षेत्र में बनवाए थे। इनमें से कुछ जलाशयों तक पहुँचने का मार्ग ही नहीं था। वहाँ केवल पैदल चलकर पहुँचा जा सकता था।

इसके प्रतिरिक्त मेरवाड़ा जिले का एक बड़ा भूभाग अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था। यह अत्यन्त ही असतोषजनक ढंग से कुछ अवधि के लिए पट्टे पर लिया हुआ क्षेत्र था। लोगों की बोली और रहन-सहन उत्तर-पश्चिमी सूबों की अपेक्षा गुजरात के अधिक निकट थी। फिर भी इन जिलों को उत्तर-पश्चिमी सूबों के अन्तर्गत रखा गया। सबसे बड़ा असतोष इस क्षेत्र में वहाँ की सरकारी भाषा फारसी को लागू करने के कारण पैदा हुआ। यह भाषा लोगों के लिए अंग्रेजी की तरह ही मुश्किल थी। फारसी जुमलो का सरकारी दस्तावेजों में खूब प्रयोग किया जाता था जिससे वाक्य के वाक्य लोगों को सुनने पर भी अर्थहीन लगते थे। इसलिए इनमें उसके प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था।<sup>३५</sup>

कर्नल हॉव और कर्नल डिकसन की सफलता का कारण उनके द्वारा अपनाए गए विशेष प्रयास थे, जिनका सामान्यतया प्रशासन में अभाव पाया जाता है। इन दोनों ने प्रत्येक कार्य में जिले की आवश्यकता को प्राथमिकता दी थी। प्रशासन इनको नकल नहीं सका था। ये दोनों पत्राचार की परिपाटी में भी ज्यादा नहीं उतरते थे तथा सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा का भी खूब प्रयोग करते थे। केन्द्रीय सरकार के कठोर नियन्त्रण के अभाव के कारण भी इनको काम करने की व्यापक छूट मिली हुई थी। इसलिए इनको सफलता मिलना स्वाभाविक था। अपनी पहल व उत्साह से इन दोनों अधिकारियों का प्रशासन लोकप्रिय सिद्ध हुआ। दोनों जिलों के छोटे होने से भी जनता को विजेय प्रशासनिक अनुविधा नहीं होती थी।<sup>३६</sup>

आगे चलकर अब अजमेर और भाँसी जिलों के अधिकारियों का एक ही सूची में समावेश किया गया तो उसके बड़े ही खराब परिणाम निकले। अजमेर के रेलमार्गों तथा हिमालय के ठंडे स्थलों से बहुत दूर होने के कारण प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों के व्यक्तिगत निरीक्षण से यह बहुत कुछ भ्रूना रहा। इनके प्रतिरिक्त यह जगह भाँसी की अपेक्षा इतनी अधिक खर्चीली थी कि अन्धे अधिकारी यहाँ



पर अपनी नियुक्ति या निरोक्षण को सदा ठालने के प्रयत्न में रहते थे<sup>३८</sup> । यहाँ के अधिकारियों का अल्प वेतन भी इस क्षेत्र की उपेक्षा का एक कारण था । कर्नल डिवसन, जिन्होंने जिले की व्यवस्था व यहाँ की आर्थिक स्थिति का विशेष अध्ययन किया था, दुर्भाग्य से प्रशासन सेवा में अल्प वेतन रखने के पक्ष में थे जबकि इसके विपरीत कैप्टन ब्रूक्स की मान्यता थी कि इस क्षेत्र में जिला अधिकारियों के अधिक स्वतंत्रता से काम करने में उनका अल्प वेतन बड़ा ही बाधक है ।<sup>३९</sup> इस पूरे काल में सरकार ने विकास कार्यों के बजाय आर्थिक कटौती पर ज्यादा ध्यान दिया । जिन गाँवों के लोगों ने सरकारी अध्यापकों को वेतन मुमनान के लिए राशि देने में आनाकानी की, वहाँ स्कूल बन्द करने के आदेश दिए गए ।<sup>४०</sup> इसके अलावा कमिश्नर के यहाँ स्थाई रूप से रहने के कारण प्रशासन में और भी शिथिलता आ गई थी । कमिश्नर इस जिले के डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट के ग्यायाधीश भी थे । उनके एक साल अधिक समय तक भजमेर में नहीं रह पाने के कारण मृत्यु दंड के अपराधियों को फैसले के अभाव में लम्बे समय तक हवालाती कंड़ी बने रहना पड़ता था । उनको अपने निर्णय के लिए सेशन कोर्ट की बैठकों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । जिले की सबके और यातायात अत्यन्त ही पिछड़ी हालत में था । क्षेत्र की समृद्धि के आधार बोध व जलाशय परम्परा के अभाव में सदा ही दहते रहते थे ।<sup>४१</sup>

सरकार ने कर्नल डिवसन को जब कमिश्नर नियुक्त किया था तब इसके पीछे केवल उनकी भूतपूर्व सेवाओं की सराहना का ही दृष्टिकोण नहीं था, अपितु प्रशासनिक आवश्यकता भी प्रमुख रही थी । कमिश्नर का पद ए०जी०जी० से भ्रूलत करने का उद्देश्य ए०जी०जी० को दैनिक प्रशासन के व्यस्त कार्यभार से, जिनमें उनका अधिराज समय नष्ट हुआ करता था, मुक्त करना था । कर्नल डिवसन को कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर उन्हें नागरिक प्रशासन के सम्पूर्ण काम सौंप दिए गए थे । दैनिक प्रशासनिक कार्यभार के कारण पहले ए. जी. जी. का काफी समय तक भजमेर से निकलना ही नहीं हो पाता था । इस कारण राजपूताना की रियासतों से सम्बन्धित राजनीतिक कामकाज के लिए समय निकालना उनके लिए कठिन हो गया था । नई व्यवस्था के अनुसार जहाँ तक नागरिक प्रशासन का प्रश्न था, कर्नल डिवसन का सीधा सम्बन्ध एवं पत्र व्यवहार उत्तर-पश्चिमी मुर्बों के लेफ्टिनेंट से कायम कर दिया गया था ।<sup>४२</sup> परन्तु कर्नल डिवसन के देहवसान के बाद भजमेर और मेरवाड़ा का प्रशासनिक भार वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कर उसके हाथों में सौंप दिया गया था तथा ए. जी. जी. को वापस भजमेर का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था । इस प्रकार कर्नल डिवसन के देहान्त के समय से लेकर सन् १८७१ तक भजमेर-मेरवाड़ा ए०जी०जी० राजपूताना के अन्तर्गत एक डिप्टी कमिश्नर ही बना रहा । सन् १८९८ से १८७१ तक ए०जी०जी० उत्तर-पश्चिमी मुर्बा सरकार के अधीन थे । साथ में छः महीने ए. जी. जी. का कार्यालय भजमेर

से २३० मील दूर भाबू पर्वत पर रहता था। उन्हें भजमेर के राजस्व कमिशनर, सेशन कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ-सिविल कोर्ट के न्यायाधीश पद पर कार्य करना होता था तथा वे सामान्य प्रशासनिक मामलों में उत्तर-पश्चिमी सूबों के विभिन्न विभागाध्यक्षों के प्रति उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था के कारण ए. जी. जी. वर्ष में केवल एक बार ही भजमेर में कचहरी कर पाते थे। इस कारण कई अभियुक्तों को बहुधा साल भर तक हवालात में बंद रहना पड़ता था।<sup>५३</sup>

— ए. जी. जी. अपने कमिशनर के कार्य में ही इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें रियासतों से सम्बन्धित राजनीतिक कार्यों के लिए समय ही नहीं मिलता था। कर्नल कीटिंग की यह बहुत सही मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट पद पर कार्य करते हुए कमिशनर की हैसियत से भजमेर जिले के साथ न्याय नहीं कर सकता है।<sup>५४</sup>

ए०जी०जी० राजामो से व्याप्त बुराईयों को समाप्त करने व उन पर नियंत्रण रखने में भी असफल रहे। इसके लिए उन्हें दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यदि उन्हें व्यस्त कार्यभार से मुक्त रखा जाता तो वे सम्भवतः अपने व्यक्तिगत प्रभाव का भी उपयोग करने में सफल हो सकते थे। यदि ए०जी०जी० को प्रशासनिक कार्यों से समय मिला होता तो वे विभिन्न रियासतों का दौरा कर वहाँ प्रशासन में फैली बुराईयों को रोकने की ओर ठोस कदम उठाते व इस बात का स्वयं निरीक्षण करते कि राजामो ने सुधारों के जो आश्वासन दिए, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस तरह की देखरेख और निकटतम सम्पर्क के अभाव में अंग्रेजों और राजपूताने के राजवाड़ों के बीच अलगाव भी बढ़ता रहा। सेशन कोर्ट, सिविल अपीलों की सुनवाई तथा विभागाध्यक्षों के साथ संदर्भ जानकारी के पत्राचार में ही वे इस तरह व्यस्त रहते थे कि राजामो व रियासतों सम्बन्धी मामलों की देखरेख का उनके पास समय ही नहीं था।<sup>५५</sup>

पूर्ववर्ती बीस वर्षों में ए०जी०जी० एक बार ही बीकानेर व बांसवाड़ा का दौरा कर सके इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं निभा पा रहे थे। इस तरह के भारी कार्यभार का तथा एकत्र प्रणाली का कुप्रभाव यह हुआ कि भजमेर जिला घोर उपेक्षा का शिकार हुआ। राजस्व बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने फरवरी १८६६ में अपने भजमेर प्रवास के बाद सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में इस व्यवस्था की कड़ी टीका-टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि "वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जिले की हालत में यद्यपि यह पड़ोसी रियासतों की तुलना में अवश्य कुछ अच्छी है तथापि अधिक सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।"<sup>५६</sup>

इस दुहरे प्रशासन के दोषों के अलावा उन्हें अन्य बहुत सी प्रशासनिक त्रुटियाँ

पर अपनी नियुक्ति या निरोक्षण को सदा टालने के प्रयत्न में रहते थे<sup>३८</sup> । यहाँ के अधिकारियों का अल्प वेतन भी इस क्षेत्र की उपेक्षा का एक कारण था । कर्नल डिवसन, जिन्होंने जिले की व्यवस्था व यहाँ की आर्थिक स्थिति का विशेष अध्ययन किया था, दुर्भाग्य से प्रशासन सेवा में अल्प वेतन रखने के पक्ष में थे जबकि इसके विपरीत कैंप्टिन ब्रुक्स की मान्यता थी कि इस क्षेत्र में जिला अधिकारियों के अधिक स्वतंत्रता से काम करने में उनका अल्प वेतन बड़ा ही बाधक है ।<sup>३९</sup> इस पूरे काल में सरकार ने विकास कार्यों के बजाय आर्थिक कठौती पर ज्यादा ध्यान दिया । जिन गाँवों के लोगो ने सरकारी अभ्यापकों को वेतन भुगतान के लिए राशि देने में घानाकानी की, वहाँ स्कूल बन्द करने के आदेश दिए गए ।<sup>४०</sup> इसके अलावा कमिश्नर के यहाँ स्थाई रूप से रहने के कारण प्रशासन में घोर भी क्षीणता आ गई थी । कमिश्नर इस जिले के डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट के ग्यायाधीश भी थे । उनके एक सापेक्ष अधिक समय तक भ्रजमेर में नहीं रह पाने के कारण मृत्यु दुःख के अपराधियों को फैसले के अभाव में लम्बे समय तक हवालाती कंड़ी बने रहना पड़ता था । उनको अपने निर्यात के लिए सेशन कोर्ट की बैठकों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । जिले की सड़कों और यातायात अत्यन्त ही पिछड़ी हालत में था । क्षेत्र की समृद्धि के आधार बांध व जलाशय मरम्मत के अभाव में सदा ही डहते रहते थे ।<sup>४१</sup>

सरकार ने कर्नल डिवसन को जब कमिश्नर नियुक्त किया था तब इसके पीछे केवल उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं की सराहना का ही दृष्टिकोण नहीं था, अपितु प्रशासनिक आवश्यकता भी प्रमुख रही थी । कमिश्नर का पद ए०जी०जी० से भ्रलग करने का उद्देश्य ए०जी०जी० को अर्धनैतिक प्रशासन के व्यस्त कार्यभार से, जिनमें उनका अधिकांश समय नष्ट हुआ करता था, मुक्त करना था । कर्नल डिवसन को कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर उन्हें नागरिक प्रशासन के सम्पूर्ण काम सौंप दिए गए थे । अर्धनैतिक प्रशासनिक कार्यभार के कारण पहले ए०जी०जी० का काफी समय तक भ्रजमेर से निकलना ही नहीं हो पाता था । इस कारण राजपूताना की रिपासर्तों से सम्बन्धित राजनीतिक कामकाज के लिए समय निकालना उनके लिए कठिन हो गया था । नई व्यवस्था के अनुसार जहाँ तक नागरिक प्रशासन का प्रश्न था, कर्नल डिवसन का सीधा सम्बन्ध एवं पत्र व्यवहार उत्तर-पश्चिमी यूरो के लेफ्टिनेंट से कायम कर दिया गया था ।<sup>४२</sup> परन्तु कर्नल डिवसन के देहावसान के बाद भ्रजमेर और मेरवाड़ा का प्रशासनिक भार वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कर उसके हाथों में सौंप दिया गया था तथा ए०जी०जी० को वापस भ्रजमेर का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था । इस प्रकार कर्नल डिवसन के देहान्त के समय से लेकर सन् १८७१ तक भ्रजमेर-मेरवाड़ा ए०जी०जी० राजपूताना के अन्तर्गत एक डिप्टी कमिश्नर ही बना रहा । सन् १८५८ से १८७१ तक ए०जी०जी० उत्तर-पश्चिमी पूवा सरकार के अधीन थे । साथ में ही वहीं ए०जी०जी० का कार्यालय भ्रजमेर

से २३० मील दूर घाबू पर्वत पर रहता था। इन्हें अजमेर के राजस्व कमिशनर, सेशन कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ-सिविल कोर्ट के न्यायाधीश पद पर कार्य करना होता था तथा वे सामान्य प्रशासनिक मामलों में उत्तर-पश्चिमी सूबों के विभिन्न विभागाध्यक्षों के प्रति उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था के कारण ए. जी. जी. वर्ष में केवल एक बार ही अजमेर में कचहरी कर पाते थे। इस कारण कई अभिभूतों को बहुधा साल भर तक हवालात में बंद रहना पड़ता था।<sup>४३</sup>

— ए. जी. जी. अपने कमिशनर के कार्य में ही इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें रियासतों से सम्बन्धित राजनीतिक कार्यों के लिए समय ही नहीं मिलता था। कर्नल कीटिंग की यह बहुत सही मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट पद पर कार्य करते हुए कमिशनर की हैसियत से अजमेर जिले के साथ न्याय नहीं कर सकता है।<sup>४४</sup>

ए०जी०जी० राजाओं से व्याप्त बुराईयों को समाप्त करने व उन पर नियंत्रण रखने में भी असफल रहे। इसके लिए उन्हें दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यदि उन्हें व्यस्त कार्यभार से मुक्त रखा जाता तो वे सम्भवतः अपने व्यक्तिगत प्रभाव का भी उपयोग करने में सफल हो सकते थे। यदि ए०जी०जी० को प्रशासनिक कार्यों से समय मिला होता तो वे विभिन्न रियासतों का दौरा कर वहाँ प्रशासन में फैली बुराईयों को रोकने की ओर ठोस कदम उठाते व इस बात का स्वयं निरीक्षण करते कि राजाओं ने सुधारों के जो आश्वासन दिए, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस तरह की देखरेख और निकटतम सम्पर्क के अभाव में अंग्रेजों और राजपूताने के राजवाड़ों के बीच मतभेद भी बढ़ता रहा। सेशन कोर्ट, सिविल अपीलों की सुनवाई तथा विभागाध्यक्षों के साथ संदर्भ जानकारी के पत्राचार में ही वे इस तरह व्यस्त रहते थे कि राजाओं व रियासतों सम्बन्धी मामलों की देखरेख का उनके पास समय ही नहीं था।<sup>४५</sup>

पूर्ववर्ती बीम वर्षों में ए०जी०जी० एक बार ही बीकानेर व बांसवाड़ा का दौरा कर सके इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं निभा पा रहे थे। इस तरह के भारी कार्यभार का तथा एकतंत्र प्रणाली का कुप्रभाव यह हुआ कि अजमेर जिला घोर उपेक्षा का शिकार हुआ। राजस्व बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने फरवरी १८६९ में अपने अजमेर प्रवास के बाद सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में इस व्यवस्था की कड़ी टीका-टिप्पणी की। उन्होंने निम्नलिखित कि “वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जिले की हालत में यद्यपि यह पड़ोसी रियासतों की तुलना में अवश्य कुछ अच्छी है तथापि अधिक सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।”<sup>४६</sup>

इस दुहरे प्रशासन के दोषों के अलावा उन्हें अन्य बहुत सी प्रशासनिक त्रुटियाँ

भी दृष्टिगोचर हुई। जिले में बड़े सैनिक महत्व के काम चल रहे थे इसलिए नसीराबाद तथा जिले में अन्यत्र नियुक्त सेना सम्बन्धी बहुत सी समस्याएं सामने आने लगी। परन्तु नसीराबाद स्थित सेनाएं बम्बई प्रेसीडेंसी के नियंत्रण में थीं, क्योंकि यहाँ कि टुकड़ियाँ बम्बई सेना का अंग मानी जाती थीं। परिणामतः एक ही जिले पर नियंत्रण के चार पृथक्-पृथक् स्रोत थे; भारत सरकार, ए०जी०जी०, उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बम्बई सरकार। बायसराय ने भी इन प्रमुविधायी तथा इनमें उत्पन्न निम्नलिखित दोषों को स्वीकार किया था। जिले के लोगों की आर्थिक गिरावट की स्थिति यह थी कि उसमें द्वैसयुक्त वाता (केवल एक भ्रमवाद को छोड़कर) कोई भी जमींदार ऐसा नहीं था जो सर तक कर्ज में डूबा हुआ न हो और जिसकी जमींदारी उसके वास्तविक मूल्य से अधिक राशि में बंधक न रही हुई हो। अधिकारी एक ओर तो अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत बिगरी करते थे और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन पर रोक के आदेश जारी करते थे। वास्तव में स्थिति इस सीमा तक पहुँच गई थी कि निकट भविष्य में ही अविलम्ब प्रभावशाली प्रशासनिक परिवर्तन आवश्यक हो गया था।<sup>५७</sup>

**नौया चरण : पुनर्गठन (१८७०-१९००) :**

उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिले के प्रशासन को विकसित करने व सर्वोच्च नियंत्रण को नियमित बनाने के 'दृष्टिकोण' से जिले के प्रशासन को पुनर्गठित करने की दिशा में कुछ सुझाव दिए थे। उनके अनुसार जिले में व्याप्त प्रशासनिक अनियमितताओं का एकमात्र हल प्रांत को भ्रमभर तथा मेरवाड़ा के दो पृथक्-पृथक् जिलों में विभाजित करना था। प्रत्येक जिले के लिए सलग-सलग सुपरि-टेंडेंट, ए०जी०जी० की मातृहृष्टी में नियुक्त एक नये अधिकारी के अधीनस्थ हो।<sup>५८</sup> इस नई व्यवस्था को लागू करने पर प्रशासनिक व्ययभार में ३५,८०८ रुपयों की वृद्धि होती थी और यदि इनमें नये सुपरि-टेंडेंट के कार्यालय के अधीनस्थ सेवकों के व्ययभार तथा सुपरि-टेंडेंट के प्रतिवर्ष चार माह के दीर्घ का अनुमान से प्रतिदिन के सान या घाट रुपये के द्विखान से होने वाला व्यय और जोड़ दिया जाता तो व्यय-भार प्रतिवर्ष ४५,००० रुपए तक पहुँचता था।<sup>५९</sup>

बायसराय महोदय ने जिले को दो पृथक् जिलों में रूप में विभाजन के सुझाव को अनावश्यक समझा। उनके अनुसार न तो क्षेत्र ही इतना विस्तृत था और न राजस्व ही इतना पर्याप्त था कि उसके लिए दो पृथक् जिलाधिकारियों को औचित्य-पूर्ण ठहराया जा सके। उनके अनुसार सूबे के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए मेरवाड़ा के लिए एक सहायक अधिकारी की सलम से नियुक्ति करने पर उस समस्या का व्यावहारिक रूप से समाधान हो सकता था। बायसराय के अनुसार सबसे बड़ी आवश्यकता भ्रमभर जिले के लिए एक कमिश्नर के पद का निर्माण कर उस पर एक

ऐसे योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की थी जो बुद्धिमान, अनुभवी एवं गैर नियम प्रतीतों के प्रशासन का अनुभव रखता हो तथा यह स्थाईतौर पर अजमेर रहे। कर्नल ब्रुक्स और हंगलिस दोनों ही अधिकारियों ने अजमेर प्रवास के समय बायसराय को यह सुझाव दिया था कि सामान्य प्रशासन चाहे सर्वोच्च सरकार अथवा ए० जी० जी० या उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रहे परन्तु जिले में एक उच्च अधिकारी की जो निरन्तर अजमेर में रह सके अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दीवानी मामलों के निर्णय के लिए विशेष प्रावधान की भी आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी।<sup>५०</sup>

सन् १८७० में बायसराय ने इसलिए अजमेर के लिए निम्नांकित प्रशासनिक पदों की स्वीकृति प्रदान की:—

# १. कमिश्नर

दो हजार रुपया मासिक वेतन—वार्षिक २५०० रुपए  
वेतन-वृद्धि १०० रुपए, पद-भूखला  
२५०० रुपए तक एवं औसतन स्थाई  
प्रवास भत्ता । १५० रुपए

# २. डिप्टी कमिश्नर

द १०००, मासिक, वार्षिक वेतन-वृद्धि ५० १२०० रुपए  
रुपए-वेतन भूखला १४०० तक ।

# ३. स्यापिक सहायक (भारतीय)

७०० रुपए, वार्षिक वेतन-वृद्धि ५० रुपए, ८५० रुपए  
वेतन भूखला १००० रुपए तक ।

# ४. सहायक कमिश्नर मेरवाड़ा

८०० रुपये

# ५. अतिरिक्त सहायक कमिश्नर मेरवाड़ा (भारतीय)

३०० रुपये

# ६. अतिरिक्त सहायक कमिश्नर अजमेर (भारतीय)

४०० रुपये

# ७. कमिश्नर कार्यालय

४०० रुपये

# ८. स्यापिक सहायक कार्यालय

३०० रुपये

कुल ६,६५० रुपये

इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुल ६,६५० रुपये मासिक खर्च था जो वर्तमान मासिक खर्च पर २७३४ रुपए, अर्थात् ३२८०८ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार था।<sup>५१</sup>

- इस प्रकार १८७१ में अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन में बड़ा महत्वपूर्ण

परिवर्तन हुआ। अन्तर्मेर-मेरवाड़ा उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार के नियंत्रण से हटाकर भारत सरकार के नियंत्रण में परराष्ट्र एवं राजनीतिक विभाग के अधीन कर दिया गया। ए० जी० जी० को इस प्रान्त का चीफ-कमिशनर नियुक्त किया गया व प्रान्त के लिए एक अलग पद कमिशनर का कामयाब किया गया। अन्तर्मेर और मेरवाड़ा में एक-एक सहायक कमिशनर की नियुक्ति की गई। इस परिवर्तन के अन्तर्गत कमिशनर को गैर नियमन् प्रान्त के गवर्नर के समकक्ष अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रान्त का पुनिश सुपरिन्टेण्डेंट तथा मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया। डिप्टी कमिशनर को दूसरे गैर नियमन् प्रान्त के डिप्टी कमिशनर के समकक्ष अधिकार व स्तर प्रदान किया गया। सहायक कमिशनर मेरवाड़ा के अधिकार जिले के उपलब्ध अधिकारी जैसे रखे गए। इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत कमिशनर पर राजस्व संबंधी किसी तरह का उत्तरदायित्व नहीं था। उसे प्रति तीन माह में एक बार महिने भर के लिए मेरवाड़ा का दौरा करना होता था अथवा आवश्यकतानुसार उसे समय-समय पर अपने उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत तथा जिले के उपलब्ध के भौतिक अथवा अमील सम्बन्धी फँसलों के लिए थोड़े समय के लिए भी उक्त क्षेत्र का दौरा करना आवश्यक था।<sup>५३</sup>

लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रान्त के शासन सम्बन्धी अधिकार ए० जी० जी० के हाथों में तीन कार्यों से दे देना आवश्यक समझते थे:—

- (१) ए० जी० जी० के अधिकार में पड़ोसी रियासतों पर भी देखरेख ज्यादा प्रभावशाली हो सकेगी।
- (२) यह व्यवस्था क्षेत्र के इस्तरदारदारों के हक में भी रहेगी क्योंकि इनकी भूमि-व्यवस्था भी पड़ोसी देशी रजवादों जैसी ही थी।
- (३) नियमित अंग्रेजी प्रशासन की अपेक्षा इस गैर नियमन् क्षेत्र के लिए सीधे सादे व परिस्थितिबोध नियंत्रण की आवश्यकता थी।<sup>५४</sup>

परन्तु लेफ्टिनेंट गवर्नर के मतानुसार इसे उत्तर-पश्चिमी सूबे के नियंत्रण में रखने के लक्ष्य में ज्यादा बर्जन था। उनके अनुसार उत्तर-पश्चिमी सूबों के अन्तर्गत रखने से राजस्व, पुनिश, जेल तथा शिक्षा विभागों पर अनुभवों विभागाध्यक्षों की देखरेख सम्भव हो सकती थी। रेल मार्ग खुल जाने से निरीक्षण नियमित रूप से सम्भव था। हमेशा ऐसे एक व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल होता जिसमें राजनीतिक निपुणता व प्रशासनिक योग्यता का समावेश हो। अतएव लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अन्तर्मेर-मेरवाड़ा को उत्तर-पश्चिम सूबे के अधीन रखने का सुझाव दिया व साथ ही उनकी राय थी कि उन सभी प्रश्नों पर जो अन्तर्मेर व निकटवर्ती राज्यों के बीच सड़े हों। ए० जी० जी० का कमिशनर की हैसियत से सामान्य नियंत्रण रहे परन्तु राजस्व, पुलिस

घोर न्यायिक मामलों संबंधी जिला अधिकारी, उत्तर-पश्चिमी सूबों की सरकार के अधीन रहे जिससे कि ए०जी०जी० को दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों से मुक्त किया जा सके।<sup>२४</sup>

परन्तु वाईसराय ने ए.जी.जी., स्थानीय अधिकारीगण, सर डम्फ्री मूरे तथा इंग्लिश से विचार-विमर्श के पश्चात् यह मन प्रकट किया कि जबतक भजमेर का प्रान्तीय प्रशासन भारत सरकार को हस्तान्तरित नहीं कर दिया जाता है तबतक प्रशासन की वर्तमान दोषपूर्ण प्रक्रिया जारी रहेगी। ए०जी०जी० अपने राजनीतिक उत्तरदायित्वों के लिए भारत सरकार के अधीन थे, सार्वजनिक निर्माण-विभाग के लिए ए०जी०जी० गवर्नर जनरल की कौंसिल के प्रति उत्तरदायी थे। भजमेर के कमिश्नर के रूप में वह उत्तर-पश्चिमी सूबों की सरकार के नियंत्रण में थे। नसीराबाद सम्बन्धी सैनिक महत्व के कार्यों के लिए वे बम्बई प्रेसीडेंसी के मुख्याधी थे। इसलिए प्रशासन के हित में था कि एक ही प्रान्त पर बहुविध नियंत्रणों को समाप्त किया जाए। गवर्नर जनरल की कौंसिल ने इसलिए यह निर्णय लिया कि भजमेर के लिए एक चीफ कमिश्नर का नया पद कायम कर ए. जी. जी. की भजमेर का चीफ कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए। ए०जी०जी० को चीफ कमिश्नर की हैसियत से भारत सरकार के "परराष्ट्र विभाग" के अधीन रखा गया। चीफ कमिश्नर की हैसियत से वे भजमेर-मेरवाड़े के वित्त व पूँजीशायल कमिश्नर होंगे। पूँजीशायल कमिश्नर का म्यायालय भजमेर-मेरवाड़ा का सर्वोच्च म्यायालय होगा इसमें कमिश्नर की भद्रासत के निर्णयों के विरुद्ध जो कि डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन के स्तर की थी—अपील की सुनवाई होगी।<sup>२५</sup>

भजमेर-मेरवाड़े के प्रशासन का नियंत्रण गृह विभाग की अपेक्षा परराष्ट्र विभाग के अन्तर्गत रखने के दो विशेष उद्देश्य थे :—

(१) यह जिला रियासती से घिरा हुआ था इसलिए उनसे सम्बन्धित प्रश्न सदा ही उठा करते थे।

(२) अन्य विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ औपचारिक जटिलता को भी कम करना जरूरी समझा गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर-पश्चिमी सूबों की सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक, सफाई कमिश्नर, जेल एवं टीकों सम्बन्धी निरीक्षक भजमेर का दौरा कर अपनी रिपोर्टें चीफ कमिश्नर के माध्यम से ठीक उसी तरह प्रस्तुत करेंगे जैसा कि मध्य प्रान्त के सम्बन्धित अधिकारीगण बरार क्षेत्र के बारे में अपनी रिपोर्टें हैदराबाद स्थित रेजीडेंट के माध्यम से प्रस्तुत करते थे।<sup>२६</sup>

१८७७ में फिर भारत सरकार ने वित्तीय कारणों से इस जिले के प्रशासन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। डिप्टी कमिश्नर का पद समाप्त कर दिया गया। कमिश्नर के अधीन भजमेर और मेरवाड़ा उपखंडों के लिए दो पृथक् असिस्टेंट, प्रशासन में मदद के लिए नियुक्त किए गए। प्रत्येक असिस्टेंट कमिश्नर को भारतीय दंड



सहिता के अन्तर्गत माने वाले अपराधों के निर्णय-हेतु जिला दंडनायक के अधिकारों के अलावा राजस्व तथा चुंगी कलेक्टर के अधिकार भी प्रदान किए गए, जिनके लिए उसे कमिश्नर की देखरेख व उसके आदेशों के अन्तर्गत काम करना था। केन्द्री में प्रतिरिक्त असि० कमिश्नर की जगह एक छोटा अधिकारी नियुक्त किया गया। १८७७ में प्रशासनिक सेवाओं को इस तरह घटाया गया—

१—कमिश्नर	रुपए	२०००-००
२—असिस्टेंट कमिश्नर, भ्रजमेर	"	१०००-००
३—असिस्टेंट कमिश्नर, मेरवाड़ा	"	८००-००
४—छावनी दंडनायक	"	६००-००
५—न्यायिक सहायक	"	८००-००
६—प्रतिरिक्त असि० कमिश्नर, भ्रजमेर	"	४००-००
७—डिप्टी मजिस्ट्रेट	"	१५८-००

उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था १ मई, १८७७ से लागू की गई।<sup>५७</sup> इस तरह भ्रजमेर-प्रशासन को सन् १८७७ में जब पुनर्गठित किया गया तो डिप्टी कमिश्नर का पद समाप्त कर दिया गया और यह अनुभव किया गया कि भ्रजमेर का प्रशासन कमिश्नर सम्हाले तथा उसकी व्यक्तिगत सहायता के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर रहे। असिस्टेंट कमिश्नर के जिम्मे स्वतन्त्र रूप से कुछ न्याय विभाग के काम भी थे। कुछ समय बाद जब यह अनुभव किया जाने लगा कि कमिश्नर के पास बहुत अधिक काम है तब धीरे-धीरे असिस्टेंट कमिश्नर को अधिकारिक काम सौंपे जाने लगे। सरकारी अनुज्ञापत्रों के अनुसार पूर्ववर्ती डिप्टी कमिश्नर को जो अधिकार प्राप्त थे वे उसे प्राप्त हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर भूराजस्व और चुंगी का कलेक्टर, जिला दण्डनायक, उपन्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कोर्ट ऑफ वाइस का व्यवस्थापक, जिला बोर्ड का अध्यक्ष तथा उप वन सरसक अधिकारी के कार्य करने लगा। प्रतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर कोषाध्यक्ष का काम सम्हालता था। इसके प्रतिरिक्त वह प्रथम श्रेणी दंडनायक, प्रथम श्रेणी उप न्यायाधीश, जिला बोर्ड का सचिव होता था तथा चुंगी व भूधर्म सबको कुछ विभागीय काम भी देखता था।<sup>५८</sup>

निम्नांकित अकतालिका २६ से यह स्पष्ट होता है कि कैसे घाटे का बजट पूर्ति के बजट में परिवर्तित हुआ—

वर्ष	राजस्व	व्यय	अन्तर
१८७८-७९	६६०६८३	४१०२६९	१४०११९
१८८१-८०	१०१३४९८	४२००६१	४९३४०७
१८८६-८०	११०७४११	४२३२३१	४८४१८०

प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद पहले साल ही लगभग पचास हजार का घाटा, ठेढ़ साल के फायदे में बदल दिया गया। ग्रामामी दस वर्षों में आय में ४,४६,७२८ रुपए अर्थात् १७ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और ४,३४,०६६ रुपए का लाभ अर्थात् २८६ प्रतिशत से अधिक रहा। इन्हीं वर्षों में जबकि प्रशासन व्यय केवल दो प्रतिशत से कुछ ही अधिक बढ़ा था जबकि पुनर्गठन के पूर्ववर्ती तीन सालों में प्रतिवर्ष प्रशासनिक व्यय आय से अधिक था व लगभग पचास हजार का प्रतिवर्ष घाटा रहता था।<sup>१०</sup> इस आर्थिक उपलब्धि का दुष्प्रभाव प्रशासनिक कार्य कुशलता पर पड़ना स्वाभाविक था। प्रशासनिक खर्चों में कमी के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अजमेर में १८७४ का गिडपूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट १५ लागू किया गया। प्रंग्रेजों ने अजमेर के साथ यह सबसे बड़ा अन्याय किया था। अजमेर के प्रशासन को आर्थिक दृष्टिकोण से देखना अनुचित था। अजमेर जैसे छोटे से व राजपूत रियासतों से घिरे एकाकी जिले का प्रशासनिक व्यय अधिक होना स्वाभाविक था। १८१८ में अजमेर के अंग्रेजों के अधीन आने के पूर्व राजनीतिक परिस्थिति के कारण जिले का अधिकांश भाग बड़ी-बड़ी जमींदारियों के रूप में राजपूतों के अधिकार में चला गया था। इन जमींदारियों की आय एक हजार से लेकर एक लाख रुपए तक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग दो तिहाई अजमेर से सरकार की आय नगण्य सी थी। ये इस्तमरारदार नाममात्र का नजराना अंग्रेज सरकार को देते थे।

सन् १८७७ के बाद जिले के प्रशासनिक कार्य में कई कारणों से वृद्धि हो गई थी। पहला कारण, १८८७ का बन्दोबस्त था जो कि अपने पूर्ववर्ती बन्दोबस्त के मुकाबले कहीं अधिक जटिल था। उसमें भूराजस्व निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों के कारण राजस्व सम्बन्धी काम बढ़ गया था। दूसरा कारण, १८८४ में अजमेर में सदर प्राबकारी व्यवस्था का लागू होना था। तीसरा कारण, आयकर कानून लागू किया जाना था। इसके अलावा अजमेर तक रेलमार्ग स्थापित हो जाने से भी वित्तीय कार्यभार बढ़ गया था। जिले में स्वायत्त शासन संस्था नियम लागू करने के कारण पहले से ही कार्य के भार से दबे अजमेर के प्रशासन की स्थिति नये भार के कारण और भी बिगड़ गई।

सन् १८८० में अजमेर के कमिश्नर को कुछ समय के लिए राजपूताना और पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के उन भूभागों पर जहाँ रेलमार्ग का निर्माण हो गया था, सेशन्स न्यायाधीश का काम सौंपा गया था। उसे उन सभी अपराधों के बारे में निर्णय करने होते थे जो अवतक अलवर के पोलिटिकल एजेंट, रेजीडेंट जयपुर और पश्चिमी रियासतों की एजेन्सी के अधिकार क्षेत्र में थे।<sup>११</sup>

प्रशासनिक पुनर्गठन के अन्तर्गत अजमेर-मेरवाड़ा में केवल तीन तहसीलदार और तीन नायब तहसीलदार रहे। सन् १८८३ में घटाकर तीन तहसीलदार और दो नायब तहसीलदार ही रहने दिए। उत्तर-पश्चिमी छुबों में तहसीलदार राजस्व कार्य

के भलावा राजस्व तथा फौजदारी अनराधों की सुनवाई और निर्णय भी किया करता था। भजमेर में तहसीलदार को इन उल्लेखित कामों के भलावा सामान्य नागरिक मामलों में मुन्सिफ का काम भी करना होता था। उत्तरी-पश्चिमी सूबों में नायब तहसीलदार के पास न्यायिक काम नहीं रहता था। भजमेर जिले में ये लोग अपने अन्य राजस्व कार्यों के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी दण्डनायक व मुन्सिफ का काम भी करते थे। अतएव भजमेर में तहसीलदार कर्मचारियों को जो काम करने पड़ते और जो जिम्मेदारियाँ बहन करनी पड़नी थी, वैसे उत्तर-पश्चिमी सूबों में वहाँ के तहसील कर्मचारियों को नहीं करनी पड़ती थी। उत्तर-पश्चिमी सूबों की तहसीलों की तुलना में भजमेर तहसील अधिक बड़ी थी।<sup>१२</sup>

भजमेर और मेरवाड़ा के दोनों जिलों का राजस्व कार्य एक अधिकारी के जिम्मे था जो राजस्व अतिरिक्त सहायक आयुक्त (रेवेन्यू एक्स्ट्रा प्रसि० कमिश्नर) कहलाता था तथा उसका सदर कार्यालय भजमेर में स्थित था।<sup>१३</sup>

भजमेर और मेरवाड़ा जिलों को तहसीलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक तहसील एक तहसीलदार के अधीन थी और उसकी सहायता के लिए नायब तहसीलदार होता था। सन् १८५८ के पूर्व में तीन तहसीलें भजमेर, रामसर और राजगढ़ थी। राजगढ़ तहसील सन् १८५८ में भंग कर दी गई और रामसर तहसील सन् १८७१ में जिले के पुनर्गठन के समय समाप्त कर दी गई थी। हाँन के कार्यकाल में मेरवाड़ा तीन तहसीलों में विभक्त था—ब्यावर, टाडगढ़ और सारोठ। कर्नल डिवसन की मृत्यु के बाद सारोठ की सीसरी तहसील ब्यावर में मिला दी गई थी<sup>१४</sup>।

तहसीलदार के अधीन गिरदावर होते थे जिन्हें अपनी तहसीलों के अधिकार क्षेत्र में राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे। ये अपने हल्के के विभिन्न ग्राम अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, निगरानी और उनके द्वारा तैयार किए गए प्राकड़ों व सूचियों में सघोषन व परिवर्धन का काम करते थे। पटवारी गाँव के लेखाधिकारी थे। प्रत्येक पटवारी के क्षेत्र में दो या अधिक गाँव रहते थे तथा उसकी सहायता के लिए कई बार सहायक पटवारी भी होते थे। ये लोग गाँव के राजस्व का हिसाब रखते थे, रजिस्टर तैयार करते और अपने हल्के में सरकार के हितों का ध्यान रखते थे।<sup>१५</sup>

राजस्व वसूली का काम पटेल और तम्बरदार किया करते थे उनका प्रमुख काम राजस्व कर वसूल करके सरकार के खजाने में जमा करवाना होता था। पिछले बन्दोबस्त के समय उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई थी। तम्बरदारों द्वारा वसूल किए गए राजस्व पर सरकार उन्हें ५ प्रतिशत की राशि देती थी। पटेलों को उनकी जमीन पर राजस्व में २५ प्रतिशत की छूट तथा मिर्चाई कर की वसूली पर २ या ३ प्रतिशत का भत्ता मिलता था<sup>१६</sup>। भजमेर-मेरवाड़ा के चीफ कमिश्नर को सन्

१९०० में यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह भारत सरकार से बिना पूछे ही

प्रधीनस्थ सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्तियाँ और पदोन्नति, स्थाई घपषा प्रस्थाई कर सकते थे।<sup>१७</sup> अजमेर-मेरवाड़ा के लिए पृथक् प्रान्तीय सेवा का गठन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बर्मचारियों की संख्या बहुत कम थी।<sup>१८</sup> सन् १८८६ में रेवेन्यू एग्स्ट्रा कमिस्टेंट कमिशनर और रजिस्ट्रार की नियुक्तियाँ भी की गईं। प्रथम अधिकारी केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों को निपटाता था और द्वितीय अधिकारी बीस रुपये तक के मजदूरों की सुनवाई कर सकता था।<sup>१९</sup>

सन् १९११ में मिटो-मार्ले सुधार के कारण जबकि एक और संपूर्ण भारत के विभिन्न पड़े प्रान्तों में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन हुए, अजमेर में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सन् १९१४ में एक छोटा सा परिवर्तन यह हुआ कि मेरवाड़ा में एसिस्टेंट कमिशनर की जगह एग्स्ट्रा एसिस्टेंट कमिशनर की नियुक्ति की गई।<sup>२०</sup>

### अजमेर-मेरवाड़ा का पिछड़ापन

यद्यपि अजमेर-मेरवाड़ा दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अंग्रेजों के प्रभुत्व में काफी पहले आ गया था तथापि इसका छोटा आकार, कम जनसंख्या तथा इसकी भौगोलिक स्थिति इसके एक स्वायत्त प्रान्त के रूप में विकसित होने में बुरी तरह से बाधक रही थी। इस छोटे से क्षेत्र के लिए अन्य विशाल प्रान्तों के समान प्रशासन-व्यवस्था की स्थापना करना संभव नहीं था। भारत सरकार ने यहाँ के लोगों के श्रम और शक्ति के स्रोतों को विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो सका व आर्थिक, राजनीतिक तथा शिक्षा-के क्षेत्र में अन्य प्रान्तों की तुलना में यह अत्यन्त पिछड़ा रहा। यही कारण था कि अजमेर की कृषि, मेडिकल व टेक्नीकल शिक्षा की दूसरे प्रान्तों के समान सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यहाँ के युवकों को प्रशामनिक सेवाओं में भी अन्य प्रान्तों के युवकों की प्राप्ति होने वाली सामान्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। यहाँ तक कि इस क्षेत्र की ग्याय व्यवस्था को वह स्तर प्राप्त नहीं हो सका जो समुक्त प्रांत या बम्बई की ग्याय व्यवस्था को उपलब्ध था। चार्टर्ड हाईकोर्ट की स्थापना तो दूर की बात रही, अजमेर में जुडीशियल कमिशनर पद पर भी हाईकोर्ट के ग्यायाधीश पद के समकक्ष योग्यता अनुभव तथा उच्च स्तर के व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं हुई<sup>२१</sup>। केवल यही नहीं अजमेर-मेरवाड़ा को कभी ऐसा चीफ कमिशनर का पद भी प्राप्त नहीं हुआ जो केवल इस प्रान्त के लिए हो। कम आय और छोटा क्षेत्र होने के कारण यहाँ भलग नियमित स्थाई सेवाओं का गठन नहीं हो सका और कम आय के कारण यह प्रान्त बाहर से आए अधिकारियों को अपनी समस्या और हित की ओर आकर्षित नहीं कर सका।<sup>२२</sup>

अंग्रेज शासित भारतीय प्रान्तों ने स्वायत्त शासन की दिशा में प्रगति प्रारम्भ कर दी थी परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन ने इस दिशा में कदाचित् ही कोई

विशेष प्रगति की। यह शिङ्गल डिस्ट्रिक्ट ही बना रहा और वहाँ पुराने स्थानीय कानून बिना किसी संशोधन के यहाँ लागू होते रहे। यदि कभी किसी मामले में नये नियम तैयार किए भी गए तो उन पर स्थानीय जनता की राय जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।<sup>७३</sup>

भजमेर सन् १८७१ में उत्तर-पश्चिमी सूबों से हटा कर भारत सरकार के अन्तर्गत एक छोटी सी प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था। यह सिर्फ भारत सरकार की राजपूताना की रियासतों के प्रति नीति के दृष्टिकोण से किया गया था। इसलिए भारत सरकार ने भजमेर प्रशासन को गृह विभाग के अन्तर्गत रखना या अन्य नियमक प्रान्तों की तरह प्रशासित करना ठीक नहीं समझा। जबकि भजमेर इस तरह के दर्जे का पूरा अधिकारी था। सन् १८७० का एक्ट १ वहाँ लागू किया गया और इसे एक पिछड़े प्रदेश की सभी कठिनाईयाँ, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार-ताएं और असुविधाएं भेलनी पड़ी। सन् १८७७ में वहाँ शिङ्गल डिस्ट्रिक्ट एक्ट (१८७४) लागू किया गया। ब्रिटेन प्रशासन का भजमेर के साथ यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। पिछड़े हुए तथा भारतीय सीमा पर स्थित क्षेत्रों पर ही यह एक्ट लागू किया जाता था। भजमेर के लोग न तो पिछड़े हुए थे और न यह भारतीय सीमा के कोने का क्षेत्र ही था। इन दो दुर्भाग्यपूर्ण कदमों का प्रतिकूल यह हुआ कि भजमेर शेष ब्रिटेन भारत से अलग-सा कर दिया गया और जिस तरह अन्य ब्रिटेन शामिल प्रान्तों को जो सुविधाएं, अधिकार, संरक्षण तथा लाभ प्राप्त होते रहे उनसे इसे वंचित रहना पड़ा। भजमेर में पिछड़ेपन का यह सबसे बड़ा कारण रहा है।<sup>७४</sup>

यह ही सचता है कि ब्रिटेन की इच्छा जानबूझकर इस क्षेत्र के विकास के अवरोध की न रही हो। भजमेर-मेरवाड़ा के अधिकांश यूरोपीय अधिकारी भारत सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेंट में थे। चीफ कमिशनर या उसके प्रथम असिस्टेंट को भजमेर-मेरवाड़ा या किसी अन्य प्रान्त का प्रशासनिक अनुभव का होना जरूरी था। ये नियुक्तियां पोलिटिकल डिपार्टमेंट में होती थीं। इन विभाग में ज्यादातर अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने इसके पूर्व में भारत में कभी काम ही नहीं किया था। यही बात कमिशनर पर भी लागू होती थी। कुछ कमिशनरों को राजस्व विभाग का अनुभव था तो कुछ को गवर्नमेंट का व कई तो दोनों ही मामलों में अनुभवहीन थे। केवल एक ही अपवाद ऐसा है जिसमें इन पद पर नियुक्ति के पूर्व उक्त अधिकारी भजमेर-मेरवाड़ा जिले में काम कर चुका था। कमिशनर सेना एवं सिविल जंग तथा जिला दफ्तर के अलावा शिक्षा विभाग का डायरेक्टर, जेल तथा वन विभागों का इंस्पेक्टर जनरल, चेंबरलैन मेयो कलेक्टर तथा व्यवस्था समिति, राजपूताना में जन्म-मरण के प्रत्येक कार्य का रजिस्ट्रार जनरल भी था। वह चुंगी, धातकर, महसूरी समितियां तथा जिला बोर्ड, नगरपालिका एवं राजस्व विभाग पर सामान्य निरीक्षण का कार्य चार भी बहुत बड़े हुए थे। पत्रिका व्यावहारिक रूप में वह इन

विशिष्ट मामलों में अल्पिम निर्णायक माना जाता था परन्तु सामान्यतः गिदा बन, मह-  
कारी समितियाँ, खुगो तथा ऐसे ही विशिष्ट क्षेत्रों में उसको कोई अनुभव नहीं होता  
था। जिन मामलों में टेक्नीकल अनुभव की आवश्यकता होती थी उनमें उसकी सहज  
बुद्धि ही मात्र आधार था।<sup>७४</sup>

अंग्रेजी भारत में प्रशासन के विकास और जनता में अपनी स्थिति और  
अधिकारों के प्रति चेतना जागृत होने पर इस तरह के क्षेत्रीय विच्छेदन की गंभीरता  
का अनुभव होने लगा। ये अधिकारीगण अजमेर-मेरवाड़ा की हालत व परिस्थितियों से  
पूर्ण परिचित नहीं थे।<sup>७५</sup> अजमेर का यह दुर्भाग्य था कि वह सभी मामलों में अन्य  
प्रान्तों में बनाए गए नियमों व उपनियमों द्वारा प्रशासित होता था। जबकि वे नियम  
वहाँ की सरकारों अपनी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार बनाती थीं। वे सब बिना  
यह समझे कि वे हम प्रांत के लिए लाभदायक होंगे या नहीं, धोए दिए जाते  
थे।<sup>७६</sup>

एक पृथक् इकाई बने रहने के कारण, अजमेर-मेरवाड़ा भारत के अन्य  
अंग्रेज शासित प्रान्तों में लागू किए जाने वाले सुधारों के लाभ से भी वंचित रहा।  
अन्य प्रांतों की तरह यहाँ न तो जिम्मेदार सरकार ही थी और न निर्वाचित सभाएं  
ही गठित हुईं। इसके प्रशासन में कौशल का अभाव सदा ही बना रहा क्योंकि एक  
छोटा-सा जिला होने के कारण पूर्णरूपेण अपने लिए पृथक् कमिश्नर, आई०जी०पी०,  
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सहकारी समिति का रजिस्ट्रार, आवकारी अधिकारी और दो  
वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की स्वतंत्र नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता था। सन् १८७१  
से इस जिले की प्रशासनिक पृथक्ता की घोषणा तथा १८७६ में सिम्प्लूड डिस्ट्रिक्ट  
एक्ट १५ (१८७४) लागू करने के कारण यहाँ के प्रशासन को गंभीर क्षति  
पहुँची व साथ ही अन्य प्रांतों के मुकाबले में इसकी प्रगति और भी पिछड़ गई।  
अजमेर जिला भारत सरकार द्वारा नियंत्रित पोलिटिकल डिपार्टमेंट के अग्रगण्य मामूली  
सी छोटी प्रशासनिक इकाई बना रहा। अजमेर-मेरवाड़ा की जनता भारत के अन्य  
शासित प्रान्तों की जनता की तरह अपने शासन में हाथ नहीं बँटा सकती थी।  
सन् १९०६ में मिटो-मार्से मुखार तथा सन् १९१६ में माटेयू चेम्सफोर्ड सुधारों में  
अजमेर-मेरवाड़ा पूर्णतया वंचित रहा।<sup>७७</sup>

इन सब बातों का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सन् १८१८ में अंग्रेजों के  
आधिपत्य से लेकर अबतक अजमेर-मेरवाड़ा में कोई तरक्की नहीं हुई। १८वीं सदी  
में मुगलों के पतनकाल से लेकर अजमेर सघर्षशील शक्तियों के बीच शतरंज की  
मुहरो की तरह घुमता रहा और हर आक्राना ने इस पर अपने दाव गड़ाए। इस  
समय में यह जिला एक तरह से विनष्ट-सा हो चला था और यहाँ की जनसंख्या  
कुल मिलाकर २५ हजार हो रह गई थी। जिसे में अंग्रेजों के आधिपत्य के साथ

शांति और स्थाई प्रशासन का युग प्रारम्भ हुआ तथा जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। व्यावर जो अंग्रेजों के आगमन के समय एक छोटा-सा गाँव था, अंग्रेजी शासन-काल में प्रमुख एवं महत्वपूर्ण व्यवसायिक केन्द्र बन गया था, जहाँ महत्वपूर्ण सूती उद्योग पनपा और उसके व्यापार में पंजाब के फजलका के बाद इसका स्थान बन गया था। मेरवाड़ा जिला जो उन दिनों ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो हल के बजाय डाल सतवार पसंद करते थे। वह एक कृषि प्रधान और औद्योगिक केन्द्र बनने लगा। अजमेर-मेरवाड़ा का अंग्रेजी प्रशासन के अन्तर्गत कुछ हित अवश्य हुआ परन्तु अन्य प्रान्तों की तरह वह आगे नहीं बढ़ सका।

### अध्याय तीस

१. मेरवाड़ा, अंग्रेजी, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच असमान भागों में विभक्त था। चूँकि मेवाड़ और मारवाड़ अपने को हस्तांतरित गाँवों की व्यवस्था करने में असमर्थ थे, अतएव इनमें से शांतिप्रिय गाँव इन रियासतों के ठाकुरों को दिए गए व शेष मेरवाड़ा के अन्तर्गत रहे। (डिक्सन, स्केच ऑफ मेरवाड़ा १८५० पृ० ६२)।
२. अजमेर के प्रथम सुपरिटेण्डेंट वास्तव में कर्नल दिक्सन थे जिन्होंने केवल ६ दिनों तक काम किया, ६ जुलाई से १८ जुलाई, १८१८ तक (सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिमिग्रिटिव-१९४१ पृ० २१८)।
३. सादूस-गजेटीयर्स ऑफ अजमेर-मेरवाड़ा (१८७५), पृ. ६१।
४. एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ऑस्टरलोनी को पत्र, दिनांक २७-८-१८१८ (रा. रा. पु. मण्डल)।
५. एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ऑस्टरलोनी को प्रेषित पत्र, दिनांक २१-६-१८१८ (रा. रा. पु. मण्डल)।
६. डिक्सन, स्केच ऑफ मेरवाड़ा (१८५०), पृ. ५।
७. सर डेविड ऑस्टरलोनी द्वारा भारत सरकार के सचिव एच. मैकेजी को पत्र दिनांक ६ जनवरी, १८२५ (रा. रा. पु. मण्डल)  
सादूस-अजमेर-मेरवाड़ा की बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७५) पृ. ७१,  
सारदा-अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिमिग्रिटिव (१९४१) पृ. २०७।
८. कुरेन पॉर, अजमेर-मेरवाड़ा की मेडिको टोपोग्रफिकल रिपोर्ट (१९००) पृ. ८१।

६. लाहस-सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा १८७५ पृ. ६२ ।
१०. संकट के दिनों में जो लोग सेत छोड़ कर दूसरे प्रदेशों की चले जाते थे- ये 'फरार' और जो लोग सेती छोड़कर पाजीबिका-हेतु शारीरिक मजदूरी करने चले जाते थे 'नादर' कहलाते थे ।
११. सुपरिंटेंडेंट अजमेर द्वारा कर्नल सदरलैंड कमिश्नर को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक २० जनवरी, १८४१ । (रा. रा. पु. मंडल) ।
१२. कर्नल सदरलैंड द्वारा सचिव, भारत सरकार को प्रेषित रिपोर्ट, दिनांक ७ फरवरी, १८४१ (रा. रा. पु. मंडल) ।
१३. लाहस-सेटलमेंट रिपोर्ट १८७४ ।
१४. लाहस सेटलमेंट रिपोर्ट, १८७४ ।
१५. सचिव भारत सरकार का ए. जी. जी. को पत्र दिनांक ११-१२-१८४१ फाइल न० ६ (रा. रा. पु. म.) ।
१६. त्रिपाठी-भगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ पृ. ६२ लाहस-सेटलमेंट रिपोर्ट, अजमेर-मेरवाड़ा १८७४ अनुच्छेद १२ ।
१७. कार्यवाहक सचिव भारत सरकार द्वारा डिक्शन को पत्र, संख्या ६२१ अ दिनांक २८ १-१८५३ (रा. रा. पु. मं.) ।
१८. कमिश्नर (द्वारा उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार के सचिव को पत्र, संख्या ५२ दिनांक ५ मार्च १८५३ ।
१९. सी सी वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, खंड १-ए अजमेर-मेरवाड़ा (१९०४) पृ. १६ ।
२०. ए. जी. जी. द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र संख्या ११४ दिनांक २५ फरवरी, १८६७ (रा. रा. पु. म.) ।
२१. उपरोक्त ।
२२. चीफ कमिश्नर कार्यालय फाइल क्रमांक ११७, पत्र व्यवहार दिनांक २९ जून १८६९ (रा. रा. पु. मंडल) ।
२३. डिप्टी कमिश्नर द्वारा उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को (कॉन्टिन जे. सी. ब्रुक्स) पत्र दिनांक २४ जुलाई, १८५८ (रा. रा. पु. मंडल) ।
२४. उपरोक्त ।
२५. उपरोक्त डिप्टी कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र संख्या ४८ दिनांक ६ फरवरी, १८६० ।



२६. कॅप्टिन बी. सॉयद द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र दिनांक मई, १८६० को (रा. रा. पु. मंडल) ।
२७. मेजर बी. पी. लॉयड द्वारा जनरल लॉरेस कमिश्नर अजमेर को पत्र क्रमांक १०४ । १८६४ दिनांक २५ अक्टूबर १८६४ । (रा. रा. पु. मंडल) ।
२८. भार. सिमसन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा सी. वेले सचिव गृह विभाग भारत सरकार को पत्र दिनांक २७-४-१८६६ क्रमांक ५५७ । १८६६ (रा. रा. पु. मंडल) ।
२९. डिप्टी कमिश्नर जनरल एस. पी. लॉरेस कार्यवाहक कमिश्नर अजमेर द्वारा डब्ल्यू. म्यूर, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र दिनांक १८-८-५८ क्रमांक २३ । १८५८ (रा. रा. पु. मंडल) ।
३०. पत्र क्रमांक ६४ दिनांक ८-४-१८५८ । (रा. रा. पु. मंडल) ।
३१. पत्र क्रमांक ४० दिनांक १८-२-१८५८ । (रा. रा. पु. मंडल) ।
३२. पत्र क्रमांक १० दिनांक २०-१-१८५८ । (रा. रा. पु. मंडल) ।
३३. पत्र क्रमांक २३, १८५८ दिनांक १८-६-१८५८ । (रा. रा. पु. म.) ।
३४. डिप्टी कमिश्नर जनरल एस. पी. लॉरेस कार्यवाहक कमिश्नर अजमेर द्वारा डब्ल्यू. म्यूर, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र दिनांक १८-८-५८ क्रमांक २३ । १८५८ ।
३५. फाइल नोटिस 'भारत सरकार के अन्तर्गत अजमेर मेरवाड़ा का पृथक् चीफ कमिश्नर के रूप में गठन, विदेश विभाग' फाइल क्रमांक ११७ । १८६७-१८७१ (रा. रा. पु. म.) ।
३६. लेफ्टि. कर्नल थार एच. कटिंग, ए. जी. जी. रायपूताना द्वारा श्री डब्ल्यू. एस. सेटन सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार क्रमांक ११५ दिनांक २६-६-१८६६ (रा. रा. पु. म.) ।
३७. फाइल क्रमांक ११७ । १८६७-१८७१ (रा. रा. पु. म.) ।
३८. लेफ्टि. गवर्नर की टिप्पणी २७ मार्च १८६८ (रा. रा. पु. म.) ।
३९. अज्ञात का पत्र क्रमांक ६४, अनुच्छेद १३, दिनांक ८-४-१८५८ (रा. रा. पु. मंडल) ।
४०. सी. प्रो. क्रमांक २३२, दिनांक ३-४-१८५८ (रा. रा. पु. म.) ।
४१. भार. सिमसन, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा सी. वेले सचिव

गृह विभाग भारत सरकार को पत्र दिनांक २७-४-१८६६ क्रमांक ६५७ ।  
१८६६ । (रा. रा. पु. मंडल) ।

४२. एच. एम. इलियट सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र  
दिनांक ११-१२-१८४८ (रा. रा. पु. मंडल) ।

४३. कर्नेल कीटिंग्स द्वारा सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक १६-४-१८६८  
(रा. रा. पु. मंडल) ।

४४. उल्लेख ।

४५. निम्न तथ्य इस पर प्रकाश डालते हैं:—

१. बीकानेर का दौरा—कर्नेल जे. सदरलैंड	१८४८
२. " " कर्नेल एच. सॉरेस	१८५६
३. डुंगरपुर " " "	१८५५
४. बांसवाड़ा " " "	१८५५
५—जैसलमेर का दौरा कर्नेल सदरलैंड	१८४७
६—जैसलमेर का दौरा इडन	१८६५
७—करोली " " "	१८५६
८—करोली " " एच. सॉरेस	१८६१
९—धीलपुर " " "	१८६१
१०—धीलपुर " " इडन	१८६६
११—प्रतापगढ़ " " सॉरेस	१८५४
१२—प्रतापगढ़ " " इडन	१८६५

४६. कमिश्नर अजमेर द्वारा सचिव भारत को पत्र क्रमांक १६६ जी फाइल  
न० २२५ (रा० रा० पु० मं०) ।

४७. परराष्ट्र विभाग भारत सरकार प्रोसीडिंग्स क्रमांक १६६५ पी दिनांक  
२२-११-१८७० । (रा० रा० पु० मं०) ।

४८. उत्तर प्रदेश सूबा के लेफ्टि० गवर्नर के प्रस्ताव, प्रस्तुत पत्र क्रमांक ६५७,  
दिनांक २७-४-१८६६ (रा० रा० पु० मं०) ।

४९. कर्नेल कीटिंग के अनुसार नई व्यवस्था के लिए निर्धारित राशि कम थी ।  
उनके अनुसार निर्धारित राशि ४६ ६०८ वार्षिक होनी चाहिए थी ।

५०. अनुच्छेद ११ प्रोसीडिंग्स क्रमांक १६६५ पी० दिनांक २२-११-१८७०  
(रा० रा० पु० मं०) ।

५१. अनुच्छेद १२ उपरोक्त ।
५२. अनुच्छेद १३ प्रोसीडिंग्स क्रमांक १६६५ पी० दिनांक २२-११-१८७० ।
५३. पत्र क्रमांक ६५७, दिनांक २७-४-१८६६ उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार ।
५४. उपरोक्त ।
५५. नोटिफिकेशन क्रमांक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र विभाग, राजनीतिक (रा० रा० पु० म०) ।
५६. नोटिफिकेशन क्रमांक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र विभाग, राजनैतिक । (रा० रा० पु० म०) ।
५७. फाइल क्रमांक ७३, प्रस्ताव—फोटो विलियम दिनांक २७ मार्च १८७७ (रा० रा० पु० म०) ।
५८. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र क्रमांक ३०८६० १८६० दिनांक २३-११-१८६० ।
५९. अजमेर बजट वर्ष ८८-८९ और १८८६-८० (रा० रा० पु० म०) ।
६०. उपरोक्त ।
६१. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र क्रमांक ३०८६० १८६० दिनांक २२-नवम्बर १८६० ।
६२. उपरोक्त ।
६३. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजमेर, (१६०४) खंड १-ए० ।
६४. अकाल प्रशासन नियमावली अजमेर-मेरवाड़ा (१६१५) पृष्ठ ३
६५. उपरोक्त पृष्ठ ४ ।
६६. उपरोक्त पृष्ठ ५ ।
६७. सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा ई० जी केल्विन चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा को पत्र शिमला दिनांक ११ जून १८०८ पत्र क्रमांक २३६२१ ए० बी० फाइल क्रमांक ३७० ।
६८. फाइल क्रमांक ३७० पत्र सत्या ६६६१-२ (६) १६११ दिनांक २४ नवम्बर १६११ कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र ।
६९. फाइल क्रमांक ७३ ए० ।
७०. सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड इतिहासिक । (१६४१) पृष्ठ २२४ ।
७१. सारदा, स्वीचेज एण्ड राईटिंग्स पृष्ठ ३२०-३२१ भारत सरकार द्वारा

मजमेर-मेरवाड़ा में प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था पर रिपोर्ट के लिए नियुक्त "एसवर्थ समिति" को प्रस्तुत ज्ञापन ।

७२. लेजिस्लेटिव असेम्बली दिल्ली में हर बिलास सारदा का भाषण दिनांक २६ फरवरी १९२५ ।
  ७३. हर बिलास सारदा, स्पीचेज एवं रीडिंग्स, पृष्ठ ३२९, ३३०, ३३१ ।
  ७४. भारत सरकार की सलाहकार समिति को, समिति के सचिव श्री लतीफी के धनुरोध पर हरबिलास सारदा द्वारा प्रस्तुत नोट दिनांक १२ मई १९३२ ।
  ७५. एसवर्थ कमेटी रिपोर्टें पृष्ठ २६ ।
  ७६. लेजिस्लेटिव असेम्बली, नई दिल्ली में २४ फरवरी, १९२५ को हरबिलास सारदा का भाषण ।
  ७७. एसवर्थ कमेटी रिपोर्टें, पृष्ठ १२ ।
  ७८. हर बिलास सारदा द्वारा भारत सरकार की सलाहकार समिति को प्रस्तुत ज्ञापन, १२ मई, १९३२ ।
-

५१. अनुच्छेद १२ उपरोक्त ।
५२. अनुच्छेद १३ प्रोसीडिंग्स क्रमांक १६६५ पी० दिनांक २२-११-१८७० ।
५३. पत्र क्रमांक ६५७, दिनांक २७-४-१८६६ उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार ।
५४. उपरोक्त ।
५५. नोटिफिकेशन क्रमांक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र विभाग, राजनीतिक (रा० रा० पु० म०) ।
५६. नोटिफिकेशन क्रमांक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र विभाग, राजनीतिक । (रा० रा० पु० म०) ।
५७. फाइन क्रमांक ७३, प्रस्ताव—फोर्ट विलियम दिनांक २७ मार्च १८७७ (रा० रा० पु० म०) ।
५८. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रमर-मेरवाड़ा को पत्र क्रमांक ३०८६० १८६० दिनांक २३-११-१८६० ।
५९. भ्रमर वज्र वर्ष ८८-८९ और १८८९-९० (रा० रा० पु० म०) ।
६०. उपरोक्त ।
६१. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रमर-मेरवाड़ा को पत्र क्रमांक ३०८६० १८६० दिनांक २२-नवम्बर १८६० ।
६२. उपरोक्त ।
६३. सी० सी० वाटसन, राकपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भ्रमर, (१९०४) खंड १-ए० ।
६४. सकल प्रकाशन नियमावली भ्रमर-मेरवाड़ा (१९१५) पृष्ठ ३
६५. उपरोक्त पृष्ठ ४ ।
६६. उपरोक्त पृष्ठ ५ ।
६७. सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा ई० जी केल्विन चीफ कमिश्नर भ्रमर मेरवाड़ा को पत्र शिमला दिनांक ११ जून १९०८ पत्र क्रमांक २३६२१ ए० बी० फाइन क्रमांक ५७० ।
६८. फाइन क्रमांक ५७० पत्र संख्या ६६६१-२ (६) १९११ दिनांक २४ नवम्बर १९११ कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र ।
६९. फाइन क्रमांक ७३ ए० ।
७०. सारदा, भ्रमर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव । (१९४१) पृष्ठ २२४ ।
७१. सारदा, स्वीथेज एण्ड राईटिंग्स पृष्ठ ३२०-३२१ भारत सरकार द्वारा

अजमेर-मेरवाड़ा में प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था पर रिपोर्ट के लिए नियुक्त "एसवर्थ समिति" को प्रस्तुत ज्ञापन ।

७२. लेजिस्लेटिव असेम्बली दिल्ली में हर विलास सारदा का भाषण दिनांक २६ फरवरी १९२५ ।
७३. हर विलास सारदा, स्पीचेज एवं रीडिंग्स, पृष्ठ ३२६, ३३०, ३३१ ।
७४. भारत सरकार की सलाहकार समिति को, समिति के सचिव श्री लतीफी के धनुरोध पर हरविलास सारदा द्वारा प्रस्तुत नोट दिनांक १२ मई १९३२ ।
७५. एसवर्थ कमेटी रिपोर्टें पृष्ठ २६ ।
७६. लेजिस्लेटिव असेम्बली, नई दिल्ली में २४ फरवरी, १९२५ को हरविलास सारदा का भाषण ।
७७. एसवर्थ कमेटी रिपोर्टें, पृष्ठ १२ ।
७८. हर विलास सारदा द्वारा भारत सरकार की सलाहकार समिति को प्रस्तुत ज्ञापन, १२ मई, १९३२ ।

## भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि

अजमेर में राजस्व-प्रशासन अंग्रेज सरकार के लिए सबसे गंभीर समस्या थी। लगातार कई परीक्षणों के पश्चात् स्याई प्रक्रिया स्थापित की जा सकी। अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र मोटेतौर पर दो भागों में विभक्त था। खालसा या वह भूमि जिसका राजस्व सीधा सरकार को भुगतान किया जाता था, (और जिसका निजी वर्चस्व इंग्लैंड के सम्राट के हाथों में था।) और तालुकादारी जिस भूमि पर इस्त-मरारी व्यवस्था लागू थी तथा जिसके लिए किसी भी तरह की सैनिक सेवाओं का बंधन नहीं था।

खालसा भूमि का सीधा सम्बन्ध और उसका नियन्त्रण अंग्रेज सम्राट के प्रशासन के अंतर्गत था। इस भूमि पर सरकार वा वर्चस्व वास्तविक एवं मालिकाना हक ठीक वैसे ही थे जैसे रियासती राजाओं या ठाकुरों के उनकी ज़मीनों पर खेती करने वाले किसानों पर थे<sup>१</sup>। इस व्यवहार के अन्तर्गत सरकार किसी भी धार्मिक संस्थान या किसी व्यक्ति की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अथवा उसके वंशजों को भूमि बख्शीश या इनाम के तौर पर भेंट कर सकती थी। ऐसी बख्शीश या भेंट यदि एक सम्पूर्ण गाँव या भाग्य गाँव की होती तो जागीर<sup>२</sup> कहलाती थी। सन् १६०४ में ऐसे ५१ गाँव जागीरों में दिए गए थे<sup>३</sup>।

**खालसा भूमि का भोग :**

खालसा भूमि में निस्वैतारी प्रथा अतीत काल से ही चली आ रही थी।

इसके अनुसार किसान विकास के लिए अपनी भूमि में कुँआ, बाड़ी, मेड़वदी प्रथवा अन्य निर्माण कार्य करता था उस भूमि में उसका मालिकाना हक मान लिया जाता था। इन हकों को बिस्वादारी हक कहा जाता है। जो भेवाड़ और मारवाड़ा में प्रचलित 'बापोता' जैसे ही है तथा दक्षिण भारत में ऐसे हक को 'मीराज' कहते हैं। 'बापोता' और 'मीराज' यश परम्परागत भूमि अधिकार होते हैं। बिस्वादारी अधिकार प्राप्त किसान को उसकी भूमि से सततक वेदखस नहीं किया जा सकता था, जबतक यह सरकार को राजस्व देता रहता था<sup>४</sup>। उसे साथ ही अपने द्वारा निर्मित या विकसित कुँओं तथा भवनो आदि को बेचने, बंधक रखने या भेंट करने का अधिकार था। केवल इतना ही नहीं, कुँओं इत्यादि के हस्तांतरण के साथ विकसित भूमि का भी हस्तांतरण माना जाता था। कालांतर में बिस्वेदारी अधिकारों का अर्थ स्थाईतौर पर विकसित भूमि में किसान के मालिकाना हकों के रूप में माना जाने लगा<sup>५</sup>। सन् १८३० के पश्चात् सरकार ने विकसित भूमि में केवल अपने मालिकाना हकों का परित्याग कर बिस्वेदारों का मालिकाना दर्जा स्वीकार कर लिया था।

### असिंचित और बंजर भूमि :

सरकार का बंजर भूमि तथा असिंचित भूमि पर स्वामित्व था। इस क्षेत्र में अत्यन्त कम वर्षा के कारण असिंचित भूमि का कोई महत्व नहीं था<sup>६</sup>। किसान असिंचित भूमि पर एक दो फसल अवश्य पैदा कर लिया करते थे, परन्तु वे उस पर स्थाईतौर पर कृषि नहीं करते थे और बाद में दूसरी ऐसी नई भूमि को जीत लिया करते थे, क्योंकि जिले में ऐसी भूमि का बाहुल्य था। इन्हीं कारणों से, सरकार ने इस भूमि पर नई छाणिया (खेड़े) बनाए और नए काश्तकारों को बसाने व उन काश्तकारों को जो इस जमीन को विकसित करना चाहते थे पट्टा प्रदान करते, व सभी किसानों से जिनमें बिस्वेदार भी शामिल थे इस भूमि पर उनके अपने मवेशियों की चराई के कर की वसूली के अधिकार का भी उपयोग किया।<sup>७</sup>

इस प्रश्न पर काफी विवाद था कि पड़ती भूमि पर सरकार का या ग्राम पंचायती का स्वामित्व है। परन्तु सन् १८३६ में एडमस्टन ने भूमि बन्दोवस्त के समय भ्रजमेर के प्रथम दो सुपरिन्टेण्डेंट की राय को, कि सरकार ऐसी सभी भूमि की मालिक है, मानकर सरकार के स्वामित्व को मान्यता प्रदान की थी<sup>८</sup>। इन अधिकारों को पुराने बिस्वेदारों को भी स्वीकार करना पड़ा। जब कर्नल डिविजन ने नये खेड़े बसाने और उन नये किसानों को जो इन्में विकसित करने व कुँए खोदने को तैयार थे, रियायतीदर पर यह भूमि देने का निर्णय किया तब कर्नल डिविजन की इस योजना का बिस्वेदारों ने कोई विरोध नहीं किया और न यह मांग ही की गया किसान इस भूमि का लगान उन्हें दिया करे।<sup>९</sup>



सन् १८१६ के बाद भूधृति में परिवर्तन :

सन् १८४६ में पहली बार गाँवों की सीमाओं का निर्धारण किया गया और ग्रामसभ की देखरेख में गाँव बन्दोबस्त किया गया। इस बन्दोबस्त से खालसा भूधृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। रैनवाली की जगह भोजावार की व्यवस्था लागू की गई<sup>१०</sup>। रैनवाली व्यवस्था में प्रत्येक किसान के घरने द्वारा विकसित भूमि में उसके कुछ विशेष हक स्वीकार किए गए थे परन्तु इसमें कृषक 'समाज' को हक नहीं थे वरन् यह अधिकार व्यक्तिगत किसान को ही था। भोजावार व्यवस्था के अन्तर्गत कृषक समाज को भाईचारा स्वामित्व सत्यान में बढा दिया गया था 'भोजा-वार व्यवस्था का सार यह है कि एक निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल जो उस गाँव का सीमा क्षेत्र होता था, उस गाँव के कृषक समाज की संपत्ति घोषित किया जाता था, और इस कृषक समाज को उस क्षेत्रफल की भूमि का मालिक समझा जाता था।<sup>११</sup> गाँव की सारी पड़ती भूमि गाँव तथा छोटे की सम्मिलित भूमि संपत्ति (ममालात जमीन) मान ली जाती थी। ये छोटे कर्नेल डिविजन द्वारा नये बसाए गए थे और उन्होंने पृथक् से इनकी व्यवस्था की थी।

मेरवाड़ा में मेरों की लूट-खसोट की वृत्ति, विरल जनसंख्या और पथरीली भूमि होने के कारण निश्चित भूधृति की प्रक्रिया का प्रादुर्भाव नहीं हो सका था। परन्तु इस क्षेत्र में भी जहाँ पहले राजपूत शासक शक्ति व्यवस्था स्थापित करने में असफल हुए थे वहाँ कर्नेल हॉल और डिविजन को सफलता मिली। उन्होंने वहाँ नए छोटे बसाए, तालाबों का निर्माण करवाया और किसानों को पट्टे जारी किए। सन् १८५१ के बन्दोबस्त में इन नए बसे हुए किसानों को भी सरकार ने पुराने किसानों के समकक्ष मान लिया और उनके कच्चे की भूमि में उनका मालिकाना हक स्वीकार कर लिया था।<sup>१२</sup>

**बिल्डर का प्रशासन :**

२८ जुलाई, १८१८ को भ्रजमेर झंसेजी राज्य में मिला लिया गया था। इसके पूर्ववर्ती वर्ष में, खालसा भूमि से वास्तविक भू-राजस्व में मराठों को कुल १,१२,०६० रुपये प्राप्त हुए थे।

भ्रजमेर के प्रथम सुपरिटेण्डेंट बिल्डर ने लगान की दरें 'संभावित घाघी फसल' निर्धारित की थी। बिल्डर ने भारत सरकार को प्रचलित व्यवस्था को रद्द करने का सुझाव दिया क्योंकि वे इसे अत्यन्त आपत्तिजनक एवं असंतोषप्रद मानते थे। उनका सुझाव था कि खालसा भूमि में प्राचीन परम्परा के अनुसार फसल को कूतकर उसके मूल्य को बाट लेना चाहिए। एफ बिल्डर ने दिनांक २७-६-१८१८ को सर डेविड पोस्टरलोनी को लिखा 'यदि आप स्वीकार करें तो मैं यह प्रस्तावित करने की अनुमति चाहता हूँ कि इस वर्ष सम्पूर्ण खालसा भूमि में फसल का बराबर भाग

करके, इससे पूर्व प्रचलित अत्यन्त आपत्तिजनक और असतोपजनक व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक भूराजस्व प्राप्त हो सवेगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके फलस्वरूप लोगों में जो संतोष और विश्वास उत्पन्न होगा उससे आगे चलकर लोगों में और अधिक उत्थम एवं विकास के प्रति परिश्रम की भावना को बल मिलेगा।" लोगों ने कूटी गई फसल का आधा मूल्य लगान के रूप में देना सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि पहले की व्यवस्था में भी आधी फसल राजस्व के रूप में ली जानी थी और निकटवर्ती पड़ोसी राजवाड़ों में भी इतना ही लगान लिया जाना था<sup>१३</sup>। पहले वर्ष सरकार को भू-राजस्व से ₹ ५६,७४६ रुपए प्राप्त हुए।

फसल के विभाजन की इस दर को एफ. विल्डर अत्यन्त प्रीतिपूर्ण मानते थे और इनकी यह भी मान्यता थी कि इससे निश्चय ही लोगों के मन में "नई सरकार की उदारता और न्यायप्रियता के प्रति विश्वास पैदा होगा।" उनकी मान्यता तो यहाँ तक थी कि तीन सालों में यह जमा दुगुना हो जाएगी जो अंग्रेजों के पूर्व किसी भी सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी थी और यह भी लोगों पर बिना किसी नए भार को थोपे ही उपलब्ध हो सकेगी<sup>१४</sup>। आगामी वर्षों में जमा में वृद्धि का भार में वे इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि तीन वर्ष का वार्षिक बन्दोबस्त लागू कर देना चाहिए जिसमें पहले वर्ष ₹ ७६,४३७ की राशि, दूसरे वर्ष ₹ २,०१,६६१ रुपए तथा तीसरे वर्ष ₹ २,४६,४३० की राशि भूराजस्व में किसानों से बमूल की जाए।<sup>१५</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि विल्डर को जिले के सीमित साधन व कृषि की गिरी हुई हालत का ज्ञान नहीं था। इसलिए उनके द्वारा निर्धारित राशि, अपूर्ण व अनिश्चित आँकड़ों व जानकारी पर आधारित थी।<sup>१६</sup> "वास्तव में वे इस क्षेत्र की वास्तविक परिस्थिति से अनभिज्ञ थे इसलिए उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में तथा लाहौर व बॉम्बे में एक गहरा अन्तर विशेषकर राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में परिलक्षित होता है। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह से सरकारी राजस्व में वृद्धि की जाए और यह वृद्धि किन सिद्धान्तों के आधार पर संभव है, इसके विश्लेषण का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने इस क्षेत्र में इतने अव्यवस्थित ढंग से काम किया कि न तो उन्होंने अपने द्वारा सुझाई गई पूर्ति के आचारों की जानकारी ही प्रदान की और न वे तथ्य ही प्रस्तुत किए जिनके आधार पर कथित कर व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। सरकार ने भी बन्दोबस्त का यह सुझाव कुछ हिचकिचाहट के साथ यह जानते हुए भी कि संभावित विकास कार्यों पर आधारित बन्दोबस्त हानिकारक व अनिश्चित हो सकता है, स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप आगे चलकर कृषकों की भावनाएं कुद हो चली और उनकी संपत्ति-संघर्ष में विकास कार्यों के प्रति भावना को भी ठेस पहुँची।<sup>१७</sup>

विल्डर के अनुमानों को पहले वर्ष में ही घबका लगा जबकि दोनों फसलें नष्ट हो जाने से बंदोबस्त असंभव हो गया। तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि सरकार एक निश्चित वार्षिक राशि १,६४,७०० रुपए लगान के रूप में वसूल करले तथा शेष रकम माफ कर दे। यह प्रस्ताव सरकार ने भी स्वीकार कर लिया और पाँचसाला बंदोबस्त की स्वीकृति प्रदान कर दी। चतुर्थ वर्ष में यह अनुभव किया गया कि उपर्युक्त निर्धारित राशि भी भारी पड़ती है और लोगों को राजस्व चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। यह स्थिति भी उन दिनों थी जबकि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में फसलें अच्छी हुई थीं। पाँचवें वर्ष अकाल की स्थिति पैदा हो जाने से केवल ३१,६२० रुपए की रकम ही राजस्व के रूप में वसूल की जा सकी।<sup>१८</sup> उस वर्ष १० जून तक छुटपुट बरसात हुई, इसके बाद केवल दो बीछारें १२ और २० अगस्त को हुई। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में सू की लपटों से तालाब और कुएँ सूख गए और खरीफ की फसल भुस्त कर नष्ट हो गई। इसके कारण बहुत से मवेशी मर गए और शेष बचे हुए पशुधन को लोग चराई के लिए भागवा की ओर ले गए। अनाज रुपए का बीस सेर बिकने लगा था। मार्च में दो बार भारी हिमपात (पाला पड़ना) से पहले से ही कमजोर बचीबुची रही की फसल भी नष्ट हो गई।

छः सूखे और अकालग्रस्त वर्ष अजमेर में बिताकर विल्डर महोदय दिसम्बर, १८२४ में स्थानांतरण पर दृग्यत्र चले गए। उन्होंने कभी भूमि की स्थिति व लोगों की हालत की सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं किया। यह एकदम अविश्वसनीय एवं शोका देने वाला तथ्य है कि जब अजमेर के पूरे राजस्व एवं पुलिस-प्रशासन का मासिक व्यय केवल १३७४ रुपए थे उनका अपना मासिक वेतन ही १००० रुपए था। विल्डर का दृष्टिकोण तत्कालीन अंग्रेज सरकार की नीति की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है।<sup>१९</sup>

### पूर्णव्यवस्था वाल (१८२४-४१)

विल्डर के स्थान पर नियुक्त हेनरी मिडलटन ने राजस्व भ्रष्टाचार के रूप में उगा-हने की नीति को पुनर्जीवित किया। उनकी यह धारणा थी कि 'नगदी के रूप में लगान देने के बजाय यह व्यवस्था गरीब किसानों द्वारा अधिक पसंद की जाएगी।'<sup>२०</sup> जिन्हें अकाल ने भूकम्भोर दिया है और जो इतने गरीब हो गए हैं कि अपने कुर्बानों तक की मरम्मत कराने में असमर्थ हैं तथा सूदखोरो के बगुल में कंठे पड़े हैं।' परन्तु पहले वर्ष (१८२१-२६) के अनुभवों से ही वे यह बात समझ गए कि यह व्यवस्था नहीं चल सकेगी। २६ नवम्बर, १८२६ तक उन्होंने नए साते तैयार कराए तथा सरकारी घास के सीतों का व्यापार गड वपों के आँकड़ों को रखा। राजस्व-कर उन्होंने १,४४,०७२ रुपए निश्चय किया और इसे पाँच साल के लिए मजूर किया। दोस्र ही यह बात भी सामने आ गई कि मिडलटन द्वारा घोषित गया लगान

भी अधिक है। निर्धारित राशि पहले साल उनके द्वारा वसूल की गई, परन्तु यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो गई कि आगामी वर्ष में इतनी राजस्व वसूली भी संभव नहीं हो सकेगी।<sup>२१</sup>

अक्टूबर, १८२७ में मिडलटन के स्थान पर केवेंडिश की नियुक्ति हुई। इन्होंने सहारनपुर जिले में राजस्व प्रशासन के कार्य का प्रच्छा अनुभव था। केवेंडिश उत्साही एवं योग्य अधिकारी थे उन्होंने शीघ्र ही इस्तमरार, भीम और जागीर के बारे में महत्वपूर्ण प्रकेक्षण किया। केवेंडिश ने कतिपय कारणों से मिडलटन द्वारा निर्धारित राजस्व को दुर्बल माना। उन्होंने लिखा कि कृषि योग्य भूमि उतनी ही रही है, जितनी मराठों के समय में थी जिससे वे केवल ८७,६८६ रुपये का राजस्व उगाहते थे। वह भी जबकि कूते की दर आधे से अधिक फसल की थी। अजमेर की भूमि पथ-रीसी होने से किसान को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और इसलिए आधी फसल लगान के रूप में देना उसकी क्षमता के बाहर है। कर-निर्धारण, भूमि की उपज के आधार पर नहीं होकर अनिर्धारित और मनमाने रूप में वसूल किया जाता है, और पहले का लगान उन अच्छे वर्षों के आधार पर किया गया है, जबकि आधामो भाव ऊँचे थे।<sup>२२</sup> उन्होंने मिडलटन द्वारा निर्धारित क्षेत्र में वे दरें लागू की जो उन्होंने पहले सहारनपुर में लागू की थीं और यह लेखा प्रस्तुत किया कि राजस्व १,४४,०७२ रुपये के बजाय ८७,६४५ रुपये होना चाहिए। उनके अनुसार प्रारम्भ से ही जिले में राजस्व तीन कारणों से अधिक कूता गया था। एक तो यह था कि मराठे अपनी ताकत के आधार पर बिना किसी नियमित आधार के किसानों से ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करते थे। दूसरा कारण यह था कि सधिया ने जब अजमेर अंग्रेजों को हस्तांतरित किया तो उसने यहाँ की राजस्व राशि को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। फलस्वरूप विल्डर ने उस असंभव स्तर की प्राप्ति के लिए भारी प्रयत्न किया। तीसरा कारण यह था कि सन् १८१८-१९ का वर्ष अजमेर के लिए खुशहाली का वर्ष था। जब कि पठोसी रियासती मेवाड़, मारवाड़ में पिछारी सरदार अमीर खान की लूटपाट के कारण कृषि चौपट हो जाने से वहाँ अन्न की भारी कमी हो गई थी और इन रियासतों में अनाज निर्यात के कारण अजमेर में भाव बहुत ऊँचे बढ़ गए थे। इस नव विजित क्षेत्र में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रथम कर निर्धारण चूँकि अनाज गलत भावों पर आधारित था इसलिए उम राशि की प्राप्ति असंभव थी। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने प्रवेश के समय प्रचलित भावों को आधार बना लिया था जो क्षेत्रीय प्रशासित के कारण काफी ऊँचे थे। वे यह अनुमान नहीं लगा सके कि शांति एवं व्यवस्था स्थापित होने व मार्ग खुले रहने से कृषि में वृद्धि एवं भावों का नीचे गिरना स्वाभाविक है।<sup>२३</sup>

केवेंडिश ने नया बन्दोबस्त करने व पुनः काल तथा अभाव की स्थिति में किसानों

को लगान देने के लिए बाध्य करने के बारे में सरकार को उन्होंने व्यक्तिगत जीज के आधार पर कूने का मुआव दिया जबकि मिडलटन की बन्दोबस्त प्रक्रिया में इसका ख्याल नहीं रखा गया था।<sup>२४</sup> इस बात पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला कि भ्रभाव के दिनों में जो छूट, सहायता इत्यादि इकट्ठी प्रदान की जाती है वह वास्तविक किसानों तक नहीं पहुँच पाती है। तहसीनदार, कानूनगों, पटवारी और पटेल इसे भ्राम्य में बोट लेते हैं। इस बात का थोर केवेंडिश को है कि उन्होंने पहली बार यहाँ पटवारी खातो की प्रथा चालू की। पटवारियों के हत्के में अधिक ग्राम रहे गए यहाँ तक कि अभी तक जिन ग्रामों के लिए बोई पटवारी नहीं था वहाँ भी पटवार व्यवस्था स्थापित की गई तथा प्रत्येक पटवारी को यह आदेश दिया गया कि वह जो भी रकम किसानों से वसूल करे उसकी लिखित रसीद प्रदान करे।<sup>२५</sup> सरकार ने केवेंडिश के प्रस्तावों को सामान्यतः स्वीकार किया परन्तु जहाँ तक लगान के भारी होने का प्रश्न था, यह निर्णय लिया कि नए बन्दोबस्त से पहले प्रत्येक ग्राम की वास्तविकता का पता लगाने का गंभीर प्रयत्न किया जाना चाहिए।<sup>२६</sup> यह भ्रजमेर का दुर्भाग्य ही था कि यहाँ का प्रथम बन्दोबस्त केवेंडिश जैसे कुशल अधिकारी की प्रेरणा मिडलटन जैसे व्यक्ति ने किया। अग्रज अधिकारियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उस साल खाद्यान्न के ऊँचे भावों के कारण राजस्व अधिक निर्धारित किया गया था। परन्तु फिर भी सरकार ने अपने राजस्व में संशोधन करना अस्वीकार कर दिया। सरकार ने केवेंडिश द्वारा प्रस्तावित कतिपय सुधारों एवं मुआवों को अवश्य स्वीकार कर लिया जैसे, भ्रकाल व भ्रभाव के दिनों में किसानों को छूट दो जाम इत्यादि। सत्य तो यह है कि जबकि भ्रजमेर में केवेंडिश रहे, किसानों को लगातार छूट मिलती रही और किसी भी वर्ष लगान की राशि मिडलटन द्वारा निर्धारित लगान की रकम तक नहीं पहुँच पाई।<sup>२७</sup>

केवेंडिश के उत्तराधिकारी मेजर स्पीयर्स ने नए बन्दोबस्त का कोई प्रयत्न नहीं किया परन्तु उसके साथ यह ध्यान रखते हुए कि निर्धारित लगान की रकम अत्यधिक भारी है, वे क्या समय छूट प्रदान करते हैं। यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया था कि मिडलटन के बन्दोबस्त में परिवर्तन आवश्यक है। एडमंस्टन ने जिनकी नियुक्ति मेजर स्पीयर्स के स्थान पर हुई थी अगले साल ही अत्यावधि बन्दोबस्त लागू किया और लगान की राशि १,१६,३०२ रुपए निर्धारित की तथा साथ ही यह श्रावधान भी रखा कि जो किसान बन्दोबस्त की नई दरों पर भुगतान न करना चाहे वे पुरानी खाम दरों पर फसल का आधा भाग कर के रूप में दे सकते हैं।<sup>२८</sup>

सन् १८३५-३६ में एडमंस्टन ने नियमित बन्दोबस्त का काम हाथ में लिया जिसे आगामी दस वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित होना था। अतएव इसे दश-वार्षिक बन्दोबस्त की संज्ञा दी गई। एडमंस्टन ने क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूर्ववर्ती

भूराजस्व की प्रशासनिक भूमि का घटितकृत चित्रण प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिले का विराम तो दूर रहा उसकी भवति हुई है। जामा को अधिक निर्धारित कर उसकी वसूली में जितनी कठिनाई हो उनकी अनियमित रूप से प्रतिबंध छूट देने की चली आ रही प्रथा को समाप्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया। एडमस्टन ने बेवेंडिश की तरह भूमि के भावों का अनुमान नहीं लगाया बल्कि उन्होंने कर निर्धारण-हेतु भावों का नियंत्रण करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की। ग्रामों की पैमाइश की गई जिसके अनुसार कृषि योग्य भूमि २६,२५७ एकड़ थी। उन्होंने इस भूमि को तीन श्रेणियों में विभक्त किया—बाही (सिंचित), ८,६८६ एकड़, तालाबी २१८० एकड़ और बाराही (प्रसिंचित) २५,०८८ एकड़। इसके पश्चात् उन्होंने नगदी फसलों वाली भूमि या दो फसली भूमि (मक्का और कपास) का संपन्न निश्चित किया जो लाम तहसील में उस समय प्रचलित मूल्यों के आधार पर था। इसके साथ ही उन्होंने प्रति बीघा अन्य फसलों की औसत उपज को भी रखा। पटेलों और महाजनों को छोड़कर लगान फसल का बाधा भाग निर्धारित किया व उसको नगदी में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के प्रचलित मूल्यों के औसत मूल्य को निर्धारित किया। इस तरह से वे एक काम चलाऊ जमाबंदी प्राप्त करने में सफल रहे, जो १५७,१५१ रुपये के लगभग थी। उन्होंने प्रत्येक ग्राम का दौरा किया और प्रत्येक जगह के बारे में सरकारी लगान की भाग पिछली वित्तीय स्थिति, वर्तमान हालत और भावी संभावनाओं के संदर्भ में निर्धारित की और किसी भी ग्राम को छोड़ा नहीं गया। दो छोटे गाँवों को लाम में लिया गया क्योंकि वे एडमस्टन के निर्धारित स्तर के निम्न नहीं हुए। शेष ग्रामों ने उनकी शर्तें स्वीकार कर ली थीं। बन्दोबस्त की निर्धारित शर्तें १२७,५२५ रुपये और खाम ग्रामों को जोड़ने पर उक्त राशि १,२६,८७२ रुपये निश्चित की गई।<sup>२६</sup>

एडमस्टन के मतानुसार भूमि-निवासी अधिकतर लापरवाह, दरिद्र और कर्जदार थे। बोहरे ग्रामों के एक तरह से स्वामी बन गए थे। वे किसानों को सरकारी लगान जमा करवाने व भवेली खरीदने के लिए रुपये कर्ज पर देते थे। वे ग्राम समाज के स्वर्ण को संचालित किया करते थे। यहाँ तक कि किसान ब्याह शादी या अन्य त्योहारों पर क्या खर्च करेंगे, यह भी इनसे संचालित होता था। महाजन किसानों को ऋण का हिमाव नहीं देते थे, और इनसे लिया गया ऋण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता ही रहता था। एडमस्टन ने प्रत्येक ग्राम में राजस्व कर-निर्धारित करने के लिए भुविश से सम्पर्क स्थापित किया क्योंकि उनकी यह मान्यता थी कि वह ग्राम समाज की इच्छानुसार ही व्यवहार करता है।<sup>२७</sup>

दस वार्षिक बन्दोबस्त कृषि योग्य भूमि और व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर किया गया था। प्रत्येक ग्राम का कर-निर्धारण गारिड तथा प्रोबेसपूर्व

ढंग से किया गया था फिर भी यह कई माने में भ्रष्ट एवं असमान था क्योंकि गाँव का लगान प्रत्येक किसान पर समान रूप से बाँट दिया गया था। भ्रवतक किसान आधी फसल पट्टेनों को देते थे और गत्येक गाँव की राशि में जो कमी होती थी उसकी पूर्ति जो लोग खेती नहीं करते थे उनको करनी पड़ती थी। कैवेंडिश ने कुछ ग्रंथों में खेबट-प्रथा लागू की थी परन्तु सभी खेतदारों के सम्मिलित उत्तरदायित्व की भावना व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण जिले के लिए भ्रजनवी चीज थी। इसे एडमंस्टन ने पूरे जिले में पहली बार लागू किया। एक किसान, जिसका कर उपज का आधा भाग निर्धारित किया गया था, उसे फसल भ्रष्टी हो या बुरी हो, चुकाना ही पड़ता था। उसे इस प्रथा के अनुसार उन किसानों के कर की रकम भी चुकानी पड़ती जो किन्हीं कठिनाईयों के कारण दूसरी जगह चले गए थे या जिन्होंने साधन के अभाव में कृषि छोड़ कर मजदूरी पर निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया था।<sup>121</sup>

यद्यपि भ्रजमेर-मेरवाड़ा पर भ्रंशजों के प्राधिपत्य के बाद यह प्रथम व्यवस्थित बंदोबस्त होते हुए भी इसमें कई गंभीर दोष थे। लगान की दर, जो फसल का आधा भाग थी, बहुत अधिक थी। वास्तव में यह दर उत्तर-पश्चिमी सूबों की प्रति एकड़ राजस्व भार से दुगुनी थी।<sup>122</sup> अतएव, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किसान और अन्य लोग यह माग करने लगे थे कि वास्तविक उपज के आधार पर लगान वसूली की प्रथा पुनः जारी की जाय। यद्यपि सरकार ने बंदोबस्त में किसी तरह के आधारभूत परिवर्तनों की इजाजत नहीं दी थी तथापि आधी को यह छूट दी गई कि वे चाहें तो सीधी व्यवस्था के अन्तर्गत जा सकते हैं। ८१ ग्रामों ने इसे स्वीकार कर राहत की माग की। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि एडमंस्टन का बंदोबस्त उन किसानों की स्थिति सुधारने में असफल रहा, जो अभाव के कारण अपने कुर्बानों की मरम्मत करने और अपनी जोतों को सुधारने में असमर्थ थे।<sup>123</sup>

कर्नल सदरलैंड जिन्होंने एडमंस्टन के जाने के कुछ ही दिनों बाद भ्रजमेर के कमिश्नर का पद सम्भाला था, कर-निर्धारण की इस प्रथा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस प्रथा को भ्रजमेर जिले के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त ठहराया तथा एक भलग ही ढंग की प्रक्रिया सुझाई जो कर्नल ड्विगसन द्वारा मेरवाड़ा में लागू की गई थी। सदरलैंड ने अनुभव किया कि यदि वैसी ही व्यवस्था भ्रजमेर के लिए लागू की जाय तो वह पूर्णतया लोकप्रिय सिद्ध होगी। कर्नल सदरलैंड ने जनवरी, १८४१ में अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि कपास, मक्का, गन्ना और अफीम की फसल देने वाली जोतों पर नकद दर लागू की जाए और अन्य फसलों वाली जोतों की पैमाइश की जाकर लगान बढ़ी की जाए तथा उपज का एक तिहाई भाग सरकारी राजस्व के रूप में लिया जाए व निश्चित प्रमुख मंडियों में प्रचलित बाजार भावी वार्षिक

आधार पर उसे नगदी में परिवर्तित किया जाय ।<sup>3४</sup> नई भूमि पर खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप यह सुझाव दिया कि इनसे भूराजस्व प्रथम वर्ष में फसल का छठा भाग, दूसरे वर्ष में पांचवा भाग, तीसरे वर्ष में चौथा भाग और तत्पश्चात् तीसरा भाग लिया जाना चाहिए । उन किसानों को जो मेड़बंदी करें या नये कुएँ खोदें उन्हें राजस्व में कुछ छूट भी दी जाए जिससे अधिकाधिक पड़त भूमि में खेती को प्रोत्साहन मिल सके ।<sup>3५</sup>

### कमल डिक्सन का बन्दोबस्त (१८४२)

इन सुझावों के आधार पर सदरसैंड ने डिक्सन के बन्दोबस्त की भूमि का तैयार की जो भजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के इतिहास में एक मानक सिद्ध हुआ है । फरवरी, १८४२ में भजमेर के सुपरिटेण्डेंट पद पर नियुक्त होने के पूर्व डिक्सन मेरवाड़ा के सुपरिटेण्डेंट थे और वहाँ उनका प्रशासन इतना सफा रहा कि भारत सरकार ने भजमेर जिले की कर-निर्धारण जैसी पेचीदी समस्या भी उनके हाथों में सौंपने का निर्णय लिया ।

डिक्सन के आगमन के साथ ही भजमेर जिले में भौतिक विकास का नया चरण प्रारम्भ हुआ । आगामी छ वर्षों में अकेले मेड़बंदी के निर्माण और मरम्मत पर ही ४,५२,७०७ रुपए सरकार ने व्यय किए । कृषि विकास के लिए किसानों को सरकार ने उदार ऋण प्रदान किए । लगान की सरकारी माँग धाधे से घटाकर १/२ कर दी गई । इसके साथ ही किसानों को यह सुविधा भी प्रदान की गई कि जो इसे स्वीकार न करता चाहे वह पुरानी छाम व्यवस्था मंजूर कर सकता है । जब कभी कोई नया तालाब बनाया जाता या मरम्मत की जाती तो लगान के साथ निर्माण व्यय का कुछ प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जाता था ।<sup>3६</sup>

कमल डिक्सन ने भजमेर जिले में कर-निर्धारण के संवत्स में भी मेरवाड़ा के ग्रामों में अपने द्वारा किए गए राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के अनुभवों का उपयोग किया । वे ग्राम उनकी सीधी व्यवस्था के अन्तर्गत थे । एडमस्टन द्वारा निर्धारित लगान से उन्होंने प्रति गाँव पर आठ प्रतिशत रुपए तालाबों के निर्माण में व्यय किए गए तथा व्यय की पूर्ति के लिए जोडे । जब कभी उन्हें यह अनुभव होता कि कोई ग्राम इस राशि का भार सहज बहन कर सकता है, तभी वे उस ग्राम पर यह भार लगाते थे । यदि उन्हें यह लगता कि कोई ग्राम इससे अधिक राशि देने में भी समर्थ है तो वे उसका लगान ऊँचा रखते व यदि कोई ग्राम सामान्य स्तर भी पूरा करने में असमर्थ होता तो वे निर्धारित राशि कम कर देते थे । लगान निर्धारित होने के पश्चात् ही लगान की दरें निर्धारित की जाती थीं । अलग-अलग गाँवों में आपस में राजस्व भार की भिन्नता के कारणों की कभी समझने का प्रयास नहीं किया गया । जिले की पूर्ण जानकारी के बावजूद कमल डिक्सन अपने वे पूर्व निर्धारित लगान में व्याप्त



प्रसमानता को नहीं रोक सके<sup>३७</sup> ।

लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय में १,५८,२७३ रुपये की राशि उचित थी । इसके अनुसार वे एडमंस्टन द्वारा निर्धारित लगान में तालाबों के निर्माण पर किए गए खर्च का ६ प्रतिशत व्यय भार और जोड़ देना चाहते थे । सन् १८४७-४८ में सरकार के लिए फसल की दो तिहाई वसूली संभव हो सकी तथा १,६७,२३७ रुपये की राशि खजाने को उपलब्ध हुई । एडमंस्टन की लगान व्यवस्था के मुकाबले में किसानों को टिक्सन की व्यवस्था के अन्तर्गत कम भार लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि अभिचित क्षेत्र में कृषि का बहुत विकास हुआ<sup>३८</sup> ।

कर्नेल टिक्सन को धरने द्वारा की गई व्यवस्था की व्यावहारिकता पर पूर्ण विश्वास था । नई बन्दोबस्त प्रक्रिया को प्रमत्त करने हुए उन्होंने कहा “यदि मौसम अनुकूल रहा और तालाब भर गए तो लोग आसानी से हवी-बुशी लगान चुका सकेंगे । यदि सूखा पड़ता है तो हमने इतनी छूट की व्यवस्था कर ली है कि लगान भरने की पीड़ा लोगों को छू तक नहीं सकेगी । यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हमने लाभ जनता के लिए रखे हैं और धरने लिए घाटे का भार । भ्रममेर-मेरवाड़ा जैसे क्षेत्र में जहाँ मौसम प्रायः ही अनिश्चित रहता है जमींदारों को बकाया लगान ■ लिख, जबकि फसल हुई ही नहीं हो परेमान करना, उन्हें हतोत्साहित करता है ।”

कर्नेल टिक्सन के नए बन्दोबस्त की मंशा प्रकाश के वर्षों को छोड़कर आसानी जमा वसूली की नहीं थी । उसने लगान की रकम इतनी ऊँची निर्धारित की कि जिसे टिक्सन के अनुसार बन्देख वगैरे में वसूल किया जा सकता था । परन्तु उन्होंने आवश्यकतानुसार छूट देने की व्यवस्था भी रखी थी । जनता ने इसे बड़े धनमने ढग से स्वीकार किया था । कर्नेल टिक्सन ने अपने बन्दोबस्त पर टिप्पणी करते हुए कहा “जनता को यह समझने में कि इस व्यवस्था में उनके हिस्से और लाभ को मुख्य स्थान दिया गया है, हमारा प्रयास व्यर्थ रहा ।” राजगढ़ परगने ने तत्काल नए लगान की स्वीकार कर लिया । रामसर के किसानों ने, जिन पर काफी भारी लगान लागू किया गया था कुछ हिक्किनाहट अवश्य दिखाई परन्तु टिक्सन के प्रभाव और उनके समझाने से नयी व्यवस्था स्वीकार कर ली ।

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यद्यपि बन्दोबस्त की स्वीकृति प्रदान कर दी थी परन्तु उनके मन में यह भय प्रचलित था कि लगान इतना अधिक है कि सम्भवतः यह जिला इतनी राशि आसानी से संग्रहण नहीं कर सकेगा । परन्तु उन्हें कर्नेल टिक्सन के स्थानीय अनुभव और क्षेत्र के बारे में गहरी जानकारी के प्रति विश्वास के कारण इस पर पारंगति प्रकट नहीं की । कोर्टे वॉल्ट डापरेवर्ट्स को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर वैसा ही संदेश इस नई व्यवस्था के बारे में था परन्तु घट में कर्नेल टिक्सन द्वारा

प्रस्तावित बन्दोबस्त उसी रूप में इक्कीस वर्षों के लिए स्वीकार कर लिया गया। बन्दोबस्त के अन्तर्गत निर्धारित कर नहीं देने पर यहाँ भंखूस करने व खाम व्यवस्था लागू करने का प्रावधान था।

यह बन्दोबस्त केवल नाम के लिए ही मौज्जावार था। कर्नल डिवसन ने बसूली की ओ पद्धति अपनाई उससे यह व्यवहार में रयतवारी बन गया था। कर्नल डिवसन ने ग्रामों को हल्कों में विभाजित कर, प्रत्येक हल्के की बसूली के लिए एक खपरासी के अधीन रखा था। खपरासी—पटेल और पटवारी की सहायता से प्रत्येक जोतदार से पटवारी के रजिस्टर में उसके नाम के ग्रामे खड़ी रकम वसूल करता था। यदि जोतदार किन्हीं कारणों से यह राशि नहीं चुकाता तो ग्राम के बलिए के माध्यम से जिसके यहाँ उसका खाता होता था, यह रकम वसूल कर ली जाती थी। यदि निर्धारित राजस्व बसूली के ये सभी तरीके निष्फल रहते तो कर्नल डिवसन को यह निर्णय लेना होता था कि इसमें कितनी छूट दी जानी चाहिए और वे इस प्रस्तावित छूट की राशि की स्वीकृति के लिए सरकार को प्रार्थना करते थे। इस तरह की छूट के लिए मई, १८३४ में कर्नल डिवसन ने १६,३२५ रुपए की राशि सरकार को प्रस्तावित की थी। यदि किसी ग्राम का लगान चुकाने में कोई बाधा उपस्थित होती तो डिप्टी कलेक्टर को वहाँ भेज कर लगान को नए सिरे से विभाजित करने की व्यवस्था की जाती थी। इस तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया पुरानी मौज्जावार पद्धति से मौलिक रूप से ही भिन्न थी। इस व्यवस्था के लिए ऐसे कलेक्टरों की आवश्यकता थी जिन्हें ग्राम के साधन-स्रोतों की पूरी-पूरी जानकारी हो<sup>३०</sup>।

ग्रामेर का बन्दोबस्त सम्पन्न करने के बाद कर्नल डिवसन ने मेरवाड़ा में लगान-निर्धारण का काम हाथ में लिया। मेरवाड़ा के बारे में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने किसी तरह का निर्देशन व नियम लागू नहीं किया। कर्नल डिवसन को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई कि वे जो भी उचित समझें लागू कर सकते हैं। डिवसन २७ सितम्बर, १८५० को मेरवाड़ा में भी बन्दोबस्त लागू करने में सफल हुए<sup>३१</sup>। गया बन्दोबस्त बीस साला था। बन्दोबस्त में वार्षिक राजस्व की राशि १,८८,७४२ रुपए निर्धारित की गई<sup>३२</sup>।

कर्नल डिवसन ने इस बन्दोबस्त में न तो भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने वाली विशद प्रक्रिया और न मूल्य-निर्धारण की ही प्रक्रिया अपनाई। किसी भी ग्राम के लिए एक मानक माप को निर्धारित करते समय उन्होंने एडमस्टन द्वारा निर्धारित लगान को आधार माना और जलाशय या मेडबन्दी का ६ प्रतिशत निर्माण-व्यय और जोड़ दिया। कर्नल डिवसन ने इस जिले के बारे में अपने गहन अनुभवों के आधार पर और भी कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ग्राम की पैगाइश होने के बाद लगान निर्धारित किया गया। इसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों के राजस्व

का भार एक-सा नहीं था। कर्नल डिक्सन ने पहले ग्रामों की हालत का अध्ययन किया और जब उन्हें यह विश्वास हुआ कि अमुक गाँव उपज का प्राया हिस्सा और अगर वहाँ तालाब का निर्माण हुआ है तो ६ प्रतिशत निर्माण कर देने की स्थिति में है, तो उन्होंने उतना उस गाँव का लगान निश्चित कर दिया। अगर उन्हें यह मालूम पड़ता कि किसान इससे अधिक दे सकते हैं या इतना नहीं दे सकते तो राशि को घटाया या बढ़ाया जा सकता था<sup>४२</sup>।

डिक्सन का बन्दोबस्त सतोपजनक कुंज से काम करता रहा और सन् १८४७-४८ में सरकार को राजस्व से राशि १,६७,२३७ रुपए प्राप्त हुए। अबतक प्राप्त राजस्व में उपरोक्त राशि सर्वाधिक थी। यह राशि उनके द्वारा प्रस्तावित १,७५,७५६ की राशि के लगभग थी। उपरोक्त राशि उन्होंने १ प्रतिशत सड़क का कर घटाकर तथा १ प्रतिशत जलाशय-निर्माण कर के समावेश के आधार पर प्रस्तावित की थी।<sup>४३</sup>

सन् १८५७ में कर्नल डिक्सन की मृत्यु से अजमेर जिले की उनकी सेवाओं से वंचित होना पड़ा। उनके निधन के साथ ही क्षेत्र में भौतिक विकास एवं नव-निर्माण का युग समाप्त हो गया। निस्मदेह उनके प्रशासन-काल में प्रकृति भी अनुकूल रही। उनके बाद राजस्व से प्राप्त राशि स्थिर रही। उनके बन्दोबस्त के सिद्धान्त को भुना दिया गया और यह भावना जनै, जनै: बन पकड़ती गई कि निर्धारित लगान सरकार की एक निश्चित वार्षिक माँग है जिसकी पूरी वसूली आवश्यक है।<sup>४४</sup>

कर्नल डिक्सन के बाद बन्दोबस्त एवं कर-निर्धारण की यह जटिल समस्या अजमेर के प्रथम डिप्टी चीफ कमिशनर कैप्टन जे० सी० ब्रुकस ने अपने हाथ में ली। उन्होंने २४ जुलाई, १८५८ को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शाम-लात की भूमि से प्राप्त लाभ का कोई लेखा नहीं रखा गया है और छूट की राशि सम्पूर्ण गाँव द्वारा उपयोग करने के कारण वास्तविक पीड़ितों तक पूरी नहीं पहुँच पाती है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने तालाब के पेटे की भूमि पर लगान की अधिक व अनुचित टहराया। उन्होंने पटवारियों की वेतन वृद्धि कर उनकी वार्षिक स्थिति को मुधारा तथा उनके हत्कों में और छोटे-छोटे गाँव जोड़ दिए ताकि काम की कमी न रहे।<sup>४५</sup> ब्रुकस ने यह अनुभव किया कि इस बन्दोबस्त में किसानों पर कर का भार अधिक है क्योंकि गन् तीन वर्षों में गेहूँ और जौ के बाजार भाव पूर्व स्तर से घाटे रह गए थे।<sup>४६</sup> सन् १८६७ तक राजस्व की राशि पूरी वसूल की जाती रही। सन् १८६६ में राजस्व प्रत्येक ग्राम के पटेल से वसूल करने के आदेश लागू किए गए।<sup>४७</sup>

साहूत का बाधोबस्त :

पुराने बन्दोबस्त की समाप्ति की अवधि समीप आ जाने से सन् १८७१ में साहूत को नए बन्दोबस्त के लिए बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रजमेर के कमिश्नर सॉन्डर्स ने उन्हें इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक निर्देशन प्रदान किया। उनसे जहाँ तक सम्भव हो सके प्रत्येक पटवारी के हल्के में एक जरीब सत्रिय रखने की सलाह दी गई ताकि काब जल्दी पूरा हो सके तथा उन्हें यथासम्भव प्रत्येक ग्राम के जोतदार की विगनवार तफ्तील तैयार करने को कहा गया जिसमें उनके जोत की भूमि और उसकी खेती का उल्लेख हो। पैमाइशों के दौरान क्षेत्रीय मानचित्र भी तैयार करवाने व पैमाइशों के सम्पन्न हो जाने के बाद प्रत्येक जोतदार को स्थानीय क्षेत्रीय मानचित्र की तथा बन्दोबस्त रेकर्ड में उसकी प्रविष्टि की एक-एक प्रति प्रदान करने का आदेश भी दिया गया।<sup>४८</sup>

खतोनी और खसरा के बारे में निम्नांकित प्रविष्टियां सुझाई गई—

१. कमांक
२. सम्बरदार का नाम
३. भालिक का नाम, जाति, पैतृक-हिस्से की राशि तथा हिस्से का भाग।
४. जोतदार का नाम, जाति, पैतृक, मीरसी अथवा नहीं कुल जोत।
५. गुजारा सूची में दर्ज खेतों की संख्या।

क्षेत्रफल—

६. उत्तर-दक्षिण मील
७. पूर्व-पश्चिम मील

सर्वे का विस्तृत क्षेत्र—

८. पड़त
९. कृषियोग्य
१०. नव तोड़

भूमि की किस्म—

११. कुँओं से सिंचित
१२. भग्न खेतों से सिंचित
१३. असिंचित
१४. कुल रकबा

## १५. फसलों की विगते

संगान—

१६. दर

१७. राशि<sup>५३</sup>

डब्ल्यू. जे. साहू की यह दृष्टि मान्यता थी कि मूल संगान अत्यधिक निर्धारित था।<sup>५४</sup> कृषियोग्य भूमि में विशेष वृद्धि नहीं हुई थी यद्यपि कुँए काफी संख्या में खोदे गए थे तथापि अधिकांश कुँए उन क्षेत्रों में खोदे गए हैं जहाँ जलाशयों से सिंचाई होती थी। उनके अनुसार अकाल के बाद कृषि-सम्पत्ति में उल्लेखनीय ह्रास हुआ था। अकाल के कारण पशुओं की संख्या बहुत कम हो गई थी। डब्ल्यू. जे. साहू का कहना था कि उन्हें राजस्व कर उपज का छठा भाग रखने का निर्देश दिया गया था जबकि कई गाँव ऐसे थे जिनसे एक चौथाई राजस्व प्राप्त किया जा सकता था।<sup>५५</sup>

साहू ने नए संगान का निर्धारण ग्रामों के आधार पर न करके खेड़ों के आधार पर किया। गवर्नर जनरल ने भी उनके इस कदम का स्वागत किया।<sup>५६</sup> यह अनुभव किया गया कि पहाड़ियों और घाटियों के कारण ग्राम एक दूसरे से अधिक पृथक् हैं और खेड़ों के लोगों के एक स्वाम पर जमा रहने के कारण आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना विद्यमान है। इसलिए संगान उनके आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह जानते हुए भी कि इन प्रकार के पृथक्करण से लोगों से संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना शिथिल होगी, इसे व्यावहारिक रूप दिया गया।<sup>५७</sup> इस पद्धति का एक लाभ यह हुआ कि पहले ग्रामों पर एक सा ही राजस्व भार था उसके बजाय विभिन्न स्तर के ग्रामों में राजस्व की विभिन्न दरें लागू की गईं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उन्होंने संगान निर्धारित करने के लिए ग्रामों को घसम-घसम समूहों में विभक्त किया और इन समूहों में कुछ आदर्श ग्राम छाटे जो आसानी से राजस्व चुकाते रहे थे। इन आदर्श ग्रामों की धार की राशि के आधार पर उन्होंने विभिन्न श्रेणियों की मिट्टी वाले गेहों के लिए उपयुक्त दरें निर्धारित कीं।<sup>५८</sup> उन्होंने एक सामान्य मध्ये वर्ग में एक एकड़ भूमि में प्राप्त उपज की इन दरों के निर्धारण का आधार माना।<sup>५९</sup> साहू द्वारा प्रयुक्त भूमि की बिस्ती पर आधारित दरों की प्रक्रिया को बाद में अन्य ग्रामों में भी लागू किया गया जहाँ पूर्ववर्ती वर्गों के धोकड़ों से यह ज्ञात हो सका कि ये दरें निर्धारित राशि का सुपनाय आसानी से कर पाने में समर्थ हैं।<sup>६०</sup> अज्ञान के वर्ग के बारे में शुनी तौर पर यह स्वीकार किया कि "अज्ञानि भूराजस्व बगुन नही होगा।"<sup>६१</sup> साहू की राय में किसान का बन्दोबस्त सीमम के विधीय तथा मूल संगान अत्यधिक ऊँचा होने के कारण घसपस रहा था। सरकार ने भी राजस्व की दरों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की

भावश्यकता को महसूस करते हुए साहस को इस पर विचार करने के लिए कहा ।<sup>५८</sup>

सिंचाई कर की समस्या का भी साहस ने हल निकाला । उन्होंने सिंचाई कर को राजस्व से पृथक् करके निर्धारित किया । तालाबों का वर्गीकरण उनकी सिंचाई की क्षमता के आधार पर प्रत्येक तालाब से सिंचाई कर की भाय की निश्चित राशि निर्धारित कर दी गई, जो कि उस तालाब से पानी लेने वाले किसान से वसूल की जाती थी । इससे भावपाशी में कुछ सीमा तक स्थिरता आ सकी । सम्पूर्ण भजमेर-मेरवाड़ा की भावपाशी की राशि ५५,४३२ रुपए निर्धारित की गई । तालाब से सीधी जाने वाली जमीन (तालाबी) की प्रति एकड़ अधिकतम न्यूनतम व औसत दरें क्रमशः ५-५ रुपए, ३-६ रुपए व ३-८ रुपए निर्धारित की गई । तालाबों के सूखे जाने पर उनके पेढे की जमीन जो भाबी कहलाती थी उसकी दरें क्रमशः १-१४ रुपए और १-६ रुपए प्रति बीघा निर्धारित की गई ।<sup>५९</sup>

किसान अपना लगान ग्राम के किसी भी मुखिए के माध्यम से जमा करा सकते थे । इस पद्धति के अनुसार मुखिया ग्राम का "वास्तविक प्रतिनिधि" बन गया था और संयुक्त उत्तरदायित्व की भ्रंसगतियां बहुत कुछ समाप्त हो गई थी । यद्यपि उन दिनों संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रणाली को स्थाई रूप से समाप्त नहीं किया जा सका था ।<sup>६०</sup>

राजस्व, जिसमें भावपाशी कर भी सम्मिलित था मेरवाड़ा में १,१८,६६१ रुपए एवं भजमेर में १,४२,८६६ रुपए निर्धारित किया गया । इस तरह दोनों जिलों को मिलाकर कुल राजस्व राशि २,६१,५५७ रुपए निर्धारित हुई । साहस द्वारा भजमेर-मेरवाड़ा के लिए निर्धारित सरकारी देय राशि डिविजन के बन्दोबस्त की निर्धारित राशि से १४ प्रतिशत कम थी । सरकारी भाय में से ५ प्रतिशत सम्बरदारों के वेतन व्यय तथा १ प्रतिशत हल्का मुखिया के वेतन के रूप में काट दिया जाता था ।<sup>६१</sup>

साहस के बन्दोबस्त को दस वर्षों से बन्दोबस्त के रूप में स्वीकार किया गया । केवल सन् १८७७ और १८७८ के सूखे के वर्षों को छोड़कर शेष वर्ष सामान्य थे । सन् १८७७ में भी लोगों ने निर्धारित लगान की पूरी राशि भदा की थी । वास्तव में सन् १८८० से १८८४ तक केवल ६५५ रुपयों की भजमेर में तथा ५६१ रुपयों की मेरवाड़ा में छूट दी गई ।<sup>६२</sup>

साहस द्वारा निर्धारित दसवर्षी बन्दोबस्त की अवधि सन् १८८४ में समाप्त हो रही थी । सन् १८८२ में भारत सरकार ने लगान मुक्तवी और छूट की समस्याओं की ओर ध्यान दिया और यह अनुभव किया गया कि इस दिशा में नए सिरे से विचार की भावश्यकता है । नई प्रक्रिया इतनी परिवर्तनीय न हो कि समूची करा-धान व्यवस्था ही पुनः नए सिरे से करनी पड़े । विशेषतः भारत सरकार इस बारे

में उत्सुक थी कि सूखे एवं अनिश्चित भू-भागों में जारी परिवर्तनीय कराधान की पद्धति परीक्षण के तौर पर एक निश्चित भू-भाग में जारी रखकर उससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर देश में अन्यत्र भी ऐसे भू-भागों में लागू की जाय।<sup>१३</sup> इस पद्धति के अन्तर्गत प्रशिक्षित पटवारी और कानूनगो की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे मानचित्रों और रेकर्डों को समय-समय पर तैयार किया जा सके।<sup>१४</sup>

सातह के बन्दोबस्त के बाद जूँकि कृषि भूमि में अधिक वृद्धि हो गई थी तथा सन् १८६८ का वर्ष जिसमें कि बन्दोबस्त की दरें लागू की गई थीं प्रकाल का वर्ष होने के कारण लगान की दरें निर्धारित हुई थीं इसलिए नए बन्दोबस्त की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। सन् १८८२ में सरकार ने नया बन्दोबस्त करवाने का फैसला किया। इस कार्य के लिए उत्तर-पश्चिमी सूबे की सरकार से एक अनुभवी अधिकारी की मांग की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस कार्य के लिए अपने प्रांत के अनुभवी बन्दोबस्त अधिकारी वार्डवे को सेवाएँ भूजमेर को प्रदान कीं।<sup>१५</sup>

**वार्डवे द्वारा प्रस्तावित सुधार**

वार्डवे ने लगान निश्चित करने के लिए ग्राम की इकाई माना। टालाब अथवा कुँधो से युक्त ग्रामों तथा कुँधो की खुदाई की सम्भावना से युक्त घाटियों को इस प्रकार का क्षेत्र निर्धारित किया जिसके लगान में घट-बढ़ नहीं हो सकती थी। मेरवाड़ा में सभी क्षेत्रों की उपयुक्त थेली में रखा गया जबकि भूजमेर में १९६ ग्रामों में से ६१ ग्रामों की इस प्रकार की थेली में रखा गया जिनके लगान में घट-बढ़ हो सकती थी। जिसे हम परिवर्तनीय क्षेत्र कह सकते हैं।<sup>१६</sup>

अपरिवर्तनीय लगान वाले क्षेत्रों के कर-निर्धारण के लिए अतिरिक्त भूमि की तीन साल की औसत उपज की दर का आधार तथा इन तीन सालों में दो अच्छे साल और एक मुश्किल साल रखा गया। इस क्षेत्र में से सातह द्वारा बन्दोबस्त किया हुआ क्षेत्र छोड़ दिया गया और क्षेत्रों का राजस्व अतिरिक्त भूमि की दर पर तय किया गया। अतिरिक्त भूमि में १२,२७० एकड़ की वृद्धि पाई गई जिससे वार्डवे की व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व में २७,००० की राशि की वृद्धि निर्धारित हुई।<sup>१७</sup>

परिवर्तनीय लगान वाले क्षेत्रों के कर-निर्धारण के लिए, ग्रामों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया—वे ग्राम जिनके कर का निर्धारण स्थाई रूप से दिया जाय तथा वे ग्राम जिनमें समयानुसार परिवर्तनशील दरें लागू होती रहें। वार्डवे महोदय ने परीक्षण के तौर पर भूजमेर और मेरवाड़ा के कुछ ग्रामों का चयन किया और उनमें परिवर्तनशील पद्धति लागू की। परिवर्तनशील पद्धति लागू करना कठिन था क्योंकि अतिरिक्त भूमि पर राजस्व की दरें बहुत कम थीं। इसके अतिरिक्त परिवर्तनशील पद्धति किसी पहाड़ी ग्राम में लागू भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि उनमें कृषि

भूमि सदा उतनी ही बनी रहती थी और सामान्य वर्षों में भी धजमेर-मेरवाड़ा में फसलो की उपज सतोपजनक ही होती थी। यहाँ, खेतों की मेड़ बांध कर उनमें वर्षा का जल रोका जाता था। पुष्कर तहसील की भी परिवर्तनशील लगान-पद्धति में से हटा देना पड़ा क्योंकि मिट्टी के टीलो के खेतों में बिखरने से जमीन के उपजाऊ-पन में वृद्धि होकर अच्छी फसलें होती थीं, विशेषतः यन्ना और बाजरा। प्रसिद्धि भूमि अधिकांशतः धजमेर के गणवाना, राजगढ और रामसर चकलों में थी। परिवर्तनशील पद्धति के परीक्षण के तौर पर, वाईटवे ने धजमेर में २६ गाँव तथा ब्यावर के १७ गाँव छाने।<sup>१८</sup> उनके द्वारा अपनाया गया सिद्धांत यह था कि निर्धारित राशि और विद्युत् बन्दोबस्त के समय की लगान-दरों को अपरिवर्तित रहने दिया जाय इनमें कुँओं से मुक्त वे भूखण्ड नहीं थे जिन्हें सरकार ने लोगों की प्रदान किए थे।<sup>१९</sup>

वाईटवे ने यह सिफारिश की कि वह सारी भूमि जो कि कुँओं व नाड़ी से सींची जाती है और जो लाहस के बन्दोबस्त के समय थी उनसे आबपाशी पर लगान दर वसूल किया जाय। दो फसली भूमि के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि उस भूमि में जो कुँओं से सिंचित होती है और जिससे दो फसलें सी जाती हैं उनसे प्रथम फसल पर पूरी दर वसूल की जानी चाहिए और दूसरी फसल पर एक चौथाई ज्यादा वसूल होनी चाहिए। जिस भूमि पर एक फसल वर्षा से होती है और दूसरी सिंचाई से बर्हा कर की बमूनी दोनों दरों के अनुसार होनी चाहिए।<sup>२०</sup> प्रसिद्धि दो फसली भूमि के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि उससे दोनों फसलों पर एक ही लगान वसूल किया जाना चाहिए।<sup>२१</sup> भारत सरकार ने वाईटवे महोदय को यह सलाह दी थी कि जिले के ग्रामों की तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए—

१. निर्धारित स्थाई लगान वाले ग्राम।
२. परिवर्तनीय लगान वाले ग्राम।
३. वे ग्राम जिनमें अंशतः स्थाई और अंशतः परिवर्तनीय लगान लागू हैं।<sup>२२</sup>

क्षेत्र की भौगोलिक बनावट एवं वर्षा की अनिश्चितता के कारण किसी भी जोतदार के पास सम्पूर्ण जोत कदाचित् ही सिंचित जोत रही होगी। उसकी जोत में प्रसिद्धि कृषि भूमि का समावेश था जिसकी उपज नाममात्र थी। वाईटवे ने किसी भी ग्राम को अंशतः स्थाई और अंशतः परिवर्तनीय लगान वाले क्षेत्र की श्रेणी में नहीं विभाजित किया जबतक कि उस ग्राम की प्राकृतिक बनावट से ऐसे दो स्पष्ट भाग न भलसकते हों।<sup>२३</sup>

वाईटवे ने अपनी रिपोर्ट में कहा “मैंने जो व्यवस्था प्रस्तावित की है, इसके अनुसार ग्राम का लगान प्रसिद्धि भूमि वाली दरों से सम्बन्ध रखता है जो भविष्य



में मूल्यों में वृद्धि होने पर बढ़ाया जा सकता है ताकि सरकार को उचित लगान प्राप्त हो सके। साथ ही भविष्य में कभी लगान में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव किए जाने पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यह परिवर्तन केवल सामान्य कुपि भूमि में वृद्धि पर ही निरंतर करेगा और इसके फलस्वरूप लगान में भी स्वाभाविक वृद्धि हो सकेगी।" वार्टवे के अनुसार इस व्यवस्था की मन्द्छाई यह थी कि सरकार और किसान दोनों की मन्द्छी फसलों के लाभ प्राप्त होते थे और सकट के दिनों में दोनों को ही हानि उठानी पड़ती थी।<sup>७४</sup>

भीषण भूकाल या प्राकृतिक कोप के दिनों के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि कमिशनर को ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिनके अन्तर्गत वह भूतलित भूमि की मौसम फसल को "शून्य", "धीयाई" या "भाधी उपज" के रूप में घोषित कर सके। ऐसे मामलों में तलित भूमि का लगान उतना ही रहना चाहिए, परन्तु यदि फसल "भाधी" घोषित की जाती है तो चार एकड़ भूतलित भूमि को दो एकड़ के तुल्य और यदि फसल "एक धीयाई" घोषित होती है तो एक एकड़ को "शून्य" के बराबर मानकर लगान नहीं लिया जाना चाहिए।<sup>७५</sup>

परिवर्तनीय लगान की उनकी पद्धति निम्नांकित उदाहरणों से जो स्वयं वार्टवे ने प्रस्तुत किए हैं, आसानी से समझी जा सकती है—

"अमुक ग्राम में यह निश्चित किया गया है कि निम्नांकित भूमि सामान्यतः जोत-भूमि में है—

एकड़	प्रति एकड़	कराधान
	रुपए में	रुपए में
भूतलित १२४	—१० घाने	७७।८
भाधी ४०	१।६	६२।८
तालाब ८	२।१३	२२।८
कुएँ ५०	३।१२	१८७।८
२२२		३५०—

इस क्षेत्र की भूतलित इकाई के बहुभंश में घटाने पर जिसकी कि भावी दरें भूतलित की मझाई गुणी, तालाबों साडे चार गुणी और कुओं से तलित भूमि की लगान दरें ६ गुणी होती हैं। भूतलित क्षेत्र के रूप में लिए जाने पर उपरोक्त क्षेत्र इस प्रकार होता:—

	एकड़
प्रसिंचित	१२४: १ = १२४
घाबी	४०: २½ = १००
तासाबी	८: ४½ = ३६
कुँघों वाली	२०: ६ = ३००
	<u>४६०</u>

उन्होंने यह भी विज्ञापण किया कि यह उपर्युक्त ५६० एकड़ "प्रसिंचित क्षेत्र" कहलाएगा और दस आना प्रति एकड़ के हिसाब से प्रसिंचित दर द्वारा गुणित किए जाने पर इससे ३५० रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।<sup>७४</sup>

प्रसिंचित क्षेत्र में प्रतिवर्ष हेरफेर होता था अतएव भूराजस्व भी प्रतिवर्ष घटता-बढ़ता रहता था। वार्डवे के अनुसार यह स्थिति ठस सकती थी यदि प्रसिंचित दरें एक विशेष सीमा तक ही परिवर्तित की जाएं। वार्डवे का कहना था कि हम यह मान सकते हैं कि अमुक ग्राम के मामले में उपरोक्त सीमा पौने नौ आने तक की है और सवा ग्यारह आने तक अच्छी फसल के दिनों की दरें हैं तो उपरोक्त दर पूर्व दर तक बढ़ सकती है और भ्रकाल के दिनों में बाढ़ की दर तक घटाई जा सकती है। इससे यह लगान भी प्रभावित नहीं होगा जिसके बारे में हम मानते हैं कि प्रसिंचित भूमि इकाई की मानक दर दस आना है।<sup>७५</sup>

उपरोक्त बन्दोबस्त बीस वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, तथापि इसकी अवधि समाप्त होने के दिनों में सरकार ने इसमें कुछ विशेष संशोधन किए। ये संशोधन मुख्यतः परिवर्तनशील लगान वाले ग्रामों के बारे में थे। परिवर्तनशील लगान की प्रक्रिया लोकप्रिय नहीं हुई और सरकार ने समय-समय पर परिवर्तनशील लगान के ह्यान पर निश्चित लगान लागू किया। सन् १८६५ में, राजस्व के विलम्बन और छूट के बारे में विशेष नियम निर्धारित किए गए। इन नियमों के अन्तर्गत जो व्यवस्था लागू की गई वह इतनी लाभप्रद रही कि भ्रकाल एवं प्राकृतिक सफट के समय, छूट के मामले में अविलम्ब कार्यवाही की जा सकी थी।<sup>७६</sup>

मजमेर-मेरवाड़ा में किसानों की राहत पहुँचाने की परम्परा सी चली आ रही थी। जो भी किसान अपनी जमीन पर कुँए आदि खुदवाकर विकास करता था, उस पर उस बन्दोबस्त तथा आगामी बन्दोबस्त के दौरान बड़ी हुई दरें लागू नहीं की जाती थी। यही प्रक्रिया तकावी ऋण और अन्य निजी कर्जों द्वारा विकास कार्यों पर भी लागू होती थी। इस्तमरारदारी जमींदारियों में बड़ी दरों का भार तत्काल लागू कर दिया जाता था और वहाँ इन पर कर-निर्धारण से छूट की अवधि किसी भी सूरत में आठ साल से अधिक नहीं होती थी। कुछ भार तो

विकास के पहले वर्ष ही लागू कर दिया जाता था। इतने कड़े नियमों के बावजूद भी इस्तमरारदारी किसान खालसा क्षेत्र के किसानों की तुलना में अधिक समृद्ध थे जबकि खालसा भूमि के किसान उन दिनों भारी कर्जों में डूबे हुए थे। अधि-प्राप्ति कानून की पैचीदगी और जमानत सम्बन्धी बड़े कड़े नियमों के कारण खालसा-भूमि के किसान सन् १५८३ के एक्ट १६ के अन्तर्गत अधि के लिए प्रार्थनापत्र देना बहुत ही असह्य नहीं करते थे।<sup>१७</sup>

यद्यपि खालसा-भूमि में भूप्राप्ति निर्धारित करने का काम कम समय में संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया था तथापि राजस्व की स्थाई माग्यार प्रदान करने की समस्या वैसी ही बनी रही। मराठों ने यहाँ नाममात्र का भी बन्दोवस्त नहीं किया था। विहडर (१८१५-२४) व मिडल्टन (१८२४-२७) ने, जो कि यहाँ अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ में अधिकारी नियुक्त हुए थे इस क्षेत्र की गरीबी का सही ज्ञान न होने के कारण कुछ समृद्ध वर्गों के भाँकड़ों व मराठों द्वारा उगाई गई रकम पर विश्वास करने के कारण राजस्व की राशि बहुत ऊँची निर्धारित की थी। कैम्ब्रिज के सुधारों ने राजस्व प्रशासन को कुछ व्यवस्थित हो दिया था। एडमंड्सन इस बापिक बन्दोवस्त जो अजमेर-मेरवाड़ा के अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत आने के बाद प्रथम व्यवस्थित बन्दोवस्त था लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि इसमें निर्धारित संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रणाली के प्रति किसानों में उत्साह का अभाव था।

कर्नल डिकसन कलादस का बन्दोवस्त इस वर्गों के लिए लागू किया गया था। बन्दोवस्त सम्बन्धी कतिपय समस्याओं की गम्भीरता से नहीं लेने के कारण अधिक सफल नहीं रहा। वाईटवे महोदय ने भी इस दिशा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परन्तु बार-बार अकाल का होना, कम उपजाऊ भूमि और वर्षा की अनिश्चितता के कारण अजमेर-मेरवाड़ा में लगान की निर्धारित बापिक राशि की वसूली अत्यन्त धीरे धीरे दोनों ही मौसम में संतोषप्रद नहीं हो सकी।

## अध्याय ४

१. जे. डी. लाट्स—“सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २६ (१८७४)
२. उपरोक्त।
३. एडिस्टेंट कमिशनर द्वारा कमिशनर अजमेर को पत्र, तस्मा २६८१ दिनांक ६ अगस्त, १८०६।
४. जे. डी. लाट्स—“सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २७ (१८७४)

५. उपरोक्त पृ. २७ (१८७४)
६. सुपरि. एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ऑस्टरलोनी को पत्र, दी भजमेर, राजस्व कार्यालय, २७ सितम्बर, १८१८ (रा. रा. पु. मण्डल) ।
७. जे. डी. लाट्टस—“सेटलमेंट रिपोर्ट भजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २७ (१८७४) ।
८. उपरोक्त ।
९. उपरोक्त ।
१०. बी. एच. डॉडन पोवेस “ए मेन्स्युशन ऑफ दी सैंड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लेण्ड टेन्पोर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया” पृ. ५२६-२८ ।
११. जे. डी. लाट्टस—“सेटलमेंट रिपोर्ट भजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २७ (१८७४)
१२. उपरोक्त ।
१३. श्री एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ऑस्टरलोनी को पत्र दिनांक २७-६-१८१८ (रा. रा. पु. मं.)
१४. श्री विल्डर सुपरि. भजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ऑस्टरलोनी रेजीडेंट दिल्ली को पत्र दिनांक २७-६-१८१८ “सरकारी भूमि का प्रस्तावित राजस्व इस वर्ष लगभग १,४४,००० सेरशाही रुपए होगा । यह रकम उससे कहीं अधिक होगी जो बापू सिधिया को प्राप्त हुआ करती थी और साथ ही हम इस व्यवस्था में अपने भाषी बन्दोबस्त को लागू करने में सर्वोत्तम आधार लागू कर सकेंगे और बिना तौगों को असंतुष्ट किए दिनोदिन अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा । मुझे जो विभिन्न किसानों की सहायता उनके हल, कुँए, बीलों के विभिन्न लेखे प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार भाषी राजस्व भाज के उदार धौकड़ी की तुलना में कहीं अधिक प्राप्त होगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह राशि तीन या चार सालों में भासानी हैं दुगुनी हो जाएगी और हस्तमरार परगने भी हमारी व्यवस्था में सीपे जाए तो मुझे विश्वास है कि जो राशि अभी कूनी गई है अर्थात् २,६७,७६२ रुपए इसी तरह बढ़ कर हमारे राजस्व में जुड़ सकेंगे ।”
१५. श्री विल्डर सुपरि. भजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ऑस्टरलोनी, रेजीडेंट दिल्ली को पत्र दिनांक १८ फरवरी, १८२० ।
१६. श्री एफ. विल्डर, सुपरि. भजमेर ने सर डेविड ऑस्टरलोनी रेजीडेंट दिल्ली को पत्र (दिनांक २७-६-१८१८) लिखा कि भूमि की वनायट किस्म (इस सूबे की) के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह रेतीली होने के बावजूद अच्छी और अत्यधिक उपजाऊ है और दो फसलें पैदा की जा सकती

है तथा ऐसा शायद ही कोई ग्राम होगा जिसमें कुएँ नहीं हों और उनमें पानी २० या ३० फीट से अधिक गहरा हो। यहाँ की ज़मीन घना और जो की फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है।

१७. जे. डी. लाट्स "सेटलमेंट रिपोर्ट भजमेर-मेरवाड़ा" पृ. २०।
१८. श्री फ्रांसिस हार्किंस रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना द्वारा पत्र क्रमांक ५३, दिनांक १२-२-१८२३ रा. (रा. पु. मण्डल) लाट्स-गजेटिर्स भजमेर-मेरवाड़ा (१८७५) पृ. ६३।
१९. सर डेविड प्रॉक्टरसोनी द्वारा एच. मैकेंजी, सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक ६-१-१८२५ (रा. रा. पु. म.)।
२०. लाट्स-सेटलमेंट रिपोर्ट भजमेर-मेरवाड़ा, पृ. ७१ (१८७४)।
२१. उपरोक्त, पृ. ७१ और ७२।
२२. केबेंडिश का पत्र दिनांक १० मई, १८२३ (रा. रा. पु. मं.)।
२३. श्री केबेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट को पत्र दिनांक २६ अप्रैल, १८२६।
२४. व्यक्तिगत जेत को कूतने की व्यवस्था। खेवटदारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी।
२५. श्री केबेंडिश सुपरि. भजमेर द्वारा केलबुक रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना को पत्र दिनांक १० व १२ जुलाई, १८२६ (रा. रा. पु. मं.)।
२६. सचिव भारत सरकार का फ्रांसिस हार्किंस रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना को पत्र, क्रमांक ७४ दिनांक ६-२-१८३० (रा. रा. पु. मं.)।
२७. जे. डी. लाट्स "सेटलमेंट रिपोर्ट भजमेर-मेरवाड़ा" (१८७४) पृ. ७२-७३।
२८. उपरोक्त, पृ. ७४।
२९. एडमस्टन-सेटलमेंट रिपोर्ट, दिनांक २६ मई, १८३६ (रा. रा. पु. मं.)।
३०. उपरोक्त।
३१. भ्रमाल के दिनों में अन्य प्रदेशों की भाग जाने वाले 'फरार' व छेटी छोड़ कर शारीरिक श्रम से मजदूरी कमाने वाले 'नादर' कहलाते थे।
३२. लाट्स—"सेटलमेंट रिपोर्ट भजमेर-मेरवाड़ा" (१८७४), पृ. ७५।
३३. सी. सी. वाट्सन-राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, भजमेर-मेरवाड़ा, १-ए (१९०४), पृ. १२।
३४. उपरोक्त पृ. १३।

३५. उपरोक्त पृ. १३ ।
३६. कर्नल डिवसन द्वारा डब्ल्यू. म्यूर सचिव उ. प्र. सरकार, भागसा, क्रमांक २६५ (१८५६) रा. रा. पु. मं. ।
३७. फाइल क्रमांक १८३, कमिशनर कार्यालय, भूमि प्रशासन, राजस्व बन्दो-बस्त और सर्वे बन्दोबस्त रेकॉर्ड, प्राचीन क्रम 'बी' १८५०-१८५२, (रा. रा. पु. मं.) ।
३८. उपरोक्त ।
३९. फाइल क्रमांक 'बी' ३ । ५ प्रा. १८५० से १८५२-अजमेर सेटलमेंट रिपोर्ट, कर्नल डिवसन (रा. रा. पु. मं.) ।
४०. कर्नल डिवसन द्वारा जे. घार्टन सचिव उ. प्र. सू. सरकार को पत्रसंख्या २७८, १८५० दिनांक २७-६-१८५० ।
४१. लाहस-सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा (१८७४) पृ. १०४ ।
४२. पत्र संख्या १५८, १८५२ । कर्नल डिवसन द्वारा डब्ल्यू. म्यूर उ. प्र. सूबा सरकार को पत्र संख्या १५८, १८५१ (रा. रा. पु. मं.) ।
४३. जे. डी. लाहस "सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा" (१८७४) पृ. ७८ ।
४४. जे. सी. ब्रुक्स द्वारा पत्र दिनांक २४ जुलाई, १८५८ ।
४५. डेविडसन द्वारा मेजर ईडन कार्यवाहक कमिशनर अजमेर को पत्र संख्या १४६ फाइल क्रमांक १४४५ (रा. रा. पु. मं.) ।
४६. उपरोक्त ।
४७. लायड डिप्टी कमिशनर अजमेर द्वारा मेजर ईडन कार्यवाहक कमिशनर को पत्र दिनांक ७-१२-१८५६ (रा. रा. पु. मं.) ।
४८. सॉइर्स कमिशनर अजमेर द्वारा ब्रुक्स चीफ कमिशनर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक ८-११-१८७१ (रा. रा. पु. मं.) ।
४९. एचिसन सचिव भारत सरकार, परराष्ट्र विभाग द्वारा कार्यवाहक चीफ कमिशनर अजमेर को पत्र, दिनांक २८ अक्टूबर, १८७१ (रा. रा. पु. मं.) ।
५०. उपरोक्त ।
५१. लाहस द्वारा सॉइर्स कमिशनर अजमेर को पत्र दिनांक १६-४-१८७२ फाइल क्रमांक १६३, पृ. ८ ।
५२. ब्रुक्स-कार्यवाहक चीफ कमिशनर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा एचिसन सचिव भारत सरकार परराष्ट्र विभाग को पत्र दिनांक १३-२-१८७२ व परराष्ट्र

विभाग का पत्र क्रमांक ३७७ दिनांक २८ अक्टूबर, १८७१, अनु-  
च्छेद ३ ।

५३. साउथ्स कमिश्नर द्वारा ब्रुक्स चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दि.  
२३ अप्रैल, १८७२ (रा. रा. पु. मं.) ।

५४. सेटलमेंट रिपोर्ट १८७४ ।

५५. सादूस द्वारा साउथ्स कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को १६ अप्रैल, १८७२  
(रा. रा. पु. मं.) ।

५६. उपरोक्त ।

५७. सेटलमेंट रिपोर्ट १८७५ ।

५८. सादूस द्वारा साउथ्स कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १६ अप्रैल,  
१८७२ (रा० रा० पु० म०) ।

५९. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, खण्ड १-ए (१९०४)  
भजमेर-मेरवाड़ा, पृष्ठ ५४० ।

६०. वाडेन पावेल—"ए मेन्स्यूस आफ दी लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लेड  
टेन्थोरस ऑफ इंडिया" पृष्ठ ५४० ।

६१. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, खण्ड १-ए, (१९०४)  
भजमेर-मेरवाड़ा, पृष्ठ २९ ।

६२. उपरोक्त, पृष्ठ २९ व ब्रुक्स कार्यवाहक चीफ कमिश्नर द्वारा एचिसन  
सचिव भारत सरकार परराष्ट्र को पत्र, दिनांक १२ जून, १८७२ ।

६३. सचिव, भारत सरकार का चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दि०  
९ अक्टूबर, १८८७ (रा० रा० पु० म०) ।

६४. उपरोक्त (रा० रा० पु० म०) ।

६५. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, खण्ड १-ए (१९०४)  
पृष्ठ २३-२४ ।

६६. उपरोक्त ।

६७. उपरोक्त ।

६८. भार० एम० बार्डवे द्वारा एल० एस० साउथ्स कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा  
को पत्र दिनांक ११ जुलाई, १८८४ (रा० रा० पु० म०) ।

६९. एच० एम० ह्यूरोड सचिव, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-  
मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १८८७, फाइल क्रमांक २९ ।

७०. वार्डवे, बन्दोबस्त अधिकारी, भजमेर-मेरवाडा द्वारा सॉडर्स कमिश्नर भजमेर-मेरवाडा को पत्र दिनांक १६ जून, १८८५ (रा० रा० पु० म०) ।
  ७१. उपरोक्त ।
  ७२. उपरोक्त ।
  ७३. वार्डवे, बन्दोबस्त अधिकारी भजमेर-मेरवाडा द्वारा कमिश्नर भजमेर को पत्र, दिनांक १६ जनवरी, १८८६ (रा० रा० पु० म०) ।
  ७४. उपरोक्त ।      ६०
  ७५. उपरोक्त ।
  ७६. उपरोक्त ।
  ७७. उपरोक्त ।
  ७८. सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, खण्ड १-ए (१९०४) भजमेर-मेरवाडा, पृष्ठ २६-२७ ।
  ७९. कमिश्नर, भजमेर-मेरवाडा द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाडा को पत्र, दिनांक २७ फरवरी, १८९१ (रा० रा० पु० म०) ।
-



## इस्तमरारदारी व्यवस्था

मजमेर-मेरवाड़ा में भूमि की व्यवस्था पड़ोसी राजपूत रियासतों जैसी ही थी। भूमि सामान्यतः दो भागों में विभक्त थी—तालुकेदारी और खालसा। तालुकेदारी भूमि वह थी जो अधिकांशतः जागीरदारों के पास ठिकानों के रूप में थी। इन ठिकानों के अधिपति यद्यपि धारम्भ में अपने राजाओं व सरदारों की सैनिक सेवा के लिए बाध्य थे तथापि कालांतर में इस प्रथा का स्थान इस्तमरारदारी प्रथा ने ले लिया था। राजस्थान में राज्य का अनादिकाल से भूमि पर वास्तविक स्वामित्व जाता आ रहा था। राज्य में जिन सामंतों को ठिकाने प्रदान किए थे भी अपनी प्रजा पर राज्य जैसे अधिकारों का प्रयोग किया करते थे।<sup>१</sup>

कर्नल टॉड ने राजस्थान की सामंत-व्यवस्था की व्याख्या एक ऐसी व्यवस्था के रूप में की है जो समाज के सभी तत्वों पर छाई हुई रहती है। उन्होंने इसकी यूरोप की मध्यकालीन सामंत-प्रथा से तुलना की है।<sup>२</sup> यह हो सकता है कि यूरोप के इन मध्यकालीन राज्यों और राजस्थान के सामंतों के मध्य परम्परागत एव प्रथाओं की कुछ समानता हो, परन्तु हम आधार पर दोनों को एक मान लेना अथवा उनमें से एक को दूसरे की अनुकृति कहना अनुचित है। यह हो सकता है कि दोनों के स्वरूप में कुछ समानता हो, परन्तु यह समानता केवल ऊपरी ही है।<sup>३</sup>

ये अपने स्वामित्व के आधार एवं प्राप्त की प्रक्रिया में एक दूसरे से भिन्न थे। कस्बेस्वरूप इन ठिकानों में विभिन्न प्रथाएं और परम्परागत अधिकार प्रचलित

ये जो ठिकाने की सेवाओं और सहयोग के आधार पर प्रदान किए गए थे। इन ठिकानेदारों का यह बर्तव्य था कि वह अपने स्वामी की सेवा करेंगे और स्वामी का यह बर्तव्य होता था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि इनमें से कोई भी ठिकानेदार इन नियमों का उल्लंघन करता तो उसका ठिकाना जब्त कर लिया जाता था। भापसी सहयोग ही एकमात्र ऐसी आधारशिला प्रतीत होती है, जिस पर सामन्त-व्यवस्था टिकी हुई थी।<sup>५</sup>

### भजमेर के ठिकानेदार

भजमेर के ठिकानेदारों को भी राजपूताना की रियासतों के जागीरदारों के समान विशेष अधिकार प्राप्त थे।<sup>६</sup> ये ठिकाने भी आरम्भ में सेवाओं के आधार पर प्रदान किए गए थे तथा कई सामन्त व्यवस्थाओं से प्रतिबधित थे। कर्नल टॉड के अनुसार ये ठिकाने सीधे उत्तराधिकारी को वंश परम्परागत भोग के लिए जीवनपर्यन्त प्राप्त हुआ करते थे और सीधे उत्तराधिकारी के अभाव में राजा द्वारा स्वीकृत गोद लिए व्यक्ति को विरासत में मिला करते थे। किसी भी अपराध या भ्रमोन्मत्ता की स्थिति में सरकार इन ठिकानों को छीन सकती थी। नए उत्तराधिकारी से नजराना प्राप्त करने के पश्चात् ही राजा उसे जागीर प्रहण करने देता था। सभी तथ्य इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इन ठिकानों को राज्य जब चाहे तब पुनः प्रहण (जब्त) करने में समर्थ था।<sup>७</sup> भजमेर के अधिकांश ठिकानों के भोग की स्थिति वही थी जो कर्नल टॉड द्वारा वर्णित है। यद्यपि ये ठिकाने ठिकानेदार को उसके जीवनकाल के लिए प्रदान किए जाते थे व मृत्यु के पश्चात् इनके खालसा किए जाने की व्यवस्था थी परन्तु कालान्तर में ये वंशपरम्परागत बन गए थे।<sup>८</sup>

भजमेर में अंग्रेजों के आगमन के समय इस सामन्त-व्यवस्था के अन्तर्गत ७० ठिकानेदार तथा चार छोटे ठिकानेदार थे जो "इस्तमरारदार" कहलाते थे। इनमें से ६४ ठिकाने राठोड़ी के, १ तिसोदियों का, १ गीड़ राजपूत और ४ चीतों के प्राप्त थे। इन ठिकानों में से १६८ गाँवों से फौज खर्च वसूल किया जाता रहा था और ७६ गाँवों पर यह कर सागू नहीं था। ये ठिकाने आरम्भ में जागीरें थीं, जो कि सैनिक सेवाओं के उपलक्ष में प्रदान की गई थीं। ठिकानेदार, जिसे कि वे प्रदान की गई थी उसकी मृत्यु पर ये राज्य (जिसने प्रदान किए थे) द्वारा अपने हाथ में लिए जा सकते थे परन्तु दूसरी जागीरों के समान बाद में ये भी वंशपरम्परागत हो गई थी। भजमेर के ये ठिकाने, सम्पूर्ण मुगलकाल, अल्पकालीन अर्थ स्पष्ट नहीं हैं। जोधपुर रियासत के राज्य-काल में व मराठों के शासन-काल में मौजूद थे।<sup>९</sup>

भजमेर के अधिकांश ठिकानों की 'बखशीश' के मूल कारणों का ज्ञान करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि कई मामलों में मूल बखशीशदाता व मूल प्राप्तकर्ता का नाम और निज आधारों पर ये ठिकाने दिए गए थे उनका प्रमाण उपलब्ध नहीं होता

है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इनमें से कुछ जागीरें गुहिलों, चौहानों तथा राठोड़ों के द्वारा दी गई थी। मुगलों द्वारा मनसबदारी प्रथा<sup>१०</sup> के अन्तर्गत सैनिक सेवाओं के उपलक्ष में भी कुछ जागीरें प्रदान की गई थीं। मिनाय,<sup>११</sup> सावर,<sup>१२</sup> जूनिय,<sup>१३</sup> मसूदा,<sup>१४</sup> पीसागन,<sup>१५</sup> के ठिकानेदार मुगलों के मनसबदार थे। इनमें से मिनाय ठिकाना सबसे पुराना था। जहाँ तक पद और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मिनाय के बाद द्वितीय स्थान मसूदा ठिकाने का है। राठोड़ों के पाम जो ठिकाने थे उनमें अधिकांश औरंगजेब द्वारा तत्कालीन जोधपुर महाराजा जसवंतसिंह के कारण उनके संबंधियों और मित्रों को प्रदान किए गए थे।<sup>१६</sup>

मुगल काल में ये ठिकाने मनसबदारी प्रथा के अन्तर्गत दिए जाते थे तथा ठिकानेदारों को सम्राट की फौज के लिए एक निश्चित संख्या में घुड़सवार प्रदान करने पड़ते थे। मुगल शासकों ने मनसबदारी को निरन्तर बदलते रहने की परम्परा रखी थी ताकि ये लोग अधिक शक्तिशाली न बन सकें। उनकी (जागीरदार की) मृत्यु के साथ ही जागीर और मनसब स्वतः सम्राट की हो जाती थी। यदि मुगल साम्राज्य एक तावत के रूप में कायम रहता तो वर्तमान ठिकानेदारों के पूर्वज कभी के इन ठिकानों से हटा दिए गए होते।<sup>१७</sup> मुगल काल में भजमेर में ये ठिकाने बराबर बने रहे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भजमेर का सूबा जोधपुर महाराजा के आधिपत्य में चला गया था। इस काल में अधिकांश ठिकाने दूसरे लोगों से बलपूर्वक छीन कर राठोड़ों को दे दिए गए थे।<sup>१८</sup> इन ठिकानेदारों का प्रारम्भ मात्र सही थीर पर बतलाना बटिन है। संभवतः इनमें से अधिकांश के पूर्वज हम क्षेत्र के मूल राजपूत नरेशों एवं विजेताओं के सम्बन्धी रहे होंगे। यह भी संभव है कि मारवाड़, मेवाड़, बूडार और हाडीनी के राजपूत मरदारों की तरह इन्हें भी ये अपनी जीत के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ हो अथवा यह ठिकाने दिल्ली के मुगल सम्राटों द्वारा अपनी तत्कालीन राजपूत विजेताओं द्वारा बख्शीय में दिए गए हों। इन इस्तमरारदारों के अधीन जो कस्बे व गाँव थे उनको देमते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि भजमेर के ठिकानेदारों को वास्तव में बड़े-बड़े भूभाग प्रदान किए गए थे। भजमेर में भजमेर के आधिपत्य के प्रारम्भिक दिनों में पूरे खालसा क्षेत्र में केवल ८१ गाँव थे जबकि इस्तमरारदारों के अधिकार में २८० कस्बे और गाँव थे। खालसा भूमि में चौसन भाग १,२६,००० रुपयों की थी जबकि इस्तमरारदारी ठिकानों की भाग ३,४०,००० रुपए थी। ये सभी इस्तमरारदारियाँ मराठों के आगमन के पूर्व से ही विद्यमान थी। केवल कुछ ही ऐसे ठिकाने थे जिनका दो या तीन सौ साल के पूर्व अस्तित्व न रहा हो। जर्नेल सदग्लैड की यह मान्यता थी कि इनके वंशपरम्परागत अधिकार का दावा निर्विवाद है।<sup>१९</sup> मराठा शासनकाल में ये इस्तमरारदार-राजा, तालुकेदार, इलाकादार, जमींदार, टाकुर और भूमिया महन्ताते थे। मराठा शासनकाल के अन्तर्गत इन ठिकानों को भोग की प्रणिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था।

मराठों को इन जागीरदारों की सैनिक सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें हमेशा पन की बहुत आवश्यकता रहती थी। फलस्वरूप उन्होंने इन जागीरों पर निर्धारित पुइसवारों की संख्या के आधार पर नगद राशि सैनिक सेवा समाप्त कर धीरे धीरे की। मराठों की नीति विभिन्न मदों के अन्तर्गत अपने राजस्व में वृद्धि करने की रही थी। उनके समय में सगान एवं भूपुति के कोई निश्चित प्रक्रिया एवं सिद्धांत नहीं थे। फलस्वरूप छोटे-छोटे ठिकानेदारों और जागीरदारों पर बड़े ठिकानों की तुलना में यह भार अधिक था क्योंकि बड़े ठिकानेदारों की शक्ति को देखते हुए उनसे विरोध मोल लेने व इन पर हाथ डालने का मराठों का भी माहम नहीं होता था।<sup>१६</sup>

### मराठा शासन-काल में परिवर्तन

मराठों की एक नीति थी 'जितना लिया जा सके ले लो' इन ठिकानेदारों में जो शक्तिशाली थे, उनके प्रति मराठों का हमलों की अपेक्षा थोड़ा बहुत पक्षपात मरा दृष्टिकोण रहता था। ये लोग अपना वार्षिक कर इच्छानुसार घटा बढ़ा लेते थे। इन पर लगाए जाने वाले उपकर भी निश्चित नहीं थे तथा हेमियत के अनुसार बदलते रहते थे। इन करों की समूची व निर्धारण का मापदण्ड मौसम की अनुकूलता, ठिकानेदार की परिस्थिति, उसकी शक्ति उमराव अपने सम्बन्धियों पर प्रभाव व साथ ही सूबेदार से उसकी मित्रता पर अधिक निर्भर करता था। इन दो मुख्य करों को छोड़कर ये 'अमल जामा' और 'फौज खर्च' कहलाते थे, मराठों ने अल्प कई उपकर लागू कर रले थे तथा इनकी सला घटने के बजाय बढ़ती ही रहती थी। मराठों ने ठिकानेदारी में एकदम कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया था। उन्होंने केवल विभिन्न मदों के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि की नीति अपनाई थी। मुगलों की अपेक्षा मराठों की व्यवस्था इन ठिकानेदारों के अधिक हित में थी क्योंकि मुगलों के शासन में ठिकाने जितने का यह भय सदा बना रहता था परन्तु मराठाकाल में यह भय नहीं था।<sup>१७</sup>

मराठों ने अन्तर्गत के ठिकानों के स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि उन्होंने उनके द्वारा प्रदत्त सैनिक सेवाओं के उपपक्ष में नगद मुगलान का आधार स्थापित किया। उपर्युक्त प्रथा के अन्त के साथ ही वह सामन्ती प्रक्रिया भी समाप्त हो चली जिसके अन्तर्गत ठिकानेदार और ठिकानों के वास्तविक स्वामी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते थे। इससे ठिकानों पर राज्य के नियन्त्रण की प्रक्रिया निर्जीव हो चली थी।<sup>१८</sup> मुगलों के काल में इन ठिकानों की बंशशील की प्रथा का आधार सैनिक सेवा था और सम्भवतः यह व्यवस्था जोधपुर नरेश महाराजा अजीतसिंह के शासनकाल में भी प्रचलित थी। सन् १७५४ में मराठों ने इस व्यवस्था से उठकारा था लिया और इसके विकल्प में उन्होंने वार्षिक कर को आधार बनाया। यह राजस्व समय-समय पर स्थानीय अधिकारियों की इच्छानुसार घट-बढ़

कर आँका जाता रहा, परन्तु सन् १८०८ या १८०९ के लगभग मराठों ने "असल जामा" को कम दर पर स्याई करने का प्रयास किया था। उन्होंने यह भी निर्णय लिया था कि भविष्य में इसके प्रतिरिक्त राजस्व वृद्धि अन्य करों या उपकरों के रूप में भ्रम से वसूल की जानी चाहिए। मराठों द्वारा लिए गए इस निर्णय का कारण कदाचित् यह रहा होगा कि कालांतर में कभी इस सूबे को जोधपुर रियासत को सौटाना पड़ सकता था या अन्य किसी परिवर्तन की स्थिति में इन करों व उपकरों को आसानी से माफ किया जा सकता था, जबकि इन्हें असली "जामा सम्मिलित करने पर यह संभव नहीं हो सकता था। सन् १८०८ से लेकर १८१८ तक अजमेर से तालिया और बापू सिधिया ने ३,४५,७४० रुपए की राशि वसूल की जिसमें से २,१०,२८० रुपए की राशि असल जामा के तौर पर थी और शेष विभिन्न करों एवं उपकरों से प्राप्त हुई थी। मराठा शासनकाल में अजमेर में इस प्रकार के लगभग ४० कर एवं उपकर प्रचलित थे।<sup>२२</sup>

### अग्नेश्वरी और इस्तमरारदार

मराठों ने कभी भी अपने अधीन ठिकानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उनकी मुख्य इच्छा धन बटोरने की थी। उन्होंने जागीरदारों को भूमि का स्वामी माना और किसानों को पूर्णतया उनकी दया पर छोड़ दिया। प्रजा के अधिकार, परम्पराओं और उनके हितों की मराठों ने अवहेलना की जिसके फलस्वरूप ठिकानेदारों का अपने ठिकाने में रहने वाली जनता पर स्वामित्व व असीमित अधिकार स्थापित हो गए थे। केवल इतना ही नहीं इन लोगों ने ठिकानों की प्रजा पर अनेक अनुचित कर एवं उपकर थोप दिए थे जिन्हें स्थानीय बोली में 'लाग-बाग' कहा जाता था।<sup>२३</sup>

अग्नेश्वरी ने इसमें परिवर्तन नहीं किया। सन् १८४१ तक ठिकानेदार प्रतिरिक्त कर वसूल करते रहे क्योंकि वे इसे असली 'जामा' का अंग समझते थे। यद्यपि उनकी वसूली भ्रम से वृषक मुद्दे के अन्तर्गत की जाती थी। अग्नेश्वरी सरकार भी कई वर्षों तक इन ठिकानों से वह सारी राशि वसूल करती रही, जो इनसे मराठे वसूल करते थे, क्योंकि अनिरिक्त करों से प्राप्त राशि सम्पूर्ण जिले के राजस्व की तीन चौपाई थी और इसके छोड़ देने से अत्यधिक आर्थिक हानि होती थी। अग्नेश्वरी ने इस्तमरारदारों को भूमिपति के रूप में स्वीकार नहीं किया था। सरकार ने इन्हें तालुकेदार माना जो सरकार के साथ आधे राजस्व के उपयोग में अधिकारी थे। यह विशेषाधिकार बणपरम्परागत था, परन्तु इसे किसी को बेचा नहीं जा सकता था और न किसी को मँट या बक्तोम में प्रदान किया जा सकता था।<sup>२४</sup>

अग्नेश्वरी ने ठिकानों के स्वरूप की सामान्य जानकारी प्राप्त किए बिना ही अजमेर के ठिकानेदारों को इस्तमरारदार मान लिया था। अजमेर के ठिकानेदार

इसके पूर्व कभी भी निश्चित त्याग कर के अधिकारी नहीं रहे थे, जबकि इस्तमरारदार शब्द के संकीर्ण अर्थ में यह अधिकार अतर्निहित होता है। अंग्रेजों ने इनके प्राय के भाग को निश्चित कर इनका नवीन नामकरण किया जिन्हें इस्तमरारदार कहते हैं। ये ठिकाने जिन भोग व्यवस्थाओं के आधार पर प्रारम्भ में प्रदान किए गए थे, उनके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार को प्राप्त अधिकार सनदें जाली थीं। थोड़ी बहुत जो सच्ची सनदें सामने भी आईं, उनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि अजमेर इस्तमरारदारों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि या तो जागीरों की थी या जीवनपर्यन्त भोग के आधार पर प्रदान किए गए ठिकाने थे। उनके आधार पर इन्हें इस्तमरारदार नहीं ठहराया जा सकता था।<sup>२३</sup>

अंग्रेज अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में अजमेर में प्रचलित विभिन्न भूवृत्ति प्रक्रियाओं को ठीक तरह से समझ नहीं सके थे। यदि वे इसका सम्पूर्ण अध्ययन करके निर्णय लेते तो वे भी ठीक मराठों की तरह प्रतिवर्ष या पाच व दस साल में लगान वृद्धि के हिस्से का अंश इन ठिकानों से लेने की व्यवस्था लागू करते। अंग्रेजों ने अपने प्रारंभिक काल से ही इन ठिकानेदारों को इस्तमरारदार स्वीकार कर लिया था। जिसकी वजह से बाद में इसमें किसी तरह का संशोधन अत्यन्त कठिन हो गया था। बाद में किसी भी संशोधन या परिवर्तन से इन ठिकानेदारों में स्थानीय अधिकारियों की प्रति ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के प्रति भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती थी। किसी भी परिवर्तन को लागू करना नितांत आवश्यक होने पर भी इस बात की सतर्कता रखी जाती थी कि परिवर्तन धीरे-धीरे एवं सामान्य रूप से लागू किया जाए। किसी भी इस्तमरारदार के निधन पर उसके पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार करते समय बहुधा उससे संशोधन स्वीकार करने को कहा जाता था। इस दिशा में अंग्रेजों के समक्ष केवल दो ही विकल्प थे एक तो स्थिति को यथावत् जारी रखना, अथवा पुरानी प्रक्रिया में संशोधन करने पर अपने प्रति इन ठिकानेदारों के तीव्र असंतोष का सामना करना। अंग्रेज शासन के प्रारंभिक दिनों में यह सकट भेलने को तैयार नहीं थे। अतएव उन्होंने स्थिति को यथावत् बनाए रखना एवं यथा समय सुझाव के रूप में परिवर्तन लाने का मार्ग ही ग्रहण किया।<sup>२४</sup>

अजमेर के इस्तमरारदारों ने अपने अधिकारों को भूमिपतियों के रूप में अन्य लोगों की अपेक्षा सबसे अधिक दृढ़ता से प्रस्तुत किए, जबकि उन्हें भूमिपति के वास्तविक अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे। केवेन्डिश की यह मान्यता थी कि जबतक किसी न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में उचित निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता है, तबतक के लिए अजमेर के ठिकानेदारों को अविध्य में सिर्फ जमींदार ही माना जाए।<sup>२५</sup>

इन इस्तमरारदारों की वैधानिक स्थिति अंग्रेजों की नज़रों में सदैव सदेहास्पद रही थी। विल्डर के अनुसार एक भी इस्तमरारदार अपने दावे के प्रमाणस्वरूप

विश्वसनीय सनद प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ था। विल्डर को तो यह संदेह था कि इनके पास शायद ही ऐसी कोई सनद रही होगी क्योंकि सभी ने यह तक प्रस्तुत किया कि भराजकता के दौरान उनकी सनदें नष्ट हो गईं थ्यवा खो गईं थी।<sup>२६</sup>

अजमेर में इस्तमरारदारी प्रथा का स्वरूप वयों के लम्बे पत्र व्यवहार के पश्चात् वही आकर निश्चित हो सका था। अजमेर के लगभग सभी भग्नेय अधिकारियों ने इस संदर्भ में गवर्नर जनरल को अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे क्योंकि सरकार पूरी जानकारी के बाद ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचना चाहती थी। स्थानीय भग्नेय अधिकारियों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी यहाँ इस्तमरारदारी व्यवस्था का कोई निश्चित एवं वैधानिक स्वरूप सही ढंग से निर्धारित करने में सफलता नहीं मिल सकी। भग्नेयों को भी यही नीति अपनानी पड़ी कि इन ठालुकेदारों का अस्तित्व किसी श्यायसगत आधार की भ्रष्टा वर्तमान स्वरूप के आधार पर ही स्वीकार कर लिया जाए।<sup>२७</sup>

इन इस्तमरारदारों की पुर्तनी एवं वैधानिक स्थिति के संबंध में सबसे पहली रिपोर्ट अजमेर के प्रथम सुपरिटेण्डेंट विल्डर ने प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार ये ठिकाने इस्तमरारदारी या निश्चित राजस्व के आधार पर शताब्दियों से इनको प्राप्त थे। इस तथ्य के बावजूद उनका सुझाव था कि भग्नेय सरकार को इन्हें इनसे ले लेना चाहिए ताकि भग्नेय प्रशासन का लाभ सामान्य जनता को सुलभ हो सके। विल्डर के मतानुसार इन जागीरदारों का अपने अधीनस्थ भूमि पर स्वामित्व का दावा अस्पष्ट था क्योंकि इनमें से एक भी इस सर्वे में विश्वसनीय सनद या प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा था। इनका दीर्घकालीन अधिकार ही एकमात्र उनके दावे का आधार था। विल्डर इन ठिकानेदारों का, राजस्व के इतने बड़े भाग पर स्वामित्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था कि यदि ये ठिकानेदार अपने ठिकानों की व्यवस्था भग्नेयों के हाम सौंपने को तैयार नहीं हैं तो इनसे प्राप्त भू-राजस्व में वृद्धि की जानी चाहिए अन्यथा जिले से प्राप्त राजस्व धीरे-धीरे घटकर नाममात्र का रह जाएगा।<sup>२८</sup>

सर डेविड मॉन्टगोमेरी ने भी इन इस्तमरारदारों के दावों पर विचार करते समय यह अनुभव किया था कि इन दावों के साथ सरकार के हितों का मेल बैठाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है। फलस्वरूप, उन्होंने इन इस्तमरारदारों की नत दम वर्षों के श्रमों का अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया कि यदि इन ठिकानों की व्यवस्था भग्नेय प्रशासन अपने हाथ में ले तो उचित मुमान्त्रा कितना देना चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि यदि ये लोग अपने अधिकार के प्रमाण स्वरूप सनदें भयवा अन्य तथ्य प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो

इनकी भूमि को लिया जा सकता है। ग्रॉन्टरनोनी तत्कालीन व्यवस्था में परिवर्तन के प्रबल इच्छुक थे और इन ठिकानेदारों द्वारा किसी भी तरह के परिवर्तन के विरोध को अनुचित समझते थे। उनका यह भी मत था कि ऐसे मामलों में कोई भी सरकार अन्य सरकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मानने या उन्हें यथावत् जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होती है।<sup>32</sup>

परन्तु ग्रंथेजी शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों में सरकार का दृष्टिकोण यह था कि सरकार को भूमिधारकों को प्रमाणस्वरूप सन्देश प्रस्तुत करने में प्रसमर्थ होने पर भी इस्तमरारदार मान लेना चाहिए क्योंकि सदियों से ठिकाने पर इनका अधिकार चला आ रहा था। तत्कालीन भारत सरकार इन ठिकानों से प्राप्त राजस्व की राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ के अनुपात में प्राप्त करना चाहती थी। सरकार का यह भी दृष्टिकोण था कि इन ठिकानों के कर-निर्धारण में वृद्धि की जा सकती है। सरकार ने भावी राजस्व के निर्धारण के लिए नए आधार प्रस्तुत करना इसलिए भी अत्यन्त आवश्यक समझा क्योंकि वर्तमान निर्धारित राशि से सरकार को भारी वार्षिक हानि उठानी पड़ती थी। यदि इन्हे ठिकानों का वास्तविक स्वामी स्वीकार कर लिया जाता तो सरकार इनके दस वर्ष के लाभ के औसत को अपनी भावी मांग का आधार मान सकती थी। वर्तमान लाभ के आधार पर सरकार का विचार इन्हें सम्पूर्ण लाभ से वंचित करने का नहीं था। यदि इन्हे भूस्वामी स्वीकार नहीं किया जाता तो इन्हे अपनी भूमि की व्यवस्था से मुक्त करना अत्यन्त कष्टदायक काम था। इन्हें अपनी भूमि से वंचित करने के लिए भी मुदावजे का आधार निश्चित करने का प्रश्न था। मुदावजे के आधार के लिए भी गत दस वर्षों के विकास कार्यों व कृषि-भूमि में वृद्धि से प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखकर ही निर्णय लिया जा सकता था। सरकार ने यह भी मत प्रकट किया था कि यदि इस्तमरारदारों को रखा जाता है तो जनता के संरक्षण के लिए भी सरकार को कदम उठाना आवश्यक होगा ऐसा करने में चाहे राजस्व के कुछ प्रशो से वंचित ही क्यों न होना पड़े। सरकार एक तरफ जनता के व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती थी और दूसरी तरफ इन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रदान किए गए इन ठिकानों को भी।<sup>33</sup>

इस सदर्भ में विल्डर के पत्र व्यवहार से यह ज्ञात होता है कि ये ठिकानेदार उनके राजस्व में किसी भी तरह की जाच के विरोध में थे। स्पष्टतः उनके इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप ग्रंथेज सरकार केवल इतना ही ज्ञात कर सकी कि ये ठिकानेदार जो अभी इन ठिकानों पर अधिकार किए हुए हैं प्राचीनकाल से वंशपरम्परागत रूप में उपभोग कर रहे थे।<sup>34</sup> विल्डर के पत्र इस घास्य पर कुछ प्रकाश डालते हैं कि इन भूस्वामियों के पास कितनी जमीन थी और ये सरकार को उसकी उपज का कितना भाग दिया करते थे और पुनर्ग्रहण व अन्य करों द्वारा इसमें कितनी वृद्धि



संभव थी।<sup>३५</sup> विल्डर का यह मत था कि इस मामले में पैमाइश ही सही न्यायिक सिद्ध हो सकती है, यद्यपि यह तथाकथित विरोधाधिकारों का उल्लंघन था। इस्तमरारदारो ने धारम्भ में इसका कड़ा विरोध भी किया परन्तु बाद में उन्हें इसकी स्वीकृति देनी पड़ी।<sup>३६</sup>

यद्यपि विल्डर इन ठिकानेदारों की आय के आंकड़े प्राप्त करने में सफल नहीं हुए तथापि वे बिना किसी भारी भ्रष्टाचार के इन ठिकानों की भूमि की पैमाइश का काम पूरा कर सके थे। वे इस निर्णय पर पहुँचे कि धारम्भ में इन ठिकानेदारों की जितनी आय अनुमानित थी, उससे कहीं अधिक वे प्राप्त करते हैं। विल्डर की यह मान्यता थी कि इन ठिकानों को यथास्थिति में बनाए रख कर भी सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि की संभावना है।<sup>३७</sup>

विल्डर के स्थानांतरण के पश्चात् उनके स्थान पर नियुक्त मिडलटन को इन इस्तमरारदारों से, जो सामान्यतः कर्ज में डूबे हुए थे, सरकारी राजस्व वसूल करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी यह मान्यता प्रकट की थी कि इन ठिकानेदारों के अधिकारों की वैधानिकता में संदेह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि भूमेजों की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इन्हें यथास्थिति में रहने दिया था और इन ठिकानेदारों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया था।<sup>३८</sup> केबेंडिश को उनकी भूमि-व्यवस्था, सम्पत्तियाँ, उनके अधिकार, विरोधाधिकार तथा उनके कर्तव्य के बारे में विस्तृत विवेचन सरकार को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था।<sup>३९</sup> कई घरानों के इतिहास की छानबीन के बाद केबेंडिश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मराठों ने सनद और पट्टों की कमी परबाह नहीं की और उन्होंने प्रत्येक ठाकुर की हस्तियत के अनुसार उससे पन राशि वसूल की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया है कि भूमेज सरकार को भी अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा उदाहरण का पालन करना चाहिए।<sup>४०</sup>

केबेंडिश ज्यों ज्यों इस सदर्भ में गहरे उत्तरते गए उन्हें पूर्ण विश्वास होता गया कि भूमेजों की यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार इन पर नया राजस्व लागू कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने यह अवश्य प्रकट किया कि कृषि के विस्तार एवं विकास के प्रोत्साहन स्वरूप यह आवश्यक होगा कि एक नियमित व व्यवस्थित प्रभार लागू किया जाए। उन्होंने सुझाया कि इस दिशा में सबसे अधिक लाभप्रद व्यवस्था यह होगी कि ठिकानेदार की अर्जित आय की राशि में से आठ भाग हिस्सा सरकार का हो। इन दिशा में वे यह चाहते थे कि सरकार अपना सउर मराठा शासन के अंतिम वर्ष को निर्धारित करे। केबेंडिश महोदय का यह दृष्टिकोण था कि यदि सरकार धारम्भ से ही इस्तमरारदारियों की व्यवस्था को सही ढंग में ग्रहण करती तो उसे मराठों की तरह प्रति पाँच या दस वर्षों में अपने प्रभारों में ठिकानेदार की अर्जित आय

के अनुसार राजस्व-प्रनुपात में वृद्धि की व्यवस्था लागू करने में सफलता प्राप्त हो सकती थी।<sup>४१</sup> इन तरह के कतिपय सुझाव प्रस्तुत करने के पश्चात् केवेंडिश ने भी यही राय प्रकट की कि इन ठिकानों की यथास्थिति बनाए रखना मराठी शासन के हित में है। उन्होंने इसी उद्देश्य से वर्तमान व्यवस्था को ठिकानेदारों के जीवनपर्यन्त यथावत् लागू रखने का सुझाव दिया। वर्तमान ठिकानेदार के नियम के पश्चात् मये उत्तराधिकार के समय इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए। उन्होंने न्यूनतम भ्रष्टाचारी कदम को ही चुना जो तत्कालीन प्रथा के जारी रखने के पक्ष में था।<sup>४२</sup>

केवेंडिश की राय में इस्तमरारदारों का अपने अधीनस्थ ठिकानों पर न तो कोई दावा और न कोई अधिकार ही सिद्ध हो सकता था। क्योंकि वे यहां के मूल निवासी नहीं थे और न ही इस भूमि पर प्रारम्भ से ही उनका अधिकार था। यद्यपि इन लोगों में से अधिकांश का अधिकार दो सौ वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं था तो भी मराठों ने उनके भू-स्वामी मानकर उनके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि इस्तमरारदारों द्वारा अपनी प्रजा से जो फौज खर्च वसूल किया जाता था, उसे बंद करने पर प्रजा को जितना लाभ नहीं पहुंचेगा उससे कहीं अधिक इस्तमरारदारों में असंतोष फैलेगा। केवेंडिश के मतानुसार मराठों में प्रमुख ठिकानेदारों को ही राजस्व के लिए जिम्मेदार ठहराया था।<sup>४३</sup>

केवेंडिश की जाच रिपोर्ट पर भारत सरकार के अधिकारियों ने गंभीर विचार-विमर्श किया। भारत सरकार के लिए यह सतोष का विषय था कि इस जांच रिपोर्ट के आधार पर वे इन ठिकानों से राजस्व वसूली में अभिवृद्धि करने के लिए वैधानिक रूप से समर्थ थे। सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठिकानों की भ्रष्टाचार में सरकार का हिस्सा राजस्व का आधा भाग होगा परन्तु कहीं भी यह भावना नहीं दिया गया कि सरकार ठिकानेदारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के पक्ष में है।<sup>४४</sup> सरकार केवल इनके वशपरम्परागत राजस्व वसूली के अधिकार स्वीकार करने को तत्पर थी। सरकार की यह मान्यता थी कि उन्हें ठिकानों को बेचने का अधिकार नहीं है।<sup>४५</sup> भारत सरकार ने इन ठिकानों में अपना राजस्व आधा निर्धारित किया।<sup>४६</sup> छोटे और बड़े ठिकानेदारों के बीच राजस्व के संबंध में कोई भेदभाव नहीं रखा।<sup>४७</sup> सरकार ने यह भी निर्णय किया कि बड़े ठिकानों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।<sup>४८</sup> सरकार की यह मान्यता थी कि ठिकानेदारों को किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने का अधिकार नहीं है तथा किसानों का उनकी जमीन व भूकान पर पैतृक हक होना चाहिए।<sup>४९</sup>

इस्तमरारदार सरकार द्वारा उनकी आय संबंधी जाच के विरोध में थे। ठिकानेदार भवतक अपने ठिकानों की व्यवस्था बिना किसी हस्तक्षेप के किया करते थे

सरकार के पाम ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिनके आचार पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती कि जागीरों के अंतर्गत कितनी कृषि योग्य भूमि है उसने कितनी उपज होती है, सरकार अगर जागीरों को जन्न करले तो उससे अतिरिक्त आय में क्या वृद्धि होगी और अगर जागीरें उन्हीं के पास रहने दी जाए तो राजस्व में वृद्धि करने की क्या संभावना है ? यद्यपि भूमि की पैमाइश अवश्य की गई थी, परंतु उसका फल कुछ नहीं निकला । इन ठिकानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न नगण्य से रहे । कदाचित् इसी कारण से केवेंडिश ने इन ठिकानेदारों को स्थिर रखते हुए एक रुपये में घाट माने का उनपर निश्चित राजस्व नियत करने का सुझाव दिया था ।

अजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर कर्नेल आस्विंस की यह मान्यता थी कि केवेंडिश द्वारा निर्धारित कर इन ठिकानेदारों पर काफी ज्यादा है । उन्होंने भारत सरकार को इन ठिकानेदारों की अंग्रेज सरकार के प्रति बफादारी को देखते हुए राशि को घटाने का सुझाव दिया था परंतु भारत सरकार ने आस्विंस के सुझाव को इस आधार पर कि सरकार इस समय इस्तिमरारदारों के अधिकारों तथा उनमें भूधृति के मामले को पुनर्जीवित करना आवश्यक नहीं समझती-कार्यान्वित नहीं किया ।<sup>१०</sup>

सदरलैंड ने ठिकानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए १५ ठिकानों का स्वयं दौरा कर सरकार को इन ठिकानों की स्थिति, सरकार के प्रति उनके दायित्व तथा सरकार के अधिकार आदि पर अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की थी । सदरलैंड के मतानुसार अंग्रेजी शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों में स्थानीय अधिकारीगणों ने इन ठिकानेदारों के प्रति बठौर इल अपनाया था । कर्नेल सदरलैंड इस्तिमरारदारी भूमि को पुनर्ग्रहण करने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि जनता इन ठिकानों के एक दीर्घकाल से चले आ रहे वंशपरम्परागत अधिकार को स्वीकार करती थी ।<sup>११</sup>

कर्नेल सदरलैंड के मन में आशंका घर किए हुए थी कि अंग्रेज सरकार के इन प्रयासों का अर्थ राजपूत ठिकानेदार वही यह नहीं लगा लें कि अंग्रेज उन्हें वंश-परम्परागत अधिकारों से संबंधित करना चाहते हैं । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनमें यह भावना प्रवेश कर गई तो अंग्रेज सरकार को इन लोगों के व्यापक असंतोष का सामना करना पड़ सकता है । वे इस बात को मानने को तत्पर नहीं थे कि ये राजपूत ठिकानेदार केवल सरकारी बेगन भोगी बनने के लिए अपनी भूमि, कस्बों, गढ़ों व गाँवों के प्राधिपत्य को सहज सौंप देंगे ।<sup>१२</sup>

सदरलैंड के अनुसार सरकार को ठिकानों से अपने राजस्व को बढ़ाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था । सदरलैंड की यह मान्यता भी थी कि उन्हें अपनी आय के धोनों की जोच या निर्धारित 'मायना' में वृद्धि उन्हें स्वीकार नहीं होगी । उनके अनुसार कई ठिकानेदार आज प्रचलित भूधृति से बिल्कुल भिन्न आधार पर प्रारम्भ से चले आ रहे थे । उन्होंने यह भी अनुभव किया कि यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा

सकता है कि मराठों द्वारा सेवा के स्थान पर सागू की गई नगद वसूली की प्रथा ठिकानेदारों के लिए पूर्व प्रचलित प्रथा की तुलना में अधिक मार थी या नहीं। यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या मराठों को इस तरह के परिवर्तन के अधिकार थे ? मराठा इसके अतिरिक्त चौथ और सरदेशमुखी भी वसूल करते रहे थे। ठिकानेदार यह रकम भी अपने ठिकानों को छूट एवं इनके भातंक से बचाने की प्रार्थना से चुकाते थे। अधिकांश मामलों में यह राशि स्थानीय मराठा सूबेदारों द्वारा घोपी जाती थी और प्राप्त रकम कदाचित् ही सिधिया के खजाने में जमा हो पाती थी।<sup>५३</sup>

कर्नल सदरलैंड के अनुसार ग्यायपूर्ण एवं सही नीति यही थी कि सरकार इन ठिकानों पर केवल 'मामला' या 'मैट' तक ही अपना लगान सीमित रखे। वह इनकी भाय की जांच के पक्ष में भी नहीं थे। उन्होंने सरकार को यह सलाह दी कि वह ठिकानों पर अपना कर ठिकानों की भाय में वृद्धि के अनुपात से बढ़ाने के ह्रादे को भी त्याग दे क्योंकि गत बाईस वर्षों के अंग्रेजी शासनकाल में जो लगान वृद्धि इन ठिकानों पर घोपी गई थी उससे वे ठिकानेदार अंग्रेज सरकार की नीति तथा उसके व्यवहार के बारे में संशयित हो चके हैं और उनमें अविश्वास की भावना घर करने लगी है। उनकी मान्यता तो यहा तक थी कि सरकार अपने को केवल निश्चित 'मामला' वसूली तक ही सीमित रखे और अन्य सभी मयि समाप्त कर दें। सरकार नए उत्तराधिकारी से गद्दी नशीनी के समय पर निर्धारित एक वर्ष के 'मामला' की राशि इन ठिकानों से माग सकती है। उनके अनुसार केवल यह कदम ही अंग्रेजों की इस्तरारियों में समृद्धि एवं भाशा का संचार करने के लिए पर्याप्त था।<sup>५४</sup> उनका यह कहना था कि ठिकानेदार न तो अपने क्षेत्र में जलाशयों के निर्माण में रुचि लेते थे क्योंकि उनकी यह पारणा थी कि इसके कारण उनकी भाय में अंगर वृद्धि हुई तो सरकार 'मामला' के अलावा दूसरे करों में वृद्धि करेगी जो कि उन पर अतिरिक्त भार होगा।<sup>५५</sup>

कर्नल सदरलैंड का सबसे महत्वपूर्ण तर्क इस तथ्य पर आधारित था कि एक और तो दूसरे प्रदेशों में अंग्रेज सरकार ने चौथ वसूली को समाप्त ही नहीं किया बल्कि कई स्थानों पर वसूल की गई राशि तक उन्हें लौटाने के लिए वाध्य किया, जबकि दूसरी ओर अंग्रेज सरकार मराठों द्वारा प्रचलित इस छूट की प्रथा को अंग्रेजों में जारी रखे हुए थी। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि मराठा आधिपत्य के समय इन ठिकानेदारों ने उनके द्वारा घोपे गए अतिरिक्त करों का सक्रिय विरोध किया था। यदि अंग्रेज सरकार की इच्छा इन अतिरिक्त करों को अनिश्चित काल तक जारी रखने की है तो इन्हें मराठों की तरह वृषक रूप से वसूल किया जाना चाहिए व इन्हे निर्धारित 'मामला' की राशि में समाहित नहीं करना चाहिए।<sup>५६</sup>

मर्नेल सदरलैंड ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा कि ये प्रतिरिक्त कर उन किसानों पर विशेष आर्थिक भार डाल रहे हैं जिनके अधिकारों एवं हितों की प्रॉजेक्ट सरकार संरक्षक बनी हुई है। यह राशि जनता को ही देनी पड़ती है।<sup>१८७</sup> इन प्रतिरिक्त करों का भार किसान पर निर्धारित 'हासिल' से अधिक होता है जो कि किसान के सामर्थ्य के बाहर है। इन करों को वसूल करने के लिए ठिकानेदार द्वारा प्रत्येक घर पर प्रतिरिक्त कर लागू किए जाते थे और उनके न देने पर जुर्माना व जल्मी की व्यवस्था थी। प्रत्येक ठिकानेदार ने फौज खर्च को चुकाने के लिए कई तरह के कर अपने ठिकानों में लागू कर रखे थे। इस परिस्थिति के लिए प्रॉजेक्ट सरकार ही जिम्मेदार थी क्योंकि जनता पर यह सब भार ठिकानेदार सरकार के प्रतिरिक्त करों के कारण डालते थे। सदरलैंड का कहना था कि इन करों की वजह से किसान को इस बात का कमी ज्ञान ही नहीं हो पाता था कि उसे राजस्व कर क्या देना है? उनके अनुसार इन करों की वसूली के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें शक्तिशाली निर्बल को आसानी से कुचल सकता था और इन जागीरों व इस्तमरारियों में किसान की श्याम मिलना संभव नहीं था, क्योंकि इस मामले में सरकारी अधिकारी भी किसी तरह की किसानों की सहूलियत पहुंचाने में असमर्थ थे क्योंकि यह एक सरकार के करों के कारण ही ठिकानेदार किसानों से वसूल करते थे। आलसा क्षेत्र में यह प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी गई थी।<sup>१८८</sup>

सदरलैंड की यह मान्यता थी कि मराठों के द्वारा घोषे गए इन प्रतिरिक्त करों को समाप्त करना इस्तमरारदार और किसान दोनों को एक बहुत बड़ी राहत पहुंचाना होगा। इन करों को वायम रखना वे प्रॉजेक्ट सरकार के लिए अघोषणीय मानते थे। उनका कहना था कि चित्त दिन ये समाप्त कर दिए जाएं उम दिन जनता में खुशी की लहर दौड़ जाएगी।<sup>१८९</sup>

सदरलैंड के अनुसार भारत के अन्य किसी भी प्रदेश में प्रॉजेक्टों का सम्पूर्ण राजपूताना जैसे जागीरदारों से नहीं हुआ था। जोधपुर रियासत में सैनिक सेवा के उपलक्ष में जागीरदारों के पास चालीस लाख प्रतिवर्ष की आय की जागीरें थी जबकि राज्य उममें से केवल बीस लाख की राशि उनसे वसूल करते थे। उदयपुर रियासत में राज्य इन जागीरदारों से चमल का छठा भाग ही ग्रहण करता था। सदरलैंड का कहना था कि भजमेर की जनता एवं इस्तमरारदारों में बीस वर्षों तक मराठों ने फौज लक्ष्य होनेवा जबरदस्ती वसूल किया था। इस सम्पूर्ण काल में इस अनुचित कर का निरंतर विरोध होता रहा था। इसकी वसूली भी बड़ी बटिनाई से हो पानी थी। इस कर ने समाज के सभी वर्गों को गरीबी और आर्थिक संकट में डाल दिया था। सरकार यदि अपनी शक्ति केवल 'मायसा' तक सीमित करदे तथा ठिकानेदारों की सहमति में प्रतिरिक्त कर की व्यवस्था करे तो वे सरकार को हर बटिन समय में इस प्रतिरिक्त मुद्राशान द्वारा मदद करते रहेंगे। इससे भजमेर का सामान वर्ग पनप भी

मकेगा। इस व्यवस्था से निश्चित बमूली सम्भव हो सकेगी तथा समय-समय पर बकाया माफी या कर स्थगन का प्रश्न ही नहीं उठेगा।<sup>१०</sup>

सदरलैंड के मत में जेम्स थाम्पसन, सचिव भारत सरकार, सहमत नहीं थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इस्तमरारदार सामान्य रूप से परेशानी एवं वित्तीय संकट में से गुज़र रहे हैं।<sup>११</sup> थाम्पसन की मान्यता थी कि फौज खर्च न तो अनुचित ही है और न इसके भार से ठिकानों की वित्तीय स्थिति पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है। उनके अनुसार इस्तमरारदारों के हक किसी अधिकृत दस्तावेज़ पर आधारित नहीं थे। उनके अधिकारों के समर्थन में वे कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए और न कभी ऐसे अधिकार अस्तित्व में ही थे। उन पर सरकारी लगान की राशि सदा ही एक पक्षीय एवं परिवर्तनशील व तराहीन सरकार की शक्ति पर आधारित रही थी। मराठा सरकार की सामान्य नीति निश्चित कर-निर्धारण की कमी नहीं थी, वे मनचाही रकम स्थिति के अनुसार बमूल करते रहते थे। थाम्पसन के अनुसार अंग्रेज़ों ने मराठों से सत्ता प्राप्त करने के बाद जहाँ तक संभव हो सका इन सभी करों को एक निर्धारित व निश्चित रूप देने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि यहाँ कोई ऐसी परम्परा नहीं मिलती जिसके आधार पर अंग्रेज़ सम्पूर्ण अतिरिक्त करों को माफ कर अपनी माँग 'जामा' तक सीमित कर दें।<sup>१२</sup> उन्होंने यह बहुत स्पष्ट कहा कि मराठों द्वारा बमूल किए जाने वाले विभिन्न करो एवं जुंभी की राशि अंग्रेज़ों की कुल माँग से कहीं अधिक थी। थाम्पसन ने इस बात की ओर भी ध्यान आकषित किया कि अंग्रेज़ों ने फौज खर्च के अतिरिक्त मराठों द्वारा आरोपित सभी करों को समाप्त कर दिए थे। फौज खर्च की राशि भी निश्चित कर दी गई थी जिसमें पिछले तेईस वर्षों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई व यह रकम मराठों द्वारा बमूल किए जाने वाली वार्षिक राशि के अनुपात में बहुत कम थी।<sup>१३</sup> इन आधारों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकार की १८३० में निर्धारित नीति में किसी तरह का संशोधन अस्वीकार कर दिया। थाम्पसन के अनुसार सरकार को अजमेर के तालुकेदारों से वृद्धिगत लगान को बमूल करने का अधिकार था और यह सन् १८३६ में गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण वे इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे।<sup>१४</sup>

सन् १८४१ में कई तालुकेदारों ने फौजखर्च के अत्यधिक भार के प्रति शिकायत की व अपने प्रार्थना-पत्र में उन्होंने लिखा कि वे इससे अत्यधिक पीड़ित हैं क्योंकि यह फौजखर्च 'मामला' राशि के अनुपात में भी कहीं ज्यादा है।<sup>१५</sup> इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह मत था कि 'मामला' के अनुपात में फौजखर्च की राशि लागू नहीं थी व अस्तित्व फौजखर्च 'मामला' राशि के पचास प्रतिशत से कुछ ही अधिक था। जेम्स थाम्पसन ठिकानेदारों की दुर्दशा का कारण फौजखर्च को नहीं मानते

ये। उनका कहना था कि अगर अधिक लगान ठिकानेदारों की परेशानी के कारण है तो फौजखर्च समाप्त कर देने से वह कंसे दूर हो सकेगी। ठिकानेदार चूँकि सरकारी लगान की राशि गत २३ वर्षों में नियमित रूप से देते रहे थे इसलिए वे इसे भी अधिक नहीं मानते थे।<sup>६४</sup> चाम्पसन ठिकानेदारों की गिरी हुई आर्थिक स्थिति का मूल कारण उनकी फिजूल खर्चों की आदत को मानते थे।<sup>६५</sup>

इस तरह अंग्रेजों की 'प्रशासनिक सेवा' के तीन प्रमुख अधिकारियों ने अंग्रेजों द्वारा फौजखर्च वसूल करने की नीति की कड़ी निंदा की थी। इन में से दो विल्डर और केवेंडिश का मत था कि राजस्व निश्चित नियमों के आधार पर ही वसूल किया जाना चाहिए।<sup>६६</sup>

सन् १८३४ के पश्चात् सरकार को इस प्रश्न पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें एक नया मोड़ आया। एडमंडस्टन ने भी जनता के कष्टों का कारण फौजखर्च को ठहराया। उनके मतानुसार समूचे अजमेर को लगान के भार से लाद दिया गया था और सभी फौजखर्च को उनके 'जामा' में समाहित कर देने से असंतुष्ट थे। मराठा-काल में फौज खर्च स्पाई-कर नहीं था। यह प्रतिरिक्त कर यदाकदा आवश्यकता पड़ने पर सरकार सड़ककाल में लोगों पर लागू करती थी और उसका ठिकाने की हितमत से कोई संबंध नहीं था। अंग्रेजों ने इसे 'जामा' में समाहित कर सदा के लिए स्पाई कर का स्वरूप दे दिया था। इसलिए ठिकानों की आर्थिक स्थिति के ह्रास का यह एक मूल कारण माना जाने लगा। अतएव इसकी समाप्ति पर जोर दिया जाने लगा। सुपरिटेण्डेंट सेपिटन, माकनाटन अपने इण्टिकोण में पूर्ववर्ती अधिकारियों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट थे। उन्होंने ठिकानेदारों की गिरी हुई हालत के लिए सरकार की फौजखर्च से संबंधित नीति को ठहराते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि व्यवस्था में कहीं कोई गभीर भूल रह गई थी। कर्नल आल्बिन ने भी सन् १८३५ से लेकर १८३६ तक अपने द्वारा लिखे गए सभी पत्रों में "फौजखर्च" को ही आर्थिक कठिनाईयों का कारण माना।<sup>६७</sup>

कर्नल आल्बिन की यह स्पष्ट राय थी कि मराठों द्वारा थोपे गए ये प्रतिरिक्त कर अनुचित थे और अजमेर के लिए अविशेष साबित हुए थे।<sup>६८</sup> उनके अनुसार अधिकोश अधिकारीगण इनको समाप्त करने के पक्ष में थे।<sup>६९</sup>

सेपिटनेंट गवर्नर की यह स्पष्ट राय थी कि अंग्रेज सरकार ने प्रारम्भ से ही दुहरी एवं उलझन भरी कर-नीति अपनाई।<sup>७०</sup> विल्डर ने इस्तमरारदारियों की भूमि के पुनर्प्राप्ति का मुआव दिया था। यदि प्रारम्भ से ही इस नीति को घनीकार कर लिया जाता तो इस स्थिति की आसानी से मुलमाया जा सकता था। एक तरफ तानुकेदारों की स्वतंत्र रूप से ठिकाने का स्वामी मानने और दूसरी तरफ उन पर करों के भार को सादने की नीति में विरोधाभास था। उनकी राय से सरकार का इस प्रश्न

पर सन् १८३० का आदेश अमंगल था। इन आदेशों ने तालुकादारों को एक घोर तो मालगुजारों की सी स्थिति प्रदान की और दूसरी तरफ उनके ठिकानों में साधारण हस्तशेप भी स्वीकार नहीं किया था।<sup>७३</sup> सेप्टिमेंट गवर्नर के अनुसार भूजों का भ्रजमेर में उद्देश्य पड़ोसी रियासतों के सम्मुख एक आदर्श प्रशामन प्रस्तुत करना था परन्तु जो नीति भूजों ने अपनाई उसके कारण वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहे थे।<sup>७४</sup>

सेप्टिमेंट गवर्नर को बाध्य होकर यह स्वीकार करना पड़ा कि कर्नल सदरलैंड का मत राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त था। यद्यपि इस प्रस्तावित कदम से सरकार को राजस्व में कुछ नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इस बात का भी विशेष उल्लेख किया कि नमीराबाद स्थित सैनिकों में प्रस्तावित कमी की जाने पर जो बचत होगी उससे राजस्व की उपरोक्त कमी की पूर्ति की जा सकेगी।<sup>७५</sup>

भूजों ने ये सब प्रतिरिक्त कर सन् १८४१ में समाप्त कर दिए जिन्हें अबतक बसूल करते रहे थे। भ्रजमेर के जागीरदार इस प्रकार भूज सरकार द्वारा इस्तमरारदार के रूप में स्वीकार कर लिए गए। सरकारी राजस्व एक सदी पूर्व मराठों द्वारा निर्धारित लगान के बराबर निश्चित कर दिया गया।<sup>७६</sup>

इस्तमरारदारों पर प्रतिरिक्त कर समाप्त करने के आदेश १७ जून, सन् १८७३ को सरकार ने घोषित किए, जिसके अनुसार इस्तमरारदारों के वर्तमान लगान को स्पार्ड एवं बलपरम्परागत कर दिया। इसके साथ ही प्रत्येक ठिकानेदार को एक सनद प्रदान की गई जिसमें उन सब शर्तों का उल्लेख था जिन पर ये ठिकाने उन्हें इस्तमरारदार के रूप में प्रदान किए गए थे।<sup>७७</sup>

सन् १८७७ के भूराजस्व विनियम के अन्तर्गत ये शर्तें समाहित करली गई थीं। शर्तों में उल्लिखित नजराना न तो कभी लागू ही किया गया और न बसूल ही किया गया बल्कि सन् १९२३ में सरकार ने इसे भी समाप्त कर दिया।<sup>७८</sup>

### इस्तमरारदारों की स्थिति

भ्रजमेर के इस्तमरारदारों की जोधपुर नरेश ने निजीतौर पर दरबार में तीन श्रेणी की ताली में प्रदान कर रखी थीं। जब कभी किसी ठिकाने की श्रेणी के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा होता तो भ्रजमेर सरकार तत्संबंधी ठिकानों की श्रेणी के निर्धारण का मामला जोधपुर दरबार को निर्णय के लिए भेजा करती थी, क्योंकि वहां भ्रजमेर के सभी ठिकानेदारों के नाम व उनकी निर्धारित श्रेणी लेखबद्ध थी।<sup>७९</sup> भूजों शासनकाल में जब कभी इस्तमरारदार दरबार में भाग लेते तो चीफ कमिश्नर को अपने हाथों से इन तालिमी सरदारों को पान और इत्र से सम्मानित करना होता था और अन्य ठाकुर और जागीरदार फर्स्ट प्रेसिडेंट के हाथों यह सम्मान



ग्रहण करते थे। द्वितीय श्रेणी वाले जागीरदारों को जूहीशियल असिस्टेंट पान इन प्रदान करते थे। अथेञ्ज शासनकाल में पूर्वप्रथा के अनुसार इन जागीरों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया था प्रथम श्रेणी में वे ताजिमी ठिकाने थे जिनके इस्तमरारदार और ठाकुर प्रथम श्रेणी के सरदार रहे थे। द्वितीय श्रेणी के ठिकाने सरकार से सनद प्राप्त गैर ताजिमी सरदारों के थे। दरबार में इनका स्थान प्रथम श्रेणी के ताजिमी सरदारों के ठीक पीछे था। जिन ठिकानों को सरकार से सनदें प्राप्त नहीं थीं वे तीसरी श्रेणी में माने जाते थे।<sup>५०</sup>

इस्तमरारदार यद्यपि राजाओं की श्रेणी में नहीं आते थे तथापि वे एक माने में विशेषाधिकार प्राप्त ठिकानेदार थे। सरकार के साथ उनके संबंध सनद में लिखी शर्तों के बंधे थे।<sup>५१</sup>

अजमेर के इस्तमरारदारों को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त थे—

१—इनकी भूसंपत्ति का स्थाई लगान होता था तथा संपत्ति अदायगी कार्य-वाही और तथा बंदोबस्त संबंधी अन्य अनिवार्यताओं से मुक्त थी।

२—केवल कुछ विशेष दमनकारी परिस्थितियों को छोड़कर इनके जमींदारों एवं प्रजा के मामले में शासन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था।

३—इनकी भूसंपत्ति बग़लपरगणत अधिकार के रूप में सुरक्षित थी, साथ ही एक प्रतिबंध यह था कि वह अपने जीवनकाल से अधिक तक के लिए इन्हें अलग नहीं कर सकते थे।

४—इस्तमरारदार के विरुद्ध किसी भी तरह के फौजदारी कानून के अंतर्गत अदायगी कार्यवाही, जिलाग्यायाधीश या सेशन ग्यायालय से निम्न ग्यायालयों में नहीं की जा सकती थी। इसके लिए भी चीफ कमिशनर को पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।

५—यद्यपि किसी इस्तमरारदार के विरुद्ध अदायगी कार्यवाही के लिए चीफ कमिशनर की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर भी उसके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह ग्यायालय में उपस्थित हो। कुछ उदाहरण ऐसे भी थे जो जहाँ इस्तमरारदारों को कठोर दण्ड की अपेक्षा हल्का दंड ही दिया गया था और उन्हें जेल न भेजकर बाराबास की सजा भोगने के लिए एक विशेष भवन में रखने की व्यवस्था चीफ कमिशनर द्वारा की गई थी।<sup>५२</sup>

उत्तराधिकारी के रूप में इस्तमरारदारी प्राप्त करने के लिए सरकार को नज़राना प्रदान करने के निम्नांकित नियम थे—

(क) सीधे बग़लत पिता से पुत्र, पौत्र के रूप में प्राप्त करने वालों से नज़राना नहीं लिया जाता था और न यह सम्पार्श्व (Collateral)

उत्तराधिकारियों से जैसे भाई भववा भाई के पुत्र उत्तराधिकार ग्रहण करने पर वसूल किया जाता था ।

- (क) जब कभी चाचा या ताऊ उत्तराधिकार ग्रहण करते तो नज़राने में वार्षिक राजस्व की आधी राशि सी जाता थी ।
- (ग) इसके धितरिक्त अन्य सभी मामलों में अपवाद स्वरूप जबतक दत्तक उत्तराधिकारी गोद लेने वाला व्यक्ति का भतीजा हो तब पूरे वार्षिक राजस्व की राशि नज़राने में सरकार को देनी होती थी ।
- (ब) नज़राना राशि का भुगतान उत्तराधिकारी ग्रहण करने के चार वर्षों के अंतर्गत किस्तों में किया जाता जिसका निर्धारण चीफ कमिश्नर या प्रमुख अधिकारी द्वारा होता था । नज़राना भुगतान की अवधि चार वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती थी ।
- (घ) उपर्युक्त नियमों के धितरिक्त यदि उत्तराधिकार ग्रहण करने के एक वर्ष के अंतर्गत जबकि नज़राने की किस्त दे दी गई हो पुनः अन्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति हो तो उससे नज़राने की नई राशि वसूल नहीं की जाती थी ।
- (ङ) यदि उत्तराधिकार के कुछ वर्षों बाद शिम पर नज़राना ग्रहण किया जाने को है तब भी उत्तराधिकार ग्रहण किया जाता है तो नज़राना अज़मेर के चीफ कमिश्नर या अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के आदेशानुसार तीन बीघाई राशि से अधिक नहीं वसूल किया जाता था ।<sup>८३</sup>

इस्तमरारदार के गोद लेने का अधिकार सन् १८४२ में स्वीकार कर लिया गया था ।<sup>८४</sup>

### प्रशासन में भागीदारी

सन् १८५७ के सैनिक विद्रोह के बाद के दिनों में भारतीय सामंतों का विश्वास प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था । सन् १८६० में अवध और पंजाब के कुछ गिने-चुने सामंतों को सरकार ने प्रशासन में भाग लेने के लिए चुना था । उन्हें औपचारिक रूप से कुछ विशेष न्यायिक एवं राजस्व-प्रशासन के कार्य सौंपे गए जिन्हें वे जिला अधिकारी के सीधे नियंत्रण एवं निगरानी में किया करते थे । इन दोनों में ही यह प्रशासनिक प्रक्रिया सफल रही थी ।<sup>८५</sup> अवध व पंजाब में इससे सामंत वर्ग का विश्वास प्राप्त करने में जो सफलता मिली उसके कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे उत्तर-पश्चिमी सूबे में भी लागू करने के पक्ष में थे ।<sup>८६</sup>

लेफ्टिनेंट गवर्नर का मत था कि अब वह समय था चुका है जबकि सरकार को

और भी उदार नीति ग्रहण करनी चाहिए और समाज के इन अगुवाओं के व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रभाव का सरकार के लिए उपयोग करना चाहिए। इससे इनमें धर्मियों के प्रति स्वामित्व की भावना बढ़ेगी।<sup>१८७</sup> लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह मत था कि उसके कुछ काम इनको प्रदान करने से एक तरफ तहसीलदार के भार को कम किया जा सकेगा और दूसरी ओर इस वर्ग की अथवा सरकार के प्रति बफादारी प्राप्त की जा सकेगी।<sup>१८८</sup> इस नीति के अंतर्गत अजमेर के इस्तमरारदार सम्मानित पुलिस अधिकारी व न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

**पुलिस अधिकारी के रूप में उनका उत्तरदायित्व**

अजमेर के इस्तमरारदार अपने ठिकाने की सीमा क्षेत्रों में तथा हल्कों में होने वाले अपराधों की जांच-पड़ताल एवं निरीक्षण करते थे। इनके हल्के चौक कमिश्नर द्वारा समय-समय पर निर्धारित होने रहते थे। इनके सीमा-क्षेत्र के गांवों या हल्कों के चौकीदार किसी भी दुर्घटना की सूचना यानेदार को न करके इस्तमरारदार को देते थे। केवल कुछ मामलों की रिपोर्ट निकटतम सरकारी पुलिस थानों में करने के साथ-साथ ही इस्तमरारदार के पास भी की जाती थी।<sup>१८९</sup>

इस्तमरारदार अपने क्षेत्र या हल्के में घटित किसी अपराध की रिपोर्ट या शिकायत मिलने पर निकटतम यानेदार या अन्य सरकारी पुलिस अधिकारी को मामले की जांच के लिए निर्देश देते थे और इस अधिकारी को वे आदेश मान्य होते थे। वह मामले की छान-बीन के बाद पूरी रिपोर्ट इस्तमरारदार को प्रस्तुत करता था जो इन पर जिला पुलिस अधीक्षक की भांति ही कार्यवाही के लिए आदेश एवं निर्देशन प्रदान करता था।<sup>१९०</sup>

पुलिस वेम को रद्द कर पढ़ने इस्तमरारदार को दंडनायक के रूप में भेजती थी और अगर कैस उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता तो वह उस पर कार्यवाही करते थे। यदि कैस उनके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता तो इस्तमरारदार सक्षेप में अपराध की सुनवाई कर और उसकी रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को भेज देते थे और यदि पुलिस की प्रतीत होता कि उक्त मामले में अभियुक्त अपराधी प्रतीत होता है तो वे दोषी व्यक्ति को भय मचूँ एवं गवाहों के जिला दंडनायक को भयवा निकटतम दंडनायक को, जिसे उस अपराध में कार्यवाही के अधिकार प्राप्त होते थे, भेज देते थे। जिस मामले में पर्याप्त साक्ष्यों अथवा अभियुक्त को जिला दंडनायक को हस्तांतरित करने के बारे में पर्याप्त आधार उपलब्ध न होते उसमें इस्तमरारदार अभियुक्त की जमानत पर रिहा कर देते या अपनी जिम्मेदारी पर कि जब भी आवश्यक होगा वे अभियुक्त को अदालत में पेश कर देंगे, उसे जमानत पर छोड़ देंगे। भयकर अपराध अथवा हिंसक घटना की स्थिति में इस्तमरारदार स्वयं घटनास्थल पर पहुँच कर जांच की कार्यवाही आरंभ कर सकते थे।<sup>१९१</sup>

दण्डनायक के रूप में उत्तरदायित्व

फौजदारी मामलों में इस्तमरारदारों के अधिकार उनके क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं तक ही सीमित थे। इस्तमरारदार उन मामलों की सुनवाई या जाँच नहीं कर सकते थे जिसमें उनका संबंधी या सेवक अभियोगी होता था। इस तरह के मामलों में इस्तमरारदार शिकायतों को सीधे जिला दंडनायक अथवा अन्य दण्डनायक के पास जाँच के लिए प्रेषित कर दिया करते थे। इस्तमरारदार को घृषक्-घृषक् श्रेणी के न्यायिक अधिकार प्राप्त थे और वे जहाँ मामलों की सुनवाई व जाँच में सक्षम थे जो इनके अधिकार-क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे। आरम्भ में इन्हें अधिकांशतः वे मामले सौंपे गए जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के थे, तत्पश्चात् जैसे-जैसे इस्तमरारदार का न्यायिक मामलों में अनुभव बढ़ता जाता था वैसे-वैसे उनके अधिकार-क्षेत्र में भी पड़ोसति होती रहती थी।<sup>६२</sup>

इन इस्तमरारदारों में जिन्हें प्रथम श्रेणी के दण्डनायक के न्यायिक अधिकार प्राप्त थे वे जान्ना फौजदारी के अनुच्छेद भात के अंतर्गत उल्लिखित सभी अपराधों की सुनवाई में सक्षम होते थे। ये वे अपराध थे जिन्हें सेशन न्यायालय में निहित किए जाते हैं। इस्तमरारदार ऐसे मामले की सुनवाई के पश्चात् अभियोग निर्धारित कर अभिमुक्त को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर देते थे।<sup>६३</sup> इसी प्रकार उन इस्तमरारदारों के भी जिन्हें द्वितीय व तृतीय श्रेणी के दण्डनायक के अधिकार थे, उनके भी अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट कर दिए गए थे।<sup>६४</sup>

प्रथम श्रेणी दंडनायक के अधिकार प्राप्त इस्तमरारदार

इस श्रेणी के इस्तमरारदार को भारतीय दंड-संहिता के अंतर्गत दो साल की कैद तथा काल कोठरी की सजा, कोड़ों एवं सामान्य कारावास (अथवा दोनों ही) तथा दो हजार की राशि तक आर्थिक दंड या अर्थ-दंड और कारावास दोनों ही प्रदान करने के अधिकार थे।<sup>६५</sup>

सिविल जज के रूप में दीवानी मुकदमों में अधिकार

इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को यह अधिकार था कि वे अपने क्षेत्र अथवा हल्के के अंतर्गत उन सभी दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते थे जिनमें विवाद की राशि सौ रुपए से अधिक की नहीं होती थी। इन इस्तमरारदारों को चीफ कमिशनर समय-समय पर वे विवाद भी निर्णय के लिए भेज सकते थे जिनकी राशि दस हजार रुपए से अधिक नहीं होती थी अथवा ऐसी अल्प राशि वाले मामले जिन्हें चीफ कमिशनर उचित समझते थे। परन्तु इस्तमरारदार उन मुकदमों में निर्णायक नहीं हो सकता था जिनमें वह स्वयं या उसका सेवक अथवा स्वयं उसमें परोक्ष रूप से भी संबंधित रहा हो। ऐसे सभी मामले निर्णय के लिए इस्तमरारदार को डिप्टी

कमिशनर को प्रेषित करने होते थे। इस्तमरारदार के फैसले के विरुद्ध अपील कमिशनर को की जाती थी। आवश्यकता महसूस होने पर इस्तमरारदार डिप्टी चीफ कमिशनर से सम्मति, राय और निर्देशन प्राप्त कर सकते थे।<sup>६४</sup>

**द्वितीय श्रेणी बंढनायक के अधिकार प्राप्त इस्तमरारदार**

इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को छ माह तक कारावास, दो सौ रुपये तक जुर्माना, कोड़ों की सजा, कारावास और जुर्माना दोनों ही, जो भारतीय दंड-संहिता के अंतर्गत एवं उनके न्यायिक अधिकार-क्षेत्र में हो, देने का अधिकार था।<sup>६५</sup>

**तृतीय श्रेणी बंढनायक के अधिकार प्राप्त इस्तमरारदार**

इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को एक माह (सामान्य एवं कठोर) तक का कारावास अथवा पचास रुपये तक जुर्माना या भारतीय दंड-संहिता के अंतर्गत दोनों ही सजा देने के अधिकार प्राप्त थे। परंतु उन्हें कालकोठरी और कोड़े की सजा देने के अधिकार नहीं थे।<sup>६६</sup>

**इस्तमरारदारियों की आंतरिक व्यवस्था**

केवेन्डिश ने ७० डिफ़ॉनों के २१८ घसनी (मूनजाम) व ७८ देखली गाँवों की जाँच के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार १५८ गाँवों में इस्तमरारदार ने स्वीकार किया कि निश्चि और विकसित भूमि जिनमें स्वयं किसान ने अपने धन या धन से निष्काई के साधन का निर्माण किया है उसमें किसान को बेदखल नहीं किया जा सकता था। ऐसी भूमि के बारे में यह धारणा थी कि इस भूमि को देखने या बँक रखने का अधिकार किसान को नहीं था, परंतु इस्तमरारदारों ने किसानों को यह अधिकार प्रदान कर रखा था कि वे यदि उचित अवधि में अपने गाँव की पुनः शोध करते थे तो वास्तव में इस भूमि पर अधिकार प्राप्त कर सकते थे। १६१ गाँवों में ऐसे किसान थे जो बतनगरमराज एक ही भूमि पर कृषि करते आए थे, इनके अधिकार भी उन किसानों जैसे थे जो कुँधो इत्यादि के मांतिक थे। अनिश्चित एवं एक घसनी भूमि के बारे में यह माना गया कि इनमें किसान इस्तमरारदार की इच्छा पर निर्भर रहना था।<sup>६७</sup>

रिपोर्ट के अनुसार १५ गाँव ऐसे थे जहाँ कुँधो के मांतिक अपने कुँए और भूमि का विपणन कर सकते थे और १३ गाँव ऐसे भी थे जहाँ पुस्तंनो रुन से अधिकारी किसान अपनी भूमि को बँक रखा सकते थे या विक्रय कर सकते थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस जाँच के दौरान अधिकारी ॥ प्रजन किसानों द्वारा उठाया गया होता और इस्तमरारदार ने उसे स्वीकार कर लिया होगा।<sup>६८</sup>

रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि ३१ गाँवों में पुर काश्त-कानों के विपणन का अधिकार था। तीन गाँवों में यह

अधिकार बंधक रखने तक ही सीमित था। जबकि २३७ गांवों में आवासी को बेदखल तो नहीं किया जा सकता था परंतु उन्हें अपनी सम्पत्ति को बेचने, बंधक रखने व हस्तांतरित करने के अधिकार नहीं थे। इस्तमरारदारो ने लोगों को अपने मकानों को बेचने के अधिकार प्रदान नहीं कर रहे थे। केवल वे ही जिनके परिवार उस ठिकाने में इस्तमरारदार के आम्रमन से पहले के बसे हुए थे, या जिन्होंने जमीन इस्तमरारदार से खरीदी थी, अपने मकान बेच सकते थे।<sup>१०१</sup> अंग्रेज सरकार की साधारणतया उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति थी परंतु सार्वभौम सत्ता होने के नाते जहाँ नागरिक अधिकारों का प्रश्न सन्निविष्ट होता ही था ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर जिनका जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो हस्तक्षेप करना अपना कर्तव्य समझती थी।<sup>१०२</sup>

सरकार किसानों के अधिकार को रखा करने के पक्ष में थी। उसकी यह मान्यता थी कि कृषि के विकास के लिए किसान की सुरक्षा एवं संरक्षण आवश्यक है। किसान को अपनी भूमि एवं आवासगृह पर स्याई अधिकार होना चाहिए। किसान को प्रतिरिक्त करों से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। परंतु यह नीति माने वाले वर्षों में पूर्णतः विभ्रमृत हो गई थी और सन् १८७३ तक ऐसी स्थिति हो गई थी कि स्वयं डिप्टी कमिश्नर को भी यह कहना पड़ा कि इस्तमरारी ठिकानों में भूमि पर ऐसे कोई अधिकार किसान के पास नहीं रहे हैं जिनके अंतर्गत किसान ठिकानेदार के अग्रसन्न होने पर उस ठिकाने में रह सके। जेम्स साटम ने अपने एक पत्र में आलोचना करते हुए लिखा था कि विवृत अंग्रेजी भूवृत्ति व्यवस्था किसानों पर थोप दी गई। इसी व्यवस्था को सन् १८७७ के भूमि एवं राजस्व विनियम की धारा २१ के अंतर्गत कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया था। जिसके अनुसार इस्तमरारी ठिकानों में किसान का इस्तमरारदार की भूमि पर किराएदार का स्थान दिया गया था।<sup>१०३</sup> इस प्रकार ठिकानेदार को किसान को बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया था। इस कारण ठिकानेदार जिससे भी नाराज हो जाते उसको ठिकाने से बाहर निकल जाने के लिए बाध्य करने लगे थे। यहाँ तक कि करों की बसूली में गैर कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने लगे। अपने इन विशेष अधिकारों के समर्थन में उनका कहना था कि निकटवर्ती राजघरानों के वंशज होने के नाते पड़ोसी रिमासतो के जागीरदारों की तुलना में उनका स्थान ऊँचा है। जबकि उनके सबसे बड़े समर्थक कर्नल सदरलैण्ड का यह मत था कि अंग्रेज सरकार की दृष्टि में उनका वही स्थान था जो उदयपुर रिमासत में वहाँ के जागीरदारों का था। छोटे से छोटा इस्तमरारदार जिसके पास कुल एक गाँव था वह भी अपनी जागीर को 'राज' और अपने आपको 'दरबार' कहलवाता था। इन इस्तमरारदारों की सामान्य प्रवृत्ति अपने आपको एक छोटा-मोटा नरेश मानने की बन गई थी। इन ठिकानों के सामान्य लोग अपने ठाकुर के प्रति गहरे आदर की भावना रखते थे। परंतु यह आदर भय

पर आधारित था, प्रेम और सद्भाव पर नहीं।<sup>१०४</sup>

किसानों की सामान्य स्थिति

ठिकानों में किसानों की स्थिति अत्यधिक असुरक्षित थी। यदि किसान ठाकुर की किसी भी लगान सबधी भाग की पूर्ति करने में असमर्थ रहता तो उसे अपनी आजीविका के साधन खो बैठने का भय बना रहता था।<sup>१०५</sup> स्थिति का सही चित्रण बेंडेन पॉवले ने इन शब्दों में किया है “पुस्तनी होने के कारण पुराने किसानों का अपने खेतों से एक रिस्ता-सा दान चला है; वह इनको छोड़ने के बजाय भारी से भारी लगान एवं लागें तक चुकाने में रातदिन एक कर देते हैं।<sup>१०६</sup> दुर्भाग्य से किसान एक वर्ग के रूप में सदा ही गुलामी में अजड़ा हुआ रहा, उसके लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना भी दूभर था। जब कभी कोई सरकारी अधिकारी इन गाँवों के दौरे पर जाता भी, तो किसान इस्तेमरारदार के आतंक के कारण अपना मुँह नहीं खोल पाते थे क्योंकि उन्हें यह भय रहता था कि यदि ठाकुर को यह पता लग गया कि उन्होंने शिकायत की है तो वह उन्हें गोली से उड़ा देगा। लगभग सभी गाँवों में किसान की स्थिति दरिद्रतापूर्ण थी। उनके रहने के मकान घोंसले जैसे थे। लोगों ने पोषण की कमी प्रतीत होती थी। किसान भारी श्रमग्रस्त थे। कड़े कर और ज़मीन की असुरक्षा दोनों के कारण अत्यंत दयनीय स्थिति पैदा हो गई थी। जिसके फलस्वरूप प्रति दस किसानों में से नौ किसान कर्जदार थे और यह कर्ज़ भी उस सीमा तक था कि वे “दिवालिया” बनकर ही उससे मुक्ति पा सकते थे।<sup>१०७</sup>

अधिकांश गाँवों में लगान उसी भूमि पर वसूल किया जाता था जिसमें फसल ली गई हो। प्रत्येक ऋतु के अवसर पर इसे ठिकानेदार अपने नाप के अनुसार नापा करते थे। उन खेतों को छोड़ दिया जाता था जिनका क्षेत्रफल निश्चित होना प्रयत्न लगान फसल के रूप में वसूल किया जाता, यर्थात् जिसमें सटाई-प्रथा प्रचलित थी। सिंचित भूमि में सामान्य खरीफ की फसल पर प्रति बीघा नगद लगान लिया जाता था, जो “बीघोड़ी” कहलाता था। इसकी दरें सामान्यतः दीर्घकाल से एक सी चली आ रही थीं और उन दिनों निर्धारित हुई थीं जबकि साधारण सस्ता या मत्तएव बेतुलनात्मक रूप से अधिक उदार थी। परंतु खरीफ पर लगान-प्रथा प्रत्येक ठिकाने की पृथक् पृथक् थीं, यहाँ तक कि एक ही ठिकाने के गाँवों में अलग-अलग थीं। रबी की फसल पर सामान्यतः उपर्युक्त के आधार पर लगान लिया जाता था, परंतु बागों की उपज पर बीघोड़ी की दरें नगदों में थी और काफी ऊँची थीं। बारानी खेती आमतौर पर परिवर्तनशील थी। अतिरिक्त बिना खाद डाले वर्षा ऋतु में पड़त पड़ी भूमि में हल चलाकर यह फसल ली जाती थी। किसान ठिकानेदार और गवि वालों की राजावत से साल भर में एक बार इन खेतों को जोता करता था। इनकी सीमा

निर्धारित नहीं होती थी तथा इसका लगान भाषती समझौते पर निर्भर करता था। यद्यपि सामान्यतः उसको यह अधिकार प्राप्त था कि वह लगातार दो वर्ष तक उस भूमि से फसल ग्रहण कर सकता था। तीसरे साल उसे अपने खेत पड़त छोड़ने पड़ते थे। बाराही ज़मीन की धोघोड़ी सबसे कम थी परन्तु यदाकदा बाँटा या फसल का भंश लगान के रूप में लिया जाता था। यदि खेत में वर्षा की कमी के कारण फसलों से भन्ताय पैदा नहीं होता या केवल भवेनियों के लिए घास चारा पैदा होता तो लगान नगदी में वसूल किया जाता था। यह व्यवस्था ज्यार की कमर पर लागू होती थी जो वर्षा के अभाव में चारे के रूप में काम आती थी।<sup>१०८</sup> कुछ गाँवों में फसल होने पर भी नगदी में लगान लेने की व्यवस्था थी। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर केकड़ी सब डिवीज़न में, खेतों में अतिरिक्त बसाहीन भूमि में रबी की फसल ली जाती थी, जिसे 'माल' कहा जाता था। इसका करायान "बाँटा" के आधार पर होता था। गड़ी फसल को कूँत कर (कूँता) ठिकानेदार का भंश निर्धारित किया जाता था। कभी-कभी यह प्रक्रिया ठिकानेदार के प्रतिनिधियों के हाथों होती थी परन्तु बहुधा पंचायत द्वारा निर्धारित होती थी जिसमें पटेल, ग्रामप्रमुख व ठिकाने के प्रतिनिधि एवं किसान होते थे।<sup>१०९</sup> ये लोग प्रति बीघा लगान की दर से फसल का लगान निर्धारित करते थे। इस तरह जो भाग ठिकाने का होता, वह जिसमें में लिया जाता था परन्तु बड़े ठिकानों में अधिकशतः इस भंश का नगदी में मूल्यांकन कर लिया जाता था। यह लगान दर 'निरल-प्रथा' के अनुसार सरकारी निकटवर्ती बाजार के भावों अथवा गाँव के वनियों द्वारा प्रस्तावित मूल्य के अनुरूप निर्धारित की जाती थी।<sup>११०</sup>

इस तरह निर्धारित लगान के साथ "लार्गे" और नेग अलग से जुड़े हुए थे। यह उपकर नगदी या फसल के रूप में वसूल किया जाता था। कई बार जहाँ लगान नगदी में लिया जाता था वहाँ प्रति रुपया कई आने इन उपकरों के रूप में जोड़े जाते थे। मूल लगान के साथ जुड़ी हुई माँगें प्रति चान्नीस सेर में दो से लेकर पन्द्रह सेर तक हो जाती थी।<sup>१११</sup> इस तरह लगान में ही बहुत कुछ वृद्धि हो जाती थी और कम उपज वाले प्रदेश के ठिकानेदारों के सतुष्ट होने के लिए यह राशि पर्याप्त थी। नकद रूप में लिए जाने वाले उपकर अलग-अलग वसूल किए जाते थे। नगदी उपकर कृषि लगान से कदाचित् ही पाँच प्रतिशत से अधिक पहुँच पाता था। इसके अन्तर्गत गृह कर 'नेवता' या विवाह-शादी के अवसर पर लगाए गए उपकर सम्मिलित नहीं थे। जिसमें वे वसूल किए जाने वाले उपकर या नेग का भार किसान पर औसतन कुल उपज का सात या आठ प्रतिशत होता था। कुछ क्षेत्रों में ये नेग दस प्रतिशत तक वसूल किए जाते थे। बहुधा भाषा लाटा (फसल का भाषा हिस्सा) जहाँ वसूल किया जाता था वहाँ इन उपकरों को छोड़ भी दिया जाता था परन्तु एक दो जगह ऐसी भी थीं जहाँ भाषा लाटा के साथ-साथ "नेग" भी वसूल किए जाते



ये धीरे-धीरे दोनों को मिलाकर किसान को अपनी उपज का साठ प्रतिशत ठिकानेदार को सौंपना पड़ता था।<sup>११२</sup>

“बाही” भयवा कुँधों से सिंचित भन्धी भूमि पर प्रति बीघा लगान की दर सात रुपए से लेकर दस रुपए तक थी तथा इनके साथ कुछ ऊँची दरों के उपकर भी जुड़े हुए थे। इससे कुँधों से सिंचित मध्यम खेती की भूमि पर लगान की दर कुछ कम थी। इस भूमि में सामान्यतः दो फसलें भयवा एक भन्धी फसल ली जा सकती थी। इसकी लगान दर भीसतन प्रति बीघा साढ़े पाँच रुपए से लेकर सात रुपए तक की थी। तीसरी खेती की भयवा पटिया किस्म की भूमि जो कुँधों से सिंचित होती थी उसकी लगान-दर तीन रुपये से लेकर पाँच रुपए प्रति बीघा थी। सरवा ठिकानों में प्रति बीघा साढ़े सात रुपए की लगान-दर तथा अतिरिक्त उपकरणों व अन्य शुल्कों को मिलाकर ६ रुपए प्रति बीघा अंकित होती थी। तालाबी भूमि में कृषि करने वाले को जल शुल्क के सहित भी काफी कम दर चुकानी होती थी। बाबी जमीन का लगान बारानी कृते के आधार पर फसल के अनुसार चुकाया जाता था। जहाँ बीघोड़ी निर्धारित थी वहाँ किसान को ६ आने से लेकर द्वाद्वी रुपए प्रतिबीघा चुकाना होता था जबकि सामान्य दर एक रुपए के लगभग थी। बीघों की रबी की फसल पर लगान भीसतन पाँच रुपए बीघा लगाया जाता था।<sup>११३</sup> इससे यह स्पष्ट है कि खालसा-भूमि की प्रपेक्षा इस्तमरारदारी ठिकानों में बहुत ही भारी लगान था।

अजमेर जैसे क्षेत्र के लिए, जहाँ पाँच फसलों में से तीन सूखे की बपेट में जाती रहती थीं, यह आवश्यक हो गया था कि लगान फसलों के अवधान के रूप में वसूल किया जाए। इसमें यह फायदा था कि फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान कर भार से बच सकता था और उसे स्वाभाविक रूप से ही राहत प्राप्त हो जाती थी।

अधिकतर ठिकानों में पुष्पती किसानों की परेशान करने के मामले बहुत ही कम पड़ते थे। कई ठिकानों में बीघोड़ी में परिवर्तन कर लगान बढ़ा दिया गया था; उदाहरणार्थ, भूल रूप से जो लगान “चित्तोड़ी” रुपए में भुगतान किया जाता था, उसके स्थान पर “बहदार” रुपए में वसूल किया जाने लगा, इससे किसान को २१ प्रतिशत का भार अधिक उठाना पड़ा। कहीं बीघोड़ी के स्थान पर बाँटा लागू करके (उदाहरणतः कपास की फसल) लगान में वृद्धि कर दी गई थी।<sup>११४</sup> इन ठिकानों में किसानों के अधिकारों के बारे में एकमात्र कानूनी प्रावधान अजमेर-भूमि एवं राजस्व-विनियम की धारा २१ थी। जिसके अनुसार इस्तमरारदारियों में किसान की रिपति भूमि पर इस्तमरारदार की इच्छा पर निर्भर एक किराएदार की थी।<sup>११५</sup>

ठिकानों का उनके क्षेत्रों पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था,

सामान्यतः एक सम्ये समय से चले आ रहे मौसमी एवं वंशपरम्परागत किसान को भूमि से बेदखल करने की प्रथा ही उनकी सुरक्षा का आधार था। परंतु किसी भी किसान को जमींदार अपनी इच्छानुसार बेदखल कर सकता था और इसके लिए उसे कारण बताना आवश्यक नहीं था। यद्यपि भ्रजमेर-भूमि एवं राजस्व-विनिमय में किसान को बेदखल करने के लिए कृषि-वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देना और किसान द्वारा निमित्त विकास कार्यों का उसे मुद्रावजा चुकाने की व्यवस्था थी।

सामान्यतः कानून के अंतर्गत एक निश्चित अवधि तक भूमि पर कार्य करने वाले किसान को उस भूमि पर कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हो जाते थे और वह कानून के अंतर्गत अपनी पूर्ण सुरक्षा का दावा कर सकता था। प्रथम में यह कानूनी मियाद १२ साल की होती थी। बंगाल-भूमि-कानून (सन् १८८५) के अंतर्गत जिस किसान ने लगातार बारह वर्षों तक अपने कच्चे की भूमि को जोता था उसे बेदखली से संरक्षण प्राप्त था। इस्तमरारदार ठिकानों के किसानों के लिए इस तरह की व्यवस्था भ्रजमेर के भूमि एवं राजस्व-विनिमय में नहीं थी। भ्रजमेर-मेरवाड़ा के इस्तमरारदारी ठिकानों में किसान को उनकी बेदखलियों के विरुद्ध कानूनी एवं मौखिक किसी भी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे।<sup>११९</sup>

इन ठिकानों में किसानों का सीधा वंशानुगत उत्तराधिकार सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता था। परंतु निकट रिश्तेदारों में गौद लेने पर इस्तमरारदार को मजूराना देना पड़ता था। उक्त मजूराने की राशि बँट करने पर भी उत्तराधिकारी को सामान्य सहज नियम के तौर पर भी भूमि के हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। कुछ परिस्थितियों में किसानों को अपने खेतों को बंधक रखने के अधिकार प्राप्त हो गए थे और इस कारण महाजनो ने कुछ भूमि भी अपने अधिकार में कर ली थी। इन ठिकानों के ८५ प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक किसान इन महाजनों या “बोहरो” से कर्ज लिया करता था। यह राशि बहुधा लगान के रूप में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ लगान फसल उठाने से पूर्व अन्न (मगोतरी) बमूल की जाती थी। पारिवारिक अवसरों, त्योहारों, विवाह, मृत्यु-संस्कार आदि पर कभी-कभी फसल नष्ट होने पर आसामी को उसके खुद के व परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यक साधन इत्यादि की खरीद के लिए महाजन ऋण दिया करता था। ऋण पर भारी ब्याज लिया जाता था, कई बार तो वह कर्जा ली गई मूलराशि से भी अधिक बढ़ा-चढ़ा कर लिखी जाती थी। बहुधा महाजन ही आदतियों का काम भी करता था, जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल बेचता था। फलस्वरूप महाजन कर्ज के पेटे फल भर लेता, लगान चुका देता और किसान को इतना कम प्रदान करता था कि जिससे वह अपना गुजारा मात्र कर सके। यह निर्विवाद सत्य है कि मौसमी फसल भी ब्याज के चुकारे के नाम पर महाजन की बहियों में दर्ज

कर ली जाती थी और मूलधन बैसा का बैसा ही बना रहता था । किसान का नाम कदाचित् ही बनिए के बही खातों में से कट पाता और वह दिनों दिन अधिक कर्ज के भार से लदता चला जाता था ।<sup>११७</sup>

अधिकांश ठिकानों में किसानों के फसल उठाने से पहले ही बकाया राशि लेने पर बल दिया जाता था । जबतक वह यह प्रदान नहीं करता उसे फसल नहीं उठाने दी जाती थी । यदि किसी में कोई पुरानी राशि बकाया नहीं होती तो उसे भारी भुगतान के लिए जमानत (साई) की व्यवस्था करने को मजबूर किया जाता था ।<sup>११८</sup> इन दोनों रकमों की व्यवस्था किसानों के लिए महाजन या बोहरी द्वारा की जाती थी । यद्यपि पोसागन में ठिकाने और महाजनों के बीच आपसी तनाव की स्थिति थी, अतएव वहाँ किसानों द्वारा आपस में इसकी व्यवस्था की जाती थी । महाजन जिस रोज जमानत या भुगतान की राशि देते उसी दिन से वही में दर्ज कर उस पर व्याज चालू कर देते । बहुधा वे इस पर रुपए में एक घना 'काटा' के नाम पर प्रतिरिक्त वसूल किया करते थे, परन्तु बोहरे यह राशि ठिकाने को तबतक भुगतान नहीं करते थे जबतक कि वे किसानों का जमा भनाज बेच नहीं लेते थे । इस पर भी किसान के नाम लगान की जो राशि जमा की जाती उसमें वे अपनी निरिपत भाड़त की रकम पहले काट लेते थे । यह व्यवस्था किसानों में लिए अभिशाप थी । यद्यपि ग्राम प्रांतों के कुछ ठिकानों में 'साई' या अधिम राशि लगान-निर्धारण के लिए फसल के कूतों के समय वसूल की जाती थी । जबतक इन दोनों राशियों में से एक राशि ठिकाना प्राप्त नहीं कर लेता, किसान का कूता रोक दिया जाता अथवा उसे कटी फसल में से अन्न निकालने या फसल अन्यत्र ले जाने से रोक दिया जाता । उन ठिकानों को यदि अधिम-राशि या साई नहीं मिलती अथवा जहाँ इनकी प्राप्ति की संभावना क्षीण हो वहाँ यदि ठिकानेदार यह अनुभव करते कि अधिम-राशि या साई की राशि मिलने की संभावनाएँ क्षीण हैं तो वे फसल को अपने कब्जे में लेकर उसे महाजन को सौंप देता और इससे किसान की बकाया राशि से लेता था ।<sup>११९</sup> यदि धनत सेत में से नहीं हटाई जाती तो एक 'सहसा' या चौकीदार फसल की निगरानी के लिए छोड़ दिया जाता था और कई बार किसान के घर पर भी ठिकाने का कोई भी व्यक्ति जिसे "तलबिया" कहा जाता था, बकाया राशि वसूल करने के लिए आता था । किसान उसे अपने घर ठहराता और धन्दी तरह से खातिर करता, यदि उस समय उसके पास कुछ उपलब्ध होता तो उसकी मेंट-पूजा की व्यवस्था भी करता ।<sup>१२०</sup> यदि ये सभी प्रयास धन-प्राप्ति में दिव्हीं कारणों से फलरहित सिद्ध होते तो किसान को अन्य तरीकों से तग दिया जाता था । उसे हल जोरने, भूमि में खाद डालने, गिराई करने, वनधों को चराने, पास काटने से रोका जाता अथवा उसे ठाकुर के गड़ या छिने में मुनाजर वहाँ बंद कर दिया जाता था उससे तिसित में भुगतान या बचन लिया जाता था । इनके प्रतिरिक्त कुछ मामलों में उसके मवेशी

घोर बंस्त-गाड़ी तक जप्त कर लिए जाते थे। पड़ोसी रियासत मेवाड़ के मेरवाड़ा वाले जागीरी ठिकानों में "साई" के अभाव में पत्तनों की कुर्की महाजन के माध्यम से रकम की बसूली घोर फसल पर सहणों की नियुक्ति की प्रथा प्रचलित थी। प्रथम श्रेणी के ठिकानेदारों को अपनी बकाया बसूली के लिए राजस्व आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त थे, इन सभी प्रयासों के अतिरिक्त भी ठिकानेदार के पास अंतिम शास्त्र के रूप में बकाया बसूली के लिए किसान को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त था।<sup>१२१</sup>

सभी इस्तमरारदारों का यह दावा था कि उनके ठिकानों के अन्तर्गत किमी भी गाँव में रहने वाले को अपना मकान या भूमि पर किमी तरह का कोई अधिकार नहीं है जब-तक कि ठिकानेदारों से वह इस आशय की विशेष स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ले।<sup>१२२</sup> केवल मिनाय, मसूदा और टाटोटी को छोड़कर सभी ठिकानों में यह व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को अपने भवन इत्यादि के विषय, बचक या भेंटस्वरूप हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे किन्हीं कारणों से गाँव स्थापना पड़ता तो, वह मकान बेच नहीं सकता था। मिनाय और चापानेरी दो बड़े गाँवों में नज़राना लेकर हस्तांतरण पर स्वीकृत कर दिया जाता था।<sup>१२३</sup> अपनी जाँच रिपोर्ट में केंवेंडिश महोदय ने इस दिशा में यह अभिमत व्यक्त किया कि "इन ठिकानों में एक गाँव गैर काश्तकार अपने मकानों, कुँओ इत्यादि का विषय कर सकते थे, जबकि दूसरे गाँव में उन्हें केवल अपनी दुकानें और कुँओ के विक्रय करने का अधिकार था। टाटोटी में पक्के मकानों के मालिकों को, जो पट्टेदार कहलाते थे इनकी बित्री एवं बचक के अधिकार प्राप्त थे परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें विक्रय मूल्य का १५ प्रतिशत बंधक राशि का १० प्रतिशत ठिकाने के खजाने में बतौर नज़राना जमा कराना होता था।"<sup>१२४</sup>

केंवेंडिश की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ठिकानों में गृहकर भी प्रचलित था। गृहकर मकान या भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर न होकर मालिक की हैसियत के आधार पर लिया जाता था। गृहकर की राशि न तो निर्धारित ही थी और न उसके बारे में किसी तरह के निश्चित नियम थे। सम्पूर्ण व्यवस्था बेदगी सी थी फिर भी बिना किसी अवरोध के यह व्यवस्था चल रही थी। मकानों में विस्तार करने पर भारी नज़राना थोपा जाता था और टूट-फूट ठीक कराने और मरम्मत पर नज़राना बसूली के लिए ठिकानों की कार्यवाही पर लोगों ने कड़ा विरोध एवं तीव्र असंतोष प्रकट किया था। पोसागन में गैर काश्तकारों ने "गृहकर चुकाना स्थगित किया जा चुका है" यह कहकर चुकाने से इन्कार कर दिया था। इसके फलस्वरूप लोगों और ठिकाने के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यद्यपि निर्णय ठिकानेदार के पक्ष में हुआ।<sup>१२५</sup>

सन् १८३० में भारत सरकार भी इस बात के पक्ष में थी कि किसानों का अपने

मकान पर स्वार्थ अधिकार होना चाहिए।<sup>१२४</sup> परन्तु उत्तरपश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रश्न पर किसी तरह के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। उल्टे कम्पनी के आइरेवटर्स ने भी इस प्रश्न पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मत को "न्यायपूर्ण एवं उचित" ठहराया। उनके अनुसार ठिकानों में लोगों को उनके मकान पर स्वामित्व के हक प्रदान करना न्यायसंगत नहीं होगा।<sup>१२५</sup> इस प्रश्न पर किसानों की धर्मार्थ सरकार से कभी न्याय प्राप्त नहीं हो सका।<sup>१२६</sup>

## अध्याय ५

१. जे० डी० साद्वन—गजेटीयर्स ऑफ अजमेर-मेरवाड़ा (सन् १८७४ के प्र-बदीवस्त पर आधारित) पृ० २३ (स)।
२. टॉड एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान पृ० ४१।
३. पी० सरन—स्टडीज इन मिडेबिल इन्डियन हिस्ट्री पृष्ठ १ से २२।
४. प्यूब्लिटेरीज एण्ड जर्मीनर्स ऑफ इन्डिया पृ० २३।
५. टॉड एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान खंड १, पृ० १९७  
"सामंती नज़राने का दस्तूर सिद्धांततः पूर्व में भी पश्चिमी देशों जैसा ही था। मेवाड़ में नज़राने का दस्तूर दे देने पर राज्य ठिकाने के उत्तराधिकारी को स्वीकृति प्रदान करता था।" यह व्यवस्था एक तरह से राज्य द्वारा जागीर पुनर्ग्रहण करने के अधिकार को इंगित करती थी। टॉड ने भी स्वीकार किया है कि (खंड १-पृ० १८६), यह एक औपचारिक विशेषाधिकार था, जिसका कदाचित् ही उपयोग हो पाया था (खंड १, पृ० १६१)।
६. जे० डी० साद्वन—गजेटीयर्स ऑफ अजमेर-मेरवाड़ा पृ० २६ (घ)।
७. कैरेटिन का पत्र दिनांक ११ जुलाई, १८२६ "यहाँ कुल ६ परगने हैं सरवा, मसूदा, पीसापन, गोविन्दगढ़, सावर, मिनाथ, केकड़ी, देवगढ़, ग्राहपुरा तथा १२ गाँव अजमेर परगने में हैं। २१८ मसली धोर ७८ दसली गाँव कुल मिलाकर २६६ हैं। सरवा धोर मसूदा के चार तालुका हैं, पीसापन, गोविन्दगढ़, मिनाथ धोर सावर के ३० उप तालुके हैं। केकड़ी उपनाम जूनीया के १४ उप तालुके हैं। देवगढ़ धोर बबेरा के ३ उप तालुके हैं धोर अजमेर परगने के ११ उप तालुके हैं"।
८. बिलडर का पत्र दिनांक २७ सितम्बर, १८१८।

१. मिनाय के हस्तमरारदार राजा ओषा के वंशज थे । भारवाड़ के चंद्रसेन (१५६३) के पोत्र राणसेन को इस क्षेत्र में भील उपद्रवियों को समाप्त करने के इस सेवा उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने मिनाय और सात परगने जागीर में दिए थे । धारम्भ में इस जागीर में कुल ८४ गाँव थे जो बाद में चौथी पीढ़ी में उदयमान (४६ गाँव) तथा घखैराज (३८ गाँव) में बँट गए । उदयमान ने मिनाय तथा घखैराज में देवलिया की मुख्य ठिकाना स्थापित किया । मिनाय ठिकाना सरकार को ७,७१७ रुपए की वार्षिक तिराज देता था और ओषपुर नरेश ने उन्हें राजा का खिताब उनकी सैनिक सेवाओं के उपलक्ष्य में प्रदान कर रखा था । (हर्लिंग प्रिन्सेज, चौपस एंड सीडिंग पर्सोनेजेस ऑफ राजपूताना एंड अजमेर (१६३८) सातवाँ संस्करण पृ० १८७ और १८८) ।
१०. सावर ठाकुर भिसोदिया वंशी सक्तावत राजपूत थे । इस ठिकाने में ३३ गाँव थे जिनकी वार्षिक आय साठ हजार थी । यह ठिकाना सरकार को ७,२१५ रुपए वार्षिक राजस्व प्रदान करता था । यह ठिकाना सम्राट जहांगीर द्वारा गोकुलदास को दी गई जागीर का अंग था । (हर्लिंग प्रिन्सेज, चौपस एंड सीडिंग पर्सोनेजेस ऑफ राजपूताना एंड अजमेर पृ० १६३) ।
११. जूनिया के ठाकुर राठीर वंशी थे । इस ठिकाने में १६ गाँव थे तथा इसकी वार्षिक आय ५०,००० रुपए थी । सरकार को यह ठिकाना ५,७२३ रुपए सालाना राजस्व देता था । जूनिया के ठाकुर केकड़ी के परंपरागत भूमिया थे अतएव उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सवार प्रदान करने पड़ते थे (हर्लिंग प्रिन्सेज, चौपस एंड सीडिंग पर्सोनेजेस ऑफ राजपूताना एंड अजमेर पृ० १६३) ।
१२. भसूदा के ठिकानेदार मेडतियावणी राठीर थे, उनके पास जिले में सबसे बड़ा और सबसे घनी ठिकाना था, जिसमें २६ गाँव थे तथा वार्षिक आय १ लाख रुपए के लगभग थी, सरकार को यह ठिकाना ८,५५५ का रानियाना चुकाता था ।
१३. पीसागन के हस्तमरारदार जोधावत वंशी राठीर राजपूत थे, तथा इनके ठिकाने में ११ गाँव थे जिनकी वार्षिक आय २३००० रुपए थी और ये सरकार को ४,५६३ रुपए वार्षिक चुकाते थे ।
१४. केवेंडिश का पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ ।
१५. केवेंडिश का पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ ।
१६. जे० डी० लाटूश-गजेटीयर ऑफ अजमेर-मेरवाड़ा पृ० २६ ।

१७. भारत सरकार के कार्यवाहक सचिव जेम्स थॉमसन को लेफ्टि० कर्नल सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनांक ७-२-१८४१ ।
१८. जे० डी० सादृश मजेटीयर्स ग्रॉफ भ्रममेर-मेरवाड़ा पृष्ठ २० ।
१९. सुपरिंटेंडेंट व पोलिटिकल एजेंट भ्रममेर द्वारा रेजीडेंट राजपूताना व दिल्ली को पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२८ । फाइल क्रमांक १५, (भ्रममेर रेकॉर्ड रा० रा० पु० म०) ।
२०. श्री हर्लिंग प्रिन्सेस चीफ्स एण्ड लीडिंग पर्सनिजेस इन राजपूताना एण्ड भ्रममेर (१९३१) पृ० १-१० ।
२१. एफ० विल्डर सुपरिंटेंडेंट भ्रममेर का मेजर जनरल सर डेविड थॉमसरलोनी को पत्र, दिनांक २४ सितम्बर, १८१८ ।
२२. भार० केवेंडिश-सुपरिंटेंडेंट व पोलिटिकल एजेंट भ्रममेर का रेजीडेंट राजपूताना व दिल्ली सर एडवर्ड कोलब्रुक बार्ट को पत्र, दिनांक ११ जुलाई, १९२९ ।
२३. भारत सरकार के सचिव जेम्स थॉमसन (भागरा) का कर्नल जे० सदरलैंड कमिशनर भ्रममेर को पत्र मई, १८४१ ।
२४. भार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेंट राजपूताना दिल्ली, कोलब्रुक को पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२८ (भ्रममेर रेकॉर्ड, रा० रा० पु० म०) ।
२५. उपरोक्त ।
२६. उपरोक्त ।
२७. भार० केवेंडिश का सदर एडवर्ड कोलब्रुक को पत्र, दिनांक ११ जुलाई, १८२९ ।
२८. एफ० विल्डर द्वारा सर डेविड थॉमसरलोनी को पत्र, दिनांक २७ सितम्बर, १८१८ ।
२९. भारत सरकार के विदेश एवं राजनीतिक विभाग का पत्र, दि० ५ मई, १९०० (फाइल क्रमांक ७२, रा० रा० पु० म०) ।
३०. एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर थॉमसरलोनी को पत्र, दिनांक २७ सितम्बर, १८१८ ।
३१. सर डेविड थॉमसरलोनी द्वारा एफ० विल्डर को पत्र, दिनांक २३ अक्टूबर, १८१८ ।
३२. २७ सितम्बर, १८१८ के एफ० विल्डर के पत्र पर सरकार एवं फोर्ट ग्रॉफ साइरेक्टर के निर्देश । (भ्रममेर रेकॉर्ड, रा० रा० पु० म०) ।

३३. एक० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी को पत्र, दि० ७ अक्टूबर, १८१८ ।
३४. एक० विल्डर द्वारा मेजर ऑक्टरलोनी को पत्र, दिनांक १२ अक्टूबर, १८१८ ।
३५. एक० विल्डर का मेजर ऑक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २० अक्टूबर, १८१८ ।
३६. एक० विल्डर द्वारा मेजर ऑक्टरलोनी को पत्र, दिनांक १७ जून, १८१६ ।
३७. मिडलटन सुपरिंटेंडेंट भजमेर द्वारा पत्र, दिनांक ६ अगस्त, १८२६ (रा० रा० पु० मं०) ।
३८. केवेंडिश सुपरिंटेंडेंट भजमेर द्वारा पत्र, दिनांक ८ मई, १८२८ (रा० रा० पु० मं०) ।
३९. केवेंडिश द्वारा पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ (रा० रा० पु० मं०) ।
४०. केवेंडिश द्वारा पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ "मराठा शासन के अंतिम वर्ष विक्रम भवन् १८७४ के राजस्व को आधार मानकर जमींदार को प्राप्त राजस्व को आधा भाग लेना उचित है । इस प्रक्रिया के लिए अपने शासन के पाँच या दस वर्ष पूर्व की कुल आय तथा बाद के पाँच या दस वर्षों की आय को नियमानुसार प्रति दस वर्ष में आधा भाग ग्रहण किया जाकर इस तरह का निर्धारण किया जा सकता है ।"
४१. केवेंडिश द्वारा पत्र, दि० १० जुलाई, १८२६ ।
४२. केवेंडिश द्वारा पत्र, दि० ११ जुलाई, १८२६ ।
४३. सचिव भारत सरकार द्वारा कार्यवाहक चीफ कमिशनर भजमेर को पत्र, दि० ६ फरवरी १८३० पत्र संख्या ७, अनुच्छेद ३-४ ।
४४. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ५ ।
४५. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ६ ।
४६. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १४ व १५ ।
४७. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १७ ।
४८. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १६ ।
४९. कर्नल मॉल्वीस, कमिशनर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा पत्र, दिनांक ३० अप्रैल, १८३५ व जून, १८३७ ।



५०. कर्नल सदरलैंड ए० जी० जी० राजपूताना द्वारा सचिव भारत सरकार पत्र, दि० ७ फरवरी, १८४१ ।
५१. उपरोक्त ।
५२. उपरोक्त ।
५३. उपरोक्त ।
५४. उपरोक्त ।
५५. उपरोक्त ।
५६. उपरोक्त ।
५७. उपरोक्त अनुच्छेद १४ ।
५८. उपरोक्त अनुच्छेद १३ ।
५९. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १० व ४० ।
६०. पत्र मई, १८४१ सचिव भारत सरकार द्वारा कमिशनर अजमेर को पत्र मई, १८४१ ।
६१. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ३ और ४ ।
६२. उपरोक्त पत्र अनु० ६ ।
६३. उपरोक्त पत्र अनु० ७ व ८ ।
६४. उपरोक्त पत्र अनु० ९ ।
६५. उपरोक्त पत्र अनु० ९ व १० ।
६६. उपरोक्त पत्र, अनुच्छेद ११, १२, १३, १४ व १५ ।
६७. लेफ्टिनेंट गवर्नर भागलपुर द्वारा पत्र, सचिव भारत सरकार ।
६८. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ।
६९. उपरोक्त पत्र ९-१०-११ अनुच्छेद ।
७०. उपरोक्त अनुच्छेद १३ व १४ ।
७१. उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १३ ।
७२. उपरोक्त अनुच्छेद १६ ।
७३. उपरोक्त अनुच्छेद १७ ।
७४. उपरोक्त अनुच्छेद १८ ।
७५. उपरोक्त अनुच्छेद १९, २०, २१, २२ ।

७६. राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स खंड १-ए भजमेर-मेरवाड़ा (११०४) पृ० ६० व जे० डी० साद्वस गजेटियर्स ऑफ भजमेर-मेरवाड़ा (१८४५) ।
७७. प्रथम डिप्टी सेक्रेट्री परराष्ट्र एवं राजनीति विभाग भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, संख्या ११०७-१ ए. शिमला दि० २१ अप्रैल, १९२० ।
७८. पत्र क्रमांक ६२६ जी०-सदृ १८८३ भजमेर-दिनांक ३० सितम्बर १८८५ डी० सी० प्रोलेडन कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा प्रथम अतिस्टेंट ए० जी० जी० राजपूताना, चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को ।
७९. फाइल क्रमांक ६५ पृ० ३ (रा० रा० पु० मण्डन) ।
८०. अतिस्टेंट सेक्रेट्री परराष्ट्र विभाग द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र क्रमांक २४७-१-ए दिनांक फोर्ट विलियम १७ जनवरी, १९०१ ।
८१. कमिश्नर भजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर को पत्र, दि० १३ फरवरी, १९१६ ।
८२. क्रमांक ५७८, भारत सरकार कार्यवाही रिपोर्ट, परराष्ट्र विभाग दिनांक ५ जून, १८६८ (फाइल क्रमांक ७१) ।
८३. डिप्टी कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १६ नवम्बर, १८६८ ।
८४. गस्ती पत्र क्रमांक १०६ ए दिनांक १६ जनवरी सन् १८६१, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को प्रेषित ।
८५. उपरोक्त ।
८६. उपरोक्त ।
८७. उपरोक्त ।
८८. उपरोक्त भजमेर रुस्त एण्ड रेग्युलेशन्स पृ० ११६० ।
८९. उपरोक्त ।
९०. उपरोक्त ।
९१. कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १२ जून, १८७४ ।
९२. उपरोक्त ।
९३. उपरोक्त ।
९४. उपरोक्त ।

६५. उपरोक्त ।

६६. उपरोक्त ।

६७. उपरोक्त ।

६८. धार० केवेंडिश सुपरिंटेंडेंट अजमेर द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना को पत्र दि० १० जुलाई, १८२६ ।

६९. उपरोक्त ।

१००. उपरोक्त ।

१०१. डिप्टी कमिश्नर अजमेर द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र दि० ८ जुलाई, १८६२, क्रमांक २०७ ।

१०२. जे० बी० लाहून, सेटलमेन्ट रिपोर्ट, १८७४ अनु० १२६ ।

१०३. उपरोक्त ।

१०४. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१९३७) ।

१०५. बाइन पोवेल ए मेग्युमल ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लैण्ड टेम्पोरै (१८८०) ।

१०६. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट (१९३७) ।

१०७. उपरोक्त—पृष्ठ १२ अनु० १६ ।

१०८. इन ठिकानों के पट्टेयों की हैसियत व अधिकार महाराष्ट्र के पट्टेयों जितने नहीं थे । वह केवल प्रमुख ग्रामजन होता था । एक समय उसे विवाह आदि पर नेम या लागू प्राप्त हुआ करती थीं, किन्तु बाद में इनका प्रचलन बंद हो गया था ।

१०९. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १९३७, पृ० १२ अनु० १६ ।

११०. उपरोक्त ।

१११. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१९३७) पृ० १३ ।

११२. उपरोक्त पृ० १३ अनु० २१ ।

११३. उपरोक्त पृ० १७ अनु० २४ ।

११४. अजमेर भू एवं राजस्व नियामक १८७७, पारा २१ ।

११५. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१९३७) पृ० ३६ ।

११६. उपरोक्त पृ० २१ अनु० ३० ।

११७. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १९३७ पृ० २२ ।

११८. उपरोक्त ।
  ११९. उपरोक्त ।
  १२०. उपरोक्त ।
  १२१. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१९३७) पृ० ३३ ।
  १२२. उपरोक्त ।
  १२३. केवेंडिश रिपोर्ट, सन् १८२६ ।
  १२४. उपरोक्त ।
  १२५. एच. भैकेंजी का पत्र क्रमांक ७४, दिनांक ६ फरवरी, सन् १८३० (रा० रा० पु० मं०) ।
  १२६. इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१९३७) पृ० ३५ ।
-

## भौम, जागीर व माफी

### भौमिया

राजपूताना की भूमि-व्यवस्था में 'भौम भोग' एक घनोक्ती और विशिष्ट प्रथा थी। 'भौम' का अर्थ है भूमि और इसका स्वामित्व धारण करने वाले को 'भौमिया' कहा जाता था जो सामंती सरकार तथा खालसा भूमि के किसान से बिल्कुल भिन्न था।<sup>१</sup> भौमिया सामंती पुनिस-व्यवस्था और स्थानीय अनियमित सैनिकों के तौर पर कुछ सेवाएं प्रदान किया करते थे। वे गाँव की फसल और मवेशियों की छुट्टियों में रक्षा करने के लिए कर्तव्यवद्ध थे।<sup>२</sup> उनके गाँव की सीमा के अन्तर्गत जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती थी। उनकी सेवाएं और जिम्मेदारियाँ केवल उनके अपने गाँव तक ही सीमित थीं।<sup>३</sup> इन्हें क्षेत्र में उत्पात दवाने के लिए सूबेदार की सहायता करनी पड़ती थी, परंतु उन्हें अपनी सीमा से बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। ये लोग अपने-अपने गाँवों की सुरक्षा एवं शांति का भार वहन करते आए थे और यदि वे अपने क्षेत्र में से चोरी गए माल की बरामदगी में असफल रहते या अपराधियों को पकड़ नहीं पाते तो उन्हें चोरी की कीमत जमा करानी होनी थी। यही प्रथा गोवट्टों सदी में शेरशाह ने भी अपनाई थी। उस समय के चौधरियों और मुकदमों को जो प्रतिष्ठा और विवेकाधिकार प्राप्त थे उनके उपनयन में वे भी इसी तरह की सेवाएं प्रदान करते थे।

कनैल टॉड के अनुसार भौमिया सजसज किसान होते थे। ये एक तरह के ग्रंथ सैनिक सामंत थे जो राज्य को सगान के उपलक्ष में सीधी सेवाएं प्रदान करते थे। भ्रमण के समय राज्य उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकता था। इस व्यवस्था पर राजा को उनके भोजन आदि की व्यवस्था करनी होती थी। भौम का भूभाग इतना प्रतिष्ठित होता था कि बड़े से बड़ा ठाकुर भी अपने अधीनस्थ गांवों में इसकी प्राप्ति के लिए उत्कटित रहा करते थे। 'भौम' ही एकमात्र ऐसा भूभाग था राज जिसका पुनर्ग्रहण नहीं कर सकता था और यह भाग सही माने में पूर्णतः बंशपरम्परागत था। यद्यपि यह भूमि भी कई व्यक्तियों में बँटती चली जाती थी तथापि इसकी अनुमति राज्य से प्राप्त करनी पड़ती थी।<sup>५</sup>

विल्डर ने भौमियों को चौकीदार माना था।<sup>६</sup> परन्तु भ्रमण-भरवाड़ा के भौमियों की तुलना बंगाल प्रेसीडेन्सी के चौकीदारों से नहीं की जानी चाहिए। भ्रमण के भौमिया बंगाल के चौकीदारों से सर्वथा भिन्न थे। भौमिया गांव का बड़ा भावमी होता था और ग्रामीण समाज उन्हें भय और आदर की मजूर से देखता था।<sup>७</sup> सामान्यतः वह अपनी गद्दी में रहा करता था और गांव में उसके रहन-सहन का स्तर अच्छा हुआ करता था। राजपूत सैनिक होने के नाते वह तलवार धारण किए रहता था और आर्थिक हालत ठीक होने की स्थिति में एक दो घोड़े भी रखा करता था। वह हल के हाथ सभी लगाया करता था, जबकि परिवार का भरण-पोषण कठिन हो जाता था।<sup>८</sup> उनके विवाह सम्बन्ध मेवाड़, भारवाड़ व जयपुर के ठाकुर परिवारों के साथ समान स्तर पर हुआ करते थे। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी उसके वश और रक्त की पवित्रता उज्ज्वल मानी जाती थी। पड़ोसी रियासतों के ठाकुरों जैसी ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव होता था।<sup>९</sup>

अंग्रेजों के शासनकाल में भ्रमण-भरवाड़ा के भौमियों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व थे।<sup>१०</sup>

प्रथम—ये लोग जिन गांवों के भौमिया होते थे, उन गांवों में यात्रियों की संपत्ति की चोरों और डाकूओं से रक्षा करना।

द्वितीय—उस जुर्म से हुई क्षति, जिसे रोकना इनका फर्ज था—उसकी पूर्ति करना।

भ्रमण में प्रचलित भौम-व्यवस्था और उससे जुड़े हुए कर्तव्यों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है—

प्रथम, भौम बंशपरम्परागत संपत्ति होती थी। इस भूमि पर राजस्व कर माफ होता था। स्वामित्व राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता था। इस तरह यह "माफी"

घोर "जागीर" से भिन्न होता था क्योंकि माफी घोर जागीर में राज्य अपने राजस्व सबधी अधिकार ही उन्हें प्रदान करता था।

द्वितीय—राज्य के विरुद्ध अपराध की स्थिति में अथवा उन अपराधों में जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति अस्त करने का प्रावधान था "भौम" को राज्य पुनर्ग्रहण कर सकता था।

तृतीय—राज्य द्वारा "भौम" के पुनर्ग्रहण कर लेने पर उसमें निहित स्वामित्व के अधिकार के साथ-साथ राजस्व से मुक्ति के अधिकार भी समाप्त हो जाते थे क्योंकि ये दोनों कभी भी पृथक् नहीं माने गए थे।

चतुर्थ—अपने कर्तव्यों की अवहेलना या त्रुटि होने पर भूमियो पर जुर्माना घोषा जा सकता था और उस अपराध की पूर्ति न होने तक राज्य उसकी भौम को जब्त कर लेता था।

यदि कोई भूमिया बिना सरकार से पूछे अपनी जमीन हस्तांतरित कर देता तो राज्य उसकी जमीन को पुनर्ग्रहण कर सकता था। राज्य को इसे किसी घोर को प्रदान करने का अधिकार था।

राजपूताना की अन्य रियासतों में भी भूमियों को इसी तरह के निम्नलिखित उत्तरदायित्व वहन करने होते थे।<sup>१०</sup>

१—अपने क्षेत्र में से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा का भार इन पर होता था।

२—अपने क्षेत्र में होने वाली डकैती के लिए वे जिम्मेदार माने जाते थे।

३—वे लोग अपनी 'भौम-भूमि' का विक्रय नहीं कर सकते थे।

४—इनकी भूमि करों से मुक्त होती थी।

५—इनसे किसी तरह की पुलिस सेवा नहीं ली जाती थी।

६—उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अव्याप्तनीय था।

७—भूमिया अपने परिवार में विवाह, भरण अथवा अचानक ऐसा ही कोई अवसर उपस्थित होने पर इस अतिरिक्त व्यय के वहन-हेतु एक अलग उपकर लागू कर सकता था।

सन् १८२१ में, इस जिले की भौम संपत्तियों के बारे में विस्तृत जाँच की गई थी। उसके अनुसार भूमियों पर मेरों घोर डाकुओं से ग्राम क्षेत्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व होता था। वे ग्राम सीमा में घरने वाले अवेधियों की निगरानी रखते थे और सूबेदार द्वारा तसब किए जाने पर दस या पन्द्रह दिन के लिए उसकी सेवा

में जाते थे, परन्तु इन दिनों का भोजन आदि का व्यय सूवेदार को वहन करना होता था ।<sup>११</sup> केवल राजपूत और पठान ही भौमिया हो सकते थे । इनकी भौम संपत्ति पंगारम्परागत होती थी, सूवेदार को भौमियों की कर्तव्यपरायणता में शिथिलता पाने प्रथवा उनके सापरवाही दिखाने पर जुर्माना करने का अधिकार था । यह कहा जाता है कि चोरी गए माल की क्षति-पूर्ति का प्रावधान आरम्भिक भौम-व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं था परन्तु बाद में मराठा शासनकाल में लागू किया गया लगता है और कालांतर में यह व्यवस्था मजबूत होती गई और बाद में इन्हें क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाने लगा । राज्य ने इसकी जिम्मेदारी भौमियों पर हस्तांतरित कर दी ।<sup>१२</sup>

छजमेर-मेरवाड़ा जिले में भूमि पाँच तरह की थी—

१—“मुंडकटी” अर्थात् पूर्वजों के युद्ध में मर जाने के कारण राजा द्वारा प्रदत्त ।

२—आश्रितिक शांति प्रथवा जनता के धान-माल की सुरक्षा के प्रयत्नों से प्रसन्न होकर प्रदान की गई ।

३—राज्य द्वारा युद्ध में शौर्य दिखाने पर प्रदान की गई “भौम” ।

४—राज्य द्वारा सीमा सुरक्षा-हेतु प्रदान की गई “भौम” ।

५—गाँवों में गश्त और निगरानी के लिए ग्रामजनों द्वारा प्रदत्त “भौम” ।<sup>१३</sup>

छजमेर में लगभग सभी भौम संपत्ति उपरोक्त चौबी और पाँचवीं श्रेणी की थी । जो लगभग एक दूसरे के समान थी । केवल दो भौम संपत्तियाँ तीसरी श्रेणी की थी । यहाँ की सभी ‘भौम’ संपत्तियाँ चाहे उनके मूल उद्गम का स्वरूप कैसा भी क्यों न रहा हो चोरी व डकैती का पता नहीं लगा पाने पर क्षति-पूर्ति के लिए जिम्मेदार थी ।<sup>१४</sup>

पाँचवीं श्रेणी के भौमिया, जिन्हें गाँव के लोगो ने गश्त एवं निगरानी के लिए भौम प्रदान की थी, उसका उपभोग राज्य की स्वीकृति से करता था । नवोकि ‘भौम’ पर राज्य का स्वामित्व होता था न कि गाँव का राज्य इसे उस व्यक्ति को ट्रस्ट के रूप में प्रदान करता था । इस “ट्रस्ट” के साथ घर-कोई शर्त जुड़ी होती थी तब उस शर्त के अंग होने पर राज्य उस भौम को पुनर्ग्रहित कर सकता था । राज्य द्वारा सीमा क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रदत्त ‘भौम’ भी सशर्त होती थी, परन्तु इस तरह का भूभाग केवल विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित परिवार को ही प्रदान किया जाता था । इस तरह सशर्त भोग वाली भौम का उपभोग करने वाले को उसकी शर्त



में राज्य की बिना स्वीकृति के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता था। इनके विषय या वषक के लिए राज्य की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक थी।<sup>१६</sup>

अजमेर-मेरवाड़ा की अधिकांश 'भौम' संपत्तियों के बारे में प्रचलित कथन यह है कि घालमगौर और उसके पुत्र शाहघालम के समय इन लोगों को प्रत्येक गाँव में गाँव वालों की येरों और चौतों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए भूमि प्रदान की गई थी। मुगल शासन द्वारा इनको सभी तरह के करों से मुक्त रखा गया था।<sup>१७</sup> इस जिले के हस्तांतरण के समय भौमियाँ "भौम" और 'मापा' नामक कर वसूल करते थे। भौम शुल्क उन सभी चीजों पर लगता था जो रास्ते में से गुजरते समय रात पड़ने पर उक्त गाँव में रहती थी। मापा शुल्क गाँव में बेची जाने वाली सभी चीजों पर कृपि सामग्री को छोड़कर वस्तु के मूल्य के कुछ प्रतिशत के आधार पर ली जाने वाली राशि होती थी। बिल्डर के प्रतिनिधित्व पर ये शुल्क समाप्त कर दिए गए थे। इनकी समाप्ति से इस्तरारदारों की हुई क्षति का उन्हें मुआवजा प्रदान दिया गया परन्तु यह मुआवजा उसके वास्तविक हकदार भौमियाँ को प्राप्त नहीं हुआ था।<sup>१८</sup>

मराठों ने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने पर भौमियों से "भौमबाब" ५ "भौम दस्तूर" वसूल करना आरम्भ किया था।<sup>१९</sup> प्रति दूसरे वर्ष इस्तरारदारों के समान इनसे भी अनिवार्य राशि भौमियाँ की हैसियत और फसल के आधार पर वसूल करते थे।<sup>२०</sup>

केबेडिश के समय में कानुनों द्वारा संगृहीत रिपोर्टें अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सन् १७५२ में जोधपुर नरेश तख्तसिंह ने "भौमबाब" वसूल की थी। उन्होंने यह कर केवल एक साल ही लिया। इस आशय का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने "भौमबाब" के रूप में कितनी राशि कितने "भौमियों" से वसूल की थी। १७६२ में स्पानीय मराठा अधिकारी शिवाजी नाना के समय से "भौमबाब" नियमित रूप से वसूल होता रहा। यह कर उन्हीं प्रमुख भौमियों से वसूल किया जाता था जो हैसियतदार होते थे और इस कर की राशि उनकी हैसियत के अनुसार ही कम या अधिक हुआ करती थी। इसकी वसूली के पीछे कोई सिद्धांत या निश्चित प्रक्रिया नहीं थी। शिवाजी नाना ने अपने दस वर्षों के प्रशासनकाल में केवल एक बार ही यह कर संगृहीत किया था। सन् १७५४ में यह कर प्रति तीसरे साल वसूल लिया जाने लगा और तातिषा छिपिया ने इसे प्रति दूसरे साल वसूल करने की प्रथा जारी की थी। आगामी ६ वर्षों में यह कर पाँच बार वसूल किया गया था। इस तरह भौमियों के शासनकाल के पूर्ववर्ती वर्षों में यह केवल दस वर्षों के लिए ही संगृहीत हुआ था। इस कर को प्रति दूसरे वर्ष वसूल नहीं करने का कारण मराठों द्वारा भौमियों के प्रति अपनी उदारता बतसाया गया था।<sup>२१</sup>

सन् १८१८ में जब यह जिला अंग्रेजों की हस्तांतरित हुआ तब भीमिया प्रति दूसरे वर्ष "भीमबाब" चुका रहे थे। हस्तांतरण के ठीक पूर्व जो राशि इस कर की मद में प्राप्त हुई थी उसे आधार मानकर बिल्डर ने ८,४०८ रुपए १२ आने ६ पाई इस कर से राज्य की आय निर्धारित कर दी थी। यह राशि प्रति दूसरे वर्ष सन् १८४२ तक वसूल होती रही। सन् १८४२ में 'पटेलबाब' और 'फौजलख' के साथ इसे भी समाप्त कर दिया गया था।<sup>२१</sup> अंग्रेजों के कमिश्नर सदरलैंड ने गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट में इसकी आलोचना करते हुए लिखा था कि फौजलख और पटेलबाब सहित ये मराठा उपकर इस्तमरारदारों पर भारी बोझ है और जिस प्रजा से ये वसूल किए जाते हैं उसका इस्तमरारदार व किसान की स्थिति पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है।<sup>२२</sup> लगभग तीन वर्षों तक सदरलैंड द्वारा उत्तरपश्चिमी सूबे और सर्वोच्च भारत सरकार के बीच एक लम्बे पत्र-व्यवहार के पश्चात् गवर्नर जनरल ने "भीमबाब" और भीम दस्तूर को पूर्णतः बिना किसी शर्त के समाप्त किया था।<sup>२३</sup> इस कर को समाप्त करते समय गवर्नर जनरल ने भीमियों को यह हिदायत दी थी कि सरकार ने जिस तरह इन करों को समाप्त कर उन्हें लाभान्वित किया है, उसी तरह वे भी गाँव से उक्त कर की वसूली समाप्त कर ग्रामीणों को लाभ पहुँचाए।

सन् १८५६ तक भीमिया गाँव वालों से कई तरह के उपकर वसूल करते थे। ये उपकर जिन्हें 'लाग' कहा जाता था सामाजिक जीवन के हर पहलू और प्रक्रिया पर लगते थे। भीमिया होली और दशहरे पर मंड वसूल करते थे, अपनी गद्दी की मरम्मत के लिए गाँव के लोगों से बेगार लेते थे तथा प्रतिवर्ष गाँव से उन्हें एक बकरा मंड होता था और कुछ गाँवों में इसके बजाय 'भैंसा' लेने की व्यवस्था थी। गाँव के बलाई को प्रतिवर्ष भीमियों के कुँए के लिए एक चरस और जूतों की जोड़ी देनी होती थी। प्रत्येक खेत से वे धान के ७० पूते लेते थे तथा कुछ गाँवों से केवल प्रति खेत मूट्टी भर धान ही वसूल किया जाता था। भीमिया के जेष्ठपुत्र के विवाह पर ग्रामीणों को उसे मंड देनी होती थी। प्रत्येक गाँव वाले को अपने घर में भी शादी के अवसर पर भीमिया के यहाँ चँदरी और 'कासा' भेजना पड़ता था। कर्नल डिवसन ने यह सुझाव दिया था कि 'भीमबाब' के समाप्त हो जाने के कारण इससे सबधित सभी 'लागें' भीमियों द्वारा ग्रामवासियों से वसूल करना भी समाप्त हो जानी चाहिए तथा विवाह के अवसर पर कासा भेजना गाँववालों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। सरकार ने कर्नल डिवसन से पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए सन् १८५४ में उन्हें अपने प्रस्तावों की व्यावहारिक रूप देने का आदेश दिया था।<sup>२४</sup>

सन् १८३० में सरकार ने भीम जमीन का समय-समय पर बदोबस्त का अधिकार रखा था।<sup>२५</sup> परन्तु अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर सदरलैंड का यह मत था कि जिस तरह इस्तमरारदारों पर सरकार ने बदोबस्त के अधिकार का परित्याग किया

या उसी आधार पर सरकार को 'भौम' पर भी इस अधिकार को भी त्याग देना चाहिए। वह इस मत के थे कि दोनों भूभाग यद्यपि पृथक् हैं, तथापि उनका आधार एक ही है व अतः केवल इतना ही है कि तालुकेदार सेवा के उपलक्ष में शुल्क प्रदान करते रहे हैं, जबकि भौमियों को यह 'माफ' किया जाता रहा है।<sup>२१</sup> सदरलैंड की सिफारिश पर सरकार ने भौम पर पुनः कराधान का अधिकार सन् १८७४ में त्याग दिया था।<sup>२२</sup>

उस समय जिले में कुल १११ भौम थे<sup>२३</sup> और वे निम्नांकित प्रकार से विभाजित थे:—

भौम-भूसंपत्तियों की संख्या		गाँवों की संख्या	
राठोड़	८२		७८
गोड़	६		८
कछवाहा	६		४
सिसोदिया	१		१
पठान	६		६
सम्यद	१		१
मेर	१		१ कोयाज
चीता	१		१ सोमलपुर
मुगल	१		० बीर
<u>१११</u>		<u>१०४</u>	

इनमें से अन्तिम तीन 'भौम' नहीं मानी गई थी। वास्तविक भौम भूसंपत्तियाँ १०८ थीं। भौम संपत्तियों के उद्गम का पता लगाना कठिन है। यद्यपि इनमें से प्राची दिल्ली के सम्राटों के द्वारा प्रदान की गई थी तथा भाषे से अधिक भौम राठोड़ों के पास थी जो अपने आपकी पड़ोसी रियासतों के राजा-महाराजाओं के रिश्तेदार मानते थे। केवेंडिश के समय में, केवल ६ गाँवों के भौमियाँ ही सनदें प्रस्तुत कर पाए थे, जेप का कहना था कि मराठों के कुशासन और भराजकता के काल में उनकी सनदें या तो नष्ट हो गई थी अथवा खो गई थीं। ख्वाजापुर की सनद जफरखाँ को सन् १७४० में गोविन्दराव ने प्रदान की थी जिसके अनुसार जफरखाँ पर अजमेर से राजौरिया तक की सड़क की सुरक्षा का भार था। इसी प्रकार दोलतराव व सिधिया द्वारा अजुनपुरा के भौम की सनद ठाकुर बनसिंह को प्रदान की गई थी।<sup>२४</sup>

बड़गाँव के लिए महाराजा सिधिया की सनद थी, जिसमें यह घोषित किया गया था कि यहाँ की जमींदारी पुराने ज़माने से ही जफरखाँ के यहाँ चली आ रही है और ग्रामियों को निर्देश दिए गए थे कि उसके वंशधरों को परम्परागत भौम के सभी हकों और हकूकों का उपभोग करने दिया जाए।<sup>३०</sup>

केकड़ी के भौमिया को दिल्ली के मुगल सम्राट् फर्रुखसय्यद ने अपने शासन के चौथे वर्ष में सनद प्रदान की थी जिसमें परगना केकड़ी के सभी कानूनगो और चौधरियों को आगाह किया गया था कि १००० बीघा जमीन, एक बाग और एक रहने का भकान राजसिंह राठीड़ को प्रदान किए गए थे।<sup>३१</sup>

नांद भौम के लिए महाराजा अमरसिंह द्वारा, हिन्दूसिंह, हिम्मतसिंह एवं बलरसिंह के नाम सनद थी जिसमें लिखा था कि उक्त व्यक्तियों ने गुजरात में सर-कुतुबखाना के साथ सझाई में बहादुरी दिखाई और कुँवर दुल्लेसिंह उस युद्ध में मारा गया था अतएव १३३१ बीघा जमीन प्रदान की जाती है।<sup>३२</sup> केवल उपर्युक्त दस्तावेज ही भौमिया अपने प्रमाण में प्रस्तुत कर सके थे। इनमें भी अजुनपुरा, खाना-पुरा और बड़गाँव की सनदों से यह वहाँ भी स्पष्ट नहीं होता है कि इनकी मूल शर्तें क्या थीं। नांद के भौमियों द्वारा प्रस्तुत सनद वास्तविक थी, परन्तु इसमें भी यह नहीं लिखा था कि यह भेंट सगत है और यह उल्लेख भी नहीं था कि यह भौम सेवा के उपलक्ष्य में है। केकड़ी की सनद भी एक सामान्य राजस्व मुक्त जागीर के सामान्य पट्टा जैसी ही थी। यदि "भौम" ग्राम्य राजस्व मुक्त जागीरों की अपेक्षा स्याई स्वा-मित्व एवं प्रतिष्ठा सूचक नहीं होती तो जूनिया जैसे ठिकाने का शक्तिशाली ठाकुर अपने आपको केकड़ी का भौमिया कहलाने में कभी शौरव अनुभव नहीं करता। जूनिया के ठाकुर ने केवेंडिश के समक्ष यह कहा था कि सम्पूर्ण केकड़ी का कस्बा मुगल सम्राट औरंगजेब ने किशनसिंह की शानदार सेवामें के उपलक्ष्य में उन्हें जागीर में प्रदान किया था। उसके ठिकाने में चौकीदारों की व्यवस्था थी और वह किसी भी तरह की प्राथमिक क्षति के लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानते थे।<sup>३३</sup>

इन १०८ भौम में प्रत्येक भौम के अन्तर्गत औसत भूमि ४६४ बीघा थी, परन्तु इन भौम में २१०२ हिस्से थे, इस तरह प्रत्येक भौम में औसतन बीस भागीदार थे जिनमें प्रत्येक के हिस्से में औसतन २६ बीघा १४ बिस्वा भूमि आती थी। पुराने बंदोबस्त की शर्तों के अन्तर्गत इनका करगणन किया जा चुका था और इनमें से प्रत्येक को १७ रुपए ८ आने राजा को देना पड़ता था।<sup>३४</sup>

सन् १८४३ के पूर्व प्रायः सभी भौमिया अपनी भौम को वंश-परम्परागत मानकर बंधक भी रख देते थे जबकि उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था। वे लापरवाह और आलसी हो गए थे तथा अपने गाँवों की रक्षा करने योग्य भी नहीं रह गए थे। वे लोग न तो घोड़े रखने का खर्च ही बहन करने की स्थिति में थे और न चौकीदार

ही रख सकते थे। जब कभी इनके क्षेत्र में चोरी या डकैती पड़ने पर इन लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए कहा जाता तो ये अपनी भूमि के बंधक होने का बहाना कर उसे टाल जाते थे। इन भूमियों के पास मचारी के साधन और शस्त्र नहीं होने के कारण ये लोग अपने क्षेत्र की चौकसी व निगरानी करने में असमर्थ थे।<sup>34</sup> जब एक बार भूमि को बंधक रख दिया जाता तो महाजन अपने कर्ज की ठोरी को इतना कस देता था कि वह भूमि कभी छूट कर इन्हे वापिस प्राप्त नहीं हो पाती थी।

इसलिए सन् १८४३ में सरकार ने यह आदेश जारी किए कि कोई भी भूमियाँ अपनी भूसंपत्ति को न तो विक्रय ही कर सकता था और न उसे बंधक ही रख सकता था। इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान रखा गया था। महाजनो को यह आदेश दिया गया था कि वे भूमि संपत्ति को बंधक नहीं रख सकते हैं। उन्हें यह निर्देश दिए गए थे कि वे अपने ऋण की वसूली अन्य साधनों द्वारा अथवा भूमियाँ की दूसरी संपत्ति से करें। सरकार ने यह भी घोषणा कर दी थी कि यदि किसी ने भूमि संपत्ति को बंधक रखा, अथवा किसी ने उस संपत्ति को बंधक के रूप में स्वीकार किया है तो बंधक भूमि संपत्ति का दावा कोई भी ग्यायालय स्वीकार नहीं करेगा तथा बंधक स्वीकार करने वाला इस भूमि के उपयोग से बंचित रहेगा। सरकार ने यह नियम बना दिया था कि यदि किसी गाँव की सीमा में कोई अपराध पड़ित होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति भूमि से होगी और इस बारे में किसी भी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी भूमियों को व भूमि संपत्ति को बंधक के रूप में स्वीकार करने वालों को उक्त आदेश से अवगत करा दिया गया था।<sup>35</sup> इस आदेश के बावजूद भी भूमियाँ अपनी जमीनों बंधक रखते रहे, फलस्वरूप सन् १८४६ में कर्नल डिवसन को इस प्रक्रिया के विषय कड़ी आज्ञा जारी करनी पड़ी। सरकार ने इनको दिए गए शर्तनामे में यह लिख दिया था कि वे अपनी भूमि का विक्रय नहीं करेंगे और न उसे बंधक ही रख सकेंगे।<sup>36</sup>

सरकार की विक्रय और बंधक पर प्रतिबन्ध इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि, यदि सरकार भूमियों के अपनी भूमि को अन्य पक्ष के हाथों विक्रय और बंधक के अधिनार स्वीकार कर लेती तो अन्य पक्ष को प्रदेश के सामान्य नियमों के अन्तर्गत इन भूमि से जुड़े अधिकार तथा उत्तरदायित्व भी वहन करने पड़ते जो कि भूल स्वामी को प्राप्त थे। सरकार की यह धारणा थी कि मासदार सूदखोर महाजन भूमियों की तरह कुशल और सुस्त बीरोदारी एवं निगरानी की व्यवस्था नहीं कर सकते थे।

राजपूताने की कुछ रियासतों में भूमियों को अपनी भूमि-संपत्ति केवल दो धनस्रोतों पर ही बंधक रखने की अनुमति थी। वे रिता के अन्तिम संस्कार के व्यय को बहन करने के लिए तथा अपनी अथवा अपने पुत्र की शादी व्यय के लिए बंधक रख

सकते थे। परन्तु उसके लिए बचक रहते समय अपने निर्वाह योग्य तथा निगरानी एवं चौकसी के कार्य में बाधा न पड़े, इस लिए उचित भूमि अपने पास रखना अनिवार्य था। मजमेर-मेरवाड़ा के कार्यवाहक कमिश्नर कर्नल ब्रुक्स ने सभी रिपासतों के बकीलों के साथ पूरे दरबार में इस प्रश्न की चर्चा की थी जिसमें उन्होंने यह राय प्रकट की थी कि भूमि राज्य की स्वीकृति से ही बचक रखी जा सकती थी, क्योंकि जिन कार्यों के लिए भूमि दी गई थी उनके पालन करवाने का उत्तरदायित्व राज्य पर था।<sup>३७</sup> कर्नल डिवसन ने इस भूसंपत्ति की व्याख्या करते हुए कहा था कि भूमि "चौकसी एवं निगरानी के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि है जिस पर भूमियो को स्वामित्व का अधिकार नहीं है।"<sup>३८</sup> कर्नल डिवसन द्वारा बचक में विरुद्ध प्रार्था जारी होने के बाद भी भूमि के विक्रय एवं बचक के उदाहरण सरकार के समक्ष आते रहे। प्रशासन को इन भूमियों के विरुद्ध कानूनी कदम उठाने में कठिनाई अनुभव होती थी क्योंकि सरकार को पहले यह निर्धारित करना था कि भूमिया अपनी भूमि-संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार रखते हैं या नहीं और क्या भूमि जिस सेवा के उपलक्ष्य में इन्हें प्रदान की गई थी उसकी पूर्ति के अभाव में अन्य भूमि की तरह उस पर सरकार राजस्व एवं कराधान लगा सकती थी या नहीं?<sup>३९</sup> मजमेर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के अनुसार भूमि "पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों सहित राजस्व एवं कर रहित भूमि थी।"<sup>४०</sup> अतएव उन्होंने इस प्रश्न को स्पष्टीकरण के लिए भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया था। भूमि पर भूमियों के मातृकाना हक के बारे में कर्नल डिवसन के बाद के काल में भी भ्रम बना हुआ था।

ब्रुक्स के अनुसार विभिन्न तरह के 'भूमि' प्रचलित थे अतएव उनके माध्यमबहार में भी भिन्नता आवश्यक थी। उन्होंने इस प्रश्न को केवल राजस्व की समस्या न मान कर सामान्य नीति का प्रश्न माना था। उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया था कि प्रथम चार श्रेणी के भूमियों के साथ व्यवहार करते समय पाँचवीं श्रेणी के भूमियों को पृथक् रखना जरूरी है। उनकी मांग्यता के अनुसार प्रथम चार श्रेणी वाले भूमियों में से कतिपय ऊँचे घरानों के थे और उनके परिवार का जयपुर और मेवाड़ के ठाकुर परिवारों के साथ विवाह संबंध एवं बराबरी का रिश्ता कायम था। अतएव उन्हें अपनी भूमि से वधित करना उचित नहीं होगा, उन्हें अपनी भूमि के विक्रय एवं बचक के अधिकार दिए जाने चाहिए। जहाँ तक पाँचवीं श्रेणी के भूमियों का प्रश्न था जिन्हें भूमि चौकसी एवं निगरानी सेवा के लिए दी गई थी, उनका मन था कि इस भूमि को सतर्क मानी जाए और इस तरह की भूमि यदि बेची या बचक रखी जाती है तो नए बंदोबस्त के अन्तर्गत उन पर कराधान लागू किया जाना चाहिए।<sup>४२</sup>

जे. सी. ब्रुक्स के अनुसार चौकसी एवं निगरानी की सेवा के निमित्त स्वीकृत

सभी "भौम" से कर वसूल किया जाना चाहिए क्योंकि पहले भी इनसे कर लेना भौचि-त्यपूर्ण माना गया था। उन्होंने इन 'भौम' पर 'भौमबाब' और 'भौम दस्तूर' फिर से लागू करने का सुझाव दिया था क्योंकि, राजपूताने की अन्य रियासतों में यह 'भौम' कभी भी सर्वथा कर मुक्त नहीं रही थी और भौमिया पहले सदा 'भौमबाब' और 'भौम दस्तूर' चुकाते रहे थे। अंग्रेजों के शासनकाल में ही सन् १८४२ तक इनसे 'भौम-बाब' और 'भौम दस्तूर' वसूल किया जाता था। सन् १८४२ में सरकार ने फौजी खर्च के साथ-साथ इसे भी समाप्त कर दिया था। ब्रुक्स के अनुसार फौजखर्च नियमित राजस्व वसूली के प्रतिरिक्त मराठों द्वारा थोपी गई 'लाग' थी जबकि 'भौम-बाब' इस तरह की कोई अनियमित प्रथा नहीं थी।<sup>४३</sup>

इन सभी बाधाओं और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल की कौंसिल ने भौम संपत्तियों के बारे में सन् १९७१ में निम्न सिद्धांत स्वीकार किए:—

१. किसी भी तरह की भौम जो प्राप्तकर्ता या उसके परिवार के अधिकार में हो उस पर कराधान नहीं किया जाए।
२. सभी भौम-संपत्ति जो स्थाई रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है अथवा भविष्य में हस्तांतरित हो उस पर कराधान लागू किया जाए।
३. सभी मशत भौम जो चौबीसी और पाँचवीं श्रेणी के अन्तर्गत आती हो यदि अस्थायी रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है अथवा भविष्य में की जाए तथा उससे सम्बद्ध शर्तों की पूर्ति होने की संभावनाएं नहीं हों तो इन पर कराधान लागू किया जाए।
४. मशत भौम, स्वामी के जीवन पर्यन्त के लिए ही बंधक रखी जा सकती है। गवर्नर जनरल 'भौमबाब' को पुनः लागू करने के पक्ष में तो नहीं थे, परंतु वे यह अवश्य चाहते थे कि इन 'भौम' के साथ सेवा संबंधी जो शर्तें जुड़ी हुई हैं वह इनसे भौम संपत्तियों के अनुपात में ली जाय। गवर्नर जनरल की यह राय थी कि यदि इनका उपयोग चोरियों को रोक-थाम में नहीं किया जा सके तो कम से कम उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए उत्तर-दायी बनाया जाए। बचक और विक्रय प्रतिबंधित हो और इनके उत्पन्न पर 'दण्डस्वरूप' 'भौम' पर कराधान लागू किया जाना चाहिए तथा अवतक की हस्तान्तरित सभी 'भौम' पर पूरा कराधान लागू होना चाहिए।<sup>४४</sup>

सन् १८६६ के एक्ट को इस जिले में लागू कर देने पर डिप्टी कमिशनर ने सभी भौमियों को अपना नाम चौकीदारों की सूची में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान किए थे। जिन्होंने व्यक्तिगत चौकीदारी करने में असमर्थता प्रकट की थी उन्हें अपने

क्षेत्र में प्रति २० बीघा विहित भूमि पर एक चौकीदार के अनुपात में चौकीदार रखने व ६० ६० प्रति चौकीदार प्रतिवर्ष उनकी तन्या चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सभी भूमियों ने इस आधार पर कि इस तरह की व्यवस्था भोम पट्टेदारी में नहीं है, इस आदेश के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए। यद्यपि इन भूमियों के निवेदन पर कोई निर्णय नहीं हुआ तथापि डिप्टी कमिशनर का आदेश भी ब्रियान्वित नहीं किया गया।<sup>४५</sup>

भूमियों में उत्तराधिकार की प्रथा स्पष्ट थी और व्यवस्थित रूप से चली आ रही थी। १६ भोम संपत्तियों में ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता था, १० भोम में बड़े लड़के को अपने छोटे के हिस्से से कुछ बड़ा भाग मिला करता था। शेष भोम सामान्य उत्तराधिकार नियमों के अनुसार बँटा करती थी।<sup>४६</sup>

व्यवस्थित चौकीदार-प्रथा स्थापित होने से पूर्व भूमियाँ चौकसी एवं निगरानी का कार्य किया करते थे। उनके हलके में चोरी और डकैती की घटनाओं पर उनका बहु फर्ज होता था कि वे अधिकारियों को सूचना प्रदान करें। परन्तु वे ऐसा कभी नहीं करते थे क्योंकि उन्हें क्षतिपूर्ति का डर रहता था। इतना ही नहीं जब पुलिस अधिकारी घटना की जाँच पड़ताल के लिए गाँव में पहुँचते तो भूमियाँ उनकी कोई मदद नहीं करते थे।<sup>४७</sup> पुलिस जब कभी घटना की जाँच के लिए गाँव में पहुँचते तो भूमियाँ आपस में ही इस बात को लेकर विवाद प्रारम्भ कर देते थे कि उस दिन किसकी चौकीदारी थी।<sup>४८</sup>

भूमियों की नियुक्ति उस काल में हुई थी जब सरकार की अपनी व्यवस्थित पुलिस नहीं थी, अतएव उस समय कदाचित् यही व्यवस्था उत्तम रही होगी कि कुछ लोगों को भूमि प्रदान करके उसके बदले में यात्रियों और ग्राहीणों की जान माल की सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथों सौंप दी जाए। परन्तु जब सरकार ने अपनी नियमित पुलिस व्यवस्था गठित कर ली तब भूमियों का उपयोग समाप्त हो गया था और भोम व्यवस्था की आवश्यकता और उपयोगिता उस अराजकता के युग के समाप्त होने के साथ ही नष्ट हो गई थी। भोम में हिस्सा पाने वाले की औसत आय १७ रुपए के लगभग थी, अतएव उसकी संपत्ति से क्षतिपूर्ति की धाशा निरर्थक थी।<sup>४९</sup> उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग कर पाना और इनसे पहले जैसी सेवाएँ प्राप्त करना भी असंभव था। समय इतनी तेजी से बदल गया था और पुलिस के कर्तव्यों को इनका सुस्पष्ट एवं नियमित कर दिया गया था कि सरकार द्वारा इसका "पुलिस-व्यवस्था" के लिए उपयोग करना संभव नहीं रहा था।

जब सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भूमियों का कैसे उपयोग किया जाए। इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकार ने मजमेर के डिप्टी कमिशनर मेजर रिपटन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।<sup>५०</sup> यह



समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भूमियाँ जिस प्रकार की सेवाएं पहले प्रदान किया करते थे, अब उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है अतएव इस दिशा में उन्होंने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए —

१. भूमियों द्वारा गाँवों की सुरक्षा का कार्य तथा उनके द्वारा चोरी और डकैती की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी समाप्त कर दी जाए।
२. गाँवों में दबो की स्थिति शांत करने तथा चोरों और डाकुओं का पीछा करने में उनका उपयोग किया जाना चाहिए।
३. प्रत्येक भूमिये को सम्राट के जन्म दिवस पर इण्टी कमिशनर के कार्यालय में उपस्थित होकर नज़राना भेंट करना होगा।
४. नज़राना की राशि पुराने 'भूमिनाम' कर की राशि ४,२०० रुपए वार्षिक के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए और यह भूमि की सभी जोतों में उचित रूप से मौजूदा पैमाइश के आधार पर विभाजित की जानी चाहिए।
५. भूमि की ज़मीन की ऋण की सदायगी स्वरूप कुकर्म नहीं किया जाए और न इस भूमि को किसी को बेचा या बंधक रखा जाए। यदि इस आदेश का उल्लंघन करे तब इस तरह की बंधक या बेची गई भूमि पर पूरी दरी से राजस्व वसूल किया जाए। परंतु यह नियम भूमियों के आपसी हस्तांतरण पर लागू नहीं था।
६. उपर्युक्त बातों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक भूमिये को सनदें प्रदान की जाएं।<sup>११</sup>

भूमि समिति ने 'भूमि' के पुनर्गठन का सुझाव इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ऐसा कदम राजपूताने में कभी भी प्रचलित नहीं था और इससे व्यापक असंतोष भड़कने की भी आशंका थी। वेदखल हुआ भूमियाँ लुटपाट और डकैती का मार्ग प्रदूषण कर सकता था और वह लोगों की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त करने में समर्थ हो सकता था। अतीत में किसी भी भूमिये को अपने कर्तव्य की अवहेलना करने के अपराध में कभी भी वेदखल नहीं किया गया था। इस संदर्भ में दृढ़ केवल जुमाने प्रथा चोरी गई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति तक ही सीमित रहता था।<sup>१२</sup>

सरकार की नीति पुरानी भूभाग-व्यवस्था और प्रथाओं के साथ समया-नुकूल परिस्थितियों के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करने की थी। अंग्रेज़ सरकार यह नहीं चाहती थी कि पुरानी प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था के मुकाबले मंते ही घबड़ी हो, स्थापित की जाए क्योंकि नई व्यवस्था

को एकाएक ग्रहण कर सेना भी संभव नहीं था ।<sup>१३</sup>

सरकार ने सन् १८७४ में भौम समिति की रिपोर्ट में सुझाए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था ।<sup>१४</sup> इसी वर्ष भौमियों को चौकीदारी और निगरानी की सेवाओं में तथा हर्जाने के उपलक्ष में क्षतिपूर्ति वाले प्रावधान से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था ।<sup>१५</sup> इन लोगों को संश्लेषणगत जागीरदार और माफीदारों की श्रेणी में घोषित किया गया और उनकी जोतों को लगान मुक्त रखा गया ।<sup>१६</sup> सन् १८७१ में सरकार ने भौमियों को सन्देश प्रदान कीं जिनमें उनके भावी भू-भाग की शर्तें निहित थीं । उसके बाद उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया । अंग्रेज सरकार ने भौमियों को उनकी अधिकांशतः पुरानी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था परन्तु उनके विशेषाधिकार कायम रहने दिए थे ।

जागीर—

जागीर भूसंपत्तियाँ अजमेर जिले में एक दूसरी ही तरह की कर रहिन होती थीं । इनको राजपूताने की रिवाजतों में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था के अनुकूल नहीं समझना चाहिए । ये अधिकांशतः अंग्रेजों से शासित प्रदेशों के धार्मिक एवं पुण्यार्थ के कामों के लिए दान अथवा भेंट के तौर पर प्रदत्त भूमि थी । जागीर में प्राप्त सम्पूर्ण गाँव या गाँव के कुछ भाग थे । प्रारम्भ में जागीरदार केवल भूराजस्व का अधिकारी होता था, परन्तु कालांतर में उसके हितों में व्यापक विस्तार हो गया था ।<sup>१७</sup>

सन् १८१८ में जिले के हस्तांतरण के समय ऐसे ६४ गाँव थे । इनमें से पाँच गाँव—भूरजकुण्ड, भाधा नादना, भूट्टी, नाथाधुना और तानपुरा विल्वर के कार्यकाल में सरकार के आदेश से पुनर्ग्रहित कर लिए गए थे ।<sup>१८</sup> केवेंडिश के कार्यकाल में ऐसे ५६ जागीर गाँव थे । सन् १८३० में नवाब हाकिमखान के निधन पर छतरी गाँव तथा सन् १८३६ में दीवान मेहदी अली खोरी के निधन पर अरारका सरकार ने अपने अधिकार में कर लिए थे । खोलास गाँव पुष्कर स्थित ब्रह्माजी के मन्दिर की जागीर थी और नदरामपुरा तथा हरमाड़ा आपाजी सिधिया के समाधि-स्थल की जागीरें थी । १२ दिसम्बर, १८६० में अंग्रेज सरकार और सिधिया के मध्य हुई संधि के अनुसार सिधिया ने अपनी अजमेर स्थित जागीरें भी अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी थी । ये पाँचों गाँव स्थाई रूप से अजमेर के सातसा भूमि में सम्मिलित कर लिए गए थे तथा मंदिर व छतरी के लिए इन गाँवों से राजस्व बंद हो गया था । इस प्रकार कुल ५२ जागीरें शेष रही, जिनमें ४६ पूरे जागीर गाँव और तीन में कुछ भाग जागीरों का था व कुछ खातमा का था । बाद में राजगढ़ व नीलखेरी के गाँव भी जागीरों में स्वीकार कर लिए जाने पर जागीरों की कुल संख्या ५४ हो गई थी । इन जागीरों में दो गाँव डेवू और मकरी में भाषी बादिक

ग्रामदानी इन गांवों के दोनों जागीरदारों को दी जाती थी और आधी सरकार को प्राप्त होती थी ।<sup>१४</sup> नांदला गांव भी स्पष्टतः दो भागों में विभाजित था । इस तरह जागीर गांवों की वास्तविक संख्या साढ़े इक्कावन अथवा बावन (५२) थी ।<sup>१०</sup>

जागीर गांव निम्न तीन श्रेणी में विभक्त थे:—

१. सस्यानों की मेंट गांव अथवा संस्थान के संबंध कार्यवाहकों की मेंट ।
२. व्यक्तिगत प्रदत्त ग्राम ।
३. निगमों को प्रदत्त गांव । इनमें किसी के नाम नहीं दिए गए थे । इसके राजस्व का वे सभी सौग उपभोग करते थे जो उसकी सीमाओं में आते थे ।<sup>११</sup>

प्रथम श्रेणी के धर्मगत निम्न संस्थान, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित जागीरों का उपभोग करते थे:—

#### १. बरगाह हवाजा मुईनुद्दीन चित्तौरी:—

१७ गांव परबतपुरा, चांदसेन, हवाजापुरा, केर धावा मेसाना, हवाजपुरा, नैरवार, कुई, पीचोलिया, तिलोरा, कलिया, बुववारा, कदमपुरा, कियतपुरा, केकरान, दातरा ।

#### २. बरगाह मोरी साहिब:—

३ गांव-डोरिया, सोमलपुरा, करिया ।

#### ३. चिल्लापीर इस्तगीर:—

१ गांव मातपुरा ।

#### ४. नाथद्वारा मंदिर:—

१ गांव-भवानीखिडा ।

#### ५. दूमरी धीमोराव:—

२ गांव-ताली खेड़ा और भगनपुरा ।

#### ६. दुधारी पुण्यार्थ ट्रस्ट —

१ गांव-नालागिबरी ।

जागीर कमिश्नर ने द्वितीय श्रेणी की जागीरों में दो तरह के जागीरदारों को मान्यता प्रदान की थी । एक तो व्यक्तिगत जागीरें जिनमें ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में जागीर का स्वामित्व ग्रहण हुआ करता था और इनके अधिकारों में भाड़े गांव से कम भूमिराशि नहीं रहती थी । दूसरी वे जागीरें जो कि भाड़े गांव से भी कम थी ।<sup>१२</sup>

इन जागीरदारों में भूमि गभी उत्तराधिकारियों में विभाजित हुआ करती थी। वे आपस में इनकी विक्रय व बचक से हस्तांतरित कर सकते थे। परन्तु बाहर के व्यक्तियों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध था। इस श्रेणी के अन्तर्गत बानेरी, भाणोरा, मोराजा (आधा), नांदवा, हाथी खेडा (आधा) एवं दीवारा के गाँव आते थे।

तृतीय श्रेणी की जागीरें व्यक्तिगत न होकर समुदायगत थीं। इन में भी पाँच गाँव आते थे। दरगाह खजादा माहब के सादिम के अधिकार में थी, बेगर एवं बनुजी के गाँव थे। पुष्कर की बड़ी बस्ती के द्वापरा पुष्कर के जागीरदार थे। पुष्कर की छोटी बस्ती के द्वापराणों की नादलिया की जागीर प्राप्त थी।

सन् १८७३ में जागीरदारों और किसानों के आपसी सम्बन्ध श्री न्यायालय द्वारा स्पष्ट कर दिए गए थे।<sup>१३</sup> वे सभी किसान जिनके कच्चे में तानाब, जलाशयो और कुँधों से सिंचित भूमि थी जिसके सिंचाई-खोन जागीरदारों द्वारा प्रदत्त सिद्ध नहीं हुए थे उक्त जोतों के स्वामी या बिस्वेदार स्वीकार कर लिए गए थे। जागीरदार उस सिंचित भूमि के स्वामी माने गए जिनके सिंचाई के खोनो का निर्माण उनके द्वारा किया गया हो।

इस्समदारदार की तरह जागीरदार को अपनी भूमिसत्ति के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार नहीं था। वह संपूर्ण संपत्ति प्रमथा उमका धन किसी भी बाहरी व्यक्ति को न तो बेच ही सकता था और न सेंटस्वरु प्रदान कर सकता था। परन्तु जागीरदार अपने जीवन पर्यन्त के लिए अपनी जमीन को पट्टे पर उठा सकता था व बचक के रूप में रख सकता था। वह उन किसानों को मासिकाना या बिस्वेदारी का हक प्रदान कर सकता था जो असिंचित और बरानी भूमि को कुँए भादि खोदकर कृषि के लिए विकसित करते थे। जागीर भूमि के बिस्वेदार को अपनी जोतों को जागीरदार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तांतरण या विक्रय करने का अधिकार था। अतएव भूमि विकास ऋण कानून के अन्तर्गत उन्हें भी जागीरदारों की तरह अधिम राशि समुचित जमानत प्रस्तुत करने पर प्रदान की जा सकती थी।<sup>१४</sup>

जागीरों के संबंध में यह नियम था कि इन जागीरों में कोई भी भागीदार अपना अंश सेंट भयवा बचक के रूप में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने जीवनकाल से अधिक समय के लिए हस्तांतरण कर सकता था। किसी बाहर के व्यक्ति को जागीर हस्तान्तरित करने वाले स्वामी की मृत्यु के पश्चात् वह सरकार द्वारा पुनर्प्राप्ति की जा सकती थी और उस पर राजस्व कराधान लागू किया जा सकता था।<sup>१५</sup>

जागीर गाँवों में जागीरदार अपना राजस्व फमल के रूप में वसूल करता था, केवल कपास और मक्का की फसलें ऐसी थी, जिन पर मुगलान नगदी में लाना जाता

था। यह राशि 'बीघोड़ी' या 'मपती' कहलाती थी। बीघोड़ी और मपती वाले क्षेत्र को छोड़कर जागीर भूमि में कूता की प्रथा थी और जागीरदार का हिस्सा भूमि की किस्मों अथवा आपसी समझौते से निर्धारित हुआ करता था। यह कराधान दो तरह का होता था जिसे स्थानीय बोली में कूता और लाटा कहा जाता था। कूता का अर्थ फसल की कटाई के समय निर्धारित कराधान होता था। फसल में ११ भूसा व अन्न को पृथक् करके उसे तोल कर अन्न निर्धारण की क्रिया को 'लाटा' कहा जाता था। लाटा द्वारा जागीरदार का हिस्सा पृथक् निकाल कर उसे दे दिया जाता था।<sup>१२</sup>

कुंभों और नालियों के निर्माण के लिए विशेष एवं निश्चित सिद्धांत नहीं थे। जब कोई किसान कुंभा अथवा नाली का निर्माण करना चाहता तो उसे जागीरदार आपसी समझौते द्वारा निर्धारित नजराना राशि लेकर पट्टा प्रदान किया करता था। जब कोई किसान कुंभा या नाली खुदवाता था तब उसकी भूमि पर राजस्व की दरें कुछ समय के लिए घटा दी जाती थीं और जब नाली या कुंभा तैयार हो जाता तब किसान अपनी जोत का स्वामी मान लिया जाता था। इन जागीरदारों में फसल-पूर्णतः बर्षा पर निर्भर थी।

### माफीदार

'माफी' की भूमि प्राप्त व्यक्ति केवल राजस्व प्राप्ति के हकदार होते थे। सरकार उन्हें तकावी उसी स्थिति में देती थी जबकि वे बिस्वेदार होते थे। माफीदार को भूमि-हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त नहीं थे। माफी के हकों को हस्तांतरित करने पर उसकी जोत पुनर्ग्रहीत की जा सकती थी।<sup>१३</sup>

'मीम' और 'जागीर' की श्रेष्ठों ने सामान्यतः उन्हें पुरानी प्रथा के अनुकूल ही बनाए रखा। यह इनमें किसी भी तरह के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इनसे इन लोगों में संदेह या असंतोष पैदा हो सकता था। अजमेर जिले की 'जागीर' व 'माफी' में केवल इतना ही अन्तर था कि जागीर का सामान्य अर्थ सम्पूर्ण गांव या गांव के अंश से लिया जाता था और माफी जोती का अर्थ निश्चित जमीन के टुकड़े से था। इन जागीरदारों के भूभाग पर किसी तरह की सैनिक सेवा या अन्य सेवा का प्रतिबन्ध नहीं था।<sup>१४</sup>

## अध्याय छ

अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दि० १२ सितम्बर, १८७३, संख्या ३१६५ राज-पूताना गजेटीयर्स भाग ३ पृ० ३७ ।

२. भार० केबेंडिश सुपरिन्टेंडेंट एंव पोलिटिकल एजेंट, अजमेर द्वारा कार्य-वाहक रेजीडेंट दिल्ली को पत्र दि० ८ जुलाई, १८३० ।

३. कर्नल डिवमन, कमिश्नर अजमेर द्वारा सेक्रेट्री उत्तरी-पश्चिमी मूवा सरकार को पत्र दि० १४ अप्रैल, १८५६, संख्या १४३ ।

४. टॉड—एम्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, खण्ड १, पृ० १६८ ।

५. भौम कमेटी रिपोर्ट सन् १८७३ ।

६. कर्नल जे० सी० ब्रुक्स कार्यवाहक चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र, भावू दि० १७ अगस्त, १८७१ व कर्नल जे० सी० ब्रुक्स द्वारा सी० यू० एचिसन सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र दि० २१ फरवरी, १८७१ संख्या १०४ ।

७. उपरोक्त ।

८. भौम कमेटी की रिपोर्ट, सन् १८७३ ।

९. उपरोक्त ।

१०. चीफ कमिश्नर अजमेर द्वारा सेक्रेट्री भारत सरकार को पत्र, दि० १० जनवरी, १८७४ संख्या ३० ।

११. भार केबेंडिश, सुपरिन्टेंडेंट एंव पोलिटिकल एजेंट द्वारा कार्यवाहक रेजीडेंट दिल्ली को पत्र, दिनांक ८ जुलाई, १८३० ।

१२. कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को सुपरिन्टेंडेंट की कार्यवाही (मई १८४३) सहित पत्र, दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ (रा. रा. पु. मं.) ।

१३. कर्नल जे. सी. ब्रुक्स, कार्यवाहक चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सी. यू. एचिसन सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र, भावू दिनांक १७ अगस्त, १८७१ संख्या २०५ ।

१४. भौम कमेटी रिपोर्ट, सन् १८७३ ।

१५. कर्नल जे. सी. ब्रुक्स, कार्यवाहक चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सी. यू. एचिसन सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र, भावू दिनांक १७ अगस्त, १८७१ संख्या २०५ ।

१६. एफ. विन्डर पोलिटिकल एजेंट एवं सुपरिन्टेंडेंट अजमेर द्वारा सी०

भॉक्टरलोनी रेजीडेंट मालवा एवं राजपूताना को पत्र, भजमेर दिनांक ५ सितम्बर, १८२२ ।

१७. भार. केवेंडिश सुपरिंटेंडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट भजमेर द्वारा कार्यवाहक रेजीडेंट, देहली को पत्र भजमेर दिनांक ८ जुलाई, १८३० ।
१८. कर्नल डिवसन, कमिश्नर भजमेर द्वारा सेक्रेट्री उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र, दिनांक ३० अक्टूबर, १८५४ सं. ४२० ।
१९. भार. केवेंडिश सुपरिंटेंडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट द्वारा कार्यवाहक, रेजीडेंट देहली को पत्र, भजमेर, दिनांक ८ जुलाई, १८३० ।
२०. भौम कमेटी रिपोर्ट, सन् १८७३ ।
२१. भार. केवेंडिश, सुपरिंटेंडेंट भजमेर द्वारा कार्यवाहक रेजीडेंट देहली को पत्र, दिनांक ८ जुलाई, १८३० ।
२२. कर्नल सदरलैंड ए. जी. जी. राजस्थान द्वारा भार. एम. हेमिल्टन, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र, दिनांक ८ जनवरी, १८४२ ।
२३. सचिव, भारत सरकार द्वारा भार. एम. सी. हेमिल्टन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र, दिनांक १४ नवम्बर, १८३२ संख्या ६६ ।
२४. भौम कमेटी रिपोर्ट, सन् १८७३ ।
२५. जे. पाम्पसन, कार्यवाहक उप सचिव भारत सरकार द्वारा कार्यवाहक रेजीडेंट एवं चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक फोर्ट विलियम, ७ दिसम्बर, १८३० ।
२६. एल. एस. साम्बर्स कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र भजमेर दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ संख्या ३१६५ ।
२७. सचिव भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर को पत्र दिनांक २९ सितम्बर, १८७९ संख्या २३० ।
२८. भौम कमेटी रिपोर्ट, सन् १८७३ ।
२९. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र भजमेर दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ संख्या ३१६५ ।
३०. भौम कमेटी रिपोर्ट, सन् १८७३ ।
३१. उपरोक्त ।
३२. उपरोक्त ।
३३. भौम कमेटी रिपोर्ट, सन् १८७३ ।

३४. एल. एस. साइर्स कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को प्रेषित पत्र भजमेर दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ संख्या ३१६५ ।
३५. "भौमियों को सनद अदायगी" फाइल, सुपरिटेण्डेंट भजमेर कार्यालय की हिन्दी कार्यवाही का अनुवाद, दिनांक ४ मई, १८४३ ।
३६. उपरोक्त फाइल, कर्नल डिवसन का आदेश ४ मई, १८४३ ।
३७. उपरोक्त दिनांक २५ जुलाई, १८४६ ।
३८. कर्नल जे. सी. ब्रुक्स कार्यवाहक चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सी. यू. एचिसन सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र आबू, दिनांक १६ अगस्त, १८७१ संख्या २०५ ।
३९. रण्टन डिप्टी कमिश्नर भजमेर द्वारा एल. एस. साइर्स कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक २७ जुलाई, १८७१ संख्या २१६४ ।
४०. उपरोक्त ।
४१. डिप्टी कमिश्नर भजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर को पत्र दिनांक २० जनवरी, १८७३ संख्या ७६ ।
४२. कर्नल जे. सी. ब्रुक्स कार्यवाहक चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सी. यू. एचिसन, सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र आबू दिनांक १६ अगस्त, १८७१ संख्या २०५ ।
४३. उपरोक्त ।
४४. सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक २८ अक्टूबर, १८७१ व फाइल "भौमियों को सनद अदायगी ।"
४५. चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार आबू, दिनांक १६ अगस्त, १८७१ संख्या २०५ व फाइल "भौमियों को सनद अदायगी" ।
४६. भौम कमेटी रिपोर्ट, सन् १८७३ ।
४७. डिप्टी कमिश्नर भजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर को पत्र दिनांक २० जनवरी, १८७३ संख्या ७६ ।
४८. जिला सुपरिटेण्डेंट पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर को पत्र दिनांक ४ जनवरी १८७३ संख्या ८ ।
४९. कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १२ दिसम्बर, १८७३ संख्या ४२१४ ।



५०. एल. एस. सांडर्स कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को क्रमेटी नियुक्त करने के बारे में पत्र दिनांक २७ जनवरी, १८७३ संख्या ३०६ ।
५१. भीम कमेटी रिपोर्ट, मर्च १८७३ ।
५२. उपरोक्त ।
५३. फाइल 'आदेश भीम संपत्तियों एवं ग्राम पुलिस' संख्या २३० द्वार. चीफ कमिश्नर अजमेर द्वारा सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक १० जनवरी, १८७६ संख्या २३० व फाइल "भीम संपत्तियों एवं ग्राम पुलिस पर आदेश" ।
५४. सचिव भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक २४ सितम्बर, १८७४ ।
५५. फाइल "भीम संपत्तियों एवं ग्राम पुलिस पर आदेश" ।
५६. एल० एस० सांडर्स कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ संख्या ३१६५ ।
५७. प्रसिस्टेंट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र अजमेर दिनांक ६ अगस्त, १९०६ क्रमांक २९८१ ।
५८. जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनांक १६ मई, १८७४ ।
५९. प्रसिस्टेंट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर को पत्र दिनांक ८ मई, १८८६ क्रमांक १०० ।
६०. कमिश्नर अजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक ३ अगस्त, १८८६ क्रमांक १८६२ ।
६१. जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनांक १६ मई, १८७४ ।

निम्नांकित तालिका प्रत्येक वर्ग की जागीरों के अन्तर्गत गाँवों तथा इन जागीरों के सङ्गम को प्रकट करती है—

जागीर देने वाले का नाम	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	कुल
अजमेर	१६	—	—	१६
जहान्नीर	१	३	४	८
गान्धारी	—	३	—	३
आलमगीर	—	३	—	३

जागीर देने वाले का नाम	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	कुल
फर्रुखशियर	२	६३	....	६५
मुहम्मद शाह	....	४	....	४
मराठा	५	६	१	१२
महाराजा प्रजीतसिंह	....	१	...	१
भद्रेश सरकार	१	१	....	२
कुल संख्या	२५	२२३	५	५२३

भाधा डेरूप प्रथम श्रेणी और भाधा भाखेरी तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत आते थे ।

उपरोक्त गाँवों में से १० गाँवों में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी माना जाता था तथा ८ गाँवों में जागीर पैतृक सम्पत्ति के रूप में बंटा करती थी ।

६२—

—प्रथम श्रेणी—

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| १. राजा देवीसिंह              | कोठाज एवं राजगढ़ ।                                |
| २. दीवान गियासुद्दीन<br>भलीला | देसवाड़ा ।  |
| ३. नवाब शमशुद्दीन भलीला       | सीदारिया, भाधा डेरूप,<br>बोराज, काजीपुरा, सोलबर । |
| ४. राजा बलबतसिंह              | मगवाना, उत्तरा एवं मगरा ।                         |
| ५. भीर इनायत-उल्लाह शाह       | कुड़ियाना, भाधा देसवाड़ा ।                        |
| ६. भीर निजाम भली              | जावासा, भटियाना ।                                 |
| ७. गुलाबसिंह                  | भर्जुनपुरा ।                                      |
| ८. सानिमराम ज्योतिषी          | मगलियावास ।                                       |
| ९. गोकुलपुरी मोसार्द          | चोवडिया ।   |

६३—मसिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र दिनांक ६ अगस्त, क्रमांक-२१८१ ।

१४—उपरोक्त ।

१५—उपरोक्त ।

१६—उपरोक्त ।

१७—लाहौर भजमेर-मेरवाड़ा की बंदोबस्त रिपोर्ट सन् १८७४ ।

१८—प्रसिस्टेन्ट कमिश्नर भजमेर द्वारा कमिश्नर भजमेर को पत्र दिनांक  
६ अगस्त, १९०६ क्रमांक २९८१ ।

---

## पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था

सन् १८६२ से पूर्व भजमेर-मेरवाड़ा में नियमित पुलिस जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस सेवाओं के लिए विभिन्न प्रथा एवं प्रक्रियाएं प्रचलित थी।<sup>१</sup> अंग्रेजों द्वारा मेरवाड़ा को अधीनस्थ करने के बाद, इस क्षेत्र में व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन के दृष्टिकोण से तीन प्रमुख भारतीय अधिकारियों की नियुक्तियां की गई थी। प्रारम्भ में एक ही अधिकारी को राजस्व व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यभार वहन करना होता था।<sup>२</sup> टाडगढ़ के तहसीलदार को जिसके क्षेत्र में ८१ गाँव और १३ ठाणियाँ थी, दक्षिणी परगने के दवेर, टाडगढ़, भायला और कोटकिराना के राजस्व सम्बन्धी कार्यों के प्रशासन के अतिरिक्त जिले के इस भूभाग में नागरिक प्रशासन की भी व्यवस्था करनी होती थी। टाडगढ़ तहसीलदार के क्षेत्र में पाँच प्रमुख पुलिस थाने थे। प्रत्येक थाने में एक पेशकार तथा तीन चपरासी नियुक्त थे। सुचारु व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षेत्र को और भी कई भागों में विभाजित किया गया था प्रत्येक। चपरासी पृथक् रूप से प्रत्येक तीन या चार-चार गाँवों की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया गया था। ये लोग अपने क्षेत्र के चपराश की स्थिति के बारे में प्रतिदिन सवधित थानों के पेशकार को सूचना देते रहते थे। इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा तहसीलदार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत घटी घटनाओं से सम्पर्क बनाए रखता था। चोरियों और डकैती की घटनाओं की सूचना संबंधित थानों या तहसीलदार को अविलम्ब की जाती थी। सारोठ तहसीलदार के क्षेत्र के अन्तर्गत जिले के केन्द्र में स्थित

सारोठ और कोटड़ा परगने ये जिनमें ५३ गाँव और १५ दाखियाँ थीं। उत्तरी क्षेत्र के तहसीलदार के अन्तर्गत ब्यावर, भ्रक, श्यामगढ़ और चाग के परगने ये जिनमें १०९ गाँव और ५२ दाखियाँ थीं। इसी तरह का प्रशासनिक उप विभाजन ब्यावर क्षेत्र का भी था, जिसके अधीन कई थानों और चउरासियों की व्यवस्था की हुई थी। टाडगढ़, देवर और सारोठ के किलों में मेर इटालियन की सैनिक टुकड़ियाँ नियुक्त की गई थीं। मेरवाड़ा के पहाड़ी भाग में व्यापारिक काफिलों और यात्रियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था थी। जब कभी कोई डकैती की घटना घटती तो क्षतिप्रस्त पक्ष की क्षतिपूर्ति का भार उन ग्रामों को वहन करना होता था, जहाँ ये दुर्घटनाएँ घटित होती थी।<sup>३</sup>

इस्तमरारदारों को उनके अपने क्षेत्रों की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था इसी आधार पर सौंपी हुई थी कि यदि कोई दुर्घटना इन क्षेत्रों के अन्तर्गत घटती तो उन्हें इसका उत्तर-दायित्व वहन करना होता था। उन दिनों इसी तरह की व्यवस्था प्रचलित थी। भूमियों को उनकी भूसंपत्ति के पूर्ण अधिकार इसी आधार पर प्राप्त थे कि वे अपने क्षेत्र की व्यवस्थित चौकसी एवं निगरानी रखें। खालसा भूमि में भूमियों की प्रथा नहीं थी। वहाँ सरकार को निगरानी एवं चौकसी के लिए चौकीदार नियुक्त करने पड़े थे। चौकीदार बहुधा पीता एवं मेर जातियों के लोगो में से नियुक्त किए जाते थे। इन पर यह जिम्मेदारी थी कि अगर उनकी लापरवाही के फलस्वरूप किसी तरह की दुर्घटना घटती तो उन्हें क्षतिपूर्ति करनी होती थी। ये लोग जरायम पेसा कौमों में से थे। इनकी नियुक्ति के पीछे यही भाव था कि जबतक वे नियुक्त होंगे तब इनके जाति भाई इन क्षेत्रों में चोरी करने का दुस्ताहम नहीं करेंगे।<sup>४</sup>

उन दिनों अजमेर-मेरवाड़ा में जब किसी व्यक्ति का सामान इस्तमरारदारी या भूमि गाँव में चोरी हो जाती तो वे कीजदारी अदालतों में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर इस्तमरारदार या भूमियों से क्षतिपूर्ति की रकम अदालत के जरिये वसूल कर सकते थे।<sup>५</sup> अजमेर-मेरवाड़ा के इस्तमरारदारों को अपने क्षेत्र की समूची पुलिस-व्यवस्था का भार वहन करना होता था। केवल कुछ ही प्रमुख कस्बों में सरकारी पुलिस चौकियों की व्यवस्था थी जो कि नोटिस, सम्मन या वारंट तलबी का काम करती थी। अजमेर जिले के एक तिहाई क्षेत्र में इस्तमरारदारी व्यवस्था थी। इस क्षेत्र की समूची पुलिस-सेवा उनके अधीनस्थ ही थी।

इस्तमरारदार को उनके कर्तव्य के प्रति सचेत रखने के लिए जिला अधिकारी को क्षतिपूर्ति लागू करने का अधिकार उपलब्ध था। इस आशय के सभी मामले दीवानी अदालतों के बजाय कीजदारी अदालतों से तय होते थे। यदि ये मामले दीवानी अदालतों के मुद्दे कर दिये गये होते तो जिला अधिकारी का इस्तमरारदारों पर नियंत्रण कमजोर जाता तथा जिला अधिकारी का इस्तमरारदारी और भूमियों से चौकसी और निगरानी

की सेवाएं लेना कठिन हो जाना । शक्ति प्रप्त व्यक्ति दीवानी दावों की लम्बी प्रक्रिया से परेशान होकर शीघ्र ही इस्तमरारदारों और भीमियों में समझौता कर लेना बड़ी अधिक उचित समझता । यही एक ऐसी प्रक्रिया थी जो इस्तमरारदारों को अपने कर्तव्यों के प्रति चौकन्ना रखे हुई थी ।<sup>१</sup> सन् १८७४ में इस्तमरारदारों का शक्तिपूर्ति का दायित्व समाप्त कर दिया था ।<sup>२</sup>

सन् १८५८ में कर्नल डिवसन ने १८ गांवों में तीन रुपये मासिक वेतन पर चौकीदारों की नियुक्तिवादी थीं । इनके वेतन का एक भाग यात्रियों में कर के रूप में तथा शेष गांव के खर्चों की राशि में से वसूल किया जाता था । कर्नल डिवसन की यह मान्यता थी कि मेर स्वयं अपनी व्यवस्था करने में सक्षम हैं । इसलिये उस क्षेत्र में केवल एक या दो बड़े कस्बों में, जहाँ व्यापारी वर्ग अधिक था, सरकारी चौकीदारों की नियुक्तियाँ की गई थीं । करने के प्रत्येक निवासी को इन चौकीदारों के वेतनस्वरूप निश्चित मात्रा में भुगतान देना होता था ।<sup>३</sup> सन् १८६१ तक इस जिने की सामान्य व्यवस्था का मार मेरवाड़ा बटालियन के हाथ में था । इस बटालियन का केन्द्रीय कार्यालय भी उन दिनों ब्यावर में स्थित था ।<sup>४</sup>

[मेरवाड़ा-क्षेत्र की पहाड़ियों में कुछ ही सड़कों थीं जहाँ से आवागमन संभव था। भ्रष्टों के अधिपत्य के पूर्व यह भाग व्यापारिक कारियों को लूटने के लिए लुटेरों का विशेष स्थान बन गया था । नयानगर, जवाजा, जस्सा खेडा, टाडगढ़ और दवेर के मशहूर बकत इस क्षेत्र में लूटपाट कर लूट का माल सीमा पार के क्षेत्रों में बेच आते थे । लूट व चोरी के माल में अधिकतर भेषजी हुआ करते थे । कभी-कभी डाकुओं के बल डाका डालने की नियत से भ्रष्टों के क्षेत्रों में बारातियों का वैश धारण करके गुजरते थे । सीमा स्थित कई ठाकुर भी इन लुटेरों को शरण एवं सुरक्षा प्रदान किया करते थे ।<sup>५</sup>

इस क्षेत्र पर भ्रष्टों के अधिपत्य के पश्चात् प्रमुख रास्ते निकटवर्ती ग्रामों की निगरानी में सौंप दिये गये थे । इस तरह के लूटपाट के भ्रष्टों की बहुत कुछ रोकथाम की जा सकी थी । कर्नल डिवसन ने लूटपाट की जिम्मेदारी रास्ते से सटे हुए ग्रामों पर थोप दी थी । मेरवाड़ा में इन रास्ते से यात्रा करने वालों से नाममात्र का शुल्क उनकी सुरक्षा-हेतु वसूल किया जाता था । इस तरह के क्षेत्र में यह शुल्क भ्रष्टों सामकर सिद्ध हुआ तथा यात्रियों की यह कर कभी मार के रूप में प्रतीत नहीं हुआ । इससे गांव के लोग यात्रियों की सुरक्षित पहुँचाने के लिए एक तरह से अनुबध्ति हो गये थे । सड़कों को बकतों और लुटेरों की कार्यवाही से मुक्त एवं सुरक्षित रखने में यह राशि उपयोगी सिद्ध हुई थी । सन् १८६७ तक इस क्षेत्र में कस्टम व चुंगी कर लगते थे जिसके कारण कई चुंगी-प्रधिकारी इस क्षेत्र में नियुक्त थे, जिनकी उपस्थिति मात्र ही इस क्षेत्र में चोरी-दो चूनेट करने वालों पर प्रभुत्व थी । डाकुओं और लुटेरों का पीछा करने

के लिए कालांतर में अग्रेसरी रिजर्व से बुलाई गई घुड़मवारों की टुकड़ी इस क्षेत्र में तैनात कर दी गई थी। बाद में इस तरह की घुड़सवार टुकड़ी का गठन अजमेर में भी कर लिया गया था।<sup>११</sup>

ठगी घोर डकैती का उन्मूलन :-

राजपूताना में ठगी घोर डकैती का दमन करने के लिए अफसर, लोभर व ईस्टर्न राजपूताना नाम की तीन एजेंसियाँ सन् १८८१ में स्थापित की गई थीं। अफसर राजपूताना एजेंसी का सदर मुकाम अजमेर में था। इसका कार्यभार "असिस्टेंट जनरल सुपरिटेण्डेंट ठगी एवं डकैती उन्मूलन" को सौंपा गया था।<sup>१२</sup> उक्त अधिकारी की तृतीय श्रेणी के वंशनायक के अधिकार प्राप्त थे।<sup>१३</sup> सन् १८८६ में अफसर, लोभर घोर ईस्टर्न राजपूताना एजेंसियों को समाहित करके राजपूताना के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया गया जिसका कार्यभार जनरल सुपरिटेण्डेंट राजपूताना के असिस्टेंट को सौंपा गया। धनवर, जयपुर घोर धाबू में भी निरीक्षण चौकियाँ कायम की गईं व असिस्टेंट का सदर मुकाम अजमेर में रखा गया।<sup>१४</sup>

डकैतियों के दमन के लिए अजमेर-मेरवाड़ा घोर सीमावर्ती पड़ोसी रियासतों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता अनुभव होने लगी। मारवाड़ ही एक अकेली ऐसी रियासत थी जिसके वकीलों की अभियुक्तों को पकड़ने में अजमेर पुलिस की सहायता करने के अधिकार प्राप्त थे। इस रियासत का एक वकील अजमेर में घोर दूसरा ब्यावर में नियुक्त था। जयपुर की घोर से एक वकील देवली में भी था। मेवाड़ का भी अपना वकील था, परन्तु बाद में हटा लिया गया था।<sup>१५</sup>

वकील अजमेर पुलिस को परवाना देते थे जिससे वह उनकी रियासत में प्रवेश कर अभियुक्त घोर चोरी का माल बरामद कर सकें।<sup>१६</sup> इस पुलिस दस्ते की सहायता के लिए भी एक चरामनी उनके साथ भेजा जाता था। जब कभी अभियुक्त घोर चोरी का माल घण्टी सीमाओं में बरामद होता तो उसे निकटवर्ती स्थानीय अधिकारियों की निगरानी में सौंप दिया जाता था। तत्पश्चात् अभियुक्त की भयमान के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता था। परन्तु सामान्य मामलों में वकील के पद घोर उसमें निहित निरकार के आधार पर कि वह अभियुक्त बरामद माल को अजमेर-मेरवाड़ा में समय पर प्रस्तुत कर सकेगा, जिसे वारंट के ही पुलिस दस्ते के साथ भेज दिया जाता था। यह व्यवस्था अक्षेत्र शासित देश घोर रियासतों के बीच सहयोग पर आधारित थी। यह सहयोग सभी निरदवर्ती रियासतों को अजमेर के संबंध में उपलब्ध था। इन रियासतों के पुलिस अधिकारियों को इन कार्य के लिए अजमेर-मेरवाड़ा में प्रवेश करने की अनुमति थी। इसके लिए उन्हें पास परवाना होना अनावश्यक था। इसके लिए इनका ही पर्याप्त था कि वे अपने आवाम की सूचना कर दें घोर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी में अजमेर पुलिस की मदद लें। अभि-

मुक्त और बरामदगुदा माल भ्रजमेर पुलिस की सुरक्षा में तबतक रखा जाता था जब-तक कि तत्सम्बन्धी नियमित कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो जाती थी। प्रसाधारण मामलों में जब भी यह अनुभव होता कि विलम्ब के कारण अभियुक्त फरार हो सकता है, यथवा श्याय में देर हो सकती है, तो उपर्युक्त रियासत पुलिस अधिकारी बिना विशेष औपचारिकता पूरी किए ही कार्यवाही सम्पन्न कर लेते थे। आवश्यकता पड़ने पर अगर भ्रजमेर पुलिस की सहायता के बिना ही यदि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता तब भी बहुधा ऐसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाता था और औपचारिकता की पूर्ति बाद में कर ली जाती थी।<sup>१७</sup> इस संबंध में पड़ोसी रियासतों की महत्व मिलती रही।<sup>१८</sup> सभी बड़ी रियासतों के अधिकृत वकील पहले भ्रजमेर में रहा करते थे और जब वे भाहु जाने छो अपने स्थान पर अन्य मातहतों को छोड़ जाते थे। ऐसी स्थिति में कभी-कभी दुविधा व परेशानी पैदा हो जाया करती थी।<sup>१९</sup> रियासतों के इन वकीलों के पद पर और कार्यों के बारे में कोई लिखित कानून नहीं था। समय-समय पर दिए गए निर्णय और सरकारी आदेश ही उसका आधार थे। इस बात का सदा ध्यान रखा जाता था कि भ्रजमेर-पुलिस और रियासतों के बीच इस संबंध में सहयोग और सहभावना बनी रहे।<sup>२०</sup>

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में राजपूताना में शराजकता की स्थिति व्याप्त थी। इसको समाप्त करने में अंग्रेजों का काफी महत्वपूर्ण योग रहा था। इस स्थिति के उत्पन्न होने के कई कारण थे। असंतुष्ट ठाकुरों द्वारा बहुधा डकैती का मार्ग अपना लेना, ठाकुरों के गिरोहों को एक राज्य से दूसरे में प्रवेश कर जाने पर वहाँ कानून व दंड की मुक्ति मिल जाना, कुछ भागों में नील और मीलों का आवास होना, जिन पर रियासतों का नियंत्रण नाममात्र का था, परन्तु इस स्थिति के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अधिकांश रियासतों में अच्छे शासन और संगठित पुलिस सेवा का अभाव था।

अगर ऐसी परिस्थितियाँ एक रियासत तक सीमित रहतीं तब तो उन्मूलन शर्तः शर्तः प्रशासन में सुधार एवं सरकारी नियंत्रण को कड़ा करके किया जा सकता था, परन्तु यह समस्या एक राज्य तक ही सीमित नहीं थी इसने अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले लिया था जिसे उन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय कहा जाता था।

इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्तरदायित्व निर्धारित करना था। इस संबंध में सन् १८३१ में यह निश्चय किया गया कि जहाँ घटना घटे उस क्षेत्र के अधिकारी को ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। उत्तरदायित्व सबंधी इस सिद्धांत को ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सन् १८३८ में यह निर्णय लिया गया कि “यदि किसी रियासत में जरूरत प्राप्त तुटेरे कोई चूट-पाट उस क्षेत्र में करते हैं तो इसका उत्तरदायित्व उस राज्य को वहन करना होगा।”<sup>२१</sup>



इन मामलों में किसी भी तरह का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के पूर्व क्षतिपूर्ति के दावेदार को यह सिद्ध करना होता था कि उसने अपनी जानमाल की हिफाजत की सामान्य व्यवस्था कर रखी थी। यात्रियों से यह अपेक्षित था कि गांव में पहुँचने पर वे सराय में रुकें ताकि गांव का चौकीदार उनकी चौकसी रख सके। उन्हें अपनी सम्पत्ति को गांव के अधिकारियों की सुरक्षा में सौंप देना आवश्यक था जो कि उसकी अमानत के तौर पर निगरानी रखते थे। मार्ग में यात्रा करते समय अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था रखना भी यात्रियों के लिए आवश्यक था। सन् १८५४ में घटित एक ऐसी घटना प्रकाश में आई जिसमें मंदसौर से चित्तौड़ को भेजी जा रही एक लाख रुपये के मूल्य की कासी मिर्च जिसकी रक्षा के लिए चार सशस्त्र व्यक्ति साथ में थे—लूट गई और उसकी क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तावित किया गया। क्षतिपूर्ति के समय यह निर्देश प्रकट किया गया कि इतनी मूल्यवान सामग्री की रक्षा के लिए तैनात केवल चार सशस्त्र व्यक्ति पर्याप्त नहीं कहे जा सकते, फलस्वरूप इस लूट का उत्तरदायित्व सम्बन्धित रियासत पर नहीं है।<sup>२२</sup>

उन दिनों व्यापारिक सामग्री और मूल्यवान वस्तुएं बहुधा बीमा कंपनियों में माध्यम से भेजी जाती थी। ये एजेंसियां "मार्ग की स्थिति" के अनुसार ही अपना सुरक्षा-शुल्क निर्धारित किया करती थी। इह तरह की एक अन्य मनोरंजक घटना का उल्लेख भी पत्रों में मिलता है। एक व्यापारी ने ३५०० रुपये का सोना और जवाहरात उदयपुर से मंदसौर भेजने के लिए उपर्युक्त माध्यम प्रथवा अन्य उचित सुरक्षा का मार्ग अपनाकर अपने दो घरेलू नौकरों के हाथों भिजवाई। ये नौकर साधुओं के वेप में बह सोना घर ले जा रहे थे। रास्ते में इन्हें भीलों ने घायल कर सामान लूट लिया था। क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत इस मामले पर टिप्पणी करते हुए उदयपुर में स्थित पोलिटिकल एजेंट ने लिखा "इस मामले में देसी रियासत को उत्तरदायी मानना मुझे ग्याय की दृष्टि से अत्यन्त सदेहास्पद लगता है क्योंकि लूटी हुई सम्पत्ति के स्वामी ने उचित सुरक्षा का तरीका अपनाने की अपेक्षा भाग्य प्रथवा देव पर भरोसा करना अधिक उचित समझा, और लोभ के लिए दो निरपराध व्यक्तियों को घायल होने के सकट में धकेल दिया।"<sup>२३</sup>

#### बकील अदालत

सुरक्षा एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से केवल उत्तरदायित्व निर्धारित करने का मिश्रित निश्चित करना ही पर्याप्त नहीं था। इसके कारण दीर्घकालीन पत्र-व्यवहार के प्रलावा और कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अतएव इस दिशा में सुधार लाने के लिए दो आवश्यक प्रशासनिक कदम और उठाए गए। पहला अराजकता के दमन के लिए अधिक सक्रिय और कड़ी कार्यवाही तथा दूसरा, अतिरिक्त के निर्धारण और

उत्तरदायित्व स्थिर करने के लिए एक नियमित आयोग की स्थापना ।<sup>२४</sup> पहले कदम के अन्तर्गत मालवा और मेवाड़ में भील सैनिक सेवा का जन्म हुआ और दूसरा प्रशासनिक कदम वकील अदालत की स्थापना था ।<sup>२५</sup> प्रारम्भ में इस तरह की तीन अदालतें भजमेर, नीमच और कोटा में थी, बाद में जोधपुर और जयपुर में भी एक-एक वकील अदालतों की स्थापना की गई ।<sup>२६</sup>

भजमेर में अठारह रियासतों के अधिकृत वकीलों में से पांच प्रतिनिधियों की एक वकील-अदालत स्थापित की गई थी । यह अदालत उन सभी फौजदारी मामलों को निपटाती थी जो एक रियासत के निवासी, व्यापारी या यात्री, दूसरी रियासतों के बारे में शिकायत के तौर पर प्रस्तुत करते थे । भजमेर से सम्बन्ध रखने वाले बाद इस पंचायत में प्रस्तुत होते थे । अदालत प्रतिवादी रियासत के वकीलों और साक्षियों को जिला हाकिमों के माध्यम से सम्मन भेजकर बुलवाती और मुकदमों की सुनवाई करती थी । सम्पूर्ण वाद की जांच के पश्चात् अदालत अपनी कार्यवाही और डिप्री ए० जी० जी० को भेज देती थी । जिस रियासत के विरुद्ध डिप्री पारित होती थी, उसके वकील द्वारावादी को क्षतिपूर्ति की राशि देनी पड़ती थी और वादी पक्ष इसकी लिखित रसीद रियासत को दिया करता था ।<sup>२७</sup> प्रारम्भ में ये वकील-अदालतें फौजदारी मामलों के साथ-साथ कुछ खास किस्म के दीवानी मामले, जैसे समझौता-भंग, विवाह-विच्छेद इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय मामले भी सुनती थी । परन्तु बाद में दीवानी मामलों की सुनवाई को प्रोत्साहन नहीं दिया जाने लगा और यह अदालत पूर्णतः फौजदारी मुकदमों की ही सुनवाई करने लगी ।<sup>२८</sup>

केवल महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुकदमों में ही ए० जी० जी० उपस्थित रहते थे अन्यथा मामलों की कार्यवाही और निर्णय उन्हें प्रेषित कर दिए जाते थे और वे अपने निरीक्षण के पश्चात् अदालत का फैसला सम्बन्धित रियासत को भेजकर उससे डिप्री की बकाया राशि चुकाने की व्यवस्था करते थे ।<sup>२९</sup> वादी एवं प्रतिवादी रियासतों के वकील इस अदालत के सदस्य होते थे परन्तु वे अपने मतों का उपयोग कभी-कभी ही किया करते थे । इन अदालतों को एक तरफा डिप्री सहूर करने का अधिकार भी था ।<sup>३०</sup>

इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य उन यात्रियों तथा लोगों को न्याय प्रदान करना होता था जो अपनी रियासत के बाहर के लोगों के हाथों जान-माल की क्षति उठाते थे । यह ऐसे सभी मामलों को सुनती और निर्णय देती थी जिनमें व्यक्ति और संपत्ति सम्बन्धी भारतीय-दंड-संहिता लागू होनी थी तथा वे सभी मामले जो भारत सरकार और राजपूताना की रियासतों के बीच प्रत्यर्पण (extradition) संधि की शर्तों के अन्तर्गत आते थे । सन् १८६२ के नियमों के अन्तर्गत इन अपराधों को "अन्तर्राष्ट्रीय" कहा गया था परन्तु सन् १८७० में इनको "अन्तर्देशीय अपराध" का नाम दिया

गया था। इनका अधिकार-क्षेत्र केवल रियासतों तक ही सीमित नहीं था वरन् भ्रजमेर-मेरवाड़ा का क्षेत्र भी इनके अधिकार के क्षेत्र में था। इस तरह की संयुक्त मदालत के गठन के पूर्व निकटवर्ती रियासतों से इन मामलों पर एक सम्झे समय तक निरर्थक पत्र-व्यवहार विभिन्न पोलिटिकल ऐजेंटों के बीच चलता रहता था। उसका प्रतिफल विलम्ब और ग्याय की असफलता के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं था। इस संयुक्त ग्यायालय के गठन के पश्चात् यह परेशानी समाप्त हो गई थी। भ्रजमेर-मेरवाड़ा के प्रेसिडेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा से सम्बन्धित मामले उठने पर इस ग्यायालय में बैठ सकते थे परन्तु उनकी उपस्थिति ग्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती थी। अन्य रियासतों अपने वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करती थीं और उनके वकीलों को मुकदमे में कहने सुनने का अधिकार था। भ्रजमेर-मेरवाड़ा को इस तरह का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यह ग्यायालय भारतीय-दंड-संहिता के अन्तर्गत उल्लिखित जान-मास संबंधी अपराधों तथा प्रत्येक-सधियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई एवं जांच करके निर्णय करने में सक्षम थी।<sup>३१</sup>

इन ग्यायालयों को जुर्माना, कारावास, भ्रष्टाचार का दंड देने और उन मामलों में जहाँ ग्यायालय की यह सदेह होता है कि इसमें स्थानीय पुलिस अथवा गाँवों का हाथ है, वहाँ पुलिस अथवा गाँव को दंड देने का अधिकार भी प्राप्त था। यद्यपि दंड संबंधी नियम लिखित नहीं थे तथापि यह ग्यायालय सामान्यतः भारतीय दंडसंहिता व स्थानीय प्रथाओं से मार्ग-दर्शन प्राप्त करता था।<sup>३२</sup>

इस ग्यायालय में उत्तरदायित्व निश्चित करने के निम्न आधार थे:—

१—यह रियासत जहाँ अपराध गठित हुआ हो।

२—यह रियासत जिसमें अपराधी का तरकास पीछा किया गया हो।

३—यह रियासत जहाँ अपराधी रहता हो।

४—यह रियासत जहाँ थोरी एवं सूट का माल अथवा उसका कुछ भाग बरामद हुआ हो।<sup>३३</sup>

उत्तरदायित्व निश्चित करने में ग्यायालय इस बात का ध्यान रखता था कि अपराध के घटित होने और अपराधी के भाग छूटने में रियासत की ओर से कितनी प्रयत्नशक्ति हुई है। यात्रियों से भी यह अपेक्षा की जाती थी कि वे जान और मास की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष हिदायतों का पालन करेंगे। रियासतों पर क्षति-पूर्ति की रकम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि यात्री ने उन हिदायतों का कहाँ तक पालन किया है।<sup>३४</sup>

मूल्यवान् वस्तुओं सहित यात्रा करने वालों को सामान्य नियमों के अन्तर्गत पहले के साथ यात्रा करनी होती थी। नियमानुसार प्रति हजार रुपए के मूल्य की

सामग्री पर दो सशस्त्र पहरेदार उसके धागे घाठ हजार तक की राशि वाली वस्तुओं के लिए प्रति हजार पर एक प्रतिरिक्त सिपाही तथा घाठ हजार से अधिक की राशि पर प्रति दो हजार पर एक अन्य प्रतिरिक्त सिपाही रखना आवश्यक था। इन काफिलों को रोज के समय गांव में रुकना आवश्यक था, जहाँ ग्राम-प्रधिकारियों को अपने आगमन से सूचित कर और उनसे चौकीदार की सेवाएं प्राप्त करनी होती थीं। इन चौकीदारों के प्रतिरिक्त उन्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा-हेतु सशस्त्र पहरे का प्रबंध करना होता था। इन चौकीदारों और सिपाहियों को अपनी सख्या के अनुपात में किसी तरह की क्षति एवं नुकसान की स्थिति में पहरे पर तैनात व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का भार वहन करना होता था।<sup>३४</sup>

यात्रियों के लिए मार्गदर्शक रखना भी जरूरी होता था। मार्गदर्शक प्रति पाँच यात्रियों पर एक, दस पर दो तथा बीस यात्रियों पर तीन की संख्या के अनुपात में होते थे। बारात आदि के लिए सशस्त्र पहरेदारों की आवश्यकता रहती थी और सोना-चांदी, जवाहरात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को किसी भी स्थिति में केवल दो या तीन बाहकों को नहीं सौंपी जा सकती थी।<sup>३५</sup>

### भूमिया

सन् १८६७ तक गांवों में भूमियों के पास पहरे व चौकी की व्यवस्था थी। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामों में पहरे एवं चौकी जैसी व्यवस्था ही प्रायः समाप्त हो गई थी। जब कभी पुलिस घटनाग्रस्त ग्राम में पहुँचती और चौकीदार की तलाश करती तो भूमियों में इस बात की लेकर भापसी कसह आरम्भ हो जाता करता था कि अपराध वाले दिन चौकीदारी की व्यवस्था किसके जिम्मे थी। बहुधा घटना घटित होने की सूचना पुलिस तक पहुँचाई ही नहीं जाती थी। पुलिस-प्रधिकारी के घटनास्थल पर पहुँचते ही भूमिया इस तरह का ढोंग रचते मानों वे सम्पूर्ण घटना से बेखबर हों। इस तरह की बिगड़ी हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप ही सरकार को बेतन भोगी नियमित चौकीदारी-व्यवस्था करनी पड़ी थी। सन् १८७० ई. लेकर सन् १८८० तक चौकीदारी-व्यवस्था शून्य, शून्य सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू की जा चुकी थी।<sup>३७</sup>

### चौकीदार

सन् १८७० में सरकार ने अजमेर-मेरवाड़ा में (जिसमें नसीराबाद, पुष्कर शहर और केकड़ी भी सम्मिलित थे) ६३० चौकीदार नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था पर प्रति चौकीदार चार रुपए मासिक वेतन के हिसाब से प्रति माह २५०० दण्ड व्यय किए जाते थे। डिप्टी कमिशनर अजमेर-मेरवाड़ा ने १ जनवरी, १८७१ को चौकीदारों की संख्या ६३० से घटाकर ४६८ निम्न तालिफानुसार कर दी थी :—<sup>३८</sup>

अजमेर

४४७ चौकीदार ।

ब्यावर

१३ चौकीदार ।

टाडगढ़

३८ चौकीदार ।

जनवरी, १८७३ में पुष्कर और केकड़ी के कस्बों को छोड़कर शेष जिले में चौकीदारों को राज्य की नौकरी से अलग कर पुनः पहले व चौकी की व्यवस्था भूमियों को सौंप दी गई थी ।<sup>४६</sup>

सन् १८७४ में भूमियों की अतिपूति की जिम्मेदारी समाप्त कर दिए जाने पर<sup>४७</sup> सरकार ने अजमेर में ३३ चौकीदार, ब्यावर में २ तथा टाडगढ़ में १३ चौकीदार नियुक्त किए थे । यह व्यवस्था सन् १८७६ तक बनी रही । नगरपालिका द्वारा नियुक्त चौकीदार इनके अतिरिक्त थे । सन् १८७० से १८७६ तक क्षेत्र में चौकीदारों की संख्या का विभाजन क्षेत्र के अनुपात में इस प्रकार का था—<sup>४८</sup>

कुल गांवों की संख्या	गांवों की संख्या जहाँ चौकीदार नियुक्त किए गए ।	चौकीदारों की संख्या
अजमेर तहसील १८४	२२	३३
ब्यावर तहसील २२८	२	२
टाडगढ़ तहसील १००	१०	१४

उपरोक्त तालिका में अजमेर और ब्यावर खास, नसीराबाद छावनी, पुष्कर शहर और केकड़ी सम्मिलित नहीं हैं । अजमेर और ब्यावर की नगरपालिका सीमाओं में नगरपालिका द्वारा पुलिस की व्यवस्था थी । सन् १८५६ के क़ानून २० के अन्तर्गत नसीराबाद, पुष्कर और केकड़ी में भी चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी जो निम्नांकित तालिका के अनुसार थी—<sup>४९</sup>

स्थान	जमादारों की संख्या	चौकीदारों की संख्या
नसीराबाद	३	४०
केकड़ी	१	१२
पुष्कर	१	१६

उन सभी स्थानों या जागीर गांवों में जहाँ घरों की संख्या दो से कम होती थी, चौकीदार नियुक्त नहीं किए जाने थे । ऐसे ४७६ गांव थे जो चौकीदारों की व्यवस्था से वंचित थे ।<sup>५०</sup>

केवल दो सौ घरों से कम आबादी वाले गांवों को ही चौकीदारी-व्यवस्था से वंचित नहीं रखा गया था, बल्कि कई बड़े-बड़े कस्बे भी चौकीदारी-व्यवस्था से वंचित रह गए थे । ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यवस्था नियमित रूप से लागू नहीं हो

पाई थी। निम्न तालिका<sup>४४</sup> उन कस्बों की है जो जनमस्या में चौकीदारी-व्यवस्था के अन्तर्गत आते थे, परन्तु इस लाभ से वंचित रहे गए थे :—

१.	जंठाना	६०० घरों से अधिक की आबादी
२.	तवीजी	५०० घरों से अधिक की आबादी
३.	सरापना	५०० घरों से अधिक की आबादी
४.	श्री नगर	८०० घरों से अधिक की आबादी
५.	वीर	६०० घरों से अधिक की आबादी
६.	राजगढ़	५५० घरों से अधिक की आबादी

चौकीदार को पुलिस के साधारण सिपाही के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। वह केवल मात्र ग्राम का वेतन भोगी नौकर होता था। जिन ग्रामों में चौकीदार नियुक्त नहीं किए गए थे, वहाँ गाँव वाले मिलकर स्वयं चौकी पहर की व्यवस्था करते थे। खालसा और जागीर ग्रामों में सभी महाजनो और गैर-काश्तकारों के घरों से प्रति घर एक रुपया वार्षिक शुल्क वसूल किया जाता था, जो कि हैड सम्बरदार का वेतन स्वरूप होता था अथवा ग्राम के सर्वे की मद में जमा कराया जाता था। चौकीदारों को चार रुपए मासिक तक वेतन मिला करता था। चौकीदार हैड सम्बरदार के अधीन होते थे जो स्वयं सरकार के प्रति जिम्मेदार होता था।<sup>४५</sup>

### जागीर पुलिस

जागीर के ग्रामों में जागीरदार हैड सम्बरदार के रूप में उत्तरदायित्व वहन करता था। सभी जागीर और खालसा ग्रामों के माफीदारों से शुल्क वसूल किया जाता था जिसे गाँव के सर्वे के मद में जमा कराया जाता था या हैड सम्बरदार को चुकाया जाता था। यह शुल्क जीत के राजस्व रहित होने पर उसके कराधान का १.१४ प्रतिशत होता था तथा इसके साथ ३.२ प्रतिशत राशि माफीदारों और जागीरदारों से सड़कों, पाठशालाओं और ढाक शुल्क के रूप में ली जाती थी। माफीदारों पर यह शुल्क कराधान की राशि का पाँच प्रतिशत हुआ करती थी।<sup>४६</sup> इस्तमरारदारियों की पुलिस-व्यवस्था आरम्भ से ही इस्तमरारदारों के अधीन थी। परन्तु सन् १८७३ में सरकार ने इस्तमरारदारियों की सम्पूर्ण पुलिस-व्यवस्था का उत्तरदायित्व उनके हाथों सौंप दिया था और सरकारी पुलिस का वहाँ कोई काम नहीं रह गया था। इस्तमरारदारी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम बलाई को चौकीदारी एवं निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया तथा जब कभी उसके क्षेत्र में किसी तरह के अपराध की घटना घटती तो उसे निकटवर्ती पुलिस थाने को इसकी सूचना देनी होती थी।

### चौकीदारी व्यवस्था में परिवर्तन

सन् १८८८ में चौकीदारी-व्यवस्था में नये नियमों के अन्तर्गत कतिपय परिवर्तन लागू किए गए।<sup>४७</sup> जिला दण्डनायक अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक गाँव

में चौकीदारों की आवश्यक संख्या निर्धारित करता था परन्तु सामान्यतः निम्न स्तर अपनाया जाता था :—

- (क) सौ से लेकर डेढ़ सौ घरों तक एक चौकीदार ।
- (ख) जहाँ १५० घरों से अधिक की बस्ती होती वहाँ प्रति डेढ़ सौ घरों पर एक चौकीदार ।
- (ग) सामान्य रूप से सौ से कम घरों वाले गाँव के लिए चौकीदार की व्यवस्था नहीं की जाती थी, परन्तु जिला-दण्डनायक उक्त गाँव की स्थिति और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक चौकीदार नियुक्त कर सकता था ।<sup>४८</sup>

नये नियमों के अन्तर्गत गाँवों के समूहीकरण की व्यवस्था लागू की गई थी । वहाँ कहीं भी गाँवों में चौकीदार की नियुक्ति के लिए आवश्यक घरों की कमी होती तो ऐसे गाँवों को मिलाकर हल्का स्थापित कर दिया जाता था । यह हल्का एक चौकीदार के जिम्मे रहता था । एक चौकीदार के जिम्मे दो या तीन या इससे भी अधिक गाँव निगरानी के लिए रहते थे । अधिकतर ये गाँव एक दूसरे से सटे हुए होते थे ।<sup>४९</sup> जिस किसी ग्राम में चौकीदारों की संख्या पाँच या पाँच से अधिक होती थी वहाँ उनमें से एक चौकीदार को मुखिया बनाया जाता था, वह जमादार कहलाता था । जमादार को छोड़कर प्रत्येक चौकीदार को सात तौली पगड़ी, एक पट्टा और चाकी रंग का कोट पहनना होता था और उसे भाला रखना पड़ता था । जमादार की वर्दी नीली पगड़ी और चाकी कोट होता था जिसकी बाईं भास्तीन पर लाल पट्टी लगी रहती थी ।<sup>५०</sup>

प्रत्येक गाँव के चौकीदार के लिए उसके गाँव के लिए नियुक्त पुलिस थाने के अधिकारी को अपराध घटने पर अधिलम्ब सूचना देना अनिवार्य था । यह नियम था कि ग्राम-चौकीदार का वेतन चार रुपए मासिक से कम व जमादार का मासिक वेतन सात रुपए से कम नहीं होना चाहिए । वेतन का निर्धारण जिला दंड-नायकों द्वारा किया जाता था और उसका भुगतान नगदी में होता था । ग्राम-चौकीदारों का वेतन और उनकी वर्दी इत्यादि का व्यय चौकीदार शुल्क में से चुकाया जाता था तथा यह शुल्क उक्त ग्राम या ग्रामों से वार्षिक कर के रूप में वसूल किया जाता था । प्रत्येक ग्रामों से कितना वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाएगा इसका निर्धारण जिला दंडनायक पर निर्भर रहता था ।<sup>५१</sup>

**इस्तमरारदारों के पुलिस-अधिकार**

सन् १८२६ में इस्तमरारदारों को न्यायिक और पुलिस-अधिकार प्रदान किए गए थे । इस्तमरारदार अपने ठिकाने या हल्के के अन्तर्गत अपराधों की जाँच करते

तथा इनके हल्को के सीमाक्षेत्र का निर्धारण समय-समय पर चीफ कमिश्नर किया करता था। इस क्षेत्र के ग्राम चौकीदार अपने यहाँ घटित अपराधों की सूचना पुलिस अधिकारी को न भेजकर इन हल्को व ठिकानों के इस्तमरारदारों को देते थे और इस्तमरारदार थानेदार या ग्रन्थ निकट के थाने के सरकारी पुलिस अधिकारी को मामला जाँच के लिए सौंप देता था। उक्त अधिकारी इस आदेश की पालना करने के लिए बाध्य होता था तथा इस्तमरारदार को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करता था जिस पर वह उसी तरह के निर्देश व आदेश पारित किया करता था जो आदेश या निर्देश ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक पारित करने से सक्षम होता था।

पुलिस द्वारा अभियोग तैयार कर लेने पर कार्यवाही की स्थिति में उसे इस्तमरारदार के पास भेजा जाता था। यदि उक्त मामला उसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर का होता तो अभियोग और पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की सुनवाई करके अपराध में दंडनीय प्रतीत होने पर वह अभियुक्त को अभियोग की कार्यवाही और साक्ष्यों सहित जिला-दंडनायक अथवा निकटवर्ती सक्षम दंडनायक को सौंप देता था। यदि इस्तमरारदार को यह प्रतीत होना कि मामले में साक्ष्य पर्याप्त नहीं होने से सदेह की गुंजाइश है तथा दंडनायक को मामला प्रेषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को जमानत पर या व्यक्तिगत मुचलके के आधार पर, अभियुक्त गयासमम आवश्यकता होने पर न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा, रिहा कर देता था। किसी गंभीर अपराध के घटित होने पर, हत्या अथवा हिंसक दंगों की स्थिति में इस्तमरारदार को स्वयं घटनास्थल पर पहुँचकर जाँच करनी होती थी।

सन् १८८८ में नई चौकीदारी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अनुसार सम्पूर्ण अजमेर-मेरवाड़ा में बेलन भोगी चौकीदारों की संख्या निम्न प्रकार थी।<sup>२२</sup>

		जमादार	चौकीदार
अजमेर	खालसा, जागीर व		
	इस्तमरारदारी	१	१५०
मेरवाड़ा	खालसा	१०	२६

#### मेरवाड़ा-बटालियन की पुलिस-सेवाएं

सन् १८६१ तक, जिले की सामान्य शांति-व्यवस्था स्थानीय सेना के हाथों में थी। यह सेना मेरवाड़ा-बटालियन कहलाती थी और इसका मुख्य कार्यालय ब्यावर में था।

मेरवाड़ा-बटालियन द्वारा सन् १८५७ के सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शित करने के कारण अंग्रेजों ने उसी वर्ष एक और मेर रेजीमेन्ट की स्थापना की थी जिसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था। प्राथिक कटौती के कारण



सन् १८६१ में इसमें छोटनी कर इसे पुरानी मेर-बटालियन में विलय कर दिया गया था। मेरवाड़ा सैनिक बटालियन की वजह से अब इसका नाम मेरवाड़ा पुलिस बटालियन रखा गया था। इसे उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार के इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन रखवा दिया गया।<sup>२३</sup>

### नागरिक सेवाओं का गठन

मेर रेजीमेंट और मेरवाड़ा-बटालियन के विलीनीकरण से सेवामुक्त हुए ५४८ व्यक्तियों से एक अर्सेनिक पुलिस संगठन का गठन कर उसे १ जनवरी, १८६२ से पुलिस अधीक्षक के अधीन रख दिया गया था। १ जनवरी, १८६२ से उत्तर-पश्चिमी सूबों में लागू पुलिस एक्ट अजमेर-मेरवाड़ा में भी लागू कर दिया गया था।<sup>२४</sup> सन् १८५३ से लेकर सन् १८७० तक नागरिक पुलिस की अपराधों की जांच-पड़ताल, रोकथाम और अभियोग चलाने की जिम्मेदारी थी। सेना का कार्य सरकारी कोषागारों, तहसील और जेल की सुरक्षा था।

मेरवाड़ा-बटालियन, कमांडर, सहायक कमांडर और ऐजुटेंट (सहायक) नामक तीन सैनिक अधिकारियों के अधीन थी। सन् १८६२ से लेकर सन् १८६६ तक कमांडर का नागरिक पुलिस सम्बन्धी कोई उत्तरदायित्व नहीं था। उप कमांडर (कमांडर इन सैंकंड) पदेन पुलिस अधीक्षक होता था और ऐजुटेंट उपअधीक्षक पुलिस के पद पर काम करता था। यह व्यवस्था उत्तमन भरी तिद्ध हुई क्योंकि दो छोटी थोड़ी के अधिकारियों को दो पृथक् अफसरों के अधीन काम करना पड़ता था। सन् १८६६ में मैनीवाल पुलिस घायलों के मुभावों पर बटालियन का कमांडर पद और जिला पुलिस अधीक्षक का पद समाहित करके एक ही अधिकारी के अन्तर्गत रख दिया गया था और उसकी सहायता के लिए दो सहायक नियुक्त किए गए थे इन में से एक को अधीन मेरवाड़ा तथा दूसरे के अधीन अजमेर-क्षेत्र था।<sup>२५</sup>

सन् १८६६ में स्वीडन नुल सैनिक पुलिस संस्था निम्नलिखित थी—<sup>२६</sup>

मानेदार (सब इंसपेक्टर)	हैड क्वार्टेयर	मुहसवार	तिपाही
१५	७६	३६	३८८

उपरोक्त नवीन व्यवस्था जो अत्यन्त अनुविधानिक तिद्ध हुई थी। कमांडर अपनी रेजीमेंट के साथ ब्यावर में रहता था। इण्टी कमिस्तर, जिसके साथ कमांडर को नागरिक प्रशासन सम्बन्धी मामलों के कारणों से नियत सम्पर्क में रहना होता था, वह बांभीग बीच दूर अजमेर में रहता था और इस तरह वह मुख्य पुलिस अधिकारी के साथ गोप्य सम्पर्क में बचि रह जाता था। प्रथम पुलिस सहायक अजमेर में इण्टी कमिस्तर के साथ रहते थे और कमांडर को अनुपस्थिति में जाने का पुलिस प्रशासन सम्भालते थे। यद्यपि मुख्य यह उत्तरदायित्व कमांडर का होता था। उक्त अधिकारी को साथ के सभी सामान्य मामले जो थोछ कमिस्तर से विचार-विमर्श के लिए

निर्धारित होते थे, अनुमति के लिए ब्यावर भेजने पड़ते थे । इससे बहुधा विलम्ब हो जाया करता था । इसके प्रतिरिक्त मेरवाड़ा क्षेत्र के लिए एक पृथक् पुलिस अधिकारी नियुक्त था और उस क्षेत्र के लिए डिप्टी कमिश्नर से विचार-विमर्श के लिए कोई अधिकारी अजमेर में नियुक्त नहीं था । अतएव जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग को कुशलता से नियंत्रित नहीं कर पाते थे । इस व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि कमांडर का ध्यान सैनिक एवं प्रसैनिक उत्तरदायित्व में बँटा रहता था और उसे बहुधा अपनी नागरिक सेवाओं के सदर्भ में ब्यावर से बाहर रहना पड़ता था । ऐसी स्थिति में सेना केवल एक ही अग्रज अधिकारी के उत्तरदायित्व में रह जाती थी । मेर कोर की विशिष्ट संरचना और मेरों के स्वभाव को देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक था कि मेर कोर की कार्य-कुशलता एवं अनुशासन तथा सद्भावना के हित में कमांडर का अपनी कोर (corps) से अलग रहना कहीं तक उचित है ? मेर कोर (corps) के कमांडर की सैनिक सेवाओं और प्रसैनिक सेवाओं में भारी विरोधाभास भी था तथा इन दोनों विभागों को एक ही पद के अन्तर्गत रखने का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता था । मेर कोर के गाँव सभी नागरिक सेवा का उत्तरदायित्व वहन करते थे परन्तु नागरिक पुलिस किसी भी रूप में मेर कोर (corps) के कार्यों से सम्बन्धित नहीं थी ।<sup>५७</sup>

अतएव इन तीन अधिकारियों में से दो अधिकारी कमांडर और ऐजुटेंट को स्थाई-रूप से मेर कोर (corps) से ही सम्बन्धित रखा गया और तृतीय अधिकारी को अजमेर और ब्यावर के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर ६०० रुपए मासिक वेतन पर सन् १८७० में नियुक्त किया गया था । इस व्यवस्था के फलस्वरूप व्यवस्था संबंधी बाधाएं समाप्त हो गई थी । इसके परिणामस्वरूप नागरिक पुलिस डिप्टी कमिश्नर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के सीधे नियंत्रण में आ गई जिससे सम्बन्धित मामलों में यथासमय व्यक्तिगत विचार-विमर्श द्वारा निर्णय लेने की सुविधा संभव हो गई थी ।<sup>५८</sup>

सन् १८७० में मेरवाड़ा-बटालियन को पुनः पूर्ण सैनिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया था । सन् १८७१ में अजमेर पुलिस विभाग को भी उत्तर-पश्चिमी सूबा के इंसपेक्टर जनरल पुलिस के नियंत्रण में हटाकर अजमेर-मेरवाड़ा कमिश्नर के हाथों में सौंप दिया गया था ।<sup>५९</sup> एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरवाड़ा में नियुक्त किया गया और उसके तत्वावधान में पाँच घाने ब्यावर, जवाड़ा, जस्ताखेड़ा, टाडपड़ और देवर में स्थापित किए गए । इन घानों के अधीन अन्य कई चौकियाँ कायम की गई थी । प्रत्येक गाँव में नियुक्त चौकीदार को वेतन भी सीधा पुलिस विभाग से चुकाया जाता था ।

सन् १८७७ में जिला पुलिस सेवा की निम्नांकित स्थिति थी—१०

यूरोपीय अधिकारी    भारतीय इन्स्पेक्टर    घुड़सवार    सिपाही  
एस० धो० और    थानेदार, हेडकांस्टेबल  
इन्स्पेक्टर ।

३

६३

४०

४४६ कुल ५८२

इसी वर्ष पुलिस थानों को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था । प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और पुलिस चौकियां । अजमेर में ६ प्रथम श्रेणी के थाने और ६ द्वितीय श्रेणी के तथा ६ पुलिस चौकियां थीं । मेरवाड़ा में ३ प्रथम श्रेणी के, २ द्वितीय श्रेणी और १६ पुलिस चौकियां निम्न तरह से स्थापित की गई—२१

जिला	पुलिस थाने का नाम	पुलिस चौकी का नाम	विशेष
प्रथम श्रेणी			
अजमेर	अजमेर सिटी एक्सटेन्शन रेल्वे वर्कशॉप नसीराबाद भांगलियावास मिनाम गोयला केकड़ी	भराखना   दिल्ली दरवाजा, भागरा दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा धोस्वी दरवाजा सराय लोहागल भदार पहाड़िया दाता सरवा बादनवाड़ा शोखला	गहर लास उपनगर अजमेर
द्वितीय श्रेणी			
अजमेर	पीसावन मेगल धो नगर सावर मगूदा पुप्पर		नागोला हरमाड़ा देवली सधाना नांद —

प्रथम थेली

मेरवाड़ा	टाडगढ़ जस्ताछेड़ा भ्यावर	भरातान  रूपनगढ़, सैदड़ा भजमेरी दरवाजा भ्यावर शहर सूरजपोल, मेवाड़ी दरवाजा, चाग दरवाजा
----------	--------------------------------	---

द्वितीय थेली

खैर जवाजा	बाघाना बर
--------------	--------------

भजमेर-मेरवाड़ा के दहनायक के अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप पुलिस चौकियों में भी परिवर्तन आवश्यक हो गया था।<sup>१२</sup> इसलिए सन् १९०३ में निम्न पुलिस थानों और पुलिस चौकियों की स्थापना की गई—<sup>१३</sup>

जिला	पुलिस थाने का नाम	पुलिस चौकी का नाम	क्षेत्र
प्रथम थेली			
भजमेर	भजमेर नगरपालिका	मदार दरवाजा, धौस्तो दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा, भागरा दरवाजा, केसरगंज, सराय । मदारनाका, रेल्वे बर्कशॉप केसर बाग, भानासागर, बाँधी नदी ।	भजमेर शहर     देहात
	भजमेर इम्पीरियल मसीराबाद	सरायना, रेस कोर्स, रेल्वे स्टेशन सोहारवाडा दांता	नसीराबाद देहाती क्षेत्र
	गोयला	सिराना	
	केकड़ी	बोगरा	
	भिनाय	वादनवाड़ा	
	मंगलियावास	देवसी	

## द्वितीय ■ खेरी

पुष्कर	नांद
पीसागन	नागलाव
गेगल	हरमाड़ा
श्री नगर	सिधाना
मसूदा	
सरवाड़	देवसी

## प्रथम खेरी

मेरवाड़ा	ब्यावर	अजमेरी दरवाजा, सूरजपोल, मेमुनीदरवाजा ब्यावर शहर चागगेट सेनेबा चौकी रूपनगर
जस्ता खेड़ा		छावनी
टाङ्गगढ		बराखान
जवाजा		भीम
देवर		बाधाना

जस्ताखेड़ा पुलिस थाने के अन्तर्गत मई १९०३ में करियादेह की एक नई पुलिस चौकी स्थापित की गई थी।<sup>१४</sup> करियादेह और सराचना की पुलिस चौकियाँ सन् १९०६ में समाप्त कर दी गई थीं। इन मामूली परिवर्तनों के अतिरिक्त इस काल में अन्य कोई विशेष परिवर्तन पुलिस थानों और चौकियों में नहीं किया गया।<sup>१५</sup>

सन् १८७७ में अजमेर जिला पुलिस की संस्था निम्न थी:—<sup>१६</sup>

यूरोपीय अधिकारी	भारतीय इन्स्पेक्टर, थानेदार	मुख्तियार सिपाही	कुल
पुलिस अधीक्षक	और हेड कास्टेबल		
एवं इन्स्पेक्टर।			

३

६३

४०

४४६

५८२

सन् १८८३ के उत्तरार्द्ध में नगरपालिका पुलिस और छावनी पुलिस का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १८३३ के बाद शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नगरपालिका अपनी सीमाओं में चौकरी एवं गश्त तथा सामान्य अपराधों की रोकथाम के लिए अपना घसत पुलिस बटोरेस्त करने लगी। अजमेर नगरपालिका की स्थापना सन् १८३३ में हुई थी। इसके पूर्व जब भारी वर्षा के कारण शहर पनाह की दिवारों कई जगहों पर गिरने लगी और मरम्मत अनिवार्य हो गई तो एक स्वायत्त कोष की स्थापना की

गई थी। यह रोजि शहर चौकसी एवं गश्त कार्यों पर भी खर्च की जाने लगी। सन् १८६७ में उक्त स्वायत्त कोष नगरपालिका कोष में परिवर्तित कर दिया गया।<sup>१७</sup> नगरपालिका में उन दिनों केवल पुलिस व्यवस्था के लिए स्वामन कोष से धन प्रदान करने के प्रतिरिक्त इस संबंध में और कोई जिम्मेदारी वहन नहीं करती थी। इसलिए सामान्य पुलिस विभाग पर हम प्रशासनिक कदम में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सन् १८८३ के पश्चात् नगरपालिका को इस आर्थिक भार से भी अपनी धाय को अन्य कार्यों पर व्यय करने-हेतु मुक्त कर दिया गया था। भ्रजमेर नगरपालिका नियम सन् १८९६ के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा जो पुलिस बंदोबस्त स्थापित किया गया था उसमें या तो चौकीदार नियुक्त किए गए थे अथवा सरकार के पुलिस कर्मचारियों की सेवा इस कार्य के लिए प्राप्त करली थी।<sup>१८</sup>

सन् १८८८ में पहली बार पुलिस सेवा परीक्षा आरम्भ की गई।<sup>१९</sup> परीक्षा समिति में निम्न पदाधिकारी सदस्य थे—

१—जिला पुलिस अधीक्षक	अध्यक्ष
२—एक डंड नायक	सदस्य
३—परीक्षा पारित इन्सपेक्टर	सदस्य

परीक्षार्थी को निम्नांकित तीन विषयों में परीक्षा देनी पड़ती थी—<sup>२०</sup>

- १—स्थानीय भाषा
- २—विभागीय जीव एवं
- ३—कवायद ।

परीक्षार्थी से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसे भारतीय डंड-संहिता, जास्ता फौजदारी कानून, अपरिवर्तित पुलिस सेवा-नियमों व आदेशों का ज्ञान विविध कानूनों, विदेशी-कानून, प्रत्यर्पण-कानून, चौकीदार-कानून, साक्षी-कानून, सन् १८८८ का छावनी-कानून, मवेशी-अपहरण या अवैध प्रवेश-कानून, जीवों पर क्रूरता नियमन-कानून, जंगलात-कानून, जुआ, निरोधक-कानून, अफीम-कानून, डाकघर-कानून और मक वू गो कानून की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।<sup>२१</sup>

यदि नियुक्ति के बाद दो वर्षों में कोई इन्सपेक्टर उक्त परीक्षा पारित करने में असफल रहता तो उसके पद में अवनति या उसे सेवा से अलग किया जा सकता था। थानेदारों, डंड कान्स्टेबलो, मुन्शी और कास्टेबलो के लिए पृथक् परीक्षाएं निर्धारित की गई थी। प्रत्येक जुलाई माह में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था। सभी थानेदारों, मुन्शी व डंड कास्टेबलो को उक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना उच्च पद पर नियुक्त या पदोन्नति नहीं की जाती थी।<sup>२२</sup>

सन् १९०३ में, जिला पुलिस-अधीक्षक के नियंत्रण में नियमित सभी श्रेणी के पुलिस कर्मचारियों की संख्या ६०४ थी। इसके अनुसार ३.८ वर्गमील क्षेत्र पर १ पुलिस कर्मचारी तथा प्रति ६७७ लोगों पर १ पुलिस कर्मचारी नियुक्त था। इस विभाग पर कुल व्यय-राशि ६,१५,८२० रुपये थी जो प्रति व्यक्ति पौने चार पाने पड़ती थी। सरकारी कोष से इस राशि में ८८,६६२ रुपये प्राप्त होते थे। शेष राशि तीनों नगरपालिकाओं, नसीराबाद धावनी तथा कुछ शराब के ठेकेदारों से प्राप्त होती थी।<sup>७३</sup>

१ भ्रजमेर, १९११ से भ्रजमेर और व्यावर नगरपालिकाओं तथा कुछ समय बाद केकड़ी नगरपालिका को भी पुलिस-सेवाओं के कार्य से मुक्त कर दिया गया था।<sup>७४</sup> सन् १९१० से स्थानीय पुलिस अधिकारियों की पुलिस सेवा-प्रशिक्षण के लिए भुरादाबाद भेजा जाने लगा।<sup>७५</sup>

उपरोक्त काल में पुलिस-प्रशासन को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। पुलिस सेवा में भरती में पूरी सावधानी नहीं बरती जा सकती थी क्योंकि स्थानीय कबायद का मैदान छोटा था तथा साथ ही एक बार किसी को मर्ती कर लेने पर उसे निकालना कठिन होता था। यद्यपि अन्य प्रदेशों में प्रसामाजिक एवं अपराधी तत्वों को जिले से निष्कासित करने एवं उनके गिरौह की रंग करने की व्यवस्था थी तथापि रियासतों से जुड़े हुए भ्रजमेर में यह कदम अव्यावहारिक था। फलस्वरूप चमन में अत्यन्त सावधानी बरतना अत्यन्त आवश्यक था। भरती किए गए व्यक्तियों में सामान्य ज्ञान का स्तर निम्न पाया जाता था।<sup>७६</sup> कभी-कभी तो सजा पाए व्यक्ति अथवा चालीस साल की उम्र से भी अविच्छिन्न बन्धु के लोग भरती कर लिए जाते थे।<sup>७७</sup>

भ्रजमेर पुलिस सेवा में दूसरे प्रदेशों के लोगों की संख्या अधिक थी। अधिकतर कर्मचारी उत्तर-पश्चिमी सूबा और प्रबंध हैं। स्थानीय लोगों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से मीलों को भरती के लिए प्रोत्साहित किया गया था क्योंकि ये लोग क्षेत्र की स्थिति से परिचित होने के कारण अच्छे सिपाही सिद्ध हुए थे। उन दिनों कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासन एवं व्यवहार को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता था। अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यों की अवहेलना के लिए दोषी कर्मचारियों का प्रतिशत पच्चीस के लगभग बना रहता था।<sup>७८</sup>

पुलिस सेवा की इस असन्तोषजनक स्थिति का मूल कारण स्थानीय लोगों में से उचित व्यक्तियों को स्थान न मिलना था। इन कमी की पूर्ति दूसरे प्रदेशों की पुलिस सेवा कर्मचारियों से तथा मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी सूबा पुलिस विभाग से की जाती थी। इन कर्मचारियों पर स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक का प्रभाव नगण्य था।

उन दिनों पुलिस विभाग द्वारा गंभीर अपराधों की सफल जाँच-पड़ताल तथा अपराधियों को दंड का प्रतिशत अत्यन्त निम्न था। इस असफलता का प्रमुख कारण जिले की विशेष भौगोलिक स्थिति थी। अजमेर चारों ओर में रियामन्त्री से घिरा हुआ था, जहाँ बहुधा अपराधी भागकर शरण ले लेते थे [अजमेर के एक महत्वपूर्ण रेल केन्द्र बन जाने तथा देश के बड़े-बड़े शहरों से जुड़ जाने के कारण भी यहाँ बाहरी विरोधकर मुरादाबाद, घनीगढ़ और आगरा के कुख्यात अपराधी असांजिक तत्व अधिक संख्या में आकर्षित होने लगे थे। स्थानीय अपराध जाँच विभाग के अधिकांश अधिकारी अनुभवहीन एवं जाँच-पड़ताल की वैज्ञानिक एवं सुचारु पद्धति से अनभिज्ञ थे। अधिकांश मुकदमों में गंभीर अपराधों के अभियुक्त भी फौजदारी अदालत में जाँच के दौरान पर्याप्त प्रमाणों के अभाव तथा अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटियों के कारण सजा पाने से बच जाते थे क्योंकि कतिपय पुलिस अधिकारियों को कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। अधिकांश मुकदमों में जानेदार अदालतों कार्यवाही के दौरान पर्याप्त गवाहियाँ प्रस्तुत करने में अनकम रहते थे। अपराधों की जाँच-पड़ताल का कार्य अनुभवहीन व अप्रशिक्षित जानेदारों के हाथों में था।<sup>१७६</sup>

उन दिनों अजमेर-मेरवाड़ा में पुलिस सेवा लोकप्रिय नहीं थी। इसमें छुट्टी के कठिन नियम व कम वेतन होने के कारण लोगों को भरती होने में हिचकिचाहट रहती थी। पुलिस विभाग में सेवामुक्त होने में एक तरह से होड़ लगी रहनी थी, कभी-कभी तो इन त्यागपत्रों की संख्या एक साल में सौ तक पहुँच जाती थी।<sup>१७७</sup> इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि अधिकांश रंगरूट अकाल एवं सूखे की स्थिति टालने के लिए पुलिस में भरती हो जाते थे और ज्योंही वह स्थिति टल जाती, वर्षा होते ही अविलम्ब त्यागपत्र देकर भाग छूटते थे। गर्मी अथवा अकाल के दिनों में लोगों का पुलिस सेवा में प्रति प्रत्याई आकर्षण हो जाता था और वे परिस्थितियोंबश ही यह सेवा अंगीकार करते थे। इसके प्रति उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं थी। अजमेर जिले के स्थानीय लोगों में से दो भारतीय रेजीमेन्टों में भी भरती हुआ करती थी। इन रेजीमेन्टों के वेतनमान पुलिस सेवा की अपेक्षा अधिक आकर्षक थे। एक नये रंगरूट को फौज में भरती होने पर एक सामान्य कांस्टेबल के वेतन से अस्सी प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ करता था। जबकि पुलिस के कर्मचारियों को अपने वेतन में से ही वर्दी तथा अन्य साज-सामान की कीमत भी चुकानी पड़ती थी। इस तरह शेष बची राशि में एक विवाहित दंपति का जीवनयापन तो अत्यन्त कठिन अवश्य कहा जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस सेवा के सभी कर्मचारियों में ऋण सक्तामक रूप से व्याप्त था।

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व न्याय-व्यवस्था

अजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व नियमित व्यवस्था नहीं थी। विवादों के फैसले बहुधा तत्कालीन से ही हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी या अपने



सगे-सम्बन्धियों की शक्ति पर आश्रित रहता था। अधिकतर अपराध एक जाति के लोगों द्वारा दूसरी जाति की महिलाओं का अपहरण भयवा विवाह-विच्छेद के होते थे।<sup>५१</sup> बहुधा इन भगड़ी का निर्णय भ्रमविश्वास भरी प्रतियाधी के द्वारा किया जाता था। एक प्रचलित तरीका तो यह था कि मन्दिर या पवित्र स्थान पर विवादास्पद संपत्ति को रखकर उसे उठाने के लिए चुनौती दी जाती थी और यह माना जाता था कि इस तरह भनाधिकृत व्यक्ति को एक धार्मिक स्थान से उस वस्तु को उठाने की हिम्मत नहीं होगी या उस पर परमात्मा का कोप होगा। कई बार विवाद का हल सौगन्ध उठाकर करवाया जाता था। यह विश्वास किया जाता था कि यदि निश्चित भवधि में सौगन्धकर्ता की स्वयं की भयवा उसके परिवार में से किसी की मृत्यु होगी भयवा उसके भवशी या सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी, तो यह माना जाएगा कि उसके द्वारा उठाई गई सौगन्ध असत्य थी और यह व्यक्ति अपराधी मान लिया जाता था। उन दिनों इसी तरह की भ्रमविश्वास भरी प्रथाएं न्याय के नाम पर प्रचलित थी।

महिलाओं के अपहरण, विवाह-समझौते के भंग करने, ज़मीन के मुकदमे, श्रद्धाओं के मुकदमे तथा सोमा-विवाद सम्बन्धी मामलों में या उन सभी मामलों में जिसमें किसी पक्ष को क्षति भयवा चोट पहुंचवाई गई हो, आदि मामलों में पंचायतों का भी उपयोग किया जाता था। असामान्य बड़े अपराधों के प्रतिरिक्त पचायत ही लोगों में न्याय-प्रशासन का एकमात्र साधन थी।

भारम्भ में मेरवाड़ा के सुपरिंटेंडेंट केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करते थे। दीवानी और फौजदारी मामलों में पंचायतें ही निर्णायक थी।<sup>५२</sup> उन दिनों अजमेर स्थित सुपरिंटेंडेंट जोधपुर, जैसलमेर और किशनगढ़ रियासतों के लिए पोलिटिकल एजेंट भी थे। इसलिए स्थानीय फौजदारी मामले उनके एक सहायक के अधीन थे एवं दीवानी मामलों को सदर अमीन तथा असाधारण गंभीर मामले सुपरिंटेंडेंट स्वयं सुनते थे।

सन् १८४२ में डिक्कन की अजमेर और मेरवाड़ा का सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया था। सन् १८५०-५१ में कर्नल डिक्कन को दीवानी और फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए थे और उनकी सहायता के लिए दो सहायक (एक अजमेर में तथा दूसरा मेरवाड़ा में) नियुक्त किए गए थे। इन दो अधिकारियों के प्रतिरिक्त अजमेर में दो सदर अमीन भी नियुक्त थे जो दीवानी और फौजदारी काम देखा करते थे।<sup>५३</sup>

सन् १८४६-४७ से दीवानी मुकदमों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू की गई थी <sup>५४</sup>

क्रम	न्यायालयों का	दीवानी न्यायाधीश	माने अधीन
	पद	का राशि संबंधी	

अधिकार अधिक से अधिक

१.	पंडित अदालत	१ से ५० तक	कनिष्ठ सदर अमीन
२.	कनिष्ठ सदर अमीन	५० से ६०० तक	वरिष्ठ सदर अमीन
३.	वरिष्ठ सदर अमीन	६०० से ४००० तक	सुपरिटेण्डेंट
४.	सहायक सुपरिटेण्डेंट	४००० से अधिक	सुपरिटेण्डेंट
५.	सुपरिटेण्डेंट	केवल अपीलों से सम्बंधित	

उन दिनों सुपरिटेण्डेंट ने नियमित बादों की सुनवाई करना स्थगित कर दिया था अतएव बहुत ही कम अपीलों की जाने लगी थीं।<sup>८५</sup>

कमिशनर सुपरिटेण्डेंट और सदर अमीन के दायित्व :—

दीवानी मुकदमों में सुपरिटेण्डेंट की कचहरी से फैसले की अपील कमिशनर को की जाती थी। हत्या के मामलों में जहाँ सुपरिटेण्डेंट को आदेश जारी करने की शक्ति नहीं था, कमिशनर आदेश जारी करता था। विशेष मामलों में सुपरिटेण्डेंट कार्यालय की अपील कमिशनर को प्रस्तुत होती थी।<sup>८६</sup>

उन दिनों सुपरिटेण्डेंट के अधिकार भी कम नहीं थे। वह दोनों जिलों के दीवानी, फौजदारी, राजस्व तथा खूंगी आदि प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था।<sup>८७</sup> वह अपने अधीनस्थ सभी अदालतों को आवश्यक आदेश जारी कर सकता था। दीवानी मामलों में वह अपने सहायक सुपरिटेण्डेंट और सदर अमीन की कचहरियों के फैसलों की अपील सुना करता था। उसे राजस्व में ऋण प्रदान करने तथा राजस्व-भुगतान स्थगित करने के भी अधिकार थे। खूंगी वसूली के सामान्य कार्यों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था।

वरिष्ठ सदर अमीन छः सौ रुपए से लेकर चार हजार की राशि तक के दीवानी मुकदमों का निर्णय करता था। फौजदारी मुकदमों तथा पुरानी प्रथा के अनुसार संपत्ति पर लिए गए बलात् कब्रों के मुकदमों की भी सुनवाई करता था। कनिष्ठ सदर अमीन के फैसले के विरुद्ध दायर की गई अपील की सुनवाई करने का उसे अधिकार प्राप्त था।<sup>८८</sup> कनिष्ठ सदर अमीन को ६०० रुपयों की राशि तक के दीवानी मामले निर्णय करने व पंडित अदालत के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था। उसका काम अजमेर शहर और बाहर की इमारतों की देखभाल का भी था। वह सभी काम सहायक अधीक्षक के निर्देशन में करता था और आवश्यक होने पर सहायक अधीक्षक या सुपरिटेण्डेंट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था।<sup>८९</sup> पंडित अदालत केवल ५० रुपयों की राशि तक के ही मामले सुना करती थी। इसका कार्य-क्षेत्र अजमेर शहर तक ही सीमित था।<sup>९०</sup>

मेरवाड़ा में सन् १८५६ के एक्ट ८ के लागू होने तक सभी दीवानी मामले पचासवें निपटाती थी।<sup>९१</sup> सन् १८१८ से सन् १८४३ तक अजमेर में यह

प्रथा प्रचलित थी कि स्थानीय लोगों और महाजनों अथवा अन्य लोगों के बीच सभी राशिगत लेन-देन के प्रपत्रों पर सुपरिटेण्डेंट के हस्ताक्षरों का होना अनिवार्य था। लेनदार को स्वयं उसके वकील या वकील के संबंधित अधिकार के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रपत्र की लिखापट्टी सत्य होने की तस्दीक करनी होती थी। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था कि लेनदार अपनी मारी संपत्ति या उसका कोई भाग बंधक रख रहा है। केवल यही पर्याप्त समझा जाता था कि संबंधित पक्ष ने पक्ष की लिखापट्टी को मौखिक तौर से सही स्वीकार कर लिया है। यदि लेनदार स्वयं प्रस्तुत होकर एक लिखित प्रपत्र प्रस्तुत कर इकरारनामों की स्वीकृति की प्रार्थना करता तो कार्यवाही में विलम्ब नहीं होता था। एक सप्ताह कागज़ पर इस मासूम का प्रार्थना-पत्र ही पर्याप्त समझा जाता था तथा यह मान लिया जाता था कि सभी कानूनी खर्च चुकाकर दीवानी अदालत की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। इस तरह की प्रक्रिया के फलस्वरूप अजमेर की जनता का एक बड़ा भाग सूदखोरों के चंगुल में फँस गया था। यदि कोई इस्तमरारदार सरकारी लगान चुकाने में असमर्थ होता तो वह किसी साहूकार को उस राशि के बदले कुछ भाग निश्चित वर्षों के लिए हथाले कर देता था। कर्नल डिवसन ने स्वयं इस प्रथा के दोषों एवं अदृष्टप्रसूता की स्थिति का चित्रण किया है। उसने इसे समाप्त करने का सबसे पहले प्रयत्न किया था।

इसके स्थान पर नियामक प्रांतों में भिविल प्रोसीजर कोड के लागू होने के पहले जो व्यवस्था थी, वह प्रारम्भ की गई। न्यायालय में दाव प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को स्वयं अथवा वकील के माध्यम से पन्द्रह दिन में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया जाता था। यदि वह उक्त अवधि में उपस्थित नहीं होता तो दावे का फैसला एक तरफ कर दिया जाता था।<sup>१२</sup> यदि प्रतिवादी अपना जवाब दावा तथा अन्य औपचारिकताएँ पन्द्रह दिन की अवधि में पूरी कर देता तब मुद्दे निर्धारित किए जाते थे और वादी को अपने सबूत और साक्षी प्रस्तुत करने के लिए ६ सप्ताह का अवसर दिया जाता था। इस तरह मामले की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व तीन माह का समय निरर्थक व्यतीत हो जाता था। इसके पश्चात् भी भूम मुद्दों के निर्धारण में भी अनावश्यक विलंब होता था।<sup>१३</sup>

#### भ्यादिक विकास (१८४८-१८७१)

सन् १८४८ तक ए. जी. जी. का आवास अजमेर में ही था और जिला कमिश्नर तथा सुपरिटेण्डेंट उनके अन्तर्गत काम करते थे। तबतक यह जिला गैर-नियामक था। साल में केवल एक बार राजस्व का मास-व्यय प्रस्तुत होता था। यहाँ न तो कानून ही लागू थे और न सदर न्यायालय का यहाँ अधिकार-क्षेत्र ही था।<sup>१४</sup> कर्नल सदरसेंट के नियम के पश्चात् जब कर्नल सो ने पदग्रहण किया तब ए. जी. जी. से अधिकांश अदालतों सम्बन्धी कार्य सुपरिटेण्डेंट को हस्तांतरित किया

गया था ।<sup>१४</sup> सन् १८५३ में ए. जी. जी. को अजमेर-मेरवाड़ा के नागरिक प्रशासन के भार से मुक्त कर दिया गया था ।<sup>१५</sup> उस समय ३ न्यायिक अपीलों ए. जी. जी. राजपूताना के बजाय सदर दीवानी अदालत, आगरा को होने लगी थी ।<sup>१७</sup>

सन् १८६२ में पुलिस एवं न्याय विभागों का पृथक्करण कर दिया गया था ।<sup>१८</sup> फौजदारी अदालतें उच्च न्यायालय के अधीन रग्यी गई थीं । उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा जो कानून लागू थे वे धीरे-धीरे अजमेर-मेरवाड़ा में लागू किए गए थे । इस तरह कुछ वर्षों में अजमेर-मेरवाड़ा गैर न्यायाधिक जिले से नियामक जिले में परिवर्तित हो गया था ।<sup>१९</sup>

निम्न आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जिले में मुकदमों की निरन्तर अभिवृद्धि होती रही.—<sup>१००</sup>

#### अज्ञ न्यायालय में बाद की संख्या ।

१८६४	१५
१८६५	००
१८६६	१८
१८६७	५
१८६८	८

#### फौजदारी अपीलों की संख्या

१८६४	२४
१८६५	७१
१८६६	६७
१८६७	६०
१८६८	—

#### दीवानी अपीलों और बादों की संख्या

१८६४	३८
१८६५	६०
१८६६	६८
१८६७	६४

#### भुटिपूर्णा व्यवस्था

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अजमेर में न्याय-व्यवस्था का जो विकास हुआ उसमें अभी भी कई भुटिया थी । एजेंट का कार्यालय ६ माह के लिए भाबू में रहता था । उसे अजमेर के राजस्व आयुक्त, अज्ञ न्यायाधीश व सदर दीवानी अदालत के न्यायाधीश के रूप में काम करने के अतिरिक्त कतिपय विविध एवं सामान्य प्रशासनिक मामलों में उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सन्तर्गत भी कार्य

करना पड़ता था ।<sup>१०१</sup> इस तरह ए. जी. जी. पर प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का बहुत भार था । ए. जी. जी. अजमेर में एक वर्ष में एक बार सत्र न्यायालय की बैठक कर पाते थे अतएव अभियुक्तों को पूरे साल भर हवालात में रखा जाता था ।<sup>१०२</sup> कार्याधिकार के कारण एजेंट का राजनीतिक कार्य भी अत्यधिक शिथिल हो गया था । वह पड़ोसी रियासतों के यथा समय दोरे तक करवाने में असमर्थ थे । स्थिति यह हो गई थी कि कर्नल कीटिंग को १६ अप्रैल, १८६८ के पत्र में स्पष्ट कहना पड़ा था कि कोई भी व्यक्ति जिसे ए. जी. जी. का कार्यभार भी बहन करना पड़ता हो, अजमेर जिले का विकास करने की स्थिति में नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रशासन का पुनर्गठन अनिवार्य हो गया था ।<sup>१०३</sup>

**न्यायपालिका का पुनर्गठन (सन् १८७२):—**

इस जिले में १ फरवरी से अजमेर न्यायालय नियमन कानून १८७२ में लागू हुआ । न्यायालयों को घाठ श्रेणियों में पुनर्गठित किया गया—<sup>१०४</sup>

१—तहसीलदार की कचहरी ।

२—सहायक कमिश्नर का न्यायालय (साधारण अधिकार) ।

३—सहायक कमिश्नर-न्यायालय (पूर्ण अधिकार) ।

४—छावनी दंडनायक-अदालत ।

५—न्यायिक सहायक कमिश्नर-अदालत ।

६—डिप्टी कमिश्नर-कचहरी ।

७—कमिश्नर-न्यायालय ।

८—चीफ कमिश्नर-न्यायालय ।

सन् १८७२ से चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, न्यायिक सहायक कमिश्नर, छावनी दंडनायक, सहायक कमिश्नर एवं अतिरिक्त सहायक कमिश्नरों की नियुक्तियाँ गवर्नर जनरल की कोसिस द्वारा की जाती थी <sup>१०५</sup> तथा तहसीलदारों की नियुक्ति का अधिकार चीफ कमिश्नर को था ।<sup>१०६</sup>

### अधिकार-क्षेत्र

चीफ कमिश्नर गवर्नर जनरल की आज्ञा में किसी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं का निर्धारण एवं परिवर्तन कर सकता था ।<sup>१०७</sup> अजमेर के विभिन्न न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र इस प्रकार थे—<sup>१०८</sup>

**कार्यालय-नाम**

**फौजदारी अधिकार-क्षेत्र**

**सौदानी अधिकार-क्षेत्र**

१—तहसीलदार

चीफ कमिश्नर द्वारा

सौदानी अदालत के

जाग्रा फौजदारी कानून के

अधिकार, दिनमें बाद

तद्दत समय-समय पर प्रदान

की राशि से रुपए से

किए गए अधिकार ।

अधिक मूल्य की नहीं हो ।

२—प्रसिस्टेंट कमिशनर  
(सामान्य अधिकार)

" "

दीवानी अदालत के अधिकार जहाँ बाद की राशि पाँच सौ रुपए के मूल्य से अधिक की नहीं हो ।

३—प्रसिस्टेंट कमिशनर  
(सम्पूर्ण अधिकार)

" "

सबुबाद न्यायालय के अधिकार जहाँ बाद की सबुबाद न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के हो और बाद की राशि १ हजार से अधिक नहीं हो ।

४—छावनी दंडनायक-  
अदालत

" "

सबुबाद न्यायालय के अधिकार जहाँ बाद सबुबाद न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का हो और बाद की राशि १ हजार से अधिक नहीं हो ।

५—न्यायिक सहायक  
कमिशनर

दंडनायक के सम्पूर्ण अधिकार

सबुबाद न्यायालय के सवाम अधिकार जहाँ बाद मूल्य १००० रुपयों से अधिक न हो ।

६—डिप्टी कमिशनर

दंडनायक के सम्पूर्ण अधिकार तथा जाय्ना फौजदारी के ४४५ ए के अन्तर्गत निहित अधिकार ।

दीवानी न्यायालय के किसी भी राशि तक के अधिकार ।

अधीनस्थ दंडनायकी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार

उपरोक्त ५ थेली के न्यायालयों में से किसी भी बाद, अपील या जारी कार्यवाही के स्थानांतरण करने का अधिकार ।

इन्हें वह स्वयं सुन सकते थे।  
ये भयवा भग्न सक्षम  
न्यायालय को बाद की  
राशि के आधार पर  
हस्तांतरित कर सकते थे।

#### ७—कमिशनर

सत्र न्यायाधीश के  
अधिकार सम्पूर्ण  
अधिकारयुक्त दंडनायक  
के न्यायालय तथा डिप्टी-  
कमिशनर के निर्णयों के  
विरुद्ध अपील सुनने के  
अधिकार।

जिला न्यायालय के  
अधिकार, तृतीय, चतुर्थ,  
पंचम और षष्ठ श्रेणी के  
न्यायालयों के फैसले के  
विरुद्ध अपील सुनने का  
अधिकार।

#### ८—चीफ कमिशनर सदर न्यायालय के अधिकार।

“ ”

सभी बावों में जहाँ  
नियमों के अन्तर्गत  
कमिशनर के निर्णय के  
विरुद्ध अपील की सुनवाई  
के अधिकार।

अपील सम्बन्धी उच्चतर  
न्यायालय के अधिकार।

#### चीफ कमिशनर

प्रथम ५ श्रेणी के न्यायालयों पर कमिशनर का सामान्य नियन्त्रण था।<sup>१०८</sup>  
चीफ कमिशनर गवर्नर जनरल की स्वीकृति से प्रथम चार न्यायालयों में से किसी भी  
न्यायालय में निहित अधिकार आनरेरी रूप में किसी एक व्यक्ति या तीन व तीन से  
अधिक व्यक्तियों को बीच के रूप में प्रदान करने का आदेश दे सकते थे।<sup>११०</sup> चीफ  
कमिशनर ग्रावर के सहायक कमिशनर को स्वायत्त सहायक कमिशनर के अधिकार  
प्रदान कर सकता था। वह किसी भी छावनी-दंडनायक के सहायक कमिशनर को भी  
विशेष अधिकार प्रदान कर सकता था।<sup>१११</sup> वह किसी भी नायब तहसीलदार को  
तहसीलदार के सम्पूर्ण भयवा भंगतः अधिकार प्रदान करने में सक्षम था। चीफ  
कमिशनर अतिरिक्त सहायक कमिशनर को सहायक कमिशनर के सम्पूर्ण भयवा भंगतः  
सामान्य भयवा पूर्ण अधिकार प्रदान कर सकता था।<sup>११२</sup> उसे मातहत अदालतों  
से बाद का प्रत्याहरण करने, स्वयं उसकी सुनवाई करने भयवा उसे भग्न सक्षम  
न्यायालय को सौंपने का भी अधिकार प्राप्त था।<sup>११३</sup>

## दीवानी न्याय-प्रक्रिया ११४

मजमेर न्यायालय-नियमन, १८७७ के अन्तर्गत इस क्षेत्र का दीवानी न्याय-प्रशासन में पुनः परिवर्तन किया गया था।<sup>११४</sup> इस क्षेत्र में सबसे छोटी मजदालत मुन्सिफ की थी। इसे सौ रुपए तक के वाद निर्णीत करने के अधिकार प्राप्त थे।<sup>११५</sup> मजमेर, ब्यावर व टाडगढ़ के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को यह अधिकार प्राप्त थे।<sup>११७</sup> मिनाय, पीसागन, सरवाड, सरवा, बादनवाड़ा और देवली के इस्तमरारदारों को भी उक्त अधिकार प्राप्त थे। मुन्सिफ कोर्ट से अपील उप न्यायाधीश (सब जज)<sup>११८</sup> प्रथम श्रेणी मुनता या जिसकी मातहत में मुन्सिफ होता था। सब जज से अपील कमिशनर जिला न्यायाधीश के रूप में सुनता था।<sup>११९</sup> चीफ कमिशनर की मजदालत में कमिशनर के यहाँ से अपीलें होती थीं।<sup>१२०</sup> पाँच सौ की राशि तक के दीवानी वाद सुनने के अधिकार छावनी दंडनायक देवली तथा अतिरिक्त सहायक कमिशनर मजमेर-मेरवाड़ा को प्राप्त थे।

निम्न अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के दीवानी न्यायाधीश के अधिकार प्राप्त थे जो दस हजार मूल्य राशि तक के सभी वाद सुन सकते थे—<sup>१२१</sup>

सहायक (असिस्टेंट) कमिशनर, मजमेर-मेरवाड़ा।

छावनी-दंडनायक, नसीराबाद।

न्यायिक सहायक कमिशनर, मजमेर।

अतिरिक्त सहायक कमिशनर, केकड़ी व मजमेर।

उप दंडनायक, ब्यावर।<sup>१२२</sup>

उपयुक्त अधिकारियों में से केवल न्यायिक सहायक कमिशनर मजमेर और अतिरिक्त सहायक कमिशनर मजमेर व मेरवाड़ा को अपीलें सुनने व निर्णय करने का अधिकार था।<sup>१२३</sup> इनके न्यायालयों से अपील सीधी कमिशनर की मजदालत में जो जिला न्यायाधीश भी थे, की जाती थी। कमिशनर के निर्णय की अपील चीफ-कमिशनर की मजदालत में की जाती थी जो कि जिले की उच्च न्यायालय थी।

पाँच सौ रुपए की राशि तक के लघुवाद न्यायालय के अधिकार सहायक कमिशनर, मेरवाड़ा, छावनी-दंडनायक, नसीराबाद, अतिरिक्त सहायक कमिशनर (द्वितीय श्रेणी) मजमेर और उपदंडनायक ब्यावर तथा २० रुपए की राशि तक के लघुवाद निर्णीत करने के अधिकार रजिस्ट्रार लघुवाद न्यायालय, मजमेर को प्राप्त थे।<sup>१२४</sup>

फौजदारी मुकदमों में कमिशनर के यहाँ से जो कि सेशन जज का कार्य भी करते थे अपील चीफ कमिशनर की मजदालत में होती थी जो कि जिले की हाईकोर्ट थी।<sup>१२५</sup> उसके अखीन मजमेर और मेरवाड़ा के असिस्टेंट कमिशनर थे जो अपने



क्षेत्रों के जिला दंडनायक भी थे। छावनी-दंडनायक, नसीराबाद, न्यायिक सहायक, प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर केकड़ी, उपदंडनायक ब्यावर और सहायक कमिश्नर डीडवाना को प्रथम श्रेणी दंडनायक के अधिकार प्राप्त थे। छावनी दंडनायक देवली, तहसीलदार अजमेर, ब्यावर और टाडगढ़ तथा घाँनरेरी दंडनायक अजमेर और ब्यावर को द्वितीय श्रेणी दंडनायक के अधिकार प्राप्त थे जिनके फौसलों की अपील जिला दंडनायक के यहाँ की जाती थी। नायब तहसीलदारों को तृतीय श्रेणी दंडनायक के अधिकार प्राप्त थे तथा इसी तरह के अधिकार घाँनरेरी दंडनायकों के रूप में भिनाय, बीसावन, सावर, खरवा बादनवाड़ा और देवली के इस्तमरारदारों को भी प्राप्त थे। सन् १८७७ में डिप्टी कमिश्नर का पद समाप्त करने पर दोनों सहायक कमिश्नर को भारतीय दंड-संहिता के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के सम्बन्ध में जिला दंडनायक के अधिकार प्रदान कर स्वतंत्र रूप से श्याम-विभाग के काम सौंपे गए थे।<sup>१२६</sup>

सन् १८७७ के पश्चात् विचाराधीन बादों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई थी।<sup>१२७</sup> सभी अधिकारियों पर न्यायिक कार्यों का बहुत भार था। उन पर अन्य नियमित प्रशासनिक कार्यों के भार के कारण प्रशासन में शिथिलता का आना स्वाभाविक ही था। इसीलिए निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी—

- (१) सन् १८८६ में प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर राजस्व
- (२) रजिस्ट्रार (सन् १८६०)

प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर 'राजस्व' केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों के लिए नियुक्त किया गया था और रजिस्ट्रार को बीस रुपये तक की राशि के लघुवाद निपटाने के अधिकार प्रदान किए गए थे।

इस व्यवस्था से लघुवाद मुकदमों को निपटाने में अधिक सहायता मिली जो निम्न भाँकड़ों से स्पष्ट है—<sup>१२८</sup>

#### लघुवाद श्यामालय के मुकदमों

वर्ष	मुकदमों की संख्या
सन् १८८३	६८६०
१८८६	७१७३
१८८७	६८४२
१८८८	६५३०
१८८९	४४७३

उक्त न्यायालयों के कार्यों में वृद्धि का एकमात्र कारण इनके कार्य-क्षेत्र को रेल मार्गों तक विस्तृत कर देना भी था। वह सभी क्षेत्र जो राजपूताना व पश्चिमी

राजपूताना रेल्वे के अन्तर्गत था और जिस पर पोलिटिकल एजेंट भलवर, रेजिडेंट जयपुर व पश्चिमी स्टेट एजेंसी का प्रशासन था, उस सभी क्षेत्र पर सन् १८८० में ब्रिस्टोर्लैंड और पर चीफ कमिश्नर ब्रजमेर को सेक्रेटरी न्यायालय के अधिकार प्रदान किए गए ।<sup>१२६</sup>

[सन् १८८१ में सहायक कमिश्नर मेरवाड़ा को जिला मजालत के अधिकार दिए गए और अब वह मूल दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सकता था । उसे लघुवाद न्यायालय का न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया । सन् १८८२ में उसे मारवाड़ा-मेरवाड़ा सीमावर्ती उस रेल मार्ग के लिए जो मारवाड़ के सिरोही क्षेत्र से गुजरता है, प्रथम श्रेणी के दंडनायक का कार्य भी सौंपा गया ।<sup>१२७</sup>

[सन् १८८४ में, छावनी दंडनायक नसीराबाद को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जिसका अधिकार स्टेट्स रेल्वे के उस भूभाग पर था जो मेवाड़ और टोंक रियासतों के मध्य पड़ता था । सन् १८८५ में, न्यायिक सहायक कमिश्नर तथा छावनी-दंडनायक, नसीराबाद को ब्रिस्टोर्लैंड रूप से लघुवाद न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा इनका अधिकार-क्षेत्र राजपूताना रेल्वे के उस भूभाग पर रखा गया जो जयपुर, किशनगढ़ और मेवाड़ तथा टोंक रियासतों में से होकर गुजरता था ।<sup>१२८</sup>

१८ सितम्बर, १८८६ को ब्रजमेर व मेरवाड़ा के सहायक कमिश्नर को उनके अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में सन् १८८८ के एक्ट १० (जाम्ना फौजदारी) लागू होने से जिला-दंडनायक के पद पर नियुक्त किया गया परन्तु दोनों ही जिलों के चुगी और घादकारी के मामले में केवल कमिश्नर को ही जिला दंडनायक के अधिकार प्रदान किए गए ।<sup>१२९</sup> ब्रजमेर के न्यायालयों में काम के बंटवारे में काम की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं थी । सन् १९०० में यह महसूस किया गया कि वर्तमान व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सहायक कमिश्नर सभी दीवानी और फौजदारी मामले को स्वीकार कर उन्हें विभिन्न न्यायालयों में वितरित करने का कार्य त्रुटिपूर्ण था ।<sup>१३०</sup> सहायक कमिश्नर का अधिकार समय प्रतिदिन विभिन्न न्यायालयों में काम के बंटवारे में ही व्यतीत हो जाता था । इन्हें स्थानीय जानकारी प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध ही नहीं हो पाता था । इस एक मूल कारण के अतिरिक्त अन्य कतिपय कारणों से भी यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न न्यायालयों के सीमा-क्षेत्र निर्धारित कर उसके आधार पर दीवानी और फौजदारी मामले का कार्य उनमें बाँटा जाए ।<sup>१३१</sup> ब्रजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर का भी यह मत था कि इस योजना से प्रशासनिक लाभ होगा ।<sup>१३२</sup>

सरकार ने नवम्बर, १९०३ में न्यायिक कार्य-विभाजन की नवीन योजना लागू की ।<sup>१३३</sup> इस प्रकार न्यायपालिका में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास जारी रहे ।

ब्रजमेर में अंग्रेजों के शासन के बाद ही आधुनिक न्याय प्रणाली प्रारम्भ हुई । प्रारम्भिक न्याय प्रक्रिया का स्वरूप सरल था । सुपरिटेण्डेंट एक साथ ही दीवानी,

फौजदारी, राजस्व और चूणी सम्बन्धी मामलों के प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था। सुपरिटेण्डेंट की कचहरी से अभीले कमिश्नर सुना करता था। सन् १८६२ तक दंडनायक और पुलिस के अधिकारों में सीमा रेखा निर्धारित नहीं हो पाई थी। सन् १८६२ के बाद पुलिस और न्याय विभागों को पृथक्-पृथक् किया गया।

अजमेर डिवीजन में जाना फौजदारी कानून लागू होने के पूर्व फौजदारी मामलों में डिप्टी कमिश्नर सत्र न्यायाधीश का कार्य करता था। कमिश्नर को केवल विस्तृत न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार ही प्राप्त नहीं थे वरन् उन्हें राजस्व संबंधी अधिकार भी प्राप्त थे। सन् १८६६ में इस दिशा में पृथक्करण का प्रयास किया गया, परन्तु यह व्यवस्थित नहीं हो पाया।

अजमेर-न्यायालय-विनियम द्वारा सन् १८७७ में उस घाघार की जिस पर घात्र की न्यायपालिका का स्वरूप विकसित हुआ है, स्थापित किया गया। सन् १८७७ के प्रावण पर न्याय-व्यवस्था उन्नीसवीं सदी तक चलती रही और बीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक वह थोड़े से संशोधनों के साथ बनी रही।

### अध्याय ७

१. सारदा, अजमेर—हिस्टोरिकल एण्ड जस्टिफिकेटिव (१९४१), पृ० २६६।
२. यह पाँच थाने-न्यावर, अवाजा, जस्सा खेड़ा, दादगढ़ और देवर में स्थापित किए गए थे। त्रिपाठी, मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास (१९१७) पृ० २०।
३. डिवान, स्केच ऑफ मेरवाड़ा (१८५०) पृ० ५।
४. बर्नल ए० जी० डेविड्सन, डिप्टी कमिश्नर द्वारा भार० एच० कीटिंग, कमिश्नर व ए० जी० जी० रात्रपूताना को पत्र, दिनांक ११ अप्रैल, १८६८ पत्र संख्या ५६८।१८६८।
५. सेप्टिमेंट जान तिस्टन, अमिस्टेट कमिश्नर द्वारा डिप्टी कमिश्नर को पत्र, दिनांक ६ अक्टूबर १८६६, पत्र संख्या १६८।१८६६।
६. डिप्टी कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्नर व ए० जी० जी० रात्रपूताना को पत्र, दिनांक ११ अप्रैल, १८६८ पत्र संख्या ५६८।१८६८।
७. कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक १७ मई, १८७७ संख्या ५६८।

८. एच० एम० रप्टन, डिप्टी कमिश्नर द्वारा एल० एस० सांडर्स कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २७ जुलाई, १८७१ ।
९. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भाग १ ।
१०. एल० एस० सांडर्स कमिश्नर भजमेर द्वारा कर्नेल जे० सी० ब्रुक्स, कार्य-वाहक चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक २५ जनवरी, १८७२ ।
११. कर्नेल जे० सी० ब्रुक्स कार्यवाहक चीफ कमिश्नर द्वारा सी० यू० एंजींसन, सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक केम्प नसीराबाद ६ फरवरी १८७२ पत्र संख्या ६८ ।
१२. एसिस्टेंट जनरल सुपरिंटेंडेंट, ठगी एवं डकैती उन्मूलन कार्यवाही द्वारा कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक ७ जुलाई, १८८४ संख्या २६६ ।
१३. चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा की विज्ञप्ति भाबू दिनांक १५ अगस्त, १८८५ संख्या ८७७ ।
१४. सचिव, भारत सरकार द्वारा जनरल सुपरिंटेंडेंट, ठगी एवं डकैती उन्मूलन कार्यवाही फोर्ट विलियम दिनांक ६ फरवरी, १८९६ पत्र संख्या २०३ जी० ।
१५. सुपरिंटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १४ जुलाई, १८९३ पत्र संख्या २७४।१६८ ।
१६. उपर्युक्त ।
१७. सुपरिंटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २६ जनवरी, १८९४ पत्र संख्या ३०४ ।
१८. प्रशासनिक रिपोर्ट भजमेर-मेरवाड़ा सन् १८८८ से १८९४ तक ।
१९. सुपरिंटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र दिनांक २६ जनवरी, १८९४ संख्या ३०४ ।
२०. प्रथम एसिस्टेंट ए० जी० जी० राजपूताना का कमिश्नर भजमेर के पत्र परसुपरिंटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा व्यक्त मत भाबू दिनांक २ जनवरी, १८९४ पत्र संख्या ७६ ।
२१. भारत सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को सखपूलर, सन् १८३७ ।
२२. वकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आलेख (भाबू रेकॉर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर) ।

२३. उपयुक्त ।
२४. उपयुक्त ।
२५. उपयुक्त ।
२६. उपयुक्त ।
२७. डिप्टी कमिश्नर द्वारा ए० जी० जी० राजपूताना की पत्र, दिनांक ११ अप्रैल, १८६८ संख्या ५६८ ।
२८. बकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आलेख (भाबू रेकॉर्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर) ।
२९. उपयुक्त ।
३०. उपयुक्त ।
३१. डिप्टी कमिश्नर द्वारा ए० जी० जी० राजपूताना की पत्र, दिनांक ११ अप्रैल, १८६८ पत्र संख्या ५६८ ।
३२. बकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आलेख (भाबू रेकॉर्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर)
३३. उपयुक्त ।
३४. उपयुक्त ।
३५. उपयुक्त ।
३६. उपयुक्त ।
३७. मुनरिटेंट्रिज जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा की पत्र, दिनांक ४ जनवरी, १८७३ पत्र संख्या ८ ।
३८. मुनरिटेंट्रिज जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा की पत्र, दिनांक १२ जुलाई, १८७६ पत्र संख्या ७६८ ।
३९. उपयुक्त ।
४०. सविश्व परराष्ट्र विभाग, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा की पत्र, दिनांक २४ सितम्बर, १८७६ पत्र संख्या ७६८ ।
४१. प्रशासनिक रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा १८७५-१८७६ ।
४२. मुनरिटेंट्रिज जिला पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर की पत्र, दिनांक १२ जुलाई, १८७६ पत्र संख्या ७६८ ।
४३. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर की पत्र, दिनांक १५ दिसम्बर, १८७४ संख्या ३८४० ।

४४. सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक १२ जुलाई, १८७६ संख्या ७६८ ।
४५. मेजर रयटन डिप्टी कमिश्नर, भजमेर द्वारा एल० एम० साटर्स, कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक ३० नवम्बर, १८७४ संख्या १२८८ ।
४६. एल० एस० साटर्स कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ ।
४७. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र दिनांक २२ अप्रैल, १८६३ पत्र संख्या १४११५ ।
४८. चीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति क्रमांक २८८ भावू, दिनांक ४ अप्रैल, १८८८ ।
४९. सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा जिला दंडनायक भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २७ जून, १८६३ संख्या ५६६ ।
५०. चीफ कमिश्नर विज्ञप्ति क्रमांक २८८ दिनांक भावू ४ अप्रैल १८८८ ।
५१. सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा जिला दंडनायक को पत्र दिनांक २७ जून, १८६३ संख्या ५६६ ।
५२. उपयुक्त ।
५३. सी० सी० बाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स खंड १ ।
५४. उपरोक्त तथा डिप्टी कमिश्नर द्वारा भार० सिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र, दिनांक १२ मई, १८६८ पत्र संख्या १ ।
५५. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पत्र, दिनांक १४ फरवरी, १८६६ संख्या ७६७ पर टिप्पणी, फाहल न० ६६ (पृ० १२२) ।
५६. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार के निजी सहायक सी० ए० डोहेल द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र, इलाहाबाद दिनांक १४ फरवरी, १८६८ संख्या ७६७ ।
५७. उपयुक्त ।
५८. एल० बाइटकिंग जिला दंडनायक भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १ जुलाई, १८८६ संख्या ८८७ ।
५९. हरविलास सारदा, भजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१९४१) पृ० २६६ ।
६०. राजपूताना मजिस्ट्रेट्स (१८७६) खंड २ ।
६१. चीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति भावू दिनांक २३ अप्रैल, १८८३ संख्या ३०८ ।

६२. असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर को पत्र दिनांक १० नवम्बर, १६०२ संख्या ३२५६ ।
६३. चीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति, दिनांक १४ फरवरी, १६०३ संख्या १५०७ ।
६४. चीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति, दिनांक ५ मई, १६०३ संख्या ५१३ ।
६५. असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर को पत्र दिनांक २२ जुलाई, १६०६ संख्या २६८३ ।
६६. राजपूताना गजेटियर्स (१८७६) खंड २ ।
६७. फाइल नं० १६, पत्र संख्या १८ दिनांक १२-४-१० ।
६८. भारत सरकार का प्रस्ताव दिनांक १८ मई, १८८२ संख्या १७१७४७ । ७५६ ।
६९. प्रशासनिक रिपोर्ट भ्रजमेर-मेरवाड़ा सन् १८८८ ।
७०. सुपरिंटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १६ अक्टूबर, १८६६ संख्या ८०१।५२६ ।
७१. उपयुक्त ।
७२. उपयुक्त ।
७३. प्रशासनिक रिपोर्ट भ्रजमेर-मेरवाड़ा वर्ष १६०२-१६०३ ।
७४. उपयुक्त, वर्ष १६११-१६१२ ।
७५. उपयुक्त, वर्ष १६१०-१६११ ।
७६. उपयुक्त, वर्ष १८६५-१८६६ ।
७७. उपयुक्त, वर्ष १८६५-१८६६ ।
७८. प्रशासनिक रिपोर्ट भ्रजमेर-मेरवाड़ा वर्ष १८६७-६८ ।
७९. उपयुक्त, वर्ष १६१० ।
८०. उपयुक्त ।
८१. इस प्रश्न पर सारा कबीला एवं उसके मित्रगण इसे अपना ही भागड़ा मानकर चलते थे । इस प्रश्न पर बहुधा गम्भीर संघर्ष उत्पन्न हो जाते थे ।
८२. फाइल क्रमांक ६६ (रा० रा० पु० म०, बीकानेर) ।
८३. गवर्नर जनरल के सचिव द्वारा ए० जी० जी० राजपूताना को पत्र दिनांक ११ दिसम्बर, १८४८ ।

८४. कमिश्नर भजमेर द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी मूवा सरकार को पत्र (मन् १८३२ से १८५८ तक भजमेर-मेरवाड़ा में प्रणामन संबंधी फाइल संख्या ७ पत्र संख्या २२) ।
८५. उपयुक्त ।
८६. कमिश्नर की बचहगी में जारी पत्र दिनांक १ डिगम्बर, १८५७ ।
८७. उपयुक्त ।
८८. उपयुक्त ।
८९. उपयुक्त ।
९०. उपयुक्त ।
९१. डिप्टी कमिश्नर भजमेर द्वारा कार्यवाहक कमिश्नर भजमेर को पत्र दिनांक १२ अग्रेस्त, १८६० ।
९२. उपयुक्त ।
९३. उपयुक्त ।
९४. सेप्टिनेंट कर्नल कीटिंग कार्यवाहक कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा भार० मिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी मूवा सरकार को पत्र, दिनांक २१ फरवरी, १८६८ पत्र संख्या ११४ ।
९५. उपयुक्त ।
९६. उपयुक्त ।
९७. सी० एल० कार्यवाहक सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर भजमेर को मन् १८३३ से १८५८ तक भजमेर-मेरवाड़ा प्रणामन पर पत्र (फाइल संख्या ७, पत्र संख्या ६२१। अ० सी० ग० रा० पु० म०, बीकानेर)
९८. सेप्टिनेंट कर्नल कीटिंग कार्यवाहक कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा भार० मिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी मूवा सरकार को पत्र, दिनांक २५ फरवरी, १८६८ पत्र संख्या ११४ ।
९९. उपयुक्त ।
१००. उपयुक्त ।
१०१. भारत सरकार के परराष्ट्र विभाग के अधीन भजमेर-मेरवाड़ा की पृथक् चौक कमिश्नरी का गठन पर फाइल, फाइल संख्या ११७ (रा० रा० पु० म०, बीकानेर) ।
१०२. उपयुक्त ।



१०३. उपर्युक्त ।

१०४. धारा ४ अजमेर न्यायालय विनियम १८७२ ।

१०५. धारा ६, उपर्युक्त ।

१०६. धारा ६ „

१०७. धारा १० „

१०८. धारा ११ „

१०९. धारा ८ „

११०. धारा १२ „

१११. धारा १४ „

११२. धारा १४ „

११३. धारा १६ „

११४. सन् १८६० के पूर्ववर्ती दम बर्षों में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों में सम्पत्ति संबंधी मुकदमों की वार्षिक औसत २६७५.२ थी । बाद के दम बर्षों में यह औसत बढ़कर २६३६.२ हो गई थी । सन् १९०२ में ३१६० नये मुकदमे दर्ज हुए थे । इस वृद्धि का कारण अकाल की वजह से श्रृणुप्रस्तता थी ।

११५. निम्न पाँच स्तर की दीवानी अदालतें स्थापित की गई थीः—

१. चीफ कमिश्नर की कचहरी ।

२. कमिश्नर की कचहरी ।

३. प्रथम श्रेणी न्यायाधीशों की अदालतें ।

४. द्वितीय श्रेणी न्यायाधीशों की अदालतें ।

५. मजिस्ट्रेट अदालत ।

११६. धारा ६ अजमेर न्यायालय विनियम १८७७ ।

११७. विज्ञप्ति नं० ३५५—ए दिनांक १ जून, १८७७ ।

११८. धारा १४ (घ) अजमेर न्यायालय विनियम १८७७ ।

११९. धारा १४ (ब) उपर्युक्त ।

१२०. धारा २२ उपर्युक्त ।

१२१. धारा ७ उपर्युक्त ।

१२२. चीफ कमिश्नर विज्ञप्ति नं० ३५५ (घ) दिनांक १ जून, १८७७ ।

१२३. चीफ कमिश्नर विज्ञप्ति सं० ३१२-सी ११४ दिनांक २४ दिसम्बर, १८९१ ।
१२४. धारा ११ भ्रजमेर न्यायालय विनियम १८७७ ।
१२५. धारा ३८ उपयुक्त ।
१२६. फाइल क्रमांक ७३ प्रस्ताव फोर्ट विनियम, दिनांक २७ मार्च, १८७७ ।
१२७. जय्ती के मुकदमों में ८२ प्रतिशत, अपील के मुकदमों में ८६ प्रतिशत और फौजदारी मुकदमों में ८७ प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
१२८. कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २२ नवम्बर, १८९० पत्र संख्या ३०८६ ।
१२९. उपयुक्त ।
१३०. उपयुक्त ।
१३१. उपयुक्त ।
१३२. भ्रकाल प्रशासन नियमावली भ्रजमेर-मेरवाड़ा (१९११) पृ० ३ ।
१३३. असिस्टेंट कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक ८ अक्टूबर, १९०० पत्र संख्या २१२३ ।
१३४. असिस्टेंट कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक २६ फरवरी, १९०१ पत्र संख्या ५६३ ।
१३५. कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक २० फरवरी, १९०१ पत्र संख्या ११४ बी तथा कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक ७ मार्च, १९०१ ।
१३६. कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १६ सितम्बर, १९०१ तथा कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १४ नवम्बर, १९०३ ।

## शिक्षा

१९४२

सन् १८४७ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले ने हाउस ऑफ कामन्स में भाषण करते हुए कहा "माननीय ! मेरा विश्वास है कि जन-साधारण को शिक्षा के साधन प्रदान करना राज्य का कर्तव्य एवं अधिकार है.....अतएव मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन-साधारण की शिक्षा केवल साध्य ही नहीं है, यह उस सकल प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन भी है। यदि यह सत्य है तो मेरा मस्तिष्क इस तर्क को कैसे स्वीकार कर सकता है कि कोई व्यक्ति इसमें ही परमछंदी का अनुभव करके चले कि जनसामान्य की शिक्षा से सरकार का कोई संबंध नहीं है।" सन् १८३३ में हाउस ऑफ कामन्स में लॉर्ड मैकाले ने पुनः कहा कि भारत का शासन इस तरह किया जाए कि वहाँ की जनता अंग्रेजों की स्वाधीनता एवं सम्मता के स्तर तक उन्नत हो सके तथा उन्होंने एक प्रश्न प्रस्तुत किया "क्या हम भारत को अपना दास बनाए रखने के लिए ही वहाँ की जनता को प्रज्ञानी रखना चाहते हैं ?" भारत आने पर उन्होंने अपने उन्हीं विद्वान्तों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में उद्घोषित किए थे। मैकाले के कारण सरकार ने भी एक प्रस्ताव द्वारा शोध ही अंग्रेजी भाषा में शिक्षा-नीति लागू करने का निर्णय लिया।

भारत में अंग्रेजी शासन में प्रथम शिक्षण संस्था कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग द्वारा सन् १७८२ में मदरसे के रूप में खोली गई थी। तत्पश्चात् सन् १७९१ में

जोनाथन डंकन ने बनारस में हिन्दुओं के लिए कॉलेज का शिलान्यास किया। सन् १८१५ में, सॉर्डे हेस्टिंग्स ने यह अभिमत प्रकट किया कि वे भारत में शिक्षा-व्यवस्था लागू करना चाहते हैं।

उन दिनों भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति के प्रश्न को लेकर एक संघर्ष छिड़ा हुआ था। राजा राममोहन राय जो भावी युग के स्वप्नदृष्टा थे उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा-नीति का समर्थन किया। ईसाई मिशनरी शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर भाषस में एक मत नहीं थे। डॉ० केरे एवं उनके सहयोगी स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के पक्ष में थे। उन्होंने १८१८ में श्री रामपुर में जो उन दिनों डेन्माक के अधीन था, एक कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का घोषित सख्य भारतीयों को ईसाई मतावलम्बी बनाने का था। सन् १८२० में, इन लोगों के द्वारा ईसाई युवकों को भूतिपूजकों में ईसाईयत का प्रचार करने का प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की गई।<sup>३</sup> परन्तु सन् १८३० में डॉ० डफ ने पुनः राजा राममोहन राय की सहायता से साहित्य, विज्ञान एवं धार्मिक शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की। इस तरह भाग्य भाषा के अध्ययन को प्रभावशाली पक्ष प्रदान की गई। डॉ० डफ की यह भाव्यता थी कि ईसाई धर्म अंग्रेजी भाषा के ज्ञान प्रसार से ही प्रसारित हो सकता है।<sup>४</sup>

उन्नीसवीं सदी में अजमेर में भी प्रचलित शैक्षणिक व्यवस्था का विनाश हुआ। कैरे ने कुछ प्रारम्भिक कठिनाईयों के बावजूद अजमेर और बाड़मेर में पुष्कर में नवम्बर, १८१८ में एक-एक स्कूल की स्थापना की। नवम्बर, १८२१ में इन दोनों में, प्रत्येक स्कूल में चालीस छात्र थे। सन् १८२१ में अजमेर सरकार ने अजमेर शहर के स्कूल के लिए तीन सौ रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा सरकार के द्वारा जन-सामान्य की शिक्षा के लिए और कोई कदम नहीं उठाया गया।<sup>५</sup>

कैरे को अक्टूबर, १८२२ में कई अन्य स्थानों पर भी स्कूल खोलने में सफलता मिली।<sup>६</sup> स्कूलों की कार्यविधि के अध्ययन के लिए एक 'जन शिक्षण-समिति' का गठन किया गया। इस समिति ने २४ अप्रैल, १८२२ को अपनी प्रथम रिपोर्ट तथा ५ मार्च, १८२५ को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे ज्ञान होता है कि शिक्षा के विस्तार की गति बहुत धीमी थी। इन स्कूलों के परिणाम इतने अपर्याप्त थे और उनके खर्च इतने भारी थे कि समिति ने ऐसे स्कूलों की उपयोगिता तक में सदेह प्रकट किया। जनरल कमेटी तथा स्थानीय अधिकारियों के निरन्तर विरोध के बावजूद कैरे ने इन स्कूलों में "ग्यूटेस्टामेंट" पढ़ाना शुरू किया जिससे छात्रों के अभिभावकों के मन-मस्तिष्क में इन स्कूलों के उद्देश्यों के प्रति सदेह होना स्वाभाविक ही था। अक्टूबर, १८३२ में साडें बेटिक ने अजमेर स्कूल का निरीक्षण किया और उसे पूर्णतया अपर्याप्त एवं निरर्थक ठहराया जिसके फलस्वरूप इसे बंद कर दिया गया।<sup>७</sup>

सन् १८३६ में अजमेर में एक सरकारी स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल में एक यूरोपीय अध्यापक तथा दो भारतीय अध्यापक एक हिन्दी के लिए व दूसरा उर्दू के लिए नियुक्त किए गए। नसीराबाद और अजमेर के यूरोपीय समाज ने इस स्कूल को दान एवं मासिक चन्दे के रूप में अच्छी सहायता प्रदान की, और कुछ वर्षों तक इस स्कूल ने अच्छी उन्नति की। सन् १८३७ के अंत में छात्रों की संख्या २१२ तक पहुँच गई थी तथा कई सानों तक स्कूल निरंतर तरक्की करता रहा। परन्तु भारतीयों के अस्तित्व में आरम्भ से ही इन सरकारी स्कूलों के खोते जाने के प्रति संदेह की भावना थी। एस० डब्ल्यू. फॉलो ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है। सरकारी स्कूलों को लोग संदेह की नज़रों से देखते हैं। उन्हें इसमें किसी विशेष उद्देश्यों की सफलता दृष्टिगोचर नहीं होती।<sup>८</sup> इस तरह की संदेह की भावना और शंका के कारण सन् १८३७ के बाद सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई, जिसके फलस्वरूप सन् १८४३ में इसे बंद कर देना पड़ा। यह स्कूल न तो भारतीय उच्च वर्ग और न मध्यम वर्ग के लोगों की ही आकर्षित कर सका और न इस पर किए जाने वाले व्यय के अनुकूल परिणाम ही निकले। इस स्कूल पर प्रति-वर्ष ६ हजार की राशि व्यय की जाती थी।<sup>९</sup> कुछ वर्षों बाद जनता शिक्षा की आवश्यकता महसूस करने लगी तथा जो संदेह इन स्कूलों के प्रति आरम्भ में बन चला था सन्तः सन्तः समाप्त होने लगा।<sup>१०</sup>

सन् १८४७ में सरकारी स्कूल खोलने और उसे कॉलेज स्तर तक उन्नत करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया। इस प्रश्न का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा निदेशकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उन्होंने १ जुलाई, १८४७ को इसके लिए स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्देश दिया कि स्कूल को कालांतर में कॉलेज के रूप में परिवर्तित करने का प्रश्न अभी न उठाया जाकर भावी निर्णय पर छोड़ दिया जाय। परन्तु एक लम्बे समय तक इस आदेश का पालन नहीं हो सका। सन् १८५१ ई. डॉ० बुच के निर्देशन में अजमेर नगर में एक सरकारी स्कूल खोला गया।<sup>११</sup>

इसके साथ-साथ ही राजपूताना के कई नरेशों व सरदारों ने अंग्रेजी भाषा सीखने की तीव्र उत्कंठा प्रकट की। अंग्रेज सरकार भी इस बात से बहुत खुश थी कि कृत्रिम प्रभावशाली प्रतिष्ठित भारतीय शासक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जयपुर के महाराजा रामसिंह अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ लेते थे और वे इस भाषा के ज्ञान वर्धन में भी रुचि ले रहे थे। उन्होंने जयपुर में एक अंग्रेजी स्कूल खोल रखा था। जयपुर से कई ठाकुरों व रियासत के प्रतिष्ठित लोगों ने अपने बच्चों की अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा के लिए निजी अध्यापक रख छोड़े थे।<sup>१२</sup> महाराजा ज्ञानगढ़ ने भी अंग्रेजी सीखने के लिए एक अध्यापक नियुक्त कर रखा था तथा इस भाषा में उनकी विशेष रुचि थी।<sup>१३</sup> अतएव इस ओर ध्यान दिया गया कि अजमेर को भी कि राजपूताना के क्षेत्र में स्थित है, इस भाषा की प्रविष्टि और राजपूताना की

इन पड़ोसी रियासतों के लोगों में इंग्लैंड के साहित्य एवं भाषा भाषा की जानकारी एवं अध्यापन प्रदान करने में पहल करनी चाहिए । <sup>१४</sup>

अजमेर में सन् १८५१ में धारम्भ किया गया स्कूल थोड़े समय में ऐसा केन्द्र-बिन्दु बन गया जिसके आधार पर घागे जाकर अजमेर में शिक्षा प्रणाली का उद्भव और विकास हुआ । <sup>१५</sup> सन् १८५४ में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में दिया गया निर्देश भी शिक्षा के विकास में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ । <sup>१६</sup> यद्यपि उसमें कुछ कमियाँ थीं । सन् १८६८ में यह स्कूल प्रिन्सिपल गोल्डिंग महोदय के प्रयास एवं सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप कॉलेज के स्तर को प्राप्त कर सका । १७ फरवरी, सन् १८६८ को कर्नल कोटिंग द्वारा कॉलेज का शिनायास किया गया था । <sup>१७</sup> इस नए कॉलेज भवन का उद्घाटन गवर्नर जनरल द्वारा १७ फरवरी, १८७० को सम्पन्न हुआ ।

साहें मेयो जब अजमेर में राजपूताना के नरेशों के दरबार में सम्मिलित होने को आए तब इस दरबार में उन्होंने राजपूताना के नरेशों व जागीरदारों के पुत्रों की शिक्षा के लिए एक रॉयल कॉलेज (गवर्नमेंट कॉलेज के अतिरिक्त) की स्थापना की घोषणा की । परन्तु गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिन्सिपल ने इस सुझाव के प्रति अस्वीकृति प्रकट की तथा अजमेर में एक और नए कॉलेज के खोलने से बचा नुकसान होगा उस ओर ध्यान आकषिप्त किया । <sup>१८</sup> उनका कहना था कि:—

१. गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ अजमेर की जनता के लिए ही नहीं खोला गया है । यहाँ के लोग यदि गरीब नहीं हैं तो धनवान भी नहीं हैं । यह कॉलेज विशेष रूप से राजपूताने में और विशेषकर राजाओं, राजकुमारों और प्रमुख जागीरदारों में शिक्षा के प्रसार के लिए खोला गया है । <sup>१९</sup>
२. यदि यहाँ नया कॉलेज खुलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज को राजपूताने की कई रियासतों के धनी एवं मध्यम वर्ग के लोगों की शिक्षा की अपेक्षा अजमेर शहर के लड़कों की शिक्षा तक ही सीमित रह जाना पड़ेगा । <sup>२०</sup>
३. गवर्नमेंट कॉलेज ने हाल ही में छात्रावास खोलकर अजमेर जिले के धनी एवं प्रभावशाली लोगों से अपना सम्पर्क स्थापित किया है, नए कॉलेज के खुलने से यह सम्पर्क समाप्त हो जाएगा । <sup>२१</sup>
४. नए कॉलेज के खुल जाने से गवर्नमेंट कॉलेज की हैसियत और उसकी वर्तमान स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी । <sup>२२</sup>
५. राजपूताना के सामंती में कॉलेज तो दूर रहा, हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता नहीं है । उनके लड़के पूरी तरह से अनपढ़ हैं और उनके लिए यदि कोई वैदिक संस्था खोलनी ही है तो साधारण प्राथमिक स्कूल ही पर्याप्त होगा । <sup>२३</sup>

प्रिन्सिपल डिमेलो के गवर्नमेन्ट कॉलेज के बारे में इतनी एक पक्षीय माम्यता एवं सद्भाव तथा उसके हितों की रक्षा की उत्कंठा को सफलता नहीं मिली। नया कॉलेज खोलने की घोषणा ने व्यावहारिक रूप ग्रहण किया तथा शीघ्र ही मेयो कॉलेज की स्थापना की गई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मेयो कॉलेज ने वायसराय द्वारा राजघराने के बच्चों में शिक्षा-प्रसार की योजना एवं अमिर्तच के फलस्वरूप जन्म लिया था।<sup>२४</sup> उनकी यह माम्यता थी कि एक तरफ राजपूत नरेश में केवल किताबी ज्ञान के अलावा नैतिक एवं शारीरिक योग्यताएं होना अत्यधिक आवश्यक है।<sup>२५</sup> अतएव सामंत वर्ग के लिए एक अलग कॉलेज की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

वायसराय ने कॉलेज की सहायताय राजपूताना के सामंतों से सार्वजनिक धनदान द्वारा एक कौष-स्थापना की योजना तैयार की जिससे मेयो कॉलेज में शिक्षकों का वेतन अन्य शिक्षा संबंधी सामग्री, छात्रवृत्तियां तथा भवन की मरम्मत आदि के लिए आवश्यक व्यय की पूर्ति समझ हो सके। अनुदान के लिए धनराशि राजाओं और प्रमुख सरदारों से आमंत्रित की गई। फलस्वरूप लगभग छः लाख की राशि के बचन प्राप्त हुए, जो बाद में सात लाख की राशि तक पहुँच गए थे।<sup>२६</sup> इस राशि पर प्राप्त व्याज तथा भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक अनुदान मिलकर कॉलेज की स्थाई धन्य का साधन बनाया गया। इस कार्य के लिए सबसे उदार सहायता जयपुर नरेश से प्राप्त हुई जिनका कुल योगदान दो लाख से भी अधिक था। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भालाबाड़ का योगदान एक-एक लाख से अधिक का था। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से कॉलेज के लिए १६७ बीघे जमीन प्रिन्सिपल और वाइस प्रिन्सिपल के लिए आवास तथा छात्रावास भवन प्रदान किया। सरकार ने निर्माण एवं चार भवनों की मरम्मत का व्यय स्वयं अपने ऊपर लिया।

मेयो कॉलेज का मुख्य भवन "भारतीय-यूनानी स्थापत्य कला का एक प्रवृत्ता सम्मिश्रण है।" इसके निर्माण में करीब ४,०१,४०० रुपये खर्च हुआ था।<sup>२७</sup> इस भवन का मिलाप्यार सर एलेग्रेड लॉयल द्वारा ५ जनवरी, १८७८ को रखा गया तथा इसका उद्घाटन ७ नवम्बर, १८८१ को वायसराय बंकीन के हाथों सम्पन्न हुआ।

अजमेर में शिक्षा की निरंतर प्रगति को देखते हुए सन् १८६६ से यहाँ द्विती कक्षाओं की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।<sup>२८</sup> इसके पूर्व जबकि शिक्षा का प्रसार कम था, सामान्य शिक्षित युवकों को भारतीय स्थापत्यों और अंग्रेज सरकार के अधीन गौहरी आमाजी से उल्लेख हो जाया करती थी, परन्तु अब शिक्षा का विज्ञान व उमदा स्तर उन्नत हो जाने के कारण एक सामान्य युवक के लिए जबतक कि वह स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त नहीं हो तबतक नौकरी प्राप्त करना

कठिन था। राजपूताना में स्नातकों के अभाव में स्थानीय नियुक्तियाँ बाहरी प्रदेशों के ऊँची शिक्षा प्राप्त युवकों से की जाने लगी। इस तरह उन्नीसवीं सदी के अन्त तक अजमेर और राजपूताना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा लोगों में जागृत हो चली थी।

उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था के लिए एक भारी धन-राशि आवश्यक होती है। सरकार की यह नीति थी कि सामान्य शिक्षा के लिए तो वह खर्च करती थी तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था गैर सरकारी स्वयं सेवी शैक्षणिक संस्थाओं के हाथों में छोड़ देती थी। भारत में दूसरे स्थानों पर भी उदाहरणस्वरूप, दिल्ली, आगरा, बरेली, मेरठ तथा अन्यत्र राजा महाराजा, जमींदार वर्ग, धनी एवं प्रतिष्ठित शिक्षित वर्ग के लोगों ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए साधन जुटाने में अनेक बढ़कर उदारतापूर्वक योगदान दिया था। अतएव, अजमेर में भी ऐसी ही भाषा व्यक्त की गई थी कि कॉलेज की नितांत आवश्यकता अनुभव करने वाले लोगों का उदार सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। फरवरी १० अप्रैल, १८६६ को इसके लिए एक सार्वजनिक सभा आमंत्रित की गई।

इस सभा का आयोजन दीनत बाग में किया गया जो पूर्णतया सफल रहा। यह नगर के गण्यमान्य लोगों की सभा थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन कमिश्नर कम्ब महोदय ने की।<sup>२६</sup> अंदे के लिए की गई अपील का जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया और उदारता से धन प्रदान किया। मसूदा राव ने व्यक्तिगत रूप से तीन हजार की राशि तथा ब्यावर के सेठ चम्पालाल ने पाँच हजार का धन दान में दिया। अजमेर कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थियों की संस्था ने इस कार्य में गंभीर रुचि लेते हुए धन संप्रदा के लिए सहयोग प्रदान किया। इन भूतपूर्व विद्यार्थियों ने कॉलेज की उन्नति के लिए अपने एक माह का वेतन प्रदान करना स्वीकार किया और इस तरह शीघ्र ही एकत्रित ग्यारह हजार की धनराशि इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि जनता में इस प्रयास की सफलता के लिए सराहनीय उत्साह था।<sup>३०</sup> सरकार ने १५ जुलाई, १८६६ से अजमेर के गवर्नमेन्ट कॉलेज में स्नातक कक्षाएं प्रारम्भ कर दीं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में विज्ञान-शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। कृषि विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं इंजीनियरों की कमी पहले ही अनुभव की जा रही थी। देश में उन दिनों टेक्नीकल विशेषज्ञों की भारी कमी थी। डरलैंड के सम्राट ने ६ जनवरी, १९१२ को कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा "मेरी यह कामना है कि इस घरेली पर स्कूलों और कॉलेजों का जाल सा बिछ जाए जिससे स्वामिभक्त तथा उपयोगी नागरिक तैयार हों सकें जो अपने कर्तव्यों के प्रति गौरव अनुभव कर सकें। मेरी यह कामना है कि मेरी भारतीय प्रजाजनों के घरों में ज्ञान का प्रसार हो तथा उनके अर्थ के फल एवं ज्ञान की गंध से सुवासित उच्च



विचार, सुख-सुविधा एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायक हो। मेरी कामना की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से पूरी की जा सकती है और भारत में शिक्षा का उद्देश्य मेरे हृदय के बहुत समीप है।<sup>३१</sup> भावी भ्रंशजी शासन की भावी शिक्षा-नीति एवं लक्ष्य की एक झलक इससे घोंकी जा सकती है।

ब्रिटिश सम्राट की इस घोषणा से भजमेर की जनता में उत्साह एवं प्रेरणा को बल मिला। यहाँ स्नातक कक्षाओं में विज्ञान-विषय का अभाव तेजी से अनुभव किया जा रहा था। इसलिए २५ मई, १९१३ को ट्रेवर टाउन हॉल भजमेर में प्रमुख नागरिकों की सभा बुलाई गई जिसमें कमिश्नर ए० टी० होम्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य इस कार्य के लिए धन-संग्रह करना था। गवर्नमेन्ट कॉलेज भजमेर में बी० एस० सी० कक्षाएं आरम्भ करने के लिए पन्द्रह हजार का सार्वजनिक धनदा इकट्ठा करने का निर्णय इस समिति ने किया।<sup>३२</sup> समिति के इस उद्देश्य की सफलता का मूल कारण इस प्रदेश के प्रमुख नागरिकों का उत्साह तथा गवर्नमेन्ट कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग था। जुलाई, १९१३ से गवर्नमेन्ट कॉलेज में बी० एस० सी० की कक्षाएं आरम्भ की गईं और इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया।<sup>३३</sup>

भजमेर में सन् १८५० के पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्थानीय लोगों द्वारा ही संचालित होती थी और उसमें किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। इन देशी पाठशालाओं की स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त था। परन्तु सन् १८५० के बाद कर्नल डिकसन द्वारा भजमेर-मेरवाड़ा में ७५ स्कूल स्थापित किए गए और लोगों को इनके व्यय की पूर्ति-हेतु, कर के रूप में साधन स्रोत जुटाने के लिए अनुप्रेरित किया गया। बाद में इन स्कूलों की संख्या घटाकर ५७ कर दी गई। सन् १८५१ में भजमेर के देहाती क्षेत्र की स्कूलों के लिए तथा मेरवाड़ा की स्कूलों के लिए भी सन् १८५२ में एक-एक निरीक्षक नियुक्त किए गए। कर्नल डिकसन के नियुक्त के पश्चात् इस कर के प्रति जनता का असंतोष बढ़ गया था। इस कारण सरकार को बाध्य होकर यह कर समाप्त करना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि वे सभी स्कूलों में जो जनता से कर के रूप में एकत्रित धन से अनुचालित होती थी बंद कर केवल सरकारी व्यय पर चलने वाली पाठशालाएं रखी जाएं।<sup>३४</sup>

इन देशी पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन बहुत कम था तथा वे अध्यापन-कार्य के अयोग्य भी थे। सरकारी निरीक्षक ने सन् १८५८ में अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जबतक इन पाठशालाओं की वर्तमान स्थिति बनी रहेगी इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर सज्जाजनक रहेगा। इससे पूर्ववर्ती रिपोर्ट में यह स्पष्ट बतलाया गया था कि इन स्कूलों में कई वर्षे व्यतीत करने के बाद भी छात्र को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह कितना अक्षय एवं अनुपयुक्त है। उसमें कहा गया है कि दस या बारह

वर्षे स्कूल में व्यतीत कर लेने के बाद जब छात्र स्कूल छोड़ता है तो उसकी योग्यता की यह स्थिति रहती है कि १०-१२ वर्ष तक फारसी भाषा या १२-१३ वर्ष तक भरवी भाषा का अध्ययन करने के बाद उसको कुरान का कामबलाऊ ज्ञान होता है और यही स्थिति उसकी दफ्तर के काम की समझ के सबब में होती है।

सन् १८७१ में अजमेर-मेरवाड़ा का सीधा नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में चले जाने से यहाँ के शिक्षा-विभागों का उत्तर-पश्चिमी मूर्खों से सम्बन्ध विच्छेद हो गया और ये विभाग कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा के सीधे नियंत्रण में आ गए जो शिक्षा विभाग के निदेशक पद का भार भी समाते हुए थे। सन् १८९१ में, अजमेर-मेरवाड़ा में ४७ अथवा प्राईमरी पाठशालाएँ थीं जिनकी छात्रसंख्या ३०८२ थी। इन सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी तौर पर ८३ प्रारम्भिक पाठशालाएँ भी चल रही थीं जिनकी छात्र संख्या २७७७ थी। आठवीं दशक में प्रकाल एवं सूखे की स्थिति के कारण प्रारम्भिक शिक्षा में स्पष्ट ह्रास हुआ था, परन्तु इसके पश्चात् सन् १९०७ में, प्राथमिक शिक्षा ने यद्यो तेजी से प्रगति की।<sup>३५</sup> सन् १८८१ में पाठशाला जाने योग्य आयु के बच्चों की तुलना में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का अनुपात १२.८ प्रतिशत, सन् १८९१ में १३.५ प्रतिशत तथा सन् १९०३ में १२.५ प्रतिशत था।

सार्वजनिक प्राथमिक पाठशालाओं का संचालन शिक्षा-विभाग के नियंत्रण में था जिसके संचालक कमिश्नर स्वयं थे। विभाग को इन सरकारी पाठशालाओं के संचालन व देखरेख के लिए सरकारी सहायता के अलावा नगरपालिकाओं एवं जिला बोर्ड से भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। पाठशालाओं में छात्रों से फीस भी ली जाती थी। अध्यापकों के वेतनमान में बहुत फर्क था। गवर्नमेन्ट बॉय स्कूल अजमेर के प्रधानाध्यापक को सौ रुपये मासिक वेतन मिलता था जबकि विभाग के कनिष्ठ अध्यापक का वेतन ६ रुपये प्रतिमाह था। पचास प्राथमिक पाठशालाओं में से सात जड़कियों के स्कूल थे और ४२ पाठशालाएँ देहातों में थीं। सन् १९०३ में सार्वजनिक प्राथमिक पाठशालाओं पर कुल व्यय १७,७२२ रुपये प्रतिवर्ष था।

अजमेर में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति अच्छी थी। सन् १९०३ में सार्वजनिक माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या १४ थी जिनमें २४६५ छात्र थे।<sup>३६</sup> इन १४ माध्यमिक पाठशालाओं में से ६ पाठशालाएँ तहसील स्तर पर ग्रामों में विशुद्ध ब्रह्म-सर पाठशालाएँ थीं। दो सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल (नसीराबाद और ब्यावर) थे तथा दो बिना सरकारी सहायता के संस्थाओं द्वारा संचालित अजमेर मिशन स्कूल और दयानन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल थे तथा एक सरकारी स्कूल था जो गवर्नमेन्ट कॉलेज में स्थित था।<sup>३७</sup>

इन दो जिलों में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेज के कर्मचारियों एवं संचालन

पर सरकार द्वारा निम्न तालिका में प्रदर्शित राशि व्यय होती थी :—

कॉलेज के अध्यापक	रुपए	२४,४०४
विविध व्यय		३,१६६
१८ ग्राम पाठशालाएं (अजमेर में)		४,६६४
विविध व्यय		२,२०४
१४ ग्राम पाठशालाएं (मेरवाड़ा में)		१,६४२
विविध व्यय		४००
गर्ल्स नॉर्मल स्कूल और महिला नॉर्मल स्कूल		
विविध व्यय सहित		१,०२०
पुरुष नॉर्मल बसास		६००
विविध व्यय		१६२
वार्षिक सरकारी व्यय		३६,३६२ रुपए
सन् १८८३ में शिक्षा-कुलक निम्नलिखित था:—		

अभिभावक की आय प्रारंभिक या लोअर या ११,१०, मिडिल हायर तीसरी  
विशुद्ध वार्षिकपुत्र ६,८,७,०० कक्षाएं ६,५,४ कक्षा आदि  
कक्षाएं

मासिक रुपए	रु. आ. पै.	रु. आ. पै.	रु. आ. पै.	रु. आ. पै.
रुपए	७ से १५	० १ ०	० ३ ०	० ४ ०
"	१५ से २५	० २ ०	० ५ ०	० ६ ०
"	२५ से ५०	० ३ ०	० ६ ०	० १२ ०
"	५० से १००	० ४ ०	१ ० ०	१ ८ ०
"	१०० से २००	० ६ ०	२ ० ०	२ ८ ०
"	२०० से ५००	० ८ ०	३ ० ०	४ ८ ०
"	५०० से १०००	० ८ ०	४ ० ०	५ ८ ०
"	१००० से अधिक	० ८ ०	५ ० ०	७ ० ०

सन् १८६६ में अजमेर-मेरवाड़ा में व्याप्त शिक्षा-प्रसार का अन्य प्रांतों से तुलनात्मक अध्ययन निम्न तालिका से संभव है।<sup>३८</sup> निम्न तालिका बंबई प्रेसीडेंसी की

है जहाँ स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या ४,०४४,६३६ थी तथा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ६४८,६४१ थी। इस तालिका में व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग इत्यादि सम्मिलित हैं :—

बम्बई :

क्षेत्र—१,६३,१४६ वर्गमील

कस्बे एवं ग्राम—४०,६६६।

जनसंख्या—२,६६,६६,२४२।

छात्रों की संख्या

११ आर्ट्स कॉलेजों में	१,६५६
४ व्यावसायिक कॉलेजों में	८६३
४६३ माध्यमिक स्कूलों में	४१,६७६
६,६३० प्राथमिक शालाओं में	५,३३,५७७
१८ प्रशिक्षण स्कूलों में	७६१
३१ विशेष स्कूलों में	२,०१६
२,७६२ निजी शिक्षण संस्थाओं में	६७,७८६
<b>कुल</b> १२,६७६ शिक्षण शालाओं में	<b>६,४८,६४१</b>

ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों बम्बई में प्रति १०० कस्बों एवं ग्रामों पर ३,१७७ शिक्षण संस्थाएँ थी और पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत १६ था।

मध्यप्रदेश में (सेन्ट्रल प्राविन्स) स्कूल जाने योग्य छात्रों की संख्या १६,४१,७२१ थी उसमें से १,४०,०६८ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।<sup>३६</sup>

	छात्र
३ आर्ट्स कॉलेजों में	३०१
२ व्यावसायिक कॉलेजों में	२६
२४६ सैकण्डरी स्कूल में	२५,४०६
२२३२ प्राथमिक शालाओं में	१,१४,०१३
५ प्रशिक्षण शालाओं में	१८१
४ विशेष स्कूलों में	१७१
<b>कुल</b> २४६२ संस्थाएँ	<b>१,४०,०६८</b>

प्रत्येक सौ कस्बों और ग्रामों पर लगभग ६ शिक्षण संस्थाएं थीं। इसमें स्कूल जाने योग्य छात्रों की संख्या का ६२ प्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इनमें निजी शिक्षण संस्थाओं की स्थिति उनकी रिपोर्ट में वर्णित नहीं होने से समझाव्यक्त नहीं है। इनके समावेश से भी संख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं होता क्योंकि वे सामान्य प्रारम्भिक स्तर की थीं। उत्तर-पश्चिम प्रांतों और अक्सर में जहाँ शिक्षा-योग्य बच्चों की संख्या १७,०३५,७६२ थी, शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र ३,५२,६७२ थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है \*—

	छात्र
२० आर्ट्स कालिजों में	१,८६३
६ व्यावसायिक कालिजों में	५७२
५०० सैकण्डरी स्कूलों में	५,६७२
६,२६२ प्राथमिक शालाओं में	२,१६,२७३
५ प्रतिशत विद्यालयों में	५६१
५० विशेष स्कूलों में	२,६२०
५,६३० निजी शिक्षण-संस्थाओं में	७१,५११
कुल १२,५०६ शिक्षण-संस्थानों में	३,५२,६७२

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रत्येक सौ कस्बों और ग्रामों पर २ शिक्षण-संस्थाएँ और स्कूल जाने वाले छात्रों का अनुपात ५ प्रतिशत था।

अजमेर-मेरवाड़ा जैसे छोटे से जिले में जहाँ स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या ८१,१५१ थी, वहाँ १०,७८० छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी। \*१

	छात्र
१ आर्ट्स कालिज	७३
१४ सैकण्डरी स्कूलों	२,६२०
५० प्राथमिक स्कूलों	४,२५४
१ प्रविशाल विद्यालय	१२
१३४ निजी शिक्षण-संस्थाएँ	३,५२१
कुल २०० शिक्षण-संस्थान	१०,७८०

इस तरह प्रत्येक सौ कस्बों और ग्रामों पर २० शिक्षण-संस्थाएँ थीं। स्कूल जाने योग्य छात्रों की संख्या तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का

अनुपात १३.५ प्रतिशत था। ऊपर दिए गए विवरण में कॉलेज के ७३ छात्र भी सम्मिलित हैं जो कि प्रथम वर्ष से लेकर चतुर्थ वर्ष तक की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे थे।

प्रान्त	प्रति सौ बच्चों एवं स्कूल जाने योग्य बच्चों ग्रामों पर शिक्षण संस्थाएं	में से स्कूल जाने वाले छात्रों का अनुपात	विशेष
बम्बई	३१.१७	१६	
मध्यप्रदेश	६००	७.२	इनमें प्राइवेट शिक्षण- संस्थाओं का समावेश नहीं है।
उत्तर-पश्चिमी सूबे एवं धवघ	१२	५	
भजमेर-मेरवाड़ा	२७	१३.५	

इस तरह भजमेर-मेरवाड़ा में शिक्षा प्रसार उल्लेखनीय गति से विकास कर रहा था और उपर्युक्त आंकड़े इस तथ्य को बताते हैं कि इस छोटे से जिले में भी शिक्षा के प्रति अत्यधिक जागृति हो चुकी थी।<sup>५२</sup>

विभिन्न स्तरों पर विभाजित विद्यार्थियों की संख्या एवं प्रतिशत निम्ना-  
कित था।<sup>५३</sup>

प्रान्त	कॉलेज	सैकण्डरी	प्राथमिक स्कूल	अन्य निम्नी शिक्षण- संस्थाएं
संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत	संख्या प्रतिशत
बम्बई	२५१६ .३६	४१६७६	६४७	५३३५६६ ८२.२६ ७०४६६ १०.८८
मध्यप्रदेश	३२७ .२३	२५४०६	१८.१४	११४०१३ ८१.३८ ३५२ २५
उत्तर- पश्चिमी सूबे	२४३५ .६६	५६१७२	१६.७६	२१६२७३ ६१.२७ ७५०६२ २१.२८
एवं धवघ				
भजमेर- मेरवाड़ा	७३ .६८	२६२०	२७.०६	४२५४ ३६.४६ ३५३३ ३२.७७

कुल संख्या	प्रतिशत
६४८६४१	१००
१४००६८	१००

निजी शिक्षण-संस्थाएँ सम्मिलित थी :-

३४२६७२	१००
१०७८०	१००

सबसे पहले सन् १८६४ में एक मिशनरी स्कूल मसूदा में खोला गया। इसके बाद भिनाय और बीर में भी मिशन स्कूल खुले। सन् १८८१ में ईसपेक्टर स्कूल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि टाटोटी, परायड़ा, सुकरानी, मसूदा, भिनाय और बीर में सरकारी स्कूल खोले जाने चाहिए। रीड ने रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा कि मिशन स्कूलों जनता में लोकप्रिय नहीं हैं व सभी जगह सरकारी स्कूलों खोलने पर बहुत जोर दिया जा रहा है तथा जिले के अधिकांश ग्रामीणों को सरकारी स्कूलों के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता है।<sup>४४</sup> मिशन स्कूलों की कार्य-प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए रीड ने लिखा "सभी दृष्टिकोणों से मैं यह विश्वास करने पर बाध्य हुआ हूँ कि क्षेत्र में मिशन स्कूलों लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुई हैं और वे जो शिक्षा प्रदान कर रही हैं वह बहुत थोड़ी है। दुर्भाग्य से इन्होंने जिले के बड़े कस्बों को अपना कार्य-क्षेत्र चुना है परन्तु मेरा यह मत है कि अब वह समय आ गया है जब इस जिले के बड़े कस्बों को सरकारी स्कूलों के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता है।"<sup>४५</sup>

एक अन्य पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा "मिशन स्कूलों जनता की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रही हैं। मसूदा और टाटोटी के ठाकुरों ने मुझ से कई बार अनुरोध किया है कि मैं उनके वहाँ सरकारी स्कूलों खोले जाने के लिए सरकार से सिफारिश करूँ और भिनाय ठाकुर (जिनसे मैं आज तक मिला तक नहीं) ने भी बार-बार यही अनुरोध मेरे डिप्टी इस्पेक्टर से किया है।"<sup>४६</sup>

इस संदर्भ में रीड का दृष्टिकोण नवीन नहीं था। इसी तरह का मत प्रशासनिक पुनर्गठन के समय, कुछ वर्षों पूर्व, मेजर डब्ल्यू वाईट ने प्रकट किया था। सन् १८७७-७८ की अपनी रिपोर्ट में मेजर डब्ल्यू वाईट ने भी मिशन स्कूलों की प्रशंसा नहीं की थी। सामान्यतः जिले में सर्वत्र लोगों ने उन्हें धनवीकार ही किया। रीड के प्रसंगों का मुख्य कारण इन मिशन स्कूलों में शिक्षा का निम्न स्तर था।<sup>४७</sup> उसने स्पष्ट कहा कि "२१ वर्षों तक बिना हस्तक्षेप किए इन्हें परीक्षण का अवसर दिया गया था परन्तु ये अपने वर्तमान सिद्ध हुए और अब यदि उनके हितों की प्रतीक्षा जनता के अवधिक आवश्यक हितों को प्राथमिकता दी जाती है तो उन्हें प्रसंगीय प्रकट नहीं करना चाहिए।"<sup>४८</sup>

म्याजर मिशन स्कूलों के सुपरिंटेंडेंट डी० डी० स्वनब्रेड ने रीड द्वारा सरकारी स्कूलें खोलने की राज्य की नीति के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया था।<sup>५६</sup> भ्रजमेर के कमिश्नर एवं निदेशक शिक्षा-विभाग सॉडर्स को उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में यह प्रसंतोष पूर्णतया स्पष्ट है। इस पत्र में उन्होंने यह सच कहा है कि इस तरह के सरकारी स्कूल खोलना सार्वजनिक धन का प्रपञ्चय मात्र है।<sup>५७</sup> मिशन के अधिकारियों ने भी भारत के वायसराय रिपन को एक आपन प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया था कि "मिशन स्कूलें जनता की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्णतया पूर्ति कर रही हैं। इन सभी में उन छात्रों की मिलित करने की पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य है जो स्कूल में उपस्थित होते हैं और नए सरकारी स्कूल खोलने का परिणाम पहले की तरह कटुता एवं द्वेष का आतावरण होगा।"<sup>५८</sup> इस तरह के आपन का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।<sup>५९</sup>

सन् १८८१ में, पाँच सरकारी स्कूलें भेंदडा, टाटोटी, मसूदा, परायड़ा और मिनाय में खोली गईं।<sup>६०</sup> मसूदा में मिशन और सरकारी स्कूल दोनों थे। वहाँ के संबंध में सन् १८८२ में हेरिल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मसूदा के अधिकांश लोग सरकारी स्कूल के जारी रखने के पक्ष में हैं और छात्रों की संख्या एवं उनके शैक्षणिक स्तर के दृष्टिकोण से सरकारी स्कूल अपने प्रतिद्वन्द्वी (मिशन स्कूल) से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं।<sup>६१</sup> यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गत सदी के अन्तिम बीस वर्षों में मिशन स्कूलों की असंतोषजनक स्थिति के कारण ही सरकारी स्कूलें स्थापित करने की नीति को प्रोत्साहन मिला था।

इस बात की संभावना पहले से ही थी कि भ्रजमेर जहाँ की अधिकांश जन-संख्या हिंदुवादी व पिछड़ी हुई थी उसमें शिक्षा की गति धीमी रहेगी।<sup>६२</sup> सन् १८७१ में भ्रजमेर में महिला नॉर्मल स्कूल स्थापित कर उसके साथ लड़कियों का एक स्कूल भी (कन्या शाला) सम्बद्ध कर दिया गया। १८७५-७६ में महिला नॉर्मल स्कूल में १२ व स्कूल में १६ छात्राएँ थी।<sup>६३</sup> लड़कियों ने सीने-पिरोने के प्रशिक्षण को अधिक पसंद दिया और इसी प्रशिक्षण से लड़कियाँ इस स्कूल की और आकर्षण में आकर्षित हुईं। १८८०-८१ में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को मिलाकर १६ स्कूलों में ५६७ लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही थी। शिक्षा योग्य महिलाओं की संख्या के अनुपात में इनका प्रतिशत १.५ था। धीरे-धीरे महिला-शिक्षा के प्रति प्रचलित अंधविश्वास कम होता गया। मुसलमान महिलाएं अपनी पर्दानशीनी के कारण और राजपूत महिलाएं अपनी जातिगत सकीर्णता के फलस्वरूप इस क्षेत्र में काफी पिछड़ी रहीं। भ्रजमेर-भेरवाड़ा की जनता के लिए महिला-शिक्षा एकदम 'अनूठी' और नवीन बात थी। इसकी धीमी गति होना भावचर्यजनक नहीं था।



[सन् १८८१ में, प्रांत में यूरोपीय छात्रों के लिए सिर्फ एक रेल्वे स्कूल अजमेर में था।<sup>१७</sup> उस वर्ष इसमें छात्रों की संख्या २६ थी और सन् १८९१ में यह बढ़कर ६४ तक पहुँच गई थी। सन् १८९६-९७ में यूरोपीय लड़के-लड़कियों के लिए एक स्कूल रोमन कैथोलिक कान्वेंट ने अजमेर में शुरू किया। इसने शीघ्र ही सभी रोमन कैथोलिक माता-पिता का ध्यान आकृष्ट कर लिया और रेल्वे स्कूल के छात्रों की संख्या घट कर सन् १९०३ में ५४ रह गई, जबकि कान्वेंट स्कूल में ८८ छात्र-छात्राओं की संख्या थी। दोनों ही सैकेंडरी स्तर की स्कूलें थी जिन्हें सरकार से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता था।<sup>१८</sup>

अजमेर-मेरवाड़ा में प्राथमिक शिक्षा-प्रसार के लिए गठ शताब्दी के चतुर्थ दशक में किए गए आरम्भिक प्रयास असफल रहे। वास्तविक आधार तो सन् १८५१ में स्थापित हुआ और शिक्षा का प्रसार तेजी से होने लगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति लोगों का अविरवास और संदेश भी सुप्त हो गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवर्न-मेण्ट कॉलेज की स्थापना और मेयो कॉलेज खोलने की घोषणा महत्वपूर्ण कदम थे। ये संस्थाएँ बुनियादी स्तर पर टाकुरों और राजबादों के राजपराने के लोगों के लिए थीं। सन् १८९६ में बी०ए० विषय तथा सन् १९१३ में बी० एस० सी० के विषय मूल जाना अजमेर-मेरवाड़ा के शैक्षणिक क्षेत्र में विकास के लक्षण थे।

महिला-शिक्षा इतना व्यापक स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकी इसके मूल में लोगों की पुराणपंथी मनोवृत्ति और सामाजिक पिछड़ापन बाधक था। गठ शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मिशनरियों ने भी प्रमुख कस्बों और ग्रामों में कई स्कूलों की स्थापना की, परन्तु मिशन स्कूलें लोगों में लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकी और उनका शैक्षणिक स्तर भी मामूलीतः काफी गिरा हुआ था।

## अध्याय ८

१. साई मेकॉले के भाषण—तांगमेन्स—चंदन (१८९३) पृ० २२३-२५।
२. उपरोक्त पृ० ७८।
३. एनीबेसेन्ट, इन्डिया ए नेशन, मद्रास १९२३ पृष्ठ १०१।
४. उपरोक्त

“यद्यपि यह सच है कि अंग्रेजी शिक्षा का ध्येय ईसाई मिशनरियों को है तथापि यह भी सही है कि उनका ध्येय शिक्षा न होकर धर्म-परिवर्तन

या तथा शिक्षा उसका माध्यम था। भारतीयों ने ईसाई धर्म की प्रवहेलना करते हुए शिक्षा का पूर्ण कायदा उठाया।

५. शिक्षा सिर्फ देशी स्कूलों में दी जाती थी। सन् १८४५-४६ में इनकी संख्या ५६ थी जिनमें से ४२ हिन्दी व संस्कृत पाठशालाएँ थीं व इनमें ८०७ छात्र अध्ययन करते थे तथा १४ फारसी व अरबी के मदरसे थे जिनमें २६६ छात्र थे। अजमेर व भादपुरा में १३ फारसी व २० हिन्दी के स्कूल थे तथा शेष भागों में थीं। राजपूत, शिक्षा के प्रति उदासीन थे। इस जाति के कुछ विद्यार्थी हिन्दी स्कूलों में भवश्य थे परन्तु फारसी मदरसे में एक भी नहीं था। (फाइल न० ६६ भार० एस० ए० बी०)।
६. इन स्कूलों में से अजमेर में ४५, पुष्कर में ५६, भिणाय में १६, कैकड़ी में १६ व रामसर में १६ विद्यार्थी थे। (फाइल नम्बर ६६ भार० एस० ए० बी०)।
७. फाइल क्रमांक ६६।
८. अजमेर देहात पाठशालाओं के निरीक्षक एस० डब्ल्यू कॉलन द्वारा एच० एस० रीड को पत्र दि० १ अक्टूबर, १८५६ पत्र संख्या ३८।
९. कर्नल सदरलैंड ए० जी० जी० राजपूताना द्वारा सचिव, भारत सरकार को पत्र, दि० १० मार्च, १८४७।
१०. अजमेर देहात पाठशालाओं के निरीक्षक एस० डब्ल्यू कॉलन द्वारा एच० एस० रीड को पत्र, दि० १ अक्टूबर, १८५६ पत्र संख्या ३८।  
 "कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली में इस आशय की प्रफवाह फैली थी कि देहली कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रवेशी पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा, इसे लोगों ने ईसाईमत का पर्याय मान लिया था। इसी तरह अजमेर में भी सैनिक विद्रोह के दिनों में यह प्रफवाह फैली थी कि गवर्न-मेंट स्कूल के विद्यार्थियों की जाति नष्ट करने के लिए उनमें एक विशिष्ट मिठाई वितरित की जाएगी। दोनों ही मामलों में कुछ अभिभावकों ने सतर्कतावश अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए स्कूल भेजना स्थगित कर दिया था, परन्तु जब ये प्रफवाहें निर्मूल सिद्ध हुईं तो वे उन्हें पुनः स्कूल भेजने लगे।"
११. सन् १८५३ में कुल २३० विद्यार्थी थे जिनमें ४४ मुसलमान और १८६ हिन्दू थे। सन् १८६१ में यह स्कूल कलकत्ता विश्वविद्यालय से मर्जित था और सन् १८६८ में इसे कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। परन्तु शिक्षकों की संख्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम कक्षा

परीक्षा के शिक्षण के लिए आवश्यक सीमा तक ही निर्धारित रखी गई थी।

१२. उत्तर-पश्चिमी प्रांत के सहायक सचिव द्वारा सचिव, भारत सरकार को पत्र, दिनांक ३ अप्रैल, १८४७।

१३. उपरोक्त।

१४. उपरोक्त।

१५. प्रोफेसर हॉन व डा. फालोन के निदेशन में स्कूल ने बड़ी तरफकी की थी।

१६. सर चार्ल्स ब्रुक ने सन् १८५४ में अपना बहुचर्चित संदेश प्रसारित किया जिसमें यूरोपीय ज्ञान के व्यापक प्रसार, प्रजा के नैतिक मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा उच्चतम योग्यता के सरकारी कर्मचारियों की प्राप्ति के सुभाव निहित थे। सरकारी व्यय से अधिकतम प्रजा को सभी उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान देने की योजना सुझाई गई थी। प्रत्येक जिले में ऐसी स्कूलें खोलने का सुभाव दिया गया था जो स्थानीय भाषा के माध्यम द्वारा उच्चतम शिक्षा प्रदान कर सकें। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर कालेज एवं विश्वविद्यालय के स्तर तक शिक्षा को पहुँचाने का लक्ष्य एवं इन माध्यम का शिक्षा कम इसमें निर्धारित किया गया था। उक्त संदेश पर आधारित सरकारी आदेश के अन्तर्गत जनता में व्याप्त अशिक्षा की समाप्ति के लिए शिक्षा-विभाग की स्थापना की गई। एस० डब्ल्यू फॉलन द्वारा एस० एस० रीड को प्रेषित पत्र, दिनांक १ अक्टूबर, १८५६ पत्र संख्या ३८।

१७. सी० एच० डिमेती कार्यवाहक प्रिंसिपल अजमेर कालेज द्वारा कर्नल ब्रूक्स ए० जी० जी० राज० को पत्र, दिनांक १३ अक्टूबर, १८७०; सन् १८८८ में कालेज अलाहाबाद विश्वविद्यालय में सम्बन्धित था और सन् १८६६ तक कालेज का शिक्षणस्तर प्रथम कला वर्ग भवना इंटरमीडियेट से प्राप्ति नहीं बढ़ पाया था। सन् १८६६ में ४२ विद्यार्थी एंट्रेंस कक्षा में पढ़ रहे थे जो मैट्रिक परीक्षा भी तैयारी कर रहे थे, जबकि चार कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ५५ थी। (द्यूम पाक, अजमेर-मेरवाड़ा की मैट्रिक्स टोपोग्राफिकल रिपोर्ट) पृ० ८८।

१८. सी० एच० डिमेती द्वारा निदेशक, शिक्षा-विभाग को पत्र दिनांक ७ नवम्बर, १८७०।

१९. उपर्युक्त।

२०. उपर्युक्त।

२१. उपयुक्त ।

२२. उपयुक्त ।

२३. उपयुक्त ।

२४. सी० यू० एचीसन द्वारा डिप्टी कमिश्नर भजमेर को पत्र दिनांक १२ जनवरी, १८७१ "इस योजना को प्रस्तुत करने में वायसराय एवं कौंसिल का मुख्य उद्देश्य राजाघों और राजपूताने की प्रजा की हवि शिक्षा के प्रति जागृति कर इस क्षेत्र में उनकी सहानुभूति प्राप्त करना है । ऐसी आशा है कि रियासतों के शासक स्वयं इतने समझदार हैं कि वे रियासतों के मध्य ऐसी संस्था की संरचना के साम को अच्छी तरह से समझते हैं ।"

२५. जे० डी० लाह्ला-गजेटीयर्स भजमेर-मेरवाड़ा (१८७५) पृ० ६२

२६. धौलपुर, जैसलमेर और झुंजरपुर की तीन रियासतों ने धारम्भ में इस कोष में भनुदान राशि नहीं दी थी परन्तु बाद में झुंजरपुर और जैसलमेर ने भनुदान राशि प्रदान कर दी थी । जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, आलावाड़, अलवर तथा टोक रियासतों ने कॉलेज पार्क में छात्रावास भवनों का ४,२८,००० रुपए की लागत से निर्माण करवाया था तथा उस पर वार्षिक व्यय लगभग १८,५६०० रुपए किया जाता रहा । इस राशि में हाऊस मास्टर और कर्मचारियों का वेतन भी समाहित था ।

२७. जे० डी० लाह्ला गजेटीयर्स भजमेर-मेरवाड़ा (१८७५) पृ० ६२ ।

२८. "गत बीस वर्षों से शिक्षा की भजमेर और राजपूताने में बहुत प्रगति हुई है । सन् १८७६ में २१ विद्यार्थी मेट्रिक की परीक्षा में बैठे थे जबकि सन् १८९६ में इन विद्यार्थियों की संख्या २०० हो गई थी । यदि उचित सुविधाएं प्राप्त होती रहीं, तो यह निश्चित है कि इनमें से अधिकांश विद्यार्थी बी० ए० तक शिक्षा जारी रख सकेंगे जिससे उन्हें सरकारी विभागों एवं राजवाड़ों में आजीविका प्राप्त हो सकेगी ।"

एफ० एल० रीड, प्रिन्सिपल गवर्नमेंट कॉलेज भजमेर द्वारा प्रसारित विज्ञापित दिनांक २३ मार्च, १८९६ ।

२९. प्रिन्सिपल रीड की विज्ञापित दिनांक २३ मार्च, १८९६ ।

३०. कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा तथा ए० जी० जी० राजपूताना को पत्र दि० २३ जून, १८९६ ।

निम्न तालिका का बी० ए० की वृक्षा को प्रारम्भ करने के लिए प्राप्त वार्षिक सहायता की सूचक है —

## अ—ठाकुर तथा इस्तमरारवार

१—रावबहादुरसिंह मसूदा	रुपए	३,०००
२—देवलिया ठाकुर	"	५००
३—दातरी ठाकुर	"	४००
४—सावर ठाकुर	"	१,०००
५—सरवा ठाकुर	"	१०
६—गोविंदगढ़ ठाकुर	"	७५
७—ठाकुर सरदारसिंह	"	७५
८—नवाब शम्सुद्दीन अलीखान	"	११०

## ब—सेठ एवं साहूकार

९—सेठ खंपालाल	रुपए	५,०००
१०—सेठ समीरमल	"	२,०००
११—सेठ मूलचन्द सोनी	"	२,०००
१२—सेठ सोभागमल	"	७००
१३—सेठ यमनालाल	"	४००
१४—सेठ हरनारायण	"	३०१
१५—भूतपूर्व विद्यार्थी एवं अन्य	"	१०,३३०

कुल योग

२८,५२६

(परिशिष्ट सूची सलग पत्र संख्या ३७७-८ दिनांक २३ नवम्बर, १९०५ त्रिनिटियल गवर्नमेन्ट कॉलेज अजमेर द्वारा कमिशनर, अजमेर-मेरवाड़ा को प्रेषित)

३१. शिक्षा-विभाग भारत सरकार द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति, २१ फरवरी, १९१३, सं० ३०१ सी० डी० ।
३२. फाइल क्रमांक २२८ सन् १९१३-१४ (कमिशनर कार्यालय, अजमेर) ।
३३. रजिस्ट्रार इलाहाबाद त्रिभुवनविद्यालय द्वारा त्रिनिटियल गवर्नमेन्ट कॉलेज अजमेर को पत्र, दि० २० जनवरी, १९१४ संख्या २८० ।

कॉलेज के पास एक अच्छा पुस्तकालय था उसके अहाते में छात्रावास भवन भी था जिसमें नार्मल स्कूल में पढ़ते बाले छात्र तथा देहातों से आए हुए छात्ररूति प्राप्त छात्रों के लिए रहने एवं खाने की व्यवस्था थी । इस

छात्रावास में पचास छात्रों की व्यवस्था थी। कॉलेज के कर्मचारी वर्ग में १ प्रिन्सिपल, संस्थाधों के प्रधानाचार्य, ६ प्रोफेसर, १३ प्राप्तेजी के शिक्षक, ६ पंडित, ६ भोसवी एवं १ पुस्तकालय व्यवस्थापक की व्यवस्था थी। (हुरेल पाक, मेडिको टोपोग्राफिकल रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा पृष्ठ ८८)।

३४. शिक्षा-कर की अलोकप्रियता का अनुमान इसी से आँका जा सकता है कि सन् १८५७ में जब भिनाय राजा की साली सती होने लगी तो पंडितों ने उसकी चिता के चारों ओर खड़े होकर उक्त सती से अपने प्रभाव द्वारा देहाती स्कूलों पर लगने वाले कर की समाप्ति की याचना की।

३५. फाइल क्रमांक २२६ सन् १८१३, कमिशनर कार्यालय, अजमेर। सन् १८७६-७७ में जिला पाठशालाओं का पुनर्गठन किया गया था। इन्हें सरकार से आर्थिक सहायता तथा ३२ वापिक शुल्क में से (१ प्रतिशत) अनुदान मिलता था। सन् १८७६-७७ से लेकर सन् १९०० तक इन पाठशालाओं की संख्या में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ था। इनकी संख्या घटावत रही। सन् १८७६ में इन पाठशालाओं के नियमित छात्रों की संख्या १७७० थी, सन् १९०० में छात्रसंख्या ४०८५ थी जिसमें २७८८ छात्र अजमेर के तथा १२९७ छात्र मेरवाड़ा के थे। अजमेर-मेरवाड़ा की मेडिको टोपोग्राफिकल रिपोर्ट हुरेल पाक पृ. ८८।

३६. क्षेत्र में १६ एडवांस्ड स्कूल भी थी जो सार्वजनिक संस्थाधों द्वारा संचालित होती थी।

३७. दो तरह की स्कूलें थी—एक तो सहसीन स्कूलें अथवा वर्निक्यूलर मिडिल स्कूलें एवं दूसरी हलकाबंदी या वर्निक्यूलर एलीमेंटरी स्कूलें थीं। सहसीन स्कूलों का सम्पूर्ण भार सरकार द्वारा वहन किया जाता था। स्कूल भवनों का निर्माण तथा शिक्षकों का वेतन सरकार चुकाती थी। सामान्य प्रभार की पूर्ति विद्यापियों के शिक्षा शुल्क से की जाती थी। हलकाबंदी स्कूलें जमींदारों से उगाहे गए शिक्षा शुल्क पर निर्भर थी—  
बिद्यालय-निरीक्षक द्वारा एस. एस. सॉटन को पत्र, दिनांक २८ अगस्त, १८७१।

३८. ई. एफ. हेरिस, कार्यवाहक प्रिन्सिपल गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर द्वारा कमिशनर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दि. १८ जुलाई, १८८६ संख्या २६५।

३९. उपर्युक्त।

४०. उपर्युक्त।

४१. उपर्युक्त ।
४२. उपर्युक्त ।
४३. उपर्युक्त ।
४४. विद्यालय निरीक्षक, अजमेर की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष सन् १८८०-८१ से प्रकृत उद्धरत ।
४५. उपर्युक्त ।
४६. रीड, प्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट कालेज द्वारा सौड्स कमिशनर अजमेर के पत्र, दि. ११ दिसम्बर, १८८१ ।
४७. रीड का कथन है कि उन्होंने मसूदा मिशन स्कूल का निरीक्षण करने पर यह देखा कि अठ्ठाई साल की शिक्षा के बाद भी छात्र साधारण गुणा करने में असमर्थ थे । अन्य विषयों में भी उनका सामान्य ज्ञान बहुत ही निम्न स्तर का था । टांटोटी मिशन स्कूल में चार साल की शिक्षा के पश्चात् भी छात्र सामान्य ज्ञान से अधिक भागे नहीं बढ़ सके थे । ध्यावर स्कूल भी पुराने रिर्कोंहों की भाँति तथा व्यक्तिगत निरीक्षण से पूर्णतया असंतोषजनक सिद्ध हुआ था । रीड प्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट कालेज, अजमेर द्वारा सौड्स कमिशनर अजमेर को पत्र दि. ११ दिसम्बर, १८८१ ।
४८. सौड्स, कमिशनर अजमेर को पत्र दिनांक २२ जून, १८८१ ।
४९. स्कूलब्रेड द्वारा कमिशनर एवं शिक्षा निदेशक अजमेर को पत्र दिनांक २२ जून, १८८१ ।
५०. स्कूलब्रेड द्वारा सौड्स को पत्र दिनांक २६ जून, १८८१ ।
५१. सन् १८८१ में आयोजित मिशन कांफ्रेंस की ओर से स्कूलब्रेड एवं जे. प्रो. द्वारा वायसराय को प्रस्तुत ज्ञापन, फाइल क्रमांक १८ ।
५२. रीड द्वारा सौड्स कमिशनर अजमेर को पत्र, फाइल दिनांक ११ दिसम्बर, १८८१ ।
५३. मसूदा स्कूल २० जून, १८८१ को बुला और शीघ्र ही ८० बच्चे भरली हो गए थे ।
५४. हेरिड द्वारा विशेष रिपोर्ट दिनांक २८ जून, सन् १८८२,
५५. सन् १८९७ में महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल पुष्कर में खोला गया था परन्तु यह परीक्षण सफल नहीं हुआ, क्योंकि इन स्कूल के अध्यापिका पद के लिए शिक्षित महिलाएं उपलब्ध नहीं हो

पाई थी। प्रिंसिपल भजमेर कॉलेज द्वारा एल. एस. साडर्स कमिशनर, भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दि. १७ फरवरी, १८७२।

५६. निरीक्षिका महिला नार्मल स्कूल द्वारा निरीक्षक शिक्षा विभाग भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र—फाईल संख्या ११।
  ५७. मैनेजर राजपूताना-भासवा रेल्वे द्वारा ए० जी०जी० के प्रथम असिस्टेंट को पत्र, दि० २५ अप्रैल, १८८२ (पत्र संख्या ५७०६)।
  ५८. रेल्वे स्कूल को मासिक सहायता ७५) रुपया व कानवेन्टे स्कूल को १००) रुपया मासिक थी।
-



## जनता की आर्थिक स्थिति

सन् १८५७ के सैनिक विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग नहीं लिया था और ग़दर एक गरजते बादल की तरह बिना बरसे ही भ्रजमेर के राजनीतिक आकाश से गुज़र गया था।<sup>१</sup> किन्तु इससे यह अनुमान लगाना ग़लत होगा कि भ्रजमेर-मेरवाड़ा की जनता अंग्रेज़ी प्रशासन के अन्तर्गत सुखी और समृद्ध थी।

भ्रजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेज़ों के शासन के अन्तर्गत किसानों की दयनीय स्थिति बराबर बनी रही। इसका मुख्य कारण यह था कि मराठों ने अपने शासन के अन्तिम वर्ष में जो लगान की रकम वसूल की थी उसी को आधार मानकर अंग्रेज़ सरकार इस पूरे क़ास में अपनी लगान की राशि को निर्धारित करती रही। ख़ालसा-क्षेत्र में केवल उन्हीं किसानों को भूमियाँ ठिकाने में हूक प्राप्त थे, जो अपनी भूमि में कुँभा, नाड़ी, मेढ़बंदी आदि का निर्माण करते थे।<sup>२</sup> अतिरिक्त और चंजर भूमि पर सरकार का स्वामित्व था।<sup>३</sup> अंग्रेज़ों के शासन के प्रारम्भिक काल में लगान की दर फसल का आधा हिस्सा होती थी। सरकार किसानों की चिरी हुई हात से अनभिज्ञ थी। उनके द्वारा निर्धारित राशि अपूर्ण एवं अविश्वस्त आँकड़ों पर आधारित थी।<sup>४</sup> लगान निर्धारित करने में उनका दृष्टिकोण सिर्फ़ राजस्व की वृद्धि करना होता था।<sup>५</sup> उन्होंने लोगों की स्थिति जानने का कभी प्रयत्न किया ही नहीं।<sup>६</sup> मेरवाड़ा में जमीन पथरीली होने के कारण बाघी फसल लगान के रूप में देना किसान की क्षमता के बाहर था। कुछ समय के लिए सरकार ने यह व्यवस्था

भी करदी थी कि अगर किसी गाँव में किसान के गाँव छोड़कर चले जाने या कृषि के धन्ये का परित्याग कर देने के कारण लगान की राशि में जो कमी होगी तो उसकी पूर्ति उन लोगों को करनी पड़ती थी जो खेती नहीं करते थे । इसने लोगों पर कर का भार बढ़ा दिया था ।<sup>१०</sup> यद्यपि बाद में लगान की दर आधी से घटा कर ३ कर दी गई थी,<sup>११</sup> परन्तु इसने भी किसानों को वास्तविक राहत प्रदान नहीं की, क्योंकि धारम्म में निर्धारित कर की दर इतनी ज्यादा थी कि उसका ३ हिस्सा भी किसानों के लिए अधिक था । सरकार ने सिंचाई के लिए कुछ तालाबों आदि का निर्माण अवश्य कराया परन्तु इसमें भी सरकार का दृष्टिकोण किसान को सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने के बजाय अपनी राजस्व की धार की वृद्धि की नीयत रहती थी । सिंचाई के साधन भी सरकार अपनी धोर से तैयार नहीं करवाती थी । जब कभी कोई नया तालाब बनाया जाता था या पुराने की मरम्मत की जाती थी तब कराधान के समय निर्माण का व्यय का अर्ध प्रतिरिक्त जोड़ा जाता था । कर्नल डिवसन जैसे व्यक्ति ने भी लगान की दर इतनी ऊँची निर्धारित की थी कि उसे अच्छे वर्षों में ही वसूल किया जा सकता था । कर्नल डिवसन ने यद्यपि अकाल व सूखे की स्थिति में लगान में आवश्यकतानुसार छूट की व्यवस्था रखी थी परन्तु सन् १८८०-८४ के बीच अजमेर में केवल ६५५ रुपए तथा मेरवाड़ा में कुल ५६१ रुपए की छूट दी गई थी ।<sup>१२</sup> इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राहत सिर्फ दिखावा मात्र थी । इस्तमरारदारी क्षेत्र में लगान के कड़े नियमों के बाद भी खालसा क्षेत्र के ग्रन्थ किसानों की तुलना में वहाँ के किसानों की स्थिति ठीक थी । खालसा-क्षेत्र के किसान भारी कर्ज में डूबे हुए थे ।<sup>१३</sup>

मराठा शासनकाल से इस्तमरारदारी क्षेत्र में किसानों की हालत खराब होने लगी थी । मराठों की नीति थी "जितना लिया जा सके ले लो ।" वे मनमाने कर इस्तमरारदारी से वसूल करते थे ।<sup>१४</sup> इस्तमरारदार जितना धन मराठों को प्रदान करते थे वह उनके द्वारा किसानों से वसूल किया जाना स्वभाविक था । मराठा काल में लगभग ४० कर व उपकर प्रचलित थे । इस कारण मराठा काल में किसानों से कई नये कर व उपकर वसूल किए जाने लगे । मुगलकाल में इन ठिकानेदारों को अपने ठिकाने छिड़ने का भय बना रहा था परन्तु मराठों ने नकद भुगतान के एवज में उन्हें अपने ठिकानों का स्थाई स्वामी बनाकर उन्हें निरकुश अधिकार प्रदान कर दिए थे ।<sup>१५</sup> मराठों की मुख्य इच्छा धन बटोरने की थी । उन्होंने इन ठिकानेदारों को भूमि का स्वामी बना कर किसानों को पूर्णतया उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था । इस कारण ठिकानेदारों को अपने ठिकाने में रहने वाली जनता पर प्रसीमित अधिकार प्राप्त हो गए थे ।<sup>१६</sup> अंग्रेजों ने इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया । अंग्रेज सरकार ने सन् १८७७ में इस्तमरारदारों पर प्रतिरिक्त कर समाप्त करते समय भी इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि उसी अनुपात में करें व लागवागो

से ग्राम जनता को राहत मिले।<sup>१४</sup> इसका परिणाम यह हुआ कि इस्तमरारदार को अधिक राहत मिलने के बाद भी जनता करों से पहले के समान ही दबी रही।<sup>१५</sup> सिर्फ उन चन्द व्यक्तियों को छोड़कर जिनके परिवार उस ठिकाने में इस्तमरारदार के आगमन के पूर्व से बसे हुए थे, शेष जनता को अपने मकानों की बेचने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था।<sup>१६</sup> अंग्रेज सरकार ने सन् १८७७ के भूमि एवं राजस्व विनियम की धारा २१ में अन्तर्गत ठिकानों में किसान को इस्तमरारदार की भूमि पर किरायेदार का स्थान दे दिया था। इस्तमरारी ठिकानों में किसान को भूमि पर ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था कि जिसके अन्तर्गत किसान ठिकानेदार के अप्रसन्न होने पर भी उस ठिकाने में रह सकता था।<sup>१७</sup> कठोर कर और धमुरक्षा के कारण ठिकानों में किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी।<sup>१८</sup> किसान को अपनी उपज का साठ प्रतिशत ठिकानेदार को लगान व अन्य सागवामों के रूप में दे देना पड़ता था।<sup>१९</sup> इस्तमरारदारी क्षेत्र में किसान को उनकी बेदखली के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे।<sup>२०</sup> अंग्रेज सरकार ने सार्वभौम सत्ता होने के नाते नागरिकों के अधिकारों के प्रश्न पर भी ठिकाने की जनता को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न नहीं किया था।<sup>२१</sup>

भायः प्रतिवर्ष अकाल पड़ने से क्षेत्र की जनता की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी। सन् १८१६, १८२४, १८३३, १८४८, १८६८, १८६०-६२, १८६८-१९०० और १९०१-१९०२ के अकाल वर्षों ने क्षेत्र में सुखमयी की स्थिति पैदा कर दी थी, जिससे लोगों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पूर्णतया नष्ट हो गया था।<sup>२२</sup> गरीब जनता राहत के लिए कराहने लगी थी। पारिवारिक बंधन शिथिल हो गए थे। क्षेत्र के तीन-चौथाई मजदूरी नष्ट हो गए थे। सन् १८७६ में राजपूताना-मालवा रेल मार्ग ने नौतिक समृद्धि के आसार उत्पन्न किए परन्तु इससे विशेष फर्क नहीं हुआ। अजमेर शहर की जनसंख्या भी पहले की अपेक्षा दुगुनी हो गई थी। शहर का महत्व बढ़ा एवं विस्तार भी हुआ परन्तु जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर अकालों के इतने गहरे प्रहार हुए कि अजमेर इनकी शक्तिपूर्ति करने में असमर्थ रहा और इसकी प्रगति में ये विपदाएं बहुधा बाधक ही बनीं रहीं।<sup>२३</sup>

अजमेर-मेरवाड़ा जिले की अधिकांश जनता कृषि प्रधान थी अतएव इस उद्यम को समझ लेने मात्र से ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि निरंतर अकालों एवं सूखों की स्थिति ने कितनी गंभीर शक्ति पहुँचाई होगी। भौगोलिक जनसंख्या केवल १७७४ प्रतिशत थी जो मुख्यतया कपास एवं चमड़े के उद्योगों, किराना एवं परचून के घंघों और रेल्वे वर्कशॉप में लगी हुई थी। खेतिहर मजदूरों के प्रतिरिक्त सामान्य श्रमिक की जनसंख्या १०२६ प्रतिशत थी। निम्नी नौकरियों और सरकारी में ४.६१ और ४.२१ प्रतिशत व्यापार में लगी हुई थी। स्वयंज साधन वाले लोग

मुश्किल से १.८०, प्रतिशत थे जबकि रोजगार एवं सरकारी सेवाओं में लगे लोग २.५६ और २.३८ प्रतिशत थे। अतः यह स्वामाविक था कि अकाल के वर्षों ने अधिकांश जनता पर क्रूर प्रहार किया और यहाँ के उद्योग चंचों पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा। २४

मुश्किल से १.८० आर्थिक कठिनाइयों के साथ ही कुछ तो शिधा प्रसार और बहुत कुछ सामाजिक-आर्थिक आन्दोलनों के फलस्वरूप राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी जिसने की लोगों में निराशा का भाव पैदा हुआ। इस निराशा की भावना ने अंग्रेज शासन के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न की। २५

यद्यपि यह जिला सन् १८५१ में नियमित व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया था तथा कर्नल डिक्सन के समय में कृषि आदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए परन्तु साथ ही यह तथ्य भी साफ है कि अंग्रेजों ने राजस्व के रूप में जहाँ दो सौ की राशि औचित्यपूर्ण मानी थी वहाँ लोगों से तीन सौ रुपए तक वसूल किए तथा जहाँ चार सौ रुपया लेना चाहिए था वहाँ पाँच सौ रुपए वसूल किए और इतने पर भी उनका सदा ही यह तर्क रहता था कि राजस्व व सरकारी शुल्क में और भी वृद्धि की गुंजाइश है। २६ फलस्वरूप जनता आर्थिक भार से दब गई थी और उसकी स्थिति भिला-रियों जैसी बन गई थी। अंग्रेजों ने चौकीदारी कर पहले दुगुना और फिर चौगुना कर दिया था। इस तरह उन्होंने लोगों को करो से दबा रखा था। सभी प्रतिष्ठित और गिणित लोगों के घंघे चौपट हो गए थे और लाखों लोग जीवनमापन की तलाश में बेघरबार हो गए थे। अब कभी कोई व्यक्ति घंघे या काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का निर्णय भी करता तो प्रत्येक व्यक्ति से सड़कों पर गुजरने के कर के रूप में एक आना व बेलगाड़ी के लिए चार आने से लेकर आठ आने तक कर वसूल किया जाता था। केवल वे ही लोग यात्रा कर पाते थे जो यह कर चुका सकते थे। किसानों की हालत दयनीय हो गई थी और नौकरी-पेशा लोगों की स्थिति भी शोचनीय थी। २७

अंग्रेजों के आधिपत्य के सम्पूर्ण काल में अजमेर-मेरवाड़ा का किसान आकाश-वृत्ति पर ही जीता था। उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन खेती था। किसान पर्याप्त सख्या में मवेशी पालकर भी अपनी आय में अतिरिक्त वृद्धि करने का प्रयास करते थे परन्तु अकाल एवं अभाव की स्थिति के कारण पशु भी अधिकांशतः मरने लगे थे। मवेशियों से उन्हें दूध, घी, ऊन और खेतों के लिए खाद उपलब्ध हुआ करती थी। २८ अकाल के समय में पाँच प्रतिशत पशु ही बच पाते थे। घास व चारे के अभाव में, मवेशियों की भारी खति होती थी और इस तरह उनके जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी कठिन हो जाता था। २९

किसानों में बच्चों की सख्या एक सबसे बड़ी समस्या थी। उन्हें अपने सीमित हाथों एवं साधनों से अनेक प्राणियों का पेट भरना होता था। एक तरफ घाए दिन परिवार में नये सदस्यों की वृद्धि और दूसरी तरफ अकाल से किसानों के लिए भोजन

और जीवनोपयोगी वस्तुएं जुटाना कठिन समस्या थी। इसका दुष्प्रभाव उनकी सुराक पर पड़ता था। उन्हें पोषण, शक्ति से हीन और अपर्याप्त भोजन पर गुजारा करना पड़ता था। सामान्यतः वे एक समय ही भोजन करते थे।<sup>३०</sup>

हृषि भूमि में भी वृद्धि हुई थी। खाद्यान्नों के ऊँचे भावों से किसान को लाभ न पहुँच कर सूदखोर भूजाली को इसका लाभ मिलता था। किसान ऋण से दबा रहता था। यदि किसान अपनी फसल निकट एवं दूरस्थ भूमियों में बेचने से जाता तो उसे अवश्य ही लाभ पहुँच पाता, परन्तु यहाँ का किसान ग्राम साहूकार पर अधिक निर्भर रहता था।<sup>३१</sup>

लोगों की सामान्य सुराक मेहँ, बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार और मोठ आदि की दालें थी। किसान अधिकांशतः जौ और मक्का पर गुजारा करता था। जिले के अधिकांश क्षेत्र में यही फसलें बहुतायत से होती थी। भूकाल एवं पशुधन के ह्रास से भी दूम किसानों के लिए जीवन की आवश्यकता न रहकर श्योंहारों की बीजों में शुमार होने लगा था। लोगों की वार्षिक खपत के अनुपात में फसलों की उपज में भारी गिरावट आ गई थी। रेल्वे की रसीदों को देखने से पता चल जाता है कि उन दिनों भ्रमर में बाहर से प्रतिवर्ष भारी गन्ना मँगवाया जाता रहा था।<sup>३२</sup>

प्रवाल के दिनों में अंग्रेज सरकार ने राहत कार्य हाथ में लेना प्रारम्भ किया था जिससे किसानों को भुलसरी और दूसरे स्थानों पर जाने से बचाया जा सका। सरकार के इन कदमों का जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा।<sup>३३</sup> सरकार तकाबी ऋण बाँटने, कतिपय भूकाल राहत कार्य और अन्य राहत सामग्री वितरित करने के कदम उठाती रहती थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जिले की स्थिति और भी खराब हो जाती तथा भारी संख्या में लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते। राहत कार्य में लगे लोगों को इतनी ही मजदूरी दी जाती थी जो मात्र उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त होती थी। रेलों के माध्यम से चारा बाहर से मँगवाया जाता था ताकि जिले के भवेलियों को बचाया जा सके।<sup>३४</sup>

भारत के सभी प्रान्तों की अपेक्षा राजपूताना अपनी विशिष्ट प्राकृतिक स्थिति के कारण घाटे दिन भूकाल से घिरा रहता था। भ्रमर-मेरवाड़ा जिले में एक भी नदी या नहर नहीं होने से यहाँ की खेती समय पर होने वाली वर्षा पर ही निर्भर थी। जब कभी वर्षा का अभाव होता, लोग सिंचाई के लिए कुँधों, जलाशयों आदि स्रोतों का उपयोग करते थे। कुँधों तातावों एवं नाडियों के निर्माण द्वारा यदि कभी एक मौसम सूखा रहता तो कुछ उपज इन साधनों से संभव हो पाती थी। इस जिले में भूकाल एवं सूखे का सामना करने के लिए इन साधन स्रोतों में वृद्धि की गई थी। इस तरह के निर्माण कार्यों से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। इस तरह एकाध वर्ष वर्षा की कमी एवं सूखे के व्यापक प्रभाव को किसान आसानी से इन सिंचाई

स्रोतों की सहायता से भेजने में समर्थ हो गया था ।<sup>३५</sup>

एक साथ ही दो तीन वर्ष तक भ्रकान का लगातार प्रकोप न होने पर भ्रकाल की इतनी मयाबहुता का यहाँ की जनता को कदापि अनुभव नहीं होता था । यद्यपि सरकार ऐसे समय राहण कार्य करती थी तथापि भ्रकाल ६ दिनों में किसानों का अपने मवेशियों के साथ दूसरे स्थानों पर जाना बना रहता था । क्योंकि किसान सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यों के प्रति कुछ ज्यादा आशावान नहीं होते थे ।<sup>३६</sup> ज्यादातर किसान मूखे एवं भ्रकाल के दिनों में अपने मवेशियों को मालवा ले जाया करते थे ।<sup>३७</sup>

जहाँ तक सुख-सुविधाओं के उपयोग का प्रश्न है अजमेर-मेरवाड़ा की कृषक जनता यह लाभ केवल अच्छी फसल प्राप्त करने पर ही उठा सकती थी । राजपूताना में भफीम और तम्बाकू भोज शीश की वस्तुओं में सम्मिलित नहीं थी । ये जीवन की आवश्यकताएँ बन गई थीं और लोग साधन उपलब्ध होने पर इनका खुलकर उपयोग किया करते थे । परन्तु भ्रकाल के दिनों का प्रभाव इन पर भी पड़ता था । देहाती में इस व्यसन का बहुत अधिक प्रचलन नहीं था परन्तु शहरों एवं कस्बों में जहाँ मजदूरी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, वहाँ दूसरी ही स्थिति थी । एक किसान शराब सभी पीता था जब उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती या उसके खेत लहलहा उठते थे । कर्ज में दबे रहने के कारण किसान आभूषण पर भी खर्च नहीं कर पाते थे । इस तरह की सभावनाएँ इसलिए भी पैदा नहीं हो सकती थी क्योंकि गाँव का महाजन बाज की तरह किसान-परिवार में समृद्धि के लक्षण नजर आने की वाट में लगा रहना था जिससे कि वह दीवानी अदालत की सहायता से उस पर भपट्टा मार सकें ।<sup>३८</sup>

“बाल्टर कृत हितकारी सभा” के उद्घाटन के साथ ही राजपूताना के राज-पूतों में विवाह एवं अन्य क्रियाकर्मों सम्बन्धी सामाजिक सुधार होने लगे थे । इन सुधारों की आवश्यकता एक लम्बे समय से अनुभव की आ रही थी । इन सुधार-आन्दोलनों का समाज में स्वागत हुआ था । शहर और गाँवों की सभी जातियों में इनका अनुकरण करने का प्रयास प्रारम्भ हुआ और विवाह एवं प्रतिम क्रियाकर्म और भवसरो पर होने वाले अवाञ्छित खर्च पर रोक के प्रयत्न प्रारम्भ हुए । सामान्य अभिहित जनता इन सुधारों के प्रति सहज ही आकृष्ट नहीं हुई होती यदि इस क्षेत्र में भ्रकाल तथा कर्ज के भार से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती । खराब आर्थिक स्थिति के कारण भी लोगो ने व्यर्थ के खर्च से बचाने के लिए सांजाजिक सुधार का महारा लिया । जब अच्छी एवं भरपूर फसल होती थी तब किसान “भोगर” आदि के नाम पर जी खोव कर व्यव करने में पीछे नहीं रहता था ।<sup>३९</sup>

जिले में रेलो के आगमन से भी चीजों के भावों में स्थिरता आई थी और

रई के व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। इस जिले से रई ही एकमात्र ऐसी व्यावसायिक फसल थी जो बाहर भेजी जाती थी परन्तु इसका किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि रेलों का साधन होने से पहले वे स्थानीय उपज के अच्छे दाम चढाया करते थे।<sup>४०</sup>

कृषकों की ऋणप्रस्तता ने व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लिया था इस ऋणप्रस्तता की वृद्धि के कारण किसानों में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टान, दूरदर्शिता का अभाव, विवाहों व क्रियाकर्म पर अपव्यय तथा ऋण चुकाने की असमर्थता इसके मुख्य कारण थे।<sup>४१</sup>

भारत में प्रचलित संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली, कस्बों एवं शहरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक गहरा प्रभाव जमाए हुए थी। इस प्रथा से लाभ और हानि दोनों ही थे। परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अगर सौभाग्य से किसान सुदक्ष और महाजन के बंगुल से बच पाता तो अन्य व्यवसायी की अपेक्षा वह अधिक अजित करने की स्थिति में था। परन्तु एक बार वह अगर बनिए की छोटी सी ऋणप्रस्तता में भी फँस जाता तो उसका पीढ़ियों तक उसके बंगुल से निकलना संभव नहीं था। विद्वद्भूत चुकाने की नैतिक परम्परा का पालन करने के कारण बहुधा सुदक्ष और अपनी बेईमानी से किसान का शोषण करता चला जाता था।<sup>४२</sup>

किसान हिसाब नहीं रखता था उसका सभी लेन देन गाँव के साहूकार के यहाँ था जहाँ उसकी अतिरिक्त फसल उसके भंडार में जमा हो जाती थी। महाजन की वही में किसान का अनाज कम मूल्य में जमा कर लिया जाता था और उसे कर्ज के रूप में घन बहुत ही ऊँची दरों पर दिया जाता था। यदि दुर्भाग्य से भीसम प्रतिकूल रहता, जो कि राजपूताना में सामान्य बात थी, तब किसान को आवश्यकता की वस्तुएं भी उसी के यहाँ से सानी पड़तीं और एक बार ऋण का साठा आरम्भ हो जाने के पश्चात् वह सदा के लिए साहूकार के हिसाब से बढ़ता ही जाता और उसका कभी अन्त नहीं हो पाता था।<sup>४३</sup>

अमानवता क्रमान एवं अनिश्चित समाज तारकालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी भी कर्त पर ऋण लेने को उद्यत रहना था व उसके भावी परिणामों की ओर बर्दाश्त ही उसका ध्यान जाता था। इस तरह उनका साहूकारों के बंगुल से छुटकारा पाना असंभव था।

सामाजिक प्रथाओं में विवाह, मृतक भोज तथा गंगोत्र प्रमुख रूप से प्रचलित थे। इनके साथ धार्मिक भावनाएं बचन के रूप में जुड़ी हुई थीं। इनका पालन करना एक तरह से अनिवार्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न होता था। इनमें विवाह भोज होते थे जो कि साधारण व्यक्ति पर अत्यधिक धार्मिक भार साद देने थे।

श्रमण ली गई राशि पर ब्याज की ऊँची दरें, गृहस्थी में नये सदस्यों की अभिवृद्धि, मौसम की अनुकूल-प्रतिकूल अस्थिरताएं, सभी मिलकर कर्ज में वृद्धि ही किया करती। लाहूर ने इन सभी तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात् जो सारांश प्रस्तुत किया है उसे काफी हद तक निश्चित एवं सही अभिव्यक्ति के रूप में लिया जा सकता है "अकाल का यह परिणाम सदा यह रहा है कि सम्पूर्ण जिला कर्ज के खंजुल में फँस जाता है और कदाचित् ही यह इससे मुक्ति पाने में सफल हो पाया हो। बकाया राजस्व चुकाने के लिए लिया गया कर्ज किसान के लिए बहुत घातक सिद्ध होता था क्योंकि उन्हें महाजन की बहुत सस्ते भाव पर अपना अनाज बेचने के लिए बाध्य होता पड़ता था और आवश्यकता पड़ने पर यही अनाज उन्हें ऊँचे भावों पर खरीदना पड़ता था।" ४४

भू-भाग भी सामान्यतः असुरक्षित था। अकेले अजमेर में रजिस्ट्रेशन के आँकड़ों से यह पता चलता है कि भूमि का बंधक या विक्रय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस तरह भूस्वामिध का हस्तान्तरण अबाधगति और अनियंत्रित जारी रहने देने का फल यह हुआ कि मूल स्वामी के पास बहुत कम भू-संपत्ति शेष रह गई थी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त तराफी करण की एका में बड़े-बड़े खेत बंधक के रूप में रहे जाते थे। ४५

सम्पूर्ण अजमेर जिले में व्यापारियों की अपेक्षा सूद पर खया देने का धंधा ज्यादा था। ऐसे वालों में से अधिकांश अमीरवाला या जैन समाज के लोग थे। ये लोग व्याज-बट्टे का धंधा करते थे। गाँवों में इनका समाज में प्रमुख स्थान था। वे किसानों को कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामग्री भी उधार दिया करते थे। ४६

जिले में रेलमार्ग खुल जाने से कपास ओटने की मशीनें लगने लगीं जिसकी वजह से यहाँ के रुई व्यापार को अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। ब्यावर, केकड़ी व नसीराबाद में जनिंग फैक्टरियां स्थापित हुई थीं। जिले में रुई और अफीम का ही निर्यात व्यापार होता था, परन्तु ब्यावर, नसीराबाद आदि स्थानों में फैक्टरियां और अजमेर में रेल कार्यालयों व रेल्वे वर्कशॉप खुल जाने से शहर की व जिले की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बाहर से साधान एवं अन्य सामग्री आयात होने लगी। अंग्रेजों के शासनकाल में, जिले के आयात और निर्यात व्यापार में अभिवृद्धि हुई थी। सभी उपरोक्त सामग्री के भावों में वृद्धि हो गई थी और गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, दालें, मोठ, घी, जौ इत्यादि के दाम बढ़ते ही जाते थे। ४७

गाँव का मजदूर, यत्नहि सही माने में अपने खेतों को जोतकर फसल के स्वामित्व वाला किसान तो नहीं था, परन्तु उसके हित इस वर्ग के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि किसान की स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ उसकी स्थिति भी



उत्पादन-पतन होता रहता था। जिने में दैनिक मजदूरी पर खेत पर मजदूर रखने की प्रथा अधिक प्रचलित थी, जो कि "हामी" कहलाते थे। ये मजदूर खेत जोतने, निराई करने, रखवाली करने और फल काटने के लिए नियुक्त किए जाते थे। इन लोगों को मजदूरी नगदी में अथवा अनाज के रूप में दी जाती थी। यदि नगद रूप में मजदूरी दी जाती तो पुरुष को चार रुपए, महिला को ३ रुपए और अल्पवयस्क को जो बारह साल से कम नहीं होता था २ रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। यदि मजदूरी खाद्यान्न के रूप में दी जाती तो पुरुष को डेढ़ सेर, महिला को एक सेर और बच्चे को आधा सेर अनाज प्रतिदिन की दर से दिया जाता था। मौसम की अनुकूलता का भी इनके वेतन पर प्रभाव पड़ता था। मजदूर अधिकांशतः चमार, बलाई, डौम आदि जाति के होते थे। मजदूरी के अलावा वे अपने जातीय व्यवसाय भी करते थे। मजदूरी के प्रतिरिक्त इनमें कई लोग पास, जंगली लकड़ी (ईंधन) बेचने का काम भी करते थे। प्रत्येक जाति का अपना जातिगत व्यवसाय होता था जैसे चमार धमड़े का काम करता था, बलाई कपड़ा बुनता था और ये लोग अपनी जीविका के लिए पूर्णतया किसान पर ही निर्भर रहते थे। ग्राम में इन की अपनी ज़मीन नहीं होने के कारण इनकी दशा इतनी दयनीय थी कि इन लोगों को ऋण भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। यही एक प्रमुख कारण था कि दो फसलों के बीच के समय में इनकी गुजर बसर बड़ी ही कठिनाई से हो पाती थी। यद्यपि ये लोग अधिकांशतः ऋणग्रस्त नहीं थे क्योंकि बिना द्रव्याधार के इन्हें ऋण मिलता ही नहीं था परन्तु ग्राम के गरीब से गरीब किसान की अपेक्षा इनकी आर्थिक हालत अत्यन्त गिरी हुई थी।<sup>४८</sup>

इन मजदूरों की मुख्य सुराक मक्का और जौ थी जिसे ये लोग गाँव के समूह किसानों के घर से द्वाध्य भाँग कर उनके साथ खाते थे। इन लोगों को मुश्किल से एक समय का भोजन ही मिल पाता था। दूध, घी, शाक भाजी इनके लिए शोहारों की चीज़ थी। गाँव में बुने मोटे कपड़े के वस्त्र ही इनका पहनावा था। उनके पहनावे में घोड़ी, बगलबन्दी, पछोश और सँदियों में एक रजाई होती थी। बहुत कम के पास यह सब होता था तथा अधिकांश की पोशाक खाली भोती ही होती थी।<sup>४९</sup>

कपास धोने व गँठें बनाने के कारगारों को बुल जाने तथा रेल्वे वर्कशाप के अजमेर में स्थापित होने पर बहुत से श्रमिक अपने घरबार छोड़कर शहरों में काम करने धने आए थे। अजमेर रेल्वे वर्कशाप के मजदूरों में उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के मनी भागों से और पंजाब के कुछ भागों के मजदूर नौकरी करने आए थे। अजमेर के श्रमिक अवगत कि अकाल की अथावहता से वे बाध्य नहीं हो जाए, हमारे स्थान पर काम करना पसंद नहीं करते थे।<sup>५०</sup>

शहर या कस्बे का मजदूर खेतिहर मजदूरों से कुछ बेहतर था। उसे अपना वेतन नकदी में मिला करता था। शहरों में एक सामान्य मजदूर का मासिक वेतन पाँच या छः रुपए होता था। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी घनाज पीस कर, पानी भर कर या अन्य शारीरिक श्रम से कुछ न कुछ अतिरिक्त उपार्जन कर लेती थी। खेतिहर मजदूरों की अपेक्षा शौकरी पेशा मजदूरों को ऋण मिलने में भी आसानी रहती थी, परन्तु ऋण की दरें वहाँ भी बहुत थीं। अजमेर के छूदसौर उचित ब्याज दर और धन की सुरक्षा की अपेक्षा अधिक बसूल करने की नियत से अपनी रकम खतरे में डालने से भी नहीं हिचकिचाते थे। शहरी जीवन ने मजदूर के जीवन में मीज-शौक का वातावरण पैदा कर दिया था। वह अपने दायरे में सभी व्यसन का उपयोग करता था। एक तरह से उसने नई आर्थिक जिम्मेदारियाँ पैदा कर अपनी आर्थिक स्थिति और भी खराब करनी थी। कुछ स्थानों पर कपास मोटने की फैब्रिकरियाँ और नए-नए कारखाने खुलने के कारण मजदूरों की आवश्यकता बढ़ गई थी अतएव मजदूरों को काम एवं अच्छा वेतन सुलभ हो गया था। परन्तु शहरी जीवन के दुर्भ्यसनों ने उसे इस तरह घेर लिया था कि उसके वेतन का एक बड़ा भाग शराब पर खर्च होता था या शादी और मौसर इत्यादि में नष्ट हो जाता था। वह अंग्रेजी मिलों के बने धोती जोड़े, जाकेट या बन्गी पहनता था। उसके रहन-सहन का स्तर निस्संदेह खेतिहर मजदूर की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा था। परन्तु अन्त दोनों का एक ही सा था। यदि एक तरफ खेतिहर मजदूर को रोजगार के अभाव में दयनीय जीवन बसर करना पड़ता था तो दूसरी ओर शहरी मजदूरों को अपनी फिजूलखर्ची के कारण कर्जदारों के कडे तकाजों का सामना करना होता था। ३१

औद्योगिक कामधंधों में अकाल के वर्षों के अतिरिक्त किसी तरह के ह्रास के संकेत नहीं मिलते थे। औद्योगिक व्यवसाय में प्रमुख घबे बुनाई, रंगाई, पीतल के बर्तनों का निर्माण तथा सुहारी, सुतारी, सुगारी व चमड़े के काम मुख्य थे। देशी कपड़े की बढ़ती हुई माँग ने बुतकरी को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर रहे थे, जबकि रंगसाजी स्थानीय कलात्मक रोजगार था। यद्यपि यूरोपीय रासायनिक रंगों का इस उद्योग पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा था परन्तु अजमेर में तबतक वे लोक-प्रिय नहीं हुए थे। सुहार और सुतार की रोजी सामान्यतः अच्छी चल रही थी। गहनों का रिवाज बहुत था। ३२

किसानों एवं गाँव के मजदूरों की समृद्धि का आधार अच्छी फसल पर निर्भर करता था। परन्तु समृद्धि का यह आधार अजमेर जिले के लिए स्वप्नमात्र था। अंग्रेजी शासनकाल के इतिहास में अच्छी फसल का कहीं भी निश्चित उल्लेख नहीं मिलता है। इन दोनों ही वर्गों का हित समान ही सा था। प्राप्त द्राकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अकाल का एक वर्ष किसान और खेतिहर मजदूर पर

इतनी गहरी मार करता था कि उसकी पूर्ति एक भ्रच्छी फसल नहीं कर पाती थी। एक भ्रकाल की मार को पूरा करने में इन्हें दस वर्ष लगते थे और वह भी उस हालत में जबकि उन दस वर्षों में दूसरा भ्रकाल न पड़े। २३

किसानों का ज्यादा समय सूखे एवं भ्रकाल में ही गुजरता था। इन प्राकृतिक विपदाओं तथा भ्रम्य कई कारणों से किसान वर्षों गहरे कर्ज में डूबा हुआ था, परन्तु अधिकांश खेतिहर यज्ञदूर कर्जदारों से मुक्त थे। भ्रजमेर सब-डिवीजन के पंजीयन प्रांके इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि भारी ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप किसान खेतों का विप्लव या बंधक अधिक करने लगे थे और यह प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता था। पहले यह भी संदेह किया जाने लगा था कि किसान पुरानी प्रथा के अनुसार कदाचित् खाद्यान्न की जमाबन्दी करने लगा हो, परन्तु इस दिशा में यदि निष्पक्ष जाँच की जाती तो यह तथ्य छुपा नहीं रहता कि जमाबन्दी के नाम पर किसानों ने केवल पीढ़ाएँ तथा गरीबी अटोर रसी थी और समृद्धि एवं ऐश्वर्य का सपना उनके निकट नहीं फटक पाया था। वे वास्तव में अत्यंत ही अरक्षित जीवन यापन कर रहे थे। अधिकांश किसानों की माय जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति तक में अर्पणित थी। कुछ किसान भ्रच्छा खा पी लेते थे परन्तु ऐसे किसानों की सख्या गिनी चुनी थी। २४

जिले के दूसरे कृषकों की भाँति, उन दिनों मेरवाड़ा का किसान भी कठिनाई से दिन गुजार पाता था। वह भ्रच्छी फसल के दिनों में अपनी अतिरिक्त माय खर्च कर डालता था और जब करान दिनों के बादल मड़राते तो उसके लिए साहूकार से ऋण लेने के अलावा और कोई दूसरा चारा शेष नहीं रहता था, परन्तु यह ऋण की राशि और ब्याज की दरें कदाचित् ही उससे चुक पाती थी। इस भूभाग की प्राकृतिक वनावट एवं इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि जिसमें उसकी हालत कभी भ्रच्छी नहीं हो सकती थी। जिले में भ्रच्छी फसल भूले भटके ही कभी-कभी होती थी अथवा यहाँ निरंतर सूखे एवं भ्रकाल-वर्षों का ताता लगा रहता था और इस वर्षों की ऋणग्रस्तता का यह सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कारण था। यद्यपि वे हाथ पुने रेजे के बन्ने से सजित अवश्य थे तथापि उनका यह पहनावा महाराष्ट्र या बरार के किसानों की तुलना में पोशाक नहीं कहा जा सकता था। उनकी माय मात्र गुजर बसर जितनी ही अर्पणित थी, इससे सुख-सुविधा जुटा पाना संभव नहीं था। कर्नल हॉन और डिक्मन ने इन लोगों को सूटपाट के घन्ने से हटाकर खेतों में जुटा दिया, यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं थी। २५

मेरवाड़ा के नेवतदारों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कृषक वर्षों अशान्त समय समाज के भ्रम्य कृषक वर्गों के स्तर तक उन्नति नहीं कर पाया था। एक सामान्य सार्वजनिक की वे लोग असम्य वनवासी से प्रतीत होते थे। गाँवों में स्कूल खोले गए थे व नई पीढ़ी लिखना-पढ़ना सीख रही थी।

जिले के अधिकांश पटवारी मेर और रावत थे और इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया था कि गाँवों की स्कूलों से निकले छात्रों को ही विशेषकर मेरों और रावतों को पटवारी के पदों पर नियुक्त किया जाए। मेर युवक जो मेरवाड़ा बटालियन में सैनिक अनुशासन की शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, अपने गाँवों को लौटने पर अपने साथ सम्पत्ता के भंडार साथ ले गए थे जिसका इन गाँवों पर प्रभाव स्पष्ट दिखता था। ४३

मेरवाड़ा के ग्रामवासियों के बारे में कर्नल ड्विगन ने यह अभिमत प्रकट किया है कि "मेर लोग विश्वासपात्र, दयालु और उदार चरित्र के होते हैं और अपनी जाति से अविच्छिन्न रूप से जुड़े रहते थे तथा एक दूसरे को परिवार का व्यक्ति मान कर चलते हैं।" ४७ सैनिक विद्रोह के समय वे भंडेज सरकार के प्रति वफादार बने रहे थे। ४८

मेरवाड़ा में व्यावर का एक ही बड़ा कस्बा था। इस नगर की समृद्धि एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना से मेरवाड़ा के लोगों की समृद्धि में भी बहुत योगदान प्राप्त हुआ था। औद्योगिक विकास के साथ मजदूर की स्थिति में भी परिवर्तन आया था। उसके लिए रोजगार की सुविधाएं सुलभ हो गई थी। व्यावर की समृद्धि का प्रभाव जिले के लोगों पर पड़ना भी स्वाभाविक ही था। ४९

एक औसत ग्रामीण मजदूर परिवार में चार सदस्य होते थे। एक मजदूर परिवार की औसत वार्षिक आय ७३ रुपए के लगभग हुमा करती थी पर्याप्त मासिक औसत ६ रुपए प्रति परिवार का अनुमान लगाया जा सकता है। मेरवाड़ा के छैतिहूर मजदूरों और नया नगर के श्रमिकों के वेतन में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। मेरवाड़ा के खेवतदार साने-पीने की चीजों में इन मजदूरों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में थे। यह कहा जा सकता है कि मेरवाड़ा के खेवतदारों को मजदूरों की अपेक्षा ज्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त थी। इसका मूल कारण कदाचित् यह हो सकता है कि मजदूरों के पास अपने खेत नहीं थे बिन पर उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता था। साधारण श्रमिक की पोशाक हाथ बुने मोटे कपड़े ( रेजे ) की होती थी। ५०

अकाल भयवा सूखे की स्थिति पैदा होने पर ग्रामीण मजदूर को किसी तरह की राहत उपलब्ध नहीं हो पाती थी। उसे निश्चय रूप से अपने परिजनों एवं घर-बार सहित भग्न जाना पड़ता था। प्रव्रजन के लिए उसका लक्ष्यविंदु मालवा भयवा वह जिला था जहाँ कोई सरकारी निर्माण का काम बड़े पैमाने पर चल रहा हो और उसे जहाँ आसानी से मजदूरी मिल सकती हो। उसके पास जमीन नहीं होने से ऋण प्राप्ति के साधन नगण्य से थे। इस दृष्टि से उसकी स्थिति मेरवाड़ा के खेवतदारों से अच्छी थी। बहुत कम श्रमिक कर्जदार पाए जाते थे। अपने भरण-पोषण एवं गुजारे लायक वेतन उसे मिल ही जाता करता था, परन्तु वह इतना कम होता था कि मजदूर के लिए इस अल्प वेतन में सुख सुविधाएं जुटा पाना

समय नहीं था। साधारणों के भावों के घटने बढ़ने के अनुसार ही उसकी स्थिति बदलती रहती थी। यदि स्वातंत्र्य सस्ता होता तो उसका गुजारा आसानी से हो जाता था अन्यथा उसे भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। खेतदारों व मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष फर्क नहीं था। ११

अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कभी प्रयास नहीं किया। यद्यपि उनकी स्वयं के बारे में यह मान्यता थी कि वे एक श्रेष्ठ जाति के हैं, उनकी अपनी सभ्यता भी श्रेष्ठ है और वे ईमानदारी के साथ पश्चिमी सभ्यता के बरदानों का वितरण पिछड़े हुए पूर्व के लोगों को प्रदान करना चाहते थे। परन्तु वे यह बात भूल गए थे कि विदेशी शासकों के अन्धे कदम भी स्थानीय जनता के मन में सन्देह उत्पन्न कर सकते हैं और उनका गलत भय लगाया जा सकता है। अपनी इन परिस्थितिगत बाधाओं के होते हुए भी उन्होंने कई ऐसे सुधार, जिन्हें वे बहुत ही आवश्यक समझते थे, लागू करने का प्रयास किया। इस दिशा में अपने उत्साह के कारण उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि कौन से सुधार अविलम्ब आवश्यक हैं और कौन से सुधार बाद में भी हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई प्रश्नों पर जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचना स्वाभाविक था।

हिन्दू समाज के कट्टरपंथी तत्वों को अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा की समाप्ति के प्रयास को अंग्रेजों के प्रति द्वेष एवं विरोध का आधार बनाने में हिचकिचाहट नहीं हुई। राज कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह सामाजिक सुधार बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था और यह प्रथा सम्य समाज के लिए एक धमिलाप थी। धार्मिक मामलों में पूर्ण निष्पक्षता बरतने के उद्देश्य से अंग्रेज सरकार उन सभी प्रयासों से दूर रही जिन से हिन्दू एवं मुसलमानों के मन में उनके प्रति किसी तरह का द्वेष उत्पन्न हो सकता था। परन्तु कोई भी सम्य प्रयास न मनुष्य को जीवित जलाने की प्रथा को बंदापि सहन नहीं कर सकता है इसलिए ईस्ट इंडिया कम्पनी के निदेशक इस धमिलाप को समाप्त करने के लिए उत्सुक थे। लार्ड विलियम बैंटिक ने इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया। उन्हें उदार एवं हिन्दू सुधारक राजा राममोहनराय और डारवानाय टगोर आदि का समर्थन प्राप्त था। परन्तु दुर्भाग्य से तत्कालीन समाज में ऐसे लोग गिने-बुने ही थे और अधिकांश हिन्दू समाज की यह मान्यता थी कि उनके किसी मामले में हस्तक्षेप धर्म विरुद्ध ॥ १२

सन् १८२९ में, सरकार की धार्मिक नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। भारत में दीर्घकाल से यह परम्परा चली आ रही थी कि राज्य, चाहे उसकी किसी भी धर्म में मान्यता हो, वह सभी जातियों के तीर्थ स्थानों का परम्परागत संरक्षक माना जाता था और धार्मिक विवादों में शासक के विभिन्न पक्षबलही होने के बावजूद

भी उसको मध्यस्थता करनी पड़ती थी। इसी तरह धीरगजेब को हिन्दुओं के धार्मिक विवाद के मुद्दे, पेणवा को रोमन कैथोलिक पादरी के अधिकारों के बारे में निर्णय देना पड़ता था। इस परम्परागत प्रथा के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों के कंधों पर यह भार माना स्वाभाविक ही था कि वे हिन्दुओं के देवालयों एवं मुसलमानों की सुप्रसिद्ध भजमेर की दरगाह के संरक्षक का कर्तव्य निभाए। भजमेर की दरगाह की देखरेख भी अंग्रेज अधिकारियों ने इसी उद्देश्य से अपने हाथों में ली थी।<sup>१३</sup> इन पवित्र स्थानों से सरकार की भाय में वृद्धि ही हुई थी क्योंकि इनकी देखरेख इत्यादि में यात्रियों से प्राप्त धन में से नाममात्र की राशि ही व्यय होती थी।<sup>१४</sup> परन्तु कम्पनी की सरकार को अपने ही देश में लोगों के तीव्र विरोध के दबाव के कारण हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक स्थल उन्हीं जातियों के संरक्षण में छोड़ देने पड़े।<sup>१५</sup>

यहाँ मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार से जनता में रोप की भावना उत्पन्न होने लगी थी। उनके धर्म-प्रचार के अधिकार को चुनौती देने का प्रश्न नहीं था परन्तु ये लोग ईसा का संदेश प्रसारित करने तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि ईसाई पादरी छुले आम हिन्दू मुसलमानों की धार्मिक परम्पराओं और उपासना पद्धति का मजबूत उड़ाते थे। विदुष्य जनता ने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेज शासन का भ्रम माना क्योंकि बहुधा इन मिशनरियों के साथ पुलिस की व्यवस्था भी रहती थी।<sup>१६</sup>

यद्यपि मिशनरी बहुत ही कुशल अध्यापक होते थे, उनकी यह कुशल शिक्षण-पद्धति पुराणपंथी हिन्दुओं के लिए चिंता का विषय बन गई थी। ईसाई मिशन के अध्यापक बालकों के मानसिक विकास तक ही सीमित नहीं रहते थे अपितु उनका सर्वोपरि उद्देश्य उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव डालना होता था। उनके मतानुसार ईसाई धर्म ही मुक्ति का केवलमात्र मार्ग था। उनका यह दावा था कि सम्पूर्ण सत्य का एकाधिकार इस धर्म के पास है और उनके इस अभिमत का एक ही अभिप्राय जो लोगों के समक्ष व्यावहारिक रूप से प्रकट होता था वह यह था कि पश्चिमी शिक्षा का उद्देश्य ही धर्म-परिवर्तन है। उदार हिन्दू यह मानकर संतोष कर लेते थे कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, परन्तु मुसलमान, जिनका दृढ़ विश्वास था कि भकेला उनका ही मजहब सच्चा मजहब है, यह रियायत देने को तैयार नहीं थे। अधिकांश हिन्दू समाज प्राचीन दर्शन से पूर्ण अनभिज्ञ था। उनका यह विश्वास था कि धार्मिक परम्पराओं का पालन और शास्त्रानुसार कर्मकाण्ड के आचरण से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अधिकांश हिन्दुओं की यह मान्यता थी कि यदि उसके पुत्रों ने उसकी मृत्यु के पश्चात् क्रियाकर्म नहीं किए तो उसकी कभी मोक्ष नहीं होगा और आत्मा भटकती रहेगी। मुसलमानों में ऐसी कोई भावना

नहीं थी। अतएव ईसाईमत-प्रचारको और और ईसाई मतानुबन्धियों के बीच विवाद का न कोई हल और न कोई मध्यम मार्ग ही था। भारतीयों के मस्तिष्क में यह बात भी घर किए हुए थी कि उसके धार्मिक प्रतिद्वन्द्वी को सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग प्राप्त है। मिशनरियों की कार्यवाहियों केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं थी। ईसाई अध्यापक प्रतिदिन जेल में बंदियों को सामान्य ज्ञान एवं ईसाई मत की शिक्षा देने के लिए जाते थे और प्रति रविवार को बाइबल का उपदेश उन्हें सुनाया जाता था।<sup>१७</sup>

लोगों के इस संदेह को नए कानून ( सन् १८४८ ) से भी दल मिला जिसके अनुसार सभी कैदियों का भोजन एक स्थान पर बनने लगा और उन्हें एक साथ भोजन करने को बाध्य होना पड़ा। यद्यपि आज सामान्य रूप से जेलों में सभी बंदियों का भोजन कुछ कैदियों द्वारा एक जगह बनाया जाता है, परन्तु उन दिनों प्रातिगत कट्टरता अधिक थी। जेलों में जाति बंधनों का कैदियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता था और प्रत्येक को अपना खाना बनाने की छूट ही हुई थी। इस नए नियम के अन्तर्गत एक जेल में सभी कैदियों के लिए ब्राह्मण रसोईदार नियुक्त किया गया था। यह उच्चवर्ण के हिन्दुओं की मर्चा नहीं लगा क्योंकि ब्राह्मणों में भी कई उपजातियाँ थीं और दूसरों के हाथों का छुमा नहीं खाते थे।<sup>१८</sup> इस नए नियम का यह गलत अर्थ लगाया गया कि इसका उद्देश्य परोक्ष रूप से हिन्दुओं की जात-पात नष्ट कर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना है। पटवारीयों या गाँवों में सरकारी हिसाब तैयार करने वाले कारकूनो को हिन्दी या नागरी लिपि सीखने के लिए मिशनरी स्कूल में भेजा था। उनकी शिक्षा वहाँ हिसाब किताब या नागरी लिपि तक ही सीमित नहीं रहती थी। मिशनरी ईसाई मत का प्रचार करने को नियुक्त किए जाते थे। व्यापारीक देशी पादरी को (जिसे हिन्दू धर्मपरिवर्तन के कारण हीन दृष्टि से देखते थे) जेलों में बंदियों के बीच प्रतिदिन ईसा का उपदेश सुनाने भेजा करते थे। नवयुवक पटवारी अपने विभागीय प्रशिक्षण के बाद गाँवों में बाईबिल की प्रतिमों के साथ सौटा करते थे। इन सब कारकों की वजह से सामान्य जनता का यह दोषारोपण करना कि सरकार के इरादे नेक नहीं हैं स्वाभाविक था।<sup>१९</sup>

जनता ने सन् १८५० के एक्ट २१ को उपर्युक्त पृष्ठभूमि में ही लिया। इस कानून के अनुसार एक धर्मपरिवर्तित नव ईसाई को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार प्रदान किया गया था। सिद्धांततः इस कानून के प्रति कोई मत-भेद नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी उपासना-विधि या धार्मिक विचारों में परिवर्तन मात्र से ही उसे पैतृक संपत्ति से वंचित रखा जाए जबतक कि वह देश के प्रचलित नियमों के विरुद्ध धाचरण करे। परन्तु हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ने ही इसे नव-ईसाईयों के लिए रियायत के रूप में लिया। हिन्दू धर्म में धर्मत्याग का

कोई स्थान नहीं है। इसलिए उसे इस नए कानून से कोई लाभ नहीं मिला और न मुसलमानों को इस कानून से किसी तरह का लाभ मिला क्योंकि उनकी शरीयत में भी भ्रजहव छोड़ने वाले की सम्पत्ति ग्रहण करने का खुला निषेध है। मतएव इस कानून को दोनों ही मतवालों ने अपने पर प्रहार के रूप में लिया। हिन्दुओं के लिए यह कानून इसलिए भी घातक माना गया क्योंकि इसके अनुसार नव-ईसाई पंतुक संपत्ति बिना किसी उत्तरदायित्व के ग्रहण कर सकता था। वह अपने पिता की सम्पत्ति का स्वामी बिना किसी तरह उसकी अन्तिम क्रिया कर्म किए ही बन सकता था।<sup>७०</sup> हिन्दू के मन में यह भावना जम जाना स्वाभाविक ही था कि इस कानून ने उस पर दुहरीचोट की है। एक तो उसका कमाऊ बेठा छिन जाता है, दूसरा वह उसको पिढवान व अन्तिम क्रिया कर्म सम्पन्न कराए बिना ही उसकी सम्पत्ति का स्वामी बन सकता है। मुसलमानों के लिए यह कानून एक तरह से धर्मत्याग को प्रोत्साहित करने वाला कदम था क्योंकि मुसलमान लोग भी मिशनरी सकट से झपूत नहीं बचे थे।<sup>७१</sup>

इस वातावरण के कारण पुण्यार्थ एवं सस्यानों की गतिविधियों तथा जन-पयोगी कार्यों के बारे में भी लोगों के मन में संदेह एव शका उत्पन्न होने लगी थी। किसी भी भवन या सड़कों के निर्माण-कार्य के दौरान यदि एकाध देवालय बीच में पड़ जाता तो उम्हे हटा देना पड़ता था। परन्तु लोगों ने आवागमन की इस सुविधा को नजरों से भ्रोक्षल करके इन्हें भी बिट्टेप का कारण ठहराया, मानो ये भवन और मार्ग, देवाल्यों को गिराने के निमित्त बनवाए जा रहे थे। सरकारी अस्पतालों के बारे में भी लोगों की ऐसी ही अग्रिय भावना बन गई थी।<sup>७२</sup>

सामान्य जन-साधारण की अंग्रेजी प्रशासन के प्रति अनुकूल भावनाएं नहीं थी। अजमेर शहर के नगण्य शिक्षित समुदाय ने अंग्रेजों के सामाजिक सुधार कानूनों एवं पश्चिमी शिक्षा-प्रणाली लागू करने की नीति का स्वागत किया था। इस बात में भी संदेह है कि बाबू समुदाय में अंग्रेजी शासन के प्रति एक मत रहा हो। इन लोगों में भी बहुधा शासन की निरकुशता एव अनुदारता की कटु आलोचना घर किए हुए थी। एक शताब्दी से भी अधिक काल तक आपसी सन्नर्ग एव सम्पर्क के बाव भी यह स्थिति थी कि हिन्दू और अंग्रेजों में आपसी व्यवहार स्थापित नहीं हुआ था।<sup>७३</sup> शासक वर्ग द्वारा अपने को सामाजिक रूप से शक्ति से वृषक् रखने की नीति के कारण उनके मन में शासक वर्ग के प्रति घृणा की भावनाओं ने घर कर लिया था। अंग्रेज अधिकारियों के दम और अपने मातहत भारतीय कर्मचारियों के प्रति हिकारत भरे दृष्टिकोण ने दोनों के मध्य एक खाई पैदा कर दी थी। अंग्रेजों का भारतीयों को अपने से अलग करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है।<sup>७४</sup> अजमेर-मेरवाड़ा में प्रशासनिक उच्च पदों से जिस व्यवस्थित ढंग से भारतीयों को अलग रखा गया था, उसके कारण भी असंतोष काफी बढ़ गया था।



भंगेजों ने सदा ही भारतीयों के प्रति—चाहे वह उच्चपदासीन अधिकारी हों या घबघा मातहत निम्न स्तरीय कर्मचारी—व्यवहार में कोई अन्तर नहीं रखा। केवल इतना ही नहीं बल्कि छोटे कर्मचारियों की तुलना में ऊँचे पदासीन भारतीयों को उनके अनादर एवं लाछनों का अधिक प्रहार सहना पड़ता था। भंगेजों द्वारा प्रचलित कानून को कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में नहीं लाया जाता था। गरीब किसानों में भी, जिनके हितों की रक्षा के लिए इन कानूनों को बनाया गया था, ये लोकप्रिय और हितकारी सिद्ध नहीं हुए थे। इसका कारण यह नहीं था कि कानून में कोई बुराई थी परन्तु इनकी अप्रियता का कारण यह भी था कि कानूनी अदालतें भ्रष्ट हो गई थी।<sup>१३</sup> इसके अतिरिक्त भंगेजी कानून की प्रक्रिया इतनी जटिल एवं पेचीदा थी कि वह साधारण गरीब एवं अशिक्षित किसान के बस की नहीं थी। उसकी अधिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह वकील नियुक्त कर सके। पुलिस और निम्न अधिकारियों का भ्रष्ट व बदनाम होना भी इन अदालतों व कानून के लोकप्रिय नहीं होने का कारण है।<sup>१४</sup> कानूनी अदालतें पैसे वालों के हाथ का खिलौना व अन्यायपूर्ण शोषण का साधन बन गई थी। साक्षियों के बना-बटी दस्तावेज व झूठे दावे उस प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्भव थे।<sup>१५</sup>

परन्तु सबसे अधिक बदनाम भूमि विक्रय सम्बन्धी कानून था। पुरानी प्रथा के अनुसार सभी व्यावहारिक रूप से भूमि अहस्तांतरित मानी गई थी। भंगेज सरकार ने इसके स्थान पर यह कानून बनाया कि जो ऋण चुकाने में असमर्थ हो उसकी भूमि बेची जा सकती है। लगान पहले से ही इतना अधिक निर्धारित था कि जमींदार उसे चुकाने में असमर्थ थे। अनुकूल मौसम में उन्हें थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता था तो प्रतिफल दिनों में उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती थी। इस कानून का किसान और ठालूकदार दोनों पर ही गहरा प्रहार हुआ।<sup>१६</sup> यही गहरी जमी हुई धूँआ और अविश्वास की भावना सन् १८५७ में सैनिक विद्रोह के रूप में फूट पड़ी थी और बाद में इसी के फलस्वरूप राजस्थान में राष्ट्रीय गतिविधियों ने प्रखर रूप धारण किया था।

## अध्याय ६

१. सी० सी० घाटसन—राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर, खण्ड १ ए (१९०४) पृष्ठ १३।
२. जे० सी० लाहल—बन्दीवस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ० २६।

३. एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ग्रॉन्टरलोनी को पत्र, दिनांक २६ सितम्बर, १८१८ ।
४. एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ग्रॉन्टरलोनी को पत्र दिनांक २६ सितम्बर, १८१८ । जे० डी० लाटूश—बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ० २० ।
५. जे० डी० लाटूश—बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ० २० ।
६. उपर्युक्त ।
७. एडमॉन्सटन—सेटलमेन्ट रिपोर्ट दिनांक २६ मई, १८३६ ।
८. कर्नल डिवसन द्वारा सचिव, उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र—संख्या २७४।१८३२ ।
९. सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए (१९०४) पृ० २२ ।
१०. कमिशनर, भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिशनर को पत्र, दिनांक २६ फरवरी, १८६१ ।
११. भार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व देहली को पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२८ ।
१२. एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ग्रॉन्टरलोनी को पत्र दि० २६ सितम्बर, १८१८ ।  
सर एलफ्रेड सॉयल—भूमिका राजपूताना गजेटीयर्स १८७६ ।
१३. भार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व देहली को पत्र दिनांक ११ जुलाई, १८२६ ।
१४. जे० थामसन सचिव, उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा सदरलैंड कमिशनर भजमेर को पत्र, मई १८४१ ।
१५. सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए भजमेर-मेरवाड़ा (१९०४) पृ० ६० । लाटूश-गजेटीयर्स ऑफ भजमेर-मेरवाड़ा (१८७५) पृ० ५० ।
१६. भार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व भालवा को पत्र दिनांक १० जुलाई, १८२६ ।
१७. लाटूश—बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) अनुच्छेद १२६ ।
१८. इस्तेमालदारों एरिया इनक्वायरी कमेटी रिपोर्ट अध्याय ४, पृ० ११ ।

१६. उपर्युक्त—अध्याय ४ पृ० २० ।  
 २०. उपर्युक्त—अध्याय १ पृ० १६ ।  
 २१. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, खंड १-८ (१९०४) पृ० १३ ।  
 २२. बुरेलपाँक—मेडीको टोपोग्राफिकल अकाउंट भजमेर-१९००-पृ० ८३१ ।  
 २३. फाइल क्रमांक ७३३ खंड २ (रा० रा० पु० मं०) सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, खंड १, भजमेर-मेरवाड़ा पृ० १३ तथा ७० से ७७ (१९०४) ।  
 २४. सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, खंड १ ए पृ० ३७ । (१९०४) सन् १८६८-६९ के प्रकाश वर्ष में जिला छोड़कर जाने वालों की संख्या २३३४५ कही जाती है। भजमेर में १४१५२, तथा मेरवाड़ा से ९,९११ व्यक्ति बाहर गए थे। अक्टूबर १८६८ से बाहर जाने का क्रम आरम्भ हुआ और मार्च १८६९ तक जारी रहा। बाहर जाने वाले व्यक्तियों में से १०६५० वापस लौट आए थे। निम्न तालिका में सन् १८६०-६२ के प्रकाश के समय बाहर जाने वाले व्यक्तियों, मृतकों अथवा पुनः न लौटने वालों के आँकड़े प्रस्तुत हैं—

जिला	निष्क्रमण	वापसी	मृतक अथवा बाहर रह गए ।
------	-----------	-------	------------------------

भजमेर	३२२१६	२३७६३	८४५६
मेरवाड़ा	<u>६२०६</u>	<u>४५५४</u>	<u>१६५३</u>
	<u>३८४२८</u>	<u>२८३१७</u>	<u>१०१११</u>

सन् १८६८-७० के प्रकाश वर्षों में जिले में कई राहत कार्य सोले गए थे। सरकार ने राहत कार्यों पर ७५६,४०७ रुपया व्यय किया था। सार्वजनिक निर्माण-विभाग के अन्तर्गत इन राहत कार्यों पर औसतन ६७४२ व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते थे। सन् १८६०-६२ के प्रकाश वर्षों में राहत कार्यों पर कार्य करने वालों की संख्या प्रतिदिन ११९८२ थी तथा सरकार ने इस पर १२५६११६ रुपये खर्च किया था। बुरेल पाँक, मेडीको टोपोग्राफिकल अकाउंट, भजमेर-मेरवाड़ा १९०० पृ० ८३-८४) ।

२५. सन् १९१६ में आयोजित देहली भजमेर राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में पटुनभात सेटी का भाषण। फाइल क्रमांक ८५-ए (रा० रा० पु० मं०) ।

२६. सालसा-भूमि का सगान कदापि कम नहीं था। जनता अधिकांशतः कृषि पर निर्भर थी और वह बड़ी ही कठिनाई से गुजारा कर पाती थी। उनका फसलों के घसावा भाजीविका का कोई और साधन नहीं था। प्रत्येक सूखे के साल का यह परिणाम होता था कि इससे जमा खोरों को घटाने पुराने कर्जों की बसूली का अवसर प्रायः मिल जाया करता था। जे० डी० साद्वश भजमेर-मेरवाड़ा का गजेटीयर्स १८७५-७६ ११३ एवं ११४।

२७. परराष्ट्र एवं गुप्त विचार-विमर्श दि० ३०-४-१८५८ क्रमांक १४ (रा० रा० पु० मं०) "कमिशनर के अनुसार सम्पूर्ण खालसा क्षेत्र में लोगों के घरों की हालत नाजुक हो गई थी तथा तालुकादारियों के मुकाबले में वहाँ के किसानों की हालत बड़ी ही दयनीय थी।" जे० डी० साद्वश भजमेर-मेरवाड़े गजेटीयर्स १८७५-७६ ६६।

२८. साद्वश के अनुसार भकाल के वर्षों में जिले से सोनी के निष्क्रमण की गति दिनोदिन बढ़ रही थी। लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भूत के कारण वे खेजड़े की छाल को पीस कर आटे में मिलाकर रोटिया बनाकर खाने को मजबूर हो गए थे। साद्वश भजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) पृ० ११०।

२९. फाइल क्रमांक ७३३ (रा० रा० पु० मं०)।

३०. फाइल क्रमांक २६६ पृ० १३ (रा० रा० पु० मं०) पृ० ११, भकाल-क्षेत्र के बीच भजमेर पृथक् पड़ जाता था, उसके पास खाद्यान्न वस्तुओं की पूर्ति का कोई साधन नहीं था, पास-धारा इतना महंगा हो गया था कि वह खाद्यान्न वस्तुओं से भी महंगे भाव पर उपलब्ध हो जाता था। इन दिनों में न तो बैलगाड़ियाँ ही चलती थी और न राजपूताना व मध्य भारत की तरह बंजारों के सामान लदे कार्रवाइें ही धूमते थे। लोगों की दशा दयनीय हो गई थी तथा साहूकारों ने उन्हें ऋण देने से भी हाथ खींच रखा था। कई स्थानों पर भवेली बिल्कुल नहीं बचे थे। ऐसी स्थिति में पुरुषों को बैल की तरह जुतकर जमीन जोतने के लिए बाध्य होना पड़ता था।

साद्वश-भजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) पृ० १०६, ११०, १११।

३१. जी० एस० ट्रेवर चोफ कमिशनर, भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव, भारत को पत्र आबू दि० ७ नवम्बर, १८६२ पत्र संख्या ११७८-७३५।

३२. उपर्युक्त।

३३. सन् १८६८-७० के अकाल वर्षों में जिले में कतिपय राहत कार्य प्रारम्भ किए गए थे उन पर सरकार ने ७,१६,४०७ रुपए व्यय किए थे तथा राहत कार्यों में प्रोत्तन ६७४२ व्यक्तियों को सार्वजनिक निर्माण-विभाग के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी मिलती थी। सन् १८६०-६१ के अकाल वर्षों में दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या ११,६८२ थी तथा राहत कार्यों पर १२,५४,११६ रुपए सरकार द्वारा व्यय किए गए थे। सन् १८६०-६२ के वर्षों में तीन निःशुल्क भोजनगृह भी खोले गए थे जिन पर सरकार ने ३३६४ रुपए ६ आने ३ पाई व्यय किया था। पर्वी मशीन महिलाओं, विधवाओं एवं वन्धों को जो जाति प्रपवांश के कारण खुद में मजदूरी करने में असमर्थ थे, घरेलू काम भी दिए गए थे, क्योंकि इनके भरण-पोषण का कोई सहारा नहीं था। अक्टूबर, १८६१ में प्रारम्भ किए गए राहत कार्य में ४,७६,२७६ व्यक्ति कार्य करते थे जिनमें से ४,७६,२६७ अजमेर तथा १२ मेरवाड़ा से थे। इन पर ७,७५,६२ रुपए व्यय हुए थे। इनमें ७७,८८५ रुपए अजमेर तथा १०७ रुपए मेरवाड़े में खर्च किए गए थे। डुरेल पॉक, मेडीको—टोपोग्राफिकल अकाउंट अजमेर-१८०० पृ० ८४ तथा ८५।

३४. बालमुकन्ददास एवं इमामुद्दीन समुक्त रिपोर्टें दि० २०-१०-१८६२

३५. फाइनल सं० ५६६ "१८६२-१८६२" (रा० रा० पु० सं०)।

३६. सन् १८६८-६९ में अजमेर-मेरवाड़ा से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या २३३४५ थी। इनमें से १०६५० व्यक्ति वापस लौटे थे। सन् १८६०-६६ में यहाँ से ३८४२८ व्यक्ति बाहर गए जिनमें से वापस लौटने वालों की संख्या २८३१७ थी। डुरेल पॉक, अजमेर-मेरवाड़ा का मेडीको-टोपोग्राफिकल अकाउंट ११६०-७० पृ० ८३।

३७. भानूदास का मत है कि सन् १८६६ में राजस्व बमूली की नई प्रक्रिया के कारण भी कृषकता ने नया स्वरूप ग्रहण कर लिया था। नई राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी सगान के लिए केवल ग्राम-मुलिया को उत्तरदायी ठहराया गया था। इस कारण उसे अकाल के दिनों में भुद के नाम पर भारी रकमे बजों पर लेनी पड़ी थीं। यद्यपि इस राशि को बाद में जाजियों के नाम पड़ा दिया गया था परन्तु न्यायालयों ने इसे निषेधात्मक नहीं स्वीकार किया तथा यह बजों की राशि ग्राम-मुलिया के माले में ही गई थी और उसकी निजी संगति से बमूली की दियारियां जारी की जाने लगी थी, जब कि यह राशि ग्राम के लिए बजों से ही गई

थी। बन्धोवस्त के समय खालसा ग्रामों में बंधक ऋण राशि ११,५४३७ रुपए थी।

सादृश भजमेर-मेरवाड़ा गजेटियर्स (१८७५) पृ० ११४। फाइनल सं० ५६८।

३८. फाइनल सख्या ७३३ खंड २ (रा० रा० पु० मं०)।

३९. उपयुक्त।

४०. बालमुकुंददास एव इमामुद्दीन द्वारा संयुक्त रिपोर्ट दिनांक २०-१०-१८७२ (रा० रा० अभिलेखागार)।

४१. सन् १८८१ से १८८६ के वर्षों में जो समृद्धि के वर्ष कहलाते थे बंधक रखे गए क्षेत्रों का वार्षिक औसत क्षेत्रफल ६०० एकड़ भूमि था। सन् १८८७-८८ का वर्ष अकाल वर्ष था तथा उस वर्ष से बंधक ऋण में वृद्धि के आंकड़े निम्न थे—

१८८७-८८	= १२०० एकड़
१८८८-८९	= २००० एकड़
१८८९-९०	= ३४०० एकड़
१८९०-९१	= ३१०० एकड़

उपरोक्त आंकड़े खालसा एव जागीर कृषि भूमि के हैं जो पंजीयन किए गए थे। इनके साथ कतिपय अर्धजीवित बंधक भूमि भी अवश्य रही होगी। उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके थे। कुल खालसा-भूमि जो बंधक थी, उसके आंकड़े निम्न हैं :—

वर्ष	क्षेत्रफल	बंधक ऋण	वार्षिक संख्या
सन् १८७३	१२६०० एकड़	रुपए ३४४००००-	रुपए ६८०००
सन् १८८६	१५७०० एकड़	रुपए ७००००००	रुपए ६१०००
सन् १८९१	२०००० एकड़	रुपए ७००००००	रुपए १४०००

लगभग ७० प्रतिशत किसानों को कृषि योग्य भूमि सूखे एवं अकाल की दिनों में बंधक रख देनी पड़ी थी। मेरवाड़ा में ६० प्रतिशत से अधिक सिंचित भूमि रहन रखी गई थी।

प्रसिस्टेंट कमिश्नर भजमेर द्वारा कमिश्नर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २२ नवम्बर, १८९१ पत्र सख्या २१२६।

४२. सादृश-भजमेर-मेरवाड़ा गजेटियर्स (१८७५) पृ. ११४।

४३. लाहूर के अनुसार भ्रजमेर में ब्रिटिश प्रशासन की नीति सदा ही धनाढ्य लोगों के पक्ष में रही थी। विल्डर ने अपने सेठों को भ्रजमेर में बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। यहाँ तक कि कर्नल डिवसन भी इसी मत के थे कि जल की पूर्ति के पश्चात् क्षेत्र की समृद्धि के लिए महाजन वर्ग को भ्रजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र में बसाये जाने के लिए प्रशासन को प्रयत्न करना चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि महाजनो के हस्तक्षेप के बिना कृषि विकास संभव नहीं है।
४४. लाहूर-बंदोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ. ८६, अनुच्छेद २०४।
४५. स्थानीय किसानों एवं बनियों के बीच तीव्र असंतोष की भावना घर किये हुए थी। इस असंतोष का प्रमुख कारण यह था कि भूमि तेजी से किसानों के हाथों से निकल कर बनियों के जुगल में फँसती जा रही थी। किसानों की प्राय के सभी स्रोत क्षरणप्रस्तता में लिप्त हो गए थे। प्रशासनिक सत्ता दिनोंदिन शिथिल होती जा रही थी और किसानों के कष्ट-निवारण में असमर्थ थी। दीवानी भदासतें वास्तविक रूप से बनियों के हितों की रक्षा करती थीं और किसानों की दृष्टि में वे शोषण के प्रमुख साधन बन गए थे। ग्रामीणों में यह भावना घर कर गई थी कि बनियें उनके साथ धोखा कर रहे थे और भदासतें भी उनके पक्ष में थीं। सरकारी संरक्षण से उसका विश्वास उठ गया था और वह पूर्णतया अपने ही साधन स्रोत पर निर्भर था। प्रसिस्टेन्ट कमिश्नर के मतानुसार सितम्बर, १८६१ में छूट की दुर्घटनाओं का मूल कारण यही था। किसानों ने मारी संस्था में संगठित होकर बनियों की दुकानों को छूट लिया था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न प्राप्त करना था और बनियों से प्रति-कार लेना था, अतएव उनके खाता बही और गोदाम जप्ट कर दिये गये थे।
- लाहूर-बंदोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ. ६६।
- प्रसिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक २२ नवम्बर, १८६१ पत्र संख्या २१२६।
४६. फाइल संख्या १६६ (रा. रा. पु. म.)।
४७. फाइल संख्या १६६, क्रमांक २०, पृ. संख्या १० (रा. रा. पु. म.)।
४८. जी. एच. ट्रेवर चीफ कमिश्नर द्वारा सचिव, भारत सरकार को पत्र दिनांक ७ नवम्बर, १८६२ पत्र संख्या ११७८।
४९. उपर्युक्त।

५०. फाइल संख्या १६५, क्रमांक संख्या २० (रा. रा. अभिलेखागार) ।
५१. हरनामदास एवं इमामुद्दीन की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक २०-१०-१९२६ (रा. रा. पु. मं.) ।
५२. उपर्युक्त ।
५३. साद्वन-भजमेर-मेरवाड़ा गजेटियम (१८७५) पृ. ११३ ।
५४. संयुक्त रिपोर्ट हरनामदास एवं इमामुद्दीन दि० २०-१०-१९२६ (रा. रा. पु. मं.) ।
५५. सेप्टिमेंट प्रीचार्ज, असिस्टेंट कमिशनर भजमेर-मेरवाड़ा की रिपोर्ट, दि. २०-१०-१८९२, पु. १४ (रा. रा. पु. मं.) लेखागार ।
५६. फाइल नं. ५६६ (रा. रा. पु. मं.) ।
५७. डिविजन, स्केच ऑफ मेरवाड़ा (१८५०) पृ. ३३ ।
५८. फाइल संख्या ६ (३), १८२१ चौक कमिशनरी कार्यालय, भजमेर ।
५९. फाइल क्रमांक ५६६, १८९२-१९१२ (रा. रा. पु. मं.) ।
६०. सेप्टिमेंट प्रीचार्ज, असिस्टेंट कमिशनर भजमेर-मेरवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक २०-१०-१८९२ (रा. रा. पु. मं.) ।
६१. उपर्युक्त ।
६२. परराष्ट्र एवं गुप्त-विमर्श, संख्या २२-२३, ३० अप्रैल, १८५८ (रा. रा. पु. मं.) ।
६३. भजमेर कमिशनर कार्यालय, फाइल संख्या ४२ (रा. रा. पु. मं.) ।
६४. भजमेर कमिशनर कार्यालय, फाइल संख्या ८५ (रा. रा. पु. मं.) ।
६५. रिसालदार अब्दुलसमद की घोषणा, रेजीडेंसी रिकॉर्ड फाइल संख्या ३ (८)-५३ ।
६६. भजमेर कमिशनर कार्यालय फाइल संख्या (रा. रा. पु. मं.) ।
६७. शेरिंग, दी इंडियन चर्च क्यूरिंग दी ग्रेट रिबेलियन (१८५६) पृ. १८४-८५ ।
६८. प्रबोन्स एन एकाउन्ट ऑफ दी म्यूटिनीज इन अवध एण्ड ऑफ दी सीज ऑफ लखनऊ रेजीडेंसी (१८५६) अनुसूची १२ पृ. ५५६ ।
६९. शेरिंग-दी इंडियन चर्च क्यूरिंग दी ग्रेट रिबेलियन (१८५६) पृ. १८६ ।
७०. भजमेर कमिशनर कार्यालय, फाइल संख्या १४ (रा. रा. पु. मं.) ।
७१. सन् १९२१ में वार्षिक समाज और भजमेर के वार्षिक अधिवेशन के अवसर



पर प्रोफेसर धीमूलाल धनोपिया का माधुख धार्य प्रतिनिधि सभा की पत्रिका, खंड ११ पृ. ४८ । (१९३१) ।

७२. चीफ कमिश्नर द्वारा गवर्नर जनरल को पत्र दि. ३० अप्रैल, १९०४ फाइल संख्या ८३ ।
७३. प्रोफेसर धीमूलाल का लेख "काजेज ऑफ दी इंडियन रिबोल्ट" राजपूताना हेराल्ड ।
७४. रसल "भाई शायरी इन इंडिया" (१८६०) खंड १ पृ. १४६ प्रीचाई "म्यूटिनीज इन राजपूताना" (१८६०) पृष्ठ २७७ ।
७५. प्रीचाई "फोम सिपाई टू सूबेदार" पृ. ४१ ।
७६. उपर्युक्त पृ. १२७-१२८ ।
७७. रायबस, उत्तर-पश्चिमी सूबा सम्बन्धी टिप्पणियाँ, पृ. ७ (१८५८) (रा. रा. पु. मं) ।
७८. अजमेर कमिश्नर कार्यालय, फाइल संख्या ८५ ए. पृ. ८८-१०० (राज. रा. पु. मं) ।



## १८५७ का विद्रोह और अजमेर

मई, सन् १८५७ में जब सैनिक विद्रोह प्रारम्भ हुआ तब कर्नल ब्रिक्सन अजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर थे। वे उत्तर-पश्चिमी सूबो के सेप्टिनेंट गवर्नर के सीधे नियंत्रण में थे। नीमच यद्यपि मध्य प्रांत के ग्वालियर में था तथापि राजपूताना के अन्तर्गत रखा गया था। नीमच के कमिश्नर का कार्य मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के अधीन था। वह नीमच छावनी में ही रहते थे।<sup>१</sup>

उन दिनों राजपूताना में कोई रेलमार्ग नहीं था। कलकत्ता-साहीर रेलमार्ग कानपुर ॥ आगे तक नहीं पहुँच पाया था और बम्बई-अजमेर ॥ बीच जो वर्तमान रेलमार्ग दिखाई देता है, उसका उस समय निर्माण नहीं हुआ था।<sup>२</sup> अजमेर से १६ मील की दूरी पर नसीराबाद छावनी में दो रेजीमेंट बंगाल नेटिव इन्फैंट्री १५ एवं ३० तथा फर्स्ट बम्बई कैवेलरी और पैदल तोपखाना बँटरी तैनात थी। नसीराबाद से केवल ६० मील दूर देवली छावनी में कोटा हस्ता तैनात था जिसमें इंडियन कैवेलरी की एक रेजीमेन्ट और इन्फैंट्री थी। भारतीय सैनिकों, घुड़सवार और पैदल सैनिकों की एक रेजीमेन्ट नीमच में थी जो नसीराबाद से १२० मील दूर था। अजमेर से सी मील दूर एरिनपुरा में जोधपुर रियासत के अनियमित सैनिकों की पूरी पलटन तैनात थी जिसकी व्यवस्था जोधपुर रियासत के हाथों में थी। मेवाड़ में उदयपुर से पचास मील दूर खैरवाड़ा में अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में भील पलटन थी।

मेरों की एक अन्य पलटन ब्यावर में भी तैनात थी।<sup>३</sup> इस तरह उन दिनों राज-पूताना में पाँच हजार भारतीय सैनिक थे और एक भी गोरी पलटन नहीं थी। केवल स्थानीय पलटनों के प्रतिरिक्त सभी सैनिक विद्रोह के लिए उत्कंठित थे और बग़ावत की चिंगारी धक्कने की बाट देख रहे थे। स्थिति इसीलिए भी विकट थी क्योंकि इस क्षेत्र में स्थित दोनों सैनिक छावनियों में नियमित सैनिकों के रूप में केवल भारतीय सैनिक थे और उनको विद्रोह की सपटों से दूर रखना संभव नहीं था।<sup>४</sup>

राजपूताना में इन पाँच हजार सिपाहियों की उपस्थिति और उनके नियंत्रण के लिए एक भी गोरी टुकड़ी का न होना तत्कालीन ए० जी० जी० के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया था। १,२८,८५५ वर्षों मील भू-भाग में विस्तृत राजपूताना की रक्षा के लिए पाँच हजार सैनिक थे जोकि स्वयं विद्रोह के लिए उत्कंठित थे। इनको नियंत्रित करने के लिए मात्र बीस गोरे सारजेंट वहाँ थे। निकटतम अंग्रेजी सेना की छावनी बम्बई प्रेसीडेंसी में स्थित थी। ऐसी स्थिति में वास्तव में अंग्रेजों के लिए माबी सकट गंभीर चिंता का विषय बन गया था।<sup>५</sup> परन्तु सारेख ने इस विकट परिस्थिति में भी अपना पैरों कायम रखा। इस परिस्थिति के मुकाबले के लिए सार्वम ने सभी रियासतों को अपने-अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और अंग्रेज सरकार की सहायता के लिए सेनाओं को तैयार रखने की धपल की थी।<sup>६</sup>

राजपूताना के बेग़र में स्थित होने के कारण, भजमेर का सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व था। यदि विद्रोहियों का भजमेर पर अधिकार हो जाता तो राजपूताना में अंग्रेजों के हितों को निस्संदेह आघात लगता। भजमेर शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी सज्जाना और सम्पत्ति थी। यदि ये सब विद्रोहियों के हाथ पड़ जाता तो उनकी स्थिति अत्यन्त मुद्दड़ हो जाती। भजमेर में भारतीय सैनिकों की केवल दो कंपनियाँ ही तैनात थी और उन्हें आसानी से विद्रोह के लिए राजी किया जा सकता था। ऐसी हालत में भजमेर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्यावर से दो मेर रेजीमेंट बुलासी गई थीं ताकि स्थानीय सिपाहियों द्वारा बग़ावत की योजना बनाने से पूर्व ही स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके।<sup>७</sup> एक मामूली पैदल सेना भी बीसा छावनी से भजमेर बुलासी गई थी।<sup>८</sup> कोटा पलटन को भी तत्काल भजमेर पहुँचने के आदेश भेज दिए गए थे,<sup>९</sup> परन्तु इन आदेशों के पहुँचने के पूर्व ही देवली स्थित पलटन ने भागरी के लिए कुछ कर दिया था। कुछ दिनों से बाजारों और छावनियों में शत्रु से भद्रेशवाहक फ़ौजों के वेश में पहुँच कर विद्रोह का संदेश प्रसारित कर रहे थे और सर्वत्र अफ़वाहों का बाजार गरम था। अफ़सरो को यद्यपि यह विश्वास था कि उनके मातहत सिपाही दगा नहीं करेंगे तथापि संपूर्ण राजपूताना में व्याप्त असंतोख की देखते हुए उन पर पूरा भरोसा संभव नहीं था। आशंका का एक और कारण यह भी था कि भजमेर में बंगाल नैटिव आर्मी की पन्द्रहवीं रेजीमेंट थोड़े समय पहले ही मेरठ से आई हुई थी, और इसमें पूरविया सिपाही भरे पड़े

ये ।<sup>१०</sup> इनको विद्रोह के लिए भड़काना बहुत आसान था । अतएव इनकी जगह मेरों को सौनात किया गया । पहाड़ी, धर्मसम्पन्न तथा नीची जाति के होने के कारण मेरों की विद्रोहियों के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं थी । मेरों के कारण ही भजमेर में विद्रोह न हो सका और सम्पूर्ण राजपूताना में विद्रोही शक्तियाँ सबल न हो सकीं ।<sup>११</sup>

सौभाग्य से राजपूताना की सभी रियासतों ने पूर्णतः अंग्रेजों की मदद की । इसका कारण यह भी था कि अंग्रेजों के संरक्षण के कारण ही ये रियासतें मराठों और पिढारियों के भय-कर आतंक और सूट से बच पाई थी ।<sup>१२</sup> सन् १८०३ से लेकर सन् १८१७ तक इन बीसह वर्षों में मराठों ने इन राजपरानों को जिस तरह सूटा और अपमानित किया था उसका सहज अनुमान संभव नहीं है । सन् १८५७ तक के मत चालीस वर्षों में मराठों की बर्बर प्रवृत्ति और उनके अत्याचार को लोग भूलें नहीं थे ।<sup>१३</sup> इसके अतिरिक्त इन रियासतों में आपसी तनाव एवं कलह की स्थिति भी बनी हुई थी । कई राजपरानों के प्रति वहीं के ठाकुरों में असंतोष फैला हुआ था । इसलिए इन राजपरानों को अंग्रेजों के संरक्षण की आवश्यकता बनी हुई थी । इन राजपरानों की आपस में भी नहीं बनती थी । इनमें राजनीतिक दूरदर्शिता न होने से वे राजनीतिक घटनाक्रम को समझने में असमर्थ थे ।<sup>१४</sup> मराठा अत्याचारों के खौफ और तत्पश्चात् पिढारियों की भारी लूट-वसोट ने राजपूताना के इन शासक राजपरानों को इतना पंगु बना दिया था कि वे बगावत का अपेक्षा अंग्रेज-संरक्षण को ज्यादा प्रवृत्त सगमते थे । इन लोगों को यह भी भय था कि बगावत के फल-स्वरूप अंग्रेजों की शक्ति क्षीण होने पर उनके अधीन असंतुष्ट ठाकुरों को सर उठाते देर नहीं लगेगी । अतएव विद्रोही सैनिकों को राजपूताने के किसी भी राजपराने से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और न उन्हें इनकी सहानुभूति ही मिली । यही कारण था कि सन् १८५७ के विद्रोह के इतिहास में राजपूताने के किसी भी राजपराने द्वारा ब्रिटिश विरोधी भूमिका निभाए जाने का उल्लेख तक नहीं मिलता है ।<sup>१५</sup> उन सभी राजाओं को, जिन्होंने इस संकटकाल में मार्गदर्शन चाहा था—यही “नेक” सलाह दी गई थी कि वे दृढतापूर्वक अंग्रेजों का साथ बफादारी से निभाएं ।<sup>१६</sup>

उन दिनों नसीराबाद छावनी में देशी पलटन की १५वीं और २०वीं इन्फेन्ट्री, भारतीय तोपखाना टुकड़ी और फर्स्ट बम्बर्ड सावर्स के सैनिक थे । १५वीं भारतीय इन्फेन्ट्री ३ मई, १८५७ को ही मेरठ से आई थी । यद्यपि नसीराबाद छावनी के सैनिक बगावत के लिए अत्यधिक उत्सुक थे तथापि अबाला से भारतीय इन्फेन्ट्री की जो टुकड़ी रायफल प्रशिक्षण प्राप्त कर गभीरसिंह जमादार के नेतृत्व में नसीराबाद लौटी थी, उसने यहाँ के सैनिकों को विश्वास दिलाया कि एन्फील्ड रायफलों और कारतूसों में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे धर्म या जाति को छतरा हो ।

इस कारण वे कुछ समय तक हथियार उठाने में हिचकते रहे। परन्तु मेरठ में सैनिक विद्रोह के समाचार ने उनमें विद्रोह की भावना प्रज्वलित कर रखी थी।<sup>१७</sup> प्रत्येक सैनिक टुकड़ी विद्रोह का साथ तो देना चाहती थी परन्तु पहल कदमी नहीं करना चाहती थी।<sup>१८</sup> अमेज़ इन अफवाहों से बुरी तरह भयभीत थे। उन्होंने सैनिक केन्द्र की रक्षा के लिए छावनी में फस्टे लांसर्स के उन सैनिकों से, जो बफादार समझे जाते थे गश्त सपवाना आरंभ कर दिया था तथा गोले भर कर तोपें सैवार कर रखी थीं।<sup>१९</sup>

सरकार ने सिपाहियों के संदेह मिटाने के लिए जितने प्रयास किए उतनी ही भाग घीर भड़की। सरकार द्वारा चिकने कारतूसों को हटा देने के आदेश ने इनमें घीर संदेह उत्पन्न कर दिया था। एक और नई अफवाह उनमें फैल गई थी कि उनका धर्म नष्ट करने के लिए छाटे में हड्डियों का चूरा मिलाया गया है। जब उनसे अजमेर के राजाने व मल्गानार का भार सौंप देने को कहा गया तो सिपाही भड़क उठे व २८ मई, १८५७ को दिन के तीन बजे खुले विद्रोह पर उतारू हो गए।<sup>२०</sup>

१५वीं नेटिव इन्फेन्ट्री के सिपाहियों ने तोरणाने के सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया था। घाऊसरो ने अपने सैनिकों को समझाने का प्रयास किया परन्तु निष्फल रहे। यद्यपि १७वीं नेटिव इन्फेन्ट्री ३० मई, १८५७ तक हिचकिचाहट के कारण सत्रिय कार्यवाही से घबरा रही परन्तु अंत में जब १५ वीं इन्फेन्ट्री के जवानों ने उन्हें भी सतवारा तो वह इनके साथ मिल गई। यहाँ तक कि सामने (मंगीतवासी सैनिक) जिनके बारे में माय्यता थी कि वे बफादार बने रहेंगे, अपने दो अफसरों और तोरणाने के साथ विद्रोहियों से मिल गए। जब उनकी विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया तो उन्होंने हवा में गोली चलाकर आदेश का पालन किया। विद्रोही लोगों से पहला गोला दगते ही लांसर्स ने भी अपनी गगारें भंग कर दीं व हथियार-उधर विनश्वर हुए। उनके जो अफसर उन्हें समझाने के लिए छाते बड़े से मारे गए उसका शायम हुए। इन अफसरों के से एक अफसर ग्यूसरी के विद्रोहियों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिए।<sup>२१</sup>

अधिक समय तक मुद्रासना करना ब्यर्थे समय कर करनेल पेन्नी ने लांसर्स को बागा बुवा दिया और सभी अधिकारियों ने वहाँ से हट कर ब्यावर पहुँचने का फैसला किया। बाकी विद्रोहियों को तोपों से पहला गोला दगते ही चंडेन् अधिकारियों ने छावनी में अपने बीबी-बख्शों को सुरक्षा के लिए ब्यावर रवाना कर दिया था। मार्ग में इनके प्राणों की रक्षा करने में अपनी स्वाधीनता का परिचय दिया और इनके आदेश के मार्ग की विद्रोहियों से रक्षा करने में सहयोग दिया। यह टोपी टूटी मात्र एक मलहरी हुई दूसरे दिन ब्यावर पहुँची। वहाँ कमिशनर काँग रिप्ले ने अधिकारियों एवं सैनिक अफसरों के दरजे की व्यवस्था करने वहाँ

की तथा महिलाओं और बच्चों को डाक्टर स्मॉल और उनकी पत्नी ने अपने यहाँ ठहराया।<sup>२२</sup> इस टोली को रातभर परेशानी एवं मार्ग की भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। ये सोच यहाँ जबतक कि विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर रुख नहीं कर दिया तबतक मेरवाड़ा बटेनियन की सुरक्षा में रहे। उसके बाद सैनिक अधिकारी अजमेर छोड़ गए जहाँ उन्हें बैरक सड़हरों के रूप में मिली। महिलाएं और बच्चे जोधपुर महाराजा के निमंत्रण पर वहाँ चले गए। महाराजा ने इन्हें साने के लिए बाहन एवं सुरक्षा के लिए अपने सैनिक भेज दिए थे। नसीराबाद से ब्यावर भागते समय मार्ग में सांसर्स के कर्नल पेन्नी को रास्ते में दिल का दौरा पड़ा जिस कारण घोड़े से सड़क पर गिरकर उसका देहान्त हो गया।<sup>२३</sup>

अग्नेजो के छावनी से भागते ही यहाँ भराजकता फैल गई थी। घरों को आग लगा दी गई, तिजोरियां तोड़ दी गई और प्राप्त घन विद्रोही सैनिकों ने धेतन के तौर पर प्राप्त में बाँट लिया था। सूट के सामान का लाइन्स में डेर लगा दिया गया था। इन विद्रोही सैनिकों ने व्यर्थ में रक्तपात नहीं किया। बगावत के समय जो चार अफसर घायल या मृत हुए उन्हें छोड़कर एक बूढ़ खून नहीं गिरा और न कलेधाम ही हुआ। ३०वीं नेटिव इन्फैंट्री ने अपने अफसरों के हाथ तक नहीं लगाया। इन अफसरों में से एक अफसर कैप्टन पैनिथिक सायकल ब्राउ बजे तक इन लोगों के साथ रहे परन्तु जब १५वीं इन्फैंट्री ने उन्हें स्पष्ट हिदायतें दीं तो भज-बूरन इन्हें भी अलग जाना पड़ा। मार्ग में इनकी सुरक्षा के लिए पाँच सैनिक तैनात कर दिए गए थे। ३०वीं पसटन के अन्य अधिकारी पूरी रात और दूसरे दिन भी अपने सैनिकों के बीच ठहरे रहे। एक सौ बीस सैनिकों की एक टुकड़ी अपने भारतीय अफसर के साथ पूरी वफादार रही तथा उसने इन भगोड़े अधिकारियों को ब्यावर तक सुरक्षित पहुँचाने तक में सहायता दी।<sup>२४</sup>

छावनी की तहस-नहस करने के बाद, विद्रोही सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। सेप्टिमेन्ट वास्टर तथा हीथकोट डिप्टी क्वार्टर मास्टर ने जोधपुर और जयपुर की सेनाओं की मदद से इन्हें घेर कर पदेड़ने का प्रयत्न भी किया परन्तु असफल रहे। इन्होंने १८ जून को दिल्ली पहुँचकर अग्नेज पसटन पर, जो कि दिल्ली का घेरा डाले हुई थी पीछे से आक्रमण किया। दूसरे दिन दोनों के बीच कड़ा सघर्ष हुआ जिसमें अग्नेज सेना पराजित हुई।<sup>२५</sup>

विद्रोही सैनिकों ने अजमेर पर आक्रमण करने के बजाय सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इसका एक कारण यह भी था कि उनके पास पहले ही सूट का माल था और वे अब अधिक समय खराब करने की स्थिति में नहीं थे। अजमेर-अस्त्रागार पर अधिकार करना कठिन कार्य था। उस समय यह अफवाह जोरों पर थी कि दोसा से अग्नेज पसटन अजमेर पहुँचने वाली है। एक महत्वपूर्ण कारण यह

भी था कि इन सिपाहियों में बहुतेरों के साथ उनके बीबी-बच्चे भी थे।<sup>२६</sup> उन दिनों विद्रोहियों का लक्ष्य दिल्ली था; इसलिए शायद उन्हें विद्रोह के बाद सीधा दिल्ली पहुँचने का निर्देश मिला होगा।

१५वीं नेटिव इन्फैण्ट्री के एक अधिकारी ई. टी. ग्रीचार्ड ने विद्रोहियों को दिल्ली कूच के बारे में बताया कि मराठा सहकें खराब थीं और उनके साथ लूट का अत्यधिक सामान था तथापि वे तेजी के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। वे अपने लूट के माल की बिना परवाह किए तेजी से आगे बढ़ते गए। कई वागियों ने तो अपनी लूट का माल रास्ते के गाँवों में ही लोगों के पास छोड़ दिया। ग्रीचार्ड ने एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बतलाया कि “राजपूताना की रियासतों के सैनिक अपने साथ अंग्रेज अफमरों के होते हुए भी इन वागी सिपाहियों पर आक्रमण करने में हिचकिचाते ही नहीं थे बल्कि उनकी सहायुभूति भी इन विद्रोहियों के साथ थी क्योंकि उनका भी यह विश्वास था कि अंग्रेजों ने उनके धर्म में हस्तक्षेप किया है।”<sup>२७</sup>

यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है कि विद्रोही सैनिकों ने अजमेर की स्थिति का लाभ नहीं उठाया। अजमेर में प्रतिरक्षा कार्यवाहियों के लिए नियत अंग्रेज अधिकारियों का न केवल लाना-पोना और सोना हराब हो गया था बल्कि वे इतने हताश हो गए थे कि ठनिक सा संदेह होने पर बस सैनिक को फाँसी पर लटका दिया करते थे। जोधपुर के महाराजा ने एक बड़ी फौज अंग्रेजों की सहायता के अजमेर भेजी थी, परन्तु इस फौज का व्यवहार बड़ा ही अपमानजनक था। इस-लिए इन पर पूर्ण विश्वास नहीं होने के कारण इसे वापस भेज दिया गया था। नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों ने अजमेर की इस कमजोर स्थिति से किसी तरह का लाभ नहीं उठाया। वे आश्चर्यजनक जल्दबाजी से दिल्ली की ओर कूच कर गए।<sup>२८</sup> यही घाटूवा के विद्रोहियों ने भी किया जिसका नेतृत्व मारवाड़ के सात ठाकुर कर रहे थे। वे पहले दिल्ली पहुँच कर बहानुर ग्राह की सेवामें उपस्थित होना चाहते थे तथा उनके फरमान हासिल करने के बाद अजमेर पर आक्रमण करना चाहते थे।<sup>२९</sup> केप्टन कॉप्लैंड ने अंग्रेजों के हाथ लगा जो मुगल पत्र-व्यवहार इस संबंध में ए. जी. जी. की प्रस्तुत किया उसके अनुसार दिल्ली के विद्रोही नेताओं ने घाटूवा के विद्रोहियों को पहले दिल्ली पहुँचने का आदेश दिया था। यदि इस सदन की सभी कड़ियों को जोड़ा जाए तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है कि विद्रोहियों में दिल्ली की ओर पहले कूच इसलिए किया क्योंकि वहाँ उनकी उपस्थिति नितांत आवश्यक थी और वे वहाँ से मुगल सम्राट का फरमान प्राप्त कर अपनी गतिविधियों और कार्यवाहियों को संवैधानिक रूप देना चाहते थे। यह स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च सत्ता से प्रसिद्ध होने की भावना उनमें लूटपाट करने की अपेक्षा कहीं अधिक थी। दिल्ली में एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना हो गई थी जिस प्रतीक मान-कर वे सभी लोगों को अपने पक्ष में कर सकते थे।<sup>३०</sup> नसीराबाद के विद्रोही

सैनिक बढ़ी ही आसानी से अजमेर पर अधिकार करने की स्थिति में थे। वे इसे लूटकर प्राप्त धन से अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना सकते थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों की ही भाँति इस उथल-पुथल के दिनों में देहली और बहादुरशाह पर टिकी हुई थी।<sup>१३१</sup> नीमच-छावनी के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली और आगरा को शूच करते समय मार्ग में देवली की छावनी को भाग लगा कर सम्पूर्ण गोला-बारूद अपने अधिकार में कर लिया था।<sup>१३२</sup>

इस उथल-पुथल के काल में ए. जी. जी. जनरल पेट्रिक सॉरेंस को विद्रोहियों पर आक्रमण की अपेक्षा अजमेर की रक्षा अधिक प्रिय थी। अजमेर में किसी भी तरह सैनिक गतिविधि का भय उनके दृष्टिकोण में इस सम्पूर्ण प्रांत का भंग्रेजों के विरुद्ध उठ सके होना था। वह ऐसा सफट मोल लेने को तैयार नहीं थे।<sup>१३३</sup>

अजमेर की स्थिति हरमेजेस्टीज इन्फेन्ट्री और १२वी बम्बई इन्फेन्ट्री के वहाँ पहुँचने पर सुदृढ़ हो गई थी। कर्नल सॉरेंस अजमेर-मेरवाड़ा के चीफ कमिश्नर के रूप में इन फौजों का भार स्वयं सम्हालने बाबू से अजमेर आ गए थे। अजमेर के किले की मरम्मत करवाकर छः माह के लिए राशन फौज के लिए वहाँ इकट्ठा कर लिया गया था। सॉरेंस के दिमाग में भंग्रेजी नीति का मुख्य लक्ष्य यही था कि अजमेर तथा वहाँ के गोला बारूद और खजाने की सुरक्षा की जाए। उनके अपने शब्दों में "अजमेर के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता था। राजपूताना के लिए उसका महत्व उतना ही था, जितना उत्तरी भारत में दिल्ली का है और वहाँ पर विद्रोह होने का भय असंतुष्ट तत्वों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाना है।" सन् १८५८ में भारत सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ब्रिगेडियर जनरल सॉरेंस ने लेफ्टिनेंट कर्नल की सेवाओं की भुक्त कठ से सराहना की, जिन्हें मेरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था। उसके द्वारा की गई उचित व्यवस्था के कारण विद्रोही तत्व अजमेर जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहर में हाथ डालने से कतराते रहे।<sup>१३४</sup>

सन् १८५७ के उथल-पुथल भरी हलचल का अंत होने पर भंग्रेज प्रशासन ने इस बात में गर्व का अनुभव किया कि राजस्थान में उपद्रव केवल नियमित सैनिकों तक ही सीमित रहा और इसका राजघरानों और आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भंग्रेजों ने इस पर भी संतोष प्रकट किया कि वे सभी लोग उनके साथ रहे, जिनके पास "धन-दौलत, संपत्ति और प्रतिष्ठा थी।"<sup>१३५</sup>

## अध्याय १०



राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ १८५७ (१९५७) पृ० १४-१५ ।

२. सड़गावत-वही पृ० २१ ।

३. ड्रेवर-ए चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१९०५) पृ० २ ।

४. हॉम्स-ए हिस्ट्री ऑफ दी म्यूटिनी (१८९८) पृ० १४८, ड्रेवर-ए चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१९९) पृ० ३ ।

५. ज्वालासहाय-सॉयल राजपूताना (१९०२) पृ १९०-२९५ ।

६. हॉम्स-ए हिस्ट्री ऑफ दी म्यूटिनी पृ० १४८, ड्रेवर-ए चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी पृ० ३ (१९०५) ।

७. फार्ड० भार० कॉल्विन द्वारा डिवसन को पत्र जिसमें उन्हें अजमेर स्थित शास्त्रागार की भेरी की रखवाली में सौंप देने के बारे में राय मांगी गई थी; दिनांक १६ मई, १८५७ । डिवसन का कॉल्विन को पत्र दिनांक १९ मई, १८५७ ।

८. डिवसन द्वारा लॉरेंस को पत्र, दिनांक २५-५-१८५७ ।

९. डिवसन द्वारा कोटा सैनिक टुकड़ी के कमान्डर कैप्टिन डेनियल को पत्र, ब्यावर दिनांक १८-५-१८५७ ।

१०. डिवसन द्वारा कॉल्विन को पत्र दिनांक १९ मई, १८५७ ।

११. ड्रेवर-ए चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१९०५) पृ० ३ से ४ ।

१२. सड़गावत-राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ १८५७ (१९५७) भूमिका पृ० ५ ।

१३. मुंशी ज्वालासहाय-सॉयल राजपूताना (१९०२) ।

१४. सड़गावत-राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ १८५७ (१९५७) पृ० ५ (भूमिका) ।

१५. उपर्युक्त भूमिका पृ० ३, ४, ५ ।

१६. राजस्थान के नरेशों द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में लॉरेन्स की रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स वेपर सं० ७७ पृ० १३०, अनुच्छेद १२० ॥ १३० । (१८६०) ।

१७. पत्र सं० १०७-ए-७८४ दिनांक २७ जुलाई, १८५८ ए. बी. जी. द्वारा भारत सरकार को पत्र दि० २७ जुलाई, १८५८ संख्या १०७-ए-७८४ ।

१८. डिवसन द्वारा लॉरेंस को पत्र, ब्यावर दिनांक २३-५-१८५७ ।

१९. मुंशी ज्वालासहाय-सॉयल राजपूताना, (१९०२) पृ० १९७-१९८ ।

३२. बी० पी० लॉयल द्वारा कंस्टिन कार्टर को पत्र दिनांक ६ जून, बी० पी० लॉयल द्वारा कनैल डुराड को पत्र । (राज० रा० अभिलेखागार) ।
३३. शॉवर्स :—ए मिस्सिस चेप्टर ग्रॉफ़ बी इन्डियन म्यूटिनी (१८८८)  
पृष्ठ ४६  
ट्रैवर :—ऐ चेप्टर ग्रॉफ़ बी इन्डियन म्यूटिनी (१९०५) पृ० ८ ।  
लड़गावत :—राजस्थान्स रोल इन बी स्ट्रगल ग्रॉफ़ १८५७ (१९५७)  
पृष्ठ २२-२३ ।
३४. ट्रैवर :—ए चेप्टर ग्रॉफ़ बी इन्डियन म्यूटिनी (१९०५) पृ० १४ ।
३५. लड़गावत :—राजस्थान्स रोल इन बी स्ट्रगल ग्रॉफ़ १८५७ पृ०  
८७-८९ ।
-

## राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी हलचल

अंग्रेज सरकार की हमेशा यह नीति रही थी कि रियासतों का प्रशासन अंग्रेज प्रशासन के मुकाबले खराब दिखता रहे ताकि देशी शासकों की तुलना में जनता अंग्रेज शासकों को अच्छा समझे। इस कारण अजमेर-मेरवाड़ा में राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति राजपूताना की रियासतों से ज्यादा होना स्वाभाविक था। अजमेर के सम्पन्न लोगों ने शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शनैः शनैः शिक्षित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी। यह राजनीतिक चेतना एक छोटे से समुदाय तक ही सीमित रही और कभी भी खुलकर विस्तृत जन चेतना का स्वरूप नहीं ले पाई। उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल की क्रान्तिकारी हलचलों का प्रभाव अजमेर पर भी दिसाई देने लगा।

बंगाल के देशभक्त क्रान्तिकारियों के साहित्य “वर्तमान रणनीति” और “मुक्ति कोन पथ” से यहाँ के नौजवान अत्यंत प्रभावित हुए थे। “बग-मग” के बाद ही अजमेर में क्रान्तिकारियों की गतिविधि आरम्भ हुई। क्रान्तिकारी “स्वराज्य” प्राप्त करना चाहते थे। इनकी यह मान्यता थी कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए ढकंठों और हत्याएं पाप नहीं हैं।<sup>१</sup> अंग्रेज सरकार के प्रति रोष एवं उसे उखाड़ फेंकने की भावना इनमें भी उतनी ही तीव्र थी जितनी कि बंगाल के आतंकवादियों में थी।<sup>२</sup> इन लोगों ने अजमेर में क्रान्तिकारी विचारधारा के प्रसार-हेतु शिक्षण सस्थानों का जाल सा बिछाकर उनके माध्यम से विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना

## राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी हलचल

अंग्रेज सरकार की हमेशा यह नीति रही थी कि रियासतों का प्रशासन अंग्रेज प्रशासन के मुकाबले खराब दिसता रहे ताकि देशी शासकों की तुलना में जनता अंग्रेज शासकों को अच्छा समझे। इस कारण भजमेर-भेरवाड़ा में राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति राजपूताना की रियासतों से ज्यादा होना स्वाभाविक था। भजमेर के सम्पन्न लोगों में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शनैः शनैः शिक्षित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी। यह राजनीतिक चेतना एक छोटे से समुदाय तक ही सीमित रही और कभी भी खुलकर विस्तृत जन चेतना का स्वरूप नहीं ले पाई। उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल की क्रान्तिकारी हलचलों का प्रभाव भजमेर पर भी दिखाई देने लगा।

बंगाल के देशभक्त क्रान्तिकारियों के साहित्य "वर्तमान रणनीति" और "भुक्ति कोन पय" से यहाँ के मीनबान अत्यंत प्रभावित हुए थे। "बंग-मंग" के बाद ही भजमेर में क्रान्तिकारियों की गतिविधि आरम्भ हुई। क्रान्तिकारी "स्वराज्य" प्राप्त करना चाहते थे। इनकी यह मान्यता थी कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए इकट्ठी और हत्याएं पाप नहीं हैं।<sup>१</sup> अंग्रेज सरकार के प्रति रोष एवं उसे उखाड़ फेंकने की भावना इनमें भी उत्पन्न हो तीव्र हो जिसकी कि बंगाल के छातकवादियों में थी।<sup>२</sup> इन लोगों ने भजमेर में क्रान्तिकारी विचारधारा के प्रसार-हेतु शिक्षण संस्थाओं का जाल सा बिछाकर उनके माध्यम से विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना

जागृत करना प्रारम्भ किया। गैरीवाल्दी और मैजिनी उनके आदर्श थे और उनकी विचारधारा इन क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी।<sup>३</sup>

उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में अजमेर-मेरवाड़ा में जो राजनीतिक चेतना बढ़ी उसके प्रेरणा स्रोत बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। राजपूताना की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अगाध श्रद्धा होने के कारण बंगाल के क्रांतिकारी इस प्रान्त के प्रति आकर्षित हुए थे। राजपूताना ने महाराणा प्रताप व दुर्गादास जैसे वीरों को जन्म दिया था जिनकी वीरता की कहानियाँ पूरे भारत में प्रचलित थीं। इन महापुरुषों की जीवनगाथा क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। बंगाल में क्रांतिकारी पंडितों का सूत्रपात महाराणा प्रताप और राठोड़ वीर दुर्गादास के वैशा-भिमान एवं बलिदान की प्रेरणास्पद भावनाओं का प्रतिफल था।<sup>४</sup> उन्नीसवीं सदी के बंगला साहित्य को राजपूताना के धूरवीरों के शौर्यपूर्ण संघर्ष से प्रेरणा मिली थी। अतएव बंगाल के क्रांतिकारियों का राजपूताना के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। अरविंद घोष द्वारा कई बार राजपूताना का दौरा करने और यहाँ के लोगों में देश प्रेम जागृत करने के उनके प्रयासों की पृष्ठभूमि में यही भावना काम कर रही थी। राजस्थान में उस समय शस्त्र कानून लागू नहीं था। इसलिए देश भर के क्रांतिकारियों को यहाँ आसानी से सस्ते भावों में हथियार मिल जाते थे।<sup>५</sup> राज-पूताना के जागीरदार जिन्हें अंग्रेजी शासन ने कुचल दिया था, उनके प्रति तीव्र असंतोष को मन ही मन सुलगाए बैठे थे। क्रांतिकारी इसका अपने हित में उपयोग करना चाहते थे।<sup>६</sup> भालाबाड़ के महाराज राणा जालमसिंह द्वितीय को गद्दी से उतार कर उन्हें अंग्रेजी द्वारा निष्कासित करने की घटना ने भी लोगों की क्रोधाग्नि भड़का दी थी।<sup>७</sup> मेवाड़ में अंग्रेजों की प्रशासनिक तानाशाही का विरोध हाउस ऑफ कॉमन्स तक में प्रतिध्वनित हुआ था और तत्कालीन अंग्रेज पोलिटिकल एजेंट के विरुद्ध वहाँ गम्भीर आरोप लगाए गए थे।<sup>८</sup>

इस तरह की घटनाओं से बंगाल के क्रांतिकारियों में यह धारणा बन चली थी कि राजपूताना की मरुभूमि में उन्हें अपने कार्य एवं गतिविधियों के प्रति व्यापक सहयोग एवं सहानुभूति प्राप्त हो सकेंगी। राजपूताना के जागीरदारों के पास वे सभी साधन-स्रोत उपलब्ध थे, जिनकी सहायता शान्ति में आवश्यकता पड़ती है। कर्नल टॉड द्वारा लिखित राजपूताना की शौर्य गाथाओं ने इस प्रान्त को भारत भर में वीर शिरो-मणि के रूप में स्थापित कर दिया था। सुप्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बकिमचन्द्र चटर्जी और नाटककार डी० एल० राय को राजपूताना की यशगाथाओं से अपार प्रोत्साहन मिला था। अतएव क्रांतिकारियों द्वारा राजपूताना के प्रति इसी भावना के बन आकर्षित होना और अपनी विद्रोही गतिविधियों के लिए राजपूताना को उपयुक्त समझना स्वाभाविक था।<sup>९</sup>

राजपूताना की प्राकृतिक विनिष्टताएँ, विस्तृत निर्जन, महभूमि, घराबली पर्वत की श्रेणियाँ, रेत के विनाश टीबे और अनुन्नतनीय वन राजद्रोही के शरण देने और अंग्रेजों के शंगुल से बचने के लिए सरदान सिद्ध हो सकते थे। धार्मिक समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द भी इस वीर भूमि की निधियों से परिवर्तित हो सकते थे। उन्होंने भी अपनी गतिविधियों के लिए प्रमुखतः शाहपुरा, जोधपुर और भजमेर को केन्द्र बनाया। इन सभी को यह भासा थी कि प्राचीन परम्पराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आन्दोलनों को राजपूताना के राजघराने और सामन्त वर्ग की सहानुभूति प्राप्त होगी। इसी भासा से सभी ने इस प्रान्त को अपनी गतिविधियों का केन्द्र चुना था।<sup>१०</sup>

भजमेर में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वालों में सरवा के राव गोपालसिंह, बारहठ केसरीसिंह, भजुनलाल सेठी और सेठ दामोदरलाल जी राठी प्रमुख थे। ये सभी लोग भजमेर के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासी थे। राव गोपालसिंह भजमेर में सरवा के इस्तरदार थे। बारहठ केसरीसिंह शाहपुरा के ब सेठी भजुनलाल जयपुर के निवासी थे। ये सभी लोग जिन्होंने इनकी प्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी उनका भजमेर से निकटतम सम्बन्ध था।<sup>११</sup> दामोदरदास जी राठी क्रांतिकारियों की अत्यधिक आर्थिक मदद करते थे। बाहर से आने वाले क्रांतिकारियों को आप अपने यहाँ छिपाकर रखते थे। शरविन्द बाबू व श्यामश्रीकृष्ण वर्मा भी आपके ही मेहमान रहते थे। उन्होंने स्वदेशी की भावना को वास्तविक रूप देने के लिए कपड़े का पहला कारखाना ब्यावर में खोला था।<sup>१२</sup> क्रांतिकारी स्वामी कुमारानन्द ने भी अपनी गतिविधियों के लिए भजमेर-मेरवाड़ा को केन्द्र बनाया था। राजस्थान के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी जो बाद में बिजयसिंह पविक के नाम से प्रख्यात हुए, सरवा में बस गए थे और राव गोपालसिंह के यहाँ काम करने थे। इस तरह भजमेर अपने निकटवर्ती क्षेत्रों सहित राजनीतिक विचारधाराओं का केन्द्र बन चला था। श्री भजुनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहठ, बिजयसिंह पविक एवं राव गोपालसिंह सरवा ने मिलकर “वीर भारत सभा” नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन कायम किया। इस संस्था का देश की दूसरी क्रांतिकारी संस्थाओं से सम्बन्ध था।<sup>१३</sup>

भजमेर के क्रांतिकारियों ने राजस्थान के जागीरदारों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त असंतोष का लाभ उठाने का भरमक प्रयत्न किया। राजस्थान का सामन्ती वर्ग अंग्रेजों से असन्तुष्ट था, क्योंकि अंग्रेजों के हाथों उन्हें अपनी राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति खोनी पड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा राजपूताना की रियासतों तथा भजमेर में प्रचलित किए गए नए नियमों से भी वे असन्तुष्ट थे क्योंकि इनका उद्देश्य जागीरदारों को शक्तिहीन करना था। बदोबस्त की कार्यवाहियाँ, सैनिक सेवा की एवज में नगद

राशि का भुगतान, सती-श्रया पर रोक, जागीर एवं सैनिक दस्तों को मंग करने की नीति ने इन सामंती सत्त्वों को नाराज कर दिया था । १४

स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व ने भी भजमेर के लोगो की भावनाओं को इस दिशा में सबसे अधिक प्रभावित किया था । स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायियों ने भजमेर को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाकर यहाँ के लोगों में धार्मिक, राजनीतिक चेतना के प्रसार में बहुत योगदान दिया था । उन्होंने राजपूतो में वैदिक सम्यता के पुनर्जागरण के लिए एक तीव्र उत्कंठा जागृत कर दी थी । १५

राव गोपालसिंह पर भार्य समाज का इसना गहरा रंग चढ़ा हुआ था कि राजनीतिक जीवन के कठोर अनुभवों एवं वैचारिक परिवर्तनों के बावजूद भी यह प्रभाव शिथिल नहीं हुआ था । उनके राजनीतिक जीवन से समास के बाद भी एक लम्बे समय तक यह प्रभाव बना रहा । १६

यदि भजमेर अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए किसी के प्रति ऋणी है तो उसमें सर्वोच्च स्थान स्वामी दयानन्द और उनके भार्य समाज भान्दोलन का है । यह स्वामी दयानन्द के अनुयायियों द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थानों के प्रथक प्रयत्नों का ही फल था कि उन्होंने देश को चोटी के सुधारक और सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रदान किए । जिन्होंने भजमेर में सामाजिक-राजनीतिक चेतना उत्पन्न की । भजमेर में लगभग सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा भार्य समाज के स्कूलों में ही ग्रहण की थी । १७

भजमेर के प्रारम्भिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपना राजनीतिक जीवन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रारम्भ किया था । राव गोपालसिंह ने अपना राजनीतिक जीवन, अकाल पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता और निर्धन तथा राजपूत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने से प्रारम्भ किया था । १८ इनका कार्य-क्षेत्र छोटे जागीरदारों और भूमिजों में था । हथियार इकट्ठे करना इनका मुख्य कार्य था । पथिक जी ओकि उस समय धूपसिंह के नाम से कार्य करते थे, राव साहब के निकट के सहयोगी थे । १९ केसरीसिंह बारहठ ने राजपूत परिवारों एवं घरानों में सांस्कृतिक जागृति लाने का बीड़ा उठाया । २० भजुननाथ सेठो ने तो अपना सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षा जगत् एवं जन समाज की सेवामें समर्पित कर दिया था । २१ इन तीनों ही नातिकारियों में पावचार्य शिक्षा-प्रणाली में प्रति धोर प्रवृत्ति थी । ये राजस्थानी तत्वों का जीवन पूर्णतः भारतीय भाषा-भाषाशास्त्रों के अनुकूल ढालना चाहते थे । उनकी प्रारम्भिक योजनाएँ यद्यपि राजनीति से दूर थीं, तथापि उनमें नातिकारी उद्देश्यों की झलक नहीं मिलती है ।

उन्होंने उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक के प्रारम्भ में एक साधु राजस्थान

के तीन विभिन्न स्थानों से अपना कार्य प्रारम्भ किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी गतिविधियों को ध्यानरूप देने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी। इनकी गतिविधियाँ भी आपस में सम्बन्धित नहीं थीं। सेठी भर्जुनसाल जैनमत प्रवर्तक संस्थाएं पसाने के पक्ष में थे। केसरीसिंह का ध्यान अधिकतर राजपूत परिवारों और धारणों पर केन्द्रित था। राय गोपालसिंह केवल राजपूतों को ही धामे साने के पक्ष में थे।<sup>२२</sup> उनका कार्य-क्षेत्र भी अत्यंत सीमित था। इन प्रारम्भिक कार्यवाहियों का उद्देश्य किसी भी तरह की अंग्रेज विरोधी गतिविधियाँ या हलचल पैदा करना नहीं था। बारहठ केसरीसिंह का धराना राजपूताना में प्रख्यात था तथा उन्हें भापा और धार्मिक कथाओं का पंडित माना जाता था। भर्जुनसाल जी सेठी अपना बाह्यरूप पूर्णतया अहिंसक बनाए हुए थे।<sup>२३</sup> राय गोपालसिंह का राजपूताना के अंग्रेज समर्थक राजपरानों में भी सम्मान था। इन क्रान्तिकारियों की प्रारम्भिक गतिविधियाँ प्रशासनिक एवं सामाजिक महत्व की थी। इस क्षेत्र में भी वे लोग एक ही नीति प्रयोग करने में सक्षम रहे। अपने प्रारम्भिक दस वर्षों में राजनीतिक जीवन में वे लोग धर्म पूर्वक सूक्ष्म और गुप्त रूप से अपने ही केंद्रों में काम करना अधिक पसंद करते थे और संयुक्त कार्यक्रम या एक संयुक्त नीति के गठन का प्रयत्न उन्होंने कभी नहीं किया।

ये क्रान्तिकारी धीरे-धीरे बाहरी क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ध्यावर में राजपूताना काँटन प्रेस और अजमेर में राजपूताना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। उनके प्रभाव से राजपूताना के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में देशभक्ति की गहरी भावना जागृत हुई। सेठ दामोदरदास राठी ने सन् १९०९ के आसपास योगीराम भरविंद और लोकमान्य तिलक को एक गुप्त बैठक में आमंत्रित किया था।<sup>२४</sup> इन बाहरी कार्यकर्ताओं को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने ही स्थानीय कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को एक निश्चित स्वरूप एवं नीति प्रदान की। उनके राजनीतिक विचारों में भारत धर्म महामंडल के स्वामी ज्ञानानंद के प्रयासों की ओर भी अधिक दृढ़ता आई।<sup>२५</sup> राय गोपालसिंह उनके साथ कलकत्ता गए, जहाँ वे प्रसिद्ध देश भक्त सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, वीरेन्द्र पाल, वीरेन्द्र घोष और देवेन्द्र के पनिष्ठ सम्पर्क में आए। इसी समय उन्होंने 'युगान्तर' 'बंदेमातरम्' और 'ममृत बाजार' पत्रिका के सम्पादकों से आपसी सम्पर्क स्थापित किया।<sup>२६</sup>

कलकत्ता से लौटने के बाद राय गोपालसिंह ने अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ कर दी थी। भर्जुनसाल सेठी अंग्रेज शासित भारत के नेताओं के सम्पर्क में आए और उन्होंने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भी वे सम्मिलित हुए थे।<sup>२७</sup>

\* सन् १९०७ का वर्ष इन कार्यकर्ताओं की सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियाँ



एवं अंग्रेज़ विरोधी हलचलों के मध्य विभाजन रेखा सिद्ध हुआ। सन् १९०७ के बाद ही केसरीसिंह जी द्वारा स्थापित चारण राजपूत बोर्डिंग हाउस ने राजनीतिक गति-विधियों में भाग लेना प्रारम्भ किया और भूमिगत "वीर भारत समा" की स्थापना की गई।<sup>३८</sup> सन् १९०७ में ही अर्जुनलाल सेठी द्वारा संचालित वर्धमान विद्यालय ने कार्य प्रारम्भ किया। इसी समय राव गोपालसिंह ने अंग्रेज़ी विरोधी गतिविधियाँ प्रारम्भ की थी।<sup>३९</sup> इस तरह सन् १९०७ का पूर्ववर्ती काल वास्तविक कार्य की अपेक्षा उमंगों एवं कल्पनाओं का काल कहा जा सकता है। इसमें बंगाल के स्वदेशी आन्दोलनकारियों और बाहरी नेताओं से सम्पर्क स्थापित हुआ, जिन्होंने यहाँ के कार्य-कर्ताओं की प्रस्पष्ट एवं अनिश्चित विचारों एवं गतिविधियों को मार्गदर्शन देकर स्पष्टता प्रदान की। सन् १९०७ से ही प्रजमेर-मेरवाड़ा ने क्रान्तिकारी चरण में प्रवेश किया। इसे एक और योगीराज अरविन्द और लोकमान्य तिलक से प्रोत्साहन मिला व दूसरी ओर बंगाल के उच्च क्रान्तिकारी नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। इससे यहाँ की गतिविधियों को दृढ़ता एवं सुस्पष्टता प्राप्त हुई।

सन् १९०७ का वर्ष यहाँ के क्रान्तिकारी इतिहास का ही महत्वपूर्ण चरण है, परन्तु यह समूचे उत्तर भारत के लिए भी इतने ही महत्व का रहा। यह लगभग वही समय था जबकि पंजाब में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में क्रान्तिकारियों की गति-विधियाँ तेज हो चली थीं और रासबिहारी बोस के अनुयायियों ने देश भर के प्रमुख स्थानों में अपने केन्द्र स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। सन् १९०७ के बाद ही दिल्ली में हरदयाल, अमीरचन्द, अवध बिहारी और बालमुकुन्द ने अपनी कार्य-वाहियाँ प्रारम्भ की थी। सन् १९०७ के बाद ही प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने बनारस में क्रान्तिकारी अनुशीलन समिति स्थापित की।<sup>४०</sup> सन् १९०७ के बाद प्रजमेर का आन्तरिक क्रान्तिकारी आन्दोलन उत्तर भारत में क्रान्ति आन्दोलन का प्रसार से पूर्णतः प्रभावित है।

प्रजमेर में राजनीतिक जागृति का उद्भव मुख्यतया बंगाल के स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रेरणा का प्रतिकूल था। अंग्रेज़-विरोधी उत्तेजना की गर्त: सनै: स्वामी दयानन्द के धार्मिक उपदेशों से भी धारा मिलता रहा। परन्तु यदि बंगाल और महाराष्ट्र के क्रान्तिकारी इस क्षेत्र के अपने साधियों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान नहीं करते तो इस क्षेत्र में राजनीतिक जागृति की गति अत्यन्त मंथर होती। राव गोपालसिंह के बारे में बम्बई पुलिस ने ए० जी० जी० को सन् १९०६ में ही यह सूचित कर दिया था कि उनके बारे में "इस तरह की बातें प्रचलित हैं कि उनका सम्पर्क राजपूतों से है और वह स्वयं प्रवल अंग्रेज़ विरोधी हैं।"<sup>४१</sup>

इन क्रान्तिकारियों ने कई क्रान्तिकारी केन्द्र, बोर्डिंग हाउस और स्कूलों के रूप में गोरे, गढ़ी पर क्रान्ति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था।<sup>४२</sup> जन-जागृति

पंदा करने में वे सफल नहीं हुए। धीरे-धीरे जन-साधारण में सार्वजनिक चेतना उत्पन्न करना उनके लिए गंभव ही था। उन्होंने शिक्षण संस्थानों का एक-एक सा विद्या दिया था जो राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में गए थे। वर्तमान विद्यालय में शिक्षा दी जाती थी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रान्ति आवश्यक है तथा सशस्त्र क्रान्ति के लिए रिवॉल्वर और पिस्तौल ज़रूरी हैं। यदि डाक भी डाला जाय तो कोई पाप नहीं है।

केसरीसिंह के भारत में अंग्रेज़ सरकार के प्रति विचार बंगाल के नातिकारियों के समान राजद्रोहात्मक एवं विप्लवकारी थे। युवकों में नातिकारी विचारधारा का प्रसार करने के उद्देश्य से उन्होंने कोटा में राजपूत बोर्डिंग हाउस और जोधपुर में राजपूत-घारण बोर्डिंग हाउस खोला था। अपने भाषणों में वे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में यह बात बूट-बूट कर भरते थे कि शिक्षा-प्रसार के लिए आवश्यक धन-राशि यदि गलत तरीके से भी प्राप्त की जाती है तो इसमें किसी तरह का पाप नहीं है।<sup>३३</sup> केसरीसिंह के सहयोग से गोमदत्त साहू और विष्णुदत्त भजमेर के घासपास के ग्रामों में राजद्रोहात्मक वातावरण बनाने में जुट गए थे। राव गोपालसिंह ने अपने लखे से गोमदत्त साहू और नारायणसिंह को भजमेर में शिक्षा पाने में सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ही युवकों का कोटा-हत्याकाण्ड में प्रमुख हाथ था। उन्होंने गेहलसिंह नामक एक नवयुवक को और तैयार किया था जो ग्रामों में प्रचार के लिए विष्णुदत्त का सहयोगी था। विष्णुदत्त चेतनभोगी अध्यापक के रूप में राव गोपालसिंह के यहाँ काम करते थे। भजुनलाल सेठी की प्रतिष्ठित नातिकारी मास्टर अमीरचन्द, अवधेशविहारी और बालमुकुन्द से अद्वैत मंत्री थे।<sup>३४</sup> ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णुदत्त इन लोगों के बीच कड़ी का काम करता था। वह सदा एक स्थल से दूसरे स्थल की यात्रा करता ही रहता था। मधोन्द्रनाथ सांग्राल की अनुशीलन समिति के दो सदस्य खरवा भेजे गए थे जो इस बनाने की कला जानते थे। मणीलाल और दामोदर निरंतर उत्तर प्रदेश और राजपूताना की यात्रा पर ही रहते थे।<sup>३५</sup>

सन् १९०७ में नातिकारी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट भलकने लगा था। १४ मई, १९०७ को खरवा के दुकानदारों ने विदेशी शक्कर बेचना बन्द कर दिया था। २३ जुलाई, १९०७ को भजमेर-मेरवाड़ा के जागीरदारों ने साहस जुटा कर अपने कष्ट एवं शिकायतों के समाधान के लिए एक समा का आयोजन किया था। राव गोपालसिंह ने २८ अक्टूबर को धर्म महामंडल की भजमेर में आयोजित एक समा की अध्यक्षता की और स्वामी ज्ञानानन्द के साथ ६ मार्च, १९०८ को वायसराय से धर्म महामंडल के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में मिलने के लिए कलकत्ता भी गए।<sup>३६</sup> विष्णुदत्त ने १९०७ तक नातिकारियों का एक अच्छा संगठन तैयार

कर लिया था। उनके प्रमुख सहयोगियों में उत्तरेखनीय नारायणसिंह, सद्मीलाल साहू, रामकरण चावुदेव, सूरजसिंह और रामप्रसाद थे। ये सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और विष्णुदत्त इन्हें भ्रजमेर ले आए थे। विष्णुदत्त क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए राजपूताना का दौरा भी किया करते थे।

इन्होंने नसीराबाद स्थित राजपूताना रायफल के सैनिक अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उनके माध्यम से सैनिकों में अंग्रेजी शासन-विरोधी भावना जागृत करने का प्रयास भी किया। इन्हीं के जरिए शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त किए जाते थे। मुस्तान खान व करीम खान नाम के व्यक्तियों के माध्यम से नसीराबाद से शस्त्र खरीदे जाते थे। मणिलाल और दामोदर नामक व्यक्तियों पर इन क्रांतिकारियों की बम प्रदान करने का जिम्मा था।<sup>३७</sup>

बारहठ केसरीसिंह का सम्पूर्ण परिवार, उनके पुत्र प्रतापसिंह और भाई जोरावरसिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। चारण राजपूत छात्रावास क्रांतिकारी गतिविधियों के केन्द्र बन गए थे और वर्धमान विशालय का इस क्षेत्र में काफी महत्व था। सन् १९११ में भूपसिंह जिन्होंने आगे चलकर बिजयसिंह पथिक के नाम से राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था—राव गोपालसिंह के निजी सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। सन् १९११ तक भ्रजमेर को केन्द्र बनाकर गुप्त समितियों ने काम आरम्भ कर दिया था।<sup>३८</sup>

इन क्रांतिकारियों की सांघाजिक, शैक्षणिक गतिविधियों को राजपूताने के कुछ राजघरानों से सहानुभूति एवं आर्थिक सहायता प्राप्त हुई होगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि क्रांतिकारियों को राजपूताने के राजघरानों का समर्थन प्राप्त था। इसकी सहानुभूति कदाचित् इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों के प्रति पूर्ण जानकारी न होने के कारण ही रही होगी क्योंकि यह अधिकारतः पूर्णतया गुप्त रूप से संचालित की जा रही थी। इन राजघरानों ने इनकी शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सहायता उदारतावश ही की, उन्हें इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति तनिक भी संदेह नहीं था। यहाँ तक कि कोटा के महाराज को भी इनके यहाँ बेसरोसिंह नौकरी करते थे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की कुछ भी जानकारी नहीं थी। स्पष्टतः कुछ राजघरानों द्वारा बारहठ केसरीसिंह और राव गोपालसिंह को दी गई वित्तीय सहायता का अर्थ उनके द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना नहीं माना जा सकता।<sup>३९</sup> जोधपुर-महंत हत्या-काण्ड के मामले में कोटा के महाराज ने अपने फैसले में कहा कि ये माम इस सदर्भ में किंचित भी ठप्पपूर्ण नहीं हैं। इन निर्णय से यह अर्थ सगा लेना भी अनुपयुक्त होगा कि राजघरानों का क्रांतिकारियों से निरपेक्ष वा संबंध रहा था।<sup>४०</sup>

सन् १९११ के बाद ही राजस्थान के क्रांतिकारियों का अधीननाथ साम्याल

घोर रासबिहारी बोस के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था। इनमें से प्रतापसिंह ने दिल्ली घोर बनारस पड़मंथ कोडो में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राजस्थान में उस समय घस्त्र-घस्त्रों पर कोई साईगिस्त न होने के कारण यह प्रान्त प्रांतिकारियों के लिए घस्त्र-घस्त्र एकत्रित करने व उनके निर्माण-हेतु गुप्त कारगुजाने स्थापित करने के लिए उद्युक्त स्थान था। इसी उद्देश्य से रामबिहारी बोस ने हार्डिंग बमकांड के बाद ही भूपसिंह घोर बालमुकुन्द को राजस्थान भेजा था। इनके राजस्थान आने के बाद वहाँ के प्रांतिकारियों का देश के क्रान्तिकारी संगठनों से संबंध स्थापित हो गया था।<sup>४१</sup>

सन् १९१२ से इन क्रान्तिकारियों ने ऊर्कतिया घोर हत्याएं प्रारम्भ कर दी थीं। जून १९१२ में बारहठ केसरीसिंह की क्रान्तिकारी टोनी ने जोधपुर के एक महत की हत्या कर दी थी। इस हत्या का उद्देश्य क्रान्तिकारी गतिविधियों के लिए धन प्राप्त करना था। क्रान्तिकारी इन दिनों धन की भारी कमी अनुभव कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अब लोगों ने डर से इनकी वंशानुगत घोर सामाजिक सत्थामों को धन देना स्थापित कर दिया था तथा वे इनसे सम्पर्क रखने में कलराते थे।<sup>४२</sup>

दिसम्बर १९१२ में हार्डिंग की हत्या का प्रयत्न किया गया जिसमें उनका एक अग्रस्थान मारा गया था। इसी दिल्ली पड़मंथ कांड के सिलसिले में बाद में सेठी भजुनलाल को गिरफ्तार किया गया था और बारहठ केसरीसिंह पर सबेह के कारण नजर रानी जाने लगी थी।<sup>४३</sup> इन क्रान्तिकारियों द्वारा आयोजित दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक हत्याकांड मारवाड के निमाज नामक कस्बे में सेठी भजुनलाल के विद्याभित्तों द्वारा किया गया था।<sup>४४</sup> यद्यपि ये दोनों ही हत्याकांड सन् १९१२ और सन् १९१३ में हुए थे परन्तु इनका सुराग मार्च, १९१४ तक पकड़ में नहीं आ सका। सन् १९१४ में वायसराय बमकांड के निमित्तले में सेठी जी के एक शिष्य शिवनारायण को गिरफ्तार किया गया था। इस व्यक्ति ने खबर कर निमाज महत हत्याकांड की भी जानकारी पुलिस को दे दी थी। इस पर मोतीचन्द को फांसी की सजा व विष्णुदत्त को दस वर्ष की काले पानी की सजा दी गई।<sup>४५</sup>

भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के अधिकारी हार्डिंग बमकांड के अभियुक्त जोरावरसिंह (बारहठ केसरीसिंह के भाई जो निमाज हत्याकांड के अभियुक्त भी थे) की तलाश में अप्रैल १९१४ में जोधपुर पहुँचे थे, उस समय गुप्तचर विभाग के सुपरिटेंडेंट थॉमसट्रान को यह पता चला कि वहाँ का एक धनी साधु भी गत दो वर्षों से लापता है। उसके अनुयायियों ने उनकी काफी तलाश भी की परन्तु उसका कहीं पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में ३ मई, १९१४ को रामकरण, केसरीसिंह जी बारहठ, लक्ष्मीलाल, हीरालाल और साहूजी को गिरफ्तार कर उन पर कोटा के सेशन न्यायालय में मुकदमा चलाया गया।<sup>४६</sup>

अंग्रेज सरकार ने राव गोपालसिंह के विरुद्ध सबसे पहले अक्टूबर १९१४ में कार्यवाही की।<sup>४७</sup> भजमेर के कमिशनर ए० टी० होम्स ने उन्हें मिलने के लिए पुष्कर बुलाया। वहाँ उन्हें एक विशेष पत्र दिया गया तथा उनसे उनके बारे में स्पष्टीकरण मांगा। उन पर निम्न आरोप लगाए गए—

१. लाहड़ी के बयानों के अनुसार राव गोपालसिंह ने केवल सत्ता विरोधी विचारों का ही प्रचार नहीं किया, अपितु खुले रूप से जातिकारी भाँदोलन का समर्थन किया और उसे भी इसमें शामिल हो जाने के लिए कई व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया।
२. उन पर यह भी आरोप था कि उनका सम्पर्क केसरीसिंह और विष्णुदत्त से रहा है। जिनका उद्देश्य अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पड़मंत्र रचना तथा राजद्रोहात्मक कार्य करना था।
३. उन्होंने विष्णुदत्त को अपने प्रतिनिधि के रूप में भजमेर और जोधपुर में उपदेशक के रूप में एक लम्बे समय तक नियुक्त रखा था।
४. उन्होंने अपने ध्येय पर भजमेर में दो नवयुवक नारायणसिंह (मृत) और लाहड़ी को पढ़ाया, जिनका कोटा व निमाज हत्याकांड में प्रमुख भाग था।
५. जब विष्णुदत्त उनके यहाँ उपदेशक के रूप में काम करता था तब उन्होंने उसकी सहायता के लिए गैरसिंह को नियुक्त किया था जोकि केसरीसिंह द्वारा स्थापित गुप्त समिति का सदस्य रह चुका था।

आरोप पत्र में यह भी लिखा गया कि उपर्युक्त आधार पर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इन जातिकारियों की गतिविधियों की उन्हें पूर्ण जानकारी होती हुए भी उन्होंने उनके सम्पर्क बनाए रखा तथा ताज के प्रति अपनी बफादारी का बचन निभाने में वे असमर्थ रहे।<sup>४८</sup>

राव गोपालसिंह इस आरोप-पत्र के सम्बन्ध में कमिशनर से मिलना चाहते थे परन्तु कमिशनर ने उनसे मिलने के बजाय लिखित उत्तर की माग की तथा उन्हें लिखित उत्तर के लिए पर्याप्त समय देने से भी इन्कार कर दिया गया। राव गोपालसिंह ने अपने लिखित उत्तर में इन सभी आरोपों को अस्वीकार किया।<sup>४९</sup>

राव गोपालसिंह के लिखित उत्तर से यह ध्वजा सजाया जा सकता है कि वे आरोप-पत्र से अच्युत हो उठे थे तथा अपनी जागीर को बचाने के चक्कर में थे। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। उस युग के जातिकारियों के लिए अपने बचाव में इस तरह के बक्तव्य देना कोई अपराध नहीं था। इसलिए राव गोपालसिंह ने जो बहाना उड़ाया वह जातिकारी परम्परा के विपरीत नहीं था। इसमें एक चुभने वाली बात यह थी कि उन्होंने सम्पूर्ण दोष बारहठ केसरीसिंह पर थोपा दिया था और उनके

विहड भारोप ऐसे समय प्रस्तुत किए जबकि उन पर कोटा में मुकुदमा चल रहा था तथा इससे जोषपुर महन्त हयाकांड के मुकुदमे में उनके विहड सरकार की बल मिसता था। परन्तु उक्त वक्तव्य के आधार पर ही यह नहीं मान लेना चाहिए कि सरवा ठाकुर का आन्तिकारी जीवन समाप्त हो जाता था। बनारस पड़यंत्र कांड में रामनाथ ने जो इकबाली बयान दिया उसमें उसने स्पष्ट कहा कि २१ फरवरी, १९१५ को सगस्त्र सैनिक बिद्रोह की योजना तैयार करने और उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए सरवा के राव गोपालसिंह भी प्रयत्नशील थे। उक्त आति की योजना समय के पूर्व ही प्रकट हो गई और वह मूर्त रूप लेने से पहले ही दबा दी गई थी।<sup>१०</sup> इससे यह स्पष्ट है कि भद्रेशों के आतंक से घबरा कर राव गोपालसिंह अपनी आन्तिकारी कार्यवाहियों को छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। इसके विपरीत प्रस्तावित सगस्त्र आति के लिए उनके द्वारा की गई तैयारी, यह प्रकट करती है कि निस्संदेह उन्होंने अपनी गतिविधियों को और भी अधिक तेज कर दिया था।

बनारस पड़यंत्र कांड के मुकुदमें के दौरान सरकारी गवाहों और मुलबिरों ने अपने बयानों में राव गोपालसिंह का भी इस पड़यंत्र में हाथ बतलाया था। मणिलाल ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि राव साहब ने उसे तथा दामोदर व प्रतापसिंह को हथियार दिए थे। इसलिए सरकार का उनके प्रति संदेह होना स्वाभाविक था। राव गोपालसिंह की इन भद्रेश विरोधी आन्तिकारी गतिविधियों के कारण भद्रेश सरकार ने २५ जून, १९१५ को उनके विहड भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत मजर-बंदी आदेश जारी किया।<sup>११</sup>

सरकार ने उन्हें बीबीस घंटे के अन्दर सरवा छोड़ कर टाडगढ़ के तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए। उन्हें वहाँ तहसीलदार टाडगढ़ द्वारा निर्धारित स्थान पर अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक तथा मूर्पास्त से सूर्योदय तक कहीं भी बाहर नहीं निकलने के आदेश दिए गए। उन पर तहसीलदार की पूर्ण अनुमति के बिना टाडगढ़ निवासियों के अतिरिक्त अन्य बाहर के व्यक्तियों से मिलने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।<sup>१२</sup> २६ जून, १९१५ को राव गोपालसिंह को सरवा छोड़ना पड़ा। वहाँ से रवाना होते समय अपने पुत्र कुंवर गणपतिसिंह को आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी मातृभूमि और भगवान के प्रति बफादार रहने की सलाह दी।<sup>१३</sup>

३० जून, १९१५ को अजमेर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने सरवा के किले की तलाशी लेते समय जनाने महल को भी नहीं छोड़ा। राव गोपालसिंह के अनुचरों की संख्या केवल दस व्यक्तियों तक सीमित कर दी गई थी। उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए केवल एक तलवार तथा शिकार के लिए दो बंदूक रखने की इजाजत थी।<sup>१४</sup> उन्हें इसके अतिरिक्त शस्त्रास्त्र सौंप देने के लिए कहा गया था परन्तु राव साहब ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उन्हें यह सूचना मिल चुकी थी कि पुलिस

सोचों से उनके विरुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याचार कर रही है। १० जुलाई को राव गोपालसिंह अपने सभी हथियारों सहित मोड़सिंह के साथ ब्यावर की ओर निकल पड़े। उदयपुर और जोधपुर के पोलिटिकल एजेंटों को उनकी गिरफ्तारी के लिए तार भेजे गए।<sup>१४</sup> पुलिस को राव साहब की जानकारी किशनगढ़ दरबार के माध्यम से मिली कि वे सलेमाबाद के मन्दिर में हैं। पुलिस ने वहाँ पहुंच कर मन्दिर को चारों ओर से घेर लिया।<sup>१५</sup> राव गोपालसिंह गिरफ्तार होने की अपेक्षा मरने-मारने के लिए तैयार थे।

इस तरह की तेज सफवाह फीज गई थी कि खरवा ठाकुर के सगे-संबंधी संगठित सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस ने स्थिति की गंभीरता का अनुभव करते हुए राव साहब को यह सलाह दी कि वे उनसे मिलें और पूर्ण भाईचारे के वातावरण में परिस्थिति पर विचार-विमर्श करें। राव गोपालसिंह ने उनसे लिखित रूप में यह जानना चाहा कि भारत रत्ना कानून के अंतर्गत अपराधों के प्रतिरिक्त टाइटल छोड़कर चले जाने की स्थिति में उन पर कौनसा जुर्म कायम किया जाएगा। सुपरिटेण्डेंट ने राव गोपालसिंह को कहा कि उनकी यह व्यक्तिगत मांग्यता है कि राजस्थान में दिल्ली-पड़पन कांड के मामले में जो प्रमाण मिले हैं वे इतने अपर्याप्त हैं कि उनके आधार पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास दिल्ली के जांच अधिकारी का लिखित पत्र है कि यदि राव गोपालसिंह पर भारत रत्ना कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है तो ऐसी समाधान है कि उन पर और मुकदमें लागू नहीं किए जाएंगे।<sup>१६</sup> इस बातचीत के आधार पर राव गोपालसिंह ने स्वयं अपने आप को पुलिस को सौंप दिया और उन्हें राजनीतिक बंदी के रूप में भ्रममेर लाया गया।<sup>१७</sup> उन्हें भ्रममेर के किले में रखा गया और १२ अक्टूबर, १९१५ को भ्रममेर के जिला बंदनायक ने उन्हें दो वर्षों की सामान्य कारावास की सजा दी।

बनारस हत्याकांड के सिलसिले में उन्हें नवम्बर में बनारस भेजा गया परन्तु सरकार के द्वारा मुकदमा हटा लेने के कारण २४ नवम्बर, १९१५ को उन्हें वापस भ्रममेर भेज दिया गया।<sup>१८</sup> ४ सितम्बर, १९१७ को उन्हें रिहा कर दिया गया परन्तु उसी दिन पुनः उन्हें भारत रत्ना कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर तिलहर भेज दिया गया जहाँ वे डेढ़ वर्ष तक हवालात में रहे। भ्रममेर-मेरवाड़ा जिले के रामसा ग्रामों व बरखों के लोगों ने हजारों की संख्या में हस्ताक्षर करके राव गोपालसिंह की रिहाई के लिए वायसरॉय को प्रार्थना-पत्र भेजे।<sup>१९</sup> सन् १९२२ में उन्हें राजनीतिक बंदियों के साथ रिहा कर दिया गया। बारहठ केसरीसिंह को जून, १९१६ तक जेल का जीवन यादना पड़ा। उनकी यह आकांक्षा थी कि राजपूत समाज में सैनिक जाति उत्पन्न कर मातृभूमि को मुक्त करवाया जाय। आठिकारी योजनाओं

की घसफन्सता से उन्हें दतना गहरा सदमा पहुँचा कि उन्होंने अम्बल तट पर एकान्त-यात्रा ग्रहण कर लिया था। धनुंनसाल सेठी को भारम्भ में जयपुर जेल में बिना कार्यवाही के भी महीने रखा गया। उसके बाद उन्हें वेवूर जेल में भेज दिया गया था। सन् १९१७ में घतिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कानकता अधिवेशन में एक प्रस्ताव जैम में सेठी जी पर हो रहे प्रत्याचारों द्वारा सरकारी नीति की भर्त्सना की तथा केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप की माँग की। सन् १९२० में, ६ वर्ष के लंबे जेल-जीवन के बाद उन्हें रिहा किया गया।<sup>११</sup>

बारहूट परिवार के सदस्य जोरावरसिंह और प्रतापसिंह का क्रान्तिकारियों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। निमात्र हत्याकांड के बाद जोरावरसिंह करारी का जीवन बिता रहे थे। उन्होंने दिल्ली में साईं हाईग पर यम फँकने के पदमित्र में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनके परबान् उन्होंने पुलिस और गुप्तधर विभाग की प्राँतों में घुल भौंछते हुए अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। मानवा और राजपूताना के पर्वतीय क्षेत्रों में छिपे रहकर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जारी रखी थी। बिहार में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के गठन पर उनकी गिरफ्तारी के वारंट बापिल लिए जाने के प्रयत्न किए गए। उन पर से गिरफ्तारी के वारंट हटा लेने के एक दिन पूर्व ही नवम्बर, १९३६ को उनका देहात हो गया था।<sup>१२</sup>

राजपूताने के क्रान्तिकारियों में सबसे अधिक ख्याति एवं महत्व प्रतापसिंह ने प्राप्त किया था। वह भारत की सभी महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने अपने बन्दी जीवन में प्रतापसिंह के अजेय साहस की मुक्तकंठ से सराहना की एवं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी। उन्हें क्रान्तिकारिता की पुढी बारहूट केसरीसिंह से विरासत में मिली थी और उन्होंने ही प्रताप के क्रान्तिकारी जीवन को ढाला था। इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्होंने भजमेर में डी० ए० बी० कालेज में मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। किशोरावस्था में ही उन्हें दिल्ली में मास्टर अमीरचन्द के पास क्रान्तिकारी प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया था। वहीं पर वे अवधबिहारी के निकट सम्पर्क में आए<sup>१३</sup> और रास-बिहारी बोस तथा शचीन्द्रनाथ सान्याल से उनका परिचय हुआ।

यह शचीन्द्रनाथ सान्याल के निकटतम सहयोगी तथा रासबिहारी बोस के विश्वासपात्र थे। उत्तरी भारत में गहरा आन्दोलन में वे शचीन्द्रनाथ सान्याल के साथ थे।<sup>१४</sup> उन्हें राजपूताना में सशस्त्र क्रान्ति को सगठित करने का काम सौंपा गया था ताकि भजमेर और नसीराबाद के मध्य सशस्त्र क्रान्ति आरम्भ की जा सके। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत सरकार के गृह सदस्य की गोली से उड़ा देने का भी काम सौंपा गया था।<sup>१५</sup> रासबिहारी बोस के भारत छोड़ देने पर वे राजपूताना चले आए और



इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे। सेठी धर्मुनसाल और अपने पिता बारहठ केसरीसिंह की गिरफ्तारी के पश्चात् क्रांतिकारी गतिविधियों का सम्पूर्ण भार प्रताप को सहन करना पड़ा था। इसमें वृजमोहन मायुर और छोटेसाल जैन उनके सहयोगी थे। बनारस पहुंचने काठ में उनके खिलाफ बारट जारी हो जाने के कारण वे हैदराबाद (सिंध) चले गए थे। सिंध से वापस लौट आने पर बीकानेर जाते समय वे भागानाड़ा के अपने एक मित्र से मिलने रुक गए थे जोकि यहाँ स्टेशन मास्टर था। वहीं पर उन्हें विश्वासघात से गिरफ्तार कर लिया गया।<sup>१६</sup> प्रताप की गिरफ्तारी के साथ ही एक तरह से अजमेर और राजपूताना में क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया था।

सद १९१५ के अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति ने, जो कुछ भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अवशेष बचे थे उन्हें क्रूरता से कुचल दिया था। राव गोपालसिंह और बारहठ केसरीसिंह के राजपूताने के राजघरानों एवं अभिजात वर्ग से उनके निकट-तम संपर्क के कारण अंग्रेज अधिकारियों को यह संदेह होता स्वभाविक ही था कि राजपूताना के राजघराने और जागीरदार भी इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों में ढोबी बहुत रुचि लेते रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने राज दरबारों में अपना सर्वोच्च सत्ता का नियंत्रण-प्रभुत्व कस दिया था। इन राजघरानों में लगभग एक दशक तक आतंक का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अंग्रेज सरकार को अपनी बफादारी से आश्वस्त करने के लिए राजपूताना और अजमेर के नरेशों एवं जागीरदारों ने अपनी प्रजा के लिए स्वराज्य की कल्पना तक को असंभव बना दिया था।

सम्बन्धित जीवन एवं अपनी योजनाओं की असफलता के कारण यहाँ के क्रांतिकारियों में निराशा की भावना पैदा हो गई थी। यद्यपि वे इसके बारे में यदा-कदा अपनी गतिविधियों से राजनीतिक जीवन में हलचल अवश्य पैदा करते रहे। क्रांतिकारी जीवन के दौरान उनके परिवारों को जो आर्थिक क्षति उठानी पड़ी उसने भी उनकी स्थिति को बाधाबोल कर दिया था।

क्रांतिकारी गतिविधियों की समाप्ति के कारण तक अजमेर का राजनीतिक आकाश एक दूमरे रंग में रंगने लगा था। क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ शिक्षित समुदाय के कुछ व्यक्तियों तक ही केन्द्रित रहीं। ये लोग न तो खुला प्रचार ही कर पाते थे और न सार्वजनिक समारोह आयोजित कर सकते थे। पुलिस द्वारा घातक-वादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहने के कारण वे आम जनता तक पहुँच भी नहीं पाते थे। बीसवीं सदी के द्वितीय दशक के अंत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक जाग्रति का प्रादुर्भाव हुआ। दिल्ली, अहमदाबाद रेलमार्ग के मध्य में स्थित होने के कारण अजमेर इन हलचलों एवं जागृति से अछूता नहीं रहा।<sup>१७</sup>

अजमेर में राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव के तीन आधार रहे हैं। प्रथम तो

भजमेर धर्म समाज की गतिविधियों का एक प्रमुख और शक्तिशाली केन्द्र रहा था। स्वामी हयानन्द ने अपने अन्तिम दिन यहीं व्यतीत किए थे और यहीं उनका निधन हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि यथासमय भजमेर हिन्दू पुनर्जागरण की दिशा में भारतीय शिखा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था। धर्म समाज ने स्वामीजी की स्मृति में एक कानेज, स्कूल, पुस्तकालय, छापाखाना एवं भनापालय की स्थापना कर भजमेर की जनता में सामाजिक और धार्मिक जाग्रति उत्पन्न कर दी थी।<sup>१८८</sup> शिखा के इसी पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही भजमेर की जनता की बौद्धिक चेतना का ही विकास नहीं हुआ अपितु उसमें एक नए ही ढंग की राजनीतिक चेतना भी जाग्रत हुई। शीतबीं सदी का प्रारम्भ भजमेर की जनता की बौद्धिक चेतना, सामाजिक जाग्रति एवं राजनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण युग था। इस शैक्षणिक एवं प्रगतिशील तथा उदार सुधारवादी आन्दोलन ने अपना स्वरूप विकसित किया और भजमेर-मेरवाड़ा की जनता के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।<sup>१८९</sup> धर्म समाज के धलावा इस क्षेत्र में हमारी पादरियों द्वारा विभिन्न शिक्षण-संस्थान खोले गए थे। उनके द्वारा भी भजमेर की जनता का दक्षिणावृत्ति विद्युद्गपन समाप्त हुआ।<sup>१९०</sup>

भजमेर में इस चेतना के फलस्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों का उदय हुआ व भजमेर में खिलाफत एवं सविनय अवज्ञा आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। १६ मार्च, १९२० को भजमेर में खिलाफत समिति की बैठक हुई। भजमेर में खिलाफत दिवस मनाया गया जिसमें डा० भंसारी, मोलाना मोहिनुद्दीन, चांदकरण शारदा और अर्जुनदास शारदा आदि ने भाग लिया।<sup>१९१</sup> सार्वजनिक सभाओं में जलियावाला बाग की क्रूरता की निंदा की गई तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के उद्देश्य की धारें बचाने का प्रयास किया गया। जनता से सत्याग्रह में भाग लेने एवं कर न चुकाने का आह्वान किया गया तथा विदेशी को भारत से खाना के निर्यात पर रोक की मांग के समर्थन में जनमत तैयार किया गया। स्वदेशी आंदोलन भजमेर में द्रुत गति से चला। सरकारी नौकरियों में सभी धेशियों एवं सभी पदों पर भारतीयों को रखने तथा भजमेर-मेरवाड़ा में भारतीय उद्योग वर्गों की स्थापना के बारे में समय-समय पर प्रस्ताव व समागमों से जनमत तैयार किया गया।<sup>१९२</sup>

राजपूताने के मध्य में स्थित होने तथा राजनीतिक जाग्रति का केन्द्र होने के कारण भजमेर उन दिनों रियासती जनता के आन्दोलनों का भी केन्द्र बना हुआ था। रियासती से निष्कासित राजनीतिक नेता यही शरण लेते थे। रियासती जनता में जाग्रति के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी यहीं से होता था। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ रियासती में उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन का संचालन भी भजमेर में ही होता था। अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में होने के बाद भी भजमेर ने

कभी अपने को राजपूताना की अन्य रियासतों से अलग नहीं माना । इसलिए रियासती घान्दोलनों में अजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था ।

### अध्याय ११

१. चीफ कमिश्नर द्वारा सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनांक १-१०-१८८२ फाइल संख्या ४६५ ई० (रा० रा० पु० मं०) ।
२. राजद्रोह समिति की रिपोर्टें पृ० ५५ (रा० रा० पु० मं०) ।  
सम्राट के विरुद्ध मोतीचन्द एवं विष्णुदत्त के मुकदमें में सत्र न्यायाधीश शाहिवादा का फैसला, फाइल संख्या ५१, अजमेर खण्ड १, राजपूताना पड़यंत्र (रा० रा० पु० मं०) ।
३. जोधपुर महल हत्याकाण्ड में कोटा महाराज का फैसला (रा० रा० पु० मं०) ।
४. राजद्रोह समिति की रिपोर्टें पृ० ५५ (रा० रा० पु० मं०) ।
५. शंकरसहाय सक्सेना-राजस्थान केसरी थी विजयसिंह पत्रिक की जीवनी (१९६३) पृ० ८७ ।
६. रेजीडेंट्स रेकॉर्डें, फाइल सं० ई० ३-४५ (रा० रा० पु० मं०) ।
७. कोटा रेकॉर्डें-सीमा भुक्तरीफ मंशर, संख्या ४, बस्ता संख्या १०२६ (रा० रा० पु० मं०) ।
८. राजपूताना हेराफ्त १८ मार्च, १८८५, ३० सितम्बर, १८८५, १० अगस्त, १८८७ ।
९. डॉ० दशरथ शर्मा-राजस्थान-सार्वजनिक जन सम्पर्क कार्यालय प्रकाशन (१९५१) ।
१०. बारहठ केसरीसिंह की धात्मकथा-राजस्थान का गोपनीय एवं रहस्यमय इतिहास-पांडुलिपि खण्ड ४ (रा० रा० पु० मं०) ।
११. फाइल संख्या ५१, खण्ड संख्या १, अजमेर रेकॉर्डें (रा० रा० पु० मं०) ।
१२. रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१९४८) पृ० २७ ।
१३. शंकरसहाय सक्सेना-राजस्थान केसरी थी विजयसिंह पत्रिक की जीवनी (१९६३) पृ० ९५ ।
१४. सद्गुणवर्त-राजस्थान रोच इन दी स्ट्रगल ऑफ १८५७ पृ० ८, ९ ।

१५. स्वामी दयानन्द श्री मेयाड़ ॥ महाराजाधिराज सम्जनसिंह तथा शाहपुरा राजाधिराज नाहरसिंह के बीच पत्र-व्यवहार (रा० रा० पु० मं०) ।
१६. गुरजनसिंह का बयान (रा० रा० पु० मं०) ।
१७. महर्षि दयानन्द शताब्दी के अवसर पर दिए गए भाषण, बीकानेर सर-  
कार, गृह विभाग फाइल संख्या सी० २०३ ।
१८. राव गोपालसिंह का बयान, भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१, खण्ड १,  
पृ० १२८ से १५४ (रा० रा० पु० मं०) ।
१९. रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१९४८) पृ० २७ ।
२०. उपरोक्त, राजस्थान पड़यंत्र पर आर्मस्ट्रोंग की टिप्पणी, भजमेर रेकॉर्ड,  
फाइल नं० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० मं०) ।
२१. उपर्युक्त ।
२२. राजपूताना पड़यंत्र, भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१ खण्ड १ (रा० रा०  
पु० मं०) ।
२३. जोधपुर महंत हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा०  
पु० मं०) ।
२४. 'हंर प्रसार, भाजादी के दीवाने पृ० ४६-५० ।
२५. मोड़सिंह पुरोहित का बयान (रा० रा० पु० मं०) ।
२६. गुरजनसिंह का बयान (रा० रा० पु० मं०) ।
२७. सेबीशन कमेटी रिपोर्ट (१९१८) पृ० ५५ से ६० ।
२८. जोधपुर महंत हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा०  
पु० मं०) ।
२९. गुरजनसिंह का बयान (रा० रा० पु० मं०) ।
३०. सेबीशन कमेटी रिपोर्ट (१९१८) पृ० ५४ ॥ ६० ।
३१. राव गोपालसिंह खरवा फाइल नं० ४६, पत्र संख्या एस० डी० एल०  
५४०८ दि० ११-११-१९०६ (रा० रा० पु० मं०) ।
३२. राजपूताना पड़यंत्र भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१, खण्ड १ (रा० रा०  
पु० मं०) ।
३३. जोधपुर महंत हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा०  
पु० मं०) ।
३४. राजपूताना पड़यंत्र, भजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ पृ०  
१७ से २६ ।

३५. मुरजनसिंह का बयान (रा० रा० पु० मं०) ।
३६. मुरजनसिंह व मोड़सिंह के बयान (रा० रा० पु० मं०) ।
३७. उपर्युक्त ।
३८. शंकरसहाय सबसेना, राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पथिक की जीवनी (१९६३) पृ० ६७ व १०० ।
३९. रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१९४६) ।  
शंकरसहाय सबसेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पथिक की जीवनी (१९६३) ।
४०. जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराज का फैसला (रा० रा० पु० मं०) ।
४१. शंकरसहाय सबसेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पथिक की जीवनी (१९६३) पृ० ६५-६६ ।
४२. जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराज का फैसला (रा० रा० पु० मं०) ।
४३. भजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० मं०) ।
४४. उपर्युक्त ।
४५. उपर्युक्त ।
४६. भजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ ।  
जोधपुर महन्त हत्याकांड में सेमन्त जय कोटा का फैसला (रा० रा० पु० मं०) ।
४७. भजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ व २ (रा० रा० पु० मं०) ।
४८. होम्स का पत्र दिनांक २३-१०-१९१४ व नमिस्नर को प्रस्तुत रिपोर्ट दि० २६-७-१९१४ ।  
भजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, (रा० रा० पु० मं०) ।
४९. राज गोशामसिंह का जवाब दि० १४-८-१९१४ फाइल नं० ५१ (रा० रा० पु० मं०) ।
५०. मोड़सिंह मुरजनसिंह व ईश्वरदान के बयान (रा० रा० पु० मं०) ।  
रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१९४६) पृ० ३१ ।  
शंकरसहाय सबसेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पथिक की जीवनी (१९६३) पृ० १००, १०१, १०२, १०३, १०४ ।

श्री शंकरसाहाय सक्सेना ने इस आन्तिकारि का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है:—

दिसम्बर १९१४ में वाराणसी में जहाँ रासबिहारी बोस छिपे हुए थे, भारत के समस्त आन्तिकारी दलों के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। विप्लव की एक पूरी योजना बना ली गई। आन्तिकारी दल के दूत मन्त्र पेशावर से सिंगापुर तक सभी अंग्रेज छावनियों में घुसकर वहाँ की परिस्थिति की जानकारी कर चुके थे। आन्तिकारियों ने सभी सैनिक छावनों में भारतीय सैनिकों से संबंध स्थापित कर लिया था और प्रत्येक छावनी में देशभक्त आन्तिकारी सैनिकों का एक दल गढ़ा कर दिया था जो सेना में आन्तिकारी भावनाओं को भरता था। आन्तिकारियों ने यह मालूम कर लिया था कि उस समय देश में कुल १५ हजार गोरे सैनिक थे। अधिकांश भारतीय सेनाएँ आति होने पर देश की आजादी के लिए आन्तिकारियों के साथ गठबन्धन करने को तैयार थी। आन्तिकारियों की योजना थी कि पहले लाहौर, राबलपिंडी और फीरोजपुर की छावनियों की सेनाएँ विद्रोह कर आन्तिकारियों और देशभक्त जनता के सहयोग हैं। वहाँ के शास्त्रागारों पर जहाँ कि देश के विनाश शास्त्रागार थे उन पर अधिकार करते। देश की दूसरी छावनियों की सेनाएँ उस सकेत को पाते ही उठ खड़ी होने को तैयार रहनी जाएँ और आन्तिकारियों की मदद से अपने-अपने प्रदेश के अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया जाए। अजमेर तथा अन्य स्थानों पर राजस्थान के आन्तिकारियों ने अंग्रेजों के भारतीय नौकरों को पहले ही अपने साथ मिलाकर तय कर लिया था कि निश्चित तिथि पर सकेत पाते ही वे अंग्रेजों को सोते हुए पकड़ उन्हें आन्तिकारियों के हवाले कर दें। जहाँ तक हो सके शक्ति बहाने से बचा जाए और देश की शासन सत्ता अपने हाथ में कर ली जाए। देश के आन्तरिक शासन पर एक बार अधिकार प्राप्त कर लेने पर अंग्रेजों के शत्रु देशों जर्मनी, तुर्की आदि से विविध सम्बन्ध जोड़ कर, जिसके लिए प्रवासी भारतीय आन्तिकारी योरोप में पहले ही ही प्रयत्न कर रहे थे, उनसे सहायता प्राप्त कर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले जवाबी हमलों का सामना करने की तैयारी की जाए।

आति की सब तैयारियाँ हो जाने पर आति का आरम्भ स्वयं अपने निरीक्षण और नेतृत्व में कराने के लिए रासबिहारी बोस जनवरी, १९१५ के आरम्भ में वाराणसी से हट कर लाहौर चले गए। दिल्ली और राजस्थान का प्रबन्ध देखने के लिए शचीन्द्र साम्बान को भेजा गया। २१ फरवरी, १९१५ भारत की आजादी के लिए सशस्त्र आति आरम्भ करने की तिथि निश्चित कर दी गई। उस दिन प्रसिद्ध आन्तिकारी देशभक्त

कर्तारसिंह अपने दल के साथ फीरोजपुर के शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाला था। उसकी सफलता की सूचना मिलते ही अन्य सभी स्थानों पर क्रांति प्रारम्भ की जाने वाली थी। राजस्थान में छरवा ठाकुर गोपालसिंह को दामोदरदास राठी से मिलकर व्यावर पर और भूपसिंह को अजमेर और नसीरानाद पर अधिकार कर लेने का कार्य सौंपा गया। जनवरी के अन्त तक यह सारी व्यवस्था कर शहीन्द्र सान्याल बाराणसी लौट गया जहाँ क्रांति का सूत्रधार वह स्वयं था।

भूपसिंह अब तेजी में राजस्थान की क्रांतिकारी शक्तियों को संगठित करने में जुट गए।

यह सब तैयारी भारत में अत्यन्त गुप्त तरीके से की जा रही थी। परन्तु योरोप तथा अन्य देशों में भारतवासियों ने सशस्त्र क्रांति की तैयारी को उतनी सतर्कतापूर्वक गुप्त नहीं रखा। फ्रांस की पुलिस ने कुछ आरंभ होने के कुछ मास बाद ही अंग्रेजों को सूचना दी कि योरोप के भारतीयों में भारत में ग्रीष्म हो फूटने वाले किसी सैनिक विद्रोह की चर्चा बहुत जोरों पर है। अतएव भारत में भी पुलिस बहुत चौकसी हो गई और फरवरी, १९१५ के आरम्भ में वह अपने एक गुप्तचर को क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित कर देने में सफल हो गई। उसका नाम कृपालसिंह था। वह क्रांतिकारियों की सारी खबरें पुलिस को देता था। क्रांतिकारियों को उस पर गोप्त ही सदेह हो गया। उन्होंने उस पर निगाह रखना आरम्भ की तो उनका संदेह पक्का हो गया क्योंकि वह प्रतिदिन एक निश्चित समय पुलिस अधिकारियों के पास जाता था। होना तो यह चाहिए था कि उसकी गुरन्त गोली मारदी जाती परन्तु पञ्जाबी क्रांतिकारी यह सोचने लगे कि कृपालसिंह को मार डालने से न जाने क्या गड़बड़ मच जाए अतएव उन्होंने कृपालसिंह को एक प्रकार से नजरबंद कर लिया और २१ फरवरी, १९१५ के स्थान पर क्रांति की तिथि बदलकर १६ फरवरी करदी। कारण यह था कि कृपालसिंह १६ फरवरी ॥ तीन चार दिन पूर्व सेना में फूट पड़ने वाले उस विप्लव की सूचना साहौर के चण्डेज् अधिकारियों को दे आया था। अस्तु २१ फरवरी के विद्रोह की सूचना चण्डेज् अधिकारियों के पास पहुँच चुकी थी। इसी कारण क्रांतिकारियों ने विप्लव की तारीख को १६ फरवरी धर्पाई दो दिन पूर्व कर दिया। परन्तु दुर्भाग्यवश एक और दुर्घटना हो गई। इस नई तारीख की सूचना को छावनी में से जाने का कार्य जिसको सौंपा गया था उसने बीटकर रामसिंहारी से कहा “छावनी में मैं १६ तारीख की सूचना दे आया” उस समय कृपालसिंह वहीं बैठा हुआ था। उस व्यक्ति

को कृपालसिंह के बारे में कुछ भी मात्तूम नहीं था। सम्भवतः यह घटना १८ फरवरी की थी। कृपालसिंह ने किसी तरह यह सूचना भी पुलिस के पास भिजवा दी।

इसके कुछ घंटों बाद ही १९ फरवरी को पर पकड़ भारम्भ हो गई। अंग्रेजों को इस क्रान्ति का पता चल गया। क्रान्ति असफल हो गई। साहौर में रासबिहारी बोस और कर्तारसिंह को धोर निराशा हुई। सच तो यह है कि १८५७ के उपरान्त विप्लव की इनकी बड़ी तैयारी इस देश में कभी नहीं हुई। यह सारी तैयारी व्यर्थ चली गई। रासबिहारी बोस को इससे गहरी निराशा हुई। साहौर से रासबिहारी बोस तुरन्त बाराणसी की ओर चल पड़े। देगढ़ोटी कृपालसिंह के विश्वासवान से देश की स्वतंत्रता का वह महायज्ञ घतफन हो गया।

राजस्थान में भूपसिंह, सरवा के रावसाहब गोपालसिंह, ठाकुर मोड़सिंह तथा सवाईसिंह आदि २१ फरवरी, १९१५ को सरवा स्टेशन से कुछ दूर जंगल में कई हजार और योद्धाओं का क्रान्तिकारी दल लिए विप्लव करने की तैयारी कर सकेत जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात्रि को दल बजे अजमेर से ग्रहमदादा जाने वाली जो रेगाड़ी सरवा से गुजरती थी उससे सरवा स्टेशन के समीप में एक बम का घमाका कार्दारम्भ का सकेत था। उस सकेत की पाते ही भूपसिंह तथा सरवा ठाकुर साहब को अजमेर और ध्यावर पर आक्रमण कर देना था। किन्तु संकेत नहीं मिला। बम का घटना नहीं हुआ। प्रगले दिन सदेरावाहक ने आकर साहौर में घटी घटनाओं की उन्हे सूचना दे दी। बहुत अधिक सख्या में अस्त्र-शस्त्र इकट्ठे किए गए थे, जिनमें ३० हजार से अधिक बंदूकें थी, बहुत अधिक राशि में गोला और बारूद आदि था, उन सभी को तुरन्त गुप्त स्थानों में छिपा दिया गया और क्रान्तिकारी और स्वयं-सेवक सैनिक दल बिखर गया।

भूपसिंह दिल्ली के रहने वाले अपने एक साथी रतियाराम को साथ ले सरवा तथा अजमेर इत्यादि में सब व्यवस्था कर बढ़ोदा तक आकर अपने सब क्रान्तिकारी साथियों को सावधान कर आए। सात आठ दिन बाद ही पुलिस ने सरवा पर छापा मार कर सरवा नरेश गोपालसिंह आदि को गिरफ्तार करने की तैयारी की। होने वाली गिरफ्तारी की खबर उन्हे क्रान्तिकारी भेदिए से पहले ही मिल गई थी। विचार-विमर्श हुआ कि क्या किया जाए। कारण यह था कि शीघ्र ही सेना की टुकड़ी उन्हे गिरफ्तार करने के लिए आने वाली थी। भूपसिंह ने कहा कि चुपचाप आत्मसमर्पण कर अंग्रेजों की जेल में अनिश्चित काल तक



पड़े रह कर सड़ने या फिर फासी के तस्ते पर लटकाए जाने की अपेक्षा लड़ते हुए मरना वही अधिक गौरवमय है। भूपसिंह की बात सबको उचित प्रतीत हुई और सभी ने आत्मसमर्पण न कर लड़ते हुए मर जाने का निश्चय किया।

अन्य सभी साधारण क्रांतिकारी दल के सदस्यों को खरवा से हटा दिया गया। इसके उपरान्त भूपसिंह, खरवा नरेश ठाकुर गोपालसिंह उसके भाई मोहंसिंह, रसियाराम और सवाईसिंह पाच क्रांतिकारी वीर बहुत से अस्त्रशस्त्र, बन्दूकें, गोला बारूद, बम इत्यादि लेकर सपा भाठ दस दिन के खाने का सामान आदि लेकर रातोंरात खरवा के गढ़ से निकलकर पास के जंगल में बनी हुई मोहदी (शिकारी बुर्ज) में मोर्चा-बन्दी कर जा डटे। दूसरे ही दिन भ्रजमेर का धर्मेज कमिश्नर ५०० सैनिकों की टुकड़ी लेकर खरवा आया। उनके गढ़ में न मिलने पर उन्हें खोजता हुआ वह उस शिकारी बुर्ज के पास पहुँचा और उसको चारों ओर से घेरकर उसने उन वीरों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन उन वीरों ने आत्मसमर्पण कर जेल में सड़ने की अपेक्षा शत्रु से लड़कर मरना ही अधिक गौरवमय समझा। जब धर्मेज कमिश्नर ने देखा कि वे लोग लड़कर मरने को तैयार हैं तो वह भयभीत हो गया। वह जानता था कि यदि वास्तव में लड़ाई हुई तो बहुत सम्भव है कि वहाँ की जनता कहीं बिद्रोही होकर उनकी रक्षा के लिए न उठ खड़ी हो। क्योंकि खरवा नरेश राष्ट्रवर गोपालसिंह उस प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय थे और जनता उन्हें यद्धा से देखती थी। इसके साथ ही भारतीय सैनिक टुकड़ी की राजमर्ति पर भी उसे पूरा भरोसा नहीं था। ऐसी दशा में यदि वह घिरे हुए क्रांतिकारियों से मुक्त करता और कुछ समय युद्ध चलता तो समस्त राजस्थान में बिद्रोह की अग्नि भड़क उठने का भय था। इसके अतिरिक्त ऊपर से भी कमिश्नर को यही आदेश मिला था कि वहाँ तक हो गोली चलने की मौक़ा न घाने दी जाए। परन्तु भ्रजमेर के पुलिस रेकर्ड में इस घटना का कहीं वर्णन नहीं है।

११. निदेशक क्रिमिनल इंस्टिट्यूट ने सचिव, परराष्ट्र व राजनीतिक विभाग भारत सरकार को अपने पत्र दिनांक १६ जून, १९१५ में लिखा कि मणिलाल ने देहली मजिस्ट्रेट के सम्मुख अपने बयान में राव गोपालसिंह का नाम भी कई पङ्क्तियों में लिया है। उसने यह भी लिखा है कि मणिलाल के बयानों के घनावा भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो राव गोपालसिंह को दोषी ठहराने हैं। सचिव परराष्ट्र व राजनीतिक विभाग भारत

सरकार ने पत्र दि० १६-६-१५ में ई० कॉलविन ए० जी० जी० राज-पूताना को राव गोपालसिंह के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश दिए—भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६, राउंड एफ पृ० १, २, ३, ४, ५, राव गोपालसिंह की नजरबन्दी के आदेश दि० २५-६-१९१५ इस फाइल में पृ० १० पर हैं।

५२. राव गोपालसिंह की नजरबन्दी के आदेश दि० २५-६-१९१५ भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६, राउंड एफ पृ० १०।

शंकरसहाय सशसेना राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पयिक की ओपनी (१९६३) पृ० १०५।

५३. सुरजनसिंह का बयान (रा० रा० पु० म०)।

५४. ई० कॉलविन ए० ए० जी० राजपूताना के आयु से निर्देश भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६।

५५. भजमेर कमिश्नर का पत्र दि० २७-८-१९१५ भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६।

५६. कमिश्नर भजमेर का तार दि० २७-८-१९१५ भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६।

दीवान किशनगढ़ का ई० कॉलविन को तार दि० २७-८-१५ भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६।

ले० कर्नल के द्वारा ई० कॉलविन को पत्र दि० २७-८-१५ भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६।

शंकरसहाय सशसेना—राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पयिक की जीवनी (१९६३) पृ० ११४-११५।

५७. ले० कर्नल के द्वारा ई० कॉलविन को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक २७-८-१५ भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६ पृ० १२३-१२२।

५८. उपर्युक्त।

५९. सुरजनसिंह का बयान—भजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६।

६०. राजपूताना एजेन्सी गुप्त फाइल संख्या ५१ ए।

६१. हर प्रसाद—आजादी के दीवाने पृ० ६५, ६६, ६७।

६२. उपर्युक्त पृ० १३, १४।

६३. उपर्युक्त पृ० १५, १६।

६४. रामनारायण चौधरी—वर्तमान राजस्थान (१९४८) पृ० ३०।

शंकरसहाय सक्सेना—राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पणिक की जीवनी (१९६३) पृ० ६५ ।

६१. रामनारायण चौधरी—वर्तमान राजस्थान (१९४८) पृ० ३१-३२ ।
६२. रामनारायण चौधरी—वर्तमान राजस्थान (१९४८) पृ० ३२ से ३६ ।
६३. सीक्रेट इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट—अनुच्छेद ५६२ अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ६८ ।
६४. सारदा—अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१९४१) पृ० २९ से ३२ ।

रामनारायण चौधरी—वर्तमान राजस्थान (१९४८) पृ० ३ ।

शंकरसहाय सक्सेना—राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पणिक की जीवनी (१९६३) पृ० ८६ ।

सीक्रेट इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट अनुच्छेद ६३ अजमेर रेकॉर्ड, फाइल, सं० ६८ ।

६५. सदाए राजस्थान—साप्ताहिक २७-७-१९२६—पृ० १३ ।
७०. सारदा—अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१९४१) पृ० ३३ से ३६ ।
- सीक्रेट इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट अनुच्छेद ५७० अजमेर रेकॉर्ड, फाइल सं० ६८ ।
७१. अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ६८ ।

## शब्दावली

### अनुसूची (क)

मजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र में स्थानीय बोली के प्रचलित शब्दों का अर्थ

भाबी भूमि	तालाब के पेटे की भूमि जो तालाब के भरने पर जल-मग्न हो जाती है।
महँट	रहट या उस पर लगने वाला कर।
बारानी भूमि	वह भूमि जो कृषि के लिए पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती हो।
बैसाख सुदि पूनम	वैशाख शुक्ला पूर्णिमा।
बिस्वा	बीघा का बीसवा भाग।
खूद	इस्तमरारदार द्वारा अपने घोड़ों और ढोरो के लिए किमानो से ली गई फसल।
झाल	कुँए की जमीन का ढालू भाग।
बीस्वासी	बिस्वा का बीसवा हिस्सा (न्यूनतम नाप)
बाँटा	खेत की उपज में से हिस्सा (कर के रूप में)
बीघोड़ी	प्रति बीघा पर लिए जाने वाला न्यूनतम कर।
बीठ	घाम का सुरक्षित मैदान या भूखण्ड।
वेगार	परिश्रम करवाने की वस्तु अथवा जिसमें पारिधमिक न दिया जाए।

चाही भूमि	जो भूमि कुम्भों से सिंचित की जाती है ।
चवरी	लड़की के पिता द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पर इस्त-मरारदार को दी गई नकद भेंट ।
रावरी जगा	वह भूमि जिसमें इस्तमरारदार अपनी खुदकाशत के रूप में खेति-ह्वर मजदूरों से फसल पैदा करवाता है ।
कूँता	खड़ी फसल में इस्तमरारदार का हिस्सा निर्धारण करने की प्रक्रिया, भू-राजस्व का एक रूप ।
खरीफ	यह फसल वर्षा पर आधारित होती है ।
कौसा	सामूहिक भोजन पर सम्मिलित न होने पर घर पर भेजा गया भोजन ।
काजक	भेड़ या चकरोँ की टोली में से जामीरदार द्वारा लिया गया बकरा या भेड़ा जो अन्न के लिए काम लाया जाय ।
कमीण	मंथन—नाई, कुम्हार, लुहार, दर्जी, घोड़ी, मंजी, चमार, अनाई इत्यादि जिनको फसल के मीके पर बनाज दिया जाता है, नगद नहीं दिया जाता ।
खानसा	सरकार से सीधी नियंत्रित भूमि ।
खळा	फसल का क्षेत्र में साफ करने के लिए लगाया ढेर ।
कांकड	बंजर, वन-भूमि, अधिकांशतः ग्राम के सीमा क्षेत्र की भूमि जिसमें कृषि न होती हो और जो सुरक्षित ब्रीड नहीं हो ।
साग	जवरन शुल्क ।
साटा या सटाई	खेते पर ही फसल का विश्रजन कर इस्तमरारदार का हिस्सा भवग निरालने की प्रक्रिया ।
माल भूमि	यह विशिष्ट भूमि जो बिना वर्षा के रबी की फसल देने में समर्थ हो ।
माफीदार	वह भूमिधारक जिसे किसी की भू-भोग नहीं देना होता ।
नेदना	इस्तमरारदार द्वारा किसान के घर विवाह या मृत्यु-भोज के अवसर पर धामयण और उम्र धवमर पर भेंट या नज़राना ।

नज़राना		किसी काम की स्वीकृति लेने के लिए दी गई राशि जैसे उत्तराधिकार ग्रहण करने भयवा मकान या भू-संपत्ति के हस्तांतरण या स्वामित्व धारण करने के अवसर पर इस्तमरारदार को भेंट ।
नेग धाली	}	तेली के कौलू पर लगाए गए फुटकर कर ।
सेल वाली		
धाणी वाली		
किराया धाली		
नेग		घांटा या बिघोड़ी के अतिरिक्त नगदी के रूप में इस्तमरारदार द्वारा किसानों से उगाहे गए उपकर ।
पट्टा		भूमिधारक वर्ग के अधिकार प्रदान करने वाला प्रपत्र जो इस्तमरारदार से किसानों को प्राप्त होता है । किसान इसे भूमि पर अपने निरन्तर स्वामित्व के प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर सकता था तथा भ्रापसी विवादों में अधिकार के निर्णय में यह पुस्ता प्रमाण सिद्ध हुआ करता था ।
परवाना		एक तरह का अस्थायी अधिकार प्रपत्र; यह पट्टे से कुछ कम महत्व का माना जाता था ।
पेशकसी	}	संपत्ति कर
हलसारा		
खालडी		
घरर		
पढाव फीस		ग्राम में रात्रि बात करने का शुल्क ।
पड़तसाद		ग्राम की वह साद जहाँ किसी का अधिकार न हो ।
पड़त सात		उन मृत पशुओं का चमड़ा जिन पर किसी का अधिकार नहीं हो और परम्परागत ऐसी खालों को बेचने का अधिकार इस्तमरारदार को प्राप्त है ।
सियालू फसल		रबी की फसल जिसकी बोवाई सर्दी में होती है ।
ऊन्नालू फसल		खरीफ की फसल जिसकी बोवाई गर्मी में होती है ।
राम राम या नज़र		नगद नज़र या भेंट ।
रसाई		बीज बोने के पूर्व खेतों में दिया गया पानी ।

शहणा	भूमिपति द्वारा नियुक्त अधिकारी जो सरकारी फसल व कटाई आदि का प्रबन्ध हो ।
साद	जमानत ।
तालाबी जमीन	जलाशयों के निकट वाली भूमि ।
थला	घास काट डालने के बाद बचा वह भू-भाग जो घास पैदा करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है ।

## अक्षुसूची (ख)

इस्तमरारी जागीरों में नगद कर अथवा “लाग” की वर्गीकृत सूची

### १—मकान-बूंगी और भूमि-शुल्क—

इन दो में से एक ही वसूल किया जाता था । जहाँ ये दोनों कर उगाए जाते थे वहाँ सामान्यतः दूसरा कर “मकान-बूंगी” न होकर किसी अन्य बहाने पर लिया जाता था और सुविधानुसार प्रत्येक मकान पर लागू किया जाता था । ये कर दो-धार आने से लेकर १० रुपये वार्षिक तक निर्धारित थे । ऊँची दरें गैर-काश्तकार या धनी लोगों से वसूल की जाती थीं ।

बूंगी का नाम	प्रयुक्त अर्थ
पेशकशी	सामान्यतः किसानों से ।
पोलरी	सामान्यतः गैर काश्तकारों से ।
घरर	“माँग”
सालिना या सालाना	“वार्षिक भुगतान”
मलबा	सामग्री का ढेर । सामान्यतः यह शब्द सभी करों व बूंगियों के सम्मिलित रूप पर प्रयुक्त होता था जो प्रति खेत अथवा प्रति घर चुकाया जाता था ।
घरराई	नियमित गृह-कर के साथ नाममात्र की घुराई जाने वाली राशि जो विकास के नाम पर ली जाती थी ।
घास बर्ष	इसे इस्तमरारदार करने ही हिसाब में जोड़ लिया करते थे ।
हमसारा	इन की बूंगी जो बहुधा प्रति घर से वसूली जाती थी ।

किराया मकान	गृह-कर ।
नशवा	समाधियाँ में प्रचलित साग प्रति घर कुछ घानों पर ।
बाँच	हिस्सा कभी-कभी प्रतिरिक्त गृह-कर के रूप में बाँट-कर वसूल की जाने वाली राशि ।
टिंगट	जंतपुरा में प्रति घर १ रुपया की दर से वसूल विशिष्ट कर ।
तदाबंद	परम्परा से लिए जाने वाले दस्तूर ।
शरराइ	नादसी और कादेड़ा में प्रयुक्त प्रतिरिक्त गृह-कर, यह विशेषतः हुत की बेमार की छूट के एवज में वसूल किया जाता था ।
धूपरी	सरकारी भफसरों को दी जाने वाली भेंट ।
सवाजुमा	सरकारी अधिकारियों के लिए विशिष्ट साधन ।
बाड़ा या बरर	बाड़े का कर रबी की फसल पर काम करने वाले मजदूरों के वेतन पर गृह-कर की एवज में वीसागन में लिया जाता था ।
सिचारी	

२—जित्ता बोई की चूंगी एवं चौकीदारी कर—

चूंगी का नाम	प्रयुक्त अर्थ
चौकी	हिफाजत के उपलक्ष में लिए जाने वाली रकम ।
सड़क	जित्ता बोई की चूंगी ।
खबर नवीस	ठिकाने द्वारा नियुक्त वेतन भोगी डाक लाने से जाने वाला व्यक्ति ।

३—बराई कर 'जिते कभी-कभी गाय गुमारी' के नाम से भी प्रयुक्त किया जाता था—

ये बहुधा सभी ठिकानों में एक से थे और यदि इनकी पुरानी दरों में कुछ वृद्धि की जाती तो किसानों में भारी असंतोष व्याप्त हो जाता था । सामान्य दरें निम्न थीं—

गाय, भैंस	८ आना
भोटी	४ आना
बकरी या भेड़	१ आना
मेमने या बकरी के बच्चे	६ पाई (दो कल्दार पैसे)



४—भूस्वामी या ठिकानेदार के परिवार में विवाह या अन्य समारोहों के अवसर पर प्रजा से उगाहा जाने वाला कर—

नाम कर

प्रयुक्त अर्थ

न्योता	विवाहादि या मृत संस्कारों पर प्रति घर बुलावा और उनसे वसूल किया जाने वाला कर ।
भोल	इस्तमरारदार के पुत्र-पौत्रादि ॥ जन्म एवं विवाहादि के अवसरों पर प्रति घर से एक रुपया शुल्क वसूली (केवल जेतपुरा) ।
भांदली	एक अन्य विवाहादि कर जो म्योता जैसा ही होता है, कुछ ही ठिकानों में लागू था—शोकली, मनीहरपुर, नादली आदि में इसकी सामान्य दर एक रुपया थी ।
जामला	ठिकाने के बाहर ब्याही गई इस्तमरारदार की बहिन-बेटियों के पुत्र-पुत्री के जन्मतसव पर वसूल किया गया कर ।
मायरा	राज्य-परिवार की बेटों के घर जन्म पर उगाया गया या उसी के विवाह के अवसर पर उगाया गया कर ।
मुकलावा	इस्तमरारदार के घर से किसी के गौने के समय उगाही जाने वाली राशि ।

५—भ्रातामी के घर पर विवाहादि अवसरों पर वसूल किए जाने वाला कर—

चूनड़ी	यह एक नियमित रूप से वसूल किए जाने वाला विवाह-कर था और इससे ठिकानों को अच्छी आय हो जाती थी । घाठ रुपए तक हैसियत ॥ अनुसार वसूल किया जाता था ।
कागली या नाता	विधवा पुनर्विवाह कर—सामान्य दर एक रुपया ।
धानापाट	चूनड़ी के भलावा एक धोर कर जो जेतपुरा में वसूला जाता था ।
सगनशादी	कुछ मामलों में चूनड़ी के भलावा छोटे-छोटे उपकर ।

१—स्यवसाय-कर—

संदी	रंगरों और चमारों से लिया जाने वाला कर ।
बमोवा या खटोड़	बड़ई (मुषार या खाती) को दुकान से वसूल किया गया कर, प्रति दुकान दो रुपए सात आने तक

पगरली	वापिन्द्र । कभी-कभी इसे भूमिकर माना जाता था ।
होद-भराई	बमारों से जुते वनवाई का कर ।
तीबरी	मालियों के घर से प्रति घर चार घाना ।
दवात-नूगन	महाजन के घर से प्रति घर पीने तीन घाना ।
रुसासी	सया रुपया प्रति घर हसवाइयों से वसूली ।
खोड़ या सदार्द	साधुओं से पाँच घाना प्रति घर ।
घाव	ईंकेतों के बँद रखने पर लिया जाने वाला कर जो जनसाधारण से वसूल होता था ।
घासभारा	कुम्हारों का कर ।
साग महाजन	घास कटाई कर (जुनियाँ में प्रचलित) ।
रेजा रगाई और कोठा नील	भू-स्वामी या जागीरदार द्वारा यहाँ तथा अन्य सामान की खरीद पर महाजन द्वारा ली जाने वाली छूट रियायत ।
घड़ा या दस्तूर रेजर	रंगरेज का कर ।
लगान घीसरा	खमड़ा कमाने पर कर ।
लगान रेजा	दुकान कर (वाइनवाड़ा में प्रयुक्त) ।
घीष कदोई	बुनकर का कर प्रति घर (देवलियाकली में ५ रुपए प्रति घर सर्वाधिक) ।
पीनन खरीफ	हलवाई के बेतन का एक चौपाई ।
अखवान	धुनकों पर कर ।
७—वाणिज्य कर—	रंगरों पर कर ।
गाड़ी या गाड़ी-भाड़ा कर	सामान्य कर नहीं ।
अरत	सामान्यतः ग्राम से निर्वाहित सामान पर १ प्रतिशत विप्रत्य-मूल्य दर से वसूल किया जाता था । कभी-कभी आयातित वस्तुओं पर भी मडियों एवं हॉट में बिक्री कर के लिए प्रस्तुत सभी वस्तुओं पर चीफ कमिशनर ने आदेश जारी कर अधिक से अधिक १ प्रतिशत कर-निर्धारण किया ।

फेरा	ग्राम में विक्री के लिए महाजन द्वारा लाए गए सामान पर एक रुपए में आधे पैसे की दर से प्रयुक्त कर ।
लदाई मेसा	मेसा-गाड़ी द्वारा ग्राम से माल बाहर ले जाने पर कर ।
निकासी चारा या घास फूस इत्यादि परछाई	बाहरी लोगों को घास या फूस बेचने पर प्रति गाड़ी सातू कर कभी-कभी एक रु० पर एक भाना तक । सिक्का जेबवाने का कर ।
भरती गाड़ी	गाड़ी द्वारा सामान बाहर निर्यात करने पर कर ।

#### ८—नज़राना—

उत्सवों पर ठाकुर की गद्दी नशीनी खेतों की परमायस, ठाकुर के जन्मदिन पर तथा नवविवाहित व्यक्ति द्वारा ठाकुर को भेंट स्वरूप राशि । सामान्यतः प्रति गाँव एक रुपया भ्रष्टाचारस्वरूप अन्यथा पूर्व प्रस्ताविक ।

राम राम	इस्तमरारदार को सलाम करके दूल्हे द्वारा दिया गया रुपया का नज़राना ।
खोहार पर नज़र	सामान्यतः पटेलों द्वारा परन्तु अन्य लोग भी हेतियत के अनुसार नज़र करते हैं ।
होली, दगाहरा, विवाली नज़र डोरी	फसलों की नपाई पर पटेल द्वारा ।
नज़र घासोत्र और चैती	जुलिया और सारवा में पटेलों द्वारा ।
सीसाला	पटेलों द्वारा प्रति तीसरे या दूसरे साल ।
साग पटेलाई	कोड़ा ग्राम में पटेलों द्वारा प्रति वर्ष तीन रुपए ।
नज़र कूँता	मिनाय में प्रति गाँव दो रुपया ।
पाट की नज़र गद्दी नशीनी ।	१) रु० प्रति घर उत्तराधिकार प्राप्ति पर ।

#### ९—ठिकाने के कर्मचारियों से संबंधित कर—

कामदार	ठाकुर के प्रतिनिधि को भेंट ।
रोहना ॥ रोहना भागी	सामान्य फसल के रूप में कभी-कभी नगदी में । सर्वाधिक केरोट ठिकानों में जहाँ एक रुपए पर उक्त कर एक भाना था ।
तमड़ा या ताम्झायत	राज्य द्वारा नियुक्त ब्राह्मण को विवाहादि पर सामान्यतः दी जाने वाली राशि ।

ढोली या दयाधी	ठिकाने के ढोली का कर (केवल ठिकाने द्वारा) नियुक्त ढोली ही जाया बजा सकता था ।
रूरासी या सासारी	प्रत्येक कर या खेत में रखवाली करने वाले का कर ।
गाँव नेग	ठिकाने के नौकरों के लिए सामान्य कर ।
नजूर सालाना	पट्टेजों से प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष ।
साग दरस्त या भाडा दरस्त ।	ठिकाने के कामदार को जिसकी देखरेख में पेड़ की कटाई हो प्रति वृक्ष एक भाना ।
दस्तूर गवाई	बसूली राजि में एक भाना प्रति रुपया कामदार के लिए ।
रबी तुलाई	सोसने का शुल्क अपिक्तर फसल के रूप में कभी-कभी नगदी में भी ।
पचकार	विवाहादि अवसरों पर ठिकाने के कर्मचारियों तथा भण्डेजों को दी जाने वाली नाममात्र की राशि ।
मुगन भेंट या डेली पूजा	पैमायश के समय दिया गया शुल्क ग्रामतौर पर ठिकानों द्वारा अपने उपभोग में ले लिया जाता था ।
बधीनी	कूते के समय भोजन के उपलक्ष में दी जाने वाली राशि ।
मलदा	(केवल दो गाँवों में लागू) देवलिया कला में कामदार की सुराकजाता में नाममात्र का शुल्क ।
गंवाई	खरबा के गाँवों के खातेदारों द्वारा प्रति गाँव एक बंधी राशि ।
१०—भुगतान पर रिमायत या छूट : बढोयस्त हिसाब पर शुल्क लगाने पर अतिरिक्त कर—	
बत्ती	यह वास्तव में विनिमय का अन्तर है परन्तु इसके साथ धीर भी कई उपकर जुड़े हुए थे जैसे, कल्दार और प्रचलित सिक्कों के विनिमय अन्तर की बमूली अन्तर न होने पर अथवा कम अन्तर पर भी अधिक की बसूली सामान्य बात थी । यह एक सामान्य और प्रापत्ति कर था जो आसामियों पर घोषा हुआ था ।
सबापा	प्रति खाता १ रु० तक ।
खचं	प्रति रुपए दो आने खातो पर ( मनोहरपुर में प्रचलित)

मल्वा	जैतपुरा के किसानों की एक मण ज्वार पर पौन आना । कुपल में १ आना, सावर में भोग या ठिकाने के हिस्से ।
घास बीठ	पारा में किसानों की जमींदार के लिए प्रचलित बाजार दर से एक ६० में ६ आने मजूरी पर घास काटनी पड़ती थी ।
अग्नी	फमल पर छोटा सा कर, मल्वा जैसा ।
उगाई	शाब्दिक अर्थों में बसूली खरवा में प्रति खेल, कुँए या हल पर अतिरिक्त उपकर ।
खाता	मसूदा के दो ग्रामी खातो पर पाँच प्रतिशत अतिरिक्त उपकर ।
मन्ती	मसूदा के ठिकाने के किराए ग्राम में बीघोड़ी के प्रति रुपए पर डेढ़ आने की दर से अतिरिक्त उपकर । भूमि की माप की दर ।

### ११. बेगार के बदले में बसूल किए जाने वाले उपकर—

बीठ घास	घास कटाई के उपलक्ष में शुल्क ।
लठ लठ	प्रति हल १ ब० कमी-कमी इससे कम भी ।
हलसरा हलवा	हल की बेगार के बदले भढ़ाई रुपया प्रति हल ।
माढ़ा गाड़ी	गाड़ी की बेगार के बदले ।
सफाई गढ़	कहाराँ द्वारा गुलगाँव में सेवा के बदले प्रति घर चार आना ।
साग-बेगार	जाट और शूजरी से उनके बँतो में सेवा न लेने की एवजी में कर, केवानिया में १ रुपए प्रति घर और पाडतिया में १ रुपया प्रति घर ।
हल और जोड़	गोविन्दगढ़ में हल सारा के अलावा ।

### १२. मन्दिर का कर—

मन्दिर	प्रति साता एक रुपया ।
धर्मादा	नियति पर कर ।

### १३. सार्वजनिक सेवाओं पर कर अस्वताल एवं मू संरक्षण व धर्मादा इत्यादि—

घोर या गाँवाई या तलाव	नानियों और जलाशयों की मरम्मत के लिए उगाहा जाने वाला कर ।
-----------------------	--

कोट	जूनिया में किले की गरम्मत के लिए उगाही गई राशि ।
शफाखाना	घसपताल के लिए धन संग्रह बहुधा ठिकानों द्वारा अपने शफाखानों के कार्यों में यह राशि व्यय कर दी जाती थी ।
सावर बाग्य	केवल भिनाय में सागु ।
घाटा	सावर में प्रति घर से दो घाने से लेकर चार घाने टीकों एवं चिकित्सालयों के लिए ।
१४. घाटा की चिकित्सियों, चूने के भट्टों एवं तेल-घाणी एवं कोल्हू इत्यादि पर रायसिद्ध—	
साग केही या शोरा	कलमीशोरा ठिकाने से बाहर निर्यात करने पर ।
घाणी खंट या तेल घाणी	तेली का कर सामान्यतः प्रति कोल्हू परन्तु बहुधा घरों पर भी कभी-कभी नगदी में अन्यथा तेल के रूप में ।
साग कोल्हू	प्रत्येक कुम्हार के भट्टे हैं या भट्टों से कुछ सी खपरल कर के रूप में ।
चक्की	भिनाय में घाटा चक्की कर ।
भट्टे का चूना	प्रत्येक भट्टे से गिनती की चूने की टोकरियां ।
किराया भट्टी	चूने निकालने की भट्टी का लायसेंस कर ।
१५. नजराना—	
यात्रा	इस्तमरारदार की तीर्थ-यात्रा पर नजराना ।
नजराना गोद	उत्तराधिकारी प्राप्त करने पर या गोद लेने पर ।
अन्य नजराने उत्तराधिकारी सम्बन्धी	
पटलाई	पटेल द्वारा नियुक्ति पर नजराना ।
पटवार पाना	पटवारी की बारी अनुसार नियुक्ति पर नजराना ।
१६. खाता लिखित रसोद, रजिस्ट्री शुल्क—	
वाँच	(हिस्सा) आठ घाने से लेकर एक रुपया प्रति खाता ।
गांव	वाँच के अनुरूप ही कर ।
लागडोरी	नपती के लिए प्रति खाता दो घाने (मनोहरपुर में) ।
सेखा या लिखाई	लिखने या हिसाब जोड़ने का शुल्क ।

चिट्ठी पट्टा	(बांदनवाड़ा में प्रचलित) सवा रुपया प्रति पट्टा ।
काटा अगोतरी	अग्रिम राजस्व देने पर नाममात्र का उपकर ।
पैमायश	पट्टे प्रदान करने पर लगान के प्रति रुपए पर एक पैसा अतिरिक्त कर, (पीसांगन में प्रचलित) ।
पट्टा	पट्टा जारी करने पर शुल्क ।

१७. पानी फालतू बहाने, नुबतान करने व सभी तरह के अनाधिकृत प्रवेशी पर जुर्माना-साली का शुल्क—

थाड़ा	मवेशियों के अनाधिकार प्रवेश पर अर्ध दंड ।
नुबतान जारायत	घास पेड़ी तालाबों आदि की सामान्य क्षति पर ।
अपखरारी	छाट में देरी पर दंड ।
इजायत	नुबतान पर क्षतिपूर्ति कसरत की एवज में कभी-कभी उक्त दंड लागू किया जाता था ।

१८. कुँघों पर कर—

घरर	प्रति कुँए पर जहाँ चड़स या साव चलता है । प्रति-साव या चड़स पर एक रुपया दस भाने ।
कुर	सामान्य कूप कर—प्राचीनकाल से चला आ रहा कर जो लेख बनवाने के लिए संभवतः सकड़ी में उप-भोग करने पर स्थापित किया गया था । साव से अतिरिक्त कर ।
घोर	कभी-कभी कुर के समान ही उस किसान पर अर्धे दंड के स्वरूप पाँच रुपए तक जो दूसरों के कुँघों पर से फसल सिंचित करते पाए जाते हों ।
गाँव सर्व घोर नवशा	सरकारी अधिकारियों तथा पैमायश वालों ॥ लिए आतिथ्य खर्च ।
हलगरा	हल खूंगी (मनोहरपुर) में कुँघों पर पार रुपए प्रति कूप ।
बावरा	मालियों घोर सेलियों पर मनोहरपुर में विशेष कर ।
सानी बाज	(साटा कोट में) कूप कर ।

१९. हल-शुल्क की बेगार की एवज में न हो—

हलवा राह राह	एक हल से अधिक नाप की भूमि पर कर ।
--------------	-----------------------------------

हलसार प्रति हल कर कभी-कभी गृह कर मान लिया जाता था ।

२०. विविध उपकर . लगान तथा "सगों" के अतिरिक्त—

बीह कर

दांतली

बसरत

ह्रासिए का कर ।

जहाँ निर्धारित क्षेत्र से अधिक फसल बोलने पर कपास की निर्धारित सीमा क्षेत्र का चौपाई या भाषा अथवा उससे अधिक बोलने पर अर्ध दंड सामान्य लगान हैं दुगना, कुछ क्षेत्रों में प्रति दस रुपए ।

ठेका

बसूल के पत्ते घटोरने, सात एकट्टी करने, गाँव के मृत डोरों की हड्डियाँ आदि का ठेका ।

हक ठिकाना

पड़त छात या गाँव में मृत साधारण पशु की खाल पर ठिकानेदार का अधिकार । पाट छाट-रोड़ी के डेरो व पड़ाव की छाव पर ठिकाने का हक ।

पड़ाव-शुल्क-गाँव में दकी बैलगाड़ियों पर चूंगी ।

महेरा

होली के दूसरे दिन शिकार वज्र के लिए ग्राम महा-जमी द्वारा ठाकुर को चूंगी ।

मुतकरवत खर्च

(केवल मनोहरपुर में) जागीरदार द्वारा दयाकदा बसूल किए जाने वाले उपकर ।

## अनुसूची (ग)

१. नेग और अन्य कर जो जिनमें में चुकाए जाते थे—

फसल के बँटवारे के समय नियमित नेग हिसाब में लिए जाते थे जो राज्य के हिस्से भोग में प्रति मण चालीस सेर पर दो सेर से १५ सेर तक बसूले जाते थे । केवेडिश महोदय के समय में भी प्रचलित थे:—

साकी

(मसूदा में) ओग में दो से दस सेर प्रति मण ।

पारारज

सामान्य नेग ठिकाना ।

कीना, कामदार, भाड़ा,  
कानूनगो

} कामदार पर ठिकाना बसूल करता था । कामदार को वेतन पर नियुक्त किया जाता था । कानूनगो हिसाब रखने वाला होता था ।





फूँची (हरी, गाँवा,) करपा, } ये सामान्यतः गाँव के ग्रन्थजों या ग्राम कर्मचारियों  
हस्तक या पायला सामन्त } के लिए होते थे, परन्तु इसे कुछ ठिकाने या ठिकाने  
सेर } के कर्मचारी रखते थे ।

रसासा, कागलिया, फल रसवानी वाले का कर ।  
सोसरी इत्यादि ।

खोली या हमामी राजे घाने का ।  
विविध कर्मचारीगण, रसोईदार,  
मंगी, चौबदार, फरान, भुगतान प्रसामान्य रहते थे ।  
चरवादार

लाग कमील ठिकाने के कर्मचारियों का सामान्य उपकर ।  
बचकी फल के माप के समय मंगी या बत्ताई धीरे सेहना  
फलन में से कुछ मुट्टी भर लिया करते थे । बहुधा इन  
सोमों के सहायक नियुक्त होते थे जो यह काम किया  
करते थे ।

३. बाँटा ■ प्रसादा लिया जाने वाला अनाज—

ईब सामगन्धी देवने वालों से नेग की सीमा निर्धारित  
नहीं थी ।

मुट्टा या मकिमा सामान्यतः सौ मुट्टों तक परन्तु कई क्षेत्रों में इससे भी  
अधिक ।

होला, बागी या छोला या बूटा भन्न की बालियाँ ।  
बीस्वाया खुड हरे चारे का उपकर, सामान्यतः औ की बालियाँ ।  
काकडी खरबूजा काछी सोमों से नेग बमूली ।  
दोवड़ी खेत की मेड़ पर उगी घास आदि ।

४. ग्राम में भृत पशुओं की खानों की रंगाई पर ठिकाने के अधिकार के रूप में लिया  
गया उपकर—

सालिपाना रंगर चटख पर तैयार खान ।  
मखवान या मूडिया एक या दो खालें चरस के मुँह का कर चमारों से  
कभी-कभी नगदी के रूप में ।  
पगरखी या पापोज चमारों से जूते, कभी-कभी नगदी के रूप में ।  
पडीस या तगी पेरा तग धोडे इत्यादि के लिए ।

डोलची होली पर रंगरों से चमड़े की डोलची पानी खींचने के लिए या पिलाई के लिए ।

#### ५. विविध—

साजूरू या बागोलाई सामान्यतः १ बकरा या भेड़ा प्रति २० भेड़ों पर, कभी-कभी नगद भुगतान, अधिक से अधिक तीन रुपए तक बलि के लिए ।

दूप-दही जाटों या गूजरों से कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर वसूली ।

काड ईंधन के लिए कंटे ।

केल्हू कुम्हारों के प्रति घर से मट्टी से खपरेल ।

भड़ा की धूपरी होली के दूसरे दिन से भस्मीय, भांग ।

धूंधिया या चरमा ऊनी लाई या कम्बल, खटीक या गडरिया से ।

गन्ने सामान्यतः किसान के गन्ने के खेतों से प्रति खेत १०० गन्ने ।

गुड की भेली गुड की डेरी (पांच सेर के लगभग) प्रति गन्ने के खेत से ।

खोड़ी रंगरों से घास की वसूली ।

सागा धूसा धूसा की वसूली ।

साग्वी गडरिए से कुछ ऊन की वसूली ।

मिर्च, गाजर, प्याज इत्यादि आवश्यकतानुसार इन चीजों की वसूली ।

बुनकरों पर कर प्रति वर्ष सूत की एक सन्धी और एक तोलिया ।

#### ६. कति—

भोज सामग्री एवं मिष्ठान्न पदार्थ मौसम या शारी के अवसर पर ठिकानेदार के लिए निर्धारित संख्या व मात्रा में दिए जाते थे । इनकी संख्या व मात्रा एक ठिकाने के गाँवों में भी पृथक्-पृथक् थी । ठाकुरों द्वारा निर्धारित काँसों की संख्या में अंत्यजों व कर्मचारियों के काँसों की संख्या सम्मिलित नहीं है । सामान्यतः ठिकाने को बहुत कम कति जाते थे कुछ स्थानों पर इनकी संख्या निश्चित थी, उदाहरणस्वरूप ६८ कति । कुछ लोग इसकी एवज में नगद राशि दे देते थे, अधिकतम ११ रुपयों तक ।

सरा							
बागमुदी	नगद राशि में परिवर्तित जो अधिकतम २४ रुपए तक होती थी । कुछ लोग कांसे के घलावा भी १३ रुपए दे देते थे ।						
सापाना	जाट और छीपों से १३० कांसे जाते थे । इनमें से अधिकांश जागीरदारों और ठिकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होते थे ।						
गरीला	ठिकाने के लिए ६५ कांसे—५ ठाकुर के, केवल १३ शेष कर्मचारियों एवं २५ दरोहों के लिए जिनका ग्राम के कामों से कोई संबंध नहीं होता था ।						
जोतायन	कांसे का कर नगद कर में परिवर्तित मिठाई की किस्म के अनुसार चार रुपए से लेकर बीस रुपए तक ।						
भिनाय	१ से लेकर ३२ कांसे ठिकाने के कर्मचारियों के लिए, ठिकाना इनमें से कुछ भी नहीं लेता था ।						
संधुन	कांसे की दर मिठाई की किस्म के अनुसार निर्धारित:— <table data-bbox="381 840 771 999"> <tr> <td>लड्डू</td><td>८ रुपए</td></tr> <tr> <td>हजुषा</td><td>६ ”</td></tr> <tr> <td>साप्ती</td><td>४ ”</td></tr> </table>	लड्डू	८ रुपए	हजुषा	६ ”	साप्ती	४ ”
लड्डू	८ रुपए						
हजुषा	६ ”						
साप्ती	४ ”						
पीसांगन	ठिकाने का हिस्सा नगदी में भुगतान होता था और भत्यजों के लिए कांसे के रुपए ।						

### ७. धीरत—

ठिकाने के द्वारा कर्मचारियों के निमित्त ली गई लागों और ग्राम भन्त्यजों को वार्षिक देय में भेद करना कठिन है । सामान्यतः इन लोगों को भोग में प्रति मण में से एक दो छँटाक या प्रति वर्ष निर्धारित सेर या सीरोजा ढेरी में से कुछ मुट्टे दिए जाते थे । भन्त्यजों में निम्न जाति के लोग आते थे:—

मुनार  
 लुहार  
 नाई  
 पटेल  
 दर्वी

तामड़ायत (पुरोहित या पण्डा आदि)

नट

मेहतर

रंगर

घोदी

टिड्डी वाला

बावर या बागरा

चमार

मील

---

